

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

हि० ग्रं० अ० प्रभाग ग्रथांक-262

एक राष्ट्र : दो शताब्दियाँ

(संयुक्त राज्य अमरीका का इतिहास)

1776—1976

लेखक

के० के० कौल

पाश्चात्य इतिहास विभाग,

लखनऊ विश्व विद्यालय

लखनऊ



उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

(ग्रंथ अकादमी प्रभाग)

राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन

महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

प्रकाशक :

विनोद चन्द्र पाण्डेय

निदेशक

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थ योजना के अंतर्गत
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
द्वारा प्रकाशित ।

© उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्था

पुनरीक्षक :

श्री माधव शरण

लखनऊ

प्रथम संस्करण : 1963

प्रतियाँ : 1100

मूल्य : 90 रुपये (नब्बे रुपये)

मुद्रक :

गर्ग प्रिन्टर्स,

२५७/२ सिसेंढी हाउस, ऐशवाग,

लखनऊ

प्रस्तावना

शिक्षा आयोग (1964-66) की संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने 1968 में शिक्षा सम्बन्धी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और 18 जनवरी 1968 को संसद के दोनों सदनो द्वारा इस सम्बन्ध में एक सङ्कल्प पारित किया गया। उस सङ्कल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था करने के लिये विश्व विद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से प्रत्येक राज्य में एक ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गयी इस राज्य में भी विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी 1970 को की गयी।

प्रामाणिक ग्रन्थ निर्माण की योजना के अंतर्गत यह अकादमी विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करा रही है और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना कर रही है। प्रकाश्य ग्रन्थों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वे पाण्डुलिपियाँ भी अकादमी द्वारा मुद्रित करायी जा रही हैं जो भारत सरकार की मानक ग्रन्थ योजना के अंतर्गत इस राष्ट्र में स्थापित विभिन्न अधिकरणों द्वारा तैयार की गयी थीं।

प्रस्तुत पुस्तक इस योजना के अंतर्गत मुद्रित एवं प्रकाशित करायी गयी है। इसका लेखन डॉ० के. के. कौल इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है तथा पुनरीक्षण श्री माधव शरण लखनऊ ने किया है इनके सहयोग के लिये उ० प्र० हिन्दी संस्थान आभारी है।

श्री के. के. कौल ने अपने अध्ययन और अध्ययसाय द्वारा तत्कालीन नौयानियों के साहस और उत्सर्ग के ऐतिहासिक विवरणों को एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास किया है उपनिवेशवाद के विकास काल में यूरोप के विभिन्न देशों के अभियानों का इसमें रोचक एवं तथ्यपरक इतिहास उपलब्ध होता है। जार्ज वाशिंगटन से रिचर्ड निक्सन तक की यह साहसिक यात्रा मानव समाज के

आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास की भी कहानी कहती है। इस दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। आशा है पाठक खुली नजर से इसको पढ़कर मानवता की सुखसमृद्धि के लिए संघर्ष करती हुई आम जनता की भावी संभावनाओं का पूर्वाग्रह रहित आकलन कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रयास की चरितार्थता व्यष्टि और समष्टि के संघर्षों एवं उपलब्धियों के तात्त्विक अन्वेषणों में ही अंतर्निहित है मुद्रण की त्रुटियों और भाषागत खलनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी।

शिव मंगल सिंह 'सुमन'

उपाध्यक्ष

उ० प्र० हिन्दी संस्थान

लखनऊ

अमरीकी इतिहास लेखकों

एवं

प्रकाशकों को

समर्पित

आमुख

विश्व राजनीति का विश्लेषण एवं क्रमवद्ध अवलोकन इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि आधुनिक राजनीति में अमरीका का विशिष्ट, महत्वपूर्ण एवं अन्यतम स्थान रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका का दो शताब्दियों का इतिहास स्वयं में एक राष्ट्र के उत्थान के संघर्ष का इतिहास रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका ने 200 वर्षों में अपनी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं राजनैतिक प्रौढ़ता से विश्व की मुख्य शक्ति के रूप में अन्य राज्यों के प्रणेता का स्वरूप गृहण किया है। किसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष कर स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता प्राप्त करना स्वयं में एक कठिन कार्य है। परन्तु इस ध्वन पथ से राष्ट्र को निजी उन्नयन की ओर अग्रसर होना केवल उसका ही नहीं अपितु साहस, विवेक एवं परिपक्वता का परिचायक है। अमरीका ने स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् लोकतंत्र, गणतंत्र एवं सामाजिक विकास के अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया।

इस पुस्तक का ध्येय अमरीका के दो दशकों के इतिहास के विविध चरणों की व्याख्या करना है। संयुक्त राज्य अमरीका ने अभिमुखीय विषम परिस्थितियों के मध्य अपने देशिक मूल्यों की पतवार के द्वारा राष्ट्र को राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदत्त की।

विश्व राजनीति में दो मुख्य राजनैतिक सिद्धान्तों से युक्त वर्गों के पारस्परिक आलोचनात्मक प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण में राष्ट्र की उत्पत्ति, उत्थान एवं विकास के प्रति जिन मूल्यों, नीतियों एवं सिद्धान्तों का सम्मिश्रण होना आवश्यक है, संयुक्त राज्य अमरीका के राजवेत्ताओं ने समयानुसार देश को नवचेतना, नवशिक्षा, तथा नव राजनीति से अवगत कराया। वॉशिंग्टन का स्वाधीनता चरण, जैफरसन, जैक्सन का गणतन्त्र एवं लोकतन्त्र, लिंकन का संघीय स्वरूप, विल्सन का आदर्शवाद, रूजवेल्ट का यथार्थवाद तथा अन्य घटनाओं ने संयुक्त राज्य अमरीका को विश्व में एक महाशक्ति का स्वरूप प्रदत्त किया है। संघीय लेखक ने इस पुस्तक में अमरीका के इतिहास के विविध चरणों का एक स्थान पर संयोजित करने का भरसक प्रयत्न किया है, तथापि अमरीका के वृहद इतिहास एवं राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक

तथा सांस्कृतिक जीवन को एक स्थान पर सूत्रबद्ध करना सरल कार्य नहीं है । लेखक के लघु प्रयास में यदि त्रुटियाँ अन्तर्बद्ध हों, तो उनके लिये क्षमायाचनीय और परामर्श वांछनीय है ।

प्रस्तुत पुस्तक लेखन का उद्देश्य हिन्दी भाषा में उपयुक्त इतिहास लेखन के अभाव की पूर्ति करना है । और लेखक इसके लिये उत्तर-प्रदेश हिन्दी संस्थान का आभारी है जिसके द्वारा यह लेखन कार्य संभव हो सका ।

लेखक उन सब प्रकाशकों एवं लेखकों का अत्यन्त आभारी है, जिनके लेखन कार्य द्वारा पुस्तक रचना में सहयोग मिला । अंततः लेखक उन सब शुभचिन्तकों के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता है जिन्होंने इस कार्य के मध्य सर्वप्रकारेण परामर्श एवं प्रोत्साहन प्रदत्त किया है । लेखक गायत्री कौल, सुचित्रा कौल एवं प्रमोद कुमार तथा जगजीवन रूपेनवार का आभारी है जिन्होंने पाण्डुलिपि के संकलन में अपना योगदान दिया । लेखक अपनी कर्तव्य त्रुटि समझता है यदि वह श्री गर्ग के प्रति आभार प्रकट न करे जिन्होंने शोध्य पत्र के मध्य धैर्यपूर्वक सहयोग प्रदत्त किया ।

—के. के. कौल

विषय-सूची

विषय-प्रवेश

संविधानवाद

अध्याय I

41-79

क्रान्ति युग स्वतन्त्रता की घोषणा स्वतन्त्रता संग्राम फ्रांस-अमरीका
संधि पेरिस में शांति प्रयास उपसंहार संवैधानिक युग उपसंहार

अध्याय II

80-90

वार्शिंग्टन अधिकारों का प्रस्ताव, हैमिल्टन की योजना, ह्विस्की
विद्रोह, दलों का उद्भव, वैदेशिक नीति, जे. की संधि, पिक्ने की
संधि,

जॉन एडम्स, विदेशी तथा राजद्रोही अधिनियम, कैंटेकी तथा वर्जी-
निया का प्रस्ताव ।

लोकवाद

अध्याय III

91-114

टॉमस जैफरसन, जैफरसन का प्रशासन, संधीवादी नीतियों में परि-
वर्तन, लुइजियाना (लुईसियाना) क्रय, लुईजियाना संधि, जैफरसन
का द्वितीय चुनाव, जैफरसन के राजनैतिक विचार, उद्योग कृषि
एवं जैफरसन, गणतंत्रिक प्रादुर्भाव, गृह नीतियाँ, वैदेशिक नीति,
अमरीकी तटस्थता, चंसापीक-लैपड घटना, निषेध अधिनियम,
1808 का चुनाव

जेम्स मैडिसन

उपसंहार

नवीन लोकतंत्र

अध्याय IV

115-136

राष्ट्रपति जैक्सन, जैक्सन के विचार, नवीन लोकतन्त्र, लाभ की

पद्धति तथा दल सत्ता, अमरीकी आदिवासी समस्या, अकृतिकरण, बैंक, उपसंहार

संयुक्त राज्यवाद

अध्याय V

137-178

देशिक संघर्ष, दास प्रथा, कपास का साम्राज्य, दास प्रथा का पुनर्जन्म, आर्थिक समस्याएँ, दक्षिण समाज, राजनीति, कैन्सास-नैब्रास्का विधेयक, युद्ध की ओर, भाई-भाई का युद्ध, विक्सवर्ग, चेटनूगा, पीच ऑरचर्ड का युद्ध, न्यू ऑरलियेन्स युद्ध, मॉनिटर तथा परमैक, शाप्सवर्ग : ऐंटीटेम का युद्ध, फ्रैंडरिक्सवर्ग का युद्ध, चांसलर्जविल : जैक्सन की मृत्यु, गेटिले वर्ग का युद्ध, मिशनरी रिज पर आक्रमण, राज्य संघ का संकुचन, अब्राहम लिंकन, यूलिसस सिम्पसन ग्रान्ट-रावर्ट एडवर्ड ली., युद्ध के परिणाम, उपसंहार
देशिक संघर्ष के युद्ध मंच की दैनिकी

पूजावाद

अध्याय VI

179-222

पुर्ननिर्माण, कृष्णविधि संग्रह (व्लैक कोड्स), उग्रवादी योजना, कांग्रेस योजना, महाभियोग, पुर्ननिर्माण समीक्षा नवयुग, ट्रूमैन प्रशासन, निष्पक्ष व्यवहार नीति, वैदेशिक सम्बन्ध, उत्तरी अटलांटिक संधि, कोरिया, साम्यवादी संकट, मैकार्थीवाद युग विकास, वस्त्र उत्पादन उद्योग, लोहा और इस्पात, आवागमन, राष्ट्रीय जनपथ, नहरों का निर्माण, रेलवे, स्टीम वाट, टेलीग्राफ, मानव शक्ति, श्रमिकों की दशा, श्रमिक संगठन, औद्योगिक क्रान्ति का महत्व, गांवों का नागरीकरण ।

साम्राज्यवाद

अध्याय VII

223-243

संयुक्त राज्य अमरीका और प्रथम महायुद्ध, युद्धरत अमरीका, उपसंहार

अध्याय VIII

244-257

महायुद्धोपमध्य अमरीका, आर्थिक, स्त्रीमताधिकार, ओप्रावासी समस्या,

सहसा वृद्धि और प्रस्फोट, श्रमिक अपसरण, विल्सनोपरांत आंतरिक दशा, वैदेशिक नीति

प्रत्याक्रमणवाद

अध्याय IX

258-304

द्वितीय विश्वयुद्ध, अमरीकी तटस्थता, द्वितीय विश्वयुद्ध और अमरीका, याल्टा सम्मेलन, उपसंहार

युद्धकालीन अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन घोषणा एवं समझौते, चर्चिल रूजवेल्ट वार्ता, प्रथम मास्को सम्मेलन, कासा ब्लांका सम्मेलन, आंग्ल-अमरीकी सम्मेलन, प्रथम किववेक सम्मेलन, मास्को विदेश मंत्री सम्मेलन, प्रथम कैरो सम्मेलन, द्वितीय कैरो सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, ब्रेटेन-वुड्स सम्मेलन, डम्बार्टन-ओक्स सम्मेलन, द्वितीय मास्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, पोट्स-डैम सम्मेलन,

राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनका प्रशासन ।

सिद्धान्तवाद

अध्याय X

305-336

शीत युद्ध, सैद्धान्तिक गुट शिविर, चार सूत्रीय कार्यक्रम, जर्मनी का नियन्त्रण, पूर्वी यूरोप, यूनान और ट्रूमैन का सिद्धान्त, फिलीस्तीन प्रश्न और मध्य पूर्व एशिया, जापान, फिलीपीन एवं प्रशान्त सुरक्षा व्यवस्था, चीन में साम्यवाद, कोरिया, नवीन अन्तराष्ट्रीय समाज व्यवस्था का सगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ और निःशस्त्रीकरण, अमरीकी महाद्वीपीय व्यवस्था एवं रियो सुरक्षा समझौता ।

अस्तित्ववाद

अध्याय XI

337-352

आइजन्हावर का प्रशासन काल, आधुनिक गणतन्त्रवाद, आर्थिक नीतियाँ, राजनैतिक दल, विदेश नीति, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया,

अध्याय XII

353-374

नव निर्माण युग, चुनाव, जॉन एफ कॅनेडी, यूरोप में नयी नीतियाँ, एशियाई नीति, हिन्द चीन में अमरीका, चीन प्रतिस्पर्धा, उच्चतम न्यायालय, दक्षिण नीग्रो क्रान्ति, कॅनेडी पटाक्षेप ।

अध्याय XIII	375-386
लिडन वेन्ज जाँनसन, विविध समस्यायें, सामाजिक सुधार, गणतन्त्र-वादियों का पुनः उदय, नीग्रो विद्रोह ।	

नव्य उपनिवेशवाद

अध्याय XIV	387-404
------------	---------

एशिया में अमरीका, नव उपनिवेशवाद की ओर, अरब देश (1951-1958), अरब देश (1959-67) छह दिवसीय युद्ध : ट्रूमैन का सिद्धान्त, मध्य पूर्व एशिया सुरक्षा संगठन एवं मिस्र, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, बगदाद समझौता, आइजनहॉवर सिद्धान्त ।

अध्याय XV	405-415
-----------	---------

पेट्रोलियम साम्राज्यवाद, बेल, मध्य पूर्व, एशिया (पश्चिमी एशिया) तेल हेतु अमरीकी प्रयत्न, अमरीकी तेल स्वार्थों का एकीकरण, युद्धो-परान्त अमरीकी योजना, ट्रूमैन सिद्धान्त एवं मध्य पूर्व एशियाई तेल, ईरान, ईराक, साऊदी अरेबिया, बहराइन तथा कुवैत, समृद्धि-युक्त वर्ष 1948-60, पेट्रोलियम राजनीति एवं आर्थिक राष्ट्रवाद ।

अध्याय XVI	416-451
------------	---------

दक्षिण पूर्व एशिया एवं अमरीका, फिलीपीन-एक सर्वेक्षण, फिलीपीन पर स्पेनिश अधिकार एवं शासन, फिलीपीनी विद्रोह एवं ब्रिटिश आधिपत्य, सुधारात्मक प्रयास, फिलीपीन क्रान्ति, फिलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य, अमरीकी शासन एवं भूमि सुधार, सामाजिक उत्थान के प्रयास, फिलिपीनीकरण, आर्थिक विकास की समस्या, स्वशासन की ओर, जापानी आधिपत्य, स्वतन्त्रता ।

अध्याय XVII	452-482
-------------	---------

अमरीका के राष्ट्रपति — एक परिचय

अध्याय XVIII	483-510
--------------	---------

अमरीका का संविधान

परिशिष्ट

रिचर्ड निक्सन का प्रशासन जिराल्ड फोर्ड का प्रशासन
निर्देश ग्रन्थ

चित्र एवं मानचित्र

चित्र

1. क्रिस्टोफर कोलम्बस	p	4 के सामने
2. जार्ज वॉशिंगटन	p.	41 के सामने
3. बँजामिन फ्रैंकलिन	p.	41 के सामने
4. टॉमस पेन	p.	47 के सामने
5. जार्ज वॉशिंगटन	p.	81 के सामने
6. जॉन एडम्स	p.	89 के सामने
7. टॉमस जैफरसन	p.	93 के सामने
8. एलेग्जैंडर हैमिल्टन	p.	99 के सामने
9. जेम्स मेडिसन	p.	109 के सामने
10. एण्ड्रू जैक्सन	p.	113 के सामने
11. जॉन कैलहून	p.	131 के सामने
12. डेनियल वॉशिंगटन	p.	131 के सामने
13. हेनरी क्ले	p.	147 के सामने
14. अब्राहम लिंकन	p.	155 के सामने
15. हैरी ट्रूमन	p.	193 के सामने
16. सैमुअल मोर्स	p.	215 के सामने
17. वुडरो विल्सन	p.	225 के सामने
18. लॉयड जार्ज ऑरलैन्डो, क्लीमेंसो और विल्सन	p.	237 के सामने
19. फ्रैंकलिन रूजवेल्ट	p.	261 के सामने
20. एटलांटिक चार्टर के समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विन्स्टन चर्चिल	p.	263 के सामने
21. तेहरान सम्मेलन में मार्शल स्टालिन और रूजवेल्ट	p.	279 के सामने

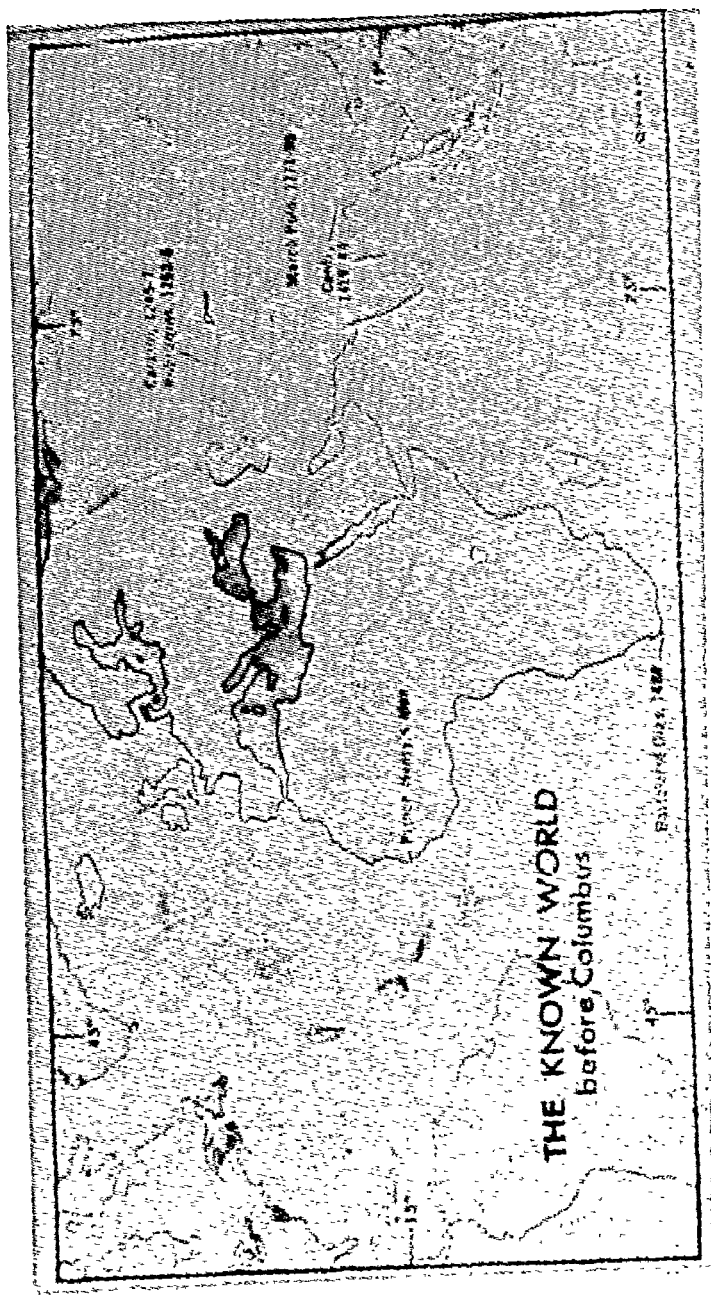
22.	याल्टा सम्मेलन में चर्चिल, रुजवेल्ट और स्टालिन	p	281 के सामने
23.	फ्रैंकलिन डी० रुजवेल्ट	p.	283 के सामने
24.	डिवाइट आइजनहाँवर	p.	339 के सामने
25.	राष्ट्रपति कैनेडी और उनकी पत्नी	p.	355 के सामने
26.	राष्ट्रपति लिडन जॉनसन	p.	375 के सामने
27.	विलियम हाँवर्ड टॉफ्ट	p.	435 के सामने
28.	रॉल्फ वाल्डो एमर्सन)		
29.	नैथेनियल हाँथान)		
30.	एडगर एलेन पो) परिशिष्ट के अन्त में		
31.	फ्रांसिस पार्कमैन) (p. 524)		
32.	एण्ड्रू जैक्सन	p.	460 के सामने
33.	थ्येडोर रुजवेल्ट	p.	471 के सामने
34.	बुडरो विल्सन	p.	473 के सामने
35.	जेम्स मनरो	p.	458 के सामने
36.	जैकरी टेलर	p.	463 के सामने
37.	टॉमस जैफरसन	p.	456 के सामने
38.	जॉन क्विन्सी एडम्स	p.	459 के सामने

मानचित्र

1.	कोलम्बस से पूर्व विश्व	p.	3 के सामने
2.	1592 के पूर्व अभियान	p.	5 के सामने
3.	कोलम्बस एवं उसके समकालीन सहयोगियों की खोज यात्रायें	p.	7 के सामने
4.	क्रान्तिकारी अभियान	p.	51 के सामने
5.	संयुक्त राज्य अमरीका (1783-1800)	p.	90 के सामने
6.	दास प्रथा—1861 तक	p.	141 के सामने
7.	गृह युद्ध अभियान	p.	159 के सामने
8.	जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्धोपरान्त अधिकृत क्षेत्र	p.	197 के सामने
9.	कोरिया युद्ध	p.	199 के सामने
10.	प्रथम विश्व युद्ध का पश्चिमी मोर्चा	p.	233 के सामने
11.	वरसाई की संधि द्वारा यूरोपीय क्षेत्रों का स्थाना- न्तरण	p.	237 के सामने

- | | | | |
|-----|--|----|--------------|
| 12. | वरसाई की संधि द्वारा उपनिवेशिक परिवर्तन | p. | 237 के सामने |
| 13. | जापान का क्षेत्रीय विस्तार | p. | 265 के सामने |
| 14. | द्वितीय विश्व युद्ध में केन्द्रीय एवं दक्षिण पश्चिम
प्रशान्त महासागरीय अभियान | p. | 267 के सामने |
| 15. | उत्तरी अफ्रीकी अभियान (1942-43) | p. | 269 के सामने |
| 16. | द्वितीय विश्व युद्ध में इटली अभियान | p. | 271 के सामने |
| 17. | नॉरमेन्डी अभियान (1944) | p. | 277 के सामने |
| 18. | शीतयुद्ध गठबंधन | p. | 307 के सामने |
| 19. | हिन्द-चीन विभाजन | p. | 347 के सामने |
| 20. | नीग्रो जनसंख्या | p. | 369 के सामने |

एक राष्ट्र : दो शताब्दियाँ
(संयुक्त राज्य अमरीका का इतिहास)
1776—1976



कोलम्बस से पूर्व विश्व

अमरीका का इतिहास

विषय-प्रवेश

प्राचीन विश्व तथा कोलम्बस

पन्द्रहवीं सदी के अन्तिम वर्षों ने एक ऐसे नवीन युग का सूत्रपात किया जिसने सम्पूर्ण विश्व-इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदत्त की। इसी युग ने सामन्तवाद के ध्वंसावशेषों पर राष्ट्रों का निर्माण किया एवं व्यापार तथा वाणिज्य को पुनर्जीवित किया। इन वर्षों ने नवीन अन्वेषणों तथा आविष्कारों से मानव जाति को अवगत कराया। अज्ञान-तिमिर-भ्रमित मनुष्य को दूरस्थ सागरवर्ती निवासियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अमरीका महाद्वीप के अन्वेषण ने एक ऐसी दीपशिखा प्रज्ज्वलित की जिसने आने वाली सदी में सम्पूर्ण विश्व का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। मनुष्य के साहस को इस प्रारम्भिक सफलता ने उसे और अधिक साहसिक, क्रियाशील तथा प्रगतिवादी बनाया। पन्द्रहवीं सदी के ये अन्तिम वर्ष अज्ञानता तथा ज्ञान के दो युगों के मध्य एक विभाजक रेखा के सदृश थे जिनको पार करते ही मानवता ने एक नव सूर्य के दर्शन किये। मानव अब अपनी सीमित परिधि में संतुष्ट न रह सकता था उसकी ज्ञान पिपासा निरन्तर नव परिधियों के अन्वेषण से ही शान्त हो सकती थी। उसके साहस, विवेक, धैर्य तथा महत्वाकांक्षाओं ने उसे निरन्तर ज्ञान की नवीन पृष्ठभूमि से परिचित कराया।

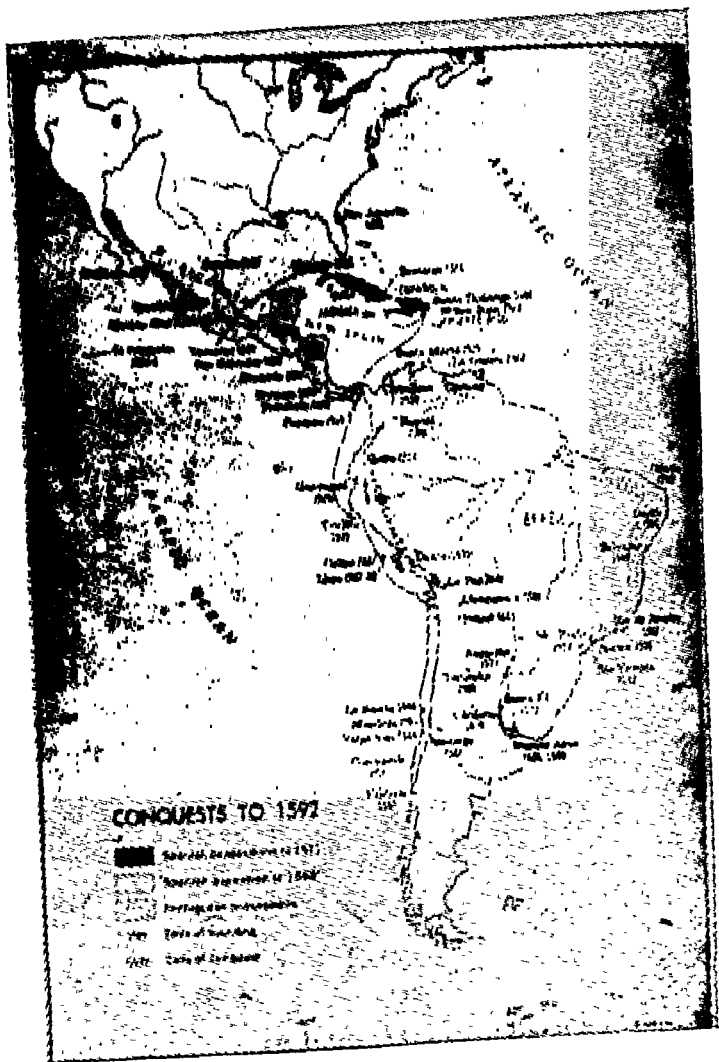
इसके पूर्व यूरोप के निवासी पृथ्वी के आकार तथा भौगोलिकता से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। पूर्व के विषय में उनका ज्ञान मार्कोपोलो के व्यक्तिगत अनुभवों तक ही सीमित था। वहाँ की अपार धन-सम्पदा एवं समृद्धि के विषय में उन्हें अतिरंजित ज्ञान था। यद्यपि ये अफ्रीका के भूमध्यसागरीय तट तथा नील की घाटी से परिचित थे, परन्तु अब भी यूरोप के पश्चिम तथा उत्तर की भूमि उनके मानचित्रों में प्रदर्शित नहीं थी। ब्रिटेन के पश्चिम में अटलांटिक अब भी सीमा विहीन था। यद्यपि अरस्तू तथा सीसदो ने महासागर

4/अमरीका का इतिहास

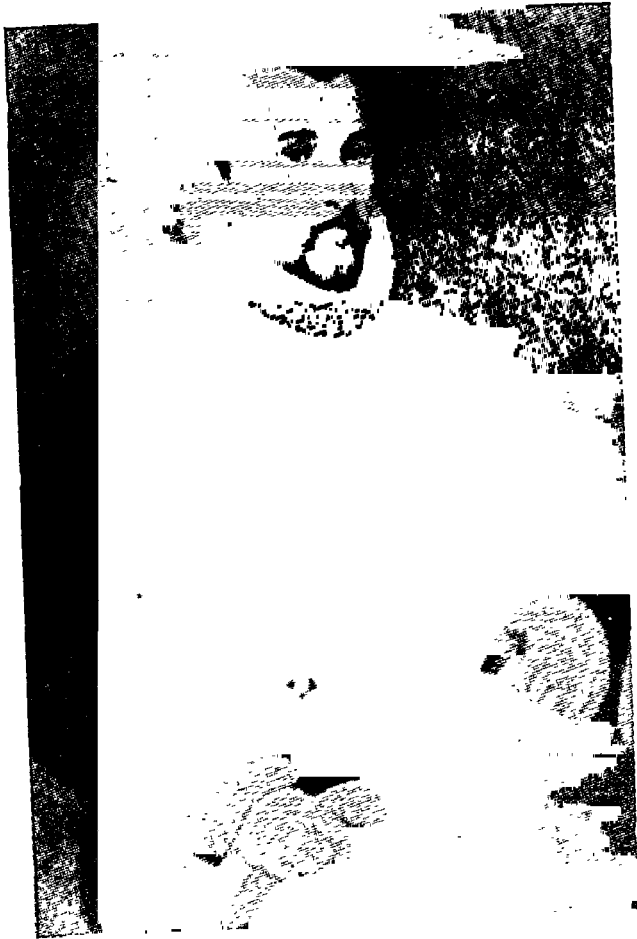
पार अपरिचित महाद्वीपों की कल्पना की थी तथापि विभिन्न प्रमुख ज्ञानविदों के अनुसार अटलांटिक मात्र एक संकीर्ण सागर के रूप में स्वेज़ तथा पूर्व को विभाजित करता था। इस छोटी सी भूल ने अमरीका के अन्वेषण में प्रत्यक्ष भूमिका अदा की। पश्चिमी यूरोप के सम्राट, सुदूर पूर्व राष्ट्रों से व्यापार हेतु नवीन मार्गों के अन्वेषण के लिये उत्सुक थे क्योंकि प्राचीन मार्गों पर इस्लाम तथा इटली का एकाधिकार हो गया था। इसी समय क्रिस्टोफर कोलम्बस ने स्पेन के सम्राट को यह पूर्णतया विश्वास दिला दिया कि वह पश्चिमी मार्गों की सहायता से भी जापान पहुँच सकता था। उसका विश्वास था कि जापान स्पेन से केवल 2500 मील दूर था। इस नवीन मार्ग में सुरक्षा की सम्भावनाएं अपेक्षाकृत अधिक थीं यद्यपि मार्ग व्यय कुछ अधिक अवश्य पड़ सकता था। इसके साथ ही साथ दिक्सूचक (मैग्नेटिक कम्पास), अक्षांश ज्ञात करने का यंत्र (एस्ट्रोलेब) जल सर्वेक्षण का प्रायोगिक मानचित्र (पोर्तोलानी) तथा वायु के विपरीत भी तीव्र गति से चलने वाले नौकाओं (कारावेल) के आविष्कारों ने नौ संचालन के क्षेत्र में प्रगति के नवीन आयाम प्रस्तुत कर दिये थे। उसने अक्टूबर 12, 1492 को तीन छोटे लकड़ी के जलयानों पर अपनी यात्रा प्रारम्भ की। इन तीन नौकायानों बीना, पिन्टा तथा सेन्तामारिया के 90 नौयात्री अपने सत्तर दिवस की रोमांचकारी नौयात्रा के पश्चात् क्यूबा के उत्तरी तट पर जा पहुँचे। वहाँ से लौटने के पश्चात् स्पेन ने उसका एक सेनानायक की भाँति स्वागत किया क्योंकि उनके विचार में उसने चीन का समुद्री मार्ग खोज लिया था। उसने वास्तव में एक नवीन महाद्वीप का अन्वेषण कर लिया था। यह भेद स्पेनवासियों को बाद में ज्ञात हुआ। परन्तु उन्होंने यह नहीं समझा था कि वास्तव में उसने एक नये विश्व का अन्वेषण कर लिया था।

अभियान

इस सफलता के पश्चात् स्पेन के शासकों की याचनाओं पर तत्कालीन पोप अलेक्जेंडर पंचम ने एजोर तथा केपवर्डी द्वीपों के पश्चिम समस्त अन्वेषित क्षेत्रों पर स्पेन का अधिकार स्वीकार कर लिया। स्पेन तथा पुर्तगाल के मध्य टोर्डीसीलास की सम्यक् संधि (जून 1494) के अनुसार केपवर्डी द्वीपों के पूर्व पुर्तगाल का अधिकार क्षेत्र घोषित कर दिया गया। क्रिस्टोफर कोलम्बस ने अपनी द्वितीय नौ-यात्रा (सितम्बर 5, 1493-जून 11, 1496) में लीवर्ड द्वीपों, प्यूर्तोरिको, इसाबेला, क्यूबा के दक्षिणी तटों, जमाइका के



1592 के पूर्व के अभियान



क्रिस्टोफर कोलम्बस (1492-1506)

तटों तथा हिस्पैनियोला के तटों की गवेषणा की। पुनः अपने तृतीय 1498-1500) एवं चतुर्थ (1502-1504) प्रयासों में कोलम्बस ने दक्षिणी अमरीका, पारिया की खाड़ी, होण्डुरान तट तथा मध्य पनामा तक की नौ-यात्रा की। यद्यपि कोलम्बस जीवन-पर्यन्त (मृत्यु मई 20, 1506) यह विश्वास दिलाता रहा कि उसने एशिया के तटों की ही गवेषणा की थी, परन्तु नये विश्व की सम्भावनाएँ भी समाज में समुचित आधार निर्मित कर रही थीं।

इसी मध्य वेनिस के निवासी जान कैवट ने अपनी दो नौ-यात्राओं में ब्रिटेन के सम्राट हेनरी सप्तम के हेतु न्यूफाउण्डलैण्ड तथा उत्तरी अमरीका के दक्षिण में स्थित डेलवेयर की खोज (1497-98) कर ली।

कोलम्बस की मृत्यु के पश्चात् इटली के निवासी अमीरीगो वेस्पुची (1451-1512) ने स्पेन के सम्राट के लिये 1499 में पुनः एक नौ-यात्रा प्रारम्भ की। अमीरीगो ने केप केसीपोर के दक्षिणी क्षेत्रों, दक्षिण-अमरीकी तटों, अमेजन नदी के उद्गम स्थान एवं ब्राजील के निकट "केपडी लाविला" की खोज की। अमीरीगो ने 1497 में मेक्सिको की खाड़ी तथा अमरीका के वर्तमान अटलांटिक तटों तक की नौ यात्रा की। 1507 में तत्कालीन भूगोल वेत्ता मार्टिन वाल्डसीमूलर ने सर्वप्रथम यह प्रस्ताव रखा कि "नवीन गवेषित विश्व का नाम "अमरीका" होना चाहिये क्योंकि इसकी खोज का सर्वाधिक श्रेय अमीरीगो को ही प्राप्य है।" 1509 में वेनिस के कैवट ने ब्रिटेन से अपनी यात्रा प्रारम्भ कर हडसन की खाड़ी की गवेषणा कर दी। स्पेन के नौ यात्री जुआन पांकडीलीआन तथा पनामा क्षेत्र तक जा पहुँचा। "फर्नाण्डो मैगीलन" नामक प्रसिद्ध पुर्तगाली अन्वेषक ने सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर लगाने का प्रयास किया। उसने 1519 में स्पेन की नौकाओं में अपनी यात्रा प्रारम्भ की तथा फिलीपीन तक जा पहुँचा परन्तु वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। शेष नौयात्री 1522 में स्पेन पहुँच गये और इस धारणा की परि-पुष्टि हो गई कि पृथ्वी गोल है। 1519-21 में हरनाण्डो कोर्टिस ने स्पेन के लिये मेक्सिको की विजय की। उत्तरी अमरीका के आन्तरिक प्रदेशों की गवेषणा में फ्रांसी जेक्यूस कार्टियर का योगदान फ्रांस के लिये अत्यन्त लाभ-दायक सिद्ध हुआ। उसने 1534-1543 में क्युबेक नदी तथा मन्ट्रीयाल तक का क्षेत्र फ्रांस के अधिकार में ला दिया। मैगीलन की ही भाँति 1577-1580 में फ्रांसिस ड्रेक ने पृथ्वी का चक्कर लगाया। उसने ब्रिटेन के लिये सैन फ्रांसिस्को नामक क्षेत्र पर अधिकार किया तथा 48° उत्तर तक उसने अपनी नौयात्रा सम्पन्न की। 1576-1606 में ब्रिटेन के मार्टिन फ्राँविरार ने उत्तरी

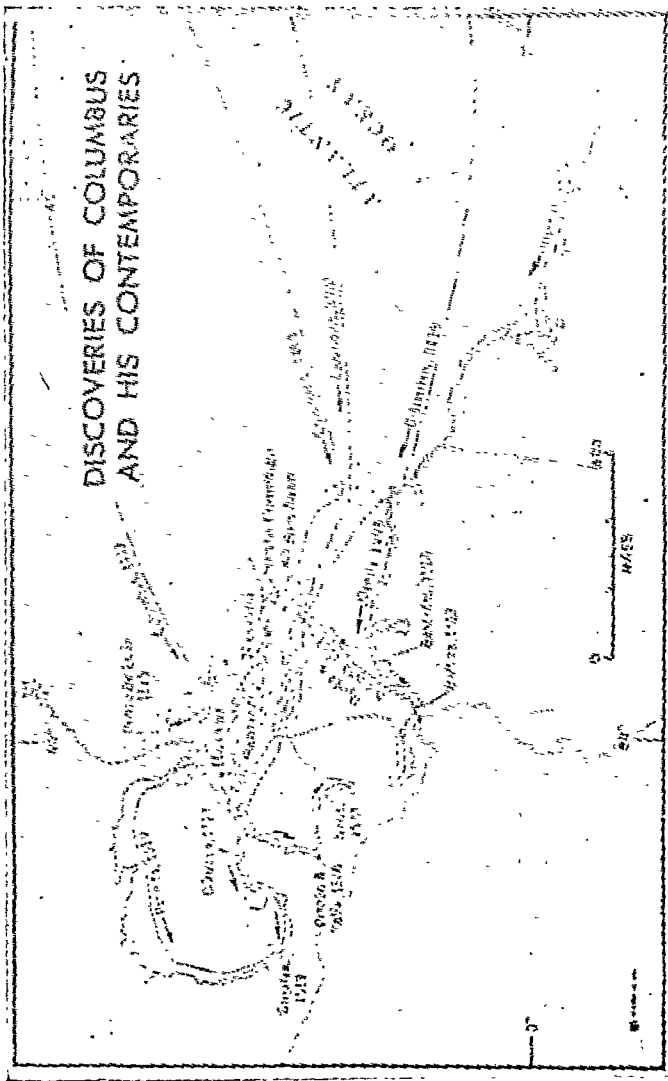
6/अमरीका का इतिहास

पश्चिमी मार्गों का गवेषण किया। वह ग्रीनलैण्ड होता हुआ वेफिन क्षेत्र तक जा पहुँचा। वहाँ से उसने हडसन की खाड़ी तक का मार्ग गवेषित किया और उसने यह घोषणा की कि एशिया के लिये सर्वाधिक उपयुक्त मार्ग यहीं था। उसके पश्चात् जान डेविस, जार्ज वेमाऊथ तथा जान नाइट ने उत्तरी पश्चिमी मार्गों पर अपनी गवेषणा जारी रखी। 1578-83 में सर हम्फ्रे गिलवर्ट ने उत्तर पश्चिमी अमरीका के उपनिवेशीकरण का असफल प्रयास किया। उसकी असफलता के पश्चात् ब्रिटेन के वाल्टर रैले ने, स्पेन के उपनिवेशों के संतुलन के लिये "वर्जिनिया" क्षेत्र की खोज कर वहाँ ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना की। यद्यपि इस उपनिवेश के सभी उपनिवेशियों की स्पेन तथा स्थानीय देशवासियों ने हत्या कर दी परन्तु पुनः जान व्हाइट के प्रयासों से (1597) वर्जिनिया उपनिवेश की स्थापना सम्भव हो सकी। इसके पश्चात् 1605-1607 में ब्रिटेन के कैथोलिकों के लिये जार्ज वेमाऊथ ने अपनी यात्रा प्रारम्भ कर वर्जिनिया (1606) में दो कम्पनियों की स्थापना की। "लन्दन कम्पनी" को 34° उत्तर तथा 41° उत्तर (आधुनिक न्यूयार्क) के मध्य तथा "प्लाईमाऊथ कम्पनी" को 45° उत्तर तथा 38° उत्तर (आधुनिक वाशिंगटन, डी०सी०) के मध्य वस्ती बनाने की अनुमति प्राप्त हो गयी।

ब्रिटिश वस्ती

ब्रिटेन ने सर्वप्रथम अमरीका के अन्वेषण का प्रयास कोलम्बस की सफलता के पश्चात् प्रारम्भ किया। सम्राट हेनरी सप्तम द्वारा नियुक्त जान वेबरने 1497 तथा 1498 में दो अभियानों में न्यूफाउण्डलैण्ड तथा मेनलैण्ड का अन्वेषण किया परन्तु उसके पश्चात् ब्रिटेन ने अन्वेषणों पर ध्यान देने की अपेक्षा यूरोपीय मुद्रा में अधिक रूचि प्रदर्शित की। 1570 में एलिजाबेथ के शासन ने ब्रिटेन को पर्याप्त स्यायित्व प्रदान किया तथा देश के वाणिज्य एवं उद्योग अत्यधिक विकसित हुये। इस स्यायित्व एवं सम्पन्नता के पश्चात् ब्रिटेन के निवासियों ने सुदूर अन्वेषणों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। 1576 में मार्टिन फ्राविशर ने लेब्रोडर अभियान किया। तत्पश्चात् जान डेविस, हेनरी हडसन, विलियम वेफिन तथा अन्य नाविकों ने विभिन्न अभियानों में उत्तरी अमरीका के नवीन प्रदेशों का अन्वेषण किया। यद्यपि सामुद्रिक आतंक से ब्रिटिश नाविक अधिक लाभान्वित होते थे परन्तु बिना उपनिवेश के धन-सम्पदा प्राप्त करना किसी भी प्रकार औचित्यपूर्ण नहीं था। अतएव उन्होंने उपनिवेशीकरण के द्वारा अधिक लाभ तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान

DISCOVERIES OF COLUMBUS AND HIS CONTEMPORARIES



का मार्ग प्राप्त करने की दिशा में अग्रसारित होने की योजना रखी। चीनी, मद्य, जैतून का तेल, सिल्क तथा वनस्पति पर स्पेनी एकाधिकार को भी उपनिवेशीकरण के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती थी। उन्होंने ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग के लिये भी उत्तरी अमरीका में लाभदायक भविष्य देखा। इस प्रकार उनके विचारों में यह भावना दृढ़ता पकड़ती गई कि वे उपनिवेशीकरण के द्वारा विदेशी एकाधिकार को चुनौती दे सकते थे तथा विदेशियों पर उनकी निर्भरता समाप्त हो सकती थी। यद्यपि साम्राज्ञी एलिजाबेथ उपनिवेशीकरण के पक्ष में थी परन्तु वह इन अभियानों पर तथा अन्य व्ययों पर शासन की पूंजी लगाने के पक्ष में नहीं थी अतः यह कार्य व्यक्तिगत लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। उत्तरी अमरीका में प्रथम उपनिवेश बनाने का कार्य सर्वप्रथम गिलवर्ट ने लिया परन्तु उसकी प्रारम्भिक दुर्घटना के पश्चात् उसके भाई रैले ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया। वह एक राजनीतिक, सेनाधिकारी नौसेनाध्यक्ष, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार तथा वैज्ञानिक था। वह अपने समय का सुप्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने वर्जीनिया तथा ७० कैलीफोर्निया के अभियान किये परन्तु उसकी योजनाएँ भी असफलताओं के कारण समाप्त हो गयीं।

फ्रांसीसी वस्ती

फ्रांसीसी शासन ने 1520 में उत्तरी अमरीका का अभियान प्रारम्भ किया। 1535 ने कार्टियर ने सेन्टलारेन्स की ओर अभियान किया तथा क्यूबेक को उपनिवेश के लिये उपयुक्त समझा परन्तु इसके पश्चात् फ्रांस भी यूरोपीय युद्धों में रत होने के कारण अन्य उपनिवेश न बना सका। यद्यपि फ्रांसीसी भी ब्रिटिश की ही भांति सामुद्रिक लूटमार करते थे। 16 वीं सदी के उत्तरार्ध में पुनः हेनरी षष्ठम ने उपनिवेशीकरण की दिशा में कदम उठाये तथा क्यूबेक तथा एकेडिया में फ्रांसीसी उपनिवेश निर्मित कर दिये गये। 1663 के पश्चात् इन उपनिवेशों का प्रशासन वाणिज्यिक कम्पनियों के हाथों से पूर्णतया निकलकर फ्रांसीसी शासनान्तर्गत आ गया। फ्रांस का उपनिवेशी संस्थान फर के व्यापार पर निर्भर था। यद्यपि इस उपनिवेशीकरण के अन्तर्गत फ्रांसीसियों का विभिन्न स्थानीय आदिवासियों से संघर्ष भी हुआ परन्तु अन्ततोगत्वा उन्होने उनसे मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लिया। फर के व्यापार के साथ-साथ धार्मिक अभियानों में फ्रांसीसी समान रूप से रूचि रखते थे। अनेक अभियानकर्ताओं ने अपना सम्पूर्ण जीवन आदिवासियों के धर्म परि-

वर्तन हेतु लगा दिया। यद्यपि फ्रांसीसी प्रभाव तीव्रता से बढ़ रहा था परन्तु औपनिवेशिक विकास की दर अपेक्षाकृत न्यून थी। 1663 के पश्चात् उपनिवेशी शक्ति का प्रसार कृषि, भूमि अनुदान, तथा औद्योगिक विकास की दिशा में हुआ। एक सामन्तवादी व्यवस्था की स्थापना फ्रांसीसी उपनिवेशों में हो गयी। इस प्रकार इन उपनिवेशों की व्यवस्था भी फ्रांस की ही भांति सामन्तवाद पर आधारित थी। इस पद्धति के अन्तर्गत भूस्वामियों का अपने कृषकों पर पूर्ण स्वामित्व होता था। पूरे उपनिवेश का प्रशासन कैथोलिक चर्च के अन्तर्गत होता था।

हालैण्ड का साम्राज्य

हालैण्ड ने स्पेन से स्वन्त्रता संग्राम के मध्य एक महान् सामुद्रिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त कर लिया था। 17 वीं सदी के पूर्वार्ध तक उसके जलयानों को चुनौती देना लगभग असम्भव था। उन्होंने अपने उपनिवेशीकरण के लिये पूर्वी द्वीप समूह को चयन किया जहाँ उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जो 20 वीं शताब्दी में जाकर समाप्त हुई। अमरीका में उनकी रुचि स्पेन से युद्ध के कारण पश्चिमी द्वीप-समूहों पर आरम्भ से प्रारम्भ हुई। 1609 में हालैण्ड ने ब्रिटिश नाविक हडसन की सहायता से एक अभियान पूर्व के मार्ग निर्धारण हेतु प्रेषित किया। 1624 में हडसन की सूचना विवरण के आधार पर फर के व्यापार हेतु उपनिवेशवासियों को भेजा गया। उन्होंने निदरलैण्ड में अपना एक उपनिवेश स्थापित किया। शनैः शनैः वे हालैण्ड, न्यू जर्सी, तथा हडसन की खाड़ी तक विस्तृत होते गये। हालैण्ड के उपनिवेशों में सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकार राज्यपाल में केन्द्रित थे। उपनिवेशियों को कोई भी राजनैतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। यह उपनिवेश प्रमुखतया फर के व्यापार में व्यस्त थे। 1629 में इस डच वेस्ट इण्डियन कम्पनी ने व्यक्तिगत स्तर पर सम्पत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया। ये व्यक्तिगत भूमिधर अपनी जमींदारी पर पूर्ण अधिकार रखते थे तथा उन्हें सामन्तवादी अधिकार प्राप्त हो गये। इन उपनिवेशों के विकास में आदिवासी संघर्षों के कारण पर्याप्त व्यवधान उत्पन्न हुये। हालैण्ड निवासियों ने वहाँ के स्थानीय कबीले आयरोक्यूओस से मैत्री कर ली अतः उन्हें उन आदिवासी कबीलों से संघर्ष करना पड़ा जो उनसे मतभेद रखते थे तथापि हालैण्ड के उपनिवेशों की संख्या पर्याप्त न्यून रही। वह भी पूर्णतया हालैण्डवासियों द्वारा आवासित नहीं थी।

स्वीडेन

स्वीडेन ने 1638 में अमरीकी उपनिवेशीकरण का प्रयास प्रारम्भ किया। इनका भी प्रमुख ध्येय फर का व्यापार ही था। उन्होंने डेलावेयर नदी के निकट अपने आवास बनाये परन्तु हालैण्ड ने इसको अपने अधिकारों के प्रति चुनौती समझकर 1635 में न्यू नीदरलैण्ड में मिला लिया।

अमरीकी सभ्यता का विकास

अमरीका में वास्तविक सभ्यता का विकास 1607 के पश्चात् प्रारम्भ हुआ जब जेम्सटाउन में प्रथम अंग्रेजी वस्ती की स्थापना हुई। वास्तव में अमरीकी सभ्यता यूरोपीय सभ्यता का प्रतिरूप है और इसका इतिहास यूरोप की विभिन्न जातियों—ब्रिटिश, डच, स्पेनिश तथा फ्रांसीसी लोगों का इतिहास है। उत्तरी अमरीका में मुख्यतः आंग्ल-सैक्सन तथा मध्य एवं दक्षिणी अमरीका में लैटिन लोगों का प्रभाव परिलक्षित होता है। पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में यूनान तथा रोम से प्रभावित रही है। यूरोप का मध्य युगीन इतिहास अन्वेषणों का इतिहास रहा है। इन अन्वेषणों का प्रभावी कारण तत्कालीन पुर्नजागरण, पूर्वी व्यापार सम्बन्ध तथा नवीन विज्ञान का प्रारम्भ था। तत्कालीन यूरोप में रोमन साम्राज्य का एकाधिकार था परन्तु रोमन साम्राज्य के सामन्तवादी व्यवस्था के विरुद्ध नवीन ज्ञान के उदय ने प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया था। पुर्नजागरण तथा नवीन ज्ञान के संश्लेषण ने पूर्वी व्यापार के त्वरण का कार्य किया तथा समाज के दो ध्रुवों के मध्य एक मध्यम वर्ग का निर्माण प्रारम्भ हो गया। यह वर्ग उच्च वर्ग के शोषण, धार्मिक रूढ़िवादिता एवं सामन्तवाद की क्रूरता के विरुद्ध वैज्ञानिक विवेक तथा प्रायोगिक सत्य के महत्व में विश्वास रखता था। यही कारण था कि यूरोप के इस युग ने पुर्नजागरण का अवलोकन कर विभिन्न नवीन अन्वेषणों को जन्म दिया। पृथ्वी के आकार, सूर्य के परिवार मंडल, चुम्बकीय सूई, भू-आकर्षण तथा टेलीस्कोप के अविष्कारों ने समाज की धार्मिक मान्यताओं को विनष्ट कर दिया। इस युग ने सीमित दायरे से बाहर आकर सुदूर प्रदेशों, महाद्वीपों, द्वीपों तथा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को खोजने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी नवीन वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति ने अमरीकी महाद्वीप के अन्वेषण में प्रमुख योगदान प्रदान किया।

कोलम्बस के पूर्व पुर्तगाल के प्रिंस हैनरी तथा डियाज ने इस परम्परा

की नींव डाली थी। कोलम्बस मार्कोपोलो के अनुभवों तथा पूर्व के विषय में प्रचलित विभिन्न विचारों से प्रभावित होकर 1492 में अमरीका पहुँचा था। कोलम्बस की सफलता, पुर्तगाल के विरुद्ध स्पेन की सफलता थी। उसका यह समझना कि उसने एशिया के मार्ग का अन्वेषण कर लिया है, 1522 में मैगेलन के विश्व भ्रमण के पश्चात् ही त्रुटिमय सिद्ध हो गया था। प्रारम्भ में वह अमरीका के करेबीयन द्वीप को ही चीन का मार्ग समझता रहा था। स्पेनवासियों ने वहाँ पर चीनी तथा अनाजों की खेती प्रारम्भ कर दी। वहाँ के देशी निवासियों की शोषण सीमा समाप्त होने पर अफ्रीका से नीग्रो लोगों का आयात किया गया। स्पेन ने पोप की घोषणा के अनुरूप नवीन महाद्वीप में एक बृहद् भू-भाग पर अपने अधिकारों को एकाधिकार का स्वरूप प्रदान कर रखा था। 1493 के पश्चात् 'टॉर्सेसिलास' संधि के प्राविधानों के अनुसार यह महाद्वीप स्पेन तथा पुर्तगाल के मध्य विभाजित कर दिया गया था।

यद्यपि कोलम्बस का अन्वेषण स्पेन के लिये गर्व की बात थी परन्तु वास्कोडिगामा के 1498 की उपलब्धि ने उसमें एक निराशा की भावना उत्पन्न कर दी थी। परन्तु 1519 में मेक्सिको के अन्वेषण ने स्पेन के खजाने को चाँदी से भरना प्रारम्भ कर दिया और स्पेन अब एक अत्यन्त ही लाभमय स्थिति में पहुँच गया। हरनाम कोर्टिस की इस सफलता के पश्चात् स्पेन ने अमरीका के अपरिचित मार्गों का अन्वेषण तीव्रता से आरम्भ कर दिया तथा उन्होंने केवल 65 वर्षों के अन्तराल में अल्टोरेडो, अमेजान क्षेत्र तथा अन्य मार्गों का अन्वेषण कर लिया। शनैः-शनैः स्पेनवासी मेक्सिको से उत्तर की ओर बढ़ते गये तथा उन्होंने मेक्सिको, कैलिफोर्निया तथा फ्लोरिडा का अन्वेषण कर लिया। मिसिसिपी की घाटी, बृहद् मैदानी भागों के साथ-साथ स्पेन ने अटलांटिक तथा प्रशान्त महासागर के तटों तक अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने दक्षिणी अमरीका में पनामा, पेरू, कोलम्बिया, वेनेजुएला तथा चिली तक के प्रदेशों तक अपने अन्वेषकों को प्रेषित किया। 1600 तक उनका साम्राज्य ब्राजील के अतिरिक्त कैलिफोर्निया की खाड़ी से व्यूनस आयर्स तक फैल गया। इसके पश्चात् यद्यपि उन्होंने कोई नवीन अन्वेषण तथा साम्राज्य का विकास नहीं किया तथापि इन्हीं प्रदेशों की प्राकृतिक सम्पदा का शोषण प्रारम्भ कर दिया।

अमरीकी स्पेन के विकास की भूमिका में प्रमुख योगदान देशी भारतीय जातिका था जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के विरुद्ध स्पेन की सहायता करते थे तथा कृषि के व्यवसाय के विपरीत स्पेन के लिये मजदूरी किये जाने पर मजदूर किये जा सकते थे। वहाँ पर स्पेन के निवासियों की सम्पदा के पीछे मुख्य स्रोत इन्हीं लाल भारतीयों का था। वहाँ पर जाति तथा वर्गों के आधार

पर समाज विभाजित होने लगा। स्पेन का शासन पूर्ण रूपेण सम्राट् के एकाधिकार में सीमित था। स्पेन ने वहाँ पर किसी भी प्रकार की नवीन विचार-धारा-प्रजातंत्र तथा एकता को विकसित होने का अवसर नहीं प्रदान किया। इसके विपरीत उन्होंने वहाँ पर कना, ईसाई धर्म, नवीन विज्ञान तथा विश्व-विद्यालयों की स्थापना की। उनके इस द्वन्दात्मक नीति ने वहाँ के निवासियों में एक विशेष भावना को जन्म दिया जिसने सांस्कृतिक क्षेत्र में अमरीका को विश्व का एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र बनाने में योगदान प्रदान किया।

कोलम्बस की अमरीका यात्रा के पश्चात् लगभग 100 वर्षों तक वहाँ मात्र स्पेनवासियों का ही अधिकार रहा। यद्यपि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने स्पेन के इस एकाधिकार का विरोध किया तथापि प्रारम्भ में उन्होंने वहाँ पर उपनिवेश बनाने के विपरीत स्पेन के जहाजों को लूटने, पूर्वी गोलार्ध से व्यापार तथा उत्तरी अमरीका के मार्ग से प्राचीन विश्व के मार्ग के अन्वेषण पर अधिक ध्यान दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि स्पेन ने नव विश्व के अत्यन्त प्रभावशाली प्रदेशों पर अधिकार कर रखा था। उत्तरी अमरीका में उन्हें आकर्षित करने हेतु कोई प्राकृतिक सम्पदा भी शेष नहीं थी। परन्तु 17वीं सदी तक ब्रिटेन तथा फ्रांस ने उ० अमरीका के प्रमुख भू-भाग पर अधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। हालैण्ड तथा स्वीडेन ने इसके विपरीत छोटे अभियान ही प्रेषित किये। 1609 में एक समझौते के अनुसार हालैण्ड ने अपने उपनिवेश बनाने प्रारम्भ कर दिये परन्तु 1586 में स्पेनिश आरमडा पर सफलता के पश्चात् ब्रिटेन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सामुद्रिक राष्ट्र हो गया। इसके पश्चात् ब्रिटेन को उ० अमरीका में अपने उपनिवेश बनाने से रोक्ना सम्भव नहीं रह गया था तथा उसने वहाँ पर स्पेन के साम्राज्य को चुनौती देना, प्रोटेस्टेण्ट धर्म का विस्तार करना तथा एशिया के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया। वहाँ पर अंग्रेजी उपनिवेश बनाने में प्रमुख भूमिका गिलबर्ट तथा रैले ने निभायी। यद्यपि उनको अपने अभियान में सम्पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई तथापि उन्होंने उपनिवेश निर्माण के मार्ग में एक नवीन शिलान्यास-स्थापन का कार्य किया। उनके पश्चात् 1607 में लन्दन कम्पनी ने जेम्सटाउन नामक वस्ती की स्थापना वर्जिनिया में की। ब्रिटेन के साथ ही साथ फ्रांस ने भी अमरीका में उपनिवेश निर्माण का कार्य मिसिसिपी घाटी पर अधिकार कर प्रारम्भ कर दिया। परन्तु फ्रांस के उपनिवेश निर्माण का सर्वाधिकार सम्राट् के पास सुरक्षित था। 1609 में हालैण्ड ने न्यू नेदरलैण्ड में अपना उपनिवेश स्थापित किया। 1664 में आंग्ल-डच सन्धिके पश्चात्

न्यू नेदरलैण्ड पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया तथा उसका नामकरण न्युयार्क के रूप में कर दिया गया। इन उपनिवेशों के निर्माण में धार्मिक मान्यताओं का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित हुआ। ब्रिटेन प्रोटेस्टैंट धर्म, फ्रांस कैथोलिक तथा हालैण्ड धर्म-निरपेक्षता का समर्थक था। यही कारण था कि हडसन नदी के पास के हालैण्ड अधिकृत क्षेत्र में विभिन्न जातियों के लोगों का अधिकार स्थापित हो गया था। चार्ल्स प्रथम के अपनयन के पश्चात् इसके विभिन्न अनुयायी तथा सहयोगी भी वर्जिनिया में निर्वासित हो गये। इसी प्रकार 1660 में ब्रिटेन में द्वितीय राजनैतिक परिवर्तन ने न्यू इंगलैण्ड में उपनिवेश की जनसंख्या बर्धन में सहयोग प्रदान किया। चार्ल्स द्वितीय के काल में ब्रिटेन की उपनिवेशी प्रवृत्ति अधिक प्रखर हो गई तथा उसने 1732 में जार्जिया पर अधिकार की घोषणा कर दी जो ब्रिटेन का अन्तिम तेरहवाँ उपनिवेश था।

स्पेन के धन एकाधिकार, तथा फ्रांस के फर व्यापार के विपरीत ब्रिटेन ने कृषि-व्यवसाय में अधिक रुचि प्रदर्शित की। भूमि के उपजाऊ होने के कारण शनैः-शनैः ब्रिटेन की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होती गयी। तम्बाकू तथा चावल की खेती ने ब्रिटेन को अत्यधिक लाभान्वित किया। भौगोलिक विभिन्नता के साथ-साथ आर्थिक कारणों ने भी उपनिवेशों की स्थापना को अत्यन्त प्रभावित किया। इन उपनिवेशों के विकास के लिये पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता थी जिससे कि उन्हें तत्काल ही लाभ प्राप्त हो सके। अतएव यह आवश्यक था कि वहाँ पर यूरोप की आवश्यकतानुसार कृषि की जाये परन्तु यूरोप को अभी केवल मसालों, चीनी तथा उन वस्तुओं की ही आवश्यकता थी जो पूर्वी द्वीप समूह तथा पश्चिमी द्वीप समूह में उपलब्ध थे। यही कारण था कि प्रारम्भिक औपनिवेशिक स्थापनाएँ उ० अमरीका के विपरीत इन द्वीप समूहों पर अधिक हुये। प्रारम्भ में उ० अमरीका फर के व्यापार के लिये अधिक उपयुक्त था। यूरोप में इसके व्यापार को लाभदायक बाजार भी उपलब्ध था। परन्तु धीरे-धीरे फर के जानवरों का अभाव होने के कारण उनका ध्यान अन्य व्यवसायों की दिशा में आकर्षित होने लगा। उ० अमरीका का क्षेत्र ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य संघर्षों का युद्ध क्षेत्र बना। एक बार उपनिवेशों की स्थापना के पश्चात् उन पर प्रतिरोध लगाना असम्भव हो चुका था।

ब्रिटेन तथा फ्रांस दोनों ने उ० अमरीका के एक वृहद् भूभाग पर एकाधिकार की घोषणा की तथा अवैधानिक रूप से यहाँ की समस्त भूमि सम्राट् की भूमि मान ली गई। उ० अमरीका की भूमि को प्रदत्त करने का अधिकार सम्राट् को था। वह किसी भी वाणिज्यिक संस्था अथवा किसी व्यक्तिगत धनिक को भूमि प्रदान कर सकता था। प्रायोगिक रूप में यह अधिनियम वास्तव में

प्रभावशाली नहीं था। यह निश्चय था कि एक बार उपनिवेशों पर अधिकार हो जाने के पश्चात् उन पर प्रतिबन्ध लगाना असम्भव हो जायेगा क्योंकि अमरीका में अभी पर्याप्त भूमि उपलब्ध थी तथा वे अधिकारों की सम्भावना के विपरीत भी उधर बढ़ सकते थे। एक बार जिस व्यक्ति ने एक उपजाऊ भूमि की खोज स्वयं की हो वह उसको किसी दूसरे को प्रदान करने के पक्ष में सहमत नहीं होता है। यही कारण था कि लगभग 150 वर्षों तक वहाँ के अधिकार तथा वैधानिक अधिकारों के मध्य संघर्ष चलता रहा।

परन्तु जब एक वर्ग ने वहाँ पर उपनिवेश बनाने की आज्ञा प्राप्त कर ली तो उसे भूमि पर अधिकारों के साथ-साथ शासन की शक्ति भी मिल गयी। यह राजनैतिक शक्ति उन लोगों के हाथों में केन्द्रित थी जिन्होंने उपनिवेशों की स्थापना में पूंजी लगायी थी। यह सभी व्यक्ति यूरोपवासी थे। ये व्यक्ति अपना राज्यपाल तथा अन्य अधिकारी नियुक्त कर अमरीका भेजे देते थे जो वहाँ शासन करता था। फ्रांसीसी तथा हालैण्ड के निवासियों ने यह व्यवस्था पूर्णरूपेण स्वीकार कर ली परन्तु ब्रिटिश उपनिवेशों ने इस व्यवस्था के विरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाया। वास्तव में 17 वीं सदी तक ब्रिटेन में स्वतंत्रता के अधिकारों का अनुभव वहाँ के निवासियों को हो चुका था। अपनी उस स्वतंत्रता को वह अमरीका जाकर भी परतंत्रता में परिणत नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यह कहा कि वे वहाँ भी "जन सामान्य अधिनियम" के अन्तर्गत ही रहेंगे तथा उनपर शासन करने का अधिकार एक निर्वाचित विधानमंडल के पास होना चाहिये। उपनिवेशों के संगठनकर्ताओं को यह स्पष्ट हो चुका था कि वहाँ पर निर्वासित लोगों के ऊपर तब तक शासन नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें वहीं वैधानिक एवं राजनैतिक अधिकार नहीं प्रदान कर दिये जाते जो ब्रिटिश जनता को ब्रिटेन में प्राप्त थे।

हालैण्ड तथा स्विस् की जनता जनसंख्या तथा पूंजी की विरलता के कारण अमरीका में अधिक विस्तार नहीं प्राप्त कर सकती थी। स्पेन को प्रारम्भ से ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त था अतएव तत्कालीन ब्रिटेन तथा फ्रांसही दो ऐसे राष्ट्र शेष थे जो 30 अमरीका पर अधिकार के लिये उत्सुक थे। इसी कारण बार-बार उनके मध्य भूमि पर अधिकारों के प्रश्न पर हिंसात्मक संघर्ष भी हो जाया करते थे। फ्रांसीसियों ने सेन्ट लारेंस में उपनिवेश स्थापित करके अमरीका के मध्य तक का मार्ग सुगम कर लिया। इस क्षेत्र पर अधिकार के कारण उन्हें सैन्य लाभ भी प्राप्त हुये। इसके विपरीत ब्रिटिश उपनिवेश 18वीं सदी तक पश्चिम के पर्वत शिखरों का अतिक्रमण नहीं कर सके थे परन्तु अन्त में इन्होंने ही वहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव प्राप्त किया। इसका

मुख्य कारण यह था कि जहाँ फ्रांसिसी मुख्यतया कृषि पर आधारित होने के कारण सुदूर प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त करने के विपरीत अपने व्यवसाय में लगे रहना अधिक उचित समझते थे, ब्रिटिश उपनिवेशी सुदूर प्रदेशों के अन्वेषण हेतु बाध्य थे। ब्रिटेन में जनसंख्या तीव्रता से वृद्धि को प्राप्त कर रही थी। वहाँ के आर्थिक रूपान्तरण ने एक वृहद् वर्ग को आर्थिक रूप से इतना निर्बल कर दिया था कि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं से भी वंचित हो गये थे। उनके पास ब्रिटेन में अन्य कोई आशा शेष नहीं रह गई थी गरीबी एवं वर्ग संघर्ष से सुरक्षा हेतु उन्हें अमरीका के इस नवीन दुनिया में प्रवेश करना आवश्यक हो चुका था। इसके विपरीत फ्रांस का सामान्य कृषक अपनी आवश्यकताओं एवं भविष्यके विषय में आश्वस्त थे तथा उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ भी सुरक्षित थीं। फ्रांसके नगरों की जनसंख्या भी ब्रिटेनके समान अधिक नहीं थी। इन कारणों से फ्रांस की अपेक्षा ब्रिटेन से प्रवासी अधिक संख्या में अमरीका आये और उन्होंने अमरीका में आकर अपने प्रभावों तथा अधिकारों को वृद्धित करना प्रारम्भ कर दिया।⁹

उ० अमरीका के उपनिवेशीकरण के पूर्व 16 वीं सदी में वहाँ के स्थानीय निवासियों (लाल भारतीय) की संख्या 1,00,000 से भी कम थी। ये आदिवासी विभिन्न कबीलों, जनजातियों, उपजातियों, संस्कृतियों, भाषाओं, संस्कारों तथा प्रथाओं में विभाजित थे। यद्यपि मेक्सिको में माया तथा ऐजटेक एवं पेरू में इन्का जातियों की सभ्यता विकसित हो रही थी परन्तु अन्य जातियाँ अभी भी विकास के प्राथमिक स्तर पर ही थीं। पूर्वी अमरीका में विस्तृत जनजातियाँ शिकार तथा कृषि पर आधारित थी। उनकी शासन व्यवस्था पर्याप्त प्रजातांत्रिक थी। उनका नायक केवल युद्ध में नायक था। अन्यथा अन्य निर्णयों के अवसर पर कबीले की जनसभा निर्णय लेती थी। कबीलों का सम्पत्ति पर एकाधिकार था तथा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे शिकार तथा खेती भी कबीले की ही सम्पत्ति थी। उनके स्त्री पुरुषों का कार्य विभाजन भी पर्याप्त प्रायोगिक तथा विवेकपूर्ण था। स्त्री अपनी प्राकृतिक शक्ति के अनुरूप कृषि का कार्य करती थी जबकि प्रदत्त शक्ति का स्वामी पुरुष शिकार तथा युद्ध में हिस्सा लेता था। वहाँ की स्थानीय सभ्यता ने प्राचीन विश्व को महत्वपूर्ण उपहार प्रदान किया। विभिन्न नवीन अनाजों, फलों, औषधियों, पौधों तथा तम्बाकू आदि का ज्ञान वहाँ की कबीली सभ्यता द्वारा उपनिवेशियों को स्थानान्तरित हुये

वहाँ पर उपनिवेशी विकास ने मँद्री तथा मतभेदों का आश्चर्यजनक संश्लेषण प्रस्तुत किया। वहाँ के कबीले में प्रचलित शिकार तथा अन्य दैनिक

आवश्यकताओं के लिये वन एक प्रमुख आवश्यकता थी। इसी के साथ-साथ उन्हें सामूहिक सम्पत्ति के विपरीत व्यक्तिगत सम्पत्ति का ज्ञान भी नहीं था। इस प्रकार उन श्वेत अधिवासियों को इन आदिवासी कबीलों का सहयोग प्राप्त हुआ जिन्होंने फर व्यापार तथा उसके लिये शिकार को प्रमुखता दी। ऐसे लोगों को इन आदिवासियों ने सहायता प्रदान की परन्तु जिन्होंने कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाया तथा इसके लिये जंगलों को कटवाना प्रारम्भ कर दिया था, उन लोगों ने इन कबीलों की आवश्यकताओं तथा भावनाओं दोनों को ठेस पहुँचायी। अतएव इन्हें इनके सहयोग के विपरीत मतभेदों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ इन उपनिवेशियों में व्याप्त व्यक्तिगत पूँजी व्यवस्था तथा स्थानीय आदिवासियों की सामूहिक व्यवस्था के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इन मतभेदों की परिणति अन्त में एक हिंसात्मक संघर्ष में हुई। इन दो विभिन्न व्यवस्थाओं का एक साथ रहना यद्यपि असम्भव नहीं था, परन्तु प्रारम्भ में बुद्धिहीनता ने एक ऐसे हिंसात्मक संघर्ष का रूप ले लिया जो लगभग 300 वर्षों तक चलता रहा। आदिवासियों की सहायता प्राप्त करने के विपरीत इन श्वेतों ने यहाँ तक कहना प्रारम्भ कर दिया था कि मृतक आदिवासी ही वास्तव में एक अच्छा आदिवासी हैं। उन्होंने इन आदिवासियों का हिंसात्मक दमन प्रारम्भ कर दिया तथा अंत में केवल उनकी जनसंख्या का 1/5 भाग ही शेष बच पायी। अर्थात् लगभग 8,00,000 आदिवासी 300 वर्षों में मार दिये गये। उनकी इस दमनकारी प्रवृत्ति में उनके द्वारा आयातित बीमारियों तथा मंछ ने भी प्रभावशील भूमिका निभाई।

यूरोपीय सभ्यता के अंग होते हुये भी अमरीका के निवासी न तो पूर्णतया यूरोपीय थे और न ही वे कोई विशेष जाति अथवा देश के रह गये थे। ब्रिटेन के निवासी होते हुये भी उन्होंने विभिन्न परम्पराओं को त्यागकर नवीन परम्पराओं को स्वीकार कर लिया था। 1607 से 1763 के मध्य वे विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों से भिन्न हो चुके थे। 1700 के पूर्व ही वे अमरीकी कहे जाने लगे थे। ब्रिटेन से पर्याप्त दूर होने के कारण उन्हें अपने साधनों पर ही आश्रित रहना पड़ता था। ब्रिटेन की कम्पनियों तथा उनके मालिकों ने उपनिवेशों को आर्थिक स्रोत बना लिया था। इस नवीन भूमि पर निवास तथा अधिवास के लिये विभिन्न नवीन प्रयासों की आवश्यकता थी जो उन्हें आकर्षित कर सके। उन्होंने कठिवादी परम्पराओं के विपरीत धार्मिक सहिष्णुता तथा भूमि अनुदानों का प्रचार किया। वहाँ पर कार्य करने की अवधि चार से सात वर्षों तक की थी। इस अधिनियम के अंतर्गत वे लोग आते थे जिनका व्यय भी स्वयं कम्पनी वहन करती थी। निर्धारित काल के पश्चात् वे दास

मुक्त भी हो सकते थे। वहाँ पर रहने वालों में सजा प्राप्त अपराधी तथा युद्ध बन्दी भी होते थे। ये प्रमुखतः वर्जीनिया तथा मेरीलैण्ड में आये। इसके पश्चात् इनका स्थान नीग्रो लोगों ने ले लिया था।

सर्व प्रथम नीग्रो दास 1619 में अमरीका आये। यह उपनिवेशियों के लिये अधिक उपयुक्त थे। इनका सेवा काल निर्धारित न होकर आजीवन था। इनकी कार्य क्षमता भी अपेक्षाकृत अधिक थी। इनके भाग जाने पर पहचाने न जाने की समस्या भी नहीं थी। 1967 में “रायल अफ्रीकन कम्पनी” के एकाधिकार के पश्चात् इन दासों का व्यापार उपनिवेशों तथा ब्रिटेन में होने लगा था। गोरे तथा काले लोगों के अतिरिक्त वहाँ के स्थानीय आदिवासियों पर भी नियंत्रण का प्रयास प्रारम्भ हुआ परन्तु उनपर नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक दुर्गम था। अतएव नीग्रो लोगों के आयात पर ही अधिक ध्यान दिया गया। परिणाम स्वरूप नीग्रो लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके साथ ही साथ 17वीं तथा 18वीं सदी में अमरीका की जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। ब्रिटेन ने तकनीकी लोगों के प्रवास पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। अतएव अन्य देशों से विभिन्न जातियों के लोगों का अमरीका में स्वागत किया गया। देश जाति एवं धर्म की दीवार स्वयमेव खण्डित होने लगी। उनमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हुये। इस प्रकार अमरीका में एक मिश्रित जाति का आविष्कार हुआ। ब्रिटेन के अतिरिक्त वहाँ पर स्काटलैण्ड, जर्मनी, स्विटजरलैण्ड तथा आयरलैण्ड के निवासी अधिक थे। कुछ ही वर्षों में जनसंख्या दसगुनी हो गयी। इन प्रवासियों में नगरों की अपेक्षा गाँवों में बसने की उत्सुकता अधिक थी। अतएव 18वीं सदी तक गाँवों की जनसंख्या अधिक रही।

17वीं सदी में ब्रिटिश अप्रवासियों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई। इस वृद्धि का कारण मुख्यतया स्टुअर्ट सम्राटों से राजनैतिक तथा धार्मिक मतभेद था। 1642 के गृह युद्ध तक लगभग 65,000 प्रावासी अमरीका पहुँच चुके थे। इनमें से लगभग आधे मुख्य भूमि पर तथा शेष पश्चिमी द्वीप पर बस गये। 1607 में इन्होंने जेम्सटाउन के नाम से वर्जीनिया की स्थापना की। रैले की योजना को एक वाणिज्यिक कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया था। इन्हें जेम्स प्रथम से इसके प्रति अधिकार भी प्राप्त हो चुका था। इन उपनिवेशवासियों में मुख्य व्यापारी तथा अभिजातवर्गीय व्यक्ति थे। उन्हें वर्जीनिया के उत्पादन से प्रमुख लाभ प्राप्त होता था। इस प्रथम उपनिवेश का इतिहास केवल सफलता का इतिहास नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्हें अकालों, बीमारियों तथा मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। आदिवासियों से संघर्ष तथा उपर्युक्त कारणों से प्रारम्भिक अभियान लगभग पूर्णतया असफल सिद्ध हुये

तथा उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त हुआ। फलस्वरूप ब्रिटेन के व्यापारियों ने वर्जीनिया के स्थान पर पश्चिमी द्वीप समूह पर अपना ध्यान केन्द्रित करना प्रारम्भ कर दिया। यह केवल उपनिवेशियों के सफल प्रशासन का ही परिणाम था कि वहाँ पर उपनिवेशों की रक्षा हो सकी। ब्रिटेन में धूम्रपान के आधुनिक व्यसन तथा जान रोलफ के द्वारा वर्जीनिया के तम्बाकू के शोधन के कारण वर्जीनिया का भविष्य लगभग सुरक्षित हो गया। आप्रवासियों को उत्साहित करने के ध्येयसे उन्हें भूमि पर अधिकार तथा शासन में योगदान का अधिकार प्रदान कर दिया गया। प्रतिनिधि सभा की स्थापना के पश्चात् भी आप्रवासियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि प्रारम्भ हो गई। स्मिथ के शासन को प्रतिस्थापित करने वाले सर सैण्टी के विरुद्ध भी कम्पनी में मतैक्य हो जाने के पश्चात् 1624 में सम्राट् ने उपनिवेशों को अपने अधिकार में ले लिया। उसके पश्चात् अमरीकी क्रान्ति तक वर्जीनिया में ब्रिटिश राज्यपाल ही नियुक्त होता रहा। 1632 में कैल्वर्ट ने वर्जीनिया की ही भाँति मेरीलैण्ड पर अधिकार करने का अधिकार-पत्र सम्राट् चार्ल्स से प्राप्त कर लिया था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाकर आप्रवास की प्रवृत्ति को तदनुसार बनाये रखा। यहाँ पर भी तम्बाकू के व्यापार के कारण उपनिवेश के विकास की निरन्तरता बनी रही। 1635 में एक विधानपालिका की स्थापना से स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो गई। मेरीलैण्ड धार्मिक मतभेदों तथा आन्तरिक समस्याओं के कारण 1691 में शासनान्तर्गत कर लिया गया। 1715 में वाल्टीमोर ने पुनः आनुवंशिक अधिकार प्राप्त कर लिया तथा अमरीकी सामन्तवादी अधिकारों का उपयोग करता रहा।

वर्जीनिया तथा मेरीलैण्ड की प्रमुख विशेषता उनकी ग्रामीण व्यवस्था में निहित थी। तम्बाकू का उत्पादन वहाँ की प्रमुख निधि थी। वहाँ से तम्बाकू ब्रिटेन भेजा जाता था जहाँ से वह पुनः परिवर्धित होकर वापस अमरीका जाता था। प्रमुख औद्योगिक आवासों का जलमार्गों के निकट स्थापित होने के कारण, यातायात की समस्या नहीं होती थी। वहाँ पर कोई बड़े नगर नहीं थे और न ही कोई उत्पादन होता था। यद्यपि वे स्व-उत्पादन तथा फर के व्यापार पर निर्भर थे। उनका जीवन यापन स्थानीय उत्पादन पर आधारित था। इन खनिज पदार्थों के उत्पादक सदैव हानि उठाते थे। जैसे-जैसे तम्बाकू की पैदावार बढ़ती गई, व्यापारियों की तुलना में इनकी स्थिति गिरती गई क्योंकि तम्बाकू का मूल्य-स्खलन होता गया तथा वे ऋणों के बोझ से लदते गये। वर्जीनिया तथा मेरीलैण्ड में प्रमुख जनसंख्या श्वेत कृषकों अथवा श्वेत दासों की थी। ये दास ब्रिटेन से इस शर्त पर आते थे कि उन्हें चार वर्षों के पश्चात्

स्वतन्त्र कर दिया जायेगा। शनैः-शनैः बहुत से इन दासों ने भी धन-सम्पदा एकत्रित कर सामाजिक तथा राजनैतिक सम्मान प्राप्त कर लिया। उदाहरणार्थ 1663 में वर्जीनिया सदन के 30 सदस्य अपने प्रारम्भिक जीवन में दास थे। तदनन्तर तम्बाकू के उत्पादकों ने अधिक लाभ की सम्भावनाओं के कारण नीग्रो व्यापार को प्रोत्साहन देना प्रारम्भ कर दिया। सर्वप्रथम 1619 में अफ्रीकी नीग्रो दासों से भरा जलयान वर्जीनिया पहुँचा। प्रारम्भ में नीग्रो के लिए कोई अन्य अधिनियम न उपलब्ध होने से उन्हें भी श्वेत दासों का स्तर प्राप्त था। यद्यपि प्रारम्भ से ही एक रंगमूलक भावनात्मक विभाजन उत्पन्न हो गया था। 17वीं शताब्दी के अंत तक नीग्रो जाति ने दासों का स्थान ले लिया। अमरीकी भू-कृषक तथा ब्रिटिश नीग्रो व्यापारियों ने बिना किसी दूरदर्शी दुष्परिणाम की चिन्ता के यह व्यापार जारी रखा। इसी मध्य एक छापक अभिजात वर्ग का उत्थान भी अमरीकी समाज में शनैः-शनैः होने लगा था। तम्बाकू की खेती से गिरती भूमिकी उत्पादन क्षमता तथा तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट के कारण लघु किसानों के लिये भूमि का स्वामित्व कठिन होता जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप बड़े भूमिधरों के जीवन स्तर, अधिकार तथा शोषण की सीमाएँ बढ़ती गईं। इन भूमिधरों ने समाज का नेतृत्व अपने हाथों में लेना प्रारम्भ कर दिया तथा अन्त में शासकवर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगे। ये उपनिवेश "काउन्टी" नामक उपभागों में विभाजित थे एवं ये पुनः "परिवेश" में बटे थे। ब्रिटेन की ही भाँति यहाँ भी प्रमुख नागरिकों में न्यायाधीश होता था जिसे असीमित प्रशासनिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे। इन्हीं व्यक्तियों का बहुधा विधानपालिका के लिये भी चुनाव होता था जिसमें मत का अधिकार धन द्वारा सीमित था। इस वर्ग को पुनः आर्थिक सुविधा प्राप्त करने का अधिकार इन राजनैतिक विकासों से प्राप्त होता गया निम्न वर्ग अथवा लघु कृषकों ने इन अन्य वर्गों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया यद्यपि समय-समय पर ये अपने अधिकारों के हनन के अवसर पर निवन्धित हो जाते थे। 1676 में एफ वेकन ने निम्न वर्ग की सुरक्षा के लिये शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह शासन द्वारा निवासियों के विरुद्ध आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के कारण किया गया था। वेकन के मृत्युपरान्त इस विद्रोह का पूर्णतया दमन कर दिया गया।

प्रारम्भ में उपनिवेशीकरण के प्रति अधिक उत्साह नहीं दिखायी पड़ रहा था। यद्यपि वर्जीनिया में उपनिवेश निर्माण का संघर्ष चल रहा था परन्तु फिर भी अभी नागरिकों में यही मान्यता प्रचलित थी कि केवल फर के व्यापार से पर्याप्त लाभ संभव नहीं क्योंकि उन्हें वहाँ किसी अन्य उपज की

आशा नहीं थी। अतएव वहाँ के लोग मत्स्य पालन पर ही पूर्णतया आश्रित थे। न्यू इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम कृषि का प्रचार मे-फ्लावरतीर्थ यात्रियों ने की। ब्रिटेन से निष्काषित इन पृथक्तावादियों ने 1620 में फ्लावर जलपोत के द्वारा वर्जीनिया के लिये प्रस्थान कर दिया परन्तु दिशा भ्रम के कारण वर्जीनिया के स्थान पर ये सब प्लाइमाउथ पहुँच गये। वहाँ पर वैधानिक शासन की अनुपस्थिति में इन्होंने स्वयं बहुमत पर आधारित शासन की स्थापना कर दी। नगर के निवासी होने के कारण ये वहाँ पर स्थापित कृषि, शिकार तथा मछली मारने की कला से अनभिज्ञ थे तथा सम्भवतया मृत्यु के ग्रास बन गये होते यदि वहाँ के देशी निवासियों ने इनकी सहायता न की होती। उन्होंने इन्हें कृषि करना, शिकार करना तथा मछली मारना सिखाया। प्लाइमाउथ के उपनिवेशियों में सबसे विशेष बात उनकी अनुशासनप्रियता थी। इस अनुशासन के लिये प्रमुख श्रेय विलियम ब्रेडफोर्ड को था जिसने अत्यन्त कुशलता से यहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। उसकी धार्मिक त्याग की भावना के अनुरूप उन्होंने कार्य किया तथा वहाँ पर शनैः-शनैः प्रतिनिधि शासन स्थापित होने लगा।

मैसाचुसेट्स के उपनिवेश की स्थापना “पृथक्तावादियों के विपरीत” “अतिनैतिकतावादियों” (प्यूरिटन) ने की। यद्यपि ये ब्रिटिश चर्च के साथ संलग्नही रहने के इच्छुक थे परन्तु स्टुअर्ट सम्राटों के कारण इनका और इनके अनुयायियों का भी ब्रिटेन में रहना दुष्कर होता जा रहा था। अतएव “प्यूरिटन वासियों” के एक समूह ने जान विन्श्राप के नेतृत्व में किसी प्रकार सम्राट् से “मैसाचुसेट्स खाड़ी कम्पनी” निर्मित करने का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। यद्यपि यह अभी तक रहस्य ही है कि किस प्रकार सम्राट् ने इन प्यूरिटन वासियों को आज्ञापत्र प्रदान कर दिया, जबकि वे उनके राजनैतिक विरोधी थे। इन्होंने बोस्टन में अपने उपनिवेश की स्थापना की। ये सभी मध्यम वर्ग के कृषक थे तथा केवल आर्थिक अभाव के कारण ही उन्होंने स्वदेश त्यागना स्वीकार किया था। वहाँ पर कृषि, शिकार, मछली तथा फर के व्यापार से इन्हें इतना लाभ होने लगा था कि ये वहाँ की सर्दी (शीत) भूलकर अपने जीवन स्तर के बढ़ते कदम की स्वयं सराहना करने लगे थे। इस उपनिवेश की विशेषता थी कि वहाँ के संगठनकर्ता ब्रिटेन नहीं बोस्टन में थे तथा शेष सभी भागीदारों ने अपने भाग भी अमरीका जाने वालों को बेच दिये थे। अतः इन लोगों पर ब्रिटेन का किसी भी प्रकार का शासन शेष नहीं रह गया था। ये अपने आप में पूर्णरूपेण वैधानिक रूप से भी स्वतंत्र हो गये थे तथा दीर्घ काल तक इन पर ब्रिटेन का शासन भी नहीं रह गया था। यद्यपि

यहाँ के निवासी भी आर्थिक सफलता के स्वप्नों के साथ अमरीका आये थे परन्तु इन्होंने लाभ के ऊपर आदेशों को प्रमुखता प्रदान की। वहाँ पर प्रजातांत्रिक शासन के ऊपर चर्च के राजनैतिक अधिकार को प्रमुखता प्रदान की गयी। प्यूरिटनवासी केवल अपने धर्म के अनुयायियों को मान्यता प्रदान करते थे। शनैः-शनैः 1630 के पश्चात् वहाँ के निवासियों को अधिनियम बनाने एवं सामान्य न्याय व्यवस्था की सुविधा भी प्राप्त होने लगी तथापि यह सुविधा भी पूरी जनसंख्या के केवल एक छोटे से हिस्से को ही प्राप्त हो सकी थी क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ भी आड़े आने लगी थी।

इनके अतिरिक्त बहुत से क्षेत्रों पर आप्रवासियों ने उपनिवेश की स्थापना की। थामस हूकर ने कनेक्टीकट तथा डेवेनपोर्ट में न्युहावेन उपनिवेशों को निर्मित किया। 1662 में ये दोनों उपनिवेश मिलकर एक हो गये। ये दोनों उपनिवेश मैसाचुसेट्स के निकट स्थापित किये गये। धार्मिक मतभेदों के आधार पर 1630 में मैसाचूसेट्स से कुछ नागरिक निष्कासित कर दिये गये। इन्होंने रोड द्वीप पर शरण लिया तथा उसे प्रवासित किया। इन निष्कासितों को रोजर विलियम ने नेतृत्व प्रदान किया था तथा इन्होंने रोड द्वीप पर एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना कर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी।

ये नवीन उपनिवेश निश्चित हो चेसापीक के उपनिवेशों से भिन्न थे। यह भिन्नता उनके आदर्शों के साथ-साथ उनके आवास तथा प्रसार के तरीके में भी परिलक्षित थी। यद्यपि प्यूरिटनवादी राजनैतिक समानता में विश्वास नहीं करते थे तथापि उन्होंने आर्थिक समानता की संस्थाएँ स्थापित कीं। इस प्रकार दक्षिण की अपेक्षा नव ब्रिटेन अधिक लोकतांत्रिक हो गया था। ये अपेक्षाकृत कम व्यक्तिवादी थे तथा इनमें मध्ययुगीन ग्रामीण समाज की समूहात्मक भावना उपस्थित थी। भूमि का वितरण व्यक्ति की अपेक्षा वस्ती के आधार पर किया गया। नागरिकों का एक समूह वस्ती स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर सकता था। तत्पश्चात् अनधिकृत भूमि पर अधिकार करने के पश्चात् उसे छोटे-छोटे खेतों में बांट दिया जाता था। शेष भूमि भविष्य के लिये सुरक्षित रखी जाती थी। इस प्रकार समूह का प्रत्येक सदस्य भूमि का स्वतंत्र स्वामी होता था उसे किसी भी प्रकार का किराया अथवा भूमि कर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। स्थानीय शासन की व्यवस्था, वस्ती में रखी गई थी। यद्यपि भूमि का वितरण समान नहीं था, तथापि वर्गों का निर्माण नहीं हुआ था। इसके साथ ही साथ एक सामूहिक आय व्यवस्था के आधार पर भूमि क्षेत्र के चारों ओर निवास निर्मित करने के कारण उनमें समूह की भावना सदैव बनी रही। यही कारण था कि सागर तटों के अतिरिक्त नवीन ब्रिटेन

छोटे-छोटे कृषकों का देश बन गया। वहाँ कोई आधारभूत नकदी फसलों की पैदावार नहीं थी न ही कोई बड़े जागीर थे और न ही कोई दासों का वर्ग था। यद्यपि चर्च के सदस्यों को विशिष्ट वर्ग के सदस्य होने का श्रेय प्राप्त था और उन्हें राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त थे परन्तु ये अधिकार सुविधा नहीं प्रदान करते थे। इस प्रकार भूमितंत्र एवं वस्ती के स्थानीय शासन में लोकतंत्र की नींव स्थापित हुई।

इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति प्रारम्भ की। सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय के रूप में नव ब्रिटेन ने मछली मारने को अपनाया। जल-पोत निर्माणकी दिशा में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाये। शीघ्र ही मैसाचुसेट्स का वाणिज्य विश्व स्तर तक रुचिकर विषय बन गया। उन्होंने काड मछली, इमारती लकड़ी तथा खाद्य वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी द्वीप समूह के लिये करना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि यूरोप में विक्रय हेतु नव ब्रिटेन में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता था अतः वे यूरोप के तैयार माल को क्रय करने से भी असमर्थ थे जिसके फलस्वरूप उन्होंने स्वयं ही तैयार मालों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया और वहाँ स्थानीय उद्योग धन्धे पनपने लगे। अधिकतर परिवार अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुयें स्वयं ही तैयार कर लेते थे। वे केवल कुछ खनिज पदार्थ, कच्चा माल तथा विलासकी वस्तुएँ क्रय करते थे। अतः कृषक परिवार स्वयं ही अपना घर बनाते थे तथा घर के फर्नीचर भी स्वयं बनाते थे। वस्त्र आदि घर की महिलायें तैयार करती थी परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक तकनीशियन भी थे जो विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे बुनाई, सिलाई, जूते बनाने, बर्तन बनाने, फर्नीचर बनाने तथा धातु का भी कार्य किया करते थे।

17वीं सदी में प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास करता था कि बिना धर्म के सामाजिक स्थायित्व सम्भव नहीं है तथा धर्म एवं नैतिकता के नियमों के पालन हेतु अधिनियमों की भी सहायता लेना आवश्यक है। इन विश्वासों को वर्जीनिया तथा प्रारम्भिक नव ब्रिटेन दोनों स्थानों पर पर्याप्त मान्यता प्राप्त थी। वर्जीनिया में शासकीय धर्म में पर्याप्त प्रभाव नहीं था। पुजारी वर्ग नैतिक रूप से पतित था। इसके साथ ही साथ सरकारी नीतियों तथा कानून का पालन करवाना भी उतना सुगम नहीं था क्योंकि जनसंख्या अधिक थी। यद्यपि नव ब्रिटेन में प्यूरिटनवाद का प्रभाव था परन्तु यह कैल्विनवाद था जिसने आम अमरीकी सभ्यता को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। इनके अनुसार "शाझेदारी" का सिद्धान्त ही सामाजिक विघटन का प्रतिरोध था। उनका विश्वास था ईश्वर उन सभी को दिशा एवं सुरक्षा प्रदान करेगा जो उसकी

इच्छाओं का पालन करेंगे। इस प्रकार की साझेदारी समाज के प्रत्येक वर्ग में दर्शनीय होने लगी। पुरुष-स्त्री तथा राज्य एवं जनता के मध्य यही साझेदारी एक राजनैतिक समाधान का आधार बनाती गयी। यही कारण था कि अमरीका का वर्तमान राजनैतिक सिद्धान्त भी इसी प्रकार के विचारों से परिपूर्ण है। इसके अनुसार अथक परिश्रम को धार्मिक कर्तव्य का स्तर प्राप्त था। राजनैतिकता कानूनी रूप से प्रतिबन्धित थी। इस प्रकार के धार्मिक नियमों को जनमानस का समर्थन प्राप्त था। तत्कालीन प्यूरिटनवादी उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों की अपेक्षा अधिक नरम थे। यद्यपि उन्होंने नशे के प्रयोग तथा पर-वैवाहिक यौन सम्बन्धों को अनैतिक कार्य बताया था फिर भी वे स्वयं उसके स्वस्थ प्रयोग के विरुद्ध नहीं थे। वास्तव में उनका धर्म व्यवहार की अपेक्षा अनुशासन को प्राथमिकता प्रदान करता था। उनका विश्वास था कि केवल ईश्वर ही प्रेम किये जाने योग्य एक शक्ति है अतएव मनुष्य के प्रति अत्यधिक प्रेम तथा स्नेह अनुपयोगी है। इस प्रकार उन्होंने मानव-संबंधों के मध्य दरार उत्पन्न करने का शिलान्यास किया। प्यूरिटनवासियों ने शिक्षा के प्रसार पर अत्यधिक जोर दिया। उनके अनुसार बाइबिल का अध्ययन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए अतएव उनका शिक्षित होना अपेक्षित था। प्रत्येक वस्ती में विद्यालय का होना वैधानिक था। इसी आधार पर 1636 में हार्वर्ड विद्यालय की स्थापना की गयी थी। 1639 में सर्वप्रथम बोस्टन में प्रेस की स्थापना की गयी। यद्यपि इन सबका प्रमुख ध्येय धार्मिक लक्ष्य की ही प्राप्ति थी परन्तु उनमें से कुछ विज्ञान तथा इतिहास को भी प्राथमिकता प्रदान करते थे। कुछ नव ब्रिटिशों ने मानवता के सिद्धान्तों को भी प्रतिपादित किया सम्भवतया प्यूरिटनवादियों ने सर्वाधिक योगदान आर्थिक क्षेत्र में किया। उन्होंने अथक परिश्रम तथा अनुशासन को प्राथमिकता प्रदान कर अमरीका को आर्थिक रूप से एक सफल राष्ट्र बनाने में सहयोग प्रदान किया। उन्होंने अपने व्यवसाय में लगन, निष्ठा तथा सफलता को ही ईश्वर की आराधना बताया। आर्थिक रूप से सम्पन्न होना ही वास्तविक दैनिक कृपा थी। इन सिद्धान्तों के प्रचार तथा प्रसार से ही नव ब्रिटेन के उपनिवेशों ने सम्पन्नता के क्षेत्र में पदापर्ण किया। अन्ततोगत्वा यही शक्ति वर्तमान अमरीकी समाज की रचना में सहायक सिद्ध हुई।

1642 के ब्रिटिश गृह युद्ध के कारण आप्रवास पर प्रतिबंध लग गया। कुछ समय के लिये अमरीकी उपनिवेशों को स्वयं के स्रोतों पर ही आश्रित होकर रहना पड़ा। इसके साथ ही साथ ये उपनिवेश राजनैतिक रूप से लगभग स्वतंत्र हो गये। परन्तु 1649 में सम्राट् चार्ल्स प्रथम का मृत्युदंड प्राप्त होने के

पश्चात् होने के पश्चात् ब्रिटिश शासन पर सदन का अधिकार हो गया जो मुख्यतः प्यूरिटनवादियों द्वारा अधिकृत था। क्रामवेल के नेतृत्व में इस दल ने उपनिवेश में अधिक हस्तक्षेप नहीं किया परन्तु 1660 के पुनर्स्थापन के पश्चात् चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल ने उपनिवेशों के विकास में पुनः योगदान देना प्रारम्भ कर दिया। सर्वप्रथम चार्ल्स द्वितीय ने 1663 में वर्जीनिया के दक्षिणी क्षेत्र में कैरोलिना के नाम से उपनिवेश स्थापित करने का कार्य सम्पन्न किया। इन्होंने वर्जीनिया के आधार पर ही भूमि का नियंत्रण किया तथा प्रत्येक उपनिवेशवादी ने अपने भूमि संरक्षण को जागीर का स्तर दे दिया। उन्होंने आबादी को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से विधानपालिका तथा धर्म निरपेक्षता को मान्यता प्रदान की। सर्वप्रथम दक्षिणी क्षेत्र में आबादी का प्रसार हुआ। यहाँ का मुख्य पैदावार चावल था। चावल ही काफी दिनों तक दक्षिणी कैरोलिना का मुख्य आर्थिक आधार रहा। चावल के व्यापार तथा पैदावार ने दास प्रथा तथा नीग्रो व्यापार को प्रश्रय देना प्रारम्भ कर दिया तथा वहाँ का समाज अभिजात वर्गीय एवं नीग्रो दासों का समाज होता गया। चार्लस्टन का विकास एक नागरिक सभ्यता का विकास था जहाँ कृषकों ने अपने आवास निर्मित करने प्रारम्भ कर दिये थे एवं जहाँ समाज पर्याप्त रूप से कार्यशील होने लगा था। 1719 में दक्षिणी कैरोलिना एक शासकीय उपनिवेश हो गया। इसके विपरीत उत्तरी कैरोलिना में पूर्णतया औपनिवेशिक विकास हुआ। यहाँ पर उन्हीं लोगों को प्रवास की अनुमति प्राप्त हुई जो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। इसमें उन लोगों की संख्या अधिक थी जो वर्जीनिया से शुल्कों तथा ऋणों से बचने के लिये पलायन कर गये थे। ५०% कैरोलिना प्रमुखतया छोटे किसानों तथा थोड़े से दासों का उपनिवेश था परन्तु यह आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ था। 1778 में यह शासकीय उपनिवेश बन गया।

कैरोलिना के तत्काल पश्चात् कनेक्टीकट तथा मेरीलैण्ड के मध्य का समस्त क्षेत्र सम्राट के भाई ड्यूक आवयार्क को सौंप दिया गया। यह समस्त क्षेत्र हालैण्ड द्वारा हस्तगत किया जा रहा था। दोनों के मध्य का यह व्यापारिक मतभेद ब्रिटेन एवं हालैण्ड के मध्य युद्ध का कारण बन गया। हालैण्ड की सामुद्रिक शक्ति के अति निर्बल होने के कारण 1664 में ब्रिटेन ने न्यू नेदरलैण्ड को आत्म-समर्पण करने के लिये बाध्य कर दिया। यद्यपि ड्यूक ने दक्षिणी क्षेत्रों का विक्रय कर दिया परन्तु उत्तरी क्षेत्र पर उसने अधिकार रखा तथा इसका नामकरण उसने न्यूयार्क के रूप में कर दिया। हालैण्ड के ही समान न्यूयार्क में

भी प्रारम्भिक शासकीय शक्तियां अधिनायकवादी ही थीं। वहाँ पर भी जागीर-दारी तथा सामन्तवादी शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। यद्यपि अधिकांश भूमि पर अभी खेती नहीं होती थी परन्तु ये कृषकों से शुल्क लेते थे तथा अभिजात शैली में रहने के आदी हो रहे थे। ड्यूक के अधिकारीगण बड़े भूमिधरों, फर के व्यापारियों तथा न्यूयार्क के सामन्तों के सहयोग से लघु कृषकों तथा नागरिक शिल्पकारों का शोषण करते थे। 1683 में सर्वप्रथम "बिना प्रतिनिधित्व के शुल्क तथा कर" के विरोध में हड़ताल प्रारम्भ हुई परन्तु 1690 के पूर्व तक यह उपनिवेश शासकीय स्तर न प्राप्त कर सका। इन सामाजिक तथा राजनैतिक गतिविधियों से न्यूयार्क में अपेक्षाकृत कम आप्रवासी आये। इन कारणों से 17वीं सदी तक न्यूयार्क तथा न्यू जेरेसी में डच भाषियों की बहुमतता रही।

1664 में न्यू जेरेसी का क्षेत्र ड्यूक ने दो अभिजातों को वित्त कर दिया। उन्होंने इसका अधिकार क्वेकर के समूह को स्थानान्तरित कर दिया। 1702 में यह क्षेत्र साम्राज्य के शासन में आ सका। इसी प्रकार 1681 में विलियम पेन ने पेनसिल्वानिया नामक उपनिवेश की स्थापना की। इस उपनिवेश में उदारवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन अपेक्षाकृत अधिक था। पेन ने प्रारम्भ से ही धर्म-निरपेक्षता एवं मानवीय आधार पर प्रत्येक जाति, धर्म, तथा राष्ट्र के लोगों को स्वागत किया। यद्यपि यह तंत्र पूर्णतया लोकतांत्रिक नहीं था क्योंकि अभी भी मताधिकार सम्पत्तिपर निर्भर थी। पेनसिलवेनिया के विकास में देर अधिक हुई क्योंकि यहाँ इच्छानुसार भूमि रखने का अधिकार प्राप्त था। उन्हें केवल सम्पूर्ण भूमि आधे हिस्से का शुल्क देना पड़ता था। इस प्रकार 17वीं सदी के पूर्व में ही अंग्रेजों ने अमरीका में अटलांटिक के तटीय एवं बृहद् क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इन उपनिवेशकारियों ने ऐसे शासनतंत्र का विकास किया जो अमरीकी शासन विशेषताओं की भूमिका बन गये। यद्यपि उत्तरी तथा दक्षिणी उपनिवेशों में आने वाले राजनैतिक महत्व पर एकाधिकार प्रदर्शित किया।

17वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 18वीं सदी का पूर्वार्ध उपनिवेशों के इतिहास में जनसंख्या, आर्थिक स्रोत तथा आत्मनिर्भरता के विकास युग के रूप में जाना जाता है। इसी मध्य ब्रिटेन तथा अमरीका के मध्य उत्पन्न दो शक्तियों के संघर्ष ने स्वातंत्र्य संघर्ष की भूमिका खड़ी की। ब्रिटेन में उत्तरोत्तर प्रशासन की प्रभावत्मकता को तीव्र करने तथा अमरीका में अपने उपनिवेशों पर स्वयं के अधिकार की मांगों से ही मतभेदों का यह संघर्ष प्रारम्भ हुआ। इसी के साथ ही साथ उपनिवेशों के समाज में वर्गों की उत्पत्ति ने लोकतंत्र की नींव रखी। यद्यपि अभी यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति का जन्म नहीं हुआ था, परन्तु समुद्री

व्यापार के त्रिगुणात्मक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था। यूरोप के व्यापारी यूरोप में बनी वस्तुओं को अफ्रीका में बेचकर दासों को क्रय करते थे जिनकी सहायता से अमरीका में कपड़ा उद्योग हेतु कपास का साम्राज्य निर्मित होने लगा था। वहाँ से कच्चा माल, फर तथा अन्य खाद्य सामग्री यूरोप लाया जाता था। इस प्रकार एक ही जलपोत से तीन बार लाभ कमाने की परम्परा का जन्म हुआ जो औद्योगिक क्रान्ति के अवसर पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। ब्रिटेन सागर के इस साम्राज्य का सम्राट् था। सागरों पर उसके चुनौती रहित साम्राज्य ने उसके उपनिवेशों को अपार सम्पत्ति का स्वामी बना दिया परन्तु इस साम्राज्य के निर्मित होने के साथ ही स्वयं इसके विघटन के कारण बन गये। उपनिवेशों के विकास ने विश्व के समस्त भागों के लोगों को प्रभावित तथा आकर्षित किया। प्रत्येक क्षेत्र से लोग आकर अमरीका में प्रवास करने लगे इनमें सभी प्रकार के व्यक्ति-शिल्पी, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, इतिहासज्ञ तथा समाजशास्त्री थे। इस प्रकार उपनिवेशी शक्तियों की विजय ने एक ऐसी परम्परा को जन्म दिया जो अनित्य थी। इसी शक्ति के कारण उपनिवेशों की जनसंख्या बढ़ती ही गई। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही साथ विचारों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तनों का आगमन हुआ। इन नवीन विचारों में राष्ट्र, धर्म एवं यौन के तत्व अप्रभावी होते गये क्योंकि यह नवीन सभ्यता इन सभी विभिन्नताओं के आश्चर्यजनक योगदान से निर्मित हो रही थी। इस प्रकार यह नव विकसित सभ्यता प्रारम्भ से ही सामन्तवाद, वर्ग भेद, यौन भेद तथा धार्मिक रुढ़िवादिता के विरुद्ध थी।

जनसंख्या की वृद्धि भी औपनिवेशिक काल में अपनी प्रचुर मात्रा में विकसित हुई। 1763 तक अमरीका की जनसंख्या लगभग 15 लाख हो गयी थी। 17वीं शताब्दी के अन्त तक अधिकतर उपनिवेशवासी समुद्र के तटीय क्षेत्र में ही प्रवास करते थे, इनमें से जो आन्तरिक भाग में रहते थे वे भी केवल नदियों के तट पर ही सीमित रहे। ये नदियाँ कनेक्टिकट, हडसन, डेलवेयर, पोटोमैक तथा जेम्स थीं। अधिकतर क्षेत्र अभी भी अरण्यों से परिपूर्ण थे तथा वहाँ पर किसी भी प्रकार की जनसंख्या नहीं थी। ये क्षेत्र अभी तक मानव अन्वेषण की सीमा में भी नहीं आ पाये थे। केवल कुछ फर के व्यापारियों ने अपलेशियम क्षेत्रों को पार किया था। 1763 तक उत्तरी तथा दक्षिणी उपनिवेशों को छोड़कर उपनिवेशियों ने पश्चिम में पर्वतमाला के मध्य विस्तृत मैदानी हिस्सों के सभी जंगलों को समाप्त कर उनपर खेती प्रारम्भ कर दी थी। कुछ व्यापारियों ने उपनिवेशी पर्वतमाला के उस पार के मैदानी भाग पर भी खेती करने का स्वप्न देखना प्रारम्भ कर दिया था। जनसंख्या में वृद्धि का माप

केवल आप्रवास ही नहीं था बल्कि जन्मदर में वृद्धि भी थी। विशेषकर वहाँ लगभग सभी आर्थिक सुरक्षाएँ उपस्थित थीं अतः वहाँ के निवासी बड़े परिवार की तरफ उन्मुख हुये। अमरीका की असीमित भूमि तथा श्रमजीवियों के अभाव के कारण, इन परिवारों का विश्वास था कि आने वाले दीर्घकाल तक वहाँ आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं हो सकता था और ऐसी परिस्थिति में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये बड़े-बड़े परिवारों से अधिक लाभ पहुँच सकता था। तत्कालीन अमरीका में बाल श्रमिकों की प्रथा भी विद्यमान थी। अतएव आर्थिक रूप से कोई भी परिवार अत्यन्त शीघ्र ही सम्पन्न हो सकता था। आँकड़ों के अनुसार अधिकतर उपनिवेशियों को प्रत्येक दो वर्ष में एक बच्चा पैदा हो पाता था और इनमें से अधिकतर 20 तथा 25 वर्ष तक यह विधि जारी रखते थे। एक व्यक्ति दो तथा तीन औरतों से शादी कर, प्रत्येक बीबी से बच्चे पैदा करता था। यद्यपि मृत्यु दर के कारण 25% बच्चे कभी युवा नहीं हो पाते थे परन्तु फिर भी जन्मदर इतनी अधिक थी कि प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या पहले की दुगुनी हो जाती थी। इसी के साथ-साथ ब्रिटेन तथा यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों, द्वीपों से आप्रवासी बहुत अधिक संख्या में सुरक्षा की तलाश में अमरीका आ जाते थे। 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने शिल्पकारों तथा विशेष आवश्यक नागरिकों के आप्रवास पर प्रतिबन्ध लगा दिया फिर भी ब्रिटेन से यह आप्रवास कम नहीं हुआ। इसका यह प्रभाव अवश्य हुआ कि विभिन्न उद्योगों के प्रारम्भ होने के पश्चात् भी कभी ब्रिटेन की आवादी बहुत अधिक नहीं हो पायी परन्तु कुछ व्यक्ति अब भी आप्रवास के पक्ष में थे। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ प्रेषित किया गया।

इसी काल में एक नये उपनिवेश जार्जिया की भी स्थापना हुई ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र को स्पेन तथा फ्रांसीसी प्रभावों से मुक्त रखना चाहती थी परन्तु इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक ही था। जार्जिया बसाने का उद्देश्य लघु कृषकों का देश बनाना था परन्तु 1740 में यह प्रमुख उद्देश्य समाप्त हो गया तथा उपनिवेशियों ने अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया और शनैः-शनैः यहाँ भी जागीरदारी तथा सामन्तवादियों का जन्म होने लगा। नीग्रो दास व्यवस्था को वैधानिक कर दिया गया। 1751 में अन्ततोगत्वा यह साम्राज्य का एक अंग हो गया।

ब्रिटिश विरोधी आप्रवासियों में फ्रांसीसी प्रमुख थे। 1685 में सम्राट् लुई ने फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट के पुजारियों तथा अनुयायियों के साथ अत्याचार प्रारम्भ कर दिया। इनमें से बहुतों ने अमरीका में चार्ल्सटन बोस्टन तथा न्यू-यु

यार्क में शरण ली। ये (हयुजनाट्स) मध्यम वर्ग के लोग थे इनकी कार्यक्षमता तथा व्यवहारिकता दोनों ही प्रभावशाली थी। इन्होंने शीघ्र ही अमरीकी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। अपने आर्थिक तथा धार्मिक आधार में समान होने के कारण ये शीघ्र ही प्यूरिटनवादियों के समान हो गये तथा इनका कोई विशिष्ट तथा अलग वर्ग न बन सका।

इनके अतिरिक्त बहुत से आप्रवासी दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी से भी आकर अमरीका में प्रवासी हुये। इनमें से प्रमुख स्विटजरलैण्ड तथा पैलेटिनेट क्षेत्रों से आये थे। मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था इस आप्रवास का प्रमुख कारण थी। जागीरदारों, सामन्तों तथा भूमिधरों द्वारा निम्न वर्ग के गरीब तथा भूमिहीन कृषकों पर किये गये अत्याचार के कारण ये जर्मनवादी भी अन्य यूरोपीयनों के सदृश्य अमरीका में प्रवास करना अधिक उपर्युक्त समझते थे। फ्रांस के लुई 14 के बार-बार जर्मनी पर आक्रमण से भी वहाँ की आर्थिक व्यवस्था शोचनीय हो गयी थी। इन आर्थिक कारणों के साथ धार्मिक तत्वों की भी न्यूनता नहीं थी। सुधार युग में जन्मे विभिन्न धर्मों पर रोमन कैथोलिकों के अत्याचारों ने उन्हें स्वतंत्रता की ओर आप्रवासित होने की चेतना प्रदान की। यह आप्रवास 1710 के पश्चात् अत्यधिक तीव्र हो गया। इन जर्मनवासियों में से अधिकांश दासों के रूप में अमरीका पहुँचे। इनमें से अधिकांश समुद्री यात्रा में ही समाप्त हो जाते थे शेष अपने स्वामियों के अत्याचारों से। परन्तु जो शेष रह जाता था वह निश्चित ही अन्त में स्वयं अपनी भूमि तथा स्वतंत्रता का अधिकारी हो जाता था। यही आकर्षण उन्हें विभिन्न संकटों के पश्चात् भी दासों के व्यापारियों के पास ले जाता था जो उपनिवेशियों के प्रतिनिधि तथा जलपोतों के स्वामी होते थे। यद्यपि जर्मनी तथा निवासी उत्तरी कैरोलिना, जार्जिया तथा न्युयार्क गये परन्तु पेनसिलवेनिया ने उन्हें सर्वाधिक आकर्षित किया। इस आकर्षण का कारण वहाँ की धर्म निरपेक्षता तथा रोज-गार की अपार सम्भावनाएँ थी। फिलाडेल्फिया के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रमुखतया जर्मन निवासी बस गये। ये शिल्प तथा तकनीकी दोनों क्षेत्रों में ब्रिटेन से आगे थे। इन दोनों में लैकास्टा को उपनिवेशों का एक प्रमुख शिल्प केन्द्र बना दिया। इनकी सुप्रसिद्ध तकनीकी वस्तुओं में राइफल प्रमुख थी। राइफल निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने अन्य सभी जातियों तथा उपनिवेशों से अधिक प्रगति की। इन्हीं राइफलों का नाम बाद में 'केन्ट की राइफल' हुआ। इसके अतिरिक्त कन्जेस्टोगा के डिव्वे बनाने के क्षेत्र में भी ये प्रमुख रहे। इन्हीं डिव्वों में विभिन्न परिवारों ने पश्चिम की तरफ प्रसार किया।

जर्मन आप्रवासियों के समान ही स्काटलैंड तथा आयरलैंड के निवासियों

ने भी अमरीका के विभिन्न उपनिवेशों को प्रवासित किया। 17वीं सदी में ब्रिटेन ने उत्तरी आयरलैण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में कैथोलिक आयरिशों के विद्रहों-के दमन के पश्चात् स्काटलैण्ड के प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायियों को प्रवासित कर दिया था। ये प्रेसवाईटोरियन चर्च संगठन को मानने वाले कैलिवनवादी लोग थे। इन्होंने अपने श्रम तथा अनुशासन के आधार पर इस क्षेत्र (उत्तरी अलस्टर) को कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। इसी के अन्त में उनकी समानता को ब्रिटिश विधि ने भ्रष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। इन विधियों का ध्येय ब्रिटिश कृषि तथा उद्योगको सुरक्षा प्रदान करना था। इस प्रकार 1714 में सर्वप्रथम स्काट आयरिश आप्रवासियों ने अमरीका के लिए प्रस्थान किया। इनके साथ ही साथ कैथोलिक आयरिश भी अमरीका आये थे परन्तु उन्हें अपने धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त न होने के कारण, वे कोई विशेष प्रभाव न बना सके। इन स्काट आयरिश आप्रवासियों को भी पेन्सिलवेनिया का उपनिवेश अधिक सुविधा जनक प्रतीत हुआ तथा जर्मन लोगों के वाद इन्हीं की जन संख्या पेन्सिलवेनिया में द्वितीय स्थान पर हो गयी। जर्मन नागरिकों के विपरीत इन्होंने राजनैतिक मतभेदों में अधिक भाग लिया। पेन्सिलवेनिया के पश्चात् ये स्काट आयरिश दक्षिण की तरफ, जाजिया एवं कैरोलिना में प्रवासित होने लगे। क्रान्ति के समय तक लगभग सभी दक्षिणी सीमान्तर्गत भाग स्काट आयरिश जातियों से परिपूर्ण थे।

इस प्रकार इन उपनिवेशों में ब्रिटिश, डच तथा स्वीडिश जातियों के साथ फ्राँसीसी, स्विस, स्काट तथा आयरिश भी थे। इनके अतिरिक्त रोड, न्युयार्क, तथा दक्षिणी कैरोलिना में यहूदी तथा इटली आदि अन्य देशों के नागरिक भी अमरीका आकर विभिन्न उपनिवेशों में प्रवासित हो गये थे। क्रान्ति से पूर्ण इन विभिन्न जातियों में अन्तर्जातीय विवाह सम्मेलन का प्रारम्भ हो गया था। वहाँ पर विभिन्न रक्त के लोगों से यौगिक रूप में एक नयी जाति का प्रारम्भ हो चुका था।

इन आप्रवासियों के अतिरिक्त 18वीं सदी में एक अन्य तत्व ने भी जनसंख्या को अत्यधिक प्रभावित किया था। 1700 में लगभग २ लाख नीग्रो अमरीका में निवास करते थे। तत्पश्चात् नीग्रो व्यापारियों ने अफ्रीका के पश्चिम तट से नीग्रो का आयात कर पश्चिमी द्वीप समूह तथा दक्षिणी उपनिवेशों को पहुंचाना प्रारम्भ किया। इस आयात की दर लगभग 3500 नीग्रो प्रतिवर्ष थी। इस प्रकार 1763 में समस्त १३ उपनिवेशों की जनसंख्या लगभग 4 लाख हो गयी थी। यद्यपि दास प्रथा लगभग सभी उपनिवेशों में प्रचलित थी परन्तु उत्तरी मैरीलैण्ड तथा डैलावेयर में इस अर्थ-न्यस्था का कोई

निश्चित तत्व नहीं था। नीग्रो को मुख्यतः घरेलू कार्य करने के लिए रोजगार प्राप्त था परन्तु दक्षिणी उपनिवेशों के क्षेत्र में बहुत ही शीघ्र इन नीग्रो दासों की संख्या श्वेत दासों के प्रशासन के लिये विभिन्न नयी विधियों का जन्म हुआ जो अत्याचार शोषण तथा पीड़ा पर आधारित थी। इन विधियों के विरुद्ध थोड़े से विद्रोह भी हुए परन्तु उन सभी विद्रोहों का दमन कर दिया गया यद्यपि क्रान्ति के पूर्व ही दास प्रथा के विरुद्ध पेन्सिलवेनिया में आवाज उठने लगी थी परन्तु श्वेत अमरीकी नीग्रो दासों को रंग के आधारपर निम्न समझते थे। इसके साथ ही साथ इन उपनिवेशों में नीग्रो दासों से समिश्रण के विरुद्ध विभिन्न विधियों का निर्माण किया गया था जिनके कारण नीग्रो दास प्रथा का उन्मूलन लगभग असम्भव हो गया था। वे किसी आधार पर यह मानने को तैयार न थे कि नीग्रो और श्वेत एक साथ रह सकते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार की समानता सम्भव है। इनके विचार में इस प्रथा के उन्मूलन का मार्ग केवल यही था कि इन्हें वापस अफ्रीका भेज दिया जाय अथवा इन्हें अमरीका में किसी अन्य भाग में प्रवासित किया जाय परन्तु इसकी भी सम्भावना नहीं थी। इस भावना के कारण उनकी रंगभेद नीति प्रकट होती है जो आज भी पूर्णतया समाप्त नहीं की जा सकी है। शेष श्वेत अमरीकी, यद्यपि दास प्रथा के विरुद्ध थे तथा आने वाली सदी में दास-प्रथा का उन्मूलन भी हो गया परन्तु मानव समानता का वास्तविक ध्येय पूर्ण न हो सका।

तत्कालीन सिद्धान्तों के अनुरूप ब्रिटिश नीतियाँ उपनिवेशों को कच्चे-माल के स्रोत के रूप में विकसित करने के पक्ष में रही। उनका ध्येय था कि ये उपनिवेश, प्रत्येक स्थिति में मातृ राष्ट्र के अधीन रहें। साम्राज्यिकतन्त्र का आधार अमरीका से कच्चा माल प्राप्त कर वहाँ ब्रिटेन से तैयार माल निर्यात करना था। इस प्रकार ब्रिटिश अपने आर्थिक साम्राज्य को अन्य सभी देशों से अधिक सुदृढ़ करनेकी तरफ अग्रसारित था। ये नीतियाँ व्यापार तथा जहाजरानी अधिनियमों द्वारा पूरी की गयी। प्रारम्भ से ही अमरीका के उपनिवेश ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध थे परन्तु 1770 से पूर्व ये मतभेद संघर्ष का रूप न ले सके। औपनिवेशिक व्यापार के प्रशासन के लिए सर्वप्रथम पद 1620 में वर्जीनिया की स्थापना के अवसरपर लिया गया। यह निश्चित किया गया कि वर्जीनीया से तम्बाकू का निर्यात केवल ब्रिटेन को ही किया जा सकता था। इसके साथ ही साथ यह बन्धन भी था कि यह व्यापार अथवा निर्यात केवल ब्रिटिश जल पोतों द्वारा ही होगा परन्तु 1650 के गृहयुद्ध के अवसर पर यह सुविधा हालैण्ड निवासियों ने हस्तगत करली। 1650 में पुनः कामनवेल्थ शासन ने एक जहाजरानी अधिनियमके अन्तर्गत समस्त उन व्यापारोंको निषिद्ध घोषित कर

दिया जो विदेशी जलपोतों पर किये जाते थे परन्तु कामनवेल्थ ने इन अधिनियमों की प्रशासनिक सुरक्षा के प्रति अधिक रुचि नहीं प्रदर्शित की। इसी प्रकार 1650 में चार्ल्स द्वितीय के शासन कालमें एक अधिनियम के द्वारा समस्त व्यापारों को ब्रिटिश अथवा औपनिवेशिक जलपोतों तक सीमित कर दिया गया। इस अधिनियम के आधार पर तम्बाकू तथा शक्कर का निर्यात केवल ब्रिटेन को ही किया जा सकता था। 1663 में लोकसभा ने एक अधिनियम के आधार पर यह निश्चित कर दिया कि उपनिवेश केवल ब्रिटेन से ही सीधे सामानों का आयात तथा क्रय कर सकते थे। इस प्रकार जहाजरानी के उपरोक्त तीन अधिनियमों के आधार पर ब्रिटिश व्यापारियों को असीमित लाभ प्राप्त होना प्रारम्भ हो गया। यद्यपि उपनिवेशों का ध्येय औपनिवेशिक व्यापार की सुविधा प्रदान करना था तथापि में पश्चिमी द्वीप समूह के साथ ही केवल व्यापारिक समन्वय रख सकते थे। यद्यपि चेसापीक उपनिवेशों में इन अधिनियमोंका विरोध नहीं हुआ परन्तु नव ब्रिटेन उपनिवेशों में प्रारम्भ से ही ये अधिनियम अरुचिकर रहे। ये उपनिवेश अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करने तथा अधिनियमों का पालन करने के अभ्यस्त थे। बोस्टन के व्यापारी प्रारम्भ से ही इन अधिनियमों का विरोध, शक्कर एवं तम्बाकू दोनों को यूरोप निर्यात करके, करने लगे थे। अन्ततोगत्वा 1684 में उपनिवेश को साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ पर एक शासकीय राज्यपाल को भी प्रेषित कर दिया गया। दो वर्षोंके पश्चात् समस्त नव ब्रिटेन उपनिवेशों को एक में मिलाकर एक नव ब्रिटेन अधिनियम (अधिराज) की स्थापना कर दी गयी। न्यूयार्क तथा न्यूजेरसी को भी व द में इसमें मिला लिया गया। सरएण्ड्रोस को वहाँ का राज्यपाल नियुक्तकर दिया गया। एण्ड्रोस ने वहाँ पर पूर्व अधिनायकीय शक्ति से शासन करना प्रारम्भ कर दिया। वह किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध था।

1689 का वर्ष ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य शत (100) वर्षीय युद्ध के आरम्भिक अध्याय के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष का वह पक्ष जिसने उपनिवेशी अमरीका को प्रभावित किया केवल 1763 में ही समाप्त हो सका परन्तु वास्तव में यह संघर्ष सम्पूर्ण विश्व पर अधिकार हेतु प्रारम्भ हुआ तथा उसने अमरीका के स्वातंत्र्य संग्राम, फ्रांस की क्रान्ति तथा नेपोलियन के युद्धों को प्रभावित किया। सागरों पर अधिकार करने के इस संघर्ष में चार महत्वपूर्ण युद्ध हुये जो अमरीका के इतिहास में सम्राट विलियम के, 1689-1697 के, सम्राज्ञी एनी के तथा 1702-1713 के युद्धों के रूप में प्रसिद्ध है। सम्राट जार्ज के उपनिवेशियों ने केप ब्रिटेन के फ्रांसीसी किले सुई वर्ग पर

अधिकार कर लिया परन्तु 1748 के एक्स ला शैपल की संधि में ब्रिटेन को यह किला वापस करना पड़ा जिसके प्रत्यावर्तन में फ्रांस ने मद्रास (भारत) को वापस किया। इस प्रकार यह युद्ध विश्व स्तर पर प्रभावी था। इसी प्रकार यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1755 में प्रारम्भ हुआ जबकि अमरीका में यह युद्ध 1754 में ही प्रारम्भ हो गया था। 1763 में पेरिस शान्ति समझौते में ब्रिटेन ने पुनः अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को बढ़ा लिया।

इस औपनिवेशिक काल के मध्य ब्रिटेन ने जिस प्रकार विदेशी युद्धों में भाग लिया, उसी प्रकार वहाँ पर सम्राट् तथा सदन के मध्य भी संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में सदन की सर्वोच्चता सिद्ध होते ही उपरोक्त युद्ध प्रारम्भ हुये थे। तत्कालीन सदन की सर्वोच्चता के पश्चात् भी औपनिवेशिक संघर्षों में न्यूनता नहीं आयी वरन् उपनिवेशों की वृद्धि हुई। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि उपनिवेशों के पीछे कार्य करने वाली शक्तियां व्यापारिक तथा आर्थिक थीं न कि व्यक्तिवादी। 1660 में पुनर्स्थापन के पश्चात् भी चार्ल्स द्वितीय तथा जेम्स द्वितीय ने सदन के विरुद्ध अपनी शक्तियों की वृद्धि का प्रयास जारी रखा। यहाँ तक की जेम्स ने कैथोलिक धर्म को खुला समर्थन प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप 1688 की रक्तहीन क्रान्ति ने अन्ततोगत्वा जेम्स को विस्थापित कर सदन की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। विलियम तृतीय केवल एक राष्ट्रपति चिन्ह के रूप में ही शेष रह गया। इस क्रान्ति ने अमरीका को भी प्रभावित किया तथा वहाँ एण्ड्रोस के शासन को उखाड़ फेंका गया। सभी धर्मों को समानता का स्तर प्रदान कर प्रोटेस्टेण्ट धर्म को आराधना का अधिकार प्रदान कर दिया गया यद्यपि 1688 की क्रान्ति अमरीकी उपनिवेशों के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती है परन्तु यह तथ्य स्पष्ट है कि इसके पश्चात् ब्रिटेन की व्यापारिक, आर्थिक तथा औपनिवेशिक नीतियाँ अधिक विस्तृत हो गयी। उपनिवेशों में औद्योगिक विकास पर 1699 के अधिनियम द्वारा रोक लगा दी गयी। 1750 में उपनिवेशों को लोहे के सामान निर्यात करने पर रोक लगा दी गई। 1733 के मोलेसिस अधिनियम ने उपनिवेशों के स्पेनी पश्चिमी द्वीप समूह तथा फ्रांसीसी पश्चिमी द्वीप समूह के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उन वस्तुओं की संख्या बढ़ गयी जिन्हें केवल ब्रिटेन को ही निर्यात किया जा सकता था। शक्कर, शोरे तथा स्प्रिट में विदेशी आयात पर तटकर बढ़ा कर उपनिवेशों को केवल ब्रिटेन से आयात करने लिये प्रोत्साहित किया गया। पर इन सभी अधिनियमों का समस्त उपनिवेश किसी न किसी प्रकार उल्लंघन किया ही करते थे। इन समस्त अधिनियमों का निर्माण ब्रिटेन में मात्र व्यापार को सुरक्षा के ध्येय

से किया जाता था। यद्यपि इन अधिनियमों से मातृ राष्ट्र ब्रिटेन के साथ-साथ उपनिवेशों को भी लाभ पहुँचता था। उन्हें किसी प्रकार के बाजार की कमी नहीं रहती थी क्योंकि ब्रिटेन वासियों को भी उपनिवेशों के तैयार माल खरीदने के लिये बाध्य किया जाता था। उन सभी व्यापारों पर तटकर तथा अन्य कर अधिक लगाये जाते थे, जिनका व्यापार केवल विदेशी बाजारों से होता था। ब्रिटेनवासी, इंग्लैण्ड में तम्बाकू की कृषि नहीं कर सकते थे। इस प्रकार ब्रिटेन ने उक्त अधिनियमों की सहायता से एक विशिष्ट साम्राज्यिक प्रारूप तैयार कर लिया था।

उपनिवेशों के आर्थिक स्वरूप पर जहाँ ब्रिटेन की साम्राज्यिक नीतियों का एकाधिकार था वहाँ ब्रिटेन अपनी राजनैतिक सर्वोच्चता स्थापित करने में असमर्थ था। प्रत्येक उपनिवेश की अपनी एक विधानपालिका थी तथा रोड एवं कनेक्टिकट द्वीपों के अतिरिक्त प्रत्येक उपनिवेशों का राज्यपाल ब्रिटेन द्वारा नियुक्त होता था। निम्न सदन में सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार का अधिनियम था तथा उच्च सदन में नामांकित गणमान्य नागरिकों का निर्वाचन होता था। समस्त साम्राज्य पर लोकसभा का अधिकार था तथा वह किसी भी उपनिवेश के लिये अधिनियम बना सकता था एवं किसी भी उपनिवेशी विधान पालिका के अधिनियम को चुनौती प्रदान कर निरस्त कर सकता था।

उपनिवेशों में भी विरोधी शक्तियाँ कार्य कर रही थी। राजनैतिक क्षेत्र में राज्यपालों के पद का सम्मान शनैः-शनैः समाप्त होता जा रहा था तथा ब्रिटेन के सदनीय संघर्ष का परिलक्षण उपनिवेशों में स्पष्ट था। वहाँ पर भी विधान परिषदों के अधिकारों के लिये संघर्ष की भूमिका बनती जा रही थी परन्तु मताधिकार की समाप्ति द्वारा प्रतिबन्धित होने से यह संघर्ष लोकतांत्रिक न रह गया था क्योंकि संघर्षों का लक्ष्य लोकमत की सर्वोच्चता में निहित नहीं था। यही कारण था कि अमरीका के स्वातंत्र्य संघर्ष तथा संविधानों के निर्माण के अवसर पर संघर्षों ने त्रिगुणात्मक स्वरूप प्राप्त कर लिया था। एक स्थान पर जहाँ विधान परिषदें, लोकसभा के अधिकारों से मुक्त होकर स्वतंत्रता के लिये संघर्षरत थी दूसरी ओर स्वयं अमरीकी नागरिकों में अभिजात वर्ग के विरुद्ध लोकमत की स्थापना हेतु संघर्ष की भूमिका तैयार हो चुकी थी।

उपनिवेशों की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वहाँ वृद्धिरत समृद्धि ने एक नवीन चेतना तथा प्रवृत्ति को जन्म दिया जिसका क्रिस्टलीकरण उस शक्ति के निर्माण में हुआ जिसने मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा लोकमत पर आधारित

राजनैतिक शक्ति तथा स्वतंत्र विचार धारा के लिये 18 वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रयास प्रारम्भ कर क्रांति को जन्म दिया। सम्भवतः अमरीका के इस नवीन समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य इसकी आर्थिक समानता थी। लगभग सभी नगरिकों को समान रूप से सस्ती भूमि उपलब्ध थी। वहाँ पर बहुत बड़े वर्ग के रूप में श्रमिक वर्ग भी नहीं था। यद्यपि वहाँ उच्च तथा निम्न वर्ग थे परन्तु उनके मध्य का अन्तर उतना बड़ा नहीं था जितना कि यूरोप अथवा विश्व के अन्य किसी देश में था। वास्तव में यह यूरोप का आर्थिक तथा धार्मिक वर्गीकरण ही था जिसने अमरीका की आबादी को बढ़ाया था। और अब यही दोनों कारण अन्त में स्वयं अपने समाज की रचना में किसी भी भांति प्रश्रय नहीं पा सकते थे यद्यपि असमानता तथा धार्मिक विभिन्नता उपस्थित थी परन्तु इसकी शक्ति एक वर्ग की शक्ति नहीं थी एतएव सामन्तवादी तथा सर्वहारा दोनों वर्गों की अनुपस्थिति में अमरीका ने मध्यम वर्ग का विकास किया। फ्रैंकलिन ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अमरीका में यूरोप के सदृश उच्चतथा निम्न वर्ग नहीं थे।

अमरीका के एक विशिष्ट चरित्र के विकास में भी वहाँ की परिस्थिति प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त होने के पश्चात् भी कुछ व्यक्तिवादी गुण समाज में उत्पन्न हुये। विभिन्न व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा की अधिकता ने उन्हें अपेक्षाकृत अधिक श्रम की तरफ उत्प्रेरित किया, उन्होंने अधिक दासों की नियुक्ति की तथा समय के साथ साथ वे अधिक अमीर भी हुये यद्यपि यह अन्तर बहुत अधिक नहीं था परन्तु एक समान वर्ग के ऊपर आर्थिक उलब्धियों के विभिन्न चरणों पर पहुँच जाना ही इस प्रवृत्ति को जन्म देने के लिये पर्याप्त था जब कि स्वयं की श्रमहीनता, अनुशासनहीनता तथा महत्वाहीनता ही वास्तव में उसकी गरीबी का कारण होती है। पूर्वजन्म, भाग्य अथवा इस प्रकार की किसी भावना को वहाँ के आर्थिक स्वरूप ने प्रश्रय नहीं दिया। अध्यात्मवाद हीन समाज के विकास ने व्यक्ति को भौतिक वादी बनाना प्रारम्भ कर दिया। उनके विचार में सफलता का उत्तरदायित्व किसी अन्य पर नहीं अपितु साहस, श्रम तथा अनुशासन में निहित होता है।

प्रारम्भ में अमरीकी उपनिवेशों की राजनैतिक गतिविधियाँ अभिजातवर्ग द्वारा संचालित थी। मत का अधिकार, विधान, परिषद के निर्माण तथा आय के विभाजन इन सभी स्थानों पर उच्च वर्ग का एकाधिकार था परन्तु इसके साथ ही साथ लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का भी जन्म हो रहा था। इस नवीन प्रवृत्ति ने अमरीकी समाज में एक मतभेद को जन्म दिया जो क्रांति युग में संघर्ष के रूप में स्पष्ट होकर आ गई। इन मतभेदों को प्रमुख प्रश्रय देने का

कार्य राजनैतिक अधिकार', भूमि पर अधिकार सिक्के तथा धर्म ने किया। राजनैतिक अधिकारों की चर्चा इसके पूर्व भी की जा चुकी है कि किस प्रकार वहाँ राजनैतिक एकाधिकार तथा सम्पत्ति के आधार पर मत के अधिकार का विरोध प्रारम्भ हो गया था। समाज में विभाजन का दूसरा कारण वहाँ के कृषकों द्वारा रिक्त भूमि पर अधिकार करने का था। उनके विचार में कोई भी उन रिक्त भूमि पर श्रम करके उन्हें अधिकृत कर सकता था परन्तु इसी के विरुद्ध दूसरा वर्ग भी आर्थिक एकाधिकार में रुचि के कारण इस प्रवृत्ति को अवैधानिक मानता था। तीसरे स्थान पर सिक्कों की समस्या थी। तत्कालीन अमरीका में सोने तथा चाँदी का अभाव होने से सिक्के आयात करने पड़ते थे। वहाँ समय-समय पर सिक्को का अभाव भी हो जाता था। साथ ही वाणिज्यिक बैंकों का भी अभाव था। वस्तु विनिमय के आर्थिक स्वरूप पर ही समाज निर्भर था। 1690 के पश्चात मैसाचूसेट्स में एक प्रकार के 'ऋण के बिल' का प्रारम्भ हुआ। ऋण लेने की समस्या कृषकों के लिये सर्वाधिक थी। तत्कालीन अमरीका को वास्तव में पेपरमनी (कागज के नोटों) की आवश्यकता थी। उसकी अनुपस्थिति ने मैसाचूसेट्स तथा रोड में एक अभूतपूर्व संघर्ष ऋणदाता तथा ऋणों के मध्य प्रारम्भ कर दी। उच्च वर्ग तथा प्रजातांत्रिक प्रवृत्तियों ने धार्मिक क्षेत्रों में भी अपना संघर्ष प्रारम्भ रखा। परन्तु 1730-1740 में अमरीका के उपनिवेशों में 'महान पुर्नजागरण' का प्रवेप हुआ। इस पुर्नजागरण का प्रारम्भ न्यू इंग्लैण्ड, जेरेसी तथा पेनसिलवेनिया में हुआ। इसका श्रेय ब्रिटेन के यात्री 'जार्ज व्हाइटफील्ड' को प्राप्त है। धीरे धीरे यह धारा दक्षिण की तरफ भी प्रवाहित हुई। धनी व्यापारियों पर इसका प्रभाव नगण्य रहा। इस प्रकार इस प्रवृत्ति ने धर्म में लोकतांत्रिक स्वरूप को विकसित किया एवं चर्च तथा राज्य के विभाजन की भी मांग रखी। औपनिवेशिक समाज के वर्गों में उत्पन्न इन मतभेदों ने एक क्रान्तिकारी वातावरण को जन्म देना प्रारम्भ किया, जिसने सर्वप्रथम मातृदेश ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के विरुद्ध अस्त्र उठाया तत्पश्चात प्राकृतिक विधि तथा मानवता के आधार पर समाज को संगठित किया। इस प्रवृत्ति तथा वातावरण के लिये 18वीं सदी की बौद्धिकता, सांस्कृतिक चलन, धार्मिक विकास, सामाजिक सिद्धांत, वैज्ञानिकता तथा दार्शनिकता एवं साहित्य तथा कला सभी किसी न किसी प्रकार उत्तरदायी थे।

उत्तरी अमरीका के ब्रिटिश उपनिवेशों के प्राथमिक जीवन काल ने वन्य देश के विभिन्न तत्वों से संघर्ष किया परन्तु काल परिवर्तन ने औपनिवेशिक समाज को सुदृढ़ता, समृद्धता, प्रौढ़ता तथा बौद्धिकता से परिपूर्ण करना प्रारम्भ कर दिया। नागरिकों ने शिक्षा तथा उच्च अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित

करना प्रारम्भ कर दिया। 1704 में सर्वप्रथम उपनिवेशों ने समाचार पत्र देखा। 18 वीं सदी में विधिवेत्ताओं, वक्ताओं, चिकित्सकों तथा दार्शनिकों की संख्या में वृद्धि हुई। 18वीं सदी के प्रारम्भ में उपनिवेशों में न केवल मौलिकता का ही विकास हुआ अपितु इसने बौद्धिक प्रसार को भी अनुभव किया। यद्यपि बौद्धिकता के लिये अमरीका बहुत अधिक सीमा तक यूरोप पर ही निर्भर था तथापि शिक्षा की चरम सीमा में अमरीकी सिद्धान्तों में परिवर्तन प्रारम्भ हो गये क्योंकि एक नवीन दिशा में विकसित होने के लिये अमरीका के पास पर्याप्त भूमि तथा अन्य आवश्यकतायें उपलब्ध थी। यह सदी वास्तव में बौद्धिकता के युग के रूप में आयी थी। इस युग ने प्राकृतिक विज्ञान के विकास में सहयोग किया तथा मध्य-युगीन उन सभी दर्शनों तथा सिद्धान्तों को निष्प्रयोजन सिद्ध कर दिया जो केवल अनुमानों पर आधारित थी। इसके विपरीत अनुभवों तथा वैज्ञानिक प्रयोगिकता पर आधारित सिद्धान्तों को मान्यता मिलनी प्रारम्भ हो गई। न्यूटन ने इसी युग में अपने सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया तथा ब्रह्माण्ड के नवीन स्वरूप को प्रायोगिक आधार पर सिद्ध किया। इस नवीन युग परिवर्तन ने लोगों में ईश्वर की उपस्थित को तो चुनौती नहीं दी परन्तु उन्होंने ईश्वर के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया। उनके विचार में यह जीवन अधिक उपयुक्त तथा संयत था। उसके विकास का ध्येय ही वास्तविक ध्येय था। इसके विपरीत पराजन्म सिद्धान्तों तथा मृत्युपरान्त जीवन के लिये धार्मिक आधार पर कार्य करना मूर्खता थी। इसी सदी ने स्वर्ग तथा नरक की निराशाओं से दूर एक आशाजनित जीवन की सफलता के लिये प्रयास करने का आवाहन किया।

न्यूटन के ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार सभी उपग्रह स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुये भी एक प्राकृतिक अधिनियम से बचे थे उसी प्रकार यह कल्पना की गई कि इस विश्व में भी स्वतंत्रता तथा कानून को एक साथ स्थापित करना सम्भव था। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम जॉनलॉक ने अपने सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया, जिसके आधार पर प्रत्येक मनुष्य को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे जिसमें सर्वाधिक मौलिक जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति की सुरक्षा प्रमुख थी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि ऐसे शासन की स्थापना होनी चाहिये जिसमें ये सभी सुविधायें जनसामान्य को उपलब्ध हों। उन्होंने 'सामाजिक सझोदारी' के आधार पर शासन के गठन की परिकल्पना की, तथा यह बताया कि व्यक्ति, राज्य से अधिक विशिष्ट है। वह उन सभी कार्यों को करने के लिये स्वतंत्र है जिनसे समाज के किसी अन्य भाग को हानि नहीं पहुंचती हो। इसी धर्म के इस विश्वास को कि 'प्रत्येक व्यक्ति में वास्तव में बुराईयों के प्रति आकर्षित होने

की उत्कंठा होती है इसलिये उस पर कठोर शासन आवश्यक है' को निराधार सिद्ध कर लॉक ने आशावादी सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार 'प्रत्येक नवजात शिशु का मस्तिक एक कोरे कागज के रूप में होता है तथा उसपर वातावरण के प्रभावों द्वारा परिवर्तन होता है। अतः अच्छे वातावरण को उपलब्ध कराकर अच्छी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता था।

इसी प्रकार के सिद्धान्तों का प्रतिपादन अर्थशास्त्र में भी हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को व्यापारिक तथा वाणिज्यिक सुविधा तथा स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये तथा उसपर शासन का अधिकार नहीं होना चाहिये। फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों (फिज़ियोक्रेट्स) ने रूढ़िवादी आर्थिक स्वरूप के विपरीत नवीन आर्थिक सिद्धान्तों (लेसेज फेयर) का सिद्धान्त प्रदान किया। उन्होंने यह बताया कि 'अर्थ का श्रोत केवल भूमि है तथा राष्ट्र केवल कृषि के विकास से सम्पन्न हो सकता है।' 1776 में सर्वाधिक चर्चित अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने "वेल्थ आफ नेशन्स" प्रकाशित की। उन्होंने यह बताया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पन्नता के लिये प्रयास करने का पूर्ण अधिकारी हो जाये तो सर्व साधारण का लाभ हो सकता है। उसके अनुसार आर्थिक न्याय तथा शोषणों के लिए जिम्मेदार एक मात्र सरकार थी जो हर स्तर पर हस्तक्षेप करने को अधिकारिणी थी।

बौद्धिक युग के दार्शनिक भी ईश्वरीय नियमों, प्रवृत्ति तथा विवेक में विश्वास रखते थे परन्तु उन्हें स्थापित संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं था। ये सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि वास्तव में मनुष्य अच्छाइयों तथा आदर्शों की तरफ आकर्षित होता है अतः उन्हें उनके प्रयासों से पृथक करना अमानवीय तथा अप्राकृतिक था। यह सिद्धान्त विभिन्न दार्शनिकों ने प्रतिपादित किया परन्तु इस क्षेत्र का सर्वाधिक चर्चित दार्शनिक वाल्टेयर का था। रूढ़िवादी संस्थाओं तथा शासन की उस आलोचना ने वास्तव में फ्रांसीसी क्रान्ति तथा 19 वीं सदी के उदारवादी आन्दोलनों को जन्म दिया।

इस युग की साहित्यिक तथा कला के क्षेत्र में उपलब्धियों ने भी बौद्धिक युग के निर्माण में योगदान प्रदान किया। इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि 18वीं सदी के साहित्य तथा कलाकारिता पर बौद्धिक युग का प्रभाव परिलक्षित था।

यूरोप के इस बौद्धिक युग का प्रभाव अमरीका के समाज, संस्थाओं तथा सिद्धान्तों पर इतना गहरा पड़ा कि उनको अस्वीकार करना लगभग असम्भव है तथा इसका मुख्य कारण यह था कि यह बौद्धिकता जिन सिद्धान्तों को प्रतिपा-

दित कर रही थी वह पहले से ही अमरीका के उपनिवेशों में विकसित हो रही थी। समानता, स्वतंत्रता तथा आशावादिता के आधार पर इस नवीन विश्व में एक नवीन सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी। इन दार्शनिकों ने अमरीकी सभ्यता का स्वागत किया तथा उपनिवेशों ने उनके सिद्धान्तों की सत्यता में विश्वास प्रकट कर उन्हें स्वच्छन्दता से अपनाया। दोनों के इस सहकारिता का अभूतपूर्व संगम बैजामिन फ्रैंकलिन के व्यक्तित्व में उपस्थित था। वह समान रूप से इस नवीन सभ्यता तथा उस नवीन बौद्धिकता का मिश्रण था। उसने मानवीय विवेक तथा मानवीय विकास के सम्भावित आशाओं पर विश्वास प्रकट किया। तत्कालीन उपनिवेशों की विचारधारा पर उसके व्यक्तित्व, दर्शन, कर्तव्य तथा सिद्धान्तों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक युग में अमरीका केवल उन्हीं मूल्यों से प्रभावित हुआ जो सर्वथा प्रायोगिक थे यद्यपि वे धर्म तथा राजनैतिक सिद्धान्तों में रुचि रखते थे परन्तु एक नये महाद्वीप को आबाद करने में उनके पास विशुद्ध विज्ञान तथा आदर्शवादी सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये समय का पर्याप्त अभाव था। इन सिद्धान्तों को सहयोग प्रदान करने हेतु कोई आर्थिक आधार उपलब्ध न था। यद्यपि अमरीका में कोई प्रथम श्रेणी का सिद्धान्त नहीं प्रतिपादित हुआ परन्तु यहाँ लोकतांत्रिक प्रकृति यूरोप की अपेक्षा अधिक प्रचलित थी। वहाँ 1639 में छापेखाने की व्यवस्था हो चुकी थी तथा 1765 के पूर्व लगभग 11 उपनिवेशों में छपाई का काम प्रारम्भ हो चुका था। 1765 तक लगभग 25 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इसके साथ ही साथ प्राथमिक, तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उपनिवेश पर्याप्त प्रगतिशील थे। अमरीका के राजनैतिक दार्शनिक तथा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त को पर्याप्त मान्यता प्रदान करने लगे थे। उनके विचार में ब्रिटेन का अधिकार मौलिक अधिकारों द्वारा प्रतिबन्धित था। 18वीं सदी में अमरीका ने विज्ञान तथा दर्शन में भी रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। इसके साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी अमरीका का योगदान सर्वथा नवीन था। उन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक विकास को प्रभुत्व प्रदान किया। इस प्रकार क्रान्ति के पूर्व अमरीका की संस्कृति पर्याप्त विकेन्द्रित हो चुकी थी। संस्कृति के इस विकेन्द्रिकरण ने उन्हें नयी प्रवृत्तियों को जन्म देने में सहायता प्रदान की। उपनिवेशों को सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा दार्शनिक विकेन्द्रीकरण ने उन्हें स्वतंत्र मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि निर्मित करने में सहयोग दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सार्वभौमिकता को चुनौती प्रदान करने हेतु पर्याप्त सांस्कृतिक तथा आर्थिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर लीं। इसके अतिरिक्त उसने कला, साहित्य तथा संगीत के क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रगति कर ली थी। एक पूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिये सभी आवश्यक तत्वों ने अमरीका के सभी उपनिवेशों में

स्थान प्राप्त कर लिया था। विज्ञान के क्षेत्र में जान विन्श्राप तथा फ्रैंकलिन, चिकित्सा क्षेत्र में विलियम डगलस तथा जॉन मार्गन, दर्शन के क्षेत्र में जोनामन एडवर्ड तथा कोल्डन, साहित्य के क्षेत्र में विलियम हिल ब्राउन तथा विलियम स्मिथ, इतिहास के क्षेत्र में विलियम ब्रेडफोर्ड और काटन मैथर, पेटिंग में रावर्ट फेंक, जान कूपले तथा संगीत क्षेत्र में विलियम स्मिथ इत्यादि ने अपने योगदानों के द्वारा अमरीका के साहित्य को पर्याप्त समृद्धिशाली बना दिया। अमरीका की इन्हीं उपलब्धियों ने इसके उपनिवेशों में यूरोप की सार्वभौमिकता को चुनौती प्रदान करने की भावना का जन्म कराया जो अन्ततोगत्वा अमरीका के स्वतंत्रता संग्राम तथा संविधान के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ।



संविधानवाद



जार्ज वाशिंगटन



बैजामिन फ्रैकलिन (1706-1790)

अध्याय 1

अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास

क्रान्ति युग

अमरीका की क्रान्ति अमरीका के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। 1763 से 1783 के बीच दो दशकों में अमरीका के लोगों ने अपना एक स्वतंत्र राजनैतिक स्वरूप निर्धारित किया था। इसके साथ ही साथ इस काल में उपनिवेशों को 'राज्यों' का रूप देकर नये संघीय अमरीका का उदय हुआ। अमरीका की यह क्रान्ति कार्ल एल. बेकर के अनुसार एक नहीं अपितु दो क्रान्तियों का सम्मेलन थी। प्रथम 'वाह्य क्रान्ति' थी जिसके अंतर्गत उपनिवेशों में ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह किया गया तथा जिसका कारण उपनिवेशों व ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। द्वितीय 'आन्तरिक क्रान्ति' थी। जिसका प्रयोजन स्वतंत्रता के पश्चात अमरीका के भविष्य की रूपरेखा का निर्धारण था। इस समय सामाजिक वर्गों में यह द्वन्द्व व्याप्त था कि ब्रिटिश अधिपत्य समाप्त होने के बाद अमरीका पर उच्च वर्ग का शासन होगा अथवा निम्न वर्ग का।

अमरीका के इतिहास का यह युग 'ज्ञान एवं विवेक' का युग था। सत्रहवीं सदी के उत्तरार्ध में अमरीका के दार्शनिकों, विद्वानों एवं वैज्ञानिकों ने धर्म एवं सत्ता को समर्थन देने की अपेक्षा विवेक शक्ति के विकास पर बल दिया। इस नवीन विचारधारा ने पुरातन मान्यताओं को क्रान्तिकारी आघात पहुंचाया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रेंकलिन (1706-90) द्वारा प्रतिपादित प्रबुद्ध जीवन दर्शन ने उपनिवेशों पर साम्राज्यवादी ब्रिटेन की शक्ति को निश्चित रूप से क्षीण बना दिया था। इस काल में धर्म निरपेक्ष स्वतंत्र अमरीकी समाज की कल्पना मुखरित हो उठी थी। उपनिवेशवासी इस बात के प्रति जागृत होने लगे थे कि ब्रिटेन के संविधान में समविष्ट नैसर्गिक अधिकार, उपनिवेशों के घोषणा पत्र के अनुरूप उन्हें भी प्राप्त थे।

वैचारिक धरातल पर हुई इस क्रान्ति के साथ-साथ तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं ने भी अमरीका में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित करने में पर्याप्त सहयोग दिया। 1756-63 के सप्त वर्षीय युद्ध ने ब्रिटेन के सम्मुख संकटग्रस्त स्थिति का प्रादुर्भाव कर दिया। युद्धोपरान्त ब्रिटेन ने स्वऋण को अदा करने के लिये उपनिवेशों को युद्ध व्यय वहन करने के लिये, बाध्य किया। साम्राज्यवादी विचारधारा ऋण संकट से मुक्त होने के लिये नवीन कर लगाये जाने के पक्ष में थी।

अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1763 की घोषणा, शक्कर अधिनियम (1764), मुद्रा अधिनियम (1764), सैनिक अवास अधिनियम (1765), विलिंगटन अधिनियम (1765) तथा टिकट अधिनियम (1765) के माध्यम से उपनिवेशों पर कर आरोपित किये। वस्तुतः यह कार्यवाहियाँ अमरीका में उपनिवेशवाद विरोधी वातावरण तैयार करने में अत्यन्त दूरदूरी साबित हुई। इससे अमरीका में विवेकजन्य विचारधारा का सूत्रपात हुआ। 1765 के टिकट अधिनियम ने उपनिवेशों के प्रत्येक वर्ग विशेषकर प्रभावशाली वर्ग को अत्याधिक उद्वेलित किया। इस अधिनियम के विरोध में “स्वतंत्रता के सपूत” नामक एक अंतःउपनिवेशी संस्था गठित की गयी। तेरह में से नौ उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अवटूर, 1765 में न्यूयार्क में आयोजित टिकट अधिनियम सम्मेलन (कांग्रेस) में अधिकारों और शिकायतों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, मुख्य नगरों के व्यापारियों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसका आशय था टिकट अधिनियम जैसे अन्य आपत्तिजनक अधिनियमों के वापस लिए जाने तक ब्रिटिश माल का वहिष्कार। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को निरस्त तो कर दिया, लेकिन अपने अधिकारों का ब्रोध कराने के लिए उसने एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत नियमों के निर्माण का अधिकार प्रत्येक परिस्थितियों में सुरक्षित था। इस अधिकार के प्रदर्शन हेतु संसद ने 1767 में “टाउन्सहेड अधिनियम” पारित किया जिसमें शीशे, लेड, कागज तथा चाय पर नवीन आयात कर आरोपित कर दिये गये। कालान्तर में ब्रिटिश माल के वहिष्कार व आयात विद्रोह के कारण साम्राज्यवादियों को टाउन्सहेड अधिनियम के निरस्तीकरण पर भी बाध्य होना पड़ा। यद्यपि संसद की सर्वोच्चता का सिद्धान्त कायम करने हेतु चाय पर लगाया गया आयात कर जारी रखा गया तथापि साम्राज्यवादी सत्ता पर औपनिवेशिक दबाव स्पष्ट परिलक्षित हो चला था। इन घटनाओं ने शासित अमरीकियों में आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव कर दिया था।

तदुपरान्त 1770 के चर्चित बोस्टन हत्याकांड ने उपनिवेशवाद विरोधी जन-अन्दोलन को और तीव्र कर दिया। इसकी प्रथम अभिव्यक्ति 16 दिसम्बर, 1773 को हुई, जब "बोस्टन चाय दल" के नाम से प्रसिद्ध एक उग्र उपनिवेश दल ने बोस्टन बंदरगाह पर स्थित एक जहाज से चाय पेटियों को निकाल कर समुद्र में फेंक दिया। इस घटना से क्रोधित होकर ब्रिटेन ने ऐसे अधिनियमों को लागू किया जिसके परिणाम स्वरूप सामंजस्य की शेष रही सम्भावना भी समाप्त हो गयी। इनमें बोस्टन बंदरगाह अधिनियम, न्याय प्रशासन अधिनियम, मैसाचुसेट्स कर अधिनियम तथा आवास अधिनियम प्रमुख थे।

क्रान्ति युग के इस काल में ब्रिटिश साम्राज्य व अमरीकी उपनिवेश ऐसी स्थिति में प्रविष्ट हो चुके थे, जहाँ से पीछे लौटना दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके थे। अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य व अमरीकी उपनिवेश दोनों ही इस स्थिति में पदापर्ण कर चुके थे कि वापस लौटना उनकी पराजय थी।

इन समस्त अधिनियमों ने आन्दोलनों को पुनः प्रेरित किया। मैसाचुसेट्स विधान सभा के प्रतिनिधियों के आग्रह पर जार्जिया के अतिरिक्त अन्य उपनिवेशों ने अपने-अपने प्रतिनिधियों को उपनिवेशों की तत्कालीन समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु सन्नद्ध किया। 5 सितम्बर, 1774 को समुद्री नगर फिलाडेल्फिया में इन प्रतिनिधियों का पहला ऐतिहासिक महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य पुर्ण स्वराज्य की मांग नहीं वरन् आन्तरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना था।

सम्मेलन में 5 सिद्धान्त स्वीकृत किये गये—

- 1— ब्रिटिश सत्ता के माध्यम से एक उपनिवेशी संघ की स्थापना की योजना को अस्वीकृत करना।
- 2— "संकल्पों की घोषणा" नाम से एक शिकायती वक्तव्य का प्रेषण।
- 3— उपनिवेशों एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार स्थगन।
- 4— ब्रिटिश उपभोक्ता सामग्री का पूर्ण बहिष्कार।
- 5— एक महाद्वीपीय संस्था की स्थापना।

यह सम्मेलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसमें विभिन्न उपनिवेशों से योग्य एवं धनी व्यक्ति भेजे गये थे। चैथम के शब्दों में "उपयुक्त समय पर आहूत यह सम्मेलन ग्रीस एवं रोम के बाद बुद्धिजीवियों का अत्यन्त शिष्ट सम्मेलन था।"

इस सम्मेलन में एक ओर जहाँ सर्व श्री जॉन एडम्स (मैसाचुसेट्स), स्टीफन हापकिन्स (रोड आइलैण्ड), थामस मिफलीन (पेन्सिलवेनिया), रिचर्ड हेनरी ली व पैट्रिक हेनरी (वर्जीनिया) तथा क्रिस्टोफर गार्डन (दक्षिणी कैरोलीना)

जैसे विप्लववादी थे वहीं दूसरी ओर पेटन रेन्डॉल्फ (सम्मेलन के अध्यक्ष), जार्ज वाशिंगटन (वर्जीनिया), जान डिकिंसन (पेन्सिलवानिया) व रूटलेजे (दक्षिणी कैरोलीना) जैसे मध्यमार्गी एवं जेम्स डुआने व जान जे (न्यूयार्क) तथा जोजफ़ गैलोवे (पेन्सिलवानिया) रूढ़िवादी विचारधारा के पोषक उपस्थित थे। संक्षेपतः विभिन्न विचारों पर सम्मिलित होकर विचार विमर्श करने का प्रथम बड़ा सम्मेलन था जिसमें उपनिवेशों के विभिन्न हितों की व्यापक समीक्षा की गयी। सम्मेलन में जार्जिया के अतिरिक्त प्रत्येक उपनिवेश से प्रतिनिधि के रूप में कुल 55 लोग सम्मिलित हुए। वैचारिक दृष्टिकोण से यह सम्मेलन न तो बहुत लघु था और निर्णय लेने तथा उसे कार्य रूप में परिणत करने के दृष्टिकोण से बड़ा ही था।

इस सम्मेलन में सर्वप्रथम दोनों संसदों की उपेक्षा की गयी तथा प्रत्येक उपनिवेश से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहने को कहा गया। अंत में सम्मेलन ने दो निर्णय पारित किए। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति व संस्था को ब्रिटेन व आयरलैण्ड से आयात निर्यात न करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके लिए 1 दिसम्बर, 1774 से ब्रिटेन से आयात बन्द करने तथा 10 दिसम्बर 1775 से चावल को छोड़कर ब्रिटिश वेस्टइंडीज को अन्य वस्तुओं का निर्यात समाप्त करने का निश्चय किया गया। दूसरे निर्णय में सम्मेलन ने मैसाचुसेट्स की खाड़ी के लोगों द्वारा पुराने संसद के कानून लागू किये जाने के विरोध का समर्थन किया। साथ ही यह चेतावनी भी दी गयी कि यदि यह कानून जबरदस्ती लागू किए गए तो सम्पूर्ण अमरीका उसका विरोध करेगा। प्रतिनिधियों का यह विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार इन कानूनों को जोर जबरदस्ती से लागू करेगी जिसका उपनिवेश पूर्णतया विरोध करेंगे। परिणामस्वरूप युद्ध प्रारम्भ हो जायेगा। 22 अक्टूबर, 1774 को यह सम्मेलन इस निर्णय के बाद समाप्त हो गया कि समस्याओं पर आगे भी विचार विमर्श हेतु सम्मेलन बुलाया जाएगा।

काँग्रेस का दूसरा सम्मेलन होने से पूर्व ही सरकार और नागरिकों के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। संघर्ष का प्रारम्भ 19 अप्रैल 1775 को कानकाई नामक स्थान से हुआ। इस प्रकार अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम का मूलपात हुआ। इसके साथ ही स्थानीय काँग्रेस पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगी। जहाँ एक ओर नयी काँग्रेस ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार कर रही थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश फौजों से भी संघर्षरत थी।

10 मई, 1775 को जबकि अभी लोकसंगठन और कानकाई की रक्त-

रंजित युद्ध का समापन नहीं हुआ था, फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन (कांग्रेस) हुआ इसमें जार्ज वॉशिंगटन का चयन अमरीकी सेनाध्यक्ष के रूप में किया गया। इस सम्मेलन में ब्रितानी शोषण के विरुद्ध हथियार उठाने के कारणों पर प्रकाश डाला गया तथा सम्राट को 'जैतून की टहनी' नामक याचिका पेश की गयी। इसी सम्मेलन के दो माह पश्चात् हथियार उठा लेने का निश्चय किया गया। यद्यपि कांग्रेस ने सैनिक कार्यवाही स्वीकार की थी तथापि इंग्लैण्ड से पूर्ण स्वतंत्रता की बात कांग्रेस के प्रतिनिधियों एवं अमरीकी जनता को अभी भी सन्देहास्पद ही लगती थी। 1782 में जैफरसन ने यह स्वीकार किया कि जुलाई, 1775 तक इंग्लैण्ड से पूर्णयता पृथक होकर एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करें। इस बात की ओर लोगों का ध्यानाकर्षण नहीं हो पाया था।

23 जून 1775 को 13 उपनिवेशों के संयुक्त सेनाध्यक्ष जार्ज वॉशिंगटन फिलाडेल्फिया से वेकर हिल पहुँचे। 17 जून को ब्रिटिस सेना ने वेकर हिल पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया। स्वतंत्र अमरीकी सेना को भारी हानि के पश्चात् यहाँ पहली ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में 1054 देश-भक्तों ने अपनी जान गँवायी।

द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् वेनीडिक्ट आरनोल्ड के नेतृत्व में कनाडा को भी चौदहवें उपनिवेश के रूप में सम्मिलित करने के प्रयास को स्वीकृति दे दी गई। अक्टूबर, 1775 तक जल सेना गठित करके कमोडार इसेक हापकिन्स के नेतृत्व में एक महाद्वीपीय वेड़ा नासाऊ (ब्रह्माज) पर आक्रमण हेतु भेजा गया।

इसके लगभग एक वर्ष बाद वर्जीनिया के रिचर्ड हेनरी ली ने अपने प्रदेश के संकेतों पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के अनुसार समस्त उपनिवेशों की स्वतंत्रता प्राप्त होनी ही चाहिये। दो अतिरिक्त प्रस्तावों में उन्होंने एक संगठन तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशी राज्यों से संधि की बात प्रस्तुत की। इस कांग्रेस के 5 सदस्यों: थामस जैफरसन, जान एडम्स, बेंजामिन फ्रैंक्लिन, रोजेन शरमन तथा राबर्ट आर० लिविंगस्टोन को लेकर एक समिति बनाई गई जिसका काम 'स्वतंत्रता की घोषणा' का स्वरूप तथा रूपरेखा तैयार करना था। इस घोषणा के प्रमुख शिल्पी थामस जैफरसन थे। 4 जुलाई 1776 को उनके प्रस्तावों को औपचारिक स्वीकृति मिल गई।

स्वतंत्रता की घोषणा

4 जुलाई, 1776 को कांग्रेस ने निर्विरोध रूप से जिस 'स्वतंत्रता

की घोषणा' को स्वीकृति प्रदान की थी उसका मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि जब कोई सरकार मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करे तो जनता को ऐसी सरकार परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। घोषणा के विपरीत ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार न केवल उपरोक्त अधिकारों की पूर्ति हेतु अक्षम थी, अपितु स्वयं निरंकुश एवं असहनीय हो चली थी। सम्राट जार्ज तृतीय का रूप दमनकारी होता जा रहा था। एक प्रबुद्ध नागरिक के लिये ऐसी परिस्थिति अत्यन्त अपमान जनक थी। यहाँ तककि उपनिवेशों को उनके अथक प्रयासों के उपरान्त भी न्याय नहीं मिल पाता था।

घोषणा पत्र में कहा गया कि "अतएव हम, संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि समस्त उपनिवेशों के नागरिकों के नाम से विश्व के सर्वोच्च न्यायाधीश को यह निवेदन करते हैं कि अब हम स्वतंत्र राज्य के निवासी हैं। इसके साथ ही वे इस समय ब्रिटिश सम्राट के प्रति समस्त निष्ठा से मुक्त हो चुके हैं तथा उनके एवं ब्रिटेन के मध्य अब किसी भी प्रकार का राजनैतिक सम्बन्ध शेष नहीं है। अतः वे युद्ध, शान्ति, संधि, व्यापार एवं अन्य उन सभी मामलों में अधिकारिक रूप से निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं, जो एक स्वतंत्र राज्य के अधिकार होते हैं।

उपरोक्त घोषणा न केवल एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की उद्घोषणा थी अपितु यह 19वीं सदी में यूरोप के इतिहास में राजनैतिक दर्शन तथा क्रान्तिकारी राष्ट्रीय विचारधारारों की भूमिका थी। इसी घोषणा की पृष्ठभूमि पर 1789 की फ्रांसीसी क्रान्ति की आधारशिला रखी गई। यही नहीं, 1848 में आयरलैण्ड, फिनलैण्ड, इटली, जर्मनी आदि देशों में हुये राष्ट्रवादी आन्दोलनों में घोषणापत्र की आत्मा स्पष्ट झलकती है। "विश्व का प्रत्येक मानव पूर्णरूपेण स्वतंत्र एवं समान है तथा उसे अपनी स्वतन्त्रता, अधिकारों की सुरक्षा के लिये संघर्ष का अधिकार प्राप्त है" ऐसी धारणाओं को धरातल पर प्रायोगिक स्वरूप देने का यह प्रथम प्रयास था।

संकट काल

अमरीकी देशभवतों ने स्वतंत्रता की घोषणा का स्वागत किया परन्तु किसी ने उसके दूरगामी परिणामों पर विचार नहीं किया। घोषणा को साकार रूप प्रदान करने के प्रयास शुरू ही हुये थे कि जनरल होवें ने वाशिंगटन तथा उसकी सेना को न्यूयार्क से निष्कासित कर दिया। इस घटना से अमरीकी मनोबल निःसन्देह क्षीण हुआ था एवं सेना तितर बितर हो चुकी थी। परन्तु थामस पेन के अनुसार अभी आशा की किरण शेष थी।" मैं ईश्वर



टॉमस पेन (1737-1809)
क्रान्ति अधिप्रचारक

को धन्यवाद देता हूँ कि मैं भयभीत नहीं हूँ। मुझे भय का कोई कारण भी नहीं दिखाई देता है। मुझे इन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान है तथा इनमें मुक्ति का मार्ग भी देख सकता हूँ। यदि हमारी सेना संगठित रहे तो होवे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। होवे की सफलता श्रेयस्कर नहीं है अपितु हमारी छोटी सी सफलता भी बन्दनीय है”।

स्वतंत्रता घोषणा पत्र में जहाँ अमरीका के हृदय में ज्योति जगा दी थी वहीं ऐसे राजभक्तों की कमी नहीं थी जो साम्राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति के विरोधी थे। अमरीकी समाज के उच्च वर्ग में राजभक्ति कुछ अधिक ही प्रबल थी। वस्तुतः इन तथाकथित राजभक्तों ने अमरीकी स्वतंत्रता मार्ग को मद्धिम बना दिया अन्यथा घोषणापत्र के अनुसार यह स्वतंत्रता अमरीका को एक वर्ष के अन्दर ही प्राप्त हो गई होती।

स्वतंत्रता संग्राम

युद्ध-पूर्व-कारक एवं वस्तुस्थिति

जितनी एकता और दृढ़ निश्चय पवित्र घोषणापत्र के शब्दों से झलकता है वैसे ही अगर अमरीकी युद्ध अभियानों में हो जाता तो अमरीका मात्र एक वर्ष में ही स्वतंत्र हो गया होता। कारण जहाँ देश पर 99 प्रतिशत नियंत्रण अमरीकियों का था, वहाँ 3000 मील दूर से दृढ़ प्रतिज्ञ अमरीकियों के खिलाफ युद्ध संचालन ग्रेट ब्रिटेन के लिये अत्यन्त दूरूह था और अंग्रेज भी हृदय से युद्ध में सम्मिलित नहीं हुये थे। अमरीका के स्वतंत्र होने में काफी समय लग जाने का कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में राजभक्तों का होना था। ये लोग मातृ सत्ता के प्रति वफादार थे। उनकी उदासीनता के कारण देशभक्तों को स्वतंत्रता संघर्ष निरन्तर बनाये रखने में अनेक कठिनाइयाँ आईं।

स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में, अगर हम पृष्ठभूमि पर ध्यान दें, तो एक और अहं बात यह थी कि स्वयं ग्रेट ब्रिटेन में अमरीका के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि सम्राट् जार्ज तृतीय को युद्ध के लिये जर्मन सेना का आश्रय लेना पड़ा।

दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम 1936-39 तक स्पेन में हुये गृह युद्ध जैसा था जिसमें वैदेशिक सहायता का बड़ा महत्व था। इस युद्ध में अमरीका को फ्रांस से यदि सहायता न मिली होती तो स्वीचीनता मात्र कोरी कल्पना मिद्ध होकर रह जाती। विद्रोहियों के दमन हेतु

ब्रिटिश कुमुक तेज हवाओं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य इनको अमरीका तक पहुंचने में 10 माह का समय लगता था। बहुत से सैनिक रास्ते में ही मृतप्राय हो जाते। शेष लम्बी यात्रा में दुर्बल हो चुके होते थे। वास्तव में ब्रिटेन के इतिहास में यह युद्ध सभी दृष्टिकोणों से अत्यन्त व्ययी सिद्ध हुआ।

ब्रिटेन की ओर से युद्ध संचालन तत्कालीन उत्तरी सरकार में औपनिवेशिक सचिव लार्ड जार्ज जरमेन ने किया जो उस समय ब्रिटेन में उपहास पात्र था। जरमेन को मिडेन के युद्ध में कायरता पूर्ण कार्यवाही के लिये सैन्य अदालत ने सजा दी थी। लेकिन अपने प्रभाव, चातुर्य और शाही समर्थन के कारण वह सरकार में महत्वपूर्ण पद पा गया था। अंग्रेज सैनिक इस बात पर अपमानित महसूस करते कि उनका नायक अदालत द्वारा घोषित कायर है।

वस्तुतः अंग्रेज सैनिक केवल सैनिक होने के नाते लड़ते थे। देशभक्ति और मनोबल का उनमें सर्वथा अभाव था। अमरीकी क्रांति की सुन्दर विवेचना करते हुये सर जी०ओ० ट्रेविलियन ने लिखा है कि अंग्रेज लोग, अमरीकी विद्रोह का अंग्रेजी जनता के राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में स्वागत करते थे। ब्रिटिश सेना में इतिहासकार सर जान फोर्टेस्क्यू के मतानुसार अमरीकी आन्दोलन की विजय का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि यह आन्दोलन आंग्ल-भाषी स्वतंत्रता प्रेमियों का विप्लव था। यहाँ तक कि अक्टूबर, 1775 में जान विल्किंस ने हाउस आफ कामन्स में घोषणा की कि अमरीका के विरुद्ध युद्ध न्यायहीन शोषण प्रवृत्ति का द्योतक है।

इसके विपरीत दूसरी ओर अमरीकी देशभक्त सेना का अध्यक्ष जार्ज वाशिंगटन प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही सफल सेनानायक सिद्ध हुआ। सेना की वाग-डोर सम्भालने के साथ-साथ वाशिंगटन कांग्रेस, राज्यों के नेताओं तथा राज्य सरकारों से सेना व्यय हेतु आर्थिक सहायता के लिये भी सतत प्रयत्नरत रहे। अपनी सेना के प्रशासकों के पारस्परिक वैमनस्य के समापन हेतु भी वह प्रयत्नशील रहे।

आर्थिक सहायता

संयुक्त राज्य अमरीका के अस्तित्व में आने से पूर्व महाद्विपीय कांग्रेस केवल पूरी तरह राज्यों पर आश्रित थी क्योंकि यह कोई वैधानिक संस्था तो थी नहीं। कांग्रेस केवल प्रस्ताव पारित कर सकती थी, कानून नहीं बना सकती थी पैसा या आपूर्ति बनाये रखने हेतु राज्यों से केवल अनुरोध कर सकती थी, आदेश नहीं दे सकती थी। इसके लिये सेनाध्यक्ष वाशिंगटन ने सेना में राज्यों के अनुसार टुकड़ियाँ गठित की तथा उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी विशेष राज्यों पर तोप दी गयी।

युद्धों के मध्य आन्दोलन को फ्रांस से आर्थिक सहायता निरन्तर प्राप्त होती रहीं फिर स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठान भी देशभक्त बने रहे। धनापूर्ति राष्ट्रीय ऋण पत्रों, राज्य ऋण पत्रों, स्वेच्छक रूप में दी गई नगद राशि अथवा वस्तु तथा अतिरिक्त विदेशी ऋणों के माध्यम से की जाती थी। उस समय एक मुद्रा बहुत प्रचलित हुई जिसे कांटीनेन्टल करेन्सी (महाद्विपीय मुद्रा) का नाम दिया गया लेकिन कुछ न्यूनताओं के कारण 1780 तक इसका लोप हो गया।

इसके साथ धन का दूसरा स्रोत राज्य बनाये गये। इसके अनुसार 50 लाख डालर प्रति राज्य की राशि निर्धारित की गयी। लेकिन यह राशि प्रत्येक राज्य के लिये नकद देना उतना आसान नहीं था। अतः कांग्रेस ने यह निश्चित किया कि शेष राशि राज्य वस्तुओं के रूप में अदा करेंगे। इस व्यवस्था के पश्चात् राज्य अपनी नियत राशि के वृहद् भाग का भुगतान मांस, आटा, रम, कम्बलों कोट आदि के माध्यम से करने लगे।

1776 से कांग्रेस ने 4 प्रतिशत फिर वाद में 6 प्रतिशत की दर से गृह ऋण लेना प्रारम्भ कर दिया लेकिन बाजार व बैंकों में चल मुद्रा का अभाव होने के कारण 1780 तक ऋण कार्यालय बन्द हो गये। इस अवधि तक उस रूप में केवल 6 करोड़ 70 लाख डालर की राशि एकत्र हो सकी। इसके अतिरिक्त फ्रांस से 1777 तक 16 लाख डालर की मदद गुप्त रूप से दे दी थी। इसके बाद फ्रांस वाह्य रूप से 1782 तक इतनी आर्थिक सहायता अमरीका को देता रहा जिससे उसके आन्तरिक ऋणों की अदायगी हो सके। 1781-82 में स्पेन ने भी डेढ़ लाख डालर का सांकेतिक ऋण दिया। शांति प्रयासों के मध्य जान आदम ने नीदरलैण्ड के निजी बैंकरों से भी 13 लाख डालर उधार लिये।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण काफी धन व्यर्थ में ही व्यय हो रहा था। इसलिए 1781 में कांग्रेस ने फिलाडेल्फिया के एक धनी व्यापारी रावर्ट मारिस को वित्त अधीक्षक नियुक्त किया। मारिस ने वित्त व्यवस्था को बड़ी सफलता से सुचारु पूर्वक चलाया। व्यय में भ्रष्टाचार का काफी सीमा तक निवारण कर दिया। यह रावर्ट मारिस के ही सुधारों का परिणाम था कि युद्ध समाप्ति से एक वर्ष पूर्व सैनिकों का वेतन बढ़ गया था तथा उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ भी नियमित रूप से उपलब्ध होने लगी थीं। लेकिन मालगुजारी की व्यवस्था बँसी ही दोषपूर्ण रही। जिसकी क्षतिपूर्ति घरेलू तथा विदेशी कर माध्यमों से की गई।

सैनिक अभियान 1775-77

वास्तविक स्वतंत्रता घोषणापत्र के प्रकाश में आने के पूर्ण से ही महत्वपूर्ण सैन्य अभियान प्रारम्भ हो गये थे, जिनका युद्ध संघर्ष पर काफी प्रभाव पड़ा ।

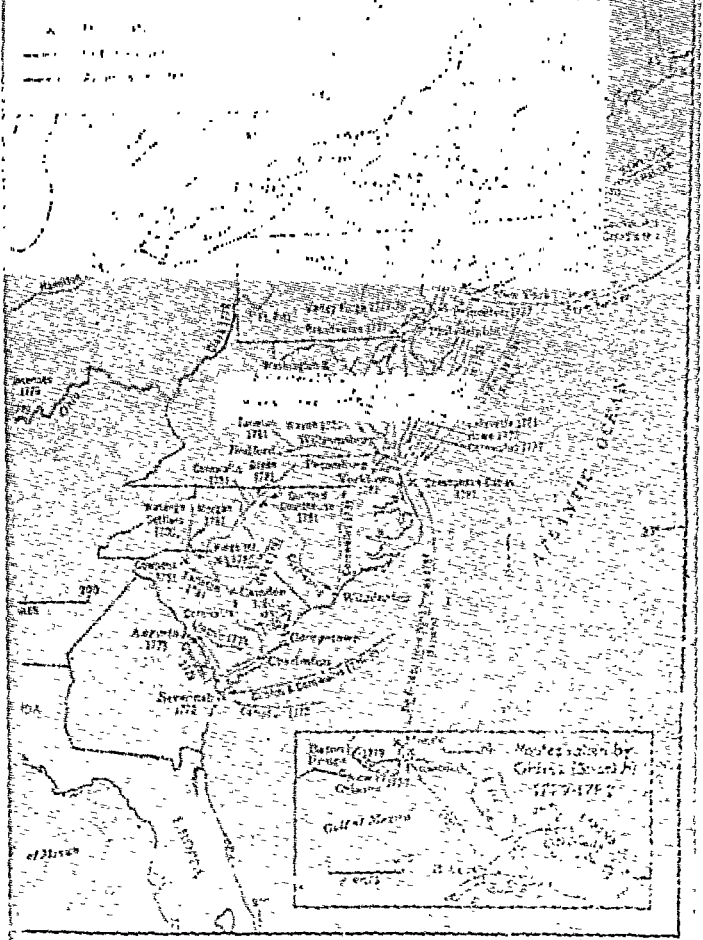
प्रारम्भ में 30 कैरोलीना के राजभक्तों ने मैक डॉ. नाल्ड के नेतृत्व में विलमिंगटन स्थित मूर क्रीक पुल के समीप 27 फरवरी, 1776 को देश भक्त सेना पर हमला करके समुद्री तट तक पहुँचने का प्रयास किया लेकिन वहाँ मिली पराजय के कारण अंग्रेजी सेना उस क्षेत्र में कभी ठीक से स्थित न रह सकी । बाध्य होकर लार्ड कार्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अपना रुख दक्षिणी कैरोलीना के चार्ल्सटन की ओर किया । लेकिन चार्ल्सटन ब्रिटेन ही नहीं स्पेन, (युद्धोमध्य उत्तरी क्षेत्र के निवासी) के लिये भी काफी व्ययी सिद्ध हुआ । जार्ज वाशिंगटन ने चार्ल्स ली के नेतृत्व में दक्षिण में कुमुक भेजी लेकिन ली के वहाँ पहुँचने से पूर्व ही देशभक्तों ने मोलट्री दुर्ग तैयार कर लिया जहाँ से उन्होंने आक्रमणकारी जलपोंतों, को लौटने के लिये विवश कर दिया । क्लिन्टन व कार्नवालिस को बाध्य होकर जनरल होवे के पास न्यूयार्क पर आक्रमण में जुटना पड़ा और 1776 में ब्रिटिश सेना दक्षिण में कोई स्थायित्व न रख सकी ।

मूर क्रीक युद्ध के ही समय उधर जार्ज वाशिंगटन की देशभक्त सेना तथा दक्षिणी राइफलधारियों ने वोस्टन पर 8 महीने तक घेरा डाले रखा । अन्ततः डारचेस्टर पहाड़ी पर अधिकार करने के पश्चात् वाशिंगटन इस स्थिति में पहुँच गया कि किसी भी समय वह वोस्टन को नष्ट कर देता । इन विपन्न परिस्थितियों में जनरल हो ने वहाँ से पलायन करना ही श्रेयस्कर समझा तथा सेन्ट पैट्रिक डे (दिवस) (1776) को वोस्टन नगर खाली कर दिया ।

1775 के प्रारम्भ में शैम्पलेन झील के समीप टिकोनडेरोगा व क्राउन प्वाइंट पर आधिपत्य के पश्चात् वेनडिक्ट आर्नोल्ड नामक उत्साही सैनिक अधिकारी ने कांग्रेस से कनाडा की ओर से आक्रमण करने के लिये स्वीकृति की इच्छा व्यक्त की । अन्ततः 12 नवम्बर, 1775 को रिचर्ड मोन्टगुमरी ने लगभग एक हजार सैनिकों की मदद से शैम्पलेन झील के मार्ग मांट्रियल पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर ली । उधर आर्नोल्ड मेन से होकर क्यूबेक तक पहुँच गया । कनाडा को भी चौदहवें राज्य के रूप में अमरीका में सम्मिलित किये जाने की इच्छा से ऐसा किया गया ।

1776 नव वर्ष के दिन माण्टगुमरी व आर्नोल्ड ने सबसे मजबूत किले

REVOLUTIONARY WAR



क्रांतिकारी अभियान

क्यूबेक पर शीघ्रता में आक्रमण कर दिया जिसके कारण कनाडा पर अमरीकी आधिपत्य नहीं रह सका। इस युद्ध में माण्टगुमरी मारा गया तथा आर्नोल्ड घायल हुआ। देखा जाये तो आर्नोल्ड माण्टगुमरी अभियान ने ब्रिटेन को कनाडा की सुरक्षा के प्रति भी सचेत कर दिया। 1777 के युद्ध अभियान में ब्रिटिश फौज को न्यूयार्क वापस लौट जाने के लिये विवश करना, अमरीकी युद्ध के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक विजय रही।

न्यूयार्क और फिलाडेल्फिया पुनः अंग्रेजों के हाथ में चले गये। उन्हें मुक्त कराने के लिये जार्ज वाशिंगटन ने अप्रैल, 1776 में बोस्टन से न्यूयार्क की ओर प्रस्थान किया। न्यूयार्क में सेना को राजभक्तों के सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ा।

ब्रिटिश सेना भी 2 जुलाई, 1776 तक हो भाइयों के नेतृत्व में न्यूयार्क पहुँच गयी। लेकिन 6 वर्ष के दीर्घ अन्तराल के पश्चात् यहाँ भी अंग्रेज परास्त हो गये। प्रारम्भ में तो वाशिंगटन को काफी पीछे हटना पड़ा तथा उसके पास 18 हजार में से कुल 5 हजार सैनिक रह गये। शनैः शनैः मौरिसटाउन के समीप उसने अपने सैनिकों को पुनर्संगठित किया फिर उसने उन पर विजय प्राप्त की।

ब्रिटिश शक्ति को न्यूयार्क में सबसे गहरा आघात 19 सितम्बर को लगा जब उत्तरी अभियान में आर्नोल्ड ने कुशलता से ब्रिटिश जनरल बरगौयन को परास्त कर दिया। 7 अक्टूबर, 1777 को फीमान फार्म पर हुए दूसरे युद्ध में भी बरगौयन को पुनः पराजय का मुख देखना पड़ा। और वह सारातोगा चला गया और 17 अक्टूबर, 1777 को उसकी सेना ने देशभक्तों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

फ्रांस का युद्ध में सहयोग

फ्रांस 1763 से ही ब्रिटेन को युद्ध में परास्त करने के अवसर में था तथा अमरीका में उसे यह अवसर मिल भी गया। नवम्बर, 1775 में कांग्रेस ने विदेशी मामलों पर एक समिति नियुक्त की तथा 1776 में सिलास डियाने को प्रतिनिधि बनाकर वस्त्र और शस्त्र की व्यवस्था करने हेतु फ्रांस भेजा। फ्रांस के तत्कालीन सम्राट लुई सोलहवें ने एक जाली कम्पनी के माध्यम से इसकी अनुमति अमरीका को दे दी। स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात् फ्रांस से गुप्त रूप से अथवा वाह्य रूप से सहायता प्राप्त करने हेतु वैजामिन फ्रैंकलिन तथा आर्थर को भेजा गया।

फ्रांस के बुद्धिजीवियों ने अमरीकी स्वतंत्रता का उत्साहपूर्वक स्वागत किया सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि फ्रांस उन दिनों यूरोप का एकमात्र निरंकुश राजतंत्र का उदाहरण था। वाल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन दिया। जहाँ एक ओर अमरीका को फ्रांस में जन समर्थन मिला वहीं कूटनीतिज्ञ राष्ट्राध्यक्ष कोत द वर्जेनेस ने फ्रांस के महत्व की रक्षा के लिये अमरीका का साथ देने का निर्देश दिया। साथ-ही-साथ वर्जेनेस ने 1778 में स्पेन का भी आह्वान किया। फ्रांसीसी व्यापारीगण भी अमरीका से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उत्सुक थे। कुल मिलाकर फ्रांस में तात्कालिक वातावरण अमरीकी देशभक्तों के पक्ष में था।

सारातोगा में ब्रिटिश पराजय के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री लार्ड नार्थ अमरीका को शीघ्र ही स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में था लेकिन सम्राट जार्ज अमरीका को किसी भी तरह मुक्त करने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि थोड़े बहुत प्रलोभनों से अमरीकियों को फिर मना लिया जाये। इसी आशय का एक अध्यादेश नार्थ ने नवम्बर, 1777 को ब्रिटिश सांसद के सम्मुख रखा जिसे फरवरी, 1778 में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके अन्तर्गत उपनिवेशों पर लगाया गया संसदीय कर हटाने, उपनिवेशों की इच्छा के विपरीत सेनायें न रखने, 1774 के उत्पीड़क अधिनियमों को वापस लेने, यहाँ तक कि व्यापार अधिनियम भी समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। बदले में अमरीका से सम्राट की अधीनता स्वीकार करने को कहा गया।

यदि यह प्रस्ताव 1775 में प्रेषित किया गया होता तो सम्भवतः ब्रिटेन दीर्घकाल तक अमरीका को अपने पक्ष में रख सका होता। क्योंकि आदम, विल्सन और जैफरसन आदि ने प्रारम्भ में तो केवल रियायतों की बात ही की थी। पूर्ण स्वराज्य की बात तो स्वयमेव ही युद्ध अभियानों में दृढ़ होती चली गयी थी।

इस प्रस्ताव को पारित होने के 11 दिन पूर्व 6 फरवरी, 1778 को फ्रैंकलिन ने वर्जेनेस के साथ संधि की। जिसके अन्तर्गत दोनों राष्ट्र अमरीका को मान्यता मिलने तक साथ निभाने के लिये वचनबद्ध थे। इस संधि से अमरीका को बहुत कुछ प्राप्त हुआ जिसके बदले में उसने वेस्टइंडीज स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशों को सुरक्षा का आश्वासन दिया।

इस संधि के तुरन्त बाद ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया तथा स्वतंत्रता संग्राम विश्वव्यापी हो गया। परिणामस्वरूप 1779 में स्पेन भी फ्रांस की सहायताार्थ युद्ध में प्रविष्ट हो गया जो अमरीकी लक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

1780 तक नीदरलैण्ड को भी, जो उस समय तटस्थ समुद्री शक्ति बन हुआ था, इंग्लैण्ड ने युद्ध में युद्धरत होने के लिए बाध्य कर दिया तथा रूस के कैथरीन द्वितीय ने सशस्त्र तटस्थ संघ संगठित किया जिसके कारण ब्रिटेन तटस्थ व्यापारियों पर आक्रमण नहीं कर सका।

संधि उपरान्त युद्ध अभियान (1778-81)

11 जुलाई, 1778 को फ्रांस ने 17 जलपोत भेजकर अमरीका को खुले तौर पर सहायता देनी प्रारम्भ कर दी। इस सैनिक दल का नेतृत्व कॉर्नेल देस्ताँ था। इस दल ने अपनी वीरता प्रमाणित कर दी लेकिन न्यूयार्क में पराजित होने के बाद यह टुकड़ी वोस्टन चली गयी जहाँ इन फ्रांसीसी सैनिकों और स्थानीय प्रशासकों में एकता नहीं थी। बाद में देस्ताँ की इस कुमुक ने वेस्ट इंडीज की तरफ प्रस्थान किया।

अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम अब तक ऐसी स्थिति में पहुँच चुका था जहाँ दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शीघ्रता में क्रूर आक्रमण किये, परिणाम स्वरूप दोनों में किसी संधि की सम्भावनाओं के विपरीत विद्वेष की अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो गई थी। सर हेनरी क्लिंटन ने न्यूयार्क में भारी मात्रा में सैनिक व साज सामान के साथ होने के बावजूद आंतरिक हिस्सों पर आक्रमण की चेष्टा नहीं की। 1779 में कमोडोर सर जार्ज कोलियर ने चेसापीक खाड़ी के समीप पोर्ट्स माउथ को विध्वंस किया तथा हडसन झील के रास्ते स्टोनी प्वाइंट पर अधिकार कर लिया। इसके प्रति उत्तर में सर जार्ज ने 1779 की ग्रीष्म से पूरे न्यूयार्क पर सफल आक्रमण किया और न्यू हेवन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा फेयरफील्ड व नोरवाक को आग लगा दी। उधर ब्रिगेडियर कैम्पबेल के नेतृत्व में इसी अटलांटिक सामुद्रिक भाग से इंग्लैण्ड ने प्रथम सफलता अर्जित की जब 29 सितम्बर, 1778 को सावन्ना पर अधिकार कर लिया गया। ईस्ट फ्लोरिडा कमान के सेनानायक जनरल अगस्तीन प्रेवोस्ट की सहायता से कैम्पबेल ने जार्जिया को पुनः ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया और वहाँ रायल गवर्नर नियुक्त किया गया।

सावन्ना के बाद प्रेवोस्ट थल मार्ग से चार्ल्सटन की ओर बढ़ा। प्रेवोस्ट चार्ल्सटन पर तो अधिकार नहीं कर सका पर उसकी अनुपस्थिति में एडमिरल देस्ताँ के नेतृत्व में अमरीकी सेनाओं ने सावन्ना पर आक्रमण कर दिया। देस्ताँ और देशभक्तों ने अपने से द्विगणित ब्रिटिश सेना को हताहत कर दिया (9 अक्टूबर, 1779)। इस अभियान में काउंट पोलास्की मारा गया तथा एडमिरल स्वयं दो बार घायल हुआ और फ्रांस वापस लौट गया।

देस्तां की वापसी तथा जाजिया पर पुनः आधिपत्य के पश्चात् जनरल कार्नवालिस ने नवीन रणनीति की योजना बनाई। जिसके अनुसार चार्ल्सटन पर दो ओर से हमला करते हुये महत्वपूर्ण वर्जीनिया राज्य तथा चेसापीक झील को हस्तगत करना था।

कार्नवालिस तथा विलन्टन ने जनवरी, 1780 को दक्षिण की ओर अभियान प्रारम्भ किया। उसके प्रत्युत्तर में कमोडार ह्विपिल की थोड़ी सी सेना चार्ल्सटन की रक्षा न कर सकी। उसका काम बढ़ती हुई अंग्रेज सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना था। अंग्रेजी सेना चार्ल्सटन बंदरगाह से 30 किलोमीटर दूर से थल मार्ग से आगे बढ़ी। यहाँ अमरीकियों को बहुत बुरी पराजय का सामना करना पड़ा जब चार्ल्सटन की रक्षा कर रहे जनरल बैंजामिन फ्रैंकलिन को 5500 सैनिकों के साथ 12 मई, 1780 को हथियार डालने पड़े।

वाशिंगटन ने न्यूयार्क की दक्षिणी सीमा पर स्थित टुकड़ियों को वापस बुलाकर उन्हें दक्षिण की ओर भेज दिया। वाशिंगटन की इच्छा के विपरीत कांग्रेस ने इस कमान की वागडोर होराशियों व गेटे के हाथों में सौंपी। कार्नवालिस ने 16 अगस्त को अयोग्य गेटे को दक्षिणी कैरोलिना स्थित कैमिडोन में बुरी तरह परास्त कर दिया।

इस प्रथम अभियान में ही पराजय हो जाने से अमरीकी अत्यन्त क्षुब्ध थे। उसी समय यह दुःखद समाचार भी प्राप्त हुआ कि वेनेडिक्ट अर्नाल्ड भी अंग्रेजी सेना के साथ मिल गये थे। कार्नवालिस अत्यन्त कुशल सेनानायक था तथा अपनी नीतियों के कारण दक्षिणी कैरोलीना पर उसने अपना अधिकार और सुदृढ़ कर लिया।

कांग्रेस ने इसके बाद गेटे के स्थान पर वाशिंगटन को इच्छानुसार जनरल नवैलियल ग्रीन को भेजा। रोड आइलैण्ड के सपूत ग्रीन को वाशिंगटन के पश्चात् अमरीका का सर्वोत्तम जनरल माना गया। नवैलियल ने सबसे पहले मानसिक रूप से पराजित सेना को पुनर्गठित किया। उसने अमरीकी सेना में नवीन उत्साह का संचार किया। इसके सुनियोजित प्रयास में 11 जनवरी तथा 15 मार्च, 1781 को क्रमशः काउपेन्स तथा गिलफोर्ड कोर्ट हाउस पर कार्नवालिस की सेना को समुद्री तट तक खदेड़ दिया। 8 सितम्बर तक यूटा स्प्रिंग पर आक्रमण करके ग्रीन ने दक्षिणी कैरोलीना के मध्य में अपना अधिकार कर लिया। इधर कार्नवालिस ने विलमिंगटन (उत्तरी कैरोलीना) की कमान के साथ वर्जीनिया के उत्तर में प्रस्थान किया। तथा 1 अगस्त, 1781 को याकंटाउन पर अधिकार करके उसे सैनिक अड्डा बना दिया जहाँ से वह चेसापीक खाड़ी, मेरीलैण्ड, वर्जीनिया पर नियंत्रण रखने में शाही नौसेना की

सहायता कर सके। इसके पश्चात् फ्रांसीसी नौसेना का युद्ध में प्रवेश प्रारम्भ हुआ।

नौसेना तथा यार्कटाउन

प्रारम्भ से ही वाशिंगटन की यह धारणा थी कि नौसैनिक शक्ति का सेना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन 1780 तक अमरीकी सेना ब्रिटिश समुद्री आधिपत्य को चुनौती नहीं दे सकी।

बोस्टन पर घेराव के मध्य वाशिंगटन ने अपनी नौसेना को शक्तिशाली बनाने के प्रयास किये। छापामार किस्म के नौसैनिक अभियानों ने ब्रिटिश सेनाओं तथा क्षतिग्रस्त करने वाले व्यापारिक जहाजों को काफी क्षति पहुँचायी। जो लोग अधिकतर सशस्त्र अमरीकी व्यापारी हुआ करते थे।

सौभाग्य से 1763 तक फ्रांसीसी नौसेना भी पुनर्गठित हो गयी। इसके दूसरी ओर अयोग्यतम ब्रिटिश एडमिरल लार्ड सैण्डविच के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना क्षीण हो गयी।

1779 में लाफायले के अनुरोध पर फ्रांस ने रोशाम्बू के नेतृत्व में 6000 सैनिक अमरीकी सहायता हेतु भेजे जिन्होंने 1780 में न्यूपोर्ट पर अधिकार कर लिया लेकिन अतिरिक्त फ्रांसीसी कुमुक की प्रतीक्षा में रोशाम्बू एक साल तक शान्त बना रहा।

अन्ततः 1 मई, 1781 को फ्रांस ने कौत द ग्रास के नेतृत्व में एक शक्तिशाली वेड़ा भेजा। यार्कटाउन पर दो फ्रांसीसी तथा एक अमरीकी वेड़े कमांडोर कौत द ग्रास के नेतृत्व में रोशाम्बू की सहायता को न्यूपोर्ट पहुँच गया।

तदुपरान्त ग्रास ने न्यूयार्क के अतिरिक्त चेसापीक खाड़ी पर आक्रमण का निश्चय किया। उधर वाशिंगटन ने रोशाम्बू के साथ हडसन झील के मार्ग किंग फेरी की ओर प्रस्थान किया। 4 हजार अमरीकी उत्तरी न्यूयार्क के रक्षार्थ छोड़ दिये गये। 25 अगस्त को ही कामोडोर द ग्रास का वेड़ा न्यूपोर्ट से चेसापीक पहुँच गया।

इन्हीं दिनों मित्र देशों की सेना के मध्य एक घटना यह हुई कि सर सैमुएल हुड व एडमिरल रोडनी के नेतृत्व में इंग्लैण्ड का सर्वश्रेष्ठ वेड़ा ग्रेवस की सहायता हेतु न्यूयार्क की ओर चल पड़ा। जबकि अमरीका की योजना चेसापीक पर हमला करने की थी।

इस योजना का आभास होते ही सर हुड तथा ग्रेवस की संयुक्त अंग्रेजी सेनाओं ने 1 सितम्बर को चेसापीक की ओर प्रस्थान किया। ग्रास के फ्रांसीसी वेड़े ने चेसापीक में 30 अगस्त से ही सैनिक शिविर लगा लिया था।

जैसे ही ग्रेवस का 19 जहाजी वेड़ा चेसापीक पहुँचा, ग्रास ने अपने 28 जहाजी वेड़े को और गहरे लिनहैवन खाड़ी तक पहुँचा दिया। यहाँ ग्रेवस हमला करने का एक अच्छा मौका चूक गया क्योंकि ग्रास दूसरे फ्रांसीसी वेड़े के आने की प्रतीक्षा करना चाहता था। 11 सितम्बर को वरास का वेड़ा भी चेसापीक पहुँच गया। इसके बाद ग्रास ने 16 सितम्बर को कार्नवालिस को यार्कटाउन में घेरने की योजना पर वाशिंगटन तथा रोशाम्बू से सलाह मशविरा किया।

अन्ततः 30 सितम्बर को वाशिंगटन, रोशाम्बू व सेन्ट सिमों के नेतृत्व में वर्जीनिया के देशभक्तों ने साथ मिलकर कार्नवालिस पर आक्रमण किया। जिसमें न्यूनतम रक्तपात के पश्चात् कार्नवालिस ने 17 अक्टूबर, 1781 को आत्मसमर्पण कर दिया।

पुनः एक बार फिर अमरीकियों को अपनी पराजय सी दिखाई दी क्योंकि ग्रास के वेड़े को 12 अप्रैल, 1722 को वेस्टइंडीज जाते समय रोडनी ने पराजित किया जिसके परिणामस्वरूप रोशाम्बू की सेना वेस्टइंडीज भेज दी गयी। फ्रांसीसी सेना के अभाव में, 1781 के अन्त में वाशिंगटन को भी व्हासर प्लेन तक पीछे हट कर क्लिन्टन पर दृष्टि रखनी पड़ी।

वर्ष 1782 में एक मात्र युद्ध पश्चिम अमरीका में हुआ। जार्ज रोजर्सक्लार्क उत्तर पश्चिम में कसकासिया व विन्सेनीज पर अधिकार के पश्चात् डेटायर को ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त कराना चाहता था लेकिन ब्रिटेन ने 1782 में समस्त उत्तर पश्चिम पर भारतीयों के सहयोग से विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद क्लार्क ने 10 नवम्बर, 1782 को स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम थल युद्ध ओहियो में लड़ा जिसमें विजय श्री का श्रेय उसी को प्राप्त हुआ।

फ्रांस अमरीका संधि

यद्यपि 1778 तक अमरीका को युद्ध में काफी हानि उठानी पड़ी थी तथापि अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस की उत्सुकता बढ़ा दी। इसी उत्सुकता व ब्रिटेन से परम्परागत प्रतिद्वंद्विता के कारण फ्रांस 1776 तक अमरीकी स्वतंत्रता संग्राम को गुप्त रूप से सहायता करता रहा। जब अमरीकी सफलता प्रदर्शित होने लगी तभी फ्रांस स्पष्ट रूप से ब्रिटेन के विरुद्ध हो गया।

मारातोंगा की ऐतिहासिक विजय के पश्चात् फ्रांस ने अमरीका के संघर्ष-रत उपनिवेशों के साथ 6 फरवरी 1778 को एक संधि की। इस संधि के निम्न प्राविधान थे।

अनुच्छेद 1. यदि वर्तमान युद्ध मध्य ब्रिटेन तथा फ्रांस में छिड़ जाय तो

संयुक्त राज्य अमरीका तथा सम्राट दोनों मिलकर ब्रिटेन का सामना करेंगे ।

- अनुच्छेद 2. वर्तमान सुरक्षात्मक संधि का प्रत्यक्ष समापन स्वाधीनता, प्रभुसत्ता, तथा स्वतंत्रता की प्रभावशाली स्थापना के बाद ही होगा ।
- अनुच्छेद 3. सफलता प्राप्त होने की स्थिति में यदि संयुक्त राज्य अमरीका ब्रिटिश शक्ति को क्षीण करना चाहेगा तो वह उत्तरी राज्यों अथवा वरमुदा के द्वीपों का भविष्य निर्धारण स्वयं करेगा ।
- अनुच्छेद 4. 1763 की पेरिस संधि के अन्तर्गत उत्तरी अमरीका के वह समस्त भाग जो ब्रिटेन के अधीन थे, संयुक्त राज्य अमरीका को प्राप्त होंगे तथा उन पर फ्रांस को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त न होगा ।
- अनुच्छेद 5. मोक्सेको की खाड़ी में स्थित ब्रिटिश अधिकृत द्वीपों पर यदि फ्रांस कब्जा कर लेगा तो वे समस्त द्वीप फ्रांस के सम्राट के अधीन माने जायेंगे ।
- अनुच्छेद 6. अमरीका की स्वतंत्रता प्राप्त तक कोई भी भागीदार युद्ध से एक पक्षीय विराम संधि करेगा ।
- अनुच्छेद 7. युद्ध के किसी भी घटनाक्रम के परिणामस्वरूप इस संधि के अन्तर्गत कोई भी भागीदार किसी भी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं होगा ।
- अनुच्छेद 8. फ्रांस के सम्राट तथा संयुक्त राज्य अमरीका उन सभी राष्ट्रों का आह्वान करते हैं, जो किसी भी प्रकार ब्रिटेन से उत्पीड़ित हों ।
- पेरिस में शान्ति प्रयास

यार्क टाउन की विजय के पश्चात् भी जार्ज तृतीय ने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में अमरीका से वंचित रहने के लिये तत्पर नहीं हूँ जबकि प्रधान-मंत्री लार्ड नार्य स्थिति की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुये अमरीका को पूर्ण स्वतंत्रता दिये जाने के पक्ष में था इसी विचार धारा के कारण उसे सम्राट का कोमभाजन बनना पड़ा । उसे प्रधानमंत्री पद त्यागने के लिये कहा गया । जार्ज तृतीय ने राकिंघम को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया ।

राकिंघम ने ही विवादास्पद टिकट अधिनियम को समाप्त किया था । उसने शेलवर्न, चार्ल्सजेम्स फोक्स को लेकर सरकार का गठन किया । ये सभी विचारधारा से पारम्परिक अमरीकी मित्र थे ।

तदुपरान्त मार्च, 1782 में शेलवर्न ने रिचर्ड ओसवालड को डा० फ्रैंकलिन से मुलह के लिये पेरिस भेजा, । फ्रैंकलिन अमरीकी कांग्रेस द्वारा शान्ति वार्ता

के लिये चुने गये 5 लोगों के आयोग में फ्रैंकलिन के अतिरिक्त जान आदम, थामस जैफरसन, जान जे. तथा हेनरी लारेन्स थे। फ्रांस की सहमति पर ये लोग किसी प्रकार का समझौता करने के लिये अधिकृत थे।

इटाली और समझौता वार्ता प्रारम्भ होने के पूर्व स्थित फ्रांसीसी मंत्री ने शर्त रखी कि अमरीका वर्जनेस फ्रांसीसी प्रधान मंत्री के नियंत्रण में रखा जाये।

उधर 12 अप्रैल, 1782 को फ्रांसीसी एडमिरल की पराजय से ब्रिटेन ने वेस्टइंडीज व जिब्राल्टर पर अधिपत्य स्थापित करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उसके विपरीत अमरीकी दीर्घगामी युद्ध में रत होने के कारण क्षुब्ध थे।

जब ओसवाल्ड संधि पत्र के साथ पेरिस पहुँचा तो अमरीकी आयोग के एक सदस्य जान जे. ने विश्वासपात्र सुलहवार्ता के लिये ओसवाल्ड को दस्तावेजों के साथ आने को कहा।

ओसवाल्ड लगभग 6 माह पश्चात् वापस लौटा। अंततः सितम्बर, 1782 के अंत में संधि वार्ता का प्रारम्भीकरण हुआ। पारस्परिक वार्ता के मध्य पश्चिमी अमरीका के प्रस्ताव पर फ्रांस इच्छुक था कि स्पेन को भी वार्ता में सम्मिलित किया जाये लेकिन जे. ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया।

30 नवम्बर, 1782 को फ्रांस की उपस्थिति में अमरीका और ब्रिटेन के मध्य प्रारम्भिक संधि हुई। इसमें यह प्राविधान था कि जब तक फ्रांस भी स्वतंत्र रूप से ब्रिटेन से अपने प्रस्तावों में वार्ता नहीं करता तब तक यह संधि प्रभावहीन समझी जाये।

20 जनवरी, 1783 को इंग्लैण्ड और फ्रांस ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। अमरीका और इंग्लैण्ड के बीच युद्ध विराम लागू नहीं हो सका था।

अन्ततोगत्वा 3 सितम्बर, 1783 से वास्तविक युद्ध विराम को मान्यता प्रदत्त की गई।

पेरिस शान्ति का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि यह एक विचित्र संधि थी। एक ओर जहाँ ब्रिटेन में अमरीका को स्वतंत्र राज्य की मान्यता दी वहीं कैंसटाइन, न्यूयार्क, चार्ल्सटाउन, सावन्ना, डेट्रयाट व उत्तर सीमा के अनेक क्षेत्र अभी भी उनके अधीन थे। इस संधि के अन्तर्गत सीमा रेखा का निर्धारण अत्यन्त अस्पष्ट रूप से किया गया जिसके फलस्वरूप उत्तर पूर्व सीमा 1842 तक विवादास्पद बनी रही।

अमरीका को संधि के अनुसार ब्रिटिश उत्तरी अमरीका में मछली पकड़ने

की सुविधा दी गई। इसके साथ इस बात की व्यवस्था की गई कि युद्ध पूर्व के ऋणों की वापसी के लिये किसी प्रश्न पर कानूनी दवाव नहीं डाला जायेगा।

इंग्लैण्ड, फ्रांस और स्पेन के बीच उसी दिन हुई संधि में इंग्लैण्ड ने जिब्राल्टर के बदले स्पेन को पूर्व व पश्चिम फ्लोरिडा का क्षेत्र सौंप दिया गया। इस प्रकार उत्तरी अमरीका का स्पेन, ब्रिटिश साम्राज्य व संयुक्त राज्य अमरीका के बीच विभाजन हो गया। इसमें स्पेन को मिसिसिपी के पश्चिम और दक्षिण का वृहद भाग मिल गया। लेकिन कालान्तर में 1846 तक अमरीका ने स्पेन के रियो ग्राण्ड तक पीछे हटा दिया।

फ्रांस की सन्धि में एक मात्र उपलब्धि वेस्टइंडीज द्वीपों पर अधिकार तथा अमरीका से व्यापारिक सम्बन्ध की सम्भावनायें मिलीं।

इस संधि के निम्न प्राविधान थे :—

- अनुच्छेद 1. ब्रिटेन के सम्राट जार्ज तृतीय संयुक्त राज्य अमरीका अर्थात् न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, टोड आइलैण्ड, कनेक्टिकर, न्यूयार्क, न्यूजेरसी, पैन्सिलवानिया, डेलावेयर, मैरीलैण्ड, वर्जीनिया, उत्तरी व दक्षिणी कैरोलीना तथा जार्जिया को स्वतंत्र एवं स्वाधीन घोषित करते हैं एवं वह तथा उनके उत्तराधिकारी इन राज्यों पर अपनी समस्त प्रभुसत्ता समाप्त करते हैं।
- अनुच्छेद 2. इस अनुच्छेद द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की सीमाएँ निर्धारित की गईं।
- अनुच्छेद 3. इस अनुच्छेद द्वारा अमरीका मत्स्य सीमा एवं उसके मत्स्य व्यापार को मान्यता प्रदान की गई।
- अनुच्छेद 4. इस अनुच्छेद में किसी भी पूर्व ऋण की अदायगी की कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई।
- अनुच्छेद 5. प्रत्येक उपनिवेश के निवासियों को कहीं भी जाने की सुविधा निर्विकार रूप से प्राप्त होगी।
- अनुच्छेद 6. समस्त जनता को उसके जीवन, सम्पत्ति तथा अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त होगी।
- अनुच्छेद 7. ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मध्य उत्पन्न समस्त वर्तमान मतभेद, विषमता एवं पारस्परिक कटुता को समाप्त समझा जाये तथा दोनों पक्षों के युद्ध बंदी स्वतंत्र किये जाँय।
- अनुच्छेद 8. मिसिसिपी नदी में व्यापार की स्वतंत्रता अमरीका के साथ ब्रिटेन तथा उसके निवासियों को भी प्राप्त होगी।
- अनुच्छेद 9. इन प्राविधानों के पूर्व यदि कोई क्षेत्र किसी संधिवार्ता द्वारा

हस्तगत कर लिया जाता है तो वह बिना किसी क्षतिपूर्ति अथवा दुर्भावना के वापस कर दिया जायेगा।

अनुच्छेद 10. इस संधि की पुष्टि 6 माह के भीतर कर दी जायेगी।

उपसंहार

अमरीका की इस क्रान्ति ने अमरीका के जीवन दर्शन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। 1763 से 1783 तक अमरीका में राजनीतिक दर्शन का आविर्भाव हुआ जिसमें उनके विचारों को समन्वित किया गया। स्वतंत्रता घोषित कर उपनिवेशों की राज्य सरकारों में परिवर्तन किया गया और संविधान के अनुच्छेदों की छाया में नव-राष्ट्र-संयुक्त राज्य अमरीका का निर्माण हुआ। अमरीका की राजनैतिक गति निःसन्देह क्रान्तिकारी थी, परन्तु क्रान्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत हैं।

कुछ इतिहासकार क्रान्ति को औपनिवेशिक विद्रोह मानते हैं, जिसका ध्येय मात्र ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इन इतिहासकारों के अनुसार औपनिवेशिक समाज लोकतांत्रिक समाज था और अमरीकी इस बात पर सहमत थे कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पश्चात् भी वर्तमान सामाजिक मूल्यों को स्वतंत्रता का आधार माना जायेगा। अन्य इतिहासकारों के अनुसार क्रान्ति का स्वरूप हिंसात्मक, सामाजिक संघर्ष एवं वर्ग संघर्ष था।

उग्रपंथी निम्न वर्ग ने उपनिवेशवाद के अलोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल कर लोकतांत्रिक समाज की माँग की। इस प्रकार इतिहासकारों ने अमरीकी क्रान्ति की विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्या की है।

राष्ट्रवादी मत

जार्ज वेनक्राफ्ट ने अपने अध्ययन में क्रान्ति को मानवता की प्रगति का स्वर्ण युग बताया। उन्होंने क्रान्ति को मानव स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता की संज्ञा दी। उनके अनुसार अमरीका ने स्वाधीनता एवं प्रगति की ज्योति प्रज्वलित की और ब्रिटेन की निरंकुशतावादी-प्रतिक्रियावादी नीतियों का बहिष्कार किया। वेनक्राफ्ट ने अमरीकी क्रान्ति के स्वरूप को उग्रवादी बताया, क्योंकि उसके द्वारा चिरस्थायी शान्ति एवं भ्रातृत्ववाद की पुष्ट परम्परा विकसित हुई। वेनक्राफ्ट ने अमरीकी क्रान्ति को हितकर प्रशंसा की। उनके विचार में अपनी स्वतंत्रता के उद्देश्य एवं निष्ठा के प्रति अमरीकी समाज संगठित था।

वेनक्रॉफ्ट ने अमरीका के इतिहास की राष्ट्रवादी परम्परा पर व्याख्या की तथा उन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अमरीकियों को पुनः इस तथ्य से अवगत कराने की चेष्टा की कि वह इस महाक्रान्ति को सदैव स्मरण रखें क्योंकि इसी के द्वारा वह आपसी संघर्षों को विस्मृत कर संगठित हुये थे ।

20वीं शताब्दी के परिवर्तन काल में वेनक्रॉफ्ट के राष्ट्रपिता की भावना से ओतप्रोत, अध्ययन के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हुई । इस प्रतिक्रिया के दो प्रमुख कारण थे । प्रथम ब्रिटेन और अमरीका के मध्य 1870 की वार्षिकगटन संधि ने पुनः दोनों देशों की विचारधाराओं के पारस्परिक मिलाप की चेष्टा की, द्वितीय अमरीका में प्रगतिशील एवं लोकवादी आन्दोलनों ने भी अमरीकी बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया । इस नवीन विचारधारा ने क्रान्ति का लोक विकास के अन्तर्गत अध्ययन करना आरम्भ किया । इस नवीन व्याख्या के अन्तर्गत दो मत सामने आये जिन्होंने वेनक्रॉफ्ट के विचारों में संशोधन किया । इसमें साम्राज्यिक तथा प्रगतिशील मत के इतिहासकार थे ।

साम्राज्यिक मत

साम्राज्यिक मत के इतिहासकारों में प्रमुख जार्ज वीयर, चार्ल्स एण्ड्रूज तथा लारेन्स जिप्सन थे । इनके विचार में क्रान्ति का अध्ययन एक संकीर्ण परिधि में सीमित नहीं किया जा सकता है । उन्होंने अमरीकी समाज तथा अंग्रेजों के मध्य स्थापित सम्बन्धों की व्याख्या करना उचित समझा । उनके विचार में मूल देश (मातृ देश) की नीतियों का विश्लेषण किये बगैर बहिष्कार करना तर्क संगत नहीं था । इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियां इतनी अनुचित नहीं थीं, जितनी कि वेनक्रॉफ्ट ने अपने अध्ययन में उनकी आलोचना की है । वीयर ने 1893 से 1912 तक चार प्रबन्ध लेख लिखे । इन लेखों में वीयर ने सत्रहवीं और अठ्ठारहवीं शताब्दी में अंग्रेजों की व्यापारिक नीति का विश्लेषण करते हुये यह मत प्रकट किया कि औपनिवेशिक एक उदार एवं प्रबुद्ध पद्धति के आधीन कार्य कर रहे थे । एण्ड्रूज ने अपने चारभागीय अध्ययन में ब्रिटेन के पोतपरिवहन अधिनियमों को औपनिवेशिकों के प्रति लाभ एवं हानि दोनों से युक्त बताया । इसके अतिरिक्त एण्ड्रूज के अनुसार उत्तरी अमरीका में ब्रिटेन का साम्राज्य आरम्भ से लेकर क्रान्तिपर्यन्त दो आन्दोलनों से लक्षित था । उपनिवेश स्वशासन की ओर अग्रसर थे और मूल देश अपने साम्राज्य पर सशक्त नियंत्रण के इच्छुक थे । इस प्रकार एण्ड्रूज के विचारानुसार ब्रिटेन की परम्परावादी विचारधारा

तथा उपनिवेशकों की उग्रवादी परिवर्तन की प्रवृत्ति ने संवैधानिक मतभेद उत्पन्न किया जिसके द्वारा क्रान्ति का बीजारोपण हुआ।

जिप्सन ने अपने बहुखण्डीय अध्ययन "दि ब्रिटिश एम्पायर विफोर दि अमेरिकन रेवोल्यूशन" में ब्रिटेन के औपनिवेशिक कर व्यवस्था को उचित बताया क्योंकि उनके विचार में उत्तरी अमरीका के उपनिवेशों की सुरक्षा में ब्रिटेन का धन एवं रक्त दोनों रूप में योगदान था। इस मत के इतिहास-वेत्ताओं एवं विद्वानों ने संक्षेप में संवैधानिक एवं परस्पर विरोधी सामाजिक संघर्ष को अमरीकी क्रान्ति के स्रोत की मान्यता दी।

प्रगतिशील मत

प्रगतिशील मत के इतिहासकारों ने साम्राज्यिक मत के इतिहासकारों से प्रथक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार अमरीकी क्रान्ति के मुख्य कारण सामाजिक एवं आर्थिक थे। प्रगतिशीलवादियों में कार्ल ब्रेकर, चार्ल्स वीयर्ड, आर्थर श्लेसिंगर (सीनियर) तथा फ्रैंकलिन जैम्सन प्रमुख थे। कार्ल ब्रेकर ने अमरीकी क्रान्ति को एक न मान कर दोहरी क्रान्ति की संज्ञा दी। प्रथम बाह्य क्रान्ति जिसका उद्देश्य ब्रिटेन के प्रति औपनिवेशिक विद्रोह था- जिसका कारण उपनिवेशों तथा मूल देश का पारस्परिक आर्थिक संघर्ष था। द्वितीय आन्तरिक क्रान्ति थी जो वर्ग संघर्ष पर आधारित थी-अर्थात् अग्रेजों के जाने के पश्चात् कौन सा वर्ग शासनारूढ़ होगा ? इस प्रकार ब्रेकर की—- क्रान्ति का अध्ययन इस पर आधारित था कि गृह शासन कौन होगा और शासक वर्ग कौन होगा ?

चार्ल्स वीयर्ड ने यद्यपि क्रान्ति से सम्बन्धित लेखन नहीं किया परन्तु उनके अध्ययन के द्वारा विद्वानों को क्रान्ति युग के अमरीकी इतिहास में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। चार्ल्स वीयर्ड के मतानुसार अमरीकी समाज में समृद्ध एवं निर्धन कृषक एवं व्यापारिक ऋणदाताओं एवं महाजन के मध्य आर्थिक तथ्यों को लेकर जो संघर्ष उत्पन्न हुआ उसने क्रान्ति युग की आधार भूमि बनाई। उसके साथ ही चार्ल्स वीयर्ड ने प्रगतिशील इतिहासकारों को 1760-1780 तक के समय का स्पष्ट अवलोकन करने का सुअवसर प्रदत्त किया। वीयर्ड के अनुसार उपरोक्त युग अमरीकी सामाजिक वर्ग में एक अनवरत आर्थिक संघर्ष का समय था। आर्थर श्लेसेंजर ने अपने अध्ययन में आर्थिक तथ्यों को लेकर वर्ग संघर्ष की प्राथमिकता दी। श्लेसेंजर ने 1763-1776 के मध्य औपनिवेशिक व्यापारिक वर्ग का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया कि यह रूढ़िवादी ने क्रान्ति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्लेसेंजर

के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्यिक नियंत्रण की कठोर नीतियों के कारण व्यापारिक वर्ग संतुष्ट था। श्लेसेन्जर ने इस तथ्य को भी घोषित किया कि 1770 के पश्चात् व्यापारियों का संघर्ष अपने मूल देश के प्रति न्यून होता गया क्योंकि व्यापारी समय के साथ उग्रवादी निम्न वर्ग से भयभीत था। श्लेसेन्जर ने अपने अध्ययन में यह भी प्रेषित किया कि व्यापारिक वर्ग जो क्रान्ति के समय निम्न वर्ग के प्रति प्रतिस्पर्धित था, वही वर्ग संविधान की रचना के समय संगठित हो गया। इस प्रकार श्लेसेन्जर ने संविधान को क्रान्ति का विरोधालंकार की मान्यता दी।

प्रगतिशील मत के एक अन्य इतिहासकार फ्रैंकलिन जेम्सन ने भी क्रान्ति का कारण वर्ग संघर्ष को माना परन्तु इनके अनुसार क्रान्ति एक सामाजिक आन्दोलन था जिसमें निम्न वर्ग अधिकाधिक अधिकार प्राप्ति का इच्छुक था। जेम्सन के अनुसार सामाजिक और आर्थिक सुधारों ने तथा भूमि वितरण ने अमरीकी समाज में विघटन उत्पन्न किया जिसके द्वारा क्रान्ति ने जन्म लिया।

नवरूढ़िवादी मत

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् एक नवीन नवरूढ़िवादी विचारधारा के इतिहासकारों का मत प्रकट हुआ। इन इतिहासकारों ने प्रगतिशील मत के इतिहासकारों के अध्ययन को चुनौती दी। इन दो मतों के विद्वानों का मूल रूप से असहमति दोनों पक्षों के औपनिवेशिक युग के अध्ययन के दृष्टिकोण में थी। नवरूढ़िवादी इतिहासकारों के मतानुसार क्रान्ति एक रूढ़िवादी आन्दोलन था जो उपनिवेशों में लोकतंत्रिक प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने हेतु किया गया। इस मत के विद्वानों ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा को मान्यता नहीं दी अपितु सामान्य मतैक्य को क्रान्ति का जनक माना। औपनिवेशिक जन समुदाय को स्वतंत्रता सम्बन्धी सिद्धांतों पर मतैक्य होने के कारण एक मूल भावना का उद्भव हुआ जिसने क्रान्ति का मार्ग प्रदर्शित किया। रूढ़िवादी मत के विद्वानों में रावर्ट ब्राउन और डेनियल वूरस्टिन ने अमरीका के इतिहास के उस युग में वर्ग संघर्ष एवं विच्छेद के स्थान पर मतैक्य एवं निरंतरता को मुख्य विचाराधारा की संज्ञा दी।

रावर्ट ब्राउन ने अपने अध्ययन में प्रगतिशील इतिहासकारों के मत का खंडन करते हुये यह विचार व्यक्त किया कि उस समय में अमरीकी समाज अलोकतांत्रिक नहीं था। ब्राउन के अनुसार उस समय का अमरीकी समाज लोकतंत्रिक मूल्यों पर आधारित था और क्रान्ति का उद्देश्य उन मूल्यों की रक्षा करना था।

इस प्रकार डेनियल वूरास्टिन ने भी क्रान्ति को एक रूढ़िवादी आन्दोलन की संज्ञा दी। उनके विचार में अमरीकी औपनिवेशक पारम्परिक अधिकारों एवं स्वाधीनता के प्रति सजग थे और ब्रिटेन से इसीलिए उनका संघर्ष था। वूरास्टिन ने क्रान्ति को औपनिवेशक विद्रोह की संज्ञा दी क्योंकि उनके विचार में अमरीका का जन्म प्रमाणक स्वतंत्रता का घोषणापत्र था न कि मानव अधिकार घोषणापत्र/इस तथ्य को लेकर वूरास्टिन ने अमरीकी क्रान्ति को आधुनिक युग के रूढ़िवादी औपनिवेशक विद्रोह का मान्यता दी। वूरास्टिन ने अमरीकी क्रान्ति को राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत उपज नहीं माना, क्योंकि उनके मतानुसार अमरीकी क्रान्ति में न तो कोई विस्मार्क था, न कोई कँवर और न ही कोई राष्ट्रीय दर्शन था। उनके विचार में अमरीकी क्रान्ति उपनिवेशवाधियों का अपने अधिकारों के प्रति विद्रोह था जो अमरीका को स्वतंत्र कराने में सिद्ध हुआ।

एक अन्य नवरूढ़िवादी इतिहासकार एडमंड मोरगन ने अमरीकी क्रान्ति को संवैधानिक अधिकारों की सजगता से ओत-प्रोत बताया। नवरूढ़िवादी इतिहासकारों ने अमरीकी क्रान्ति को एक परिमित रूढ़िवादी आन्दोलन की संज्ञा दी क्योंकि उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों से अधिक संवैधानिक एवं वैचारिक तथ्यों को प्राथमिकता दी। इस प्रकार इन इतिहासकारों के विचार में अमरीका का क्रान्ति युग वैचारिक संवैधानिक आन्दोलन तथा अमरीकी जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का संघर्ष था।

एक अन्य विद्वान वनार्ड वेलियन ने 1750 से 1776 के युग में प्रकाशित पुस्तिकाओं का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि अमरीकी क्रान्ति का पय प्रदर्शित करने का श्रेय अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी सामान्य विधि तथा प्रबुद्ध चिंतकों ने अमरीकी क्रान्ति को जागरूकता प्रदत्त की।

अमरीकी क्रान्ति औपनिवेशी सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के विभिन्न मूल्यों के द्वारा आरम्भ हुई। अमरीकी क्रान्ति एक स्वयं सफल क्रान्ति थी। इरविंग क्रिस्टोल के अनुसार कि अमरीकी क्रान्ति एक वास्तविक क्रान्ति थी, परन्तु जिस प्रकार अन्य सफल क्रान्तियों के साथ सामाजिक एवं राजनैतिक दोषों का गठबन्धन रहा है। अमरीका की क्रान्ति भी उससे पृथक नहीं थी। इरविंग क्रिस्टोल ने यह भी स्पष्ट किया कि अमरीकी क्रान्ति फ्रांसीसी क्रान्ति की भांति आधुनिक नहीं थी क्योंकि इस क्रान्ति ने जन-साधारण को भविष्य के प्रति कोई आश्वासन नहीं दिया परन्तु जन-साधारण को सुगमय जीवन का लक्ष्य बोध प्राप्त करने की प्रेरणा दी। एक अन्य इतिहासकार रावर्ट निस्वत

ने अमरीकी क्रान्ति को परिक्षिप्त की संज्ञा दी क्योंकि उनके विचार में अमरीका में क्रान्ति के पूर्व और क्रान्ति के पश्चात् रूस, इंग्लैण्ड और फ्रांस की भाँति राजनैतिक शक्ति केन्द्रित थी। राबर्ट निस्वत ने अमरीकी समाज के एकीकरण और संगठन का श्रेय धर्म को भी दिया। उनके विचार में अमरीकी क्रान्ति केवल एक स्थानीय क्रान्ति नहीं थी अपितु एक व्यापक आन्दोलन था। थॉमस जैफरसन ने जॉन एडम्स को लिखा कि जुलाई, 1776 में ज्योति प्रज्वलित हुई वह अपने में इतनी परिपूर्ण थी जिसको निरंकुशता की अशक्त धारा शान्त नहीं कर सकती थी।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अमरीकी क्रान्ति जन-साधारण में प्रवाहित वह धारा थी जिसने उनकी आत्मा में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। इस प्रकार स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता की आत्मिक लगन ने निरंकुशता, परतंत्रता तथा राजनैतिक केन्द्रियता के विरुद्ध मानवता की भावना को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की। इस क्रान्ति ने अमरीका के जनजीवन में स्वशासन, स्वधर्म एवं स्वदेश की भावना उत्पन्न कर एक सफल क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

संवैधानिक युग

क्रान्ति युग में अमरीका के राजनैतिक भविष्य के प्रति उत्पन्न आशंकाये निर्मूल नहीं थी। अमरीका तेरह स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित था एवं उनके पास किसी भी प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता का कारण उपस्थित नहीं था। इन उपनिवेशों में प्रजातांत्रिक तथा अभिजातीय दोनों प्रकार का राजनैतिक झुकाव दृष्टगत था। सम्पूर्ण अमरीकी समाज वर्गों में विभाजित था। क्रान्ति युग के प्रणेता उच्च वर्ग के लोग थे तथा उनकी संधि एक ऐसे समाज को स्थापना में थी जिसमें उनके स्वार्थ पूर्णरूपेण सुरक्षित रह सके। इस वर्ष के अभिजातीय मान्यताओं के पोषक सम्पूर्ण आर्थिक श्रोतों के केन्द्रीयकरण में विश्वास रखते थे परन्तु उस काल की प्रजातांत्रिक शक्तियों ने पूँजी के विभाजन हेतु जो आवाज उठाई उसमें तत्कालीन अमरीकी वातावरण में एक वैचारिक द्वन्द उत्पन्न कर दिया। तथापि दोनों ही वैचारिक ध्रुव निजी सम्पत्ति की सुरक्षा की पक्षधर थी। यही कारण था कि "संवैधानिक सम्मेलन के आयोजन हेतु सर्वसाधारण का मत लेना उचित नहीं समझा गया तथा प्रतिनिधियों के चुनाव हेतु पूँजी की योग्यता को मान्यता दी गई। अधिकतर राज्यों ने सीधे पूँजी को ही मत प्रदान करने की योग्यता प्रदान की तथा शेष ने कर देने वालों को मत के अधिकार से वंचित रखा।"

शासन की शैली के लिए उत्पन्न द्वन्द के मूल में भी यही आर्थिक मूल्य कार्यरत थे। एक तरफ जहाँ उच्च, कुलीन एवं अभिजात्य वर्ग के एक राष्ट्रीय शासन तथा समस्त शक्तियों के केन्द्रीयकरण का हिमायती था, प्रजातांत्रिक मूल्यों के पोषक राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासन के स्थापना की दिशा में कार्यरत था। प्रथम विचारों के मूल में जहाँ उद्योग तथा वाणिज्य की सुरक्षा का प्रश्न निहित था, विरोधी विचार उसमें उत्पीड़न का श्रोत देख रहे थे तथा उनके विचार में विकेन्द्रीत शासन अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली सम्भव प्रतीत हो रहा था।

आधुनिक अमरीका के निर्माण में इन दोनों ही विचारधाराओं का पर्याप्त सहयोग रहा है। जैफरसन के प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों में यदि अमरीकी जनता ने पृथक मूल्यों का विकास किया तो इसके विरोधी शक्ति ने अमरीका में समृद्धि, शक्ति एवं मान सम्मान का समावेश कराया। जैफरसन के ही प्रयत्नों के कारण अमरीका ने अपने नव निर्माण में वर्ग द्वन्द को स्थान नहीं दिया तथा वहाँ का समाज प्रवाहमय मूल्यों से ओत-प्रोत होता गया। परन्तु इसके विपरीत हैमिल्टन ने अमरीका को एक केन्द्रीय शक्ति में बाँधा जिसके कारण अति-रिक्त पूँजी का विकास वृद्धि हुआ एवं जिस पूँजी की सहायता से वहाँ की उत्पादन क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इस नीति के ही कारण विभिन्न वर्गों को पूँजी सुरक्षा, उत्पादनों के लिये चुंगी, आयात-निर्यात के लिए सुरक्षित सागर तथा बन्दरगाह पूँजीपतियों के लिये सुरक्षित मुद्रा, सामाजिक व्यवस्था के लिए उपर्युक्त विधि-विधान तथा इन सबके लिये एक शक्तिशाली केन्द्र की प्राप्ति संभव हो सकी।

स्वतंत्रता संग्राम के प्रारम्भिक वर्षों में अराजक तत्वों का हस्तक्षेप रहा। न्यायालयों का महत्व समाप्त हो गया एवं राज्य कर सम्बन्धी विधि निरंकुश हो गई। परन्तु इसके तत्काल पश्चात् ही अमरीका ने राजनैतिक आदर्शों पर आधारित विधि का निर्माण कर लिया तथा राज्य संविधानों की सहायता से इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा में किये गये वायदों को यथा-सम्भव पूर्ण करना प्रारम्भ कर दिया। जेम्स मेडिसन ने भी कहा है विश्व अमरीका में स्थापित स्वतंत्र शासन की प्रणाली पर आश्चर्य चकित रह गया क्योंकि निश्चय ही यह विश्व का प्रथम अनुभव था।'

एकता का अधिनियम

1775 मे 1781 तक सभी तरह उपनिवेशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक केन्द्रीय कमेटी (महाद्वीपीय कांग्रेस) के रूप में युद्ध का संचालन किया जा रहा

था। अतः देश की अखण्डता के लिए आवश्यक था कि सभी उपनिवेशों को सूत्रबद्ध किया जाय। कांग्रेस ने जान डिकिंसन की अध्यक्षता में परिसंघ एवं 'एकता अधिनियम' को लिखने के लिए कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी ने उसको 17 नवम्बर, 1777 को पूर्ण कर राज्यों को सौंप दिया तथा 1778 की मध्य गर्मियों तक दस राज्यों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। मैरीलैण्ड ही एक ऐसा राज्य था जिसने 1 मार्च, 1781 तक इस अधिनियम को अपनी सहमति नहीं दी थी जिसके कारण परिसंघ एवं 'एकता अधिनियम' सन् 1781 तक लागू न हो सका।

संघवाद का सिद्धान्त

संघवाद के सिद्धान्त को 1781 के परिसंघ के अनुच्छेद में समाविष्ट किया गया। इस सिद्धान्त का अर्थ था, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासकीय शक्तियों में शक्ति समन्वय। इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक राज्यों को राष्ट्रीय कांग्रेस में समान प्रभुत्व प्राप्त था किन्तु यह प्रभुत्व केवल राज्यों पर था न कि व्यक्तियों पर। यह सिद्धान्त अपने आप में एक अप्रभावी सिद्धान्त था जिसके कारण अनुच्छेदों का प्रभाव क्षीण रहा तथा नवीन सरकार की नीतियाँ दुर्बल रहीं अतएव 1783 के पेरिस की सन्धि से 1789 से वाशिंगटन के शुभारम्भ तक अमरीका में एक शशक्त शासन की स्थापना की माँग निरन्तर बनी रही। वहाँ एक ऐसी सरकार की आवश्यकता थी जो आन्तरिक करों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी मामलों में समान रूप से प्रभावी व शक्तिशाली हो। उन्हें एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेतृत्व तथा राष्ट्रीय न्यायालय की भी आवश्यकता थी। इस अधिनियम का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व को निरन्तर बनाये रखना था। कांग्रेस को केवल युद्ध तथा शान्ति सम्बन्धी अधिकार ही सौंपे गये थे, इसको कर व्यापार सम्बन्धी कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। केवल कांग्रेस, डाकघर तथा धातु-सिक्कों का मूल्यांकन, भार उत्तोलक आदि का मापक स्थापित करना तथा कुछ विशेष प्रकार के विवादों को निर्णय करने का ही अधिकार था। ये सभी अधिकार इन राज्यों को पहले भी प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त इन्हें अन्य कोई भी अधिकार नहीं प्रदान किये गये। भूमि सम्बन्धी-नीति के बारे में भी अधिनियम ने कांग्रेस को कोई भी स्पष्ट अधिकार नहीं दिया था।

इस अधिनियम का मुख्य सार ही राष्ट्रीय और प्रदेशीय सरकारों के अधिकारों का विभाजन था जो कि सही ढंग से हो नहीं पाया था, इस तरह से अधिनियम में मुख्य दोष यह था कि वह कांग्रेस को न तो व्यापार और

कर आदि का अधिकार दे पाया, न ही संघीय कार्य व न्यायपालिका तथा आपातकालीन अधिकार दिये थे। यही कारण था कि अन्य तेरह उपनिवेश इसको मान्यता देने में असमंजस में थे। कांग्रेस के पास ऐसा कोई मापक भी नहीं था जिससे वह राज्यों से धन की याचना कर सकती न ही कोई राज्य धन देना स्वीकार कर रहा था। कांग्रेसी सदस्यों का कोई वेतनमान भी नहीं था और न ही उन्हें कोई वैतनिक कार्य करने की अनुमति थी।

नवीन-उपनिवेशी तंत्र

यद्यपि संघवाद का सिद्धान्त एक निर्वल सिद्धान्त था। इसने सर्वसाधारण भूमि नीति के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका के निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व योगदान दिया। यह योजना उत्तर पश्चिमी अध्यादेश में घोषित की गई थी और इसके अन्तर्गत ओहायो का उत्तरी क्षेत्र आता था। इसके द्वारा एलेग्नी पर्वतमाला के पश्चिम के वंजर प्रदेशों को व्यवस्थित ढंग से आबाद करना था वहाँ की आवादी (आदिवासियों) को नियमित कार्यों द्वारा विकसित करने का कार्य किया गया तत्पश्चात् अन्य राज्यों की तरह इसे भी समान अधिकारों वाला राज्य बना दिया गया। इस अध्यादेश में तीन अवस्थाओं की व्यवस्था की गई जिसके अनुसार सर्वप्रथम कांग्रेस एक राज्य की स्थापना करेगी जिसमें एक राज्यपाल तथा तीन न्यायाधीश होंगे। इनके बनाये अधिनियमों में हस्तक्षेप करने का अधिकार कांग्रेस के पास सुरक्षित होगा। इसके पश्चात् जब राज्य की आवादी पाँच हजार से अधिक हो जायेगी तब वहाँ दो सदनों के एक विधान मंडल का प्राविधान रखा जायेगा जिसमें निम्न सदनों के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं करेगी और अन्त में जब आवादी साठ हजार के ऊपर पहुँच जायेगी तब उसे एक सम्पूर्ण राज्य का स्तर प्राप्त हो जायेगा।

इस प्रकार से अमेरिका ने औपनिवेशिक समस्या का समाधान किया और जैसे-जैसे राष्ट्र प्रशान्त महासागर की तरफ बढ़ता गया दूसरे राज्यों की संख्या बढ़ती गयी यह संख्या बढ़कर 13 से 48 हो गई।

इसके पश्चात् भी राज्य संघीय व्यवस्था में विभिन्न राज्यों की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक थी एक प्रवेक्षक ने कहा "कि राज्यों के आन्तरिक अमन्तोष गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं" घामसेवेन ने बहुत पहले ही मुझाव दिया था कि एक महाद्वीप हेतु अधिकार व्यवस्था का घोषणा पत्र निर्मित करने के लिये आवश्यक है कि एक महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया जाय। "इसके साथ-साथ कांग्रेस के अन्दर ईमानदारी से नेतृत्व का भी अभाव हो चुका था, जिसके कारण

जार्ज वाशिंगटन को लिखना पड़ा कि “राज्य केवल रेत के रस्सों से जुड़े ही पड़े हैं।”

शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार की माँग

1786 तक कानफेडरेशन (परिसंघ) एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखने में असफल हो चुका था, विचारशील व्यक्ति जार्जवाशिंगटन, राबर्ट मोरिस, जोन आदम सरमन आदि इस परिणाम पर पहुँचे कि शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार के बिना देश का नव निर्माण कदापि सम्भव नहीं है। 1786 में जार्ज वाशिंगटन को लिखना पड़ा “कि मुझे राष्ट्र की एकता खतरे में दिखाई देती है बिना किसी राष्ट्रीय सरकार के राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखना सम्भव न हो सकेगा।” एलैंगजेन्डर, हैमिल्टन ने इस बात को और स्पष्ट करते हुये लिखा कि “अब हम इस स्थिति में पहुँच चुके हैं कि शायद ही ऐसा कुछ शेष हो जो राष्ट्रीय गौरव तथा स्वतंत्रता को कायम रख सके।”

ऐनापोलिस का सम्मेलन

अब तक एक शक्ति केन्द्र की माँग सर्वत्र व्याप्त हो चुकी थी। 1785 में मैरीलैन्ड तथा वर्जीनिया राज्य के मध्य पैटोमेक नदी के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ। अतः दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन माउंट वर्नन पर जार्ज वाशिंगटन के साथ हुआ। सम्मेलन में पैटोमेक तथा चैसपीक खाड़ी में समुद्री व्यापार सम्बन्धी प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ परन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि पेन्सलवेनिया तथा डेलावेयर भी इस व्यापार में साझेदारी के इच्छुक हैं तो वर्जीनिया ने 1786 में एनापोलिस में एक वाणिज्य सम्मेलन बुलाने की घोषणा की जिसमें सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया परन्तु सम्मेलन में केवल पाँच राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हुये। हैमिल्टन ने सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को इस बात पर सहमत कर लिया कि संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति पर विचार विमर्श हेतु मई, 1787 को फिलाडेल्फिया में सम्मेलन आयोजित किया जाय जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जो संघ की आवश्यकतानुसार संघीय सरकार के संविधान के लिये पर्याप्त हो।

कांग्रेस ने भी इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और इसके लिये अनुमति की घोषणा कर दी। रोड द्वीप को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने प्रतिनिधि चुने। उस सम्मेलन में बारह राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ये प्रतिनिधि राज्यों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। वर्जीनिया से

एडमण्ड रैनडाल्फ (गवर्नर) जेम्स मैडीसन (संविधान का पिता) और जार्ज वॉशिंग्टन (सम्मेलन का अध्यक्ष) न्यूयार्क से एलेग्जेंडर हैमिल्टन' डेलावेयर से जान डिकिन्सन (संविधान का अधिवक्ता) न्यूजर्सी से विलियम पेटरसन, पेनसिल्वेनिया के रावर्ट मोरिस (प्रसिद्ध वैकर) ने भाग लिया । इस तरह से 1787 में इस सम्मेलन में उस समय के सबसे अधिक प्रतिभाशाली और चरित्रवान व्यक्ति एकत्रित थे । परन्तु जैफरसन, पैट्रिक हैनरी, जान एडम्स तथा टॉमस पेन, सैमुअल एडम्स आदि जैसे लोग सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे । इस तरह से स्पष्ट था कि उग्रपन्थियों(आमूल परिवर्तनवादियों)की सम्मेलन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका था किन्तु इतना अवश्य था कि सम्मेलन के प्रतिनिधियों में अधिकांश धनी व्यक्ति थे, अमरीका में तत्कालिक व्यक्ति सम्पत्तिशाली हीं थे जैसा कि जान फ्रैकलिन ने कहा था कि अठारहवीं सदी में अमरीका में लोग अधिकतर सम्पत्तिवान थे तथा निर्धनों की संख्या न्यून थी । इस तरह यह सदापि सम्मेलन उस समय के श्रेष्ठ सम्मेलनों में से एक था ।

अधिवेशन का कार्य

यद्यपि उस सम्मेलन को केवल परिसंघ के अनुच्छेदों को संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया था परन्तु सम्मेलन के प्रारम्भ में ही राष्ट्रवादी (विल्सन, मैडिसन) प्रतिनिधि जो अनुच्छेदों में पूर्ण परिवर्तन कर एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना का निर्माण कर चुके थे, उन प्रति- निधियों पर प्रभावी हो गये जो अनुच्छेदों के केवल संशोधन के इच्छुक थे ।

25 मई, 1787 को ओल्ड स्टेट हाउस (जहाँ स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी)में प्रारम्भ हुआ । 29 मई को रेन्डाल्फ ने वर्जीनिया द्वारा प्रस्तावित योजना को सम्मेलन में रखा । इस योजना में एक सशक्त राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव था जिसको कि सम्मेलन के वाद विवाद का आधार मान लिया गया । उस योजना के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय विधानपालिका, एक राष्ट्रीय कार्यपालिका तथा एक राष्ट्रीय न्यायपालिका की स्थापना का अधिकार दोनों सदनों तथा जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को सौंप दिया गया । तत्पश्चात् केन्द्र तथा राज्यों में अधिकार सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हो गये । वर्जीनिया राज्य के प्रतिनिधि अवर सदन के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा एवं प्रवर सदन के सदस्यों का अवर सदन द्वारा तथा जिनको तत्पश्चात् कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के गठन का अधिकार होगा । उसके विपरीत न्यूजरेमी केवल एक विधान पालिका के पक्ष में था जिसका गठन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर हो । उनके अनुसार कार्यपालिका का निर्वाचन कांग्रेस

द्वारा होना चाहिये था तथा न्यायपालिका के गठन का अधिकार कार्यपालिका के पास होनी चाहिये। अन्ततोगत्वा इस समस्या का समाधान एक समझौते के द्वारा सम्भव हो सका।

संघीय संविधान

इस संविधान के अनुसार सम्पूर्ण प्रभुसत्ता केन्द्र को प्रदान कर दी गई। केन्द्र का व्यक्तियों पर सीधा अधिकार हो गया। केन्द्रीय विधि का अधिकार क्षेत्र राज्य अधिकारियों, न्यायालयों तथा संघियों पर माना गया। इसके अधिकारों को सुरक्षा के लिये राज्य सेना को प्रयोग करने की छूट भी प्रदान कर दी गई। इस प्रकार केन्द्र केवल राज्यों का संघ ही नहीं रह गया अपितु केन्द्र का व्यक्ति विशेष पर अधिकार विशेष क्षेत्रों तक सीमित रखा गया एवं शेष क्षेत्रों को राज्याधिकार के अन्तर्गत माना गया। संविधान के रचयिताओं के अनुसार केन्द्र का शासन तब प्रभावी नहीं हो सकता था जब तक उसका अधिकार सीधे क्षेत्र से न हो।

परिसंघ के अनुसार संघीय शासन को विदेश, प्रतिरक्षा, तथा करा-रोपण का अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ संविधान को इस प्रकार रखा गया कि भविष्य में भी संशोधन किये जा सकें। शासन व्यवस्था को समन्वयता के लिए तीन शाखायें विधान सभा (लेजिस्लेटिव), कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) तथा न्यायपालिका (ज्यूडिशरी) का निर्माण किया गया। इन तीनों के मध्य शक्ति संतुलन इस तरह से रखा गया कि इनके कार्यों एवं अधिकारों में पूर्ण सामंजस्य बना रहे और यह आपस में एक दूसरे पर प्रतिबंध रखते हुये एक दूसरे को संतुलित रखें जिससे कि कोई एक शाखा प्रबल होकर नियंत्रण को अपने हाथ में न ले सके और एक निरंकुश शासन न स्थापित हो सके। कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) के प्रश्न पर सबसे अधिक विवाद उत्पन्न हुआ। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन कांग्रेस के द्वारा किया जाता तो वह विधायक शाखा के ऊपर निर्भर हो जाती तथा शक्ति के असंतुलन का भय होता अंत में यह निर्णय लिया गया कि एक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाय और प्रत्येक राज्य के सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य उसके सदस्य हों तथा यह राष्ट्रपति का चुनाव करें लेकिन इस प्रणाली को राजनैतिक दलों ने 20 वें संशोधन द्वारा इसको संशोधित किया। इस प्रकार से अवर सदन जनता के द्वारा निर्वाचित होता था परन्तु यह अपरोक्ष रूप से गठित सीनेट द्वारा संतुलित किया गया और ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकीय मंडल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार तीनों शाखाएँ स्वयं में पूर्ण एवं

स्वतंत्र थी तथापि प्रत्येक का दूसरे पर प्रतिबन्ध स्थापित रहा। कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकते थे जब तक कि राष्ट्रपति उसको अनुमोदित न कर दें और राष्ट्रपति को भी अपने महत्वपूर्ण नियुक्तियों तथा संघियों पर सीनेट से अनुमति लेनी पड़ती एवं कांग्रेस राष्ट्रपति पर उसके त्रुटिपूर्ण कार्यों के लिये महाभियोग भी लगा सकती थी। तीसरी शाखा यद्यपि न्यायपालिका के लिये न्यायाधीश का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के द्वारा परामर्श और अनुमति से करने की व्यवस्था की गई। वह अपनी व्यवहार कुशलता के आधार पर आजीवन न्यायाधीश रह सकता था। न्यायपालिका को कानूनों और संविधानों के अन्तर्गत उत्पन्न सब मामलों की सुनवाई का अधिकार था। इस प्रकार न्यायपालिका को संविधान और कानून दोनों की व्याख्या करने का अधिकार था।

इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को करा-रोपण का पूर्ण अधिकार दिया गया। उसे ऋण लेने तथा इसके लिये सारे देश पर शुल्क एवं कर आरोपित करने का अधिकार था। उसे डाक घर, सिक्के ढालने, पेटेन्ट और सर्वाधिकार देने, वाट और माप निर्धारित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। उसे सुरक्षा एवं शांति कायम रखने के लिये सेना तथा नवसेना रखने का भी अधिकार प्रदान किया गया। संघीय शासन को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय का भी अधिकार था। अतएव यह संविधान परिसंघ के अनुच्छेद की तुलना में अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी था। केन्द्र के अतिरिक्त राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार प्रदान किये गये। स्थानीय शासन के सभी अधिकार जैसे विद्यालय, अदालतें, पुलिस, बैंकों और कम्पनियों का गठन, आवागमन के साधन आदि कार्य राज्यों को सौंप दिये गये थे। इस तरह से सम्मेलन के मध्य जो अन्य बाधाएँ थीं उनका भी निवारण कर दिया गया। 16 जुलाई को इस समझौते को भी स्वीकार कर लिया गया जिसके अनुसार छोटे राज्यों को समान प्रतिनिधित्व आत्रादी के अनुसार से दिया गया। इसी समय इस बात का भी निश्चय कर लिया गया कि मर्फी तरह के धनादेश (मनी-बिल) प्रतिनिधि सभा द्वारा ही किये जायेंगे।

सम्मेलन के अन्त में कांग्रेस को कर वसूल करने की अनुमति दे दी गई। इसके पश्चात् दास नमस्वा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उत्तरी क्षेत्र जबकि अमरीकी जलयानों की सुरक्षा में रुचि रखता था दक्षिणी क्षेत्र किसी भी ऐसे नियम के विरुद्ध था जिसके कारण उसके कृषि जनित उत्पादनों के यूरोप निर्यात करने में बाधा उत्पन्न हो। एक समझौते के अनुसार यह निश्चित किया गया कि केन्द्रीय सरकार उत्तरी क्षेत्रों के लाभ हेतु नौकायन के नियम

बना सकती थी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लाभ हेतु निर्यात करों को लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसके साथ ही साथ दासों के आयात को आगामी 20 वर्षों के लिये बंधता प्रदान कर दी गई। दक्षिणी राज्यों के सम्बन्ध में एक अन्य समस्या उत्पन्न हो गई कि कांग्रेस की सदस्यता के निर्वाचन के लिये दासों की संख्या को वहाँ की जनसंख्या का हिस्सा समझा जाये या नहीं। अन्ततोगत्वा यह निश्चित हुआ कि उनकी सम्पूर्ण जनसंख्या का 2/5 भाग जनसंख्या में माना जाय।

17 सितम्बर, 1787 को सम्मेलन की अन्तिम बैठक हुई और संविधान पर सभी उपस्थित 39 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये। यद्यपि संघीय संविधान मुख्यतया परिसंघ के अनुच्छेदों पर आधारित था तथा सर्वथा पूर्ण था। बँजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार “यद्यपि मैं संविधान के सभी भागों को पसन्द नहीं करता, तो भी यह देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि यह संविधान एक प्रकार से लगभग सर्वथा पूर्ण ही है।” अमरीकी संविधान में स्थापित आशावादिता का निरूपण फ्रैंकलिन की उस उक्ति से हो सकता है जो उसने संविधान के अन्तिम रूप से तैयार होने पर की थी। “मैंने सम्मेलन के दौरान उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में आशाओं और निराशाओं के उतार-चढ़ाव में बार-बार अध्यक्ष के पीछे के उस सूर्य की ओर देखा और मैं कभी यह निश्चित न कर सका कि यह उदय हो रहा है या अस्त। परन्तु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि यह अस्त नहीं बल्कि उदय हो रहा है।”

इस तरह से सम्मेलन समाप्त हुआ एवं अब इस संविधान को कम से कम 9 राज्यों की सहमति की आवश्यकता थी।

अनुसमर्थन

जन-माधारण के मण्डितक में अभी भी संविधान के सम्बन्ध में सन्देह था। जैसे ही कांग्रेस ने संविधान राज्यों को प्रस्तुत किया वैसे ही जनमत दो दलों में विभक्त हो गया। एक संववादी और दूसरा संघ विरोधी। यह कहना अत्यन्त ही दुष्कर था कि बहुमत किसकी तरफ है फिर भी अधिकारी छोटे और निर्बल राज्य नये संविधान के समर्थन में थे। अपवाद के रूप में न्यूहैम्पशायर तथा रोड द्वीप थे। जबकि बड़े-बड़े राज्यों ने काफी लम्बे संघर्ष के बाद संविधान का अनुमोदन किया। उत्तरी केरोलिना ने तब तक संविधान का समर्थन नहीं किया जब तक कि आर्थिक समस्या का समाधान न हो गया।

डेलैवेयर ने सर्वप्रथम 7 दिसम्बर, 1787 को सर्वसम्मति से अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके पाँच दिन बाद पेनसिल्वेनिया ने अत्यधिक वाद

विवाद के पश्चात् 23 के विरुद्ध 46 मतों से स्वीकृति दी। जबकि न्यूजर्सी ने जार्जिया की तरह सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। कौन्टकेट ने एक के विरुद्ध 3 मतों से सहमति प्रदान की।

परन्तु अभी तक बड़े राज्यों जिनके विना संविधान लागू नहीं हो सकता था, अपनी सहमति प्रदान नहीं की थी। मैसाचुसेट्स में उग्र संघर्ष हुआ। वहीं स्वीकृति जॉन हैनकॉक और सैम्युल एडम्स के निर्णय पर आधारित थी। प्रथम एडम्स ने उसका विरोध किया परन्तु बोस्टन के व्यापारियों, वकीलों व फार्म मालिकों के समर्थन के कारण 6 फरवरी को 168 के विरुद्ध 187 ने स्वीकृति दे दी। मैरीलैण्ड ने अप्रैल में और दक्षिणी कैरोलिना ने मई में स्वीकृति दी। न्यू हैम्पशायर ने मैसाचुसेट्स की स्वीकृति के तुरन्त पश्चात् स्वीकृति प्रदान कर दी।

इस तरह से 9 राज्यों ने अपनी स्वीकृति तो प्रदान कर दी फिर भी सबसे बड़े राज्य वर्जीनिया तथा न्यूयार्क ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। वर्जीनिया के निर्णय पर ही वार्शिंगटन का भविष्य आधारित था परन्तु अथक संघर्ष के बाद 25 जून को 79 के विरुद्ध 89 मतों से संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। अब न्यूयार्क में सबसे बड़ा संघर्ष था। संघ विरोधियों का दो तिहाई से ज्यादा बहुमत था, संघवादियों के विजय के लक्षण कम ही नजर आते थे। अतः बुद्धिजीवियों के सहयोग को प्राप्त करने के लिये हैमिल्टन, मैडिसन तथा जॉन जे० ने संविधान के प्रचार हेतु 85 निबन्धों के संग्रह (द पैडरालिस्ट) को प्रकाशित कराया। यह कहना कठिन है कि इसका प्रभाव कितना हुआ लेकिन 26 जुलाई को 27 के विरुद्ध 30 वोटों से न्यूयार्क ने भी संशोधन की याचना के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और उसके बाद 21 नवम्बर, 1789 को उत्तरी कैरोलिना और 29 मई, 1790 को रोड द्वीप ने भी कांग्रेस के कारण अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

इस तरह से संविधान को बड़े-बड़े राज्यों ने बहुत ही कम मतों से स्वीकृति प्रदान की थी। यह कहना अत्यन्त दुष्कर था कि जनमत की वास्तविक इच्छा क्या थी। वह सभी संशोधन जिनकी अनुशंसा नये संविधान की स्वीकृति के लिये की गई थी, वास्तव में, इस बात का द्योतक थी कि अभी संविधान की जनमत के अनुरूप नहीं है। पैट्रिक हैनरी ने अपने मत को व्यक्त करते हुये कहा कि "मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि अधिकांश ग्रामीण जन-जीवन ने संविधान का विरोध किया" वास्तव में कृषि प्रधान ऋण ग्रस्त जिलों से ही सबसे ज्यादा विरोध किया गया जबकि धनी मध्यम वर्गीय तथा उन लोगों जिनको पुराने संविधान के कारण हानि हो रही थी, नये संविधान

का समर्थन किया। इस बात को वीयर्ड के शब्दों में “न तो संविधान सभी लोगों ने बनाया जैसा कि विधि शास्त्री कहते हैं न ही राज्यों ने इसको खड़ा किया जैसा कि दक्षिणी व्यर्थनवादी (नल्लीफायर्स) कहते हैं अपितु यह यह उन लोगों का कार्य है जिनके स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है और जो अपने को पूर्ण राष्ट्रवादी समझते हैं।”

उपसंहार

अमरीका के इतिहास में अमरीकी संविधान को विवादास्पद प्रलेख की संज्ञा दी जाती है। अमरीकी संविधान को अमरीका के उच्चतम न्यायालय की कई पीढ़ियों ने अपनी अभिरुचि के अनुसार अमरीकी समाज की संवैधानिक निर्णयों की पुनः व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त अमरीका के राजनैतिक दलों एवं राष्ट्रपतियों ने संविधान की व्याख्या अपने स्वार्थ लक्ष्य एवं सरकारी विचारों एवं सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से की। इतिहासकारों ने भी अमरीकी इतिहास के विभिन्न चरणों को विवादास्पद व्याख्या के द्वारा प्रस्तुत किया। यद्यपि संवैधानिक व्याख्या की प्रशंसा एवं आलोचना समय-समय पर की गई परन्तु इतिहासकारों को संविधान के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण बौद्धिक वातावरण के साथ सदैव परिवर्तनशील रहा है।

अमरीकी संविधान 1787 से गृह युद्ध तक संघीय संघ को लेकर इतिहासकारों के अनुसार विवादपूर्ण अभिलेख रहा है। इस संविधान को उत्तर एवं दक्षिण के राजवेत्ताओं ने निजी हितों को लेकर प्रादेशिक एवं केन्द्रीय सरकारों के सम्बन्धों पर तर्क-वितर्क किया। अनेक राजनीतिज्ञों ने संघीय सरकारों के अन्तर्गत अधिसंख्यक एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संघीय सरकार के आधीन विभिन्न रूप से व्याख्या करने की चेष्टा की है। निःसन्देह इतिहासज्ञों ने संविधान के प्रति प्रतिपादित सिद्धान्तों पर अपने विचार प्रकट किये किन्तु गृह युद्ध ने सम्भवतः संवैधानिक राष्ट्रीय धारा को प्रोत्साहन दिया।

राष्ट्रीय मत

गृह युद्ध के पश्चात् संविधान की व्याख्या करने वाले इतिहासकारों की विचारधाराओं को तीन पृथक मतों में सुव्यक्त किया जा सकता है। प्रथम मत राष्ट्रिय विचारधारा का मत है जो गृह युद्धके पश्चात् दशकों में विकसित हुआ। इस मत का प्रतिनिधित्व जार्ज वेनक्राफ्ट एवं जान फिस्के ने किया। इन दोनों इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक युग में व्यक्तिगत

स्वतंत्रता ऐंग्लो-सैक्सन लोगों को उत्कृष्ट राजनैतिक योग्यता पर आधारित था जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने सशक्त एवं स्थिर राष्ट्रों का निर्माण किया। इस मत के प्रवक्ताओं ने अमरीका की प्रचलित लोकतांत्रिक समस्याओं का सम्बन्ध प्राचीन जर्मनी की जन जातियों से किया। इन विद्वानों के मतानुसार अमरीकी संविधान विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इस संविधान ने मानवता को सभ्यता एवं शासन की पद्धति से अवगत कराया। वैन क्राफ्ट और फिस्के ने अपने ग्रंथों में अमरीकी संविधान को राष्ट्रीय संस्थापकों द्वारा कृत एक महान कार्य की संज्ञा दी। क्योंकि उनके विचार में यह प्रलेख धर्मनिष्ठा एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था तथा लोकतांत्रिक राष्ट्रीय स्वप्न का साकार स्वरूप था। उपरोक्त विश्व व्यापी संवैधानिक प्रशंसा के वृंदगान में हरमन वॉन होलस्ट ने अपने बहुग्रन्थीय कार्य में अमरीकी इतिहासकारों की आलोचना करते हुये इस तथ्य को स्पष्ट किया कि अमरीकी संविधान किसी भी रूप में दैविक रचना नहीं था। वॉन होलस्ट की विचारधारा अल्प सांख्यिक होने के नाते अपने युग में मान्य नहीं हो सकी। वैनक्राफ्ट ने 1880 में प्रकाशित अपनी दो खंडीय पुस्तक में यह मत प्रकट किया कि 1781 में अनुसमर्पित परिसंघ के अनुच्छेदों में स्वशासन हेतु एक कृत्रिम मार्ग निर्देशित किया था। वैनक्राफ्ट के अनुसार ब्रिटेन एवं स्पेन के बाह्य संकटों तथा आंतरिक समस्याओं (शेज विद्रोह आदि) ने अमरीका के लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया कि उनको एक सफल और साधनयुक्त शासन की आवश्यकता थी। वैनक्राफ्ट के मतानुसार संविधान एक ऐसा प्रलेख था जिसने अमरीका को एक ऐसी नवीन शासन प्रणाली प्रदत्त की जिसमें न कोई राजा था, न युवराज था और न ही सामन्तवर्ग। वैनक्राफ्ट ने संविधान के तर्क हेतु सम्भवतः रक्तरेजित गृहयुद्ध को महत्वपूर्ण नहीं समझा। जान फिस्के ने अपनी पुस्तक "दिक्रीटिकल पीरियड ऑफ अमेरीकन हिस्ट्री, 1783-1789" में संविधान से पूर्व एवं पश्चात अमरीकी राष्ट्र की स्थिति का नाटकीय वर्णन किया है। फिस्के के विचार में 1783 की शान्ति के पश्चात का समय अमरीकी इतिहास का अत्यन्त संकटपूर्ण काल था क्योंकि परिसंघ के अन्तर्गत राष्ट्र निपात पूर्णतया सम्भव था। इसका मुख्य कारण निर्बल एवं अशक्त केन्द्रीय सरकार थी जो प्रदेशों के पारस्परिक झगड़ों, आर्थिक मंदी, आन्तरिक उपद्रवों तथा राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने में नितान्त असफल थी। परन्तु संविधान निर्माण ने, फिस्के के अनुसार, राष्ट्र की विपाद पूर्ण एवं निराशाजनक स्थितिमें एक आशापूर्ण परिवर्तन ला दिया। फिस्के ने भी ब्रिटिश राजवेत्ता ग्लैडस्टन की भाँति संविधान को मानव के मस्तिष्क एवं कार्य का अनुपम

दृष्टांत माना ।

इस प्रकार राष्ट्रीय मत के विद्वानों ने संविधान को राष्ट्रभक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन किया । इन इतिहासकारों ने संविधान के संस्थापकों को उन महान लोगों की संज्ञा दी जो न्यायोचित सिद्धान्तों तथा राष्ट्रीय कल्याण की भावना से प्रेरित थे । इन विद्वानों के अनुसार अमरीकी जनता लोकतांत्रिक समाज के मूल्यों में अनुरक्त थी और संविधान इन मूल्यों का मूर्त स्वरूप था ।

प्रगतिशील मत

20वीं शताब्दी के संधिकाल में जनसमर्थित एवं प्रगतिशील सुधार आन्दोलनों ने संविधान के प्रति विचारधारा में विशिष्ट परिवर्तन ला दिया । प्रगतिशील सुधारकों ने राष्ट्रीय औद्योगीकरण की समस्याओं की विवेचना करते हुये अमरीकी समाज में राजनैतिक शक्तियों एवं सम्पत्ति के असंतुलन को अमरीकी लोकतंत्र के लिये सर्वनाशी बताया । अमरीकी सरकार ने 1890 से लेकर शताब्दी के संधिकाल तक आर्थिक श्रमिक तथा संबैधानिक विधान पारित किये परन्तु अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने अनेक राजकीय एवं राष्ट्रीय विधानों की नवीन तकों के अन्तर्गत व्याख्या की और फलस्वरूप एक पृथक विचारधारा को जन्म दिया ।

ऐसे समय में प्रगतिशील इतिहासकारों ने जो संबैधानिक मोहभ्रमित से प्रभावित थे, अपना मत प्रकट किया । इन विद्वानों की विचारधारा समयानुसार भ्रमित होती रही क्योंकि इनके विचार में संविधान एक लोकतांत्रिक प्रलेख न होकर एक प्रतिक्रिया वादी दस्तावेज था । इन इतिहासकारों ने इस संविधान के द्वारा समृद्ध एवं शक्तिशाली वर्ग के अधिकारों का संरक्षण प्राप्त था । इस प्रकार उपरोक्त इतिहासकारों के अनुसार संविधान के रचयिताओं ने उग्रवादी विचारधारा से परे हटकर रूढ़िवादी विचारधारा को मान्यता दी । अपने मत की पुष्टि में इन विद्वानों ने संविधान के अप्रजातांतीय मुख्य लक्षणों की ओर इंगित किया । नियंत्रण एवं संतुलन की पद्धति संशोधन की कठिन कार्यप्रणाली तथा न्यायिक विशेषाधिकार इस प्रकार जहाँ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने संविधान को लोकतांत्रिक विकास में एक उन्नत कदम माना वहाँ प्रगतिवादी इतिहासकारों ने इस संविधान को लोकप्रिय सरकार के गत्याविरोध की संज्ञा दी । प्रगतिशील मत के इतिहासवेत्ता सुधार तरंग के साथ-साथ ऐतिहासिक वृत्ति के अन्दर परिवर्तन के द्वारा भी प्रभावित थे । इसका परिवर्तन का मुख्य कारण 'नवइतिहास' का उन्मज्जन था । इस नवइतिहास लेखन के समर्थकों ने

अतीत के इतिहास को रूढ़िवादी इतिहास की रचना बताया। इस प्रकार नव इतिहास लेखन के उद्घोषकों में मुख्य चार्ल्स ए० वीयर्ड थे।

चार्ल्स वीयर्ड ने प्रगतिशील दृष्टिकोण की व्याख्या अत्यन्त सफलतापूर्वक की है। यद्यपि अन्य इतिहासकारों रिचर्ड हिल्डर्थ एवं जॉन मार्शल ने भी वीयर्ड की भाँति संविधान के प्रति आर्थिक विचारधारा को लेखबद्ध किया परन्तु वीयर्ड के तर्क अधिक युक्ति-संगत थे। वीयर्ड ने अपनी पुस्तक एन इकोनामिक इन्टरपर्टेशन आफ दि कान्स्टीच्यूशन 1913 में संविधान रचयिताओं के आर्थिक स्तर का पूर्ण अध्ययन किया है। वीयर्ड ने अपने अध्ययन में यह निर्णय लिया कि अमरीका का संवैधानिक आन्दोलन का प्रवर्तन चार मुख्य हितों के कारण हुआ। वह स्वार्थ निहित थे, मुद्रा, सार्वजनिक सुरक्षा, उत्पादन एवं निर्माणकर्ता तथा व्यापार एवं पोत परिवहन। वीयर्ड ने स्पष्ट रूप से संविधान के रचनाकारों को अपने स्वार्थों की सुरक्षा के प्रति सजग बताया। वीयर्ड ने अपने विश्लेषणात्मक निष्कर्ष में इस प्रमाण का पुष्टिकरण किया कि संविधान निर्माताओं ने सम्पत्तिहीन जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया।

अतः वीयर्ड के अध्ययन ने इतिहासवेत्ताओं को एक सीमा तक प्रभावित किया। अमरीकी इतिहासकारों की एक पूर्ण पीढ़ी इस तथ्य से आश्चस्त हुई कि संविधान को केवल वर्ग संघर्ष के निबन्धन में समझा जा सकता था। वीयर्डवाद के समर्थित इतिहासकारों में मैरिल जैनसन मुख्य थे। अपनी दो पुस्तकों 'दि आर्टिकल्स आफ कन्फेडरेशन' (1940) तथा 'दि न्यू नेशन (1950)' में जैनसन ने फिस्के के विचारों का खंडन किया। वीयर्ड एवं जैनसन के अनुसार संविधान एक प्रति क्रान्तिकारी प्रलेख था जो सशक्त स्वार्थहितों में लिप्त अल्पसंख्यक वर्ग ने जन-साधारण पर अलोकतांत्रिक रूप में उद्घोषित किया। इस प्रकार जिन इतिहासकारों ने जैनसन के इस मत का समर्थन किया कि संविधान वर्ग संघर्ष पर आधारित था 'नव वीयर्डवादी' कहलाये जाने लगे।

संशोधकीय एवं नव रूढ़िवादी मत

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् वीयर्ड विरोधी 'संशोधकीय विचारधारा' प्रस्फुटित हुई। इन संशोधकीय लेखकों के अनुसार वीयर्ड ने अपने अध्ययन में संतोषजनक रूप से घटनाओं की व्याख्या नहीं की है इन संशोधकीय विचारधारा के इतिहासकारों ने नवरूढ़िवादी इतिहासकारों के साथ सम्मिलित होकर वीयर्ड के अध्ययन के सिद्धान्तों की आलोचना की। इन्होंने संविधान को वर्ग संघर्ष पर आधारित न मानकर मतैक्य पर आधारित माना। इसके अतिरिक्त इन लेखकों ने क्रान्ति एवं संवैधानिक युग को निरन्तर विकास वृद्धि के काल की मान्यता

दी। इन नवरूढ़िवादी इतिहासकारों में प्रमुख 'बैंजमन राइट, 'रावर्ट ब्राउन' तथा 'हैनरी स्टील' कोमेजर थे। इन इतिहासकारों ने अमरीकी संविधान को मौलिक रूप में राजनैतिक प्रलेख की संज्ञा दी। बैंजमन राइट ने क्रान्ति एवं संविधान काल में एक मौलिक निरन्तरता और सामंजस्य को दर्शित किया। क्योंकि राइट के विचारानुसार 1787 में वही सब व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे जो 1776 की क्रान्ति में भी विशिष्ट स्थान रखते थे। इस प्रकार राइट ने इस तथ्य को स्थापित किया कि क्रान्ति के राजनैतिक विचारों की राज्य संविधानों में पूर्णतया व्याख्या की गई थी। इस प्रकार संवैधानिक युग को किसी भाँति क्रान्ति की प्रतिक्रिया नहीं कहा जा सकता था। हैनरी स्टील कोमेजर ने भी संविधान को आर्थिक रूप न देकर राजनैतिक रूप की संज्ञा दी। रावर्ट ब्राउन ने भी अपने अध्ययन में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया कि संवैधानिक आन्दोलन अन्य महत्वपूर्ण आन्दोलनों की भाँति लघुवर्ग के द्वारा प्रारम्भित हुआ। यह लोग अपने-अपने राज्यों में आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त ब्राउन के अनुसार 1780 के आसपास अमरीकी समाज मध्यवर्गीय लोकतंत्र का प्रतिनिधिक था। इस प्रकार संविधान मध्यवर्गीय लोकतंत्रीय विचारधारा पर आधारित था न कि उच्चवर्गीय अभिजातीय विचारों से प्रभावित था। एक अन्य संशोधकीय इतिहासकार 'फारेस्ट मेक्डॉनल्ड' ने अपनी पुस्तक 'वी दि पीपुल' में संविधान के आर्थिक स्वरूप को मान्यता दी परन्तु वीयर्ड के अन्वेषण को सरलीकरण की उपमा दी।

इस प्रकार उपरोक्त विद्वानों एवं इतिहासवेत्ताओं के विचारों के व्याख्यात्मक विश्लेषण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि अमरीकी संविधान मूलरूप से लोकतंत्रीय विचारों पर आधारित था तथा उसके निर्माण में मध्यवर्गीय कृषि समुदाय का योगदान था वस्तुतः अमरीकी संविधान एक ऐतिहासिक राजनैतिक प्रलेख था जिसने अमरीकी समाज एवं जनता का लोकतांत्रिक मार्ग प्रशस्त किया।



अध्याय 2

वाशिंगटन एवं एडम्स

नवीन संविधान के साथ ही साथ अमरीका का भविष्य चुनौतियों से परिपूर्ण था। क्या देश इस संविधान के साथ सामंजस्य कर सकेगा? क्या देश का भविष्य गणतन्त्र के रूप में निखरेगा? ऐसे कुछ प्रश्न संयुक्त राज्य अमरीका के प्रत्येक नागरिक के हृदय में उद्बलित हो रहे थे,

अंततः 4 मार्च 1789 में नवीन संविधानानुसार अमरीका की नव कांग्रेस का चयन हुआ। इस अमरीकी कांग्रेस ने जार्ज वाशिंगटन को सर्व सम्मति से अमरीका का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया।

जार्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लिये एक सौभाग्यशाली घटना थी, वाशिंगटन के चरित्र एवं ख्याति ने नव संविधान के अन्तर्गत नव शासन को सबलता प्रदत्त की, यद्यपि जार्ज वाशिंगटन एक विशिष्ट व्यक्तित्व के स्वामी थे परन्तु उनको राज्यसंघ के आन्तरिक एवम् बाह्य नीतियों के मूल प्रश्नों का समाधान करना था, उन्होंने नवशासन में विश्वास की चेष्टा की जिसके द्वारा आन्तरिक एवम् वैदेशिक क्षेत्रों में चरित्र प्रतिष्ठा अर्जित की जा सके। जार्ज वाशिंगटन ने अपने प्रतिष्ठा एवं निष्ठा के कारण अमरीका के नवराष्ट्र को सशक्त एवं सबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, राष्ट्रपति ने पदासीन होते ही इस तथ्य में आस्था व्यक्त की कि कांग्रेस की नीति किसी भी प्रकार के स्वार्थ हितों अथवा मत भेदों से प्रभावित न होकर केवल जनहित या जनकल्याण हेतु होगी, यद्यपि संघीय सरकार के अनुच्छेदों ने गृह समस्याओं के समाधान में कोई विशेष योगदान नहीं दिया परन्तु जार्ज वाशिंगटन को समस्त गृह समस्याओं तथा विदेशी नीति को सफल बनाने में अथक प्रयास करने पड़े। प्रथम राष्ट्रपति ने अमरीकी प्रशासन को सुचारु रूप से प्रशासित करने हेतु अपने योग्य अनुयायियों का चयन किया, यद्यपि उपराष्ट्रपति जान एडम्स का निर्वाचन कांग्रेस द्वारा घोषित हो



जार्ज वॉशिंग्टन (1732-1799)
अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति

चुका था इसके अतिरिक्त वाशिंगटन का सर्वप्रथम उत्तरदायित्व एक कुशल प्रशासन का गठन करना था। इस हेतु राष्ट्रपति को अपने उन अनुयायियों का चयन करना था जो कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ योग्य, चरित्रवान, निष्ठा युक्त तथा अनुभवी हों।

वाशिंगटन ने जॉन जे को उच्चतम मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया, टामस जैफरसन को राज्य सचिव नियुक्त किया। राष्ट्रपति ने एलैग्जेंडर हैमिल्टन को वित्त सचिव, एडमण्ड रैंडालफ को महान्यायवादी के पदपर आसीन किया। इसके अतिरिक्त हैनरी जान्स को युद्ध सचिव बनाया गया।

राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु विभिन्न विभागाध्यक्षों से समय-समय पर भेंटें वार्ता करने का नियम बनाया। यह मंत्रीमंडल प्रणाली की ओर प्रथम चरण था। यद्यपि संविधान के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी थे परन्तु प्रारम्भिक घटनाचक्रों से प्रभावित होकर, वाशिंगटन ने उपरोक्त नियम को स्पष्ट किया कि विभागाध्यक्षों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति की ओर है अर्थात् प्रशासनिक कार्यों का मूल श्रोत राष्ट्रपति था।

अमरीका की तत्कालीन परिस्थितियाँ अत्यन्त चिन्ताजनक थीं। नवीन संविधान की प्रभावोत्पत्तिका अभी तक अस्पष्ट थी दोहरे शासन सभी संघीय तन्त्र को अपना औचित्य सिद्ध करना शेष था, तथा शासकीय कोष न केवल रिक्त था अपितु ऋणों से परिपूर्ण था। उपरोक्त परिस्थितियों में अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जार्ज वाशिंगटन के समक्ष अत्यन्त कठिन चुनौतियाँ उपस्थित थीं, इन सभी का सामना करने के लिये वाशिंगटन ने 'महत्त्वपूर्ण क्रान्ति' से प्रेरणा प्राप्त कर सुधारों का प्रशासन प्रारम्भ किया, आपका विश्वास था कि 'सामुदायिक विकास' के मार्ग में दलगत राजनीति तथा स्थानीयता अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकेगी" स्वतंत्रता की पवित्र अग्नि तथा 'गणतान्त्रिक स्वरूप' की सुरक्षा ही उनका प्रमुख ध्येय था, भौतिक सिद्धान्तों पर आधारित अमरीका का संविधान केवल एक न्यूनतम तथा कुछ अधिकतम सिद्धान्तों को ही प्रतिपादित करता था। अतएव प्रथम राष्ट्रपति तथा प्रथम कांग्रेस के निर्णयों का अभी विशेष महत्त्व था, इसके अतिरिक्त कुछ पूर्वोदाहरणों का निर्णय अकस्मात् हो गया। सीनेट द्वारा सन्धियों पर वार्तालाप उच्चतम न्यायालय की परामर्श समिति तथा कैबिनेट प्रणाली आदि का जन्म शनैः-शनैः स्वयं स्पष्ट होता गया। 1789 में प्रथम सीमा शुल्क अधिनियम पारित करने की योजना पर विचार किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व कर में वृद्धि करने तथा शैशव

कालीन अमरीकी उद्योग की रक्षा करना था। इस अधिनियम को पारित करने हेतु जब विचार विमर्श आरम्भ हुआ तब वह राष्ट्रीय नियम प्रान्तीय तथा स्थानीय स्वार्थों का संघर्ष-स्थल बन गया। न्यू इंग्लैण्ड वाले एक मत के थे। प्रत्येक राज्य व प्रान्त का स्वार्थ इसमें निहित था कि वह अपने निजी उद्योग अथवा सीमा पर अधिक शुल्क न लगने दे तथापि कई मास के बाद विवाद के पश्चात् 4 जुलाई 1789 को राष्ट्रपति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम को मान्यता प्रदान की गयी।

अधिकारों का प्रस्ताव

प्रथम कांग्रेस ने सर्वप्रथम जनसामान्य को प्रदत्त वचन पालने के लिये संविधान को 'अधिकारों के प्रस्ताव' को प्रदान करने का निर्णय लिया। 4 जून को सर्व प्रथम मेडिसन से यह प्रस्ताव कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किया। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदत्त संशोधनों को सम्बन्धित समिति ने स्वीकार कर अन्ततोगत्वा इस प्रस्ताव को सीनेट में प्रेषित कर दिया जो दिसम्बर 11, 1791 को पारित होकर अमरीका के संविधान का एक प्रमुख भाग हो गया। इस प्रस्ताव में उन सभी स्वतंत्रताओं का उल्लेख था जिन्हें संघीय सरकार प्रभावित नहीं करती थी। धार्मिक स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस, न्याय तथा सभा की स्वतंत्रता के अतिरिक्त संघीय शासन पर तीन अन्य प्रतिबन्ध भी लगाये गये जिनके अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को सेना रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती थी। उसे सर्वसाधारण की तलाशी लेने तथा सेना के प्रयोग का अधिकार भी नहीं दिया गया। बिना कारण बताये किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता था। यद्यपि इन प्रस्तावों की लिखित रूप में संविधान में स्वीकार करना, बहुत से अमरीकियों को आवश्यक नहीं लगा परन्तु इसके मौलिक महत्व के कारण अन्ततोगत्वा प्रस्ताव पारित हो गया।

हैमिल्टन की योजना

1789 में राष्ट्र को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सरकार के समीप प्रशासकीय कार्यों को सम्पन्न करने के लिये धन का अत्यन्त अभाव था। अतः वित्त सचिव एलेग्जेंडर हैमिल्टन ने जनवरी, 1790 में बहुमुखी आर्थिक योजना की पूर्ति हेतु कुछ नये प्रस्ताव रखे वह इस प्रकार से हैं :-

1. केन्द्रीय सरकार आन्तरिक और विदेशी ऋणों का भुगतान करने की व्यवस्था करे जो क्रमशः 44,414,085 डालर और 11,710,378 डालर थे।

2. युद्धकालीन ऋण भार केन्द्रीय सरकार वहन करे ।
 3. विदेशी माल पर अधिक कर लगाया जाय । इसके अतिरिक्त शराब पर भी कर लगाया जाय ।
 4. केन्द्रीय सरकार एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का अधिकार प्रदान करे ।
- हैमिल्टन की इन योजनाओं से कांग्रेस में काफी द्वेष हो गया विपक्षियों ने यह कहना प्रारम्भ किया कि पूर्णरूपेण ऋण को समाप्त करने में देश नष्ट-प्राय हो जायेगा और कम दर पर सरकारी ऋण पत्र क्रय करने वाले लाभान्वित होंगे । इसके अतिरिक्त संघीय बैंक असंवैधानिक था । इस पर अन्तराल तक वाद विवाद होता रहा अंत में हैमिल्टन अपनी योजना पूर्ति में कांग्रेस को सहमत करने में सफल हुये । सरकारी ऋण की अदायगी में कांग्रेस के अधिकांश सदस्य हैमिल्टन से सहमत थे । किन्तु अनेक कांग्रेस के सदस्य इस प्रस्ताव से असहमत थे कि ऋण के पुराने प्रमाण पत्रों को नये प्रमाण पत्रों के मूल्य पर परिवर्तित कर दिया जाय । 1780 में जब राष्ट्र संकट कालीन समय से ग्रस्त था, इन प्रमाण पत्रों के अधिकारी इन्हें मूल्यांश पर विक्रय के लिये बाध्य हो गये थे । अन्ततः कांग्रेस को ऋण भुगतान अधिनियम को हैमिल्टन की इच्छानुसार पारित करना पड़ा ।

हैमिल्टन को राज्य सरकारों के युद्ध ऋणों को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण समापन अधिनियम पारित कराने में काफी संकट का सामना करना पड़ा । विपक्षी यह तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कि इसमें राज्य के अन्य लोगों को भी ऋण भुगतान के लिये केन्द्रीय सरकार अन्य राज्यों के ऋण समापन के लिये कर प्रदत्त करने पड़ेंगे । वर्जीनिया से अधिक मात्रा में मैसाचुसेट्स के ऋण थे, वर्जीनियावासी यह अनुपयुक्त समझते थे कि वे मैसाचुसेट्स के ऋण को भी अदा करें । अतः उन लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया । इसके लिये हैमिल्टन ने जैफरसन से समझौता किया । उपरोक्त समझौते में हैमिल्टन वर्जीनिया वासियों की इस भावना से लाभान्वित हुये कि वे राष्ट्र की राजधानी अपने समीप दक्षिण में बनाने के इच्छुक थे अतः वर्जीनिया के समर्थन को दक्षिण में राजधानी बनाने में उत्तर के समर्थन के बदले निश्चित कर लिया गया ।

हैमिल्टन के बैंक बिल को कांग्रेस में पेश किये जाने पर मैडिसन तथा जैफरसन ने इस बिल को असंवैधानिक कहकर उसका तीव्र विरोध किया । वास्तव में जैफरसन तथा हैमिल्टन का संघर्ष एक सैद्धान्तिक मतभेद का प्रतिफल था । जैफरसन समाज के उच्च तथा पूंजीपति वर्ग द्वारा कृपकों का लाभ हो सकता है । इसपर सहमत नहीं था जबकि हैमिल्टन के अनुसार धनिक वर्ग

के पूंजी तथा ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र लाभान्वित हो सकता था। हैमिल्टन पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था और जैफरसन कृषक वर्ग का। जैफरसन इस पक्ष में कदापि नहीं था कि राष्ट्रपति तथा कांग्रेस को इस प्रकार का राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया जाय क्योंकि संविधान में संघीय शासन के अधिकारों के अन्तर्गत यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। इसके अनुसार इस प्रकार का कोई भी अधिकार "शक्तियों के केन्द्रीयकरण का प्रारम्भ होगी परन्तु हैमिल्टन के अनुसार समस्त अस्पष्ट अधिकार संघीय शासन के पास थे। इसके अतिरिक्त कर, वाणिज्य तथा ऋण के क्षेत्र में बहुत से अधिकार संघ के पास होने से राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने का उसका औचित्य भी अस्पष्ट नहीं था।

यद्यपि इस प्रस्ताव से अधिकतर लोग सहमत थे किन्तु वाशिंगटन ने अपने सलाहकारों से इस विषय पर विचार विमर्श किया वाशिंगटन ने सब पर विचार करने के बाद हैमिल्टन की राय को अधिक उपयुक्त समझा और बैंक बिल पर हस्ताक्षर कर उसे पारित कर दिया। 1791 में इस बैंक ने एक अधिकार पत्र के अन्तर्गत कार्य किया जिसके अनुसार 20 वर्ष के लिये उसे कार्य करने के अधिकार प्रदान किये गये।

ह्विस्की विद्रोह

हैमिल्टन ने आवश्यक कर की अनियमित व्यवस्था के कारण पश्चिमी प्रान्तों की कर व्यवस्था को पुनः परिवर्तित किया। हैमिल्टन की इस परिवर्तित नीति के कारण पश्चिमी प्रान्तों में रोष की भावना का उदय हुआ क्योंकि इन प्रान्तों को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की कर व्यवस्था का सामना करना पड़ा। इस कर ने उन कृषकों पर एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया जो अपने अतिरिक्त अन्न के द्वारा ह्विस्की बना कर धन उपार्जित करते थे। अपने अन्न की विक्री कृषक इसलिये नहीं कर पाता था कि यातायात के साधन उपयुक्त नहीं थे ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की कर योजना ने आक्रोश की भावना को प्रेरित किया। पिट्सवर्ग के निकटवर्ती जिलों में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। वहाँ की जनता ने राजस्व कर अधिकारियों की पूर्ण-रूप से अवहेलना की तथा हिसावादी तत्वों ने न्याय विरोधी कार्य प्रारम्भ कर दिये। राज्यपाल को निधि व्यवस्था की स्थापना हेतु सेना का प्रयोग करना चाहिये था परन्तु अपने मतदाताओं के भय से उन्होंने कोई सफल नीति का प्रयोग नहीं किया। अंततः, 1794 में हैमिल्टन के परामर्श पर राष्ट्रपति वाशिंगटन को कठोर अनुशासन नीति का परिपालन करना पड़ा। हेनरी ली के

अन्तर्गत सेना ने उपद्रवकारियों को दबाकर पुनः स्थिति को नियंत्रण में कर लिया तथा संधीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हैमिल्टन की नीति ने जनता को उत्तेजित किया तथा संधीय शक्ति को स्थापित किया इस आवकारी कर नीतियों में स्थायी स्थान निर्मित नहीं किया।

दलों का उद्भव

संधीय युग का प्रारम्भ एकता की भावना के साथ हुआ था, परन्तु राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों के कारण वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। हैमिल्टन के प्रशासनिक महत्व की आधारशिला पर ही दलों का उद्भव सम्पन्न हुआ। वाशिंगटन के राज्य सचिव जैफरसन ने इन सैद्धान्तिक मतभेदों के आधार पर विरोधों को एक विरोधी दल का स्वरूप प्रदान किया। दलों के उद्भव का शिलान्यास, जैफरसन ने 1791 में मेडिसिन, जार्ज क्लिन्टन, लिविंगस्टन, एरन बर से विचार विमर्श कर न्यूयार्क एवं वर्जीनिया के वाटेनाईजिंग एक्जकरान द्वारा प्रारम्भ किया। 1791 तक यह स्पष्ट हो चुका था कि विरोधी दल अवश्यम्भावी है परन्तु वाशिंगटन के कार्य काल तक अभी स्पष्ट रूप रेखा नहीं तैयार हो सकी थी। जैफरसन तथा हैमिल्टन दोनों ने वाशिंगटन को द्वितीय कार्य काल के लिये आमंत्रित किया परन्तु 1793 तक जैफरसन, हैमिल्टन के प्रशासन में अत्यन्त अनावश्यक तत्व हो जाने के कारण, त्यागपत्र देने पर बाध्य हो गया। वाशिंगटन ने एडमण्ड रैण्डाल्फ को अपना राज्य सचिव नियुक्त कर लिया। यद्यपि वाशिंगटन के कार्यकाल के अन्तिम चरण तक उसका कैबिनेट संधीय रहा। इन परिस्थितियों ने शनैः शनैः दो दलों का निर्माण किया जिसमें एक संधीय दल था तथा द्वितीय प्रजातांत्रिक-गणतांत्रिक दल।

संधीय शासन प्रारम्भ में संगठित रूप से प्रारम्भ हुआ परन्तु शीघ्र ही विभिन्न समस्याओं पर पारस्परिक मतभेद दृष्टिगोचर होने लगा। इस मतभेद के क्षेत्र में हैमिल्टन व जैफरसन मुख्य प्रतिद्वन्दी थे व जैफरसन के प्रमुख सिद्धान्तों में निम्नलिखित कार्य नियत थे :—

- 1- लोकतांत्रिक भूमि सम्बन्धी कार्य।
- 2- सम्पत्ति का विस्तार।
- 3- ऋण को व्याज की ओर सहानुभूति का दृष्टिकोण।
- 4- केन्द्रीय सरकार के प्रति अविश्वास।
- 5- मनुष्यता की पूर्णता में विश्वास।
- 6- जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासित करने का अधिकार।

इसके समानान्तर हैमिल्टन के विचार थे कि :—

- 1— संतुलित विविधता पर आधारित आर्थिक व्यवस्था ।
- 2— वित्त, उद्योग, वाणिज्य तथा पोत परिवहन को सरकारी प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- 3— ऋणदाता व्याज के प्रति सहानुभूति ।
- 4— सशक्त राष्ट्रीय सरकार ।
- 5— जन प्रशासन के प्रति अविश्वास ।
- 6— विशिष्ट वर्ग की सरकार के प्रति आस्था ।

हैमिल्टन व जैफरसन की नीतियों का मतभेद केवल उनका व्यक्तिगत विचारधारा का एक न होना था परन्तु दो राष्ट्रीय दलों की विचारधारा का भी पोषक था जैफरसन के दल को “गणतंत्रीय दल” अथवा लोकतांत्रिक गणतंत्रीय दल भी कहा जाता था । इसी प्रकार हैमिल्टन की विचारधारा से संघीय दल प्रेरित था । जब 1789 तक फ्रांस की क्रान्ति का उदय हुआ तो अमरीका भी क्रान्ति के मूल तत्वों स्वतंत्रता, समानता भ्रातृत्व से प्रभावित हुआ परन्तु समय के साथ राजनैतिक दलों ने अपनी सहानुभूति को भी राजनीतिक रूप प्रदत्त किया । “जैफरसन की “लोकतांत्रिक गणतंत्रीय दल” की सहानुभूति फ्रान्स के साथ थी और हैमिल्टन के “संघीय दल” की विचारधारा ब्रिटेन के साथ गठबन्धन करने की इच्छा से प्रेरित थी ।

वैदेशिक नीति :

वाशिंगटन की वैदेशिक नीति से अधिकांश लोग असंतुष्ट थे । जैफरसन का विश्वास था कि वाशिंगटन की आन्तरिक व वैदेशिक नीतियों पर हैमिल्टन का प्रभाव है । 1179 में यूरोप में फ्रान्स व ब्रिटेन के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध की प्रतिक्रिया अमरीका में बहुत तीव्र गति से हुई । मुख्यरूप से न्यू इंग्लैण्ड में व्यवसायिक वर्ग तथा अनेक धार्मिक व्यक्ति गणराज्य से घृणा करते थे, उससे उनके हितों को हानि पहुँचती थी । दक्षिण के कृषकों के शहर मैकेनिकों की फ्रान्स से सहानुभूति थी । 20 अप्रैल 1792 को फ्रान्स ने आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । जिसने समस्त यूरोप को युद्धरत कर दिया । फरवरी 1793 में ग्रेटब्रिटेन के साथ फ्रान्स ने युद्ध कर दिया । फ्रान्स समझता था कि 1778 की संधि जिसके अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका मित्रता के लिए बाध्य था, अब भी लागू है और युद्ध से अलग रहेगा ।

अतः वाशिंगटन ने अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर 22 अप्रैल, को

तटस्थता की घोषणा जारी कर दी परन्तु इस घोषणा की तीव्र निन्दा हुई। इसका लाभ उठाने के लिये अमरीका में नियुक्त फ्रान्सीसी राजदूत गिनेट ने अमरीकी जनता से सीधे अपील कीं और जब सरकार ने अपने बन्दरगाह फ्रांसीसीयों के जहाजों के संचालन के लिये बन्द कर दिये तो गिनेट ने उक्त आदेश का उल्लंघन किया जिससे वाशिंगटन नाराज हो गया और उसने कठोरता से कार्यवाही करने का आदेश दिया। गिनेट के इस व्यवहार से अमरीका में फ्रांसीसी समर्थक दल को काफी अपमानित होना पड़ा।

जे० की सन्धि

पेरिस की सन्धि के पश्चात संयुक्त राज्य और ग्रेट ब्रिटेन के सम्बन्धों में काफी दरार पड़ गयी थी। उनमें से इंग्लैण्ड का उत्तरी पश्चिमी सीमाओं को खाली करने, आदिवासियों का विद्रोह तथा ब्रिटिश द्वारा अमरीका के वाणिज्य पर प्रतिरोध इत्यादि मुख्य कारण थे। इसके अतिरिक्त 1793 को इंग्लैण्ड तथा फ्रांस के युद्ध में इंग्लैण्ड ने अमरीका की तटस्थता को स्वीकार नहीं किया।

उक्त मतभेदों को देखते हुये जान जे जो एक अनुभवी कूटनीति के साथ-साथ मुख्य न्यायधीश भी था को 1794 में लन्दन भेजा गया। जान जे 19 नवम्बर, 1794 को ब्रिटेन के साथ संधि करने में सफल हुये। अपनी कुशलता तथा बुद्धिमत्ता से वह सब कुछ प्राप्त करने में सफल हुआ जिसके लिए उसे भेजा गया था। ब्रिटिश लोगों ने अमरीका में स्थित ब्रिटिश चौकियों को इस शर्त पर हटाना स्वीकार किया कि ब्रिटिश जनता को वहां व्यापार की अनुमति होनी चाहिये। मुख्य सीमा रेखा को स्थापित करने के लिये आयोग स्थापित करना, अमरीकी जहाजों की क्षतिपूर्ति तथा ब्रिटिश ईस्ट तथा वेस्ट इंडीज में अमरीकी वाणिज्य व्यापार की सुविधायें 10 वर्ष तक प्राप्त करने का वचन जे को प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ अमरीकी लोगों को युद्ध के पहले ब्रिटिश व्यापारियों के कर्जों को चुकाने तथा ब्रिटिश वेस्ट इंडीज के साथ रूई चीनी और शीरे का व्यापार बन्द करना स्वीकार करना पड़ा। इस सन्धि पर अमरीका में बहुत तीव्र उत्तेजना प्रदर्शित कीं गयी। जान जे के पुतले जलाये गये, सम्पादकों तथा वक्ताओं ने वाशिंगटन की निन्दा की लेकिन वाशिंगटन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तथा गिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ सन्धि स्वीकार कर ली जिससे व्यापारिक वर्ग ने राष्ट्रीय सरकार के प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त किया।

1795 की पिकने संधि

ब्रिटेन अमरीका के मध्य समझौते से मेडिड में स्पेन के विदेश मंत्री को उत्तरी अमरीका के अधिकृत प्रदेश पर खतरा प्रतीत होने लगा। अमरीका के सीमान्तवासी दक्षिणी पश्चिम में पढ़ने के लिये निरन्तर दबाव डाल रहे थे अतः स्पेन को चिरकाल तक अपने सीमान्तों पर अधिकार रख पाने में संशय होने लगा। जब थामस पिकने एक विशेष दूत के रूप में आया तो उसे वह सब कुछ आसानी से सुलभ हो गया जिसके लिये अमरीकी दस वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षारत थे। इस सन्धि में अमरीका वासियों को मिसिसिपी के मुहाने पर्यन्त नौवाहन का अधिकार प्रदान किया गया तथा समुद्री जहाजों पर सामान लादने के लिये न्यु ओरलीयेन्स में सामान जमा करने का अधिकार भी दे दिया गया। फ्लोरिडा का सीमा निर्धारण भी किया गया। इस प्रकार अमरीका ने ब्रिटेन और स्पेन द्वारा अपने अधिकारों को स्वीकार करा लिया था।

जॉन एडम्स

1796 में राष्ट्रपति वाशिंगटन के अवकाश प्राप्त कर लेने के पश्चात् जान एडम्स अमरीका के दूसरे राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। जान एडम्स योग्य, उच्चाशय, मनस्वी परन्तु कठोर तथा अपनी स्वभाव विशेषता के चारित्रिक गुणों से युक्त थे। अपने स्वभाव के कारण राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व ही वह हैमिल्टन के विचारों से असहमत थे। इस प्रकार एडम्स को पदासीन होते ही अपनी परोक्ष में विभक्त दल और अपने समीप विभक्त मंत्रिमण्डल का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय गगन पर गम्भीर समस्याओं के वादल आच्छादित थे। इन सब में फ्रांस की समस्या अधिक चिन्ताजनक और महत्वपूर्ण थी। फ्रांस की स्थिति जे० की सन्धि के कारण तनाव पूर्ण हो चुकी थी। उसको तनाव मुक्त करने हेतु एडम्स ने अपने तीन प्रतिनिधियों को फ्रांस भेजा ये तीन प्रतिनिधि थे—जॉन मार्शल, एलब्रिज गेरी और चार्ल्स पिकने। इन प्रतिनिधियों के फ्रांस पहुँचने पर वहाँ के विदेश मंत्री तैलिरॉ ने इस विशिष्ट मंडल से भेंट करना उचित नहीं समझा और अपने तीन अभिकर्ता एवं परिसहायक अमरीका से आये प्रतिनिधियों से मिलने भेजा। तैलिरॉ के अभिकर्ताओं को अमरीकी दूतों ने अपनी विज्ञप्तियों में एक्स० वाई० जेड० नामकरण किया। इन प्रतिनिधियों की पारस्परिक भेंट वार्ता में फ्राँसीसी प्रतिनिधियों ने अमरीका से ऋण और दो लाख 50



जॉन एडम्स (1735-1826)
अमरीका के दूसरे राष्ट्रपति

हजार डालर रिश्वत की माँग की। फ्रांस के इस प्रकार की वार्ता के द्वारा अमरीका में आक्रोश की भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और 1798 में अमरीका और फ्रांस के मध्य समुद्री युद्धों का अनुक्रम आरम्भ हो गया। इन छोट-छोट समुद्री युद्धों में अमरीका फ्रांस को पराजित करता रहा और प्रकट रूप से युद्ध की सम्भावना तीव्रता से बढ़ती गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि अमरीका और फ्रांस के मध्य समस्याएँ युद्ध के रूप में परिणत हो जायेंगी।

निःसंदेह, राष्ट्रपति एडम्स के कठोर व्यक्तित्व ने राष्ट्रहित किया। युद्ध के इच्छुक हैमिल्टन के परामर्श को मान्यता न देकर अपने एक नये मंत्री विलियम वान्समरे को फ्रांस भेजने का निश्चय किया। इससे पूर्व फ्रांसीसी विदेश मंत्री तैलिरॉ ने इस बात का आश्वासन दिया कि अमरीका के मंत्री का उचित स्वागत किया जायेगा। इसी मध्य राष्ट्रपति पर संधीय दबाव ने राष्ट्रपति को एक मंत्री भेजने के स्थान पर एक शिष्ट मंडल भेजने पर बाध्य किया।

जब इस शिष्ट मंडल की फ्रांस में प्रथम वार्ता आरम्भ हुई तब तक फ्रांस में भ्रष्ट और मूर्ख “फ्रेंच डायरेक्टरी” के स्थान पर नेपोलियन का सशक्त शासन आरम्भ हो चुका था। इस परिवर्तन के कारण अमरीका को फ्रांस से संधि करने में पूर्वोक्त कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ा। 30 सितम्बर, 1800 में फ्रांस और अमरीका में मार्फनटेन की संधि की जो कि 1800 के सम्मेलन के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इस सम्मेलन ने यह निर्णय लिया कि पुरानी संधियों को समाप्त कर नवीन सम्बन्ध स्थापित करने पर बल दिया गया।

राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने इस प्रकार अपने देश को युद्ध से सुरक्षित रखा तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को विस्फोटक होने से बचाया।

विदेशीय तथा राजद्रोही अधिनियम

अमरीका तथा फ्रांस की यौद्धिक स्थिति से लाभ उठाकर राष्ट्रपति एडम्स ने अपनी गृह नीति को सशक्त बनाने हेतु चार विदेशीय तथा राजद्रोही अधिनियमों को पारित किया :-

1. देशीकरण अधिनियम :- इस अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण-रूपेण नागरिकता प्राप्त करने हेतु अमरीका में 5 से 14 वर्ष की निवास अवधि का होना अनिवार्य माना गया।
2. विदेशी अधिनियम :- इस अधिनियम के द्वारा अमरीका के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि उन सब विदेशियों को जिनसे आंत-

रिक शांति तथा सुरक्षा का भय हो उनको राष्ट्रपति देश से निष्कासित कर सकता था ।

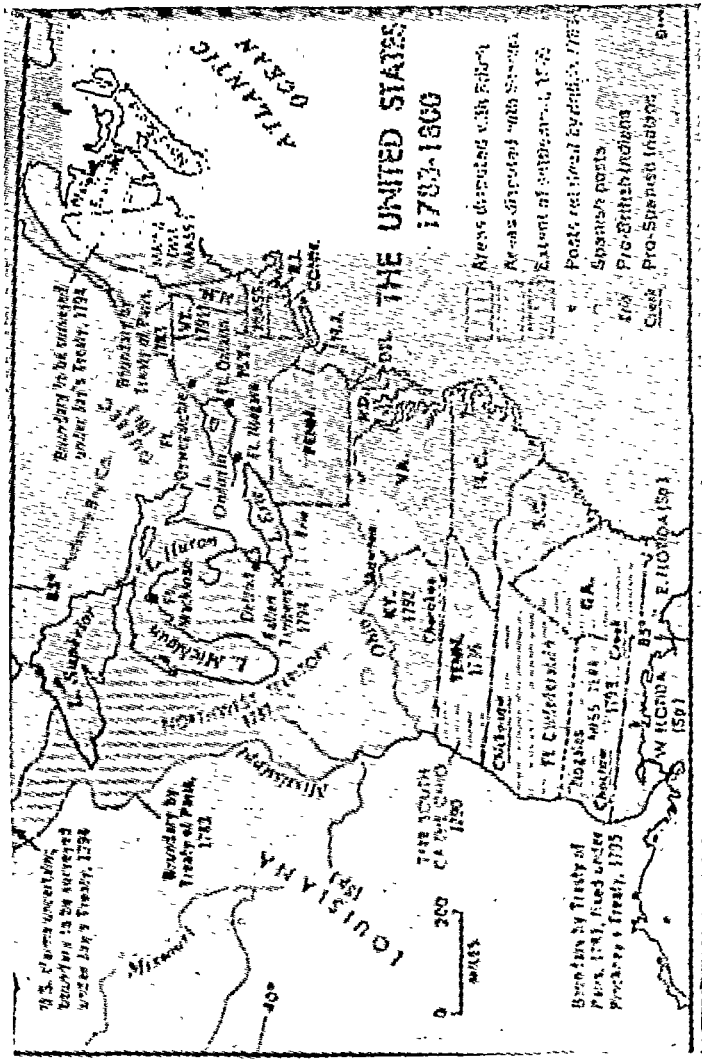
3. विदेशी शत्रु अधिनियम :—इस अधिनियम के मुख्य प्राविधान के द्वारा राष्ट्रपति को युद्ध के समय धार्मिक कारण, अन्य देशीय तत्वों को बंदी बनाने का अधिकार दिया जाना ।
4. राजद्रोही अधिनियम :—इस अंतिम अधिनियम के द्वारा किसी भी न्याय-युक्त सरकारी कार्य के विरोध करने पर अपराधी सिद्ध करना था । इसके अन्य प्राविधानों में सरकारी आलोचना तथा विद्वेषपूर्ण लेख के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्रयोजन था ।

उपरोक्त असंवैधानिक अधिनियमों की भर्त्सना गणतंत्रीय तथा अन्य उदारवादी मानवीय अधिकारों के पोषण करने वाली विचारधारा की जनता ने की । संघीय नेताओं में केवल जान मार्शल ने ही प्रकट रूप में इन अधिनियमों की आलोचना की । उसने इनको नैसर्गिक अधिकारों से वंचित बताया ।

कैन्टेकी तथा वर्जीनिया का प्रस्ताव

1798-99 में टामस जैफसन तथा मैडीसन ने कैन्टेकी और वर्जीनिया की विधान सभाओं से स्वरचित प्रस्ताव पारित कराये । इन प्रस्तावों में इस तथ्य को उद्घोषित किया गया कि “विदेशी तथा राजद्रोही अधिनियम” असंवैधानिक थे और अन्य प्रदेशीय विधान सभाओं से विरोध प्रकट करने के लिये आह्वान किया । इसमें कैन्टेकी विधान सभा ने इस तथ्य की पुष्टि की कि प्रदेशीय सरकारों को इस बात का पूर्ण अधिकार है कि वह संविधान के उल्लंघन को मान्यता न दे । 1800 में गणतंत्रीय दल ने उपरोक्त समस्त अधिनियम अथवा प्रस्तावों को चुनाव लाभ हेतु प्रमाणित किया । इस प्रकार 1800 में जान एडम्स का शासन काल समाप्त हुआ और स्वयं के शब्दों में उनके समाधिलेख पर निम्नलिखित शब्द अंकित होने चाहिये—“यहाँ जान एडम्स शान्त स्थित हैं जिन्होंने 1800 में फ्रांस के साथ शान्ति स्थापित करने का उत्तरदायित्व लिया ।”





संयुक्त राज्य अमरीका (1783-1800)

लोकवाद



टॉमस जैफरसन (1743-1826)
अमरीका के तीसरे राष्ट्रपति

अध्याय 3

टामस जैफरसन

अब्राहम लिंकन के पश्चात्, टामस जैफरसन का स्थान अमरीका के इतिहास में अद्वितीय है। इनके विचार में किसी भी शासन अथवा सामाजिक संस्था का प्रमुख कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को विना किसी भेद-भाव के सुरक्षा प्रदान करना था। वर्जीनिया के कृषक समाज का पर्याप्त प्रभाव उनके विचारों तथा दृष्टिकोणों में परलक्षित होता था। उनके अनुसार नैतिकता तथा राजनैतिक क्षमता के लिये कृषि उपर्युक्त जीवन स्थापना थी। बड़े नगर व्यक्ति को भ्रष्टाचार की दिशा में प्रेषित करते हैं। अतएव उनके अनुसार अमरीका के निवासियों की अधिकारिक सुरक्षा तभी सम्भव थी जब तक कि वह कृषक जीवन यापन पर आधारित हो। जैफरसन प्रतिष्ठित, विद्वान तथा विवेकी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके राजनैतिक विचार बहुत कुछ समाजवादी तथा प्रजातान्त्रिक थे। वह संवेदनशील होते हुये भी भावुक नहीं थे।

4 मार्च, 1801 को प्रातः टामस जैफरसन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। जैफरसन प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका उद्घाटन भाषण वार्शिंग्टन में हुआ क्योंकि 1800 में वार्शिंग्टन राजकीय रूप से राजधानी घोषित की गई। जैफरसन प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने जार्ज वार्शिंग्टन के समय से चले आ रहे कांग्रेस को उद्घोषित करने के नियम को भंग किया। उन्होंने कांग्रेस को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधित करने की परम्परा को भंग कर लिखित भाषण भेजा। 6 फीट, 2.5 इंच लम्बे जैफरसन एक कृषक के रूप में दिखाई दे रहे थे। यद्यपि वह एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। जैफरसन के राजनैतिक विचार प्रजातंत्रवादी की तुलना में समाजवादी अधिक थे। वह वास्तव में राजनीतिज्ञ कम दर्शन शास्त्री अधिक थे। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उन्हीं के राजनैतिक विचारों की नींव पर आज अमरीका का लोकतंत्र आधा-

रित है। उन्होंने अपने विरोधी संघवादियों को आलोचना के विपरीत उनको सच्चे गणतंत्र में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया।

चैनिंग के अनुसार जैफरसन एक ऐसे आदर्शवादी थे जो कि अमरीका की राजनीति में देश को एकाधिकार से बचाने की इच्छा से कार्यरत थे। वास्तव में जैफरसन एक सुधारवादी थे। इसलिये उन्होंने अभिजातीय वर्गीय प्रणाली का सदैव विरोध किया। वह धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने के भी पक्ष में नहीं थे। जैफरसन ने सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना की तथा नागरिक एवं दंड संहिता का पुर्नवलोकन कर यातनामय दण्ड प्रणाली को समाप्त कर दिया। उन्होंने दास प्रथा का उन्मुक्त रूप से विरोध किया एवं नीग्रो जाति के कल्याणार्थ विभिन्न सुधारात्मक योजनायें तैयार करवाईं। वह वास्तव में जननायक थे तथा जनता के कल्याण एवं राष्ट्र की उन्नति में विश्वास रखते थे।

जैफरसन यथार्थवाद के प्रतिपादक थे और यही कारण था कि उन्होंने यूनानी विचारकों के सिद्धान्तों को अप्रभावी माना। यहाँ तक कि प्लेटों के सिद्धान्तों से भी वह प्रभावित नहीं थे। इसके विपरीत वे मान्टेस्क्यू के राजनैतिक दर्शन से प्रर्याप्त प्रभावित थे। टामस पेन के मनावाधिकारों के प्रशंसक होने के कारण उनका कहना था कि अमरीका को एक बुद्धिमत्तापूर्ण और मितभापी सरकार चाहिये जो देश में व्यवस्था कायम रखे किन्तु अन्य रूप में जनता को अपने कार्य करने हेतु और अपनी स्थिति को सुधारने के लिये निर्बाध छोड़ दें। श्रमिकों को भोजन विशिष्ट करना जैफरसन की मानस दर्शन में निहित नहीं था अर्थात् श्रमिकों के मुँह से उसकी अर्जित रोटी न छीने, इसके अतिरिक्त उसे राज्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये। उन्हें सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु अस्पष्ट मित्रता का वह विरोधी था। उनके अनुसार अमरीका को किसी भी राष्ट्र से अस्थायी एवं अस्पष्ट मित्रता नहीं करनी चाहिये। यह जैफरसन का एक ऐसा मुहावरा था जो बहुत दिनों तक याद रखा गया। जैफरसन ने यह आश्वासन दिया कि वह अपने वैज्ञानिक सिद्धान्तों द्वारा "सैनिक अधिकारियों के ऊपर नागरिक अधिकारों की श्रेष्ठता" प्रतिपादित कर देंगे तथा वह लोकप्रिय चुनावों की सहायता से स्वतंत्रजित क्रान्ति की सम्भावनाओं को समाप्त कर देने में समर्थ होंगे।

जैफरसन निरन्तर दो बार राष्ट्रपति रहे। उनके राष्ट्रपतित्व काल में गणतान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक कार्यवाहियों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष पद के साथ संलग्न प्रशासनिक आडम्बर एवं राजकीय समारोहों

को समाप्त कर दिया। साप्ताहिक दरवार बन्द कर दिये गये। राजदरवार के शिष्टाचारों एवं शब्दों को समाप्त कर दिया गया तथा महामहिम, एक्सलेन्सी जैसे सम्मानिक शब्दों को प्रशासनिक भाषा से बहिष्कृत कर दिया गया।

जैफरसन ने अपने अधिकारियों को जनता का न्यायी मानकर चलने की शिक्षा दी। उसने कृषि को प्रोत्साहन दिया और आदिवासियों के उत्पादनों को क्रय कर भूमि का बन्दोबस्त किया उनको पश्चिम की ओर निवसित होने में सहायता प्रदान की। जैफरसन का विश्वास था कि राजनीतिक प्रजातंत्र तथा कृषि समाज के मध्य एक घनिष्ट समन्वय होना आवश्यक है। अतः उसने ऐसे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन नहीं दिया जिससे कृषि को हानि पहुँचती हो।

जैफरसन का प्रशासन

जैफरसन के प्रशासन का प्रथम वर्ष अत्यन्त ही शान्त एवं प्रगतिशील रहा। अमियाँ की संधि ने यूरोप के लिये (मार्च 1802-मार्च 1803) एक प्रकार से युद्ध विराम का कार्य किया जिसके कारण जैफरसन गृह समस्याओं की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित कर सके। गणतंत्रिक दल का कांग्रेस के दोनों सदनों पर अधिकार था साथ ही जैफरसन का मन्त्रिमण्डल भी सुयोग्य एवं क्रियाशील व्यक्तियों से परिपूर्ण था। जेम्स मेडिसन (सेक्रेटरी आफ स्टेट) राज्य सचिव एक बुद्धिमान एवं योग्य व्यक्ति था जो कि राष्ट्रपति के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार था। सेक्रेटरी आफ ट्रेजरी (वित्त सचिव) एल्वर्ट गैलेटिन जिसका जन्म स्थान स्वित्जरलैण्ड था, एक दूरदर्शी व्यक्ति था। इसके विपरीत भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि जैफरसन को संघवादियों को गणतंत्रवादियों के सिद्धान्तों को स्वीकार करना पड़ा और संघवासियों को गणतंत्रवादियों के सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। जैफरसन को स्वीकार करना पड़ा "कि हम सब गणतंत्रवादी हैं और हम सब संघवादी हैं।"

संधीवादी नीतियों में परिवर्तन

जैफरसन को विधिव व्यवस्था की स्थापना में संघवादी नीतियों में (जिनको वह संघवादी नियमों के विपरीत समझते थे) परिवर्तन करना पड़ा। देशीयकरण (नेचुरलाइजेशन) अधिनियम को समाप्त कर दिया गया तथा नागरिकता के लिये .5 वर्ष का समय निर्धारित कर दिया गया। जैफरसन ने विदेशी अधिनियम तथा राजद्रोह अधिनियम के अन्तर्गत पाये गये व्यक्तियों को क्षमा प्रदान कर दी। 1800 के न्याय अधिनियम को परिवर्तित

कर दिया और मिडनाइट न्यायाधीशों को हटा दिया गया। इस कानून के अन्तर्गत एडम्स ने जाते-जाते सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर संघवादियों को नियुक्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त बैंक आफ यूनाइटेड स्टेट को तदानुसार कार्य करने दिया गया लेकिन आवश्यक कर जिसका वित्त सचिव एल्बर्ट गैलेटिन ने 'ह्विस्की विद्रोह' के समय विरोध किया था, को समाप्त कर दिया गया। अन्य कर भी कम कर दिये गये। जैफरसन ने शासकीय व्यय कम करने और राष्ट्रीय ऋण चुकता कर देने हेतु गैलेटिन को प्रोत्साहित किया जिसके परिणामस्वरूप 1806 में राष्ट्रीय आय से कम कर एक करोड़ पैतालिस लाख डालर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय व्यय केवल 85 लाख डालर हुआ। जिसके फलस्वरूप 60 लाख डालर की रकम बचत के रूप में उपलब्ध हुई। 1807 के अन्त तक गैलेटिन की मितव्यता के कारण राष्ट्रीय ऋण केवल सात करोड़ पचास लाख रह गया।

सम्पूर्ण राष्ट्र में जैफरसनवाद की लहर दौड़ गई। एक के पश्चात् दूसरा राज्य चुनाव में मत देने और पद ग्रहण के लिये सम्पत्ति की शर्तों को समाप्त कर रहा था और ऋणदाताओं तथा तत्सम्बन्धी अपराधियों के लिये उदार कानून पारित किये जा रहे थे लेकिन भाग्यवश जैफरसन तथा देश को एक ऐसी दिशा की ओर मुड़ने के लिये बाध्य कर दिया, जहाँ वे जाने के इच्छुक न थे। जैफरसन ने संविधान के सुदृढ़ निर्माण में योगदान दिया था और संघीय सरकार के अधिकारों को प्रोत्साहन दिया था। लेकिन जब उन्होंने पद त्याग किया तो युद्ध जिससे उनको घृणा थी, उनके समक्ष था।

लुईजियाना क्रय

राष्ट्रपति जैफरसन के प्रशासन में 'लुईजियाना क्रय' एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके साथ ही अमरीका के संविधान के लिये यह एक महत्वपूर्ण समस्या भी थी। पिकने की संधि ने पश्चिमी वाणिज्य समस्या को कुछ समय के लिये हल तो कर दिया था फिर भी स्पेन के साथ संघर्ष का होना निश्चित था, क्योंकि मिसिसिपी नदी के तटीय प्रदेश में बन्दरगाह होने से मसूद्री व्यापार में बाधाएँ पड़ने की सम्भावनायें थीं।

यद्यपि लुईजियाना और फ्लोरिडा स्पेन के निर्वल अधिकारों में थे अतएव इससे कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न नहीं होती थी लेकिन जब नैपोलियन ने निर्वल स्पेन को लुईजियाना का विशाल प्रदेश वापस फ्रांस को लौटा देने के लिये बाध्य कर दिया तो संयुक्त राज्य अमरीका के लिये यह एक संकट उत्पन्न हो गया। क्योंकि न्यू ऑर्लियेन्स ओहायो और मिसिसिपी के अमरीकी उत्पादकों

को जलयानों द्वारा निर्यात करने का एक मात्र बन्दरगाह था तथा नेपोलियन अमरीका के पश्चिम की ओर फ्रांस को एक औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में देखना चाहता था जिसमें कि वह उत्तरी अमरीका के 'एंग्लो सेक्सन उपनिवेश' को संतुलित कर सके।

जैफरसन ने इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने फ्रांस को चेतावनी दी कि अमरीका ब्रिटिश वेड़े और ब्रिटिश राष्ट्र की सहायता से न्यू आरलीन्ज (आर्लियेन्स) पर आक्रमण कर देगा। नेपोलियन जानता था कि आर्मियाँ की संक्षिप्त संधि के बाद ब्रिटेन के साथ दूसरा युद्ध सुनिश्चित है और लुइजियाना (लुइसियाना) उसके अधिकार से निकल सकता है। अतः उसको यह सम्भावना सत्य प्रतीत हुई कि अमरीका ब्रिटेन के साथ मिलकर आक्रमण कर सकता है। इसके साथ ही नेपोलियन के फ्रांसीसी शासित हैटी के 1802 के विद्रोहियों तथा पोलेम्बुखार के कारण भी निराशा थी। वह नीग्रो नेता तूस्सेल्ट-वरन्यूर को भी दवा नहीं पाया। इसलिये उसने लुइजियाना को ब्रिटिश लोगों के वजाय अमरीका को ही बेच देना उपयुक्त समझा जिससे कि संयुक्त राज्य से मित्रता हो सके और जो आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी हो।

लुइजियाना संधि

जैफरसन ने कांग्रेस से लगभग 2 मिलियन डालर प्राप्त कर लिये। जेम्स मनरो तथा लिविंगस्टन को फ्रांस और स्पेन भेजा गया। नेपोलियन ने 15,000,000 डालर में लुइजियाना (लुइसियाना) का विशाल प्रदेश अमरीका को विक्रय करना स्वीकार कर लिया और लिविंगस्टन तथा मनरो ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिये। यह अमरीकी इतिहास में एक ऐसी महान संधि थी कि लिविंगस्टन को कहना पड़ा "कि हम बहुत वर्षों तक जीवित रहेंगे" परन्तु हमारी जिन्दगी में यह कार्य सबसे महान है क्योंकि इस दिन से संयुक्त अमरीका विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक हो गया।"

इस एक सुखद समझौते से संयुक्त राज्य अमरीका ने 10 लाख वर्गमीटर से भी विशाल प्रदेश प्राप्त कर लिया लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में विदेशी भूमि को खरीदने की व्यवस्था नहीं थी। राष्ट्रपति जैफरसन ने दो बार यह प्रस्ताव रखा कि संविधान में संशोधन करके उक्त सौदे को स्वीकार किया जाय। 21 अक्टूबर, 1803 को न्यू इंग्लैण्ड के संघवादियों के अत्यन्त विरोध के पश्चात् भी कांग्रेस ने इस संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी।

जैफरसन का द्वितीय चुनाव

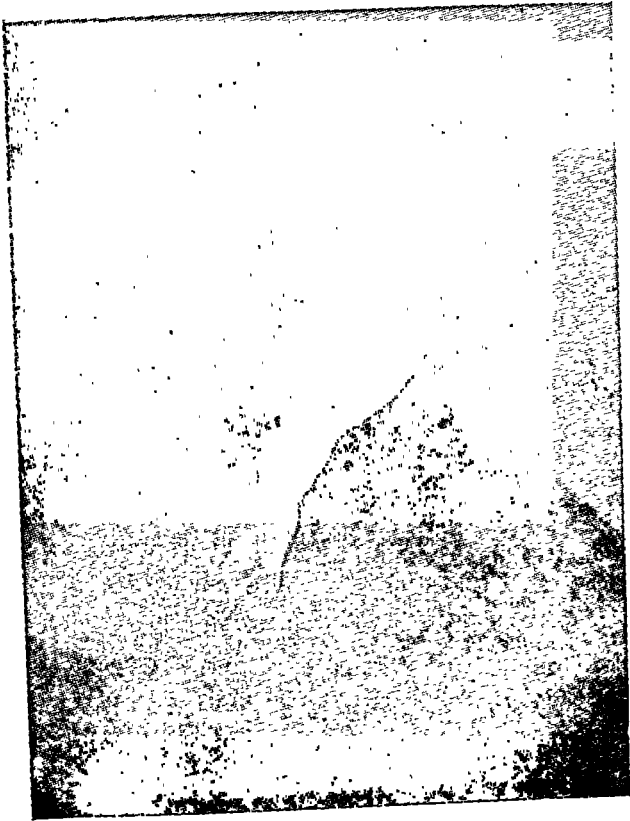
अपने प्रथम कार्य-काल के समाप्त होने तक वह सुदूर क्षेत्रों तक लोक-प्रियता प्राप्त कर चुके थे। लुईजियाना का ऋय उनकी जनप्रियता के लिये बरदान सिद्ध हुआ था इसके साथ-साथ ऋण का काफी हद तक भुगतान कर दिया गया था। करों में अत्यधिक कमी कर दी गई थी जिससे जनमानस शान्ति की साँसें ले रहा था। भूमि के प्रबन्ध हेतु उदार नीतियाँ अपनाई गई थी और संयुक्त राज्य अमरीका उन्नति के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जैफरसन संघवादियों की शक्ति को भी कम करने में आश्चर्यजनक रूप से सफल हुये थे जिसके कारण उनके विरोधी भी इस बात का विश्वास करने लगे थे कि राष्ट्र का संघीय स्वरूप राष्ट्रपति जैफरसन के हाथों में सुरक्षित है।

टामस जैफरसन का 1800 में चुनाव क्रान्ति तथा मूलभूत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता था। निःसन्देह वर्जीनिया के गणतन्त्रीय राष्ट्रपति अन्य संघीय राजनीतिज्ञों हैमल्टन तथा जान एडम्स राजनैतिक, सामाजिक, व आर्थिक विचारधारा में पृथक था परन्तु जैफरसन के सिद्धांतों तथा उसके प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक पद्धति में अन्तर था।

जैफरसन ने हैमिल्टन एवं उसके सहयोगियों द्वारा कृत संघीय संरचना में विशेष परिवर्तन लाने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने न तो मतदान के लिये सम्पत्तीय योग्यता पर आक्षेप किया और न ही प्रथम संयुक्त राज्य बैंक को समाप्त करने की चेष्टा की। यद्यपि संघीय सरकार की केन्द्रीयकरण की नीति में उसका अविश्वास था परन्तु केन्द्रीयकरण के विस्तार के अवरोध में विशेष प्रयत्न नहीं किया। हैमिल्टन ने उन नीतियों का परिपालन किया जिनसे व्यापारियों, साहूकारों तथा अन्य उच्च आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वालों का लाभ था क्योंकि उनके विचार में औद्योगीकरण के द्वारा राष्ट्र को शक्ति एवं सम्पत्तियुक्त किया जा सकता था। दूसरी ओर जैफरसन पूर्ण स्वामित्व की कृपक नीतियों के समर्थक थे परन्तु उनके शासन काल में औद्योगीकरण को दृढ़ आधार प्रदत्त किया गया।

इस प्रकार 1800 की तथाकथित क्रान्ति ने व्यापारिक एवं आर्थिक वर्ग से उच्च कृपक वर्ग की ओर किञ्चित् परिवर्तन किया। उसमें संशय नहीं कि जैफरसन और उसके दल की लोकप्रियता जनसाधारण के मध्य विशेषकर कृपकों में असीम थी उनके कृपकतत्व ज्ञान के द्वारा कृपक समाज का प्रत्येक वर्ग प्रभावित था।

यद्यपि जैफरसनने संघीय नीतियों का विपरीतीकरण न करके राष्ट्रीय



एलेगजैंडर हैमिल्टन (1757-1804)

अधिकारों का प्रयोग न्यूनतम किया। जैफरसन के समय में अधिकारियों का सामाजिक जीवन भी लोकतांत्रिक सुविधाओं से परिपूर्ण था।

जैफरसन के राजनैतिक विचार

अमरीका के प्रारम्भिक लोकतांत्रिक आन्दोलन में टॉमस जैफरसन का एक प्रमुख व्यक्तित्व था। जैफरसन का उद्भव स्वाधीनता घोषणापत्र के रचयिता के रूप में हुआ और वह निर्विवाद रूप से गणतन्त्रीय दल का नेता था जैफरसन के विचार किसी एक पुस्तक में निहित नहीं थे वरन् अनेक पुस्तिकाओं (पैम्फलेट), सरकारी प्रलेखों में तथा अमरीका व फ्रांस में अपने मित्रों के साथ विपुल पत्र व्यवहारिता में निहित थे, उसके मौलिक राजनीतिक सिद्धांत की आधार शिला जनविश्वास पर आधारित थी और वह मूल रूप से सशक्त केन्द्रित सरकार के विरुद्ध था। जैफरसन के ये सिद्धांत स्वयं में परस्पर विरोधी थे क्योंकि लोकतांत्रिक विचारों के विकास तथा जनशक्ति में विश्वास ने समय के साथ ही साथ सरकारी कार्य के विस्तार की मांग की इस प्रकार जैफरसन की यह मान्यता कि सरकार जनता के लिये होनी चाहिये, जनता की सरकार की भावना में परिवर्तित हो गई।

जैफरसन अपने स्वभाव के द्वारा एक उग्र सुधारवादी थे। उसने अपने स्वयं के प्रान्त में अभिजात वर्ग के ज्येष्ठाधिकार का अत्यन्त विरोध किया और धार्मिक संस्थाओं के स्थापन को भी मान्यता नहीं दी। जैफरसन ने नागरिक विद्यालय पद्धति को परिष्कृत किया और उन्होंने पुरातन न्यायविधि के स्थापन पर नवीन नागरिक एवं दण्डसंहिता का प्रतिपादन किया। उन्होंने दासता का प्रतिरोध किया तथा नीग्रो उपनिवेश योजना का विन्यास किया, जैफरसन का जनसाधारण में अटूट विश्वास उनकी राजनैतिक सफलता का मूलकारण था। यद्यपि जैफरसन के विचार मौलिक नहीं थे जिसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया परन्तु फिर भी उसके विचार व सिद्धांत अमरीकी मनोवृत्ति तथा मनोभाव के अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया सक्षम थे। जैफरसन अपने राजनीतिक साहित्य में सिडनी, जॉन लॉक एवं टॉमस पैन से प्रभावित थे। स्वयं अमरीकी क्रान्तिकारी आन्दोलन का सक्रिय नेता होने के कारण वह फ्रांसीसी लोगों के प्रयत्नों से सहानुभूति था जैफरसन अहस्तक्षेप नीति के प्रतिपालक थे तथा उनके विचार में राज्य को किसी के अधिकारों पर सरकार का अनाधिकार हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये था। वह रूस के स्वच्छन्दतावादी मत के समर्थक थे कि प्राकृत सर्वोत्तम है।

इसके अतिरिक्त जैफरसन सामाजिक अनुबन्ध को राज्य के लिये वास्तविक तथा ऐतिहासिक आधारशिला मानता था। अपने सिद्धांत को निष्पादित करने हेतु उन्होंने दो सुझाव रखे। क्रान्ति तथा समय-समय पर अनुबन्ध सहमति का नवीनीकरण करना। उनके विचार में शासकों के प्रति सतर्क दृष्टि रखना स्वतंत्रता की प्रत्याभूति थी। शासन का एक मात्र उत्तरदायित्व जनसाधारण के हित में लक्षित रखने का स्वप्न जैफरसन की महानतम इच्छा थी। इसलिये उन्होंने सरकार की असफल नीतियों के विरुद्ध क्रान्ति का आह्वान किया। जैफरसन के विचार में शासन की अहितकारी दमनकारी नीतियों को सहन करने की अपेक्षा गस्त्रधारण करना अधिक उचित था। क्रान्ति उनके अनुसार उन परिस्थितियों में उचित थी जिन राज्यों में अत्याचारी दमनकारी निरंकुश शासन था। गणतंत्रीय राज्यों में जैफरसन का विश्वास था कि निरन्तर संवैधानिक गोष्ठियाँ करते रहने से जनता तथा राज्य का समन्वय होता रहा है। जैफरसन का मत था कि प्रत्येक पीढ़ी को अपने निमित्त सामाजिक ढाँचे एवं न्यायपद्धति पर जीवित रहना चाहिये और तदनुसार सरकारी संस्थाओं को भी समय के साथ परिवर्तनशील होना चाहिये क्योंकि मैडिसन के सिद्धांत के विरुद्ध जीवित लोगों को शासन करना चाहिये न कि मृत लोगों को, अपितु यह आवश्यक नहीं कि पूर्वजों के संरचित सामाजिक, राजनैतिक एवं न्याय कार्य को ही मान्यता दी जाय बल्कि उन्हें कालचक्र के अनुसार परिवर्तित कर लेना चाहिये। जैफरसन एक बुद्धजीवी सिद्धांतवादी होने के नाते न्याय तंत्र को रूढ़िवादी परम्परा तथा सिद्धांतों के पक्ष में नहीं थे- उनके विचारानुसार लोकतांत्रिक जनमत की भावना न्यायतंत्र के चक्र में उलझ जाती थी। इसके साथ ही जैफरसन लोकप्रिय न्याय के पक्ष में थे क्योंकि उनका मुख्य राजनैतिक ध्येय लोकतांत्रिक सिद्धांतों की व्याख्या तथा जनसाधारण की भावना को सुख्यरित करने की ओर परिलक्षित था।

उद्योग कृपि एवं जैफरसन

जैफरसन राजनैतिक प्रजातंत्र, जन-नैतिकता तथा कृषक समाज के मध्य निकट संबंधों पर विश्वास करते थे। उत्पादनों की उन नीतियों को वह मान्यता नहीं प्रदान करते थे जो कृषि विकास के लिये हानिकारक थीं। 1781 में उसने कृषि के लाभों तथा उद्योगों के हानिकारक परिणामों पर एक निबन्ध भी लिखा। उनके अनुसार कृषि का कार्य करने वाले ईश्वर प्रिय होते हैं वह यूरोप के उन अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते थे जो इस सिद्धांत को

प्रतिपादित करते थे कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वपूर्ति के लिए ही उत्पादन करना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्येक नागरिक को स्वावलम्बी होना चाहिये और राष्ट्र को उन पर निर्भर रह कर गर्वित होना चाहिये न कि वह राष्ट्र पर एक बोझ बन जाय। अमरीका में यदि भूमि उपलब्ध थी तो वहाँ के नागरिकों को कृषि जनित उद्योगों पर निर्भर रहना चाहिए था। यूरोप के उद्योग, अमरीका के लिए पर्याप्त उत्पादन करते थे और अमरीकी निवासी भी पूर्णतया यूरोप पर ही आश्रित थे। नैतिकता के क्षेत्र में भी कृषक अपेक्षाकृत न्यून व भ्रष्ट थे। गणतन्त्र की सुरक्षा नागरिकों की नैतिकता एवं आत्मा से होती थी तथा उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता संविधान तथा अधिनियमों को विनष्ट कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैफरसन पूर्णतया कृषि के विकास हेतु समर्पित थे। बड़े उद्योगों, बड़े नगरों को वह प्रत्येक प्रकार से हानिकारक तथा असुविधाजनक मानते थे। उनकी इन मान्यताओं के पीछे अमरीका में उपलब्ध पर्याप्त भूमि तथा राजनैतिक नैतिकता की भावना निहित थी जिसका कि यूरोप में पर्याप्त अभाव था। यही कारण था कि जैफरसन यूरोपीय व्यवस्था को अमरीका के लिये उपयुक्त न समझ कर यूरोप के ही लिये उचित समझते थे।

गणतान्त्रिक प्रादुर्भाव

जैफरसन के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन को 1776 की क्रान्ति के समान ही एक परिवर्तन समझा जाता है क्योंकि उनके लिए तत्कालीन चुनाव संघवादियों की बढ़ती हुई राजतान्त्रिक शक्तियों के विरुद्ध प्रजातान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। जैफरसन एवं उनके अनुयायी प्रत्येक राज्य के अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार उन्हीं राज्यों के अधिकारों के अन्तर्गत निहित करने के पक्ष में थे। जैफरसन संविधान के विरुद्ध प्रत्येक नियमों को अप्रभावकारी तथा असंवैधानिक मानते थे। संवैधानिक शक्तियों के सिद्धान्तों पर दोनों दलों में अपरिमित मतभेद थे। जैफरसन विदेशी अधिनियमों के एवं राजद्रोह अधिकारियों के विरुद्ध थे। इन अधिनियमों का ध्येय राजनैतिक विरोध को समाप्त करना था। गणतन्त्रवादियों के विचारानुसार 'राजद्रोह अधिनियम' असंवैधानिक था क्योंकि संघ कार्यालयों का क्षेत्र केवल उन्हीं अपराधों के लिए वैधानिक था जिनका संविधान में वर्णन था उनका मत था कि इन न्यायालयों को संविधान के अनुसार कोई भी सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र नहीं प्राप्त था तथा उनका यह प्रयास संघ की शक्तियों

को संगठित करने के क्षेत्र में प्रथम चरण था। गणतन्त्रवादियों ने अपनी प्रतिक्रिया वर्जीनिया तथा केन्टकी के प्रस्तावों में प्रदर्शित की। ये दोनों प्रस्ताव स्वयं जैफरसन ने लिखे थे जिनके अनुसार सामान्य शासन के सदस्यों द्वारा जनसाधारण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के दुरुपयोग की स्थिति में जनसाधारण द्वारा परिवर्तन ही वास्तविक संवैधानिक प्रतिकार होना चाहिए। प्रत्येक राज्य को नैसर्गिक अधिकार था कि वह अपनी सीमाओं के अन्तर्गत किसी भी बाह्य अधिकारों के विरुद्ध अधिनियमों का विकास कर सके जिसके आधार पर वे अपनी सीमाओं में स्वयं अपनी स्वतन्त्र शक्तियों की आधार शिला प्रतिपादित कर सकें।

दक्षिणी गणतन्त्र, उत्तरी प्रजातन्त्र तथा संघवादी राजतन्त्र के मध्य उपस्थित विचारों के संघर्ष ने जैफरसन को सर्वाधिक प्रेरित किया यद्यपि उन्होंने अपनी विजय को प्रमुख तथा राजतन्त्रिक शक्तियों के विरुद्ध क्रान्ति की संज्ञा दी। इस प्रकार राष्ट्रपति जैफरसन स्वयं को नवीन गणतन्त्र का संस्थापक समझने लगे। वह इस विजय के पश्चात् गणतन्त्र के भविष्य के प्रति आशान्वित थे। उन्होंने अपने विचार में विश्व के सम्मुख यह उदाहरण रखा कि संघवादी शक्तियाँ राजतन्त्रिक केन्द्रीयकरण की द्योतक हैं। अतएव किसी भी प्रकार का केन्द्रीयकरण लोकतन्त्रीय सिद्धान्त के विपरीत था।

उनके विचार में अमरीका की कृषि सामर्थ्य सर्वथा मौलिक थी जिसके आधार पर निर्मित नीतियाँ अमरीकी जनता को समृद्ध एवं सम्पन्न बना सकती थी। वह बहुत उद्योगों, बैंकों तथा पूंजी पर आधारित किसी भी व्यवस्था के अलोचक थे। यह सिद्धान्त पूर्णतया: दक्षिणी गणतान्त्रिक मान्यताओं के अनुरूप थे। उत्तरी प्रजातन्त्र से इनमें कोई समानता नहीं थी। पेनसिलवानिया तथा तथा न्यू इंग्लैण्ड के प्रजातन्त्र में निहित 'स्वतंत्रता से ध्यार' कुछ सीमा तक इन गणतान्त्रिक सिद्धान्तों से समानता रखते थे परन्तु सामान्यतः यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त से भी विपरीत थे। इस प्रकार जैफरसन का विश्वास सरकार द्वारा कृषि के विकास को प्रेरित करने, राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा, संवैधानिक शक्तियों की सुरक्षा, तथा सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था में निहित था। विदेशी शक्तियों में गणतान्त्रिक शक्तियों का प्रमुख ध्येय युद्ध से दूर रहना था। उनका विश्वास था कि यूरोप के राष्ट्रों में एकता सम्भव नहीं थी अतएव उनकी प्रतिस्पर्धाओं पर विश्वास किया जा सकने वाली नीतियाँ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकती थी। जैफरसन का विश्वास था कि कांग्रेस का

एक साधारण अधिनियम यूरोपीय राष्ट्रों की अर्धदिशा को मोड़ सकता था। इस आशय का एक पत्र उन्होंने टामसपेन को लिखा था जिसके अनुसार जन ऊर्जा को युद्ध में विनष्ट करना किसी भी प्रकार उचित नहीं था। अपनी नीतियों के लिए भी युद्ध करने से स्वयं को विलग रखना ही उचित मार्ग था। उन सिद्धान्तों का प्रति-पादन शान्ति पूर्वक नीति निर्धारण करके भी किया जा सकता था। उनका विश्वास था कि विदेशी राज्य अमरीकी वाणिज्य के प्रति अत्यधिक उत्सुक थे तथा राज्यों के मध्य वाणिज्य सभ्यता तथा सैद्धान्तिक एकता स्थापित करके उनको लाभावन्ति किया जा सकता था।

गृह नीतियाँ

जैफरसन की गृह-नीतियाँ मुख्यतया राज्यों की निजी सेना पर आधारित सुरक्षा शक्ति, करों के न्यूनीकरण, शासन की मितव्ययता तथा नागरिकीकरण काल को न्यून करने पर आधारित थी। राष्ट्रपति होने के पश्चात् जैफरसन के लिये यह आवश्यक हो गया था कि वह प्रशासन से संबंधित विशेष समस्याओं पर ध्यान दे। तत्कालीन विश्व की स्थिति में नेपोलियन के युद्धों में उन्हें प्रमुख रूप से ध्यान देना पड़ा। वह देशी राज्यों के मध्य उपस्थिति शान्ति, मैत्री तथा बन्धुत्व की भावना से प्रोत्साहित होकर उसके आधार पर सांस्कृतिक विकास के लिए समुद्यत थे। उनके विचार में वारवैरी राज्य के त्रिपोली क्षेत्र के अतिरिक्त सर्वत्र सामान्य शान्ति उपस्थित थी। भूमध्य-सागरीय वाणिज्य की सुरक्षा हेतु अमरीकी सैनिकों द्वारा प्रदर्शित शौर्य भी उनके अनुसार विश्व शान्ति का संदेश था जिसके अनुसार पर्याप्त शक्तिशाली होते हुये भी अमरीका मानव हितों में विश्वास करता था न कि मानव विनाश में

जैफरसन के मत में अमरीका इस स्थिति में था कि वह समस्त आन्तरिक करों को समाप्त कर नवीन उत्थान की दिशा में अग्रसरित हो सके। अतएव आवश्यक शूलक, टिकट कर, नीलामी, लाइसेन्स, भार-वाहन, समाचार पत्रों पर टिकट तथा शक्कर से करों को समाप्त किया जा सकता था क्योंकि करों के अन्य स्रोतों में पर्याप्त कमी एवं आन्तरिक लगान हेतु निरीक्षकों की सेवाये समाप्त कर दी गई। इसी प्रकार के अन्य सुधारों को कार्यान्वित रूप प्रदान करने के भी आश्वासन जैफरसन ने देशवासियों को दिये।

कृषि, उत्पादन, वाणिज्य तथा जहाजरानी (पोतपरिवहन) जैफरसन के विचार में अमरीका की समृद्धि के लिए आवश्यक चार स्तम्भ थे। युद्ध सचिव के मतानुसार अमरीका की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अर्थ की आवश्यकता थी।

यद्यपि जैफरसन समस्त अन्तराष्ट्रीय मामलों को मानवता एवं शान्ति के स्तर पर सुलझाने को तत्पर थे, वह अमरीका की सुरक्षा के लिए सेना को पर्याप्त प्राथमिकता देने के पक्ष में थे ।

देशीकरण के विषय में भी वह अधिनियमों में परिवर्तन हेतु वचनबद्ध थे । नागरिकता प्राप्त करने हेतु 14 वर्ष का स्थायी निवास उनके विचार में एक अनुचित व्यवस्था थी । वह प्रशासन हेतु उन सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने के पक्ष में थे जो पूँजी एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान कर सकें । जैफरसन प्रताणित मानवता को अपनी भूमि पर सुरक्षा प्रदान करने के पक्ष में थे । जैफरसन एवं उनके सहायक अमरीकी ऋणों के न्यूनीकरण के लिये इच्छुक थे वे करों की वृद्धि के पक्ष में नहीं थे ।

इसके अतिरिक्त जैफरसन के सम्मुख एक अन्य समस्या गणतन्त्रवादियों की नियुक्ति की थी । इसके पूर्व वाशिंगटन एवं एडम्स ने कदाचित ही किसी राजनैतिक विरोधी की नियुक्ति की थी । जैफरसन ने यह देखा कि कुछ नियुक्तियाँ की जा चुकी थी परन्तु उनके नियुक्ति पत्र अभी प्रेषित नहीं किये गये थे । उन्होंने अपने सचिव को वह नियुक्ति पत्र भेजने से मना कर दिया । उनमें से एक ने नियुक्ति पत्र के लिए उच्चतम न्यायालय में दावा किया परन्तु संघवादी मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल भी उस नियुक्ति को वैधानिक न सिद्ध कर सके क्योंकि वह संविधान के विरुद्ध था । इस प्रकार नियुक्ति के क्षेत्र में जैफरसन ने अपने पूर्वाधिकारों का ही अनुकरण किया तथा संघवादियों के स्थान पर गणतन्त्रवादियों की नियुक्ति की गई ।

जैफरसन की प्रमुख उपलब्धियों में वारवेरी के जलदस्युओं का उन्मूलन लुईजियाना का क्रय तथा लेविस एवं काँक का अभियान रहा । इसके साथ ही साथ उन्होंने विरोधी दल की परम्परा का शिलान्यास किया ।

वैदेशिक नीति

विभिन्न अवसरों पर जैफरसन ने यह घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमरीका यूरोप के युद्धों में तटस्थ रहेगा । उसका विश्वास था कि उसकी आर्थिक अवपीड़न की नीति विदेशी शक्तियों को अमरीका के अधिकारों की सुरक्षा एवं आदर के लिये प्रभाव डाल सकेंगी । 1803 के यूरोपीय संघर्ष में अमरीका की तटस्थता नवीन कगार पर आ खड़ी हुई । अधिकारों की सुरक्षा एवं तटस्थता की नीति ने तत्कालीन रावर्ट एवं राष्ट्रपति दोनों को उस समय आवेगित कर लिया जब महान शक्तियाँ युद्ध संघर्ष में रत थीं । ब्रिटेन की

जहाजरानी (पोत परिवहन) का सागरपर अधिपत्य एवं ग्रवनस के नैपोलियन के महाद्वीप पर चुनीती रहित अधिपत्य ने विरोधी राष्ट्रों के व्यापार को विनष्ट करने की नीति को जन्म दिया क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस आरक्षित बन्दरगाहों पर व्यापार करने में असमर्थ था तथा फ्रांस ब्रिटेन के सागर में अपने जलयान नहीं भेज सकता था, दोनों ने तटस्थ (पोत परिवहन) जहाजरानी पर व्यापार की नीति अपनाती प्रारम्भ कर दी। इस नीति के कारण अमरीकी पोत परिवहन जहाजरानी की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई।

वाशिंगटन तथा एडम्स ने अपने कार्यकाल में फ्रांस तथा इंग्लैण्ड के साथ किसी भी प्रकार के तनाव को बढ़ने नहीं दिया था। उन्होंने युद्ध की उपेक्षा की जिसके कारण अमरीका अपनी गैरशान्ति अवस्था में उन्नति कर सका। राष्ट्रपति जैफरसन के प्रथम पांच वर्ष भी बिना किसी विदेशी समस्या के शान्ति पूर्वक व्यतीत हो गये।

अमरीकी तटस्थता

इसी मध्य दोनों राष्ट्रों में आवश्यक सामग्री का आयात तटस्थ जहाज (पोत) द्वारा विरोधी क्षेत्र से करना प्रारम्भ कर दिया। कुछ समय तक यह नीति दोनों की मुख्य युद्ध नीति रहीं परन्तु समस्या बलात मतों के प्रश्न पर आरम्भ हुई।

1790 तक आंग्ल-फ्रान्सीसी संघर्षों तक ब्रिटेन में 1756 के अधिनियमों को मान्यता प्राप्त थी जिसके अनुसार शान्ति के अवसर पर तटस्थ व्यापार की सुविधा उन बन्दरगाहों पर नहीं थीं जो तटस्थ राष्ट्रों के लिए बन्द थे। परन्तु 1800 में ब्रिटेन ने यह अधिनियम बना दिया कि यदि कोई जहाज (पोत) फ्रान्सीसी वेस्ट इन्डिया से आते समय बन्दरगाह पर शुल्क प्रदान कर दे तो वस्तु अमरीकी हो जाएगी तथा उसे पुनः प्रेषित करने की सुविधा प्रदान हो जायगी। 1804 तक यह व्यापारिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर गई परन्तु अगले वर्ष इस्सेक्स घटना के पश्चात इस प्रकार की वस्तुओं को फ्रान्सीसी करार दे दिया गया तथा उनपर व्यापार निषेध लागू हो गया। मई 10, 1806 को ब्रिटेन ने एक अधिनियम के अन्तर्गत महाद्वीप की नाकाबन्दी प्रारम्भ कर दी। नवम्बर 21 को नेपोलियन ने बर्लिन डिक्री (आदेश) के द्वारा ब्रिटिश द्वीप का अवरोध कर दिया। यद्यपि इस अवरोध हेतु फ्रान्स के पास पर्याप्त जहाजरानी नहीं उपलब्ध थीं, परन्तु फ्रांसीसी हमलावर तथा आक्रामक गुरिल्ला विधि के द्वारा वे अमरीकी तटस्थता पोतपरिवहन को पर्याप्त हानि पहुँचा सकते थे। परन्तु ब्रिटेन तथा फ्रान्स के आपसी मतभेद एवं संघर्ष ने एक नवीन परिस्थिति को जन्म दिया। फ्रान्स के सम्राट

नेपोलियन ने 1805 के युद्धोपरान्त यूरोपीय महाद्वीप पर राजनैतिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया था जबकि ट्राफालगर के युद्ध के पश्चात ब्रिटेन का सागर पर पूर्ण अधिकार हों गया था ।

जैफरसन ने अपने संधीय अधिकार का दूसरा आश्चर्यजनक उपयोग ब्रिटेन और नेपोलियन के बीच संघर्ष में अमरीकी तटस्थता बनाये रखने में किया । क्योंकि अमरीकी राज्य को युद्ध की अपेक्षा शान्ति की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता थी । ब्रिटेन द्वारा युद्ध में हस्तक्षेप का ध्येय यूरोप में शक्ति संतुलन बनाये रखना था । परन्तु अपने-अपने क्षेत्र में दोनों के एकाधिकारी होने के कारण सीधा प्रहार सम्भव नहीं था । यही कारण था कि उन्होंने इस संघर्ष को वाणिज्य स्वरूप प्रदान किया । परन्तु दोनों शक्तियों के इस संघर्ष की व्यापारिक नीति का अमरीका के व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ा । ब्रिटेन की नीतियों से अमरीकी जलयानों के मूल्यवान व्यापार पर द्योतक प्रहार हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने उन अमरीकी जलयानों के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया जो फ्रान्सीसी वेस्ट इन्डीज के उत्पादन को वहन करते थे उन्होंने स्पेन से एल्ब तक के समस्त तटीय बन्दरगाहों पर उनका प्रवेश वर्जित कर दिया । जबकि दूसरी तरफ फ्रान्स ने ऐसे अमरीकी जलपोतों को बन्दी बनाने का आदेश पारित कर दिया था जो ब्रिटिश जल-सेना के द्वारा तलाशी स्वीकार कर लेते थे अथवा ब्रिटिश बन्दरगाहों पर आया जाया करते हों । ब्रिटेन और फ्रान्स की इन नीतियों के कारण अमरीकी जलयानों द्वारा यूरोप में व्यापारिक गतिविधियों को लागू रखना सम्भव नहीं था । ब्रिटेन की नौ सैनिक प्रवेश नीतियों के कारण अमरीकी जनता में अत्याधिक असन्तोष व्याप्त हो रहा था । इसके साथ ही साथ ब्रिटिश नौसैनिक असुविधाओं तथा अपर्याप्त वेतनमान के कारण ब्रिटिश नौसेना छोड़कर अमरीकी नौसेना तथा जलयानों पर प्रवेश प्राप्त कर रहे थे । उनकी छानबीन के कारण भी अमरीकी जनता में तीव्र विरोध उत्पन्न हो रहा था । अमरीकी अधिकारियों के लिये यह अपमान की बात थी कि ब्रिटिश अधिकारी उनके नौसैनिक ब्रेडों तथा व्यापारिक जलयानों की छानबीन करें । जबकि ब्रिटेन उन पलायित नौसैनिकों का अमरीकी नागरिकरण के विरुद्ध था जबकि अमरीकी नीतियाँ इसके विपरीत थीं ।

चैसापीक—लंपर्ड घटना

जून 1807 में स्थिति उस समय अत्यन्त विस्फोटक हो गई जबकि नव-

निर्मित अमरीकी जलयान 'चैसापीक' की तलाशी ब्रिटेन के जलयान 'लैपर्ड' के अधिकारियों ने लेने की कोशिश की। अमरीकी कामांडर के विरोध करने पर उत्पन्न संघर्ष के फलस्वरूप तीन अमरीकियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा अट्ठारह दुर्घटनाग्रस्त हो गये। इस दुर्घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये हैनरी एडम्स ने कहा कि 'इतिहास में प्रथम बार अमरीकी जनता ने जून 1807 की घटना से राष्ट्रीयता की भावना को पहचाना।

निषेध अधिनियम (एम्बार्गो एक्ट)

राष्ट्रपति जैफरसन के इस सिद्धांत को कि 'अमरीका को यूरोपीय संघर्षों में तटस्थ रहना चाहिए' 1803 के यूरोपीय युद्ध में चुनौती का सामना करना पड़ा किन्तु राष्ट्रपति जैफरसन अपनी नीति पर दृढ़ रहे।

इसी सिद्धांत के अन्तर्गत फ्रांस तथा इंग्लैण्ड से संघर्ष रहित सम्बन्धों के लिए अन्त में दिसम्बर 1807 में जैफरसन ने कांग्रेस से निषेध अधिनियम (एम्बार्गो-एक्ट) पारित करवाया, जिसके अन्तर्गत वैदेशिक व्यापार को पूर्णतया बन्द कर दिया गया जो कि एक दूसरा प्रयोग था इसके परिणामस्वरूप अमरीका का पोत परिवहन व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया। 1807 में निर्यात 108.343 मिलियन (दश लदा) से घटाकर 180 में 12.431 मिलियन रह गया तथा आयात 13.5 मिलियन से घटाकर 56.990 मिलियन रह गया। मैकमास्टर के अनुसार निषेध अधिनियम के कारण लगभग 55,000 नाविक तथा 100,000 मशीनें और श्रमिक बेरोजगार हो गये एवं साथ ही पोतपरिवहन आय में 12500,000 की कमी और (सीमाशुल्क कर 16 मिलियन से घटकर हजारों में पहुँच गया था। इस समय वह की स्थित न्यूयार्क में एक ब्रिटिश यात्री ने वर्णन करते हुये लिखा "पोतों (जहाजों) के डेक वीरान हो गये थे, बन्दरगाह (पत्तन) भी पूर्णतया निर्जन प्रतीत हो रहे थे।

इस प्रकार विपम परिस्थियों के कारण न्यू इंग्लैण्ड तथा न्यूयार्क में तीव्र असन्तोष व्याप्त हो गया था दक्षिण और पश्चिम के कृषकों को भी असुविधा होने लगी थी किन्तु यह आशा कि इस निषेध से ब्रिटेन माल न मिलने के कारण अपनी परिवर्तन के लिये बाध्य हो जायेगा, सफल नहीं हुई।

अन्त में अपने समर्थकों के कारण राष्ट्रपति जैफरसन ने राष्ट्रपति पद त्यागने से पूर्व निषेध अधिनियम के स्थान पर असम्पर्क अधिनियम (नान इन्टर-कोर्स एक्ट) पारित कर दिया। इसमें ब्रिटेन फ्रांस एवं अधीनस्थ प्रदेशों के

साथ वाणिज्य का विरोध किया गया, किन्तु साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि यदि उनमें से कोई राष्ट्र तटस्थ देश के वाणिज्य पर आक्रमण करना बन्द कर देगा तो उसके साथ वाणिज्य पर प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा। 1810 में नेपोलियन की सरकारी तौर पर इस घोषणा से कि उसने अपने आक्रमणों का मार्ग छोड़ दिया है (जो कि वास्तव में गलत थी) पर संयुक्त राज्य ने विश्वास करके अपने व्यापार निषेध को ब्रिटेन तक ही सीमित कर दिया।

1808 का चुनाव

राष्ट्रपति जैफरसन का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका था। इस समय निषेध अधिनियम का तीव्र विरोध हो रहा था, साथ ही गणतांत्रिक दल में भी मतभेद उत्पन्न हो चुका था। इसके पश्चात भी जैफरसन ने अपनी कुशलता से अपने प्रत्याशी जेम्स मेडिसन को राष्ट्रपति निर्वाचित करा दिया। यद्यपि संघवादियों ने न्यूइंग्लैण्ड में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था एवं कांग्रेस के दोनों सदनों में उनके प्रतिनिधियों की संख्या भी पर्याप्त वृद्धि को प्राप्त कर चुकी थी।

यद्यपि राष्ट्रपति जैफरसन की निषेध नीति असफल हो गई थी तथापि जैफरसन को महान राजनीतिज्ञ, प्रजातान्त्रिक तथा मानव स्वतन्त्रता का समर्थक होने का गौरव प्राप्त है। जैफरसन को गणतांत्रिक दल तथा 1800 के चुनाव में उसकी महत्वपूर्ण विजय जैफरसन के बुद्धि, कौशल संयमित राजनीति एवं प्रमाणिक विवेक का ज्वलंत उदाहरण है। यद्यपि दल का विघटन हुआ लेकिन इसके पीछे भी कई ऐसे कारण थे जिनपर जैफरसन का कोई नियंत्रण नहीं था। तथापि विरोधियों के प्रति उसके असीम धैर्य तथा शान्ति की नीति ने उनको महान राजनीतिज्ञ साबित कर दिया। लिंकन के अतिरिक्त राष्ट्रपति जैफरसन की भांति राजनीतिक तीक्ष्ण बुद्धि तथा उच्च राजनीतिज्ञ होने का गौरव अन्य किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है।

जेम्स मेडिसन

1808 के चुनावों में संवैधानिक सम्मेलन का प्रमुख सदस्य, अधिकारों के विधेयक का प्रमुख प्रवर्तक, वर्जीनिया मुझाव का निर्माणकर्ता एवं प्रमुख जैफरसनवादी जेम्स मेडिसन राष्ट्रपति बनकर आया। अपने पद पर आते ही उन्हें



जेम्स मेडिसन (1751—1836)
अमरीका के चौथे राष्ट्रपति

उस समस्या से सामना करना पड़ा जिसे जैफरसन भी सुलझा न सके थे। कि किस प्रकार अमरीका एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में नेपोलियन के युद्धों से स्वयं को सुरक्षित रख सकेगा अमरीका का व्यापार ब्रिटेन तथा फ्रान्स के मध्य असुरक्षित हो चुका था। शक्ति प्रदर्शन का मार्ग जैफरसन द्वारा युद्ध मितव्ययता की नीतियों के कारण असम्भव था क्योंकि अमरीका अपने छोटे मास्क नौकाओं द्वारा अपनी तटीय सुरक्षा करने में भी समर्थ नहीं था। आर्थिक बचाव की नीति भी अपनायी गई, परन्तु उसका कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ।

मेडिसन ने ब्रिटिश मन्त्री अँस्कन के साथ समझौते के लिए वार्तालाप प्रारम्भ किया। इस समझौते में यह निश्चित किया गया कि ब्रिटेन अपने आदेशों से अमरीका का नाम हटा देगा तथा अमरीका ब्रिटिश व्यापार पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर देगा एवं फ्रान्सीसी व्यापार पर प्रतिबन्ध लागू रखेगा परन्तु ब्रिटिश विदेश सचिव कैनिम ने उपरोक्त समझौते को मान्यता प्रदान करना अस्वीकार कर दिया।

तत्पश्चात् अमरीकी नीतियाँ फ्राँस की तरफ अभिसारित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मेकन-अधिनियम संख्या-2, काँग्रेस द्वारा स्वीकृत की गई। इस अधिनियम के आधार पर समस्त आयात पर से प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया एवं राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि ब्रिटेन अथवा फ्रान्स किसी के भी साथ समझौता कर सकता था। मेकन अधिनियम के अन्तर्गत फ्रान्स ने व्यापारिक प्रस्ताव रखा जिसे मेडिसन ने स्वीकार कर लिया परन्तु समय के साथ यह तथ्य सम्मुख आया कि नेपोलियन विभिन्न अवसरों पर उस समझौते के अनुच्छेदों का अतिक्रमण करने लगा था। इस प्रकार इस अधिनियम से एक तरफ अमरीका ने ब्रिटेन को शंकित कर दिया तथा उसे फ्रान्स से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस मध्य काल में, खोज एवं अधिकार की नीतियों के कारण अमरीका का एक वर्ग ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध हो गया था। अक्टूबर 27, 1810 को मेडिसन ने फ्लोरिडा के पश्चिम में वृद्धिरत अमरीकी निवासियों को अमरीका में सम्मिलित कर, कुछ सीमा तक उपर्युक्त वर्ग की भावनाओं को आंशिक सन्तोष प्रदान किया। यह वह कार्य था जिसे जैफरसन चाहते हुये भी न कर सके थे।

इसी मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में नवीन घटनाओं ने जन्म लिया। तेंसकगतावा (पैगम्बर) विद्रोह के पीछे ब्रिटिश नीतियों का हाथ, घटनास्थल पर ब्रिटिश हथियारों के प्राप्त होने से सिद्ध हो गया। इस घटना के 13 माह पश्चात् जब काँग्रेस का सम्मेलन हुआ उसमें ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की माँग चरम सीमा

पर सम्मुख आयी। ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की माँग के पीछे केवल उपरोक्त घटना का ही हाथ था अन्यथा फ्रान्स भी अमरीका के लिए कम हानिकारक नहीं सिद्ध हुआ था। न्यु-इंग्लैण्ड, न्युयार्क तथा न्युजेरसी के अतिरिक्त सभी राज्यों ने युद्ध का समर्थन किया। संघवादियों तथा एक अल्पमत वर्ग युद्ध की घोषणा के केवल दो दिन पूर्व ही ब्रिटेन ने घोषणा की कि वह आदेशों को वापस ले रहा है परन्तु जब तक पर्याप्त विलम्ब हो चुका था।

यद्यपि संघवादियों ने युद्ध की घोषणा को एक पागल, अधिनायक के समर्थन के रूप में देखा, मेडिसन तथा उसके समर्थकों ने ब्रिटेन के साथ युद्ध को अपना आन्तरिक मसला ही बताया। ब्रिटेन तथा उसके सन्धिबद्ध राष्ट्रों के सम्मुख सर्वप्रथम नेपोलियन की नीतियाँ थीं, यद्यपि तत्कालीन अमरीकी सैनिक सामर्थ्य अपेक्षाकृत अधिक समर्थनवादी नहीं थी। उन्होंने युद्ध की घोषणा की। जैफरसन की सैनिक-नीतियों के कारण अमरीकी जहाजरानी में संविधान, संयुक्त राज्य तथा राष्ट्रपति, इन तीन नवीन 44 मारक युद्धपोतों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभावशाली नवसेना नहीं थी। सैनिकों की संख्या भी 7000 से अधिक नहीं थी तथा उनमें अनुशासन तथा प्रशिक्षण का भी पर्याप्त अभाव था। सैनिकों का अधिरक्षण भी तुलनात्मक रूप से पुराने सैनिकों के हाथ में था जो क्रान्तिकारी युग की उपज थे।

1812 में वहाँ पर दो कनाडा थे। निम्न सेन्ट लारेन्स के पास कनाडा में फ्रान्सीसी भाषी नागरिकों की बहुलता थी तथा दूसरे में ब्रिटिश एवं अमरीकी नागरिकों एवं अन्यवासियों की। युद्ध विज्ञान के अनुसार यदि मांट्रियल के समीप सेन्ट लारेन्स से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता तो ऊपरी कनाडा की सुरक्षा असम्भव थी, परन्तु अमरीकी युद्ध नीतियाँ यह अवसर न प्राप्त कर सकीं क्योंकि उनमें युद्ध का पर्याप्त अनुभव नहीं था।

सर्वप्रथम विलियम हल ने प्रस्थान किया तथा डिट्रायट के पश्चिम तक आक्रमण किया। इस युद्ध में देशी लोगों ने टिकमसे की अध्यक्षता में अमरीकियों का पर्याप्त विरोध किया। कनाडा के जनरल आइजक ब्राक ने सर्वप्रथम प्रत्येक स्थान पर अमरीकी सेना को पराजित किया परन्तु नियागरा नदी के पास जान ई० वूल की सैनिक टुकड़ी के साथ संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अमरीका की नवीन नौ सैनिक तीनों युद्धपोतों ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की। अन्त में हैरिसन ने डिट्रायट, ऊपरी कनाडा, ऑन्तारियो झील तक का समस्त क्षेत्र हस्तगत कर लिया। टिकमसे की मृत्यु के कारण भी देशी लोगों के विरोध की नैतिकता कम हो चुकी थी।

अप्रैल 1814 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात् ब्रिटेन अमरीकी युद्ध

की दिशा में हस्तक्षेप करने हेतु स्वतन्त्र हो गया। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने अटलान्टिक तट की नाकेबन्दी कर दी तथा मेन के बहुतायत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तत्पश्चात् उन्होंने वाशिंगटन पर आक्रमण किया। इस युद्ध में ब्रिटेन की सेना ह्वाइट तक पहुँच गई तथा मेडिसन किसी प्रकार सुरक्षित निकल सके। उन्होंने कांग्रेस को लाइब्रेरी जला दी वाल्टीमोर पर आक्रमण किया। उत्तर में ब्रिटिश सेना को पराजित कर उन्हें वापिस लौटने के लिये विवश कर दिया। इसके उपरान्त ब्रिटिश सेना ने न्यू-आर्लियेन्ज (आर्लीन्ज) पर आक्रमण किया। वहाँ की सुरक्षा का भार अमरीकी जनरल एन्ड्र्यू जैक्सन पर था। तत्कालिक युद्ध में ब्रिटिश सेना को अपरिमित हानि पहुँचायी, जिसमें आक्रामक जनरल एडवर्ड, पैकनहम की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सेना ने युद्ध भूमि छोड़ दी तथा वापस लौट गये।

इस समस्त युद्ध काल में संघवादियों ने युद्ध के प्रयासों का विरोध किया न्यू-इंग्लैण्ड ने अपेक्षाकृत न्यून सैनिकों को प्रेषित किया था। दिसम्बर 15 को हार्टफोर्ड में मैसाचुसेट्स, रोडइ (रोड) एवं कैंटेकर द्वीप के प्रतिनिधि एकत्रित हुये। इस सम्मेलन में केन्द्र की शक्तियों को पर्याप्त रूप से न्यून कर दिया गया। सुरक्षा का प्राविधान पूर्णरूपेण राज्यों के अन्तर्गत कर दिया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया। नवीन राज्य के अधिकरण के लिए कांग्रेस के 2/3 मतों को आवश्यक माना गया। इसी प्रकार वाणिज्य तथा युद्ध की घोषणा के लिए भी केन्द्र को अपेक्षाकृत कम शक्तियाँ प्रदान की गईं। इन प्रस्तावों के साथ जब सम्मेलन के प्रतिनिधि वाशिंगटन के लिए प्रस्थान करने वाले थे तभी न्यूआर्लियेन्ज के विजय का समाचार प्राप्त हुआ। उसके पश्चात् अब वाशिंगटन जाने का कोई औचित्य शेष नहीं था। इस युद्ध में गणतान्त्रिक नीतियों की विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि अमरीका में संघवादी दल का अन्त हो चुका है।

दिसम्बर-14, 1814 को शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुये इस समझौते के पश्चात् ब्रिटेन ने मेन, ओहायो तथा मिसूडी के कुछ भागों पर अपने अधिकारों की तत्कालीन माँगों को समाप्त कर दिया। युद्ध पूर्व की स्थिति को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। फरवरी 17, 1815 को इस समझौते पर सीनेट के अनुमोदन के साथ ही सागर पर स्वतन्त्रता का युद्ध तथा द्वितीय स्वतन्त्रता संग्राम का अन्त हो गया।

उपसंहार

इतिहासकारों ने अमरीकी इतिहास के संघीय युग में जैफरसन और

हैमिल्टन को परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रतीक माना है। इन इतिहासकारों ने जैफरसन और हैमिल्टन को लोकतंत्र एवं अभिजाततंत्र, औद्योगिकवाद एवं कृषकवाद तथा राष्ट्रीय शासन एवं शासकीय अधिकारों की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जैफरसन को फ्रांस का समर्थक तथा हैमिल्टन को ब्रिटिश समर्थक मानकर इन दोनों के राजनैतिक विचारों का विश्लेषण किया परन्तु 1800 में संघीय पराजय के पश्चात् अमरीका ने जैफरसन के गणतंत्रीय युग में प्रवेश किया।

जैफरसन के गणतंत्र में लोकतंत्र एवं लोकवाद का समन्वय था। जैफरसन तथा मेडिसन ने अमरीकी समाज में भू-सम्बन्धी कार्यों एवं भू-कृषकों को अमरीकी प्रशासकीय नीतियों में स्थान दिया। इसलिये इतिहासज्ञों ने इस अमरीकी युग को 'कृषि आनन्दधाम' कहा है। निःसन्देह, जैफरसन महान व्यापार एवं महान शासन को सन्देहात्मक दृष्टि से देखते थे। गणतंत्रीय दल के सदस्य समतावादी समाज के समर्थक थे। जब संघीय शासन ने अपनी लोकतांत्रिक विरोधी नीतियों को अपनाकर "विदेशी तथा राजद्रोही अधिनियम (1798)" पारित किया तो इसके विरुद्ध कृषि वर्ग ने आक्रोश प्रकट कर संघीय शासन को निष्कापित किया। इस प्रकार गणतांत्रिक विजय को "1800 की क्रांति" का नामकरण किया जाता है।

इस प्रकार 20 वीं शताब्दी के पूर्व काल के अमरीकी इतिहास को लोकतांत्रिक एवं उच्चवर्गीय निरंकुशतावाद का निरन्तर संघर्ष की व्याख्या की जाती है। आगामी वर्षों में हैमिल्टन और जैफरसन के द्विभाजन को अमरीकी इतिहास में प्रयोगात्मक रूप दिया। जैफरसन का गणतंत्रवाद सम्भवतः इसी आधार पर जैक्सन के लोकतंत्र का पूर्वज कहा जाता है।

जैफरसन के गणतंत्रवाद की व्याख्या इतिहासकारों ने आलोचना तथा समर्थन दोनों प्रकार से की है। जैफरसन के विपक्षीय इतिहासकारों में रिचर्ड हिल्डर्थ का नाम प्रमुख है। हिल्डर्थ ब्रिटिश दार्शनिक जर्मिनिथम के उपयोगितावाद से प्रभावित थे। इस कारण अपने विचारों में उन्होंने अनुभव को सिद्धांत से वरिष्ठता प्रदान की। उनके विचारों में हैमिल्टन जैफरसन से अधिक यथार्थता एवं संघीय नीतियों के परिपालक थे। हर्मन होल्सट के अतिरिक्त हिल्डर्थ ने भी अपनी बहुखंडीय पुस्तक (कान्स्टीट्यूशनल एण्ड पालेटीकल हिस्ट्री आफ यूनाइटेड स्टेट्स) में उन्होंने भी जैफरसन का विरोध किया क्योंकि इनके विचारों का मूल विषय संघीय शक्ति को केन्द्रिय करना था। जैफरसन के प्रति विरोधी विचारधारा में हेनरी एडम्स ही ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अमरीकी समाज के विकास की ओर ध्यान केन्द्रित किया।



एण्ड्रू जैक्सन (1767-1845)
अमरीका के सातवें राष्ट्रपति

यद्यपि एडम्स के इतिहास लेखन ने जैफरसन को विरोचित नायक की संज्ञा नहीं दी किन्तु उन्होंने जैफरसन को अमरीकी प्रशासन के विकास एवं राष्ट्रीय चेतना एवं बोध का परिचायक माना। इसके साथ ही इसको भी स्पष्ट किया कि जैफरसन की प्रशासनिक घटनाओं में उनकी दार्शनिक एवं तात्विक विचारों का सम्मिश्रण नहीं था। एडम्स ने उसकी व्याख्या करते हुये अपना मत प्रकट किया कि जैफरसन को अनेक समयों पर अपने स्थितप्रज्ञ विचारों को त्यागकर शासन की वास्तविकता से समझौता करना पड़ा। एडम्स ने अपने अध्ययन में जैफरसन के प्रशासनिक एवं दर्शनिक दोनों पक्षों पर प्रकाश डाला। इसलिये वर्तमान युग के इतिहासकार भी इसका निर्णय नहीं कर सके कि एडम्स का इतिहास जैफरसन के पक्ष में था या विपक्ष में? इस पर भी एडम्स संघीय युग के इतिहासकारों में परिवर्तिय व्यक्तित्व के परिचायक थे। एडम्स ने अपने इतिहास लेखन में 19 वीं शताब्दी की विचारधारा से हटकर इतिहास लेखन में वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन दिया।

अमरीकी इतिहासलेखन में 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में आकस्मिक परिवर्तन आया जो कि प्रचलित सामाजिक, एवं राजनैतिक सुधारों से प्रभावित था। ये इतिहासकार जैफरसन की उदारवादी विचारधारा के प्रति सहानुभूतिक थे और प्रथम बार इतिहासवेत्ताओं ने अमरीका के पूर्व इतिहास को संघीय-विग गणतन्त्रीय विचारों से परे जैफरसन-जैक्सन लोकतंत्रिक विचार धारा के द्वारा मूल्यांकन किया।

प्रगतिशील मत

बीसवीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों में प्रगतिशील मत के लेखकों चार्ल्स वीयर्ड, क्लॉड बीबर और वरनान पेरिग्टन ने जैफरसन को इतिहासिक वरिष्ठता प्रदत्त की। चार्ल्स वीयर्ड ने 1975 में अपनी पुस्तक में संघीय युग की आर्थिक दृष्टिकोण से व्याख्या की। अपनी चिरपरिचित विचारधारा कि संविधान निर्माण 'पूँजीवादी गुट' का कार्य था, वीयर्ड ने जैफरसन के भूसम्पदावाद को वरीयता प्रदान की। वीयर्ड ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पूँजीवाद भूसम्पदावाद के संघर्ष ने संस्थावाद को जन्म देकर राजनैतिक दलों की नींव रखी। इसी के अन्तर्गत वीयर्ड ने कहा कि लोकतंत्र ने किसी राजनैतिक सिद्धान्त पर आघात नहीं किया वरन् इसने केवल राजनैतिक शक्ति को एक सामाजिक, आर्थिक तथा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तित कर दिया। वीयर्ड ने जैफरसन के लोकतन्त्रिय भूसम्पदावाद को अभिजात वर्ग द्वारा मार्ग दर्शित

वताया। इसके अतिरिक्त वीयर्ड ने जैफरसन को अपनी नीतियों के परिपालन में-असफल भी बताया क्योंकि इस इतिहासवेत्ता के अनुसार जैफरसन ने संग्रहीत वर्ग को अनेक सुविधायें एवं अनुदान प्रदत्त किये। वीयर्ड की पुस्तक वास्तविक रूप में उदारवादी सहयोगियों के प्रति विवादास्पद लेखन कार्य था।

वीयर्ड के लगभग एक दशक पश्चात् क्लॉड वौअर ने अपनी पुस्तक "जैफरसन एण्ड हैमिल्टन" दि स्ट्रगल फार डेमोक्रेसी इन अमरीका" में जैफरसन के लोकतंत्र को सकारात्मक अभिगम का रूप दिया। और वौअर के अनुसार जैफरसन एवं हैमिल्टन का संघर्ष अभिजाततंत्र का प्रतीक था। इसी संघर्ष के द्वारा राष्ट्र के भाग्य का भविष्य निर्धारण हो सकता था। वौअर ने जैफरसन को केवल सिद्धान्ती न मानकर सक्षम राजनीतिज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया। वौअर ने अमरीका की उन्नति का श्रेय जैफरसन को दिया कि उन्होंने हैमिल्टन की संरक्षता में पनप रही अभिजातवर्गीय शक्तियों को निरस्त कर दिया।

वर्नान पैरिंग्टन ने अपने अध्ययन में जैफरसन की आलोचना करते हुये भी उनको उदारवादी सिद्धान्तों का नेता माना। वर्नान के अनुसार जैफरसन भू-सम्पदा युग समाज की उपज थे और इसलिये स्वदेशी अमरीकन उदारवाद के द्योतक थे। पैरिंग्टन ने जैफरसन को साधारण, एवं स्वाभाविक व आर्थिक नीति का परिपालक बताया क्योंकि उन्होंने अमरीकी समाज एवं राजनीति के लिये एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् एक सचेतन मतैक्यवर्ग के इतिहासकारों ने जैफरसन-हैमिल्टन द्विविभाजन का संतुलित रूप पर प्रकाश डाला। इन लेखकों में प्रमुख मार्कूज कनलिफ, जान मिलर एवं लुईहार्ट्स थे। इन लेखकों ने उपरोक्त दोनों राजमनीपियों को सामाजिक, एवं राष्ट्रीय तनाव के लिये दोषी ठहराया और यह मत प्रकट किया कि इन दोनों की नीतियों का मध्यमार्ग अमरीकी समाज के प्रति उत्तम होता। एक अन्य विद्वान 'मेरिल पेटर्सन' ने बताया—“कि जैफरसन प्रत्यक्ष रूप में उग्रवादी से अधिक रूढ़िवादी थे, सैद्धान्तिक से अधिक प्रयोगिक में तथा बिखजनीन से अधिक राष्ट्रवादी थे।” 'मार्टन वार्डन' ने जैफरसन को प्रथम कोटि के राष्ट्रवादी की मान्यता दी परन्तु इनके मतानुसार जैफरसन की संरक्षता में अमरीका ने उन लक्ष्यों की उपलब्धियाँ की जिनके लिये इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल तथा हालैण्ड एक शताब्दी से इच्छुक थे।

उपरोक्त इतिहासकारों के अध्ययन एवं विचारों के विश्लेषण ने जैफरसन एवं हैमिल्टन की राजनीतिक एवं आर्थिक पक्षों का गूढ़ विश्लेषण किया। उस समय के इन दोनों राजनीतिज्ञों के मार्ग निर्देशन में भिन्नता का भाव होने के उपरान्त भी राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के प्रति समझपता थी।

अध्याय 4

नवीन लोकतंत्र

राष्ट्रपति जैक्सन

अमरीकी राष्ट्र एक गहन क्रान्ति के मध्य था जब एण्ड्रू जैक्सन ने मार्च 4, 1829 को सातवें राष्ट्रपति के रूप में ह्वाइट हाउस में पदापर्ण किया। यद्यपि उस समय किसी भी प्रकार की हिंसक क्रान्ति का प्रकट स्वरूप नहीं था परन्तु राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन हेतु क्रान्ति की अन्तर्धारा प्रवाहित थी। इस युग के इतिहासकारों ने इस काल को 'जैक्सन युग' की संज्ञा दी है क्योंकि इस काल ने 1812 के युद्धोपरान्त तथा गृह युद्ध के आरम्भ तक सेतु बन्धन का कार्य किया। फलतः जैक्सन का युग परिवर्तन का युग था, नव काल था तथा सुधार युग था।

1828 का चुनाव एक अप्रत्याशित चुनाव था जिसमें एण्ड्रू जैक्सन के समर्थकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। वार्शिंग्टन पहुँचने पर निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जैक्सन ने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष से भेंट करने की परम्परा का निर्वाह करना भी आवश्यक नहीं समझा तथा एडम्स ने अपने उत्तराधिकारी के साथ संसद भवन जाने की परम्परा का वहिष्कार किया। जैक्सन के पदासीन होने के समय अमरीका अपने 40 वें वर्ष में था और सबल सुदृढ़ता ग्रहण करने का इच्छुक था।

जैक्सन के विचार

जैक्सन अमरीका के विशिष्ट राष्ट्रपतियों में थे जिनकी लोकतांत्रिक विचारधारा में ग्रथार्थता एवं व्यवहारिकता का सामंजस्य था। उन्हें जनसाधारण पर विश्वास था तथा उनसे सहानुभूति थी क्योंकि वह स्वयं इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका प्रारम्भिक जीवन आम जनता की भाँति ही अत्यन्त

कठिनाईयों एवं निर्धनता में व्यतीत हुआ था ।

अमरीकी सामाजिक स्वरूप में जैक्सन की सत्ता एक परिवर्तनशील शक्ति के रूप में उभरी । उनका राजनैतिक दर्शन एक नवीन युग का द्योतक था । वह विशेषाधिकारों, एकाधिकारों, तथा पूंजीवादी मान्यताओं के कट्टर विरोधी थे तथा राजनैतिक समानता के सच्चे समर्थक थे । किन्तु इसके विपरीत उनका डेमोक्रेटिक (प्रजातांत्रिक) दल स्वयं विभिन्न लोलुपताओं के कारण दो भिन्न-भिन्न मान्यताओं का पोषक था । इन दलों में अधिकांश कृषक, अन्वेषक, किसान तथा अल्प भूमिधर एवं व्यापारी थे । जहाँ एलेगनी से परे राष्ट्रवादी भावनायें कार्यरत थी वहीं पर 13 प्रारम्भिक राज्यों की अपेक्षा नये राज्यों में स्थानीय भावनाओं की अपेक्षा राष्ट्रीय भावनाएँ अधिक प्रभावोत्पादक थीं । इसके अतिरिक्त पश्चिमी राज्यों में राजनैतिक समानता एक तथ्य के रूप में स्वीकार की जाती थी और उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी प्रतीत होता था । उन्हें पूर्वी नियंत्रण वाली बैंकिंग संस्थाओं में रुचि नहीं थी । यदि एक वर्ग एकाधिकारों का घोर विरोधी था तो दूसरा उसका समर्थक । जहाँ एक ओर बैंकों के घोषणा पत्रों को भी मान्यता नहीं मिल रही थी वहीं पूर्वी नगरों में 1812 के युद्ध, संरक्षित तटकरों एवं आयात प्रतिबन्ध से प्रोत्साहित होकर नवीन मिल एवं कारखाने प्रारम्भ हो रहे थे । फलस्वरूप अमरीका के इस क्षेत्र में श्रमिक वर्ग का घनत्व बढ़ता जा रहा था । न्यूयार्क अब केवल संघीय नगर नहीं था अपितु एक अतिजनसंख्या वाला लोकतांत्रिक शहर बन चुका था । 1828 से गृह युद्ध तक जैफरसन के प्रजातंत्र ने अमरीका को प्रभावित किया । यह प्रजातंत्र एक प्रकार का राष्ट्रीय आन्दोलन था जो भौगोलिक सीमाओं से पूर्णतया अनभिज्ञ था । परन्तु इसी के साथ-साथ यह हेनरी क्ले के अमरीकी तंत्र का विरोध कर राष्ट्र विरोधी भी हो गई थी । अमरीकी तंत्र का अर्थ था सड़कें, नहरें तथा कुछ रेलवे लाइनों का राज्यों की सहायता से निर्माण । जैक्सन का प्रजातंत्र समानता में विश्वास करता था परन्तु यह समानता केवल श्वेतों की समानता थी । यह अभिजातवर्गीय विरोधियों की अपेक्षा लाल भारतीयों और नीग्रो लोगों की ओर असहिष्णु थी । इस लोकतंत्र में उस यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं था जो पूंजीपति वर्ग को उसके स्तर से नीचे लाकर सामाजिक समानता की पक्षधर थी । अपितु यह सबको समानता का अवसर प्रदान करने के पक्ष में थी । कतिपय यह निःशुल्क शिक्षा की भी पक्षपाती थी । जैक्सन के प्रजातंत्र ने सामाजिक तथा राजनैतिक समानता को प्रोत्साहन दिया । यदि इसके उज्ज्वल पक्ष में साधारण जन को शासन में सक्रिय योगदान

प्रदान करता था तो विपरीत पहलू संस्कृति के नकार में निहित थी। प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार टॉकविल (टोकवील) के अनुसार "अमरीका से उस जाति का विलीय होना प्रारम्भ हो गया जिसने महान लोगों को जन्म दिया था। उनके साथ ही वहाँ सुसंस्कृति भी नष्टप्राय हो चली जहाँ शिक्षा तथा ज्ञान में वृद्धि होती रही थी वहीं विशिष्ट चरित्रों का पर्याप्त अभाव हो गया था। समाज धनधान्य से सम्पन्न होते हुये भी विशिष्ट चरित्रों के अभाव से रिक्त था।

नवीन लोकतंत्र

जैक्सन के राष्ट्रपति काल में अमरीका में अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुये जिनका ध्येय सामान्य जन को सरकार में सहभागिता प्रदान करना था। इस काल में रूढ़िवादी परम्पराओं को समाप्त कर नवीन राजनैतिक विधियाँ अपनायी गयी जिनके आधार पर विशेषाधिकारित वर्ग की शक्तियों को पर्याप्त स्तर तक प्रतिबन्धित कर दिया गया।

जैक्सन का प्रजातंत्र वह उग्रवादी आन्दोलन था जिसने सामंतवाद तथा रूढ़िवादी परम्पराओं को समाप्त कर अमरीका में एक नवीन लोकप्रिय शासन का शिलान्यास किया। यद्यपि इसके नेताओं ने लोकतंत्रीय राजनैतिक सिद्धान्तों में अपेक्षाकृत न्यून परिवर्तन किया परन्तु उन्होंने इसके विपरीत तत्कालीन परिचित सिद्धान्तों को ही उदारवादी रूप में प्रतिपादित किया। निर्वाचक समूह में वृद्धि करके उन्होंने प्रजातंत्र में एक आधारभूत क्रान्ति को जन्म दिया।

जैक्सन का लोकतंत्र दो शक्तियों पर आधारित था। प्रथम सीमान्तिक दशा एवं पश्चिम दक्षिण में विचार धारणा, द्वितीय नगरों तथा औद्योगिक वर्ग का विकास था। 1830 तक प्रारम्भिक 13 राज्यों के अतिरिक्त 9 अन्य राज्यों का योज्य हो चुका था। 1850 तक 16 अन्य राज्य अमरीका में विलय हो चुके थे जिनमें से केवल दो मेन तथा वॉरमान्ट को छोड़कर शेष सभी पश्चिमी राज्य थे। इन नवीन राज्यों में आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति के विकासानुकूल थी। सीमान्तवादी जीवन ने राज्यों में आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगतता का समावेश किया। इसने सामाजिक समुदाय के सदस्यों में समानता के सिद्धान्त का रोपण किया। तत्कालीन समाज में पूँजी के केन्द्रीयकरण, आधुनिक रहन-सहन, ऐश्वर्ययुक्त वर्ग, एवं ऐतिहासिक परम्परा का पर्याप्त अभाव था। इस प्रकार की स्थिति अभिजात वर्ग के विचारानुकूल सर्वथा नहीं थी। इस प्रकार नव विचारधारा के क्षेत्र में अग्रसर व्यक्तियों को

आनुवंशिक सामन्तवाद, विशेषाधिकारिता वर्ग, परिहास का विषय था तथा धर्म तथा धन-सम्पदा पर आधारित योग्यतायें अस्वीकार्य थीं। वहाँ के निवासियों में जनता की सर्वोच्चता तथा अधिकारों में विश्वास था। विशेषाधिकारों के विषय में सदैव उन्होंने निषेधात्मक मनोवृत्ति अपनायी जबकि जन-शक्ति तथा मौलिक अधिकारों को उन्होंने पर्याप्त औचित्य प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त नगर की जनसंख्या में वृद्धि ने तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के विकास ने भी नव वातावरण को जन्म दिया। इस विचारधारा ने पूर्ण स्वामित्व युक्त अभिजात तंत्र को अमान्यता प्रदान कर राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी की माँग प्रस्तुत की। इस प्रकार पूर्वी प्रान्त में भी पश्चिमी एवं दक्षिण के प्रान्तों की भाँति कार्यों में रुचि प्रदर्शित करना आरम्भ किया।

उपरोक्त प्रजातांत्रिक प्रवृत्ति को जैक्सन के निर्वाचन के साथ राष्ट्रीय राजनीति में अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हुआ। जैक्सन के व्यक्तित्व में इस नवीन प्रजातंत्र के लक्षण अभिलक्षित थे। राष्ट्रपति पद के लिये जान एडम्स जैसे कुशल एवं प्रवीण व्यक्ति को पराजित कर उन्होंने अमरीका में रूढ़िवादी राष्ट्रपतियों की पद्धति को समाप्त कर एक नवसत्त का उद्भव किया। जैक्सन की विजय को अनेक गम्भीर विचारकों ने 'जन नरेश' की संज्ञा दी। उनके विचार में यह निकृष्ट जन तत्त्वों, अज्ञानपूर्ण तथा अयोग्य लोकतंत्र का प्रादुर्भाव था क्योंकि नव लोकतंत्र, इन मनीषियों के अनुसार, गणतंत्र के लिये गहन संकट का विषय था जिसमें लिप्त होकर गणतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो सकता था। परन्तु राष्ट्रीय राजनीति में नवीन परिवर्तन का प्रभाव शीघ्र स्पष्ट होने लगा। राष्ट्रपति ने स्वयं को जनता का प्रतिनिधि बताया तथा विधान पालिका एवं न्यायपालिका पर कार्यपालिका को प्रधानता प्रदान की। यह परिवर्तन अमरीका के इतिहास में एक नवीन परिवर्तन था क्योंकि जिस समय राज्यों के संविधान का निर्माण किया गया था, विधानपालिका को सर्वोच्च स्तर प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय शासन में भी काँग्रेस को सर्वोच्चता प्राप्त थी। काँग्रेस के सदस्य राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन करते थे, उन्होंने दो राष्ट्रपतियों का प्रत्यक्ष चयन भी किया था तथा उनके विधि निर्माण की शक्ति को कदाचित् ही कार्यपालिका द्वारा अवरुद्ध किया जा सका था। राष्ट्र की समस्त समस्याओं में उनका सर्वाधिकार लगभग सुरक्षित था। जैक्सन के राष्ट्रपति काल में प्रथम बार निषेधाधिकार (वीटो) शक्ति का जन्म हुआ जिसका अनुमान कदाचित् ही किया गया था। इस प्रकार राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकारों में पर्याप्त विस्तार हुआ तथा विधान-

पालिका पर प्रथम वार नियंत्रण विधि का प्रयोग किया गया।

विधानपालिका ने क्रांति काल में अत्यंत प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर लिया था परन्तु वर्तमान स्थिति ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को जन्म दिया और यह जैक्सन प्रशासन में मुख्यतः इंगित थी। जैक्सन ने स्वयं को काँग्रेस की भाँति जनप्रतिनिधि बताया तथा इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया कि राष्ट्रपति किसी भी रूप में दोनों अमरीकी सदनों से अवर नहीं था। क्रांति के पश्चात् कार्यपालिका के जिन अधिकारों का ह्रास कर दिया गया था उन मूल शक्तियों को पुनः कार्यपालिका ने हस्तगत कर लिया। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति जैक्सन की विजय क्रांति द्वारा प्राप्त विधानपालिका एवं अभिजातीय काँग्रेस की शक्तियों एवं अधिकारों के ऊपर जन समर्थित कार्यपालिका की सर्वोच्चता की द्योतक थी। यह अमरीका के राजनैतिक इतिहास में एक नवीन युग का प्रारम्भ था जिसके अन्तर्गत पुनः पुरातन ऐतिहासिक कथानक की पुनरावृत्ति हुई जिसमें जन समर्थित शक्तिशाली कार्यपालिका ने अभिजातीय वर्ग पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। निसन्देह जैक्सन को यह विश्वास था कि जनता का प्रतिनिधि वह स्वयं है न कि अभिजात वर्गीय विधानपालिका। इस संघर्ष में जनता ने भी उसके विश्वास की पुष्टि की तथा उसे अपना नेता माना। उसकी विजय की पुष्टिकरण में जनता उसे अधिक अधिकारों से सुसज्जित करना चाहती थी।

समान प्रकार की कार्यपालिका के अधिकारों का विकास राज्यों में भी परिलक्षित हुआ और सत्य तो यह था कि यह आन्दोलन राष्ट्रीय सरकार में न हो कर राज्यों से ही प्रारम्भ हुआ। राज्यपाल का चयन विधानपालिका से लेकर सीधे जनमत को हस्तान्तरित कर दिया गया, राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि को प्रवर्द्धित किया गया तथा कार्यपालिका के निपेधाधिकार के अधिकार को राज्यपाल में निहित कर उसे नियुक्ति अधिकार भी प्रदत्त किये गये। प्रारम्भिक "पूँजी पर आधारित योग्यता" को समाप्त कर सरकारी पदों के लिये समस्त जनता को समकरणता की नीति का पालन किया गया और इस प्रकार प्रशासकीय क्षेत्र में एक नवीन धारणा का समावेश किया गया। 1821 के न्यूयार्क सम्मेलन में एक प्रतिनिधि ने कहा कि "राज्यपाल के अधिकारों एवं उसके पदाधिकारित स्रोत के सम्बन्ध में एक गम्भीर त्रुटि है। वह कौन है? एवं वह किसके द्वारा नियुक्त होता है? क्या वह ब्रिटेन के सम्राट से अधिकार प्राप्त करता है? क्या वह एक अपहारक है? यदि ऐसा है तो आइये हम संयुक्त होकर उसे पदच्युत कर दें। परन्तु श्रीमन् वह जनता का प्रतिनिधि है वह लोकप्रियता के आधार पर जनमत द्वारा निर्वाचित है तथा

उनके हितों से अभिज्ञानित है। वह दुष्टता के प्रति हमारा 'सतर्क प्रहरी है।'

इस शताब्दी के पूर्वाध में लोकतांत्रिक आन्दोलन का सुस्पष्ट लक्षण कार्यपालिका के विकास के रूप में हुआ जिसके द्वारा विधान पालिका के अधिकारों का ह्रास हुआ। इसके साथ ही राजतंत्र के पुनः स्थापित होने का भय भी लुप्त हो गया तथा विधानपालिका को प्राप्त विश्वास भी समाप्त हो गया। जनता को वैधानिक गुट एवं 'अभितांत्रिक साहूकारी' से अधिक विश्वास व्यक्ति विशेष के पर्याप्त अधिकारों में निहित था। सदैव की भाँति इस बार भी अभिजातीय तंत्र को कार्यपालिका के ही द्वारा पराजित किया गया। राष्ट्रीय क्षेत्र में इस परिवर्तन का केन्द्र जैक्सन था जबकि राज्यों में परिवर्तनशील शक्तियों की भी यही मनोवृत्ति थी परन्तु वह विधानपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य शक्ति संतुलन को बनाने के लिये उद्यत थी।

राष्ट्रीय प्रशासन के क्षेत्र में अन्य दूसरा विषय उग्रवादी लोकतंत्र था जिसमें "पद के आवर्तन" तथा "लाभ की पद्धति" (इनामी पद्धति) ने मान्यता प्राप्त की। यह मुक्तया दलगत संस्था की विजय थी परन्तु पद के आवर्तन का सिद्धांत प्रमुखतया लोकतांत्रिक था। यह परिवर्तन राज्य संविधानों में इसके पूर्व ही पदों के कार्यकाल को न्यून करके तथा पूर्ण निर्वाचन को समाप्त करके प्राप्त कर ली गई थी। परन्तु अब यह सामान्य नियम बना दिया गया कि प्रत्येक पद अल्प कार्यकाल के लिये ही प्राप्त किया जा सकता था जिससे कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो सके। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित था कि किसी भी पद के लिये अन्य व्यक्ति भी उतना ही सक्षम है जितना कि दूसरा व्यक्ति। अतएव प्रत्येक नागरिक को शासकीय-जिम्मेदारी प्राप्त होने की सुविधा होनी चाहिये। इस सिद्धांत ने इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि पदों की योग्यता विशेषता के आधार पर प्राप्त होनी चाहिये जो कि केवल दीर्घ कार्यकाल के अनुभव से ही प्राप्त हो सकती है।

जैक्सन ने स्वयं अपने वार्षिक संदेश के अवसर पर यह कहा कि यह नवीन पद्धति दो विचारधाराओं पर आधारित है। प्रथम, यह कि किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने के लिये अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है तथा द्वितीय, यह कि दीर्घ कार्यकाल वास्तव में सरकारी पद के दुरुपयोग की जन्मदाता है। उनके विचार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम संख्या में होते हैं जो दीर्घ कार्यकाल के पश्चात् अपने कर्तव्यों से च्युत न हो जाते हों। उनका कहना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी योग्यता रख सकता है परन्तु वह एक दीर्घ अनुभव के उपरान्त सामान्यतः समाप्त हो जाती है। उनके विचार में वह नवीन पद्धति पूंजी की योग्यता को समाप्त करने वाली थी तथा यद्यपि व्यक्तिगत

स्तर पर आलोचना के योग्य होते हुये भी वह पद्धति गणतांत्रिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करती थी। इस नवीन पद्धति में पद अथवा लम्बे अवधि के कार्य काल का उसी प्रकार विरोध था, जिस प्रकार इसके पूर्व राज्यतंत्र अथवा अभिजातीय विशेषाधिकारों का विरोध किया गया था। यह आक्रमण इस आंदोलन का वह भाग है जिसने विशेषाधिकारों को क्षीण कर लोकतांत्रिक राजनैतिक संस्था को प्राथमिकता प्रदान की है। परिणाम स्वरूप कुछ उत्पन्न विचारों के उग्रवादी होने की सम्भावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था।

इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन निर्वाचन हेतु 'पूँजी की योग्यता' की आवश्यकता को समाप्त कर उसको "मानवाधार" प्रदान करना था। यह परिवर्तन राजनैतिक समाज में सर्वाधिक मौलिक होने के कारण विशेष विचारोत्तेजक था। उस काल में जब गणतंत्र की स्थापना की गई थी निर्वाचकों की योग्यता पर विशेष प्रतिबन्ध आरोपित किये गये थे। राजनैतिक शक्ति विशेषकर उन हाथों में सुरक्षित कर दी गई जो विशेष अर्थ में 'जनता' थी। शनैः-शनैः यह योग्यता संघ सरकार की स्थापना के साथ-साथ न्यून होती गई। बहुत ही कम राज्यों ने "पूँजी की योग्यता" की समाप्ति के आधार को संघ में मिलान के अवसर पर स्वीकार किया था। पुरातन राज्यों ने धीरे धीरे अपने संविधान में प्रदत्त योग्यताओं को समाप्त करना प्रारम्भ कर दिया था यद्यपि वर्जीनिया, न्यूयार्क, मैसाचुसेट्स तथा रोड (रोडड) द्वीप में इसके विपरीत तीव्र प्रक्रियायें व्यक्त की गई परन्तु परिवर्तन की गति तदनुसार बनी रहीं। किसी भी रूढ़िवादी व्यवस्था की पुनरावृत्ति नहीं की गई तथा सदी के मध्य तक निर्वाचन हेतु पूँजी की योग्यता लगभग सभी राज्यों में समाप्त कर दी गयी थी। यद्यपि निर्वाचन हेतु कुछ प्रतिबन्ध अब भी शेष रहे थे परन्तु उनके लक्षण न तो दमनात्मक थे और न ही समाज के किसी वृहत समुदाय को मत अपवर्जित करते थे। तथापि अधिकांश राज्यों में पूँजी की योग्यता समाप्त कर "सार्विक मताधिकार" की योग्यता को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इस प्रकार रूढ़वादी काल का अन्त हो गया तथा नवीन लोकतांत्रिक युग का जन्म इस सिद्धांत के साथ हुआ जिसने मानवाधिकारों तथा मौलिक अधिकारों को सुअवसर प्रदत्त किया।

अतीव संघर्षोपरांत ही इस नवीन परिवर्तन को मान्यता प्राप्त हो सकी थी परन्तु इस परिवर्तन के विरुद्ध आश्चर्यजनक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। सर्वोच्च आश्चर्य इस बात का था कि इस नवीन सिद्धांत का विरोध तत्कालिक वीर्यवर्ग के प्रमुख अधिवक्ताओं जैसे जॉन एडम्स, डेनियल विन्स्टर जोजफ स्टोरी, कैंट, मेडिसन, मुनरो, मार्शल एवं रेन्डाल्फ ने किया।

यद्यपि इस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा उस वर्ग से की गई थी जो मूलतः पदाधिकारियों का वर्ग था क्योंकि उनके लिये यह नवीन परिवर्तन निराधार, तर्कविहीन एवं न्याय रहित था। उनके विचार में यह सिद्धान्त पूर्णतया लोकतंत्र विरोधी था। कॅन्ट के विचार में लोकप्रिय निर्वाचन का यह सिद्धान्त स्वतंत्रता विरोधी, अल्पसांख्यिक दमनकारक, न्याय का अवमूल्यन, विशेषाधिकारों पर आक्रमण, असामान्य करारोपण, अपक्व एवं अस्थायी अधिनियम था। प्रत्येक रूप से इस तथ्य का पुष्टिकरण किया गया कि पूर्ण स्वामित्व सर्वाधिक सुरक्षित राजनैतिक अधिकारों का केन्द्र था। इस सिद्धान्त के विचारकों के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वर्ग ही केवल सक्रिय राजनैतिक समस्याओं में भाग ले सकता था। परन्तु शनैः शनैः भूस्वामी वर्ग का अधित्याग एवं उनके प्रति अविश्वास की भावना का प्रदुर्भाव होने लगा। यह परिवर्तन जैक्सन युग का एक महत्वपूर्ण योगदान था।

इसी समय उपनिवेशिक तथा क्रान्ति युग की उस पद्धति का भी समापन डेलावेयर एवं मैसाचूसेट्स राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों में हो गया जिसमें पूंजी के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती थी। सामान्यतः मध्य शताब्दी तक पूंजी पर आधारित योग्यता सरकारी पद हेतु केवल अतीतयुगेन थी। अतएव सरकारी पदों पर अब केवल विशेषाधिकार प्राप्त अल्पवर्ग का ही अधिपत्य शेष नहीं रह गया था अपितु अधिकारों के विकेन्द्रीकरण ने पदोप्राप्ति का द्वार खोल दिया था।

नियुक्ति तथा निर्वाचन के क्षेत्र में प्रचलित प्रतिबन्धों के साथ एक अन्य प्रतिबन्ध धर्मलक्षित था। न्यूयार्क एवं रोड (रोहड) द्वीप के अतिरिक्त समस्त राज्यों में रोमन कैथोलिक धर्मावलाम्बियों को अनर्हीकृत कर दिया गया था। यद्यपि यह अनर्ह करना बहुत ही अल्प काल तक ही रहा एवं शीघ्र ही राज्यों के संविधानों ने इस धारा का परित्याग कर दिया। सर्वप्रथम प्रोटेस्टेन्ट प्राविधान को समाप्त कर दिया गया तथा तत्पश्चात् धार्मिक प्रतिबन्धों को भी समाप्त कर दिया गया। प्रोटेस्टेन्ट, रोमन कैथोलिक, यहूदी, एकवादी एवं नास्तिक मान्यताओं को समान आधार प्रदान कर राजनैतिक क्षेत्र में उन्हें पूर्ण रूपेण समता प्रदान की गई। यद्यपि उस काल की मनोवृत्ति धार्मिक मूल्यों पर आधारित राजनैतिक संरचना के विपरीत थी, इन प्रतिबन्धों के पोषकों द्वारा भी तीव्र प्रतिक्रिया एवं विरोध प्रकट किया गया परन्तु उनकी विवेक शक्ति का अचिंत्य इतना क्षीण था कि उनकी मागों को जन शक्ति प्रभावशाली समर्थन नहीं प्राप्त हो सका।

उपरोक्त धार्मिक निर्वन्धों के समाप्त होते ही राज्यों में लागू धार्मिक

करों का औचित्य समाप्त हो गया। इनका प्रारम्भ क्रान्ति युग से हुआ था। संविधान में धार्मिक आधार को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी तदुपरान्त राज्यों ने भी उसको स्वीकार कर लिया था। 1833 तक धार्मिक करों को न्यूहैम्प शायर के अतिरिक्त समस्त राज्यों से समाप्त कर दिया गया। न्यूहैम्पशायर में अब भी क्रान्तिकारी संविधान को ही मान्यता प्राप्त थी।

इस प्रकार अमरीकी संस्थाओं का धर्म एवं राज्य का प्रचलित लक्षण समाप्त हुआ। यह विचार, यद्यपि जैफरसन ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किये थे परन्तु वह इनको कार्य रूप देने में असमर्थ रहे। उसी विवेकपूर्ण कार्य को जैक्सन ने अपनाया। उन्होंने कहा "चेतन का अधिकार" का आत्मसमर्पण मूल संविधान में नहीं किया गया था अपितु वे विशिष्टों द्वारा सुरक्षित कर लिये गये थे अतएव उनपर शासनाधिकार का कोई औचित्य शेष नहीं था। शासन केवल उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती थी जो अन्य के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकती हो।

इस काल के प्रजातांत्रिक आन्दोलन की दूसरी प्रमुख विशेषता जनता द्वारा अपने अधिकारियों के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करना था। इसके पूर्व यह अधिकार विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्त था अतएव अधिकारियों का चयन अपरोक्ष था। इस परिवर्तन द्वारा जनता ने न केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल, सदन के प्रतिनिधि एवं कोषाधिकारी तथा लेखा परीक्षकों के निर्वाचन का अधिकार प्राप्त कर लिया अपितु उसने छोटे-छोटे अधिकारियों, लिपिकों, न्यायाधीशों के भी निर्वाचन का अधिकार प्राप्त कर लिया। इन समस्त परिवर्तनों के पीछे यह मान्यता कार्यरत थी कि विधानपालिका वस्तुतः एक अधिनायकवादी संस्था थी एवं जनता को स्वयं ही अपने अधिकारियों का निर्वाचन करना चाहिये।

इन परिवर्तनों के समकक्ष, न्यायपालिका के विरुद्ध भी प्रतिक्रियाएँ एवं भय प्रारम्भ हो गये थे। इन न्यायपालिकाओं को विशेषतया अभिजातीय समझा जाने लगा था। राज्य एवं केन्द्र दोनों न्यायालयों को सन्देहात्मक दृष्टि से देखा जा रहा था। संघ न्यायालय से भय का कारण उसका राज्यों पर अधिकार क्षेत्र तथा राज्यों में न्यायालयों को प्रजातांत्रिक भावनाओं के अन्तर्गत हानिकारक समझा जा रहा था। इस इच्छा को न्यायपालिका पर दो प्रकार से उनका कार्यकाल कम करने तथा उनके चुनाव को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करके कार्यान्वित किया गया। गगतंत्र के प्रारम्भिक वर्षों में न्यायाधीशों को उनके उच्च व्यवहार के आधार पर कार्यकाल प्रदान किया जाता था। आजीवन कार्यकाल, लोकतंत्र के लिये सर्वथा अनुपयुक्त था एवं प्रथम अवसर प्राप्त होते

ही उन्हें समाप्त कर दिया गया। आजीवन कार्यकाल को 5 से 15 वर्ष के मध्य कर दिया गया। प्रमुखतया 6, 7, 8 तथा 9 वर्ष का कार्यकाल स्वीकार किये गये। निर्वाचन की पद्धति अपेक्षाकृत धीरे-धीरे अपनाई गई। सर्वप्रथम प्रान्तीय न्यायधीशों एवं छोटे न्यायधीशों में निर्वाचन की पद्धति का अनुसरण किया गया। तत्पश्चात् 1846 से 1853 के मध्य 13 राज्यों ने निर्वाचन की पद्धति स्वीकार ली। इस प्रकार इन दो प्रकरणों द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति ने न्यायपालिका पर भी सर्वोच्चता का अधिकार सिद्ध कर दिया।

1830 से 1850 के मध्य संविधान के मौलिक प्राविधानों में परिवर्तन हेतु जनतंत्र का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार इस नवीन लोकतांत्रिक आन्दोलन ने अमरीका में रूढ़िवादी, क्रान्ति युगीन अभिजातीय स्वेच्छाधारी विधानपालिका तथा न्यायपालिका के ऊपर लोकप्रिय, जन समर्थित एवं जन प्रतिनिधित्व के द्योतक कार्यपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। 4 मार्च, 1829 को जैक्सन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर उसके अनुयायियों का जो समूह राजधानी में एकत्रित हुआ वह सर्वथा अपूर्व था। समस्त वातावरण उत्तेजना तथा उमंगों से परिपूर्ण था निश्चय ही यह उनके नवीन लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का मानवीकरण था। जैक्सन के लोकतंत्र का स्वागत करते हुये एक गणतंत्रीय समाचार पत्र ने टीका करते हुये लिखा कि जनलोकतंत्र ने निरंकुशता के दैत्य का नाश कर जनता को अपनी शक्ति एवं अधिकारों के प्रति सजग किया था। अमरीका के संस्थापकों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी आशंका प्रकट करते हुये इसे अन्ततः आतंकवाद के निष्कर्ष की मान्यता दी।

लाभ की पद्धति (इनामी पद्धति) तथा दल सत्ता

जैक्सन के लोकतंत्र का एक प्रमुख पक्ष सरकारी पदों का अपने अनुयायियों के मध्य प्रकट रूप से वितरण करना भी था। यद्यपि इस पद्धति की उपलब्धि स्वयं जैक्सन ने नहीं की थी तथापि उसने अपने पूर्वाधिकारियों की अपेक्षा इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से अधिक किया। अपने विश्वसनीय कार्यकर्त्ताओं को इन सरकारी पदों पर नियुक्त कर उसने अपने दल की स्थिति दृढ़ कर ली। कालान्तर में यह दल की राजनैतिक शक्ति का एक प्रमुख यंत्र हो गया। अधिकारियों की नियुक्ति में किसी भी सिद्धान्त को प्राथमिकता नहीं प्रदान की गई अपितु जैक्सन के प्रति निष्ठावान होना ही प्रमुख योग्यता थी। इस पद्धति में टाक-टार, सीमा शुल्क विभाग तथा अन्य विभागों पर व्या-

पक प्रभावः पड़ा। अधिकारियों के स्थानान्तरण, पदच्युति तथा अपनयन हेतु किसी भी प्रकार का कारण देना आवश्यक नहीं समझा गया।

यथार्थ रूप से यह कहना कि जैक्सन ने किस सीमा तक प्रशासनिक सेवाओं को प्रभावित किया, सम्भव नहीं है। परन्तु यह निश्चय ही कहा जा सकता है कि यह नियुक्ति की विधि तथा संख्या ही थी जिसने प्रमुखतया जनमत को प्रभावित किया था। तथापि 1830 के पश्चात् मतभेदों में पर्याप्त कमी हो चुकी थी। ऐसे विषयों पर कांग्रेस में प्रस्ताव रखे जाते थे जैसे कि 1835 में एक प्रस्ताव रखा गया कि किसी भी नियुक्ति के पूर्व उपयुक्त कारणों का होना आवश्यक था। यह प्रस्ताव कैलहन ने 1820 में अधिनियम को समाप्त करने के लिये रखा था। यद्यपि सीनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया परन्तु सदन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार अन्तिम विजय जैक्सन को ही प्राप्त हुई। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जैक्सन ने कभी भी अपने निर्णय के प्रति खेद प्रकट किया हो। सम्भवतया एडम्स द्वारा कार्यकारिणी के भ्रष्ट प्रयोग के ही कारण जैक्सन ने उपर्युक्त निर्णय लिया हो। उनके विचार में सरकारी-तंत्र पर्याप्त भ्रष्ट हो चुका था तथा उसमें सुधारात्मक कार्य अत्यन्त आवश्यक था। लेखाधिकारी के अपनयन के अवसर पर उसने वॉन व्यूरेन को यह सूचित किया कि उपयुक्त अपनयन ईमानदारी के आधार पर किया गया है क्योंकि जनता सुधार चाहती थी एवं उसे निराश नहीं किया जा सकता था।

जैक्सन ने कदाचित ही अपने सर्वाधिकारों को अस्वीकृत किया। 1831 में सीनेट ने एक प्रस्ताव यह रखा कि किसी अन्य राज्य के नागरिक की नियुक्ति दूसरे राज्य में करना अनुचित था। 1833 में जैक्सन ने इसके उत्तर में मिसिसिपी में कुछ राज्यों की नियुक्तियों को अस्वीकृत कर दिया। क्योंकि उस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नामांकन अयोग्य घोषित हो चुके थे।

यद्यपि जैक्सन इस पद्धति के अन्वेषक नहीं थे परन्तु राज्यों से केन्द्र तक उसको विकसित करने का श्रेय जैक्सन तथा उसके अनुयायियों एवं परामर्श-दाताओं को ही था। इस प्रकार रूढ़िवादी पद्धति को समाप्त कर जैक्सन ने नवीन पद्धति द्वारा जनतांत्रिक प्रवृत्ति को विकसित किया।

(अमरीकी इण्डियन समस्या) अमरीकी आदिवासी समस्या

जैक्सन का प्रशासन आवर्तन परिवर्तन के सिद्धान्त पर आधारित था। अनेक राजनेताओं को इनामी पद्धति का अर्थ आवर्तन था परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं था क्योंकि इनामी पद्धति केवल आवर्तन परिवर्तन ही में सीमित

नहीं थी अपितु उपरोक्त आधारशिल्प पर निर्मित सिद्धान्त के अन्तर्गत इससे संलग्न समस्याओं की भी वह पूर्ति करती थी। जैक्सन ने स्वयं दिसम्बर, 1829 को कहा कि मेधावी एवं अभिज्ञा व्यक्ति किसी भी रूप में सरकारी अधिकारी पद पाने योग्य थे क्योंकि उनके अनुसार किसी 'व्यक्ति विशेष' को लोक राजस्व व्यय पर निरन्तर सहयोग प्रदत्त नहीं किया जा सकता था।

जैक्सन को इस का पूर्ण विश्वास था कि आवर्तन-परिवर्तन के सिद्धान्त द्वारा अमरीकी जनता की मतपेटिका द्वारा इच्छित अमरीकी समाज के परिवर्तन की अप्रत्यक्ष अभिलाषा को पूर्ण किया जा सकता था। राष्ट्रपति की यह नीति जैफरसन के उस सिद्धान्त पर भी आधारित थी कि जनता एवं सरकार में भागीदारी अधिनायक तंत्रीय शासन की उत्पत्ति में अवरोधीय शक्ति का कार्य करती है। परिवर्तन के नियम का आधारभूत भी इसके समरूप था केवल जैक्सन ने उपरोक्त सिद्धान्त को सत्ता के परिधान से युक्त कर क्रान्ति का स्वरूप दिया। जैक्सन युग के प्रवर्तकों ने यदि 'दास समस्या' के समाधान में असफलता ग्रहण की तो आदिवासी (इण्डियन) समस्या के प्रति ऐसी धारणा गलत होगी कि इस ओर उनका ध्यान केन्द्रित नहीं हुआ। इस विषय पर उन्होंने प्रतिशोध की भावना से कार्य किया जो कि उस समय के अमरीकी समाज को सन्तुष्ट करने में सहायक था। इस समस्यायिक समाधान का भीषण प्रभाव अमरीकी राष्ट्र पर हुआ जिसका अनुभव तत्कालीन अमरीकी परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। आदिवासी प्रश्न को लेकर जैक्सन प्रशासन ने जो निर्णय लिया, वह उस प्रशासन की 'लोकतांत्रिक परिधि' से बाहर था।

कुछ आधुनिक अमरीकी बुद्धिवेत्ताओं ने तथा इतिहासकारों ने उस समय के प्रशासन की नीति को सुविचारित जातिसंहार की संज्ञा दी है। वरनार्ड शीहेन ने श्वेत जाति को अमरीकी आदिवासियों के नाश का मूल दोष दिया है। एक अन्य आधुनिक इतिहासकार ने भी व्यांगात्मक रूप से यह कहा है कि यह बहुत सौभाग्यपूर्ण है कि सौ वर्ष पश्चात् उनके विध्वंस का मूल खोत्र बनकर अब उनके प्रति चिन्ता एवं सहायता प्रकट की जा रही है।

इसके उपरान्त भी अनेक अमरीकावासियों का आदिवासियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण किंचित भावुकता से परिपूर्ण है। निःसन्देह यह सत्य है कि यदि श्वेत जाति उस समय मानवीय मूल्यों से युक्त होती अथवा अपने लालच को रोक पाती और संघीय शासन आदिवासियों के प्रति इतना कठोर न होता तो सम्भवतः जैक्सन युग के लोकतांत्रिक प्रणाली पर आघात न किये जाते।

इसी संदर्भ में यह अत्यन्त रोचक है कि जब तक अमरीका में लोक-तंत्रीय प्रणाली का विकास नहीं हुआ, बहुमत को श्रेय नहीं दिया गया तथा राजनैतिक नेताओं को जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया तब तक आदिवासियों के उन्मूलन का प्रश्न ही नहीं हुआ। इससे भी अधिक लोकतांत्रिक विरोधाभास तब उत्पन्न हुआ जब आदिवासियों को अपने पूर्वजों की भूमि को त्याग कर दूरवर्ती एवं निर्जन क्षेत्र में जाना पड़ा और वह भी राष्ट्रपति एण्ड्रू जैक्सन के समय में जो 'महान लोकतंत्र' के प्रतीक थे। परन्तु इस जटिल प्रश्न को पूर्ण रूप से अर्थगत करने हेतु तथा राष्ट्रपति जैक्सन की स्थिति को संतुलित एवं तर्कसहित समझने हेतु 'श्वेत आदिवासी प्रश्न' को प्रारम्भ से जानना अत्यावश्यक है।

आदिवासियों के प्रति अमरीकी नीति प्रारम्भ से ही भद्र एवं अहितेच्छु रही। यह विरोधाभासित नीति उत्तरी अमरीका में अंग्रेजों के आगमन से आरम्भ हुई। अंग्रेजों ने आदिवासियों को पश्चिमी सभ्यता एवं ईसाई मत धारण करने हेतु चेष्टा की और दंडस्वरूप उनकी भूमि को हस्तगत कर लिया। परन्तु अमरीकी क्रान्ति के मध्य इस प्रकार की अस्पष्ट नीति में परिवर्तन आया। इसका मुख्य कारण था कि अधिकांश आदिवासियों ने ब्रिटिश लोगों का साथ दिया और फलतः अमरीकी लोगों से स्वयं के गलत निर्णय लिये जाने के कारण दंडित भी हुये और वह दंड जन समर्थित था।

संविधान की घोषणा के पश्चात् तथा स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता की सरकार की स्थापना ने आदिवासियों के प्रति नीति में परिवर्तन किया।

संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने जो प्रबुद्धता युग के मान्य थे, अपने निर्णय में आदिवासियों को अविकसित सभ्यता का प्रतीक समझ उनमें सभ्यता को निविष्ट करने की सहमति प्रकट की अर्थात् आदिवासी शनैः शनैः अमरीकी सभ्यता का अंग बन जायेंगे। जार्ज वाशिंगटन ने तथा उनके युद्ध सचिव हेनरी नाक्स (युद्ध सचिव ही आदिवासी समस्या देखते थे) ने राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत आदिवासियों को सभ्यता का ज्ञान करा संघ में सम्मिलित करने की योजना निर्मित की। वाशिंगटन का विचार था कि आदिवासियों का श्वेत जाति की भाँति शीघ्र ही समाजीकरण कर लिया जायेगा ओर वे संयुक्त राष्ट्र के अंग बन जायेंगे। राष्ट्रपति जैफरसन ने भी उपरोक्त नीति का अनुसरण किया और उन्होंने आदिवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सम्बोधित करते हुये कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा थी कि आदिवासी स्वयं को कृषि कार्य में लगाकर अपना गृह निर्माण करें और मृत्युपश्चात् अपनी पत्नी बच्चों को सौंप जाय और परिवार सदा पुष्पित होता रहे। इसके अतिरिक्त

जैफरसन ने उनको आश्वासन दिया कि समाजीकरण के पश्चात् एक जातीय होकर सब अमरीकावासी समरूप रहेंगे परन्तु इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करने पर और स्वयं को सभ्यता से परे रखने पर आदिवासियों को जन्तुओं के साथ जंगल में पथरीले पर्वतों की ओर भेज दिया जायेगा ।

इस प्रकार जब तक एण्ड्रू जैक्सन राष्ट्रपति निर्वाचित हुये उस समय तक अमरीकी राष्ट्रपतियों के समस्त प्रयोग आदिवासियों के प्रति असफल हो चुके थे और उन्हें अमरीकी समाज में विलीनीकरण का प्रश्न समाप्त हो चुका था । ऐसी स्थिति में लोकप्रिय मतदान के द्वारा विजयी राष्ट्रपति को इस गहन समस्या का समाधान करना था और राष्ट्रपति प्रशासन ने आरम्भ से ही जनता की रूचि का ध्यान रखा । अपने प्रथम - वार्षिक भाषण में (1829) कांग्रेस को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ दक्षिणजनी जातियों ने जार्जिया एवं अल्बामा में स्वतन्त्र सरकार बनाने का प्रयत्न किया परन्तु जार्जिया एवं अल्बामा ने अपने अधिकारों को आदिवासियों पर भी प्रस्थापित किया । इन राज्यों का तर्क था कि जन-जातियाँ उनकी प्रभुसत्ता के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रही थी । आदिवासियों ने इन राज्यों से भयग्रस्त होकर संयुक्त राष्ट्र सरकार से सुरक्षा की माँग की । इन परिस्थितियों में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या संयुक्त राष्ट्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती थी ? संविधान के अनुसार किसी राज्य क्षेत्र में कोई अन्य राज्य बिना विधानसभा की स्वीकृति के स्थापित नहीं किया जा सकता था । तदनुसार संयुक्त राष्ट्रीय सरकार ने जनजातियों को अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और यह परामर्श दिया कि यदि वे राज्यकीय शासन के अधीन नहीं रहना चाहते तो मिसिसिपी के पार उत्प्रवास की व्यवस्था करें । राष्ट्रपति के पास इस उत्प्रवास की नीति के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था । इस पर भी राष्ट्रपति ने जनजातियों को ऐच्छिक उत्प्रवास की सुविधा दी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आदिवासी अपने पूर्वजों की समाधियों को त्याग दूरस्थ स्थानों को प्रस्थान करें । परन्तु यदि आदिवासी अपने क्रमात् राज्यों में उनके अधीनस्थ नहीं रहना चाहते थे तो उन्हें राज्यों को त्यागना होगा । इतिहासकारों ने जैक्सन को आदिवासियों के प्रति घृणायुक्त नीति का पालक दर्शाया है परन्तु यह निष्कर्ष संतुलित नहीं है । जैक्सन की नीति का विश्लेषण करते हुये फ्रांसिस प्रूण ने चार तथ्यों की ओर इंगित किया है प्रथम जैक्सन आदिवासियों की नृशंस हत्या का पात्र बन सकते थे परन्तु उनके प्रशासन में इस प्रकार का विचार मान्य नहीं हो सकता था । द्वितीय वह श्वेत आदिवासी एकीकरण का प्रयास कर सकते थे परन्तु उनसे पूर्व राष्ट्रपतियों ने इसका प्रयास किया और असफल रहे । इसका मुख्य

कारण अमरीका की श्वेत जाति का स्वयं को उच्च मान्यता देना था तथा दक्षिण इसमें मुख्य था। तृतीय स्थिति में राष्ट्रपति आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते थे और ऐसी परिस्थिति में पूर्ण देश एक सैनिक शिविर बन जाता और आदिवासी श्वेत जगत में एक द्वीप समूह के समान होते। चतुर्थ एवं अन्तिम विकल्प में राष्ट्रपति को उत्प्रवास की नीति का पालन करना शेष था जो एक सीमा तक राष्ट्रहित में था। यद्यपि यह विश्वास करना कठिन है कि राष्ट्रपति जैक्सन जो कि आदिवासी योद्धा के नाम से जाने जाते थे इन जनजातियों की ओर संतुलित नीति का परिपालन करेंगे परंतु इस सत्य को स्वीकृत नहीं किया जा सकता कि इस महान योद्धा ने 1813 के क्रीक युद्ध में एक मृतक आदिवासी स्त्री की गोद से उसके पुत्र को अपना लिया। ऐसी स्थिति में जबकि अन्य आदिवासी स्त्रियों ने उस बालक का पोषण करने से इंकार कर दिया इस पर जैक्सन ने उस बालक के पोषण का भार अपने ऊपर लिया और उसका नामकरण 'लिनकाँयर' किया। इस बालक को उन्होंने अपने परिवार के सदस्य की भाँति पोषित किया और सुशिक्षा प्रदत्त की। अभाग्यवश वह बालक सत्रह वर्ष की अवस्था में मृत्युग्रस्त हो गया। ऐसी दशा में जैक्सन को आदिवासी घृणा से युक्त किस प्रकार माना जा सकता था? सम्भवतया संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने अपनी आदिवासी नीति में इन लोगों को मिसिसीपी नदी के पश्चिम क्षेत्र में उत्प्रवास के निश्चय के फलस्वरूप 'मानव अनर्थ' के प्रति विचार नहीं किया था। तत्पश्चात् 1834 में कांग्रेस के द्वारा अधिनियम पारित होने पर आदिवासी प्रदेश आरक्षित किया गया जो ओक्लहोमा राज्य में स्वरूपित हुआ।

अकृतीकरण (नलीफिकेशन)

अमरीका के इतिहास में दासता के प्रश्न को लेकर प्रथम गम्भीर राष्ट्रीय विस्फोट जैक्सन प्रशासन में हुआ। परन्तु राष्ट्रपति के सशक्त नेतृत्व के कारण, दोनों ओर समझौते के इच्छुक होने के कारण तथा संघ को सुरक्षित रखने के लिये एक अस्थायी वातावरण-निर्मित कर लिया गया जिसमें अमरीका भ्रातृ रक्तपात से कुछ समय के लिये तो रक्षित हो गया। इतिहासकार विलियम फ्रीहर्लिंग के अनुसार 1832 की विवादात्मक स्थिति केवल तीस वर्ष पश्चात् घटित घटना की प्रस्तावना थी। जब गृह युद्ध आरम्भ हुआ तो अनेक अमरीका वासियों ने जैक्सन युग का स्मरण किया। यहाँ तक कि 1860 के चुनाव में कई एक अमरीकी मतदाताओं ने जैक्सन को मत प्रदान किया। यद्यपि यह

मुख्यतापूर्ण कार्य था परन्तु वे सम्भवतया इस तथ्य को उज्वलता प्रदत्त करना चाहते थे कि अमरीका को 'ओल्ड हिक्की' की भांति नेतृत्व की आवश्यकता थी।

जैक्सन के प्रशासन में अमरीकी राष्ट्र की उत्पत्ति के चालीस वर्ष पश्चात् उत्तर में दासता की प्रथा को लेकर तथा दक्षिण में सीमा शुल्क एवं अकृतीकरण के प्रश्नों पर राजनैतिक विचारधारा में परिवर्तन प्रतीत होने लगा। इस विचारधारा ने भविष्य में संघीय संकट उत्पन्न कर दिया। इस संकट का विवेचन करने से पूर्व कुछ मुख्य तत्वों का परीक्षण करना नितान्त आवश्यक है। इन तत्वों में राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता के साथ ही उन लोगों की महत्वाकांक्षा निहित थी जो जैक्सन के पश्चात् राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के स्वप्न देख रहे थे। इनमें जान कैलहून तथा वॉन ब्यूरेन की प्रतिस्पर्धा मुख्य थी। शनैः शनैः जब कैलहून को राजनीतिक भविष्य धूमिल प्रतीत होने लगा तो वह दुःसाहसी हो गया और दासता के प्रश्न को लेकर अपनी निराशा की क्षति पूर्ति करने लगा।

उपरोक्त स्थिति का निर्णायक परिणाम कैलहून के एक मुद्रित लेख (प्रस्ताव) विवृत्ति एवं विरोध (एक्सपोजीशन एण्ड प्रोटैस्ट) का दक्षिणी केरोलिना विधान मंडल से पारित हो जाना था। इस प्रस्ताव एवं लेख में कैलहून ने संरक्षित सीमा शुल्क की भर्त्सना की तथा अकृतीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अन्तर्गत इस विचार पर तर्क किया गया कि यदि संघीय शासन कोई ऐसा विधान पारित करेगा जिसका परिणाम किसी राज्य के हितों के प्रति हानिकारक था तो वह राज्य उस विधान से अपने क्षेत्र में वैधानिक रूप से क्रियात्मक होने से रोक सकता था। इसका अर्थ यह था कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में संघीय विधान को अकृत कर सकती थी। इसके अतिरिक्त यदि तीन-चौथाई राज्यों ने किसी भी विधान को अकृत कर दिया तो वह सर्वत्र समान्य समझा जायेगा। कैलहून के अनुसार अकृतीकरण ही एक ऐसा उपाय था जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग सुरक्षित था तथा गणतंत्र में बहुसंख्यक शासन को सदैव अल्पसंख्यक अधिकारों के द्वारा संतुलित रखना चाहिये। कैलहून ने अपने तर्क में यहाँ तक कहा कि यदि संघीय शासन किसी एक राज्य के अकृतीकरण को स्वीकार नहीं करता तो उसे संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार था। इसके साथ ही कैलहून का कहना था कि अकृतीकरण का सिद्धांत सम्बन्ध विच्छेद तथा संघीय विघटन निरोधक था।

उपरोक्त विचारों के सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय पुनरीक्षण ने ऐतिहासिक वेवस्टर-हेन वाद-विवाद को 1830 में जन्म दिया। इस वाद-विवाद में हेन ने कैलहून के विचारों को समर्थन प्रदान करने हेतु अकृतीकरण तथा दासता



डेनियल वैब्सटर (1782—1852)



जॉन कॉल्डवेल कैलहून (1782-1850)

का समर्थन अपनी तर्क संगत युक्तियों द्वारा किया। इसके विपरीत वेवस्टर ने अपने ओजस्वी भाषण में स्वाधीनता और संघ को एक दूसरे का परिपूरक बताया और अकृतीकरण को संयुक्त राज्य के विघटन के श्रोत की संज्ञा दी।

निःसन्देह वेवस्टर का भाषण विस्मयकारक था परन्तु अकस्मात् इस सार्विक वाद विवाद से राष्ट्रीय एकता विभूषण हो सकती थी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जैक्सन ने 'वॉनब्यूरेन' से परामर्श कर इस वाद-विवाद को शीघ्र समाप्त करने का निश्चय किया। एक कट्टर राष्ट्रवादी होने के नाते अकृतीकरण के विचार से घृणा थी। राष्ट्रपति जैक्सन को इसका अवसर अप्रैल, 1830 में टामस जैफरसन के जन्म दिवस समारोह में प्राप्त हुआ। इस अवसर में राष्ट्रपति ने इस बात कि घोषणा की कि किसी भी मूल्य पर संघीय शासन को सुरक्षित रखा जायेगा। घोषणा के उपरान्त भी कैलहून और उनके अनुयायियों ने दिवालियेपन का राजनीति अपनाते का पूर्ण प्रयत्न किया परन्तु राष्ट्रपति जैक्सन की राजनैतिक सतर्कता एवं नेतृत्व की प्रबुद्धता ने संघीय शासन को न केवल विघटित होने से सुरक्षित रखा वरन् राष्ट्र की भ्रातृतीय रक्तपात से रक्षा की।

बैंक

राष्ट्रपति जैक्सन के प्रशासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना उनका अमरीकी बैंक के प्रति संघर्ष था। राष्ट्रपति के बैंक संघर्ष को अधिक उपयुक्त 'जैक्सन युद्ध' की संज्ञा दी जा सकती है। इस संघर्ष ने राष्ट्रीय राजनीति को पुनः निर्मित किया। सम्भवतया 1816 से 1850 तक की समस्त घटनाओं को राष्ट्रपति के इस कार्य ने धूमिल कर दिया। इस संघर्ष ने एक नये राजनैतिक 'विग दल' का भी सृजन किया। इसके अतिरिक्त इस राजनैतिक घटना ने लोकतंत्रिक दल का चारित्रिक निर्माण किया तथा नेतृत्व के प्रति श्रद्धा एवं स्थाई अनुशासन को प्रोत्साहन दिया।

बैंक के प्रति राष्ट्रपति के राजनीतिक एवं आर्थिक युद्ध के प्रारम्भ ने संयुक्त राष्ट्र की मौलिक संरचना में परिवर्तन किया। इस द्वितीय संयुक्त राष्ट्र बैंक ने 1812 के पश्चात् अमरीकी वित्ततंत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। अनेक नागरिकों के लिये यह बैंक एक वृहद् व्यापार, एकाधिकार एवं शक्तिशाली निगम के रूप में प्रतिनिधित्व करता था। बैंक की इस "आर्थिक पुंज" की स्थिति को अनेक अमरीकी राजवेत्ता एवं राष्ट्रवादी राष्ट्र हित में नहीं समझते थे। इनमें जैक्सन भी एक थे। जैक्सन को बैंक के असीमित अधिकारों के प्रति रोष था क्योंकि बैंक का एक मात्र उद्देश्य अपने अंशधारियों (शेयर

होल्डर) का कल्याण करना था और सामान्य जनता के प्रति इस बैंक की कोई कल्याणकारी नीति नहीं थी। इसके अतिरिक्त स्वपूँजी केन्द्रीयकरण के द्वारा संयुक्त राष्ट्र बैंक राजनैतिक विशेषाधिकारों में सदैव हस्तक्षेप की चेष्टा में रत रहता था। इस समय बैंक का अध्यक्ष निकोलस विडल था, जिसके पास मस्तिष्क, रूपरंग, धन, परिवार, सुरुचि, व्यवहार कौशल एवं अपार आर्थिक प्रबुद्धता थी। इसके साथ विडल में अहं बहुत था और वह विशेष कांग्रेस सदस्यों का समर्थन एवं सहयोग करता था।

राष्ट्रपति जैक्सन ने 1829 में अपने कांग्रेस के प्रेषित सन्देश में संयुक्त राष्ट्र बैंक की आलोचना की। राष्ट्रपति ने बैंक की प्रचलित प्रणाली को जनसाधारण के विरोध में माना। उनके विचार में बैंक ने ठोस एवं समान मुद्रा प्रणाली को नहीं अपनाया था। इसलिये जैक्सन बैंक में शासकीय नियंत्रण के पक्षपाती थे। अतः 1832 में बैंक को पुनः अधिकृत मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव को वर्तमान अधिकारों द्वारा राष्ट्रपति जैक्सन ने अस्वीकृत कर दिया। यद्यपि यह प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो चुका था परन्तु राष्ट्रपति के इस कार्य के द्वारा राष्ट्र में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से असंतोष की भावना उत्पन्न हुयी। यद्यपि राष्ट्रपति के इस कार्य को अनेक अमरीकी विधि वेत्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं राष्ट्रवेत्ताओं ने प्रशंसा की दृष्टि से देखा। फिर भी जैक्सन के इस कार्य ने सम्पूर्ण देश में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न कर दी।

इसी मध्य राष्ट्रपति के चुनाव घोषित किये गये और इसमें संयुक्त राष्ट्र बैंक एक ज्वलंत विषय था, और जैक्सन का विरोध उनकी आर्थिक नीतियों के कारण कैलहून ने किया। कैलहून ने अपने चुनाव प्रचार में जैक्सन की नीतियों का तर्कयुक्त खण्डन किया और जनसाधारण से यह अनुरोध किया कि वे जैक्सन की आर्थिक नियंत्रण की नीति का वहिष्कार करें परन्तु चुनाव में जैक्सन को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। चुनावोपरान्त अधिकार पत्र की स्वीकृति नहीं दी गई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र बैंक को समाप्त कर जैक्सन ने अपने काल के महत्वपूर्ण वैधानिक निर्णय का सूत्रपात किया। यह निर्णय लोकतांत्रिक विचारधारा की महान विजय थी और विग दल के लिये एक निराशाजनक पराजय।

निस्सन्देह, राष्ट्रपति जैक्सन अपने प्रशासकीय कार्यों के मध्य एक आलोचनात्मक व्यक्तित्व के स्वामी रहे परन्तु उनकी आलोचना के अन्तर्गत भी उनके निर्णीत कार्यों में लोकतांत्रिक स्वाधीनता का समन्वय था, इसमें सन्देह नहीं

कि राष्ट्रपति जैक्सन अमरीका के इतिहास में सदैव एक निर्णायक के रूप में जाने जाते रहेंगे। जस्टिस स्टोरी ने राष्ट्रपति जैक्सन के प्रशासन को जन-उलसित की संज्ञा दी है। उनके विचार में किंग भाँव (जन नरेश) का चुनाव जन दिवस था। जैक्सन जनता के राष्ट्रपति थे और जन प्रशासन के प्रतीक थे।

उप-संहार

1828 में राष्ट्रपति एण्ड्रू जैक्सन का चुनाव अमरीकी इतिहासकारों ने अमरीका के इतिहास में युग संघ के रूप में किया है क्योंकि जैक्सन के चुनाव से पूर्व जो राष्ट्रपति आये वे वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स के थे। इसलिये यह लोग अभिजातीय विशिष्ट वर्ग से सम्बन्धित माने जाते थे जबकि एण्ड्रू जैक्सन स्वनिर्मित, स्वलम्बित और सैन्यनायकत्व से परिपूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी था। इन अभिलक्षणों के कारण उनका व्यक्तित्व आकर्षणमय समझा जाता था। जैक्सन का चुनाव जनसाधारण के लिये लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय थी।

इस प्रकार 1828 से 1840 का समय अमरीकी इतिहास में विद्वानों के लिये विवादास्पद युग था। राष्ट्रपति जैक्सन के कार्यों का मूल्यांकन प्रारम्भिक काल में अत्यन्त आलोचनात्मक था। जैक्सन के प्रति प्रथम गम्भीर लेखन कार्य का श्रेय उसके जीवनी लेखक जैम्स पार्टन को है। पार्टन ने इस तथ्य को मान्यता दी कि 'ओल्ड हिकरी' यद्यपि अमरीकी जनता के आदर्श थे, परन्तु राष्ट्रपति पद पर उनका उन्नयन अमरीकी लोगों की दृष्टि थी क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा की हुई अच्छी नीतियाँ अधिक समय तक न कार्यान्वित हो सकीं परन्तु अहितकारी नीतियाँ (इनामी पद्धति) अपनी अमित छाप छोड़ गयी। पार्टन की आलोचना का अनुवाद 19वीं शताब्दी के अन्य लेखकों हरमन वान होल्सट, विलियम समनर तथा जैम्स स्काउलर ने किया। इन लेखकों ने इस मत का समर्थन किया कि जैक्सन अशिक्षित, निरक्षर, अनभिज्ञ तथा भावनाग्रस्त व्यक्ति थे और उनके समस्त कार्य शक्ति संचय की ओर लक्षित थे। पार्टन ने लिखा है, कि जैक्सन स्वयं अपनी अनभिज्ञता एवं अज्ञानता के द्वारा बंदी थे वह अपनी चक्रपरिधि में उसी प्रकार सीमित थे जिस प्रकार सिंह अपनी माँद में रहता है। उन्नीसवीं शताब्दी के इन इतिहासकारों का जैक्सन के प्रति द्वेष उनकी स्वयं की राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं था, वरन् इनमें से बहुत से विद्वान स्वयं को 19वीं शताब्दी के आर्थिक उदारवेत्ता की संज्ञा देते थे और वे अहस्तक्षेप नीति के प्रतिपालक थे। इस प्रकार वे जैक्सन की रचनात्मक आर्थिक हस्तक्षेप की नीति से सहमत नहीं थे। यद्यपि जैक्सन की नीतियाँ

जिसमें उनका अमरीकी वैकों पर प्रहार भी सम्मिलित था, इन विद्वानों को रुचिकर न थीं, परन्तु वे जैक्सन के शक्तिपूर्ण एवं निश्चयात्मक राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने जैक्सन के राष्ट्रपतित्व की निन्दा एवं अवमूल्यन इस तथ्य पर किया कि जैक्सन ने अमरीकी राजनीति को लोकतन्त्रात्मक रूप प्रदत्त कर इस वर्ग का बहिष्कार किया जो सरकारी शक्ति की बागडोर अपने हाथों में लिये रहने का अभ्यस्त था। इसके अतिरिक्त यह लोग इसलिये भी जैक्सन के प्रति विद्वेष की भावना से युक्त थे क्योंकि इनकी दृष्टि में जैक्सन की लोकतांत्रिक नीति स्वयं में एक आन्दोलन थी। जिसके कारण इन मध्यमवर्गीय तथा लघु अभिजातवर्गीय तत्वों की पद एवं शक्ति का हास हो रहा था।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अमरीकी ऐतिहासिक अध्ययन में अत्याधिक परिवर्तनों का आना प्रारम्भ हुआ। इन इतिहासकारों ने लोकतांत्रिक एवं उदारवादी दृष्टि से अमरीकी इतिहास में घटित घटनाओं का अध्ययन किया। इनके अध्ययन के कारण इन इतिहासकारों को प्रगतिवादी मतावलम्बी समझा गया और इस प्रकार इन लेखकों ने जैक्सन के उग्रवादी पुनर्मूल्यांकन की आधारशिला रखी। प्रगतिवादी इतिहासकारों का जैक्सन की ओर परिवर्तन सर्वप्रथम फ्रेडरिक टर्नर के द्वारा प्रतिभूत हुआ। टर्नर के अनुसार जैक्सन का उत्थान अमरीकी लोकतांत्रिक उद्देश्यों की ओर सफल चरण था और जनसाधारण का राष्ट्रपति को समर्थन इस बात का द्योतक था कि 'नव लोकतन्त्र' जिसमें सम्पत्ति से पूर्व व्यक्ति को प्राथमिकता तथा जन सहयोगिता को श्रेष्ठ समझा जाता था, अमरीकी समाज का प्रमुख अंग था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक प्रगतिशील इतिहासकारों ने जैक्सन की लोकतांत्रिक नीतियों का समर्थन किया। अनेकों लेख पुस्तिकाओं तथा पुस्तकों में विद्वानों ने विकसित राजनीतिक लोकतन्त्र को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त 'इनामी पद्धति' को समर्थन देते हुये यह कहा गया कि इस पद्धति ने समय से चले आ रहे अभिजातीय तंत्रवाद को समाप्त कर लोकतांत्रिक विकल्प को स्थान दिया। उपरोक्त लेखकों का मत था कि 'इनामी पद्धति' लोकतंत्र का तर्कसंगत निष्कर्ष था।

प्रगतिवादी लेखन कार्य का चर्मोत्कर्ष आर्थर श्लेजिंगर की पुस्तक 'दि एज आफ जैक्सन' के प्रकाशन के साथ हुआ। (श्लेजिंगर) श्लेजिंगर ने 'जैक्सन के लोकतंत्र' की व्याख्या करते हुये इस तथ्य को स्पष्ट किया कि जैक्सन ने अपनी लोकतांत्रिक नीतियों में अमरीका को एक नवीन युग में प्रविष्ट कराया क्योंकि श्लेजिंगर के अनुसार अब तक अमरीका में प्रान्तीयता का युग था परन्तु जैक्सन

के साथ वर्ग समस्या ने जन्म लिया। जैक्सन को समर्थन प्रदान करने वाला, श्लेजिगर के अनुसार श्रमिक, कृषक तथा अपूँजीवादी समुदाय था। इसके अतिरिक्त जैक्सन युग उदारवादी और रूढ़िवादी अमरीकी समाज का एक चरण था जिसने अमरीका की सदैव से चली आ रही उस नीति का समर्थन किया कि राज्य नियंत्रण की प्रतियोगिता में सक्षम, सुयोग्य एवं कार्यक्षम व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी। इस पद्धति पर आधारित जैफरसन एवं जैक्सन ने अमरीकी उदारवादी विचार धारा को जीवित रखा। श्लेजिगर ने जैक्सन की बैंक की नीति को उदारवादी सुधारकपद्धति के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की।

श्लेजिगर ने जैक्सन के लोकतंत्र की जो व्याख्या दी, वह बहुत समय तक निर्विवाद नहीं रह सकी। सामान्य रूप से श्लेजिगर के आलोचक दो मतों में विभक्त थे। 1- उद्यमशील लेखकों का मत, 2- नवरूढ़िवादी लेखकों का मत। उद्यमशील लेखकों में ब्रे हैमण्ड ने जैक्सन की आलोचना करते हुये कहा कि जैक्सन अमरीका की प्रगतिशील लोकतांत्रिक नीति का प्रतीक माना जाता है। परन्तु जैक्सन और उसके मध्यवर्गीय उद्यमशील अनुयायियों ने अहस्तक्षेप की नीति अपने संकीर्ण ध्येय की प्राप्ति हेतु अपनाई। इसके अतिरिक्त हैमण्ड इस तथ्य को मान्यता देने के पक्ष में नहीं था कि जैक्सन जनता का प्रतिनिधित्व करता था। इसके साथ ही उद्यमशील लेखकों में रिचर्डहाफस्टाटर तथा जोजफ जार्फमैन ने हैमण्ड के विचारों की पुष्टि की। इन्होंने अपने लेखन में जैक्सन के आन्दोलन को उदारवादी, उदारचित्त, पूँजीवाद के विस्तार की शृंखला माना। इनके विचार में विशेषाधिकार से घृणा तथा अहस्तक्षेप सिद्धान्त के प्रभाव ने जैक्सन के लोकतंत्र में असंतोषजनक सामंजस्य उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त नवरूढ़िवादी इतिहासकारों ने वर्गीय विश्लेषण के सिद्धान्त को जैक्सन के लोकतंत्र से प्रथम रखा क्योंकि उनके विचार में अमरीकी समाज स्वयं जाँन लाँक के मध्यवर्गीय उदारवाद से प्रभावित था। इन नवरूढ़िवादी इतिहासकारों में कुछ विद्वानों ने जैक्सन के लोकतंत्र का श्रोत तथा विकास अध्ययन मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। इन मनो-वैज्ञानिकी मत के इतिहासकारों के अनुसार जैक्सन मतानुयायियों के सुधार प्रयत्न किसी विशेष सिद्धांत के द्वारा उत्पन्न नहीं था वरन् समाज में अपनी स्थिति को यथापूर्व स्थान प्राप्त करवाने की चिन्ता में जैक्सनवादियों से सुधार योजना कार्यान्वित करवाई। अर्थात् जैक्सन के सुधार स्वयं की सामाजिक असुरक्षा के प्रति रोग निवारक थी। इसी मत के एक अन्य लेखक मार्विन मायर ने मनोवैज्ञानिकी विश्लेषण करते हुए इस विचार को प्रकट किया कि जैक्सन कृषक गणतंत्र की विशिष्टताओं को आधुनिक पूँजीवाद के

उत्सर्ग के बिना बनाये रखने का इच्छुक था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्ग के इतिहासकार जैक्सन के आन्दोलन को संगठित नहीं मानते थे क्योंकि जैक्सन युग को इन्होंने स्तर और स्थिति का संघर्ष माना। इन नव रूढ़िवादी इतिहासकारों ने अपनी लेख पुष्टि में व्यवहारिक विज्ञान तथा सांख्यिकीय आधार को प्रमुखता दी।

इनसे पृथक ली वेन्सन के विचार में जैक्सन का समय 'समतावादी युग' था क्योंकि जैक्सन के कार्य लोकतांत्रिक सँचे के उपयुक्त नहीं थे। उपरोक्त सभी विचारकों ने अपने-अपने अध्ययन से जैक्सन के कार्यों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है और प्रत्येक ने कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ दिये हैं जिनका उत्तर समयानुकूल इतिहासकार एवं बौद्धिकवेत्ता देते रहेंगे।



संयुक्त राज्यवाद

अध्याय 5

देशिक संघर्ष

दास प्रथा

क्रांति के समय से उत्तरी प्रान्त डेलावेयर में दास प्रथा का ह्रास हो रहा था परन्तु दास प्रथा की समाप्ति का शनैः शनैः कोई प्रशासकीय उपचार निकट भविष्य में प्रतीत नहीं होता था। 1790 तक संयुक्त राज्य में लगभग साठ लाख बंधक दास थे। इसमें से अधिकांश दक्षिण अमेरिका में थे क्योंकि दक्षिणी अमरीका दास प्रथा का चिरकालीन परिपालक था। यद्यपि दक्षिणी क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों और समाज सुधारकों ने इस दास प्रथा को समाप्त करने की चेष्टा की। दासों की समस्या का प्रश्न उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा दक्षिण में अधिक जटिल होने के कारण टामस (थामस) जैफरसन आदिके कार्य प्रयोगात्मक रूप से सफल न हो सके। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि स्वतंत्र किये गये दासों के प्रति किस प्रकार की नीति निर्धारित की जाय। इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र की उदासीनता एवं कपास उद्योग ने भी दास प्रथा उन्मूलन में अवरोध उत्पन्न किया। उत्तर दक्षिण की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं लघु उद्योगीकरण ने सदैव स्वार्थ निहित परिधि के अन्तर्गत रहकर दास मुक्ति के मूल प्रश्न को प्राथमिकता प्रदान करने में संकोच किया।

कपास का साम्राज्य

यद्यपि पश्चिम में प्रजातांत्रिक शक्तियों का विकास हो रहा था, परन्तु दक्षिणी अमरीका के मूल्यों में परिवर्तन की दिशा ठीक उसके विपरीत थी। यह परिवर्तन दक्षिणी राज्यों में कपास की उपज में वृद्धि के कारण हो रहा था। कपास की उपज के साथ साथ दासों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही थी। 1815 के मध्य दक्षिणी राज्यों में कपास का साम्राज्य स्थापित था

जिसका आधार दास प्रथा थी। 1793 तक कपास की उपज काफी कम थी परन्तु शनैः शनैः कपास में बढ़ती रुचि के कारण यही उपज 1830 तक द्विगुणित हो गई। कपास उत्पन्न करने वाले दक्षिणी कैरोलीना एवं जार्जिया से लुइसियाना (लुइजियाना) के लाल नदी एवं टैक्सास तक फैलते गये। इस प्रकार कपास का साम्राज्य उपजाऊ जमीन तक वृद्धि को प्राप्त करता गया था। इसका उपयोग भी अनेकों माध्यमों से होने लगा। 1793 में कपास के बीज को साफकर कपास निकालने के लिये मशीन का आविष्कार किया गया और इस विधि के द्वारा कपास की ओटाई सरल हो गई तथा लाभ की प्रतिशतता एवं सम्भावनाएँ बढ़ गई। इसके अतिरिक्त तम्बाकू, एवं चीनी की कृषि में तुलनात्मक रूप से कम लाभ होने लगा। फलस्वरूप कपास का साम्राज्य धीरे-धीरे वृहदतर होता गया।

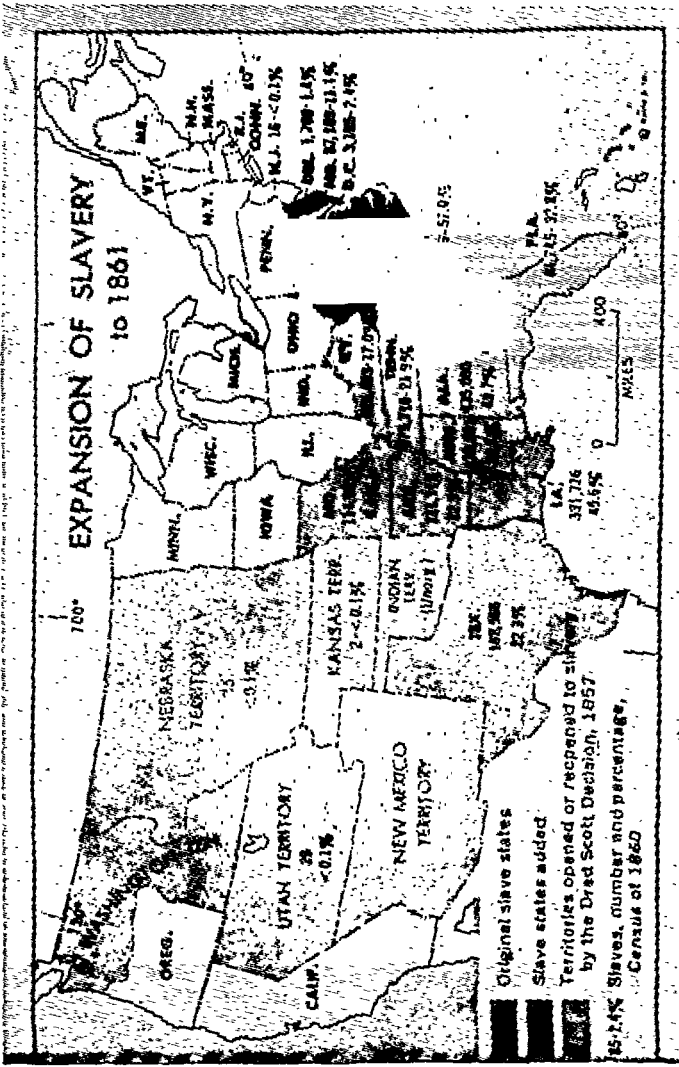
इसके साथ ही साथ ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग के विकास से बाजार की सुरक्षा भी बढ़ती गई। जैसे जैसे कपास की खेती में विकास होता गया दास प्रथा के उन्मूलन की सम्भावनाएँ न्यून होती गई। चावल तथा चीनी की खेती में विभिन्न प्रकार के कार्यों की आवश्यकता पड़ती थी जबकि कपास की खेती असीर तथा गरीब दोनों प्रकार के किसानों के लिये लाभदायक थी, क्योंकि हजारों एकड़ भूमि की खेती कुछ सौ गुलामों (दासों) द्वारा, तथा छोटी खेती दी या तीन गुलामों (दासों) द्वारा की जा सकती थी। यही कारण था कि कपास की खेती को प्रमुखता प्रदान की गई।

कपास साम्राज्य का दक्षिणी कैरोलीना एवं जार्जिया से मध्य टेनेसी तक विस्तार होता गया। 1810 तक अस्सी लाख पौण्ड मूल्य की खेती होने लगी थी। 1812 के युद्धोपरान्त अलाबामा, मिसीसीपी तथा लुईजियाना तक क्षेत्र विस्तार हुआ। कपास का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम तक 1000 मील एवं उत्तर से दक्षिण तक 200 से 700 मील तक विस्तृत हो गया। 1812 के युद्ध से गृहयुद्ध तक प्रत्येक दशा में इसकी उपज द्विगुणित होती गई।

दास प्रथा का पुर्नजन्म

1793 के पश्चात् कपास के साम्राज्य में वृद्धि के साथ-साथ दास प्रथा का पुर्नजन्म होने लगा। डा० एल्बर्ट श्विटजर के अनुसार नीग्रो जाति दासों के लिये सर्वथा अनुकूल थी। इनमें परिश्रम की अपूर्व क्षमता थी अतः परिश्रमी होने के कारण कोई भी अन्य जाति का दास इतना लाभदायक नहीं सिद्ध हो सकता था। दासों की पूर्ति के लिये स्थानीय दासों पर ही निर्भर

EXPANSION OF SLAVERY to 1861



1861 तक दास प्रथा का विस्तार

रहना पड़ता था क्योंकि 1808 से दासों का आयात अवैधानिक हो गया था। यह पूर्ति उत्तरी राज्यों द्वारा दक्षिणी राज्यों को दासों के विक्रय से प्रारम्भ होने लगी। परन्तु यह विक्री भी कपास के वृहत साम्राज्य के लिये पूर्ण नहीं हो पाती थी अतः दासों के मूल्य में शनै-शनैः वृद्धि होने लगी। कभी-कभी इनके मूल्य 1500 से 2000 डालर तक हो जाते थे। फिर भी इनकी संख्या में 1790 में आठ लाख से 1860 में चार लाख हो गयी। दासों के स्तर एवं स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार की सामान्य धारणा निर्धारित नहीं की जा सकती थी। क्योंकि जहाँ उत्तरी अमरीका एवं यूरोपीय लोग नीग्रो जाति को नापसन्द करते थे वहीं दक्षिणी अमरीका के लोग अपने दासों के साथ पुत्रवत्-व्यवहार करते थे। इसके पीछे सम्भवतया यह भी कारण हो सकता था कि उनकी समस्त खेती इन दासों पर निर्भर थी एवं उनके स्वयं के स्तर का आंकलन भी दासों की संख्या से किया जाता था। ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं था कि दासों के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता। फिर भी यह माना जाता था कि नीग्रो दास थे एवं उनके मालिक उनके साथ मनमाना व्यवहार कर सकते थे। इसके विपरीत दासों की मनोवृत्ति के संबंध में भी कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार के संगठित प्रतिरोध का प्रदर्शन नहीं किया। इसके लिये यह भी कारण हो सकता था कि उनको इस प्रकार का कोई प्रतिरोध करने का सुअवसर न मिला हो।

दासों के प्रशासन के लिये “काला अधिनियम” की व्यवस्था की गयी। इसके अनुसार गुलामों के स्तर तथा उनके दुरुव्यवहार पर अंकुश लगाया जा सकता था। यह अधिनियम विभिन्न राज्यों में विभिन्नता लिये हुये था। परन्तु 1822 के एक कटु अनुभव के पश्चात् 1830 तक यह अधिनियम सामान्यतः प्रत्येक राज्य में कठोर कर दिया गया। 1822 में डेनमार्क वेजी नामक एक नीग्रो ने चार्ल्सटन में एक संगठित विद्रोह करने की चेष्टा की परन्तु उसके प्रयत्न के पूर्व ही उसको दबा दिया गया। 1831 में पुनः वर्जिनिया में नेटटर्नर ने एक विद्रोह प्रारम्भ कर दिया जिसको दबाने के पूर्व ही उन्होंने साठ गोरों को मार दिया। इस अनुभव के पश्चात् दामों द्वारा विद्रोह की सम्भावनाएँ पूर्णतया समाप्त हो गईं क्योंकि अब “काला अधिनियम” अपेक्षाकृत अधिक सचेत कर दिया गया।

1820 के पश्चात् दक्षिणी मनोवृत्ति में दासता के प्रति परिवर्तन दृष्टि-गोचर होने लगा। प्रथम बार राजनैतिक एवं बौद्धिक वर्ग ने यह घोषित करना प्रारम्भ कर दिया कि दासता कोई बुराई नहीं है अपितु यह कि दासता एक अच्छी संस्था है। 1822 में दासता के पक्ष में पत्र प्रकाशित किये गये। सम्भवतया इस दासता पक्षीय वर्ग का सर्वप्रमुख अधिवक्ता टामस आर० ड्यू था।

गृह युद्ध के लगभग 30 वर्षों पूर्व तक एक वृहद् बौद्धिक वर्ग दासता के पक्ष में वक्तव्य देता रहा।

इसी नवीन मनोवृत्ति के कारण दासता विरोधी वर्ग की आवाज बुलन्द हो सकी। यद्यपि इनके विचार में दासता एक अमानवीय संस्था थी, परन्तु इसका निराकरण निकट भविष्य में सम्भव नहीं था। इसी के साथ-साथ दासता पक्षीय वर्ग के असहनीय मनोवृत्ति के कारण दासता विरोधी वर्ग को प्रयाप्त समर्थन न प्राप्त हो सका। इनके पास एक ही विकल्प शेष था कि ये दक्षिणी क्षेत्र से पलायन कर जायें। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिणी क्षेत्र से उदारवादी वर्ग का पूर्णतया निष्कासन हो गया।

उत्तरी अमरीका तथा विश्व के अन्य भागों में उदारवादी मान्यताओं के जन्म के कारण दक्षिणी अमरीका अपने आपको एकाकी समझने लगे। फ्रांस में क्रान्ति के समय तथा ब्रिटिश साम्राज्य में 1833 में एवं लैटिन अमरीका में 1860 में दासता समाप्त कर दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी लोग दासता के पक्ष में धर्म, विज्ञान, इतिहास एवं अर्थशास्त्र से वक्तव्य एवं उदाहरण प्रस्तुत करने लगे।

दासता के पक्ष में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण तर्क यह था कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी वर्ग को शारीरिक श्रम करना ही होगा। सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के लिये एक ऐसे वर्ग की भी आवश्यकता होगी जो श्रम विमुख न हो। ऐसी स्थिति में अमरीका के समाज को उत्तरी श्रमिक आश्रित समाज अथवा दक्षिणी दास आधारित समाज में से किसी एक को प्राथमिकता देनी होगी। दोनों में से दासता, इनके तर्कानुसार अधिक सुरक्षित एवं स्थायी संस्था थी। क्योंकि दास प्रथा में श्रमिक संगठनों, हड़तालों तथा जातिवादी वर्ग का भय नहीं था। इसके साथ ही साथ उत्तरी उत्पादकों के विपरीत दक्षिणी कृषक अपने दासों को अधिक सुविधा प्रदान करते थे यद्यपि श्रमिकों को इनके अनुसार वह सुविधाएँ नहीं प्राप्त थी। इस मनोवृत्तियों, तर्कों तथा मान्यताओं के आधार पर दक्षिणी अमरीकियों ने दास प्रथा को समस्त विश्व में व्याप्त हो जाने का तर्क प्रस्तुत किया।

आर्थिक समस्याएँ

इन समस्त लाभों के पश्चात् भी दक्षिणी अर्थ व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। दासता के कारण दक्षिणी आर्थिक व्यवस्था उतनी प्रगतिशील नहीं हो पायी जितनी कि उत्तरी। केवल कपास पर आधारित होने के कारण दक्षिण

में अन्य व्यवसायों को प्रोत्साहन न प्राप्त हो सका। दासता के परिणाम स्वरूप अप्रवास पर भी अपरोक्ष रूप से प्रतिरोध लग गया क्योंकि यूरोप के प्रवासी उत्तरी अमरीका में अधिक लाभ की सम्भावनायें देखते थे। 1860 में केवल 13.4% विदेशी अप्रवासी दक्षिणी राज्यों में निवास करते थे। इसके साथ ही साथ दक्षिणी क्षेत्रों की मनोवृत्तियों पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। वहाँ के समाज में दासों की संख्या एवं कपास की खेती के आधार पर ही निर्भर करती थी। अतएव युवा वर्ग में भी अधिक कपास पैदा करने एवं अधिक दास रखने की मनोवृत्ति ही पनप सकी। इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी अमरीकी राज्यों में अन्य व्यवसायों, मजदूर वर्गों, व्यापार आदि को प्रोत्साहन न प्राप्त हो सका तथा दक्षिणी सामाजिक संरचना में प्रमुखतया ग्रामीण एवं कृषक ही हो पाये।

कृषक समाज आधारभूत रूप में औद्योगिक समाज पर निर्भर करता है ब्रिटिश उत्पादकों द्वारा अमरीकी कपास के लिये भूगतान किये गये सम्पूर्ण धन का केवल आधा भाग ही दक्षिणी खेतिहरों को प्राप्त होता था शेष आधा भाग उत्तरी राज्य के व्यापारिक संस्थानों को मिलता था। ब्रिटेन को जाने वाला कपास उत्तरी अमरीका के पोर्तों पर से ब्रिटेन जाता था। इसी प्रकार ब्रिटेन से तैयार माल उत्तरी क्षेत्रों से होता हुआ दक्षिण की ओर आता था। परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों को न तो उनकी मेहनत की पूर्ण कीमत प्राप्त होती थी और न ही उन्हें उत्तरी राज्यों की अपेक्षा कम मूल्य वाली वस्तुएँ प्राप्त होती थी उनको उत्पादन हेतु आवश्यक ऋण भी उत्तरी राज्यों के बैंकों से लेना पड़ता था क्योंकि दक्षिण में बैंकों की संख्या न्यून थी। परिणामस्वरूप 1860 तक दक्षिणी राज्यों पर उत्तरी राज्यों की एक वृहद् राशि ऋण हो गयी।

1820 के पश्चात् दक्षिण के नेताओं ने निरन्तर दक्षिण को उत्तरी राज्यों की प्रभुता से मुक्त कराने के लिये तर्क, वक्तव्य एवं भाषण दिये परन्तु इसका कोई लाभप्रद परिणाम सम्भव न हो सका। दक्षिणी राज्य ब्रिटेन से प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके अपने उद्योगों का विकास कर सकते थे। 1860 तक समस्त अमरीकी उद्योगों का केवल 10% भाग दक्षिण में था। इसके पश्चात् दक्षिण के औद्योगिक तथा आर्थिक प्रगति में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों का अधिक हाथ था। दक्षिण में अन्य प्राकृतिक सम्पदा भी उपलब्ध थी परन्तु वह तब तक पूंजी निर्मित करने में असमर्थ थी जब तक कि कपास का साम्राज्य स्थापित था।

दक्षिणी समाज

1860 के पूर्व दक्षिणी अमरीका के श्वेतों का दासता प्रथा से सीधा सम्बंध काफी कम था। दास रखने की प्रथा छोटे कृषकों के यहाँ अधिक थी। प्रत्येक परिवार लगभग पाँच दास रखता था जब कि बड़े किसान समस्त दासों का केवल 1/4 भाग ही रखते थे। 1850 में लगभग तीन लाख अड़तालिस हजार दास रखने वाले परिवार थे। इनमें से आधे पाँच से कम तथा तीन चौथाई परिवार दस के लगभग दास रखते थे। केवल तिरान्वे हजार परिवारों के पास दस से अधिक एवं 8000 परिवारों के पास पचास से अधिक दास थे। अतएव दक्षिण का वास्तविक प्रतिनिधि अल्पमतीय धनी श्वेत वर्ग नहीं था अपितु यह वर्ग बहुमतीय छोटे कृषकों का वर्ग था।

1832 में वर्जीनिया विधान मंडल में दास प्रथा के उन्मूलन के लिये प्रस्ताव रखा गया परन्तु यह बहुत थोड़े मतों से पराजित हुआ, क्योंकि वर्जीनिया में दासता की प्रथा का अभाव था। इस प्रस्ताव में नीग्रों लोगों को अफ्रीका प्रेषित करने का प्राविधान भी रखा गया था। तत्पश्चात् नार्थ कैरोलिना के हिन्टन आर० हेल्पर ने 'दक्षिण का संकट' नामक प्रकाशन में यह लिखा कि किस प्रकार दासता के कारण दक्षिण का आर्थिक एवं सांस्कृतिक ह्रास हो रहा था। इस प्रकाशन का दक्षिण के खेतिहरों ने अत्यधिक विरोध किया

समस्त कपास के साम्राज्य में छोटे-छोटे कृषकों का वर्ग एक मध्यम वर्ग का निर्माण करता था। इस वर्ग की मान्यता दासता के विपरीत थी। यद्यपि ये धनी किसानों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे फिर भी रंगभेद के कारण उच्चता की भावना इनके अन्दर भी थी जिसको ये समाप्त नहीं करना चाहते थे। इनके सम्मुख धनी किसानों का उदाहरण भी था जो गरीबी के स्तर से धीरे-धीरे दासों की सहायता से अमीर हो गये थे। इस भावना के होते हुये भी वर्ग संघर्ष तो दक्षिण में सम्भव न हो सका परन्तु धीरे-धीरे जब प्रगति की सम्भावनाएँ भूमि के कम उपलब्ध होने एवं दासों के महँगे हो जाने से कम हो गयी तो उन्होंने अधिक दासों की पूर्ति, अन्य क्षेत्रों पर निवास, मूल्यों में कमी तथा कपास के व्यापार में लाभ के लिए आवाज उठाना प्रारम्भ कर दिया। यह वर्ग उन लोगों का था जो तुलनात्मक रूप में गरीब थे तथा जिनके पास दासों की संख्या या तो बिल्कुल कम थी या एकदम नहीं। धनी किसानों का वर्ग दक्षिणी अमरीका में अल्पमत में था। इनके रहन सहन का स्तर अत्यन्त ऊँचा था एवं इनके पास दासों की अत्यधिक संख्या उपलब्ध थी। वहाँ समस्त प्रशासन, न्याय तथा आर्थिक एकाधिकार इसी वर्ग के पास सुरक्षित था। न्याय

व्यवस्था "स्थानीय न्यायालयों" में केन्द्रित थी जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति शासन अथवा राज्यपाल द्वारा आजीवन के लिये की जाती थी। इन न्यायाधीशों का चयन सदैव उच्च वर्ग से ही होता था। तदपश्चात् दक्षिण में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के आगमन के कारण यह नियुक्ति चुनाव के आधार पर होने लगी, फिर भी अभी पाँच राज्यों में स्थानीय न्यायालयों की व्यवस्था स्थिर थी। इनके अन्दर अभिजात-वर्गीय समस्त भावनाएँ उपस्थित थी तथा इनका परिवार भी अभिजात वर्गीय शैली में जीवन व्यतीत करता था।

उत्तरी राज्यों की अपेक्षा दक्षिणी राज्यों में सांस्कृतिक गतिविधियाँ अत्यन्त न्यून थीं। कृषि, राजनीति तथा वाद विवाद के अतिरिक्त इनके पास अन्य कोई साधन नहीं था। शिक्षा का अभाव था, एवं शिक्षित स्नातकों को अवैतनिक शिक्षा में अधिक रुचि थी। विश्व के नवीन दर्शनों, सिद्धांतों तथा मूल्यों के प्रति इनमें विद्वेष की भावना बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि ये समस्त दर्शन, मूल्य एवं सिद्धांत वैज्ञानिकता तथा मानवतावाद पर आधारित थे जो वर्ग समुदाय के स्वार्थों के विपरीत थे। इन सिद्धांतों में विश्वास प्रकट करने का अर्थ कपास के साम्राज्य का अवमूल्यन तथा दासता की प्रथा की समाप्ति करना था। समस्त वर्ग इसके पक्ष में नहीं था। इन नवीन दर्शनों में अनावस्था के कारण नवीन अधिनियमों में भी इनका विश्वास नहीं रहा जो अपेक्षाकृत अधिक मानवीय थे एवं शांति तथा अहिंसा में विश्वास रखते थे। तदनुसार इन समुदायों के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानवीयता के विरुद्ध विद्रोह ने जन्म लिया जिसने हिंसक प्रवृत्तियों तथा हिंसक संस्कृति को जन्म दिया। इसके विपरीत उत्तरी राज्य अपेक्षाकृत अधिक वैतनिक, वैधानिक, मानवीय एवं उद्योगी होते जा रहे थे। इन समस्त विरोधी प्रतिक्रियाओं से उत्तरी राज्यों के विपरीत दक्षिणी राज्यों में नगरों का विकास भी नहीं हो पा रहा था। न्यू ऑरलीज के अतिरिक्त दक्षिण में किसी भी नगर की जनसंख्या पचास हजार से अधिक नहीं थी।

राजनीति

उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों की इन विपरीत मान्यताओं, मूल्यों तथा आदर्शों के कारण ही 1787 में संघीय तथा गणतंत्रीय वर्गों में मतभेद उत्पन्न हुआ 19 वीं सदी के आर्थिक मूल्यों ने भी इस मतभेद को वृद्धि प्रदान की। 1820 एवं 1830 तक संघीय राजनीति में ये मतभेद विशेषरूप से प्रभावशील थे, परन्तु 1848 के पश्चात् इनके ऊपर ही राजनीतिक दिशा निर्धारित होने लगी।

1820 तक यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिणी राज्य प्रमुख रूप से कृषक रहेगे एवं संघीय संविधान द्वारा आर्थिक प्रगति में लाभ केवल उत्तर को ही प्राप्त हो सकेगा। उत्तरी राज्य अधिक "आयातकर" की माँग कर रहे थे क्योंकि उन्हें विदेशी व्यापार से प्रतियोगिता करनी थी जबकि दक्षिणी राज्य करों में न्यूनता की माँग कर रहे थे। दक्षिणी राज्य संघ द्वारा मछली के व्यापार एवं जहाजरानी (पोत परिवहन) की सुरक्षा का विरोध भी कर रहे थे। दक्षिण में नहरों तथा सड़कों का निर्माण भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि संघ का प्रमुख कोष उत्तर के विकास पर ही खर्च होता था। अतएव उन्होंने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि उनके द्वारा लागत का हिस्सा अधिक होने के पश्चात् भी उन्हें समुचित लाभ नहीं प्राप्त होता। अतः संघ उत्तरी व्यापार द्वारा दक्षिणी कृषिकों का शोषण का कार्य करता है।

1820 के पश्चात् दक्षिणी कैरोलीना में लाभ की मात्रा कम होने लगी, क्योंकि भूमि का उपजाऊपन कम हो गया था एवं पश्चिम की तरफ अप्रवास बढ़ गया था। अतः उन्होंने संघीय शासन से सहायता की माँग प्रारम्भ की। उस समय कैलहून राज्य का प्रमुख राजनैतिक व्यक्ति था। धीरे-धीरे वह दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने लगा। उसके विचार में उत्तर दक्षिण के सिद्धांतों में आधार भूत रूप में अन्तर था। प्रतिनिधियों की सभा में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम ही होने वाला था। इस प्रतिनिधित्व के ह्रास के भय को रोकना, कैलहून के अनुसार, आवश्यक था। वह संघीय शासन के अधिकारों को कम करने के लिये प्रयत्नशील था। 1820 में उसने "राज्यों को सर्वोच्चता" का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कोई भी राज्य केन्द्रीय संघीय शासन के किसी भी असंवैधानिक अधिनियम को निरस्त कर सकती थी। इसके पश्चात् उसने ऐसे सिद्धांतों को स्थापित करने का सुझाव दिया जिसके अनुसार संघीय अधिनियमों के लिये दोनों भागों का समर्थन आवश्यक था। यदि उसके सुझावों को मान्यता मिल जाती तो सम्भवतः संघीय शासन की शक्तियाँ अत्यन्त निर्बल हो जाती।

कृषि के विकास तथा संघीय शक्तियों में न्यूनता के सिद्धांतों के आधार पर कैलहून को जैफरसन तथा जॉन टेलर का उत्तर-त्रिकारी कहा जा सकता है। परन्तु उसमें जैफरसन का उदारवाद निहित नहीं था। दासता की प्रथा को मान्यता प्रदान करते हुये उन्होंने "स्वतंत्रता की घोषणा" में प्रतिपादित मानवाधिकारों तथा समानता के सिद्धांतों का विरोध किया। संघीय शक्तियों का विरोध वह केवल दक्षिण के प्रति दासता अवरोध नीति के लिये करता था परन्तु यह विरोध एक प्रकार से देशद्रोह था। धीरे-धीरे 1830 के पश्चात् यह



हैनरी क्ले (1777-1852)

विरोध एक अन्तर्राज्यीय संघर्ष में परिवर्तित होता गया ।

1850 का समझौता

हेनरी क्ले ने 29 जनवरी 1850 को उत्तर-दक्षिण के मतभेदों में समझौते हेतु निम्न लिखित प्रस्ताव रखे ।

1. केलिफोर्निया का संघीय प्रवेश
2. मैक्सिको से प्राप्त क्षेत्र में संतुलित शासन
3. टेक्सास एवं न्यू मैक्सिको की सीमाओं की व्यवस्था का समाधान करना ।
4. कोलम्बिया में दास-प्रथा के प्रति निरहस्तक्षेप की नीति का पालन करना ।
5. कोलम्बिया में दास व्यापार का निषेध ।
6. पलायक दासों के प्रति प्रभावक कानून की स्थापना ।

इसके साथ ही क्ले ने घोषणा की कि अन्तर-प्रांतीय दास व्यापार में कांग्रेस को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था । इस प्रकार गम्भीर परिस्थित में हेनरी क्ले की बुद्धिमत्ता ने इस तत्कालिक संघर्षमय संकट को टाल दिया । 5 फरवरी, 1850 को क्ले ने यह योजना रखी कि केलिफोर्निया को स्वतंत्र राज्य की भाँति सम्मिलित किया जाय और न्यू मैक्सिको और यूटा को ऐसे प्रदेश बनने दिया जाय जहाँ दासता विरोधी और समर्थक पर नियंत्रण न हो । पलायक दासों को उनके स्वामियों को लौटाने के लिये एक अधिक प्रभावशाली सशक्त तंत्र की स्थापना की जाये कोलम्बिया में दास व्यापार को निषेध कर दिया जाय एवं टेक्सास प्रदेश की कुछ भूमि न्यू मैक्सिको में सम्मिलित होने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति की जाय । दोनों ही पक्षों को इसमें थोड़ा बहुत त्याग करना था ।

इस योजना के अधिकांश प्रस्तावों के परोक्ष में डगलस का मस्तिष्क था, परन्तु क्ले ने उन्हें नकारात्मक स्वरूप प्रदान किया और इस योजना में उसके समर्थन के बिना कुछ नहीं हो पाता । इन प्रस्तावों को सफल बनाने के लिये समस्त वर्गों में उसकी प्रतिष्ठा, उसके व्यवहार, उसकी निष्ठा और दक्षिण पर उसके प्रभाव तथा उसके व्यक्तित्व का उपयोग आवश्यक था ।

1850 के समझौते को स्वरूप प्रदान करने के लिये जो वाद-विवाद हुये, उसका अमरीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है । क्ले के भाषण के एक माह पश्चात् संसदीय पद्धति के महारथी कैलहून ने इसके प्रति विख्यात तर्क प्रस्तुत करते हुये घोषणा की कि एक संकटमय संघर्ष के परिहार हेतु दक्षिण के परिवाद का निवारण कराना आवश्यक है । क्ले की भाँति उनका भाषण समझौते

के प्रति विनय से परिपूर्ण नहीं होता था अपितु उनका कहना था कि निर्वल एवं अशक्त दल से समझौता करके एकता एवं संगठन का समन्वय नहीं किया जा सकता था लेकिन उत्तर और दक्षिण को आपस में संयुक्त करने वाली कड़ियाँ भी एक-एक कर टूट रही थी। यदि आन्दोलन इतना ही त्वरित रूप धारण किये रहा तो अन्त में इसके भयंकर परिणाम हो सकते थे और राज्यों को एकता स्थापित रखने हेतु युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहता। कैलहून इस भाषण को पढ़ते समय इतना भाव-विभोर हो गया था कि उसका भाषण उसके मित्र सीनेटर जेम्स मेसन के द्वारा पढ़ा गया।

यह सत्य है कि कैलहून का भाषण उत्तरी क्षेत्र को उन्नति की ओर यथार्थ रूप से इंगित कर रहा था परन्तु दक्षिण को पूर्णतया गलत निर्देशित कर रहा था। 1860 तक संघीय (फैडरल) सरकार में दक्षिणी प्रान्तों का प्रभाव अधिक था और यह दक्षिणी नेताओं की शिथिलता थी कि वह अपने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण नहीं बना सके।

सूर्जंड तथा चेज ने इस समझौते को अनुचित ठहराते हुये इसका तीव्र विरोध किया। परन्तु क्ले के प्रस्ताव का वक्टर ने शानदार समर्थन किया। सात मार्च को वक्टर ने एक भव्य भाषण में जो कि उसके जीवन का अन्तिम भाषण था, यह तर्क प्रस्तुत किया कि मैसाचुसेट्स वासी भी उत्तर वासियों की तरह इस समस्या पर विचार न कर एक अमरीकी की तरह एकता की दृष्टिकोण रखें। उसकी घोषणा ने शान्तिपूर्ण, पृथकवादी एवं दासता विरोधी न्यू इंग्लैण्ड के उग्रवादियों का क्रोध भड़का दिया। वास्तव में उसका सन्देश एक साहसपूर्ण कार्य था जो राष्ट्र के प्रति उसकी अन्तिम सेवा थी। इसके समर्थन के पश्चात् भी क्ले का मौलिक अधिनियम पारित न हो सका। तद्पश्चात् उसका सीनेटर डगलस ने पुनः लेखन किया तब कांग्रेस ने उसे पारित कर दिया। इसी समय 9 अक्टूबर 1850 को राष्ट्रपति जैकबी टेलर की मृत्यु हो गई। यदि वह राष्ट्रपति बनता तो संभवतः अपने विरोधवादी दल का प्रयोग करता, परन्तु उसके उत्तराधिकारी फिलीप फ्रैन्को ने समय नष्ट करने के बजाय प्रस्ताव पारित करने का प्रयत्न किया और इस तरह क्ले, वेक्टर और डगलस के उग्रवादी विचारों की विजय हुई।

इस संसदीय विरोध के अन्त में एक पूर्ण शान्तिपूर्ण समझौता हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि इस समझौते में प्रत्येक दल के अधिकारी पूर्णतः सन्तुष्ट थे कि वे अपने विचारों को अंतिम रूप में स्वीकार कर लेंगे। परन्तु अन्तिम क्षणों में दक्षिण के दल ने अन्तिम क्षणों में अचानक उठ खड़े और अपने विचारों को अंतिम रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

उल्लंघन करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने दासों को पलायन में सहायता करनी आरम्भ कर दी जिससे पलायक दासों की संख्या में वृद्धि होती गई। सागरीय तट के दास जहाजों से भाग निकले। कुछ ओहायो नदी की ओर भाग गये तथा कुछ एपलैशियन पर्वत श्रेणियों से होकर पेन्सिलवेनिया जा पहुँचे। 1850 में उत्तरी राज्यों में अप्रावासी बीस हजार पलायक दासों को फिर से पकड़ने के लिये एक कानून पारित किया गया लेकिन इनको पकड़ने पर उपद्रव होने लगे। 1852 में श्रीमती हैरियट वीचर स्टोव को "अंकल टाम्स केबिन" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें गुलामों के प्रति अन्याय और अत्याचार का वर्णन था। श्रीमती स्टोव ने बताया था कि अत्याचार को दासता से पृथक नहीं किया जा सकता और इन स्वतंत्र समाज और दास समाज में कभी भी संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। लाखों प्रतिर्या विक्रम वाली इस पुस्तक ने उत्तरी मत दाताओं की भावी पीढ़ी में एक परिवर्तन उत्पन्न कर दिया।

1854 में दास प्रथा का प्रश्न फिर तीव्रता से उठ खड़ा हुआ। दक्षिणी नेतागण मिसूरी समझौते को भंग कर समस्त ऊपरी मिसूरी घाटी को दास प्रथा के लिये प्राप्त कर लेना चाहते थे जिससे उत्तरी समाज में भयंकर प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई। मिसूरी नदी के नीचे की भूमि, जो नेब्रास्का तथा कैंसास राज्य की भूमि थी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी। इस भूभाग में होकर शिकागों से प्रशान्त तक रेल मार्ग भी बन सकता था।

मिसूरी समझौते की उत्तरी सीमा को शीघ्र ही समाप्त करने का इच्छुक शिकागोवासी स्टीफन ए० डगलस था जो इस प्रदेश के लिये गठित सीनेट समिति का सदस्य भी था। लेकिन उसका तीव्र विरोध किया गया। मिसूरी समझौते के अन्तर्गत यह सारा प्रदेश दासता के लिये निषिद्ध घोषित कर दिया गया था मिसूरी ने अपने पश्चिमी सीमा तट से सटे कैंसास भूभाग को स्वतंत्र प्रदेश घोषित करने का विरोध किया। नीग्रो गुलामों का इस स्वतंत्र प्रदेश से भाग जाना वायेंहाथ का खेल था। इसके अतिरिक्त मिसूरी प्रदेश के तीन स्वतंत्र पड़ोसी प्रदेश थे जहाँ पहले से ही तेज आन्दोलन जारी था जिसके दबाव से मिसूरी को भी स्वतंत्र (दास रहित) प्रदेश घोषित करना पड़ता। कुछ समय के लिये वाशिंगटन स्थिति मिसूरी नेताओं ने दक्षिण की मदद से कैंसास के स्वतंत्र होने के सभी प्रयत्नों को निष्फल कर दिया।

कैंसास नेब्रास्का विधेयक :

मार्च, 1854 में सीनेटर डगलस ने विरोधियों की उपेक्षा कर एक नया

प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसने सभी स्वतन्त्र राज्या के लोगों का रोप से भर दिया। इस योजना का अन्तिम स्वरूप यह था कि 1850 के समझौते की धाराओं के कारण मिसूरी समझौता कभी का नष्ट हो चुका था तथा अब उटा और न्यू मैक्सिको को दासता वाले अथवा दास रहित राज्य बनने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिल गई। यह विधेयक कैन्सास और नैब्रास्का को दो प्रदेशों का रूप प्रदान करने के उपबद्ध करता था जहाँ बसने वाले दासता प्रथा से स्वतन्त्र थे। यह इन प्रदेशवासियों को अधिकार देता था कि वे संघ राज्य में स्वतन्त्र या दास राज्य के अधिकार से प्रवेश करने का स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं।

डगलस का विश्वास था कि उत्तरी क्षेत्र शीघ्र ही उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैन्सास नैब्रास्का विधेयक पर तीव्र वाद विवाद उठा। स्वतन्त्र राज्यों के निवासियों ने उसकी निन्दा की। वॉशिंगटन से लेकर शिकागो तक उसकी अर्थियाँ जलाई गईं।

कैन्सास नैब्रास्का विधेयक वास्तव में दक्षिणवासियों को इस बात की रिश्वत के सदृश थी कि वे "नार्दन दास कान्टीनेन्टल" रेल मार्ग का निर्माण करने देंगे।

डगलस के इस दुर्भाग्यपूर्ण कदम का तात्कालिक प्रभाव भी व्यापक हुआ। विंग दल जो नव प्रदेशों में दासता के प्रश्न को प्रमुखता नहीं दे रहा था समाप्त हो गया और उसके स्थान पर एक नये शक्तिशाली राजनैतिक दल "रिपब्लिकन दल" का उदय हुआ। यह दल आदर्शवादी, प्रेरणादायक विधान व शक्तिशाली नव युवकों का आकर्षण केन्द्र एवं पूर्वी व्यवसायियों और पश्चिमी कृषकों में आरम्भ से ही लोकप्रिय और शक्तिशाली था। इनकी प्रमुख माँग थी कि सभी प्रदेशों को दास प्रथा से रहित रखा जाय। 1856 में इस दल ने राष्ट्राध्यक्ष पद के लिये जान सी० फ्रीमोन्ट को प्रत्याशी नियुक्त किया। फ्रीमोन्ट के नाम का प्रभाव अधिकांश उत्तरी राज्यों में व्याप्त होगया था। यदि वह अक्टूबर के चुनाव में पैनसिलवेनिया में विजित हो जाता तो शायद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जेम्स बुकानैन को भी अपना पद त्याग करना पड़ता।

इसके साथ ही "स्वतन्त्र भूमि" दल के सूअर्ड और अन्य नेताओं का प्रभाव अत्यन्त बढ़ गया था और इनके साथ साथ एक लम्बे क्रंद का इलेनॉय का वकील अब्राहम लिंकन, जिसने इन नये मामलों पर शानदार तर्क प्रस्तुत किये महान घटनाचक्र की ओर बढ़ रहा था।

16 अक्टूबर, 1854 को पेवारिया में अब्राहम लिंकन ने स्वतन्त्र भूमि के सिद्धान्तों में अपना सर्वश्रेष्ठ वक्तव्य दिया। "उसने कहा कि दासता जिस

स्थिति में हो वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता यदि मुझे सारे नैतिक अधिकार और शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाँय तो मैं यह नहीं जानना चाहूँगा कि मुझे दास प्रथा की इस स्थिति में उनका क्या उपयोग करना है।” उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस को मिसूरी समझौते को जो विभिन्न समुदायों के मध्य किया गया समझौता है, भंग करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसने कहा कि “जनता की राय” का सिद्धान्त मिथ्या है क्योंकि पश्चिम में दास प्रथा का प्रश्न केवल वहाँ के निवासियों का प्रश्न ही नहीं वरन् वह सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमरीका का प्रश्न है” यदि नैब्रास्का के इक्तीस आदमियों को इस कथन का अधिकार है कि 32 वाँ नागरिक दास नहीं रख सकता तो इक्तीस राज्यों को भी यह कहने का उतना ही नैतिक अधिकार है कि 32 वें राज्य में दास प्रथा नहीं रह सकती ?”

दक्षिण के दास स्वामियों तथा उत्तर के स्वतंत्र लोगों ने कैंसास में बसने के अप्रवास में गंभीर पारस्परिक संघर्षों को जन्म दिया जिनमें से अनेक ने नृशंस तथा छापामार युद्ध का रूप धारण कर लिया। दोनों समुदायों ने अपने पक्ष के बसने वालों को यह प्रदेश हस्तगत करने के लिये नवीन योजनायें बनाई। इनमें उत्तर के प्रवासी सहायक संघ अधिक सक्रिय और व्यस्त रहे। वे लोग पूर्ण तैयारी के साथ पहुँचे। ब्रुकलिन के लोकप्रिय पादरी हेनरी वार्ड बीचर ने एक सभा में, जहाँ शस्त्रों की माँग की जा रही थी, भाषण देते हुये कहा कि वहाँ की राइफल वाइविल की अपेक्षा अधिक नैतिकतापूर्ण साधन है और उनकी इस उक्ति ने वाद में राइफलों को “बीचर की वाइविल” की संज्ञा दे दी। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर वालों की स्थिति अच्छी हो गई। इसके दो कारण थे इनमें से प्रथम पड़ोसी प्रदेश होने से तथा मिसीसीपी घाटी में स्वतंत्र लोगों की अधिकता होने से एवं दूसरा कारण दूसरे प्रदेश में दासों को ले जाने में यह खतरा था कि कहीं वाद में वह स्वतंत्र न हो जाय। अतः दक्षिण ने ज्यादा उत्साह प्रदर्शित नहीं किया फिर भी सीमा प्रदेश के अनेक अनुपयुक्त लोग उत्तरी लोगों में आतंक की स्थिति का प्रादुर्भाव करने या अवैधमत प्रदान करने हेतु कैंसास में गये। यद्यपि दास रखने वाले दक्षिणी लोगों को वाशिंगटन में ब्रुकानैन प्रशासन का समर्थन प्राप्त था इसलिये वह संघर्ष चलता रहा और सम्पूर्ण राष्ट्र में इसके कारण संघर्ष की स्थिति का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार की त्रुटियों को करने वाले राष्ट्रपति ब्रुकानैन कांग्रेस के उन दोनों सदनों जहाँ लोकतांत्रिकों की अधिकता थी संविधान के अन्तर्गत कैंसास को ‘दास राज्य’ के समान स्वीकार करने के लिये तत्पर हुआ तो उत्तर में लोग इसके विरुद्ध हो गये। यहाँ तक कि उसका प्रभाव यह हुआ

कि राष्ट्रपति बुकानैन से डगलस के संबंध भी खराब हो गये।

इसी मध्य अधिकांश उत्तर वासियों ने जब यह देखा कि दक्षिण वालों ने 1850 का समझौता भंग कर दिया तो उन्होंने दास कानून का पालन करने से इंकार कर दिया क्योंकि यह कानून भी इसी समझौते के कारण था। कवि जान ग्रीन विटियर ने ये शब्द लिखे :—

“हमारी सीमाओं में दासों का पीछा न किया जा सकेगा, हमारी स्टेट में उन पर वेड़ियाँ न पड़ सकेगी, हमारी धरती पर कोई गुलाम न होगा।”

बहुत से राज्यों ने “व्यक्तिगत स्वाधीनता कानून” पास कर दिये जिससे भागे हुए दासों को पकड़ने सम्बंधी संघीय कानून निरर्थक हो गया। 1854 मई में जब वोस्टन में एक दास एन्थोनी वन्स पकड़ा गया तो मंत्रीगण उसकी मुक्ति हेतु गये। पूर्वी मैसाचुसेट्स में एक दास को पकड़ने के लिये पूरी पुलिस और सेना लगानी पड़ी।

युद्ध की ओर :—

इन परिस्थितियों में राष्ट्र युद्ध की ओर बढ़ रहा था। 1857 के आरम्भ में सर्वोच्च न्यायाधीश रोजर टैनी और उच्चतम न्यायालय के बहुमत ने ड्रेड स्काट अभियोग में घोषणा की कि कांग्रेस को प्रदेशों से दास प्रथा को दूर रखने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का ऐसा अर्थ करना बुरा था और इसके लिये प्रस्तुत किये गये तर्क भी औचित्यपूर्ण न थे। शीघ्र ही स्वतंत्र राज्यों के न्याय अधिवक्ताओं ने तथा नेताओं ने न्यायालय की तीव्र रूप से भर्त्सना की इससे पूर्व न्यायालय के निर्णय के प्रति ऐसा कटु वातावरण नहीं उत्पन्न हुआ था। साथ ही साथ इस बात की भी घोषणा की गई कि वे न्यायालय से शीघ्र ऐसे लुटिपूर्ण अर्थ को परिवर्तित करने के लिये बाध्य कर देंगे।

इसी मध्य अब्राहम लिंकन एवं स्टीफन डगलस में राजनैतिक रूप में दासता प्रथा को लेकर वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आरम्भ हो गईं। लिंकन-डगलस प्रतियोगिताओं ने दास प्रथा के पक्ष एवं विपक्ष पर प्रकाश डालकर जनता को इस संस्था के प्रति पुनः विचार करने पर प्रेरित किया। लिंकन ने दासता को नैतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से दोषपूर्ण संस्था की संज्ञा दी। डगलस ने नैतिकता के प्रश्न का विषयान्तर कर फ्रीकोर्ट सिद्धान्त को मान्यता दी। जिसके अनुसार दासता का प्रश्न प्रान्तीय संविधान के अन्तर्गत था। उपरोक्त सिद्धान्त ने दक्षिण में आलोचना का वातावरण उत्पन्न किया। 1860 में राष्ट्रपति के चुनाव में इन्हीं कारणों से दक्षिण ने समर्थन नहीं प्रदान किया था। 1860 में भी दास प्रथा तीन सौ वर्षों से अमरीका के किसी न

किसी उपनिवेश क्षेत्र में प्रचलित थी। स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात् भी दास प्रथा संयुक्त राष्ट्र में एक संस्था के रूप में बनी रही। उत्तरी क्षेत्र में दासता का प्रायः उद्योगीकरण के कारण समाप्त हो रहा था, परन्तु दक्षिण में कपास ओटन के उद्योग के कारण सबसे सस्ता एवं सुलभ आर्थिक लाभ दासों की उपलब्धि थी। इस प्रकार दक्षिण के वनस्पति उद्योगों के लिये दासता प्रथा का समाप्तिकरण सबसे तीव्र आर्थिक संकट था। दासता के प्रश्न का तीव्ररीकरण संघीय शासन में प्रान्तों के सम्मिलित होने के साथ हुआ। कैंसास के क्षेत्र के सृजन के पश्चात् उत्तर में इसे स्वतंत्र प्रदेश बनाने का अनुरोध किया, परन्तु दक्षिण ने इस क्षेत्र में दास प्रथा को प्रचलित रखने का परामर्श प्रेषित किया। उत्तरी क्षेत्र की जनता ने पलायक दासों को कनाडा (कैनेडा) की सीमा के पार भेजने में सहायता की और दक्षिणी क्षेत्रों में दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई। 16 अक्टूबर, 1856 को जान ब्राउन ने हारपर्स फेरी के संघीय शस्त्रागार पर अधिकार की चेष्टा की जिससे कि दासों को शस्त्र देकर दक्षिण में विद्रोह किया जा सके। जान ब्राउन के इस अर्ध प्रयास ने उसको राजद्रोह के कारण मृत्युदंड प्राप्त कराया, किंतु उसने गृह युद्ध के प्रारम्भ की नींव तो रख ही दी थी।

देशिक संघर्ष के विस्तार से परिचित होने से पूर्व यह ज्ञात होना आवश्यक है कि उत्तर और दक्षिण की तुलनात्मक स्थिति क्या थी? उत्तर में सेना को एकत्रित एवं संगठित करने के उद्देश्य से नागरिक सेना एवं अन्य रूप से भर्ती का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। जुलाई, 1861 में सेना में प्रवेश में आकर्षण उत्पन्न करने हेतु 100 डालर का अतिरिक्त वेतन देने का प्रयोजन किया गया। 1863 में वही धनराशि नवीन सैनिकों के लिये 302 डालर कर दी गई और अनुभवी सैनिकों के लिये 402 डालर की व्यवस्था की गई। यद्यपि इस प्रकार की सरकारी नीति में धनाकर्षण अवश्य था किंतु यह अधिक सफल न हो सकी। फलतः 1862 और 63 में ड्राफ्ट अधिनियमों के द्वारा अनिवार्य योजना को कार्यान्वित किया गया।

उत्तर में उद्योग एवं यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। उत्तर के उद्योगीकरण के कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। संचारण एवं रेलवे ने सैनिक और खाद्य सामग्री के यातायात में युद्ध में पर्याप्त रूप से योगदान दिया। इस प्रकार उत्तरी राज्यों ने सेना, यातायात, संचारण एवं खाद्य सामग्री की विपुलता ने उत्तरी क्षेत्रों को युद्ध में एक स्थायित्व प्रदत्त किया।

दक्षिण में भी सेना के संगठन हेतु नागरिक एवं अनिवार्य भर्ती को योजनाबद्ध किया गया। दक्षिण में 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु तक के लोगों

को राज्यसंघ की सेना में भर्ती किया गया। युद्ध के अंतिम दिनों में जब दक्षिण को पराजयका मुख देखना पड़ रहा था, तो नीग्रो दासों को भी सेना में प्रविष्ट किया जाने लगा।

आर्थिक रूप से भी दक्षिण की स्थिति उत्तर की अपेक्षा अधिक अशक्त थी। दक्षिण वस्तुपूर्ति हेतु बाह्य क्षेत्रों पर निर्भर था। उत्तर की सर्वाधिक इच्छा यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप के द्वारा उत्तरी सागरीय प्रतिबन्ध को समाप्त कर अपनी आर्थिक गतिहीनता को गतिमय करना था। दक्षिण की यह सैन्य अभिलाषा कभी पूर्ण न हो सकने के कारण यह क्षेत्र आर्थिक रूप से संकटग्रस्त ही रहा।

भाई-भाई का युद्ध

अब्राहम लिंकन (नवम्बर 6, 1860) के चुनाव ने दक्षिण में प्रथम सम्बन्ध विच्छेद धारा को प्रवाहित किया। दक्षिण के कपास कृषक सात प्रदेशों में गणतंत्रीय दल के दासता प्रसार में अवरोध उत्पन्न करने की नीति अपनी समृद्धि एवं सुरक्षा के लिये हानिकारक समझते थे। उन्होंने इस नीति के विरुद्ध संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने का निश्चय किया। इन प्रान्तों का कहना था कि सम्बन्ध विच्छेद करना उनका संवैधानिक अधिकार था। इस प्रकार दिसम्बर 20 को दक्षिण कैरोलिना से प्रथकवाद प्रारम्भ होकर 1 जनवरी, 1861 को टैक्सास के सम्बन्ध विच्छेद के साथ समाप्त हुआ। इन प्रान्तों के सदस्यों का अधिवेशन फरवरी 4, 1861 को मोन्टगुमरी में हुआ एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत मिसीसीपी के जैफरसन डेविस को राष्ट्रपति एवं जाजिया के एलेग्जेण्डर स्टीफन को उप राष्ट्रपति घोषित किया गया। अपने इस कार्य हेतु पृथकवादी प्रान्तों ने स्वयं के विचार में ऐसा कोई पग नहीं उठाया था जिसके द्वारा युद्ध के संकट का आभास हो।

इससे पूर्व पदमुक्त राष्ट्रपति बुकानैन ने कांग्रेस को अपने सन्देश में इस तथ्य से अवगत कराया कि यद्यपि सम्बन्ध विच्छेद का अधिकार अमान्य था परन्तु संविधान में संघीय शासन को ऐसा कोई अधिकार प्रदत्त नहीं था जिसके द्वारा संघीय शासन किसी प्रान्तीय शासन को अपने में निहित करने के लिये बाध्य कर सकें। बुकानैन ने अपने प्रशासन के अन्तिम दिवसों में पृथकवाद की समस्या को परिहार्य करने की चेष्टा की क्योंकि वह इसका उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी पर छोड़ देना चाहते थे। निर्वाचित राष्ट्रपति ने यह विश्वास प्रकट किया कि किसी प्रकार के समझौतों के द्वारा एकता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। राष्ट्रपति लिंकन का कहना था कि अपने में विभाजित सदन



अब्राहम लिंकन (1809-1865)
अमरीका के सोलहवें राष्ट्रपति

स्थायी एवं दृढ़ नहीं हो सकता था और इस प्रकार दासता एवं स्वतन्त्रता के प्रश्न का एक ही बार समाधान हो जाना चाहिये। इसका अर्थ था कि या तो दासता विरोध करने वाले जनमानस से दास प्रथा के उन्मूलन की चेष्टा करें अथवा दास प्रथा के अधिवक्ता इसकी वैधानिक रूप से बनाने की चेष्टा करें। अब्राहम लिंकन ने मार्च 4, 1861 में अपने उद्घाटन भाषण में शिष्ट शैली का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की, कि उनका उद्देश्य प्रांतीय दास प्रथा में हस्तक्षेप करना नहीं था किन्तु वे सम्बन्ध विच्छेद के अध्यादेशों को मान्यता देने को तत्पर नहीं थे। राष्ट्रपति ने इस बात की इच्छा व्यक्त की कि वे शासन सम्पत्ति एवं स्थानों को स्वाधिकृत करना शासन का प्रमुख लक्ष्य समझते थे। इस प्रकार की घोषणा नवीन राज्य संघ के नेताओं के लिये मानहानिकारक थी। शनैः-शनै दक्षिण कैरोलिना की सरकार फॉट सुम्टर पर अधिकार करने की इच्छुक थी जो कि एक कृत्रिम द्वीप पर बना हुआ था और मुख्य पत्तन का प्रवेश द्वार होने के कारण इसका महत्व था। राज्य संघ सघीय रक्षक सेना को वहाँ से हटाने की माँग कर रहे थे। युद्ध कारण को प्रोत्साहित किया क्योंकि संघीयशासन में तथा दक्षिण कैरोलिना सरकार में संघर्षरत स्थित का प्रादुर्भाव हो गया था। ऐसी स्थित में युद्ध का होना प्रायः अनिवार्य था और 12 अप्रैल 1861 को प्रातः साढ़े चार बजे सुम्टर को लेकर गृह युद्ध का प्रारम्भ हुआ। आगामी दिवस कमाण्डर मेजर एण्डर्सन ने आत्म-समर्पण करने की इच्छा व्यक्त की और 14 अप्रैल को संघीय ध्वज को उतार लिया गया और दुर्ग को रिक्त कर दिया गया।

राष्ट्रपति लिंकन ने 15 अप्रैल को पचहत्तर हजार नागरिक सेना को तीन मास के लिये संवैधानिक कर्तव्य का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी राजद्रोह की स्थिति का सामना करना उनका कर्तव्य था।

राष्ट्रपति के आह्वान ने द्वितीय सम्बन्ध विच्छेद धारा को प्रवाहित किया। संघ के आग्नीय दास प्रथा युक्त प्रान्तों में मैरीलैण्ड एव डेलावेयर को छोड़कर सभी ने संघीय शासन की अवज्ञा की। यह प्रान्त मूल रूप से पृथक्वाद के समर्थक नहीं थे, परन्तु उनकी सहानुभूति दक्षिण के प्रति निहित थी। फलतः वे युद्ध स्थिति में दक्षिण के विरुद्ध न जाकर उसके साथ युद्धरत रहना चाहते थे। इस प्रकार वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलीना, टेनेसी तथा अर्कन्सास राज्य संघ में सम्मिलित हो गये। राज्य संघ की राजधानी मांटगुमरी से रिचमॉन्ड में स्थानांतरित कर दी गई। रिचमॉन्ड का चयन सामरिक रूप से लाभप्रद नहीं था क्योंकि यह सीमाओं से अधिक सन्निकट थी तथा वार्गिंग्टन से भी 100 मील से कम दूरी पर स्थित थी। संघर्ष प्रारम्भ होने पर 19 अप्रैल को प्रथक्वादियों

ने वाशिंगटन को अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार वाशिंगटन को रेल संचार से विच्छेद कर दिया यद्यपि इस बात का आभास किया जा रहा था कि राज्य एवं सैनिक अगामी क्षेत्रों में युद्धरत होंगे परन्तु वे इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहते थे जिससे यूरोप वाले उनको गृह युद्ध का प्रवर्तक समझे।

इसी मध्य लिंकन ने कैन्टकी एवं मिसूरी को भी संघ के पक्ष में कर लिया था कैन्टकी जो कि समझौते की परम्परा को मान्यता देता था युद्धोरम्भ पर तटस्थता की नीति की घोषणा कर दी। यह ऐसी स्थिति थी जो संघीय शासन के लिए स्थायी रूप से हितकर नहीं थी किंतु कैन्टकी से खाद्य पूर्ति होने के कारण राज्य संघ को इस प्रांत की तटस्थता से लाभ था। ऐसी परिस्थिति में दोनों प्रतिद्वन्दी शासन इस प्रांत को अपनी ओर सम्मिलित करने के इच्छुक थे, यदि कैन्टकी दक्षिण के साथ गठबंधन करता था तो राज्य संघ की सीमा उत्तर से ओहायो तक स्थित हो जाती थी और ओहायो घाटी इस युद्ध के लिए एक निर्णायक प्रभाव सिद्ध हो सकती थी, इसका कारण यह था कि इसके द्वारा वाशिंगटन और पश्चिम का संचारण सुरुचिपूर्ण हो सकता था, लिंकन स्वयं कैन्टकी का होनेके कारण जैफरसन को और अपने देशवासियों को परामर्शदाताओं से अधिक महत्व देता था। जैफरसन डेविस भी क्योंकि इसी प्रांत का था, लिंकन ने अपनी राजनैतिक निपुणता के द्वारा शांति एवं प्रतीक्षा की नीति को प्राथमिकता दी। लिंकन यह भलीभाँति समझते थे कि किसी भी रूप में शक्ति प्रदर्शन करने का अर्थ इस प्रांत का दक्षिण के साथ मिल जाना होगा। सितम्बर 1861 में राज्य संघ की धैर्य प्रतीक्षा समाप्त हो गई और कैन्टकी पर शक्ति प्रयोग किया गया। मिसूरी में दोनों ओर से गृह युद्ध के प्रारम्भिक चरण का स्वाभाविक विस्तार आरम्भ हुआ। राज्यसंघ एवं संघीय सैनिकों से 'गुरिल्ला युद्ध' होता रहा और 'पी रिज' के युद्ध में संघीय सेना को नियंत्रण स्थिति प्राप्त हुई। इस प्रकार लिंकन ने कैन्टकी, मेरीलैण्ड तथा मिसूरी के अतिरिक्त पश्चिमी वर्जीनिया को भी संघ में सम्मिलित कर लिया। वर्जीनिया प्रांत का यह क्षेत्र प्रांत में पृथक था और भौगोलिक एवं आर्थिक रूप से ओहायो घाटी से सम्बन्धित था। यहाँ के निवासी एक अवधि से पूर्वी क्षेत्र के लोगों से त्रस्त थे जो प्रांतीय शासन को नियन्त्रित किये हुये थे। उन्होंने इस परिस्थिति का पूर्ण लाभ उठाया और इस एक पक्षीय साझेदारी से स्वतंत्र होना चाहा। इसके अतिरिक्त पश्चिमी वर्जीनिया की जनता संघीय शासन की समर्थक थी और दास प्रथा के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। रिचमॉण्ड शासन ने इस क्षेत्र को अपने से पृथक न करने का प्रयास किया परन्तु मैकलालन ने राज्य संघ के इस प्रयास को असफल कर दिया।

इस प्रकार उत्तर और दक्षिण के इस संघर्ष में केवल विजय और शांति का प्रश्न ही नहीं था वरन् संघीय व्यवस्था का प्रश्न था। दोनों पक्षों में सैनिक और संचारण का अभाव था परंतु दोनों ही पक्ष अपने को सशक्त करने हेतु सन्नद्ध थे।

दक्षिणी राष्ट्रपति युद्ध तथा सेना से पूर्णरूप से विज्ञ थे उन्हें सेना तथा सेनाधिकारियों के उत्तरदायित्व का पूर्ण ज्ञान था। इसके अतिरिक्त दक्षिणी सेना के पास रावर्ट ई०ली०, एलवर्ट जाँस्टन तथा जोजैफ जौन्सन जैसे योग्य अधिकारी थे। दक्षिणी राष्ट्रपति जैफरसन डेविस ने अपने सैनिक अधिकारियों का निपुणता से संचालन किया और संकट के समय भी उनका पूर्णरूपेण सहयोग दिया।

संघीय सेना की स्थिति इससे पृथक् थी। मार्च 1865 तक मेजर जनरल से उच्च पद वहाँ पर नहीं था। सेना के अधिकारियों में सामंजस्य न होने से अस्त-व्यस्तता एवं मतभेद एवं ईर्ष्या उत्पन्न हो रही थी। अब्राहम लिंकन को सैनिक अनुभव नहीं था और व्यक्तिगत रूप से वे सैनिक अधिकारियों को कम जानते थे। अधिकारियों की नियुक्ति में वह राजनैतिक आधार को महत्व देते थे। फ्रेमोन्ट, वटलर इसके स्पष्ट उदाहरण थे। यदि कोई सेना अधिकारी एक बार किसी अभियान में पराजित होता था तो उसे पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जाता था। यद्यपि इस विलोपन की पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति लिंकन ने अवर स्तर से सुयोग्य अधिकारियों की प्रगति की किंतु इस प्रयोग में कुछ सुयोग्य अधिकारी भी निष्कासित करने से सेना की उपयुक्तता का ह्रास होने लगा। लिंकन की नागरिक सेना एकत्रित करने की योजना में सफलता प्राप्त की। और उत्तरी लोगों में रिचमॉण्ड की ओर प्रस्थान की भावना जाग्रत होने लगी।

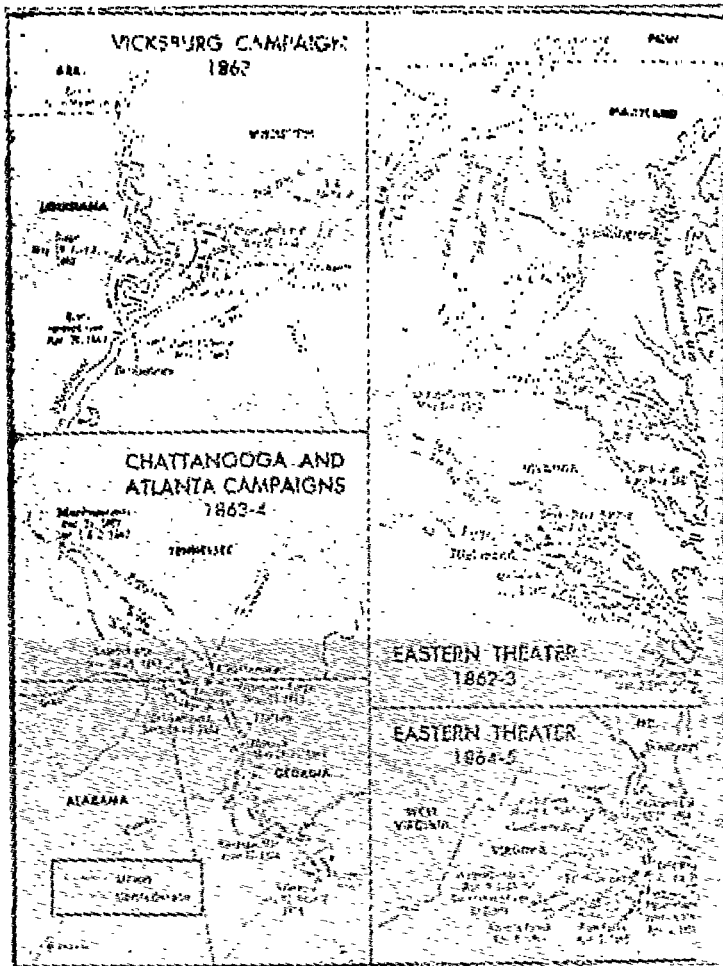
उत्तरी लोगों की इस भावना के अन्तर्गत यह उद्देश्य था कि जैफरसन डेविस की नवीन राजधानी में बुलाई गयी राज्य संघ कांग्रेस से पूर्व ही रिचमॉण्ड पर संघीय अधिकार हो जाना चाहिये। इस प्रकार के अभियान को यथार्थ रूप प्रदत्त करना संघीय सेना अध्यक्ष विन फील्ड स्कॉट ने उपयुक्त नहीं समझा। स्कॉट के अनुसार संघीय सहायक सेना एवं नागरिक सेना इस प्रकार के अभियानों के लिये दक्ष नहीं थी और इस सेना के लिये कुठामसह हीनता के लक्षण अतिवृद्धि का प्रकाश है। इस परामर्श को संघीय मंत्रिमंडल ने प्रत्याक्षिप्त किया। मेजर रू डेविनल्लैकडोहेरी को अभियान अधिकारी, त्रिसुवतर्कियाडगमाजीमेकडेवेलाको त्रजय सिंग की सेना को दसूरीपाडी एवं जैफरसनकी अध्यक्षता में यीतिके द्वारा बुलाइत क्रैप्रथम युद्ध में विजयि होतरी

पड़ा मैकडोनेल की अनुशासनहीन सेना ने अपने अभियान में सैनिक अविकसितता का पूर्ण परिचय दिया। जॉन्स्टन जो कि व्यूरीगार्ड और स्वयं की सेनाओं का अध्यक्ष था इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राज्य संघीय सेनाएँ विजयोपरान्त भी संघीय राज्य की पराजित सेना से अधिक अव्यवस्थित थी।

बुलरन की इस विजय ने दक्षिण को एक प्रकार से हानि पहुँचायी। दक्षिण की सेना इस विजय से अस्त व्यस्त हो गयी। सैनिक बिना आज्ञा छूट्टी जाने लगे, सैनिक भर्ती में ह्रास होने लगा और राज्य संघ अपनी स्वार्थ परता का परिचय देने लगे। दूसरी ओर संघ राज्य ने सेना का नेतृत्व जार्ज ब्रिन्टन मेकलालन को प्रदत्त किया। मेकलालन एक कुशल सेनापति होने के साथ एक कठोर अनुशासन प्रिय सैनिक थे। मेकलालन ने एक निपुण संगठन होने के कारण राज्य संघी की नागरिक एवं सहायक सेना में आशातीत वृद्धि की ओर उनकी सैनिक कुशलता एवं प्रशिक्षण के नेतृत्व में भर्ती हुए इन नव सैनिकों को सेना का सकारात्मक रूप प्रदान किया।

जार्ज मेकलालन मैक्सिको युद्ध के अनुभवी सैनिक तथा वेस्ट पाइंट के स्नातक थे। उन्होंने अपने सैनिक जीवन में सम्मान एवं प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उनमें सैन्य संगठन की योग्यता के साथ आत्म विश्वास का महान गुण था परन्तु वह अपने स्वभाव के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग नहीं कर पाते थे।

1861-62 के पूर्वी अभियान में 'फ़ेयर ओवर्स' तथा सप्तदिवसीय युद्ध में मेकलालन की यौद्धिक प्रतिभा का स्पष्ट अपसरण प्रतीत होने लगा। इसके पश्चात् मेकलालन 'एंटी टैम' में सेनापति ली० से संघर्षरत हुये। यद्यपि इस युद्ध में किसी ओर से विजय प्राप्त न हो सकी किन्तु ली० की युद्ध निपुणता की अवनति ने उन्हें अपने पद से मुक्त करा दिया। इस युद्ध के पश्चात् राष्ट्रपति लिंकन ने विमुक्त घोषणा कर दास प्रथा को पुनः समाप्त करने का मार्ग प्रगस्त किया। राष्ट्रपति की विमुक्ति घोषणा ने दासों में एक नवीन प्रोत्साहन उत्पन्न किया वे दास जो राज्यसंघ के अन्तर्गत कार्यरत थे उन्होंने राज्यसंघ पर उत्तरी सेना द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में उसको पूर्ण सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार पूर्वी क्षेत्रीय अभियानों में सेनाध्यक्ष ली० ने उत्तर पर अनेक आक्रमण किये परन्तु इस अनुभवी सेनाध्यक्ष को प्रत्येक स्थल पर अपमान सहना पड़ा। युद्ध में पश्चिमी क्षेत्र में सेनाध्यक्ष ग्रान्ट विजयश्री प्राप्त कर रहे थे। विक्सबर्ग और चेटनूगा की विजय ने संघीय शासन को युद्ध के केन्द्रीय स्थलों पर सुदृढ़ एवं सशक्त कर दिया। इन युद्धों के पश्चात् सेनाध्यक्ष ग्रान्ट को सम्पूर्ण सेनाओं का सेनाध्यक्ष बना दिया गया। इस प्रकार शर्मन और ग्रान्ट के निरन्तर विजय अभियानों ने इस देशिक संघर्ष को 1864 की शरद् ऋतु में अंतिम चरण



गृह युद्ध अभियान

पर पहुँचा दिया। यद्यपि, 1865 के आरम्भ में राज्य संघ के अधिकारी इस युद्ध का विस्तार नहीं करना चाहते थे क्योंकि राज्यसंघ की पराजय निश्चित थी।

4 मार्च 1865 में राष्ट्रपति लिंकन ने अपना दूसरा राष्ट्रपति काल का सत्र आरम्भ किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में शान्ति तथा एकता बनाये रखने के लिए कहा कि किसी की ओर भी हमारी मलिनता नहीं है अर्थात् किसी के प्रति हमारे मन में विद्वेष, मालिन्य एवं दुर्भावना नहीं है परन्तु हितैषिता एवं सद्भावना की भावना सबके प्रति विद्यमान है।

अप्रैल, 1865 में जैफरसन डेविस को बन्दी बना लिया गया परन्तु दुर्भाग्यवश 14 अप्रैल को फ्रोड्स थियेटर में जॉन बूथ नामक हत्यारे ने राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। अब्राहम लिंकन जिन्होंने 'एक राष्ट्र' का स्वप्न संजोया था, अपने इस स्वप्न को साकार होते न देख सके लिंकन जैसे महान राष्ट्रपति ने ही इस देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध को आरम्भ कर अमरीका को वास्तविक संयुक्त राष्ट्र के रूप में सफलता प्रदत्त करने का सफल प्रयास किया।

विकसवर्ग

1861 के वसन्तकाल में ग्रान्ट की सेनाओं ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। ग्रान्ट का निश्चय मिसिसिपी नदी पर पूर्ण अधिकार करना था। ग्रान्ट द्वारा न्यू ओरिलियेन्स (ऑरलीज) विजयोपरांत इस राज्य के निचले भाग से दक्षिणी सेनाओं को भागने के लिये विवश कर दिया गया। कुछ समय तक ग्रान्ट को विकसवर्ग पर जो दक्षिणी सेनाओं का गढ़ था, रोक दिया गया। दक्षिणी सेनाओं का नेतृत्व जोजफ ई० जॉन्स्टन के हाथों में था। ग्रान्ट पर दो ओर से आक्रमण हो रहा था अपितु उसने अपनी बुद्धिमता से 4 जुलाई, 1863 को विकसवर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अब ग्रान्ट ने अपनी सेना को मिसिसिपी के पश्चिमी किनारे पर लगा दिया था और तीस मील दक्षिण की ओर आगे बढ़ना आरम्भ कर दिया एवं विकसवर्ग के चारों ओर अपना घेरा डाल दिया। इस प्रकार संघीय सेना ने विकसवर्ग पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय की तुलना नेपोलियन की 1796 में इटली पर की गई विजय से की गई है। इस विजय के उपलक्ष्य में लिंकन ने कहा था, "मिसिसिपी अब निर्वाह होकर समुद्र से भेट करने जा रही है।" इसके बाद दक्षिण दो भागों में विभक्त हो गया, तथा नदी पार टैक्सास और अर्कन्सास नामक उपजाऊ प्रदेशों से पूर्व

के राज्यों के लिये रसद ला सकना असम्भव हो गया।

चेटनूगा

चेटनूगा पर अधिकार इस अभियान हेतु अत्यन्त आवश्यक था क्योंकि इसका अपना सैनिक महत्व था। इस कारण यह क्षेत्र कई माह तक क्रियाशीलता का केन्द्र रहा। जब रोजक्रेन्स ने इस पर अपना अधिकार किया तो चिकमांगा के युद्ध में जनरल ब्राग ने रोजक्रेन्स को पराजित किया। रोजक्रेन्स की पूरी सेना को नष्ट होने से बचाकर उसके अवर अधिकारी जनरल टामस ने अपनी सैन्य बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अक्टूबर में ग्रांट ने पश्चिमी संघीय सेना का कार्यभार संभाला। उन्होंने रोजक्रेन्स को पदच्युत कर टामस को प्रत्येक मूल्य पर सैन्य घेरे को बनाये रखने के लिये कहा। ग्रांट ने नवम्बर में टामस को सैन्य सहायता प्रदत्त कर चेटनूगा के युद्ध में ब्राग की सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की।

1864 में संघीय यौद्धिक उद्देश्य पश्चिमी क्षेत्र में अटलांटा अभियान था। अटलांटा दक्षिण के यातायात एवं उद्योग का केन्द्र था। दक्षिण के विचार में अटलांटा सैनिक परिधि से दूर स्थित होने के कारण सुरक्षित क्षेत्र था। संघीय सेना में उत्तरी सेनाओं का कार्यभार सेनाध्यक्ष ग्रांट को दिया गया। सेनाध्यक्ष ग्रांट ने पश्चिम के क्षेत्र की सेना शर्मन के नेतृत्व में भेजी। 1864 में शर्मन अटलांटा की ओर अग्रसर हुआ शर्मन के आक्रमिक प्रसार को रोकने में जॉन्स्टन की रण कौशलता कार्य न कर सकी और उसके कार्य से असंतुष्ट होकर जैफरसन डेविस ने जॉन बेल हुड को वहाँ का सेनानायक बना दिया इस परिवर्तन से युद्ध की गतिविधियों में और अधिक तीव्रता उत्पन्न हुई और युद्ध प्रगमन त्वरित हो गया फलतः अटलांटा संघीय विजय का द्योतक बन गया।

संघीय सेना से पराजित होकर दक्षिणी सेनापति ने टेनेसी की ओर प्रस्थान किया उसका विचार था कि उत्तरी आक्रमण के भय स्वरूप शर्मन को वापस बुला लिया जायेगा। इस ओर अविचलित शर्मन ने अपने योग्य अधिकारी टामस को हुड का अनुसरण करने हेतु प्रेषित किया। दूसरी ओर सेनापति शर्मन ने एक साहसिक अभियान योजना की रूप रेखा संयोजित की। इस योजना के अन्तर्गत शर्मन अटलांटा से, सेवाना की ओर प्रस्थान करना चाहता था और जाजिया के समृद्ध कृषि संस्थानों को ध्वस्त कर राज्य संघ को जार-जार कर देना चाहता था। यद्यपि राष्ट्रपति लिंकन एवं सेनाध्यक्ष यूलिसिस ग्रांट उसकी योजना से पूर्णतया सहमत नहीं थे किन्तु उन्होंने शर्मन को अपनी योजना को कार्यान्वित करने की आज्ञा प्रदत्त की। फलतः 12 नवम्बर

को अपने 62 हजार विस्वस्त सैनिकों के साथ सेनापति शर्मन ने अपने प्रसिद्ध "सागर प्रस्थान" को साकार रूप दिया। लगभग एक माह के पश्चात् शर्मन सेवाना पहुँचा और 20 दिसम्बर को शर्मन ने राष्ट्रपति लिंकन को यह सन्देश भेजा कि मैं आपको बड़े दिन (क्रिसमस) के उपलक्ष्य पर सेवाना नगर, प्रचुर युद्ध सामग्री तथा 25 हजार कपास के गट्ठे उपहार स्वरूप प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

शर्मन के अटलांटा से सागर प्रस्थान के तीन सौ मील की यात्रा में उन्होंने कृपि उद्योगों एवं यातायात के साधनों को विध्वंस किया। इस अभियान के मध्य किसी प्रकार कोई विशेष अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया और सैनिकों ने इस प्रस्थान को वन विहार की भाँति आनन्दपूर्ण रूप से लिया। सम्भवतः इस देशिक संघर्ष में शर्मन प्रथम सेनापति था जिसने आधुनिक युद्ध को आर्थिक रूप दिया।

पीच ऑरचर्ड का युद्ध

देशिक संघर्ष के प्रथम वर्ष में कोई अधिक घटनायें घटित नहीं हुईं। केवल 1861 में बुलरन के युद्ध में संघीय सेना पराजित हुई थी। इस मध्य यह विचार धारा उत्पन्न हुई कि यदि उत्तर युद्ध विजय करना चाहता है तो उसे दक्षिण की ओर आक्रामक नीति के द्वारा युद्ध रत होना पड़ेगा। फलस्वरूप 1862 की वसन्त ऋतु में सेनापति यूलिसिस ग्रान्ट और जडान कारलोस व्यूले की अध्यक्षता में उत्तरी सेना टेनिसी की ओर अग्रसर हुई। इस सेना ने शिलो (दक्षिणी पूर्व टेनिसी में एक राष्ट्रीय उद्यान) में अपना शिविर बनाया। इस उद्यान में अधिकतर आड़ू के वृक्ष थे। अप्रैल, 6, 1862 को राज्य संघ की सेनाओं ने सेनापति ग्रान्ट के सैनिक शिविर पर आक्रमण किया। दो दिवसों के रक्त रंजित युद्ध के पश्चात् दक्षिणी सेना को पीछे हटा दिया गया। इस युद्ध के मध्य छोटे-छोटे पक्षी कलोल-कलरव करते रहे और सायंकालीन तेईस हजार सैनिकों के मृत शरीर आड़ू के पत्तों से ढके हुये थे।

न्यू ऑरलियेन्स (ऑरलीन्ज) युद्ध

युद्ध के आरम्भ में दक्षिण के पास नौ सेना का अभाव था। इसके विपरीत उत्तर में उनके पास नब्बे युद्ध पोत थे जिनके द्वारा उन्होंने तीन हजार पाँच सौ मील लम्बे राज्यसंघ के सागरीय तट को नौ सैनिक नाकाबन्दी से युद्ध करने का प्रयास किया। शीघ्र ही संघीय नौ सेना ने सागरीय प्रभुत्व प्राप्त

करने की चेष्टा की। संधीय नौ सेना का सबसे महत्वपूर्ण नौ सैनिक आक्रमण नौ सेनाध्यक्ष डेविड ग्लासगो फॉरजेट के नेतृत्व में हुआ। लगभग एक सप्ताह तक फारजेट की नौकाओं द्वारा जैक्सन और सेन्ट फिलिप के दुर्गों पर गोलाबारी होती रही। अन्ततः 24 अप्रैल, 1862 को नौ सेना के वेड़े ने न्यू आंरलियेन्स (आंरलीन्ज) की ओर प्रस्थान किया और सायंकाल तक नगर पर अपना अधिकार कर लिया।

मॉनिटर तथा मरमैक

सागरीय उपक्रमण का श्रेय संधीय शक्तियों को ही नहीं था। 20 अप्रैल, 1861 को राज्यसंघ ने नारफोक नौ सैनिक आस्थान पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात् मरमैक पोत में आग लगाकर उसे जलमग्न करने की चेष्टा की गई परन्तु दक्षिण के अनुभवी सेना अधिकारियों ने मरमैक को पुनर्निर्मित कर जल युद्ध के प्रति प्रस्तुत कर दिया। उत्तरवासियों ने मरमैक से अधिक सशक्त एवं सुदृढ़ जलपोत मॉनिटर का निर्माण किया। मॉनिटर अमरीकी इतिहास में प्रथम वाष्प यंत्रित आक्रामक युद्धपोत था। यद्यपि यह युद्ध अनिर्णित रहा, किन्तु इस युद्ध का ऐतिहासिक महत्व था। चूँकि प्रथम बार दो लौह कवचित युद्धपोतों में युद्ध हुआ, इसने भविष्य के लिये सागरीय युद्ध के लिये पोत निर्माण का द्वार खोल दिया।

शार्प्सवर्ग: ऐंटीटेम का युद्ध

संधीय सैनिकों की सफलता ने सेनापति ली के अभियानों में विशेष अवरोध उत्पन्न नहीं किया। सेना अध्यक्ष ली उत्तरी क्षेत्र में मेरीलैण्ड तक आगे बढ़ वाशिंगटन के लिये संकट उत्पन्न कर रहा था। ली पैन्सेलवेनिया में अग्रिम जाकर भी वर्जीनिया के साथ संचारण सम्बन्ध बनाये रखना चाहता था। उसका उद्देश्य अग्रिम जाकर हारपर्स फेरी पर अधिकार करना था। दुर्भाग्यवश सेनाध्यक्ष ली की सैनिक गतिविधियों की सूचना संधीय अधिकारियों के हाथों में आ गई। फलस्वरूप संधीय सेनाध्यक्ष मेकलालन ने अपनी सेना को राज्य संघ की सेनाओं को रोकने हेतु भेज दिया। सेनापति ली और स्टोनवेल जैक्सन की सेनाओं में शार्प्सवर्ग के बाहर ऐंटीटेम में यह युद्ध हुआ और दक्षिणी आक्रमण सफल हो गया। देशिक संघर्ष में इस युद्ध से पूर्व एवं पश्चात् इतने सैनिक युद्ध में हताहत नहीं हुये जितना कि इस युद्ध में हुये।

फ्रैंडरिक्स वर्ग का युद्ध

1862 की गर्त में तीन उत्तरी सेनायें युद्ध क्षेत्र में थीं। प्रथम पेटोमॅक सेना पूर्व में स्थित थी द्वितीय कम्बरलैण्ड की सेना मध्य टेनिसी में थी, और तृतीय टेनेसी की सेना मिसीसीपी नदी के तट पर विद्यमान थी। तृतीय सेना सेनापति ग्रान्ट की अध्यक्षता में विक्स वर्ग की ओर अग्रसर थी। रोजक्रांस की अध्यक्षता में द्वितीय सेना दक्षिण से नेशविल की ओर प्रयाण कर रही थी। प्रथम सेना की टुकड़ी सेनापति वर्नसाइड के नेतृत्व में फ्रैंडरिक्स वर्ग नामक स्थान पर 13 दिसम्बर, 1862 को सेनापति ली के सम्मुख आयी। इस युद्ध में गोलावारी से आच्छादित वातावरण में वर्नसाइड ने अपनी सेना को नदी के पार उतारने की चेष्टा की परन्तु ली के सैनिकों ने उत्तरी सैनिकों को पीछे हटा दिया। इसी युद्ध में संघीय छाताधारी (वैलून) थैंडेस ली ने राज्य संघ की सैनिक गतिविधियों का प्रेक्षण किया। यह देशिक संघर्ष में सैनिक विज्ञान की एक नवीन उपलब्धि थी।

चांसर्लजविल: जैक्सन की मृत्यु

अप्रैल 1863 में हुकर जिसने सेनापति वर्नसाइड का स्थान ग्रहण किया था, 70 हजार सैनिकों के साथ फ्रैंडरिक्स वर्ग के उत्तर में प्रवेश कर चांसर्लजविल में स्थित हुआ। स्टोनवॉल जैक्सन पच्चीस हजार सेना के साथ हुकर पर आक्रमण करने के लिये अग्रसर हुआ। दो तीन दिवस के असमंजस पूर्ण युद्ध के पश्चात् हुकर ने सत्रह हजार मृत सैनिक छोड़कर अपसरण किया। परन्तु दक्षिण ने इस युद्ध में स्टोनवॉल जैक्सन को खो दिया। मृत्यु से पहले जैक्सन के अन्तिम शब्द थे "कि नदी के उस पार चलकर वृक्षों की छाया में विश्राम करना चाहिये।"

गैटिज (गेटिस) वर्ग का युद्ध

जून, 1863 में सेनापति ली ने अपनी सेनाओं को उत्तर पश्चिम की ओर प्रेषित किया। 28 जून को उन्हें ज्ञात हुआ कि हुकर की सेना मेजर जनरल जार्ज गॉरडन मीड के नेतृत्व में फ्रैंडरिक में एकत्रित हो रही थी। ली ने गैटिजवर्ग में अपनी सेना को केन्द्रित करने का निश्चय लिया। जुलाई एक से 3 के मध्य देशिक संघर्ष का सर्वाधिक दुःखांत एवं नृशंस युद्ध गैटिजवर्ग में हुआ। इस युद्ध में राज्य संघ की गौर्यता के उपरान्त भी राज्य संघीय (कान्फ़ेडरेसी) सैनिकों का नरसंहार हुआ। देशिक संघर्ष को वास्तविक भाई-भाई के युद्ध का रूप इसी

अभियान में प्रत्यक्ष दृष्टागोचर हुआ जब दो भाई विलियम कल्प संघ की ओर से और वैजले कल्प राज्य संघ की ओर से युद्धरत हुये । इनमें वैजले कल्प की मृत्यु हो गई ।

मिशनरी रिज पर आक्रमण

नवम्बर, 1863 में कम्बलरलैण्ड की सेना लगभग एक वर्ष से विश्रामित थी और केवल चेटनूगा में ब्रैकस्टन ब्रैग की सेना के सम्मुख थी रोजक्रांस की सेना में हुकर, शर्मन एवं ग्रान्ट सम्मिलित हो गये थे, परन्तु राज्य संघ (कार्न्फड्रेसी) लुकआऊट माऊन्टेन तथा मिशनरी रिज पर अधिकार कर अपनी सुदृढ़ता का परिचय दे रहे थे । यद्यपि 23 नवम्बर को ग्रान्ट ने आक्रमण किया परन्तु 2 दिन पश्चात् उसे मध्यस्थित हो जाना पड़ा और संघीय सैनिकों ने अपनी ओर से बिना आज्ञा प्राप्त किये मिशनरी रिज पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली । इस प्रकार संघीय सेना ने पश्चिम में विक्सवर्ग पर अधिकार करने के पश्चात् दक्षिण को कठिनाई उत्पन्न कर दी थी ।

राज्य संघ (कार्न्फड्रेसी) का संकुचन

9 मार्च 1864 को यूलीसस ग्रान्ट को समस्त संघीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनाधिकारी नियुक्त किया गया । ग्रान्ट ने यह निर्णय लिया कि राज्यसंघ की सेनाओं पर आक्रामक नीति के द्वारा ही युद्ध विजय हो सकती थी । दक्षिण की दो मुख्य सेनायें थीं—एक उत्तरी वर्जीनिया में सेनापति ली. की अध्यक्षता में, तथा दूसरी ओर टैनेसी में सेना का नेतृत्व जान्स्टन कर रहे थे । शर्मन को पश्चिमी सेना का नेतृत्व प्रदत्त किया गया और उनको जान्स्टन की सेना को पराजित कर एटलान्टा की ओर अग्रसर होने के लिये आज्ञा दी गई । इधर पूर्व में ग्रान्ट राज्य संघ की राजधानी रिचमॉन्ट की ओर बढ़ने की चेष्टा में पीटरस वर्ग में ली. के द्वारा रोक लिये गये । राष्ट्रपति लिंकन को नवम्बर में अपने चुनाव हेतु किसी विशिष्ट (मुख्य) विजय को प्राप्त करना अनिवार्य था और उन्हें यह शुभ अवसर 2 सितम्बर को शर्मन ने एटलान्टा विजय द्वारा प्रदान किया ।

अब्राहम लिंकन

अब्राहम लिंकन अमरीका के सोलहवें राष्ट्रपति थे । उनका राष्ट्रपति काल अमरीका के इतिहास में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण था । लिंकन ने अपने राष्ट्रपति पद पर आसीन होते ही वर्पों से चली आ रही दासता और प्रशासकीय अस्थिरता के प्रश्नों का समाधान करने की सफलतापूर्ण चेष्टा की ।

अब्राहम लिंकन उस ज्योति के पुंज थे जिसने अमरीका को नव राजनीति एवं नव समाज प्रदत्त किया। लिंकन अपनी सत्यनिष्ठा, सहृदयता, आत्मिक निष्कपटता तथा हास्य मिश्रित वार्ता के द्वारा जन साधारण के हृदयों में अंकित हो गये। उनके गम्भीर एवं अटूट साहस ने समस्त कठिनाईयों के उपरांत भी अमरीका को नवचेतना से विकसित किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषता उनकी सरलता में विद्यमान थी, जो भी सामान्य जनता का व्यक्ति उनसे मिला उसको लिंकन मूल रूप से प्रभावित करते थे। इसका कारण यह था कि प्रत्येक व्यक्ति इस साधारण तथ्य से विज्ञ था कि लिंकन पर विश्वास किया जा सकता है।

अब्राहम लिंकन ने देशिक संघर्ष का आह्वान अमरीकी लोकतंत्र की गौरव गरिमा को सुरक्षित रखने के लिये किया। लिंकन का कथन था "क्योंकि मैं दास नहीं बनना चाहता इसलिये मैं स्वामी भी नहीं होना चाहता" यही उनके लोकतंत्र का आधार था। उनके उदार व्यक्तित्व एवं उच्च विचारों का प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध के मध्य उन्होंने दक्षिण-वासियों के प्रति किसी अनुचित एवं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया।

लिंकन ने अमरीका का यथार्थ रूप से संयुक्त राष्ट्रीय निर्माण किया, दासता उन्मूलन कर समाज को नव ज्योति दी तथा अमरीकी राजनैतिक तंत्र को केन्द्रित किया। इस महान नेता ने अमरीकी इतिहास में उस अध्याय का आरम्भ किया जिसके उपरान्त देश उन्नति के सोपान पर अग्रसरित हुआ। दुर्भाग्यवश अमरीकी ऐतिहासिक एकता के सृजन के स्रोत की आकस्मिक हत्या ने उसे अपने स्वप्न को साकार देखने से वंचित रखा।

यूलिसस सिम्पसन ग्रान्ट-रावर्ट एडवर्ड ली.

देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध के युद्ध मंच पर दो सेनाध्यक्षों का नाम प्रायः लिया जाता है। यह सेनाध्यक्ष थे, उत्तर के यूलिसस ग्रान्ट और दक्षिण के रावर्ट ली। दोनों सेनाध्यक्षों की प्रतिभा, निपुणता तथा शौर्यता पर अनेक पुस्तकें एवं किंवदंतियाँ लिखी गईं। लेखकों ने अपनी भाषा शैली एवं विचारानुसार दोनों व्यक्तियों की व्याख्या आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर की है।

रावर्ट ली. के जीवनी लेखक डगलस फ्रीमैन ने ली. की प्रतिभा, योग्य नेतृत्व, सेवाभावना तथा मानवीयता की सराहना की है। निःसन्देह ली. अपने संगठन कार्य सैनिकों के प्रति सहृदयता की भावना, अपरिमित साहस तथा

आकर्षक व्यक्तित्व के कारण अपनी सेना और सेनाधिकारियों मध्य श्रद्धा के पात्र थे । फ्रीमैन ने रावर्ट ली. की योग्यता की सराहना करते हुये यह भी स्पष्ट किया कि रावर्ट ली के गुण भी अवगुण में परिणत हो गये थे । फ्रीमैन के अनुसार ली की अत्यधिक सौम्यता एवं सरल स्वभाव तथा सैनिकों पर आवश्यकता से अधिक विश्वास युद्ध में एक वास्तविक सैनिक के अवगुण थे । हैरी विलियम्स ने भी ली. को एक निपुण युद्धमंचीय सामरिक नीतिज्ञ की संज्ञा दी किन्तु राज्य संघ के अवर सैनिक अधिकारियों की अयोग्य योजनाओं तथा कार्यों ने ली की सैनिक उज्ज्वलता को धूमिल कर दिया । हैरी विलियम्स ने अपनी पुस्तक 'लिकन एण्ड हिज जनरल्स' में वूलिसस ग्रांट के व्यक्तित्व के प्रति लिखते हुये कहा कि ग्रांट का व्यक्तित्व आकर्षण हीन था और सम्भवतः हास्यास्पद व्यक्तित्व का स्वामी था । इसके उपरान्त भी ग्रांट के व्यक्तित्व को उज्ज्वल करने वाली त्रिविध विशेषतायें उसमें समाहित थी-गहन विचारशक्ति, दृढ़ संकल्प तथा सौम्यता व सरलता । ग्रांट को युद्ध के समय उतनी ही यौद्धिक शिक्षा प्राप्त थी जितनी सामान्य वेस्ट प्वाइंट के स्नातक तथा साधारण नियमित सैनिक अधिकारी में होनी चाहिये परंतु ग्रांट में रणनीति प्रतिभा के साथ अपने अधिकारियों की योग्यता से लाभान्वित होने की पूर्ण क्षमता थी । विक्सवर्ग के युद्ध में ग्रांट ने अपनी युद्धमंचीय सामरिक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया । इसमें संशय नहीं कि रावर्ट ली में रणनीतिज्ञता तथा परोक्ष मौलिकता ग्रांट से अधिक थी किन्तु राज्यसंघ की निम्न सैनिक स्थिति ने रावर्ट ली. की विकसित प्रतिभा को अयोग्यता में परिणत कर दिया ।

उपरोक्त दोनों सेनाध्यक्षों के चरित्र एवं देशिक संघ में उनकी यौद्धिक नीतियों के विश्लेषण से दोनों सेनानायक अपनी निजी भूमिका में अपूर्व थे । हैरी विलियम्स ने सैद्धांतिक रूप से ग्रांट को ली से उत्तम सेनापति की संज्ञा दी उनके अनुसार ग्रांट को आधुनिक रणनीति का ज्ञान ली. की अपेक्षाकृत अधिक था । ली. को विलियम्स ने एक परम्परावादी सेनाध्यक्ष की मान्यता दी है । इसके अतिरिक्त ग्रांट का सैनिक संगठन ली के सैन्य योजना से अधिक सुव्यवस्थित था । इस प्रकार ली परम्परावादी सेनाध्यक्षों की अंतिम कड़ी थे और ग्रांट आधुनिक पंक्ति के प्रथम सेनाध्यक्ष थे ।

रावर्ट एडवर्ड ली.

इस युद्ध के परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों को रावर्ट ई० ली० जैसा लब्ध प्रतिष्ठित सैनिक मिला जो सेनापतियों में सबसे प्रतिभाशाली एवं शूरवीर था । उसके योग्य नेतृत्व, सेवा भावना, मानवीय भावना आदि ने उसको

अत्यन्त उच्च स्थान पर पदासीन किया। उसने दक्षिणवासियों से यह अनुरोध किया कि वे उत्तरवासियों के प्रति भूतपूर्व शत्रुता को भूलकर नवयुग की तरह उनके साथ नये सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करें। सेनापति ली० के शांत एवं दयालु व्यक्तित्व का लाभ उसके अधीनस्थ भरपूर उठाते थे क्योंकि कठोर अधिकारीगण को अपनी इच्छानुसार कार्य कराने में वह अपने आप को असमर्थ पाता था। सैन्य तकनीकी की अपेक्षा वह सामरिक नीति के विशेषज्ञ थे। अपनी संगठन शक्ति, व्योरे के प्रति पूर्ण जागरूकता, अपने सैनिकों के प्रति सहृदय भावना, अपरिमित साहस तथा आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह अपनी सेना के जवानों की पूर्ण श्रद्धा के पात्र बन गये थे। वाशिंगटन के समान ही उसके अन्दर आत्म नियंत्रण था। वह कभी भी सीमा का अतिक्रमण नहीं करते थे। सेनानायक ली. हार जीत, विग्रह, संधि में महान था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात वह केवल पाँच वर्षों तक जीवित रहा। इस काल में उसने अपना सारा समय आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में दक्षिण पुनर्गठन और उत्तर दक्षिण में मैत्री भाव उत्पन्न करने में लगाया।

राबर्ट ली. के जीवनी लेखक डगलस फ्रीमैन ने राबर्ट ली. की योग्यताओं की प्रशंसा करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि ली के गुण भी अवगुण में परिणित हो गये फ्रीमैन ने ली. की अत्याधिक सौम्यता एवं अपने सैनिकों पर वास्तविकता से अधिक विश्वास और युद्ध में भी मानवतावादी होना एक सैनिक के अवगुण बताया।

✓ युद्ध के परिणाम।

देशिक संघर्ष ने अमरीका के इतिहास में एक नवीन युग एवं अध्याय का समावेश किया। इस गृह युद्ध के मध्य तथा उपरान्त अमरीका की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। अमरीकी इतिहास में इस भाई-भाई के युद्ध ने जहाँ एक घोर संघर्ष तथा विध्वंसता का परिचय दिया वहाँ दूसरी ओर इस संघर्ष ने अमरीका के सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक मूल्यों में वृद्धि की।

राजनैतिक:

देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध ने चिरकालिक प्रान्तीय एवं संघीय राज्यों के अधिकारों के विवाद को समाप्त कर दिया। इस संघर्ष ने अमरीका की राजनैतिक एवं प्रशासनिक केन्द्रों को सुदृढ़ता प्रदान की। राजनैतिक रूप से

अमरीका को वास्तविक संयुक्त राष्ट्र का रूप प्रदत्त किया। निसन्देह दास प्रथा का उन्मूलन, केन्द्रीय शक्तियों का संगठन एवं राष्ट्र की एक रूपता इस संघर्ष की उपलब्धि थी।

आर्थिक :

इस आन्तरिक युद्ध के मध्य उत्तरी चित्रों में आशातीत विकास विस्तार एवं समृद्धि का नया वातावरण उत्पन्न हुआ। युद्ध सामग्री उद्योग के साथ कपास ओटन तथा अन्य उद्योगों ने भी विकासशीलता ग्रहण की। इस औद्योगिक क्रांति ने नगर निर्माण यातायात तथा रेल उद्योग में विस्तार किया। इसके साथ कृषि उद्योगों एवं खनिज पदार्थों के उद्योगों का विकास भी हुआ। 1812 के युद्ध ने फैक्टरी प्रणाली का आरम्भ किया था और इस प्रकार देशिक संघर्ष ने औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया।

गृह युद्ध ने अमरीका के इतिहास में नव आर्थिक युग का समन्वय किया। इस युग में अमरीका औद्योगिक समृद्धि से पूँजीवाद युग की ओर अग्रसर हुआ जिससे भविष्य में संयुक्त राज्य अमरीका एक सबल, सुदृढ़ एवं सशक्त राजनैतिक एवं आर्थिक साम्राज्य बनने में सफल हुआ।

सामाजिक

राजनैतिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ अमरीका के सामाजिक मूल्यों में भी वृद्धि हुई। यद्यपि अमरीकी समाज में पूँजीपति एवं समृद्ध वर्ग का उदय हुआ परन्तु श्रमिकों की स्थिति में सेवा एवं शिक्षा का भी प्रचुर विकास हुआ। इस काल में अमरीकी स्वास्थ्य एवं सफाई नियमों ने भी सैनिक हितों के प्रति प्रशंसनीय कार्य किया। क्लेरा बाटर्न ने परिचारिका (नर्स) तथा अमरीकी रेड क्रॉस संस्था को एक नया रूप प्रदान किया। युद्धरत होने के उपरान्त भी संघीय शासन ने तकनीकी एवं कृषि विद्यालयों, सैनिक तथा सामान्य शिक्षा के उत्थान हेतु अधिनियम पारित किये जिनमें मुख्य 1862 का मॉरल अधिनियम था।

अमरीकी देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध अथवा भाई भाई का युद्ध वास्तविक रूप में एक देशीय संघर्ष था। यदि फ्रांस ने नेपोलियन तृतीय की पड़ोसीय योजना में ब्रिटेन एवं रूस सम्मिलित हो गये होते तो सम्भवतः अमरीकी संघर्ष केवल उत्तर दक्षिण का संघर्ष न रह जाता और अमरीकी इतिहास के इस अध्याय में किंचित परिवर्तन हो जाता।

उपसंहार

अमरीका के इतिहास में कुछ ही घटनायें ऐसी हैं जिनके विषय में गृह युद्ध से अधिक अध्ययन किया गया हो। अमरीका में प्रतिवर्ष इस काल की व्याख्या, विश्लेषण एवं तथ्यों को लेकर अनेक पुस्तकें, पुस्तिकायें एवं पत्रिकाओं में विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि देशिक संघर्ष एक भाई-भाई का युद्ध था और इसमें अन्य कोई बाह्य शक्ति आवेष्टित नहीं थी। फलस्वरूप अमरीकी विद्वान एवं इतिहास-वेत्ता इस संघर्ष अथवा युद्ध को औचित्य प्रदान करने हेतु अथवा अनुचित बताने हेतु निरन्तर विषलेषणात्मक अध्ययन लेखन कर रहे हैं। अमरीका के इतिहासकारों को देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध के प्रति उतना ही आकर्षण रहा है जितना फ्रांसीसीयों को फ्रांसीसी क्रांति के प्रति है। समकालिक इतिहासकारों ने दक्षिण और उत्तर की स्थित की व्याख्या अपने अपने तर्क के द्वारा की है। दक्षिणी लेखकों ने युद्ध को षडयंत्र की संज्ञा दी तथा उत्तर को दक्षिण की स्थापित संस्थाओं का हन्ता समझा। उत्तरी इतिहासवेत्ताओं ने दक्षिण को पृथक्वादी एवं दास प्रथा की अनैतिक संस्था का संरक्षक माना। हैनरी विल्सन के अनुसार दक्षिण ने सदैव गणतंत्रीय संस्थाओं की अनुप्रणित मनो-वृत्तियों को आक्रामक स्वरूप देकर पूर्ण राष्ट्र को रक्तंजित युद्ध की ओर अग्रसर किया। विल्सन के उपरोक्त मत का समर्थन कई अन्य लेखकों ने किया कि उत्तर के लोग (जनता) संघ एवं संविधान के रक्षक थे जबकि दक्षिणी लोगों ने अकारण एवं आक्रामक नीति का परिपालन किया।

दूसरी ओर दक्षिण के लेखकों ने उत्तरी लोगों को स्वयं के राजनैतिक एवं आर्थिक लाभ के लिये दक्षिण के प्रति अभिधावक नीति धारण करने का उत्तरदायी समझा। उत्तरी वासी अपनी निरंकुश नीति का परिपालन दक्षिण पर करना चाहते थे और इसलिये उन लोगों ने उत्तर पर अनुचित आक्रमण-शीलता का परिचय दिया। इस प्रकार उत्तर दक्षिण के अन्य वक्तों के एक दूसरे के प्रति आरोपप्रस्त विवाद से हटकर अन्य मत प्रकट हुआ जिसने इस युद्ध को 'निरर्थक' एवं 'वर्जनीय' बतलाया। जेम्स बुकानन (ब्यूकानन) ने 1865 में अपनी पुस्तक में इस युद्ध का मुख्य कारण उत्तरी उन्मूलनवादियों की चिरकालिक, क्रियाशील एवं दुराग्रही नीति को दिया है जिन्होंने कांग्रेस में तथा बाहर सदैव दक्षिण दास प्रथा के प्रति विद्वेष की भावना को उत्तेजित किया। इस लेखक के अनुसार युद्ध का परिहार किया जा सकता था यदि उत्तरी लोग इतने हठधर्मी एवं दुराग्रही न होते और दक्षिण के वासी इतने अतिवादी एवं उग्रवादी न होते।

उपरोक्त तीनों समकालिक विचारधाराओं ने ऐतिहासिक वाद-विवाद का श्रीगणेश किया परन्तु 1890 में ऐतिहासिक प्रौढ़ता ने जन्म लिया क्योंकि इस समय में इतिहासकारों ने लेखकों के देशिक संघर्ष का 'इतिहास' की दृष्टि से अवलोकन किया न कि सामयिक घटना के रूप में। इसके अतिरिक्त उपरोक्त लेखक इस युद्ध के प्रति समकालिक लेखकों के सदृश्य व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक नहीं थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में अमरीकी विद्वान राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित थे। वे इस देशिक संघर्ष को अप्रत्यक्ष कृपा दान की संज्ञा देने लगे थे क्योंकि न केवल इसके द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था अपितु प्रांतीय संघर्ष भी समाप्त हो गया था। राष्ट्रीयवादी ऐतिहासिक महत्व के विद्वानों में जेम्स फोर्ड रोहडस ने दासता के प्रश्न को युद्ध का मौलिक कारण माना क्योंकि फोर्ड के अनुसार दासता का विकास औद्योगिकरण की प्रगति के कारण हुआ तथा 'कपास ओटन' ने दासता उन्मूलन को परिलक्षित किया। यद्यपि राष्ट्रवादी लेखकों ने गृह युद्ध को अदम्य संघर्ष की संज्ञा दी, उन्होंने इस युद्ध को अपरोक्ष रूप से अमरीका के प्रति लाभकारी माना। रोहडस ने भी देशिक संघर्ष (गृह युद्ध) का मुख्य श्रेय आधुनिक एवं संगठित संयुक्त राष्ट्र अमरीका के जन्म को दिया। राष्ट्रवादी मत के लेखक दक्षिण के प्रति आलोचनात्मक लेखन में विश्वास नहीं करते थे वरन वे दास प्रथा एवं पृथकवाद के सिद्धांत के विरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त यह इतिहास-वेत्ता दक्षिण में सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास न होने का कारण दासता की संस्था को देते थे। वुडरो विल्सन ने भी दासता के कारण दक्षिण को राष्ट्रीयता की भावना की परिधि से बाहर होने की संज्ञा दी तथा उत्तर दक्षिण संघर्ष को अनिवार्य माना। एक अन्य इतिहासकार एडवर्ड चैनिंग के अनुसार अमरीका में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य दो मित्त सामाजिक संस्थाएँ विकसित हो चुकी थी। दक्षिण अपने कृषि उत्पादन के प्रति दास श्रमिकों पर निर्भर था तथा उत्तर अपनी कृषि, उद्योग द्वारा व्यापार को वेतन पद्धति पर निर्धारित किये हुये था। ऐसी दो समानान्तर संस्थाएँ जिनकी सामाजिक आधारशिला भिन्न थी, अधिक समय तक एक शासन के अन्तर्गत स्थायी नहीं रह सकती थीं। उपरोक्त स्थिति में इनको या तो मौलिक रूप से पृथक हो जाना चाहिए अथवा एक को नष्ट हो जाना चाहिये अथवा एकीकरण कर स्थायित्व प्राप्त कर लेना चाहिये।

अतएव बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उपरोक्त विद्वानों को प्रगतिशील मत के विद्वानों की चुनौती का सामना करना पड़ा। प्रगतिशील विचारकों में चार्ल्स वियर्ड एवं मेथ्यू जोजेफसन प्रमुख थे। वियर्ड ने देशिक संघर्ष अथवा

युद्ध को एक सामाजिक संघर्ष की मान्यता दी क्योंकि इस युद्ध ने अमरीकी समाज में नवीन वर्गीय व्यवस्था की स्थापना की तथा औद्योगिक उन्नति ने एक समृद्ध वर्ग को जन्म दिया। चार्ल्स वियर्ड तथा मेरी वियर्ड ने अपने विश्लेषण में देशिक संघर्ष को प्यूरिटन क्रान्ति एवं फ्रांस की क्रान्ति की भाँति सामाजिक क्रान्ति की संज्ञा दी जिसके द्वारा उत्तर ने दक्षिण के विकसित अभिजात तंत्र को सभाप्त किया। इस प्रकार वियर्ड की विचारधारा से सहमत जोसेफसन ने भी युद्ध पश्चात् युग को 'सामन्ती लुटेरों का काल बताया। क्योंकि उनके अनुसार इस युग का संश्लेषण करते हुये इस तथ्य को स्पष्ट किया, नवनिर्माण काल में आर्थिक जीवन अनवरत रूप से विकसित हुआ परन्तु इस क्रान्तिकारी परिवर्तन ने अमरीका में एक लघु पूँजीपति समाज का विनर्धन किया। यद्यपि वियर्डवाद की आर्थिक व्याख्या ने गृहयुद्ध को एक नया मोड़ दिया परन्तु 1930 के आर्थिक मंदी दशक में कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों ने अन्य आर्थिक तत्वों पर विचार प्रकट किये और वियर्ड के उन शब्दों को 'कि गृह युद्ध द्वितीय अमरीकी क्रान्ति था' को मार्क्सवादी स्वरूप दिया। इनमें प्रमुख जेम्स ऐलन ने गृह युद्ध को अभिजात्य वर्ग एवं मध्यम वर्ग के संघर्ष से उत्पन्न पूँजीवाद के विकास का काल बताया। ऐलन के अनुसार दासता संस्था का विध्वंस आवश्यक था क्योंकि इस के द्वारा राष्ट्रीय एकता होगी और उसके द्वारा पूँजीवाद का विकास और तत्पश्चात् श्रमिक आन्दोलनों के प्रति एक आधार भूमि का निर्माण होगा। इस निमित्त मंच पर जो नाटक होगा उसके मुख्य पात्र उच्च वर्ग और सर्वहारा वर्ग होंगे।

उपरोक्त आर्थिक व्याख्याओं के पुष्पित होने के साथ-साथ दो अन्य ऐतिहासिक मतों का समावेश भी 1930 के आस पास हुआ। इन मतों में प्रथम दक्षिण में क्षेत्रीय रूचि रखने वाले इतिहासकारों का योगदान था। इनमें प्रमुख फ्रैंक आउसले थे जिनके विचारानुसार गृह युद्ध उत्तरी लोगों के अहं केन्द्र प्रांतीयवाद में केन्द्रित था। आउसले का कथन था कि उत्तर अपने में स्वयं एक राष्ट्र की अनुभूति रखता था और अन्य प्रान्तों की गौरव गरिमा एवं प्रतिष्ठा को मान्यता प्रदान करने में नितान्त अक्षम था। आउसले ने उत्तर को उन्मूलनवादी तंत्र से युक्त नृशंस एवं दुराग्रही मतान्ध की संज्ञा दी। आउसले ने अपने तर्क को सशक्त करने हेतु जान ब्राउन की कार्यान्वित घटना को समक्ष रखा और स्पष्ट किया कि राल्फ वाल्डो एमरसन जैसे दार्शनिक ने भी ब्राउन को जीसस कहा। इसलिये आउसले के विचार में दक्षिण के राजवेत्ता बुद्धिवेत्ता एवं नैतिक आचार्यों ने भी यद्योन्मत उत्तर की ओर मौन धारण करना अनुचित समझा। आउसले ने पुनः इस तथ्य को इंगित किया कि दो राष्ट्रों को

की भाँति ही दो प्रांतों में पारस्परिक भ्रातृभावता मान एवं आत्म सम्मान पर शान्ति निर्भर हो सकती थी और इस सिद्धांत के हनन के पश्चात् एकता बनाये रखना अत्यन्त कठिन था ।

1930 एवं 1940 के मध्य देशिक संघर्ष से सम्बन्धित इतिहास लेखन का दूसरा मत संशोधकों का था । इस मत के प्रमुख विद्वान थे एवरी क्रेवन एवं जेम्स रेण्डाल । इनकी धारणा थी कि युद्ध रोगात्मक भाव प्रवणता एवं विवेक से उत्पन्न होता और इसलिये युद्ध सामान्य रूप से तथा देशिक विशेष रूप से अनिष्टता के द्योतक हैं । इनके मतानुसार युद्ध वर्जनीय था । रेण्डाल ने मानव प्रकृति की व्याख्या के पुष्टिकरण में ग्राहम वेल्स के विचारों को व्यक्त किया । उनके अनुसार असंगत एवं विवेकहीन प्रवृत्ति के द्वारा अनेक देशिक संघर्ष हुये ।

क्रेवन और रेण्डाल ने किसी भी समस्या पर हिंसा एवं युद्ध को आवश्यक नहीं माना । इनकी दृष्टि में युद्ध निरर्थक था तथा गृह युद्ध को युद्ध न मानकर इन संशोधकीय विचारधारा के लेखकों ने युद्ध संगठित हत्या तथा मानव कसाई खाने की संज्ञा दी ।

यद्यपि इन संशोधकीय विचारधारा के लेखक 1940 के आस पास तक लोकप्रिय रहे परन्तु सैमुअल मॉरीसन तथा आर्थर श्लेजिगर जूनिया ने उपरोक्त मत का खण्डन किया । श्लेजिगर के विचार में इतिहास का रूप उद्धारक एवं निष्क्रेता का नहीं है और न ही मानव इतिहास से इसकी अपेक्षा करनी चाहिये । उन्होंने देशिक संघर्ष एवं इतिहास का दार्शनिक विश्लेषण करते हुये इतिहास को मानव जीवन की अनेक असमाधेय समस्याओं के सम्मिश्रण की संज्ञा देकर इतिहास को दुःखान्त तथा यदा कदा विनाशकारी भी बताया है । श्लेजिगर के विचार में इतिहास केवल भावना अथवा व्यक्तिगत मत के द्वारा परिचलित नहीं होता । मानव जीवन की समस्याओं एवं कठिन प्रश्नों को निष्पक्ष होकर विश्लेषण करना इतिहासवेत्ता का कार्य है । सैमुअल मॉरीसन ने युद्ध को मानव इतिहास का अपरिहार्य पक्ष माना है उनके विचार में युद्ध के द्वारा ऐसे प्रश्न का समाधान हो सकता था जिसकी उपलब्धि मानव हित में हो सकती थी । इन इतिहासकारों ने युद्ध को दासता से उत्तम माना और इस तथ्य को स्पष्ट किया कि युद्ध सदैव मानव इतिहास का अनिवार्य पक्ष रहा है क्योंकि सामाजिक संघर्ष नैतिकता की परिधि में रहकर भी मात्र तटस्थता के द्वारा उसका समाधान नहीं हो सकता है । उपरोक्त विभिन्न विश्लेषणों के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट होता है कि देशिक संघर्ष अमरीका के इतिहास में एक ऐसा मर्मस्थल है जिसका अध्ययन नैतिक, भावनात्मक आर्थिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोणों से किया गया है । निःसन्देह इतिहासकारों ने अपने विचारों का विश्लेषण

अपनी तर्कबुद्धि से किया है जो समयचक्र के साथ-साथ बौद्धिक परिवर्तन में लीन होती गई। इसमें संशय नहीं है कि मानव गृह युद्ध बुद्धि वेत्ताओं एवं इतिहासकारों के लिये विवाद का विषय रहा है और रहेगा।

देशिक संघर्ष के युद्ध मंच की दैनिकी

तिथियाँ

1861

मार्च 4

राष्ट्रपति लिंकन का उद्घाटन समारोह

अप्रैल 12

फोर्ट सुम्टर पर आक्रमण, गृह युद्ध का प्रारम्भ

पूर्वी युद्ध क्षेत्र

पश्चिमी युद्ध क्षेत्र

मई 10

लियोन द्वारा जैक्सन का
आत्मसमर्पण

जुलाई 21

बुलरन का युद्ध

नवम्बर 1

मैकलालन की मुख्य सेनाध्यक्ष
पद पर नियुक्ति

नवम्बर 19

हेलिक तथा ब्यूले की क्रमशः
मिसूरी तथा ओहायो के विभा-
गाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति।

1862

जनवरी 19

मिल स्पॅरिंग्स का युद्ध

फरवरी 6

सेनाध्यक्ष ग्रान्ट द्वारा हेनरी
दुर्ग पर अधिकार।

फरवरी 16

डोनेलसन दुर्ग का आत्मसमर्पण

मार्च 9

मॉनिटर तथा मरमैक का
युद्ध

मार्च 16

हेलिक की पश्चिमी सेना के
अध्यक्ष पद पर नियुक्ति।

मार्च 23

जैक्सन द्वारा कन्संटाउन
दुर्ग पर आक्रमण

मार्च	29		मिसीसीपी क्षेत्र में एल्बर्ट जॉन्स्टन की सेनापति पद पर नियुक्ति ।
अप्रैल	2	मनरो गढ़ी में मैक्लालन का आगमन	
अप्रैल	6-7		शिलो का युद्ध तथा अल्बर्ट जॉन्स्टन की मृत्यु ।
मई	1		संघ द्वारा न्यू ऑर्लिगेन्स (आरलीन्ज) पर अधिकार ।
मई	8	जैक्सन द्वारा मैक्डुअल में मिलराय एवं ग्रैनेक की पराजय	
मई	25	विन्चेस्टर में जैक्सन द्वारा बैक्स की पराजय	
मई	31	सेवन पाइन्स का युद्ध	
जून	1	राबर्ट ली. द्वारा सेना का नेतृत्व	
जून	8	जैक्सन द्वारा फ्रीमाँट की क्रास में पराजय	
जून	9	पोर्ट रिपब्लिक में जैक्सन द्वारा शील्श की पराजय	
जून	17	शेनानदो घाटी से जैक्सन का प्रस्थान	
जून	26	मैक्लालन के पार्श्व में जैक्सन का आगमन, सप्त दिवसीय युद्ध का आरम्भ - पोप की वर्जीनिया की सेना के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति	
जून	27		पश्चिम में राज्य संघ की सेनाओं का ब्रैग द्वारा संचालन
जुलाई	1	मोलवर्न हिल का युद्ध	
जुलाई	2	जेम्स नदी पर मैक्लालन का आगमन	
जुलाई	11	हेलेक की सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्ति	ग्रान्ट को टेनिसी तथा मिसी-सीपी सेनाओं का नेतृत्व
अगस्त			एडमण्ड कर्वीस्मिथ द्वारा केन्टकी पर आक्रमण ।

अगस्त 29-30	बुलरन का द्वितीय युद्ध	
सितम्बर		ब्रैग द्वारा मध्य टेनिसी पर आक्रमण
सितम्बर 4	ली का पेंटोमैक पारगमन कर मेरी लैण्ड में आगमन	
सितम्बर 5	पोप के स्थान पर मैक्लालन की पुनः नियुक्ति	
सितम्बर 17	एन्टीटेम का युद्ध	
सितम्बर 19	ली. द्वारा पेंटोमैक का पुनः पारगमन	
अक्टूबर 3		कारिन्थ का युद्ध
अक्टूबर 8		पैरीविल का युद्ध
अक्टूबर 26	मैक्लालन का पेंटोमैक पारगमन	
नवम्बर 7	बर्नसाईड की मैक्लालन के स्थान पर नियुक्ति	
नवम्बर 24		ग्रान्ट का विक्सवर्ग की ओर प्रथम संचालन
दिसम्बर 13	फ्रेडरिक्सवर्ग का युद्ध	
दिसम्बर 29		शर्मन की चिकेसो में पराजय
दिसम्बर 31		मरफीजवर्गो का युद्ध
1863		

जनवरी 26	हुकर की बर्नसाईड के स्थान पर नियुक्ति	
फरवरी		याजू अभियान
अप्रैल 30		ग्रान्ट का मिसीसीपी पारगमन
मई 2-4	चांस्लर्जविल का युद्ध	पोर्ट जिब्सन पर ग्रान्ट का अधिकार
मई 10	स्टोनवेल जैक्सन का देहान्त	
मई 12		रेमंड का युद्ध
मई 16		चैम्पियन हिल का युद्ध
मई 17		पेंम्बर्टन का विक्सवर्ग की ओर निष्क्रमण

जून	15	ली. का मेरीलैण्ड में आगमन	
जून	28	हुकर के स्थान पर मीड की नियुक्ति	
जुलाई	1-3	गैट्सबर्ग का युद्ध	
जुलाई	4		विक्सबर्ग का आत्मसमर्पण
जुलाई	9		पोर्ट हडसन का आत्मसमर्पण
जुलाई	14	ली का पेटोमेक पारगमन का अपसरण	
सितम्बर	7-8		ब्रैग द्वारा चेटनूगा का परित्याग
सितम्बर	19-20		ब्रैग द्वारा चिकेमोंगा में रोजक्रान की पराजय।
अक्टूबर	16		ग्रान्ट का मिसीसीपी सैनिक क्षेत्र का अध्यक्ष बनना तथा शर्मन का टेनिसी क्षेत्र का।
अक्टूबर	19	मीड रेपहेनेक की ओर अग्रसरित	
नवम्बर	1		ब्रैग ने वर्नसाइड के विरुद्ध नाक्सविले में लांगस्ट्रीट को भेजा
नवम्बर	24-25		चेटनूगा का युद्ध
नवम्बर	26	मीड द्वारा रेपिडॉन का पारगमन	
दिसम्बर	1	मीड का उत्तरी रेपिडॉन की ओर अपसरण	
1864			

फरवरी	14		शर्मन का मरीडन में आगमन
मार्च			बैंक का रेड रिवर अभियान
मार्च	9	ग्रान्ट की मुख्य सेनाध्यक्ष पद पश्चिम में ग्रान्ट के स्थान पर पर नियुक्ति	शर्मन की नियुक्ति
मई			रेड रिवर अभियान की असफलता

मई 4	ग्रान्ट का रेपीडान पारगमन	शर्मन का चेटनूगा से अटलांटा प्रस्थान
मई 5-6	विल्डरनेस का युद्ध	
मई 8-12	स्पाट सिल्वेनिया कोर्ट हाऊस की परिधि में युद्ध	
मई 12	जे० ई० वी० स्टुअर्ट की मृत्यु	
मई 16	बोरगार द्वारा बटलर को सीमाबद्ध करना	
जून 1-3	कोल्ड हार्वर का युद्ध	
जून 12	जेम्स रिवर पारगमन करने हेतु ग्रान्ट का निष्क्रमण	
जून 13	शेनान्दो घाटी का युद्ध	
जून 15	ग्रान्ट की सेना का जेम्स नदी के दक्षिणी तट पर आगमन	
जून 15-18	पीटरसवर्ग पर आक्रमण	
जून 27		केनिसो पर्वत का युद्ध
जुलाई 9	जुवेल एण्डर्सन अर्ली द्वारा वेलेस की पराजय	
जुलाई 11	अर्ली का वाशिंगटन के निकट पहुँचना ।	
जुलाड 14	अर्ली का पेटोमेक का पुनः पारगमन	
जुलाई 17		जानस्टन के स्थान पर हूड की नियुक्ति
जुलाई 20		पीच टी का युद्ध
जुलाई 22		अटलांटा युद्ध
जुलाई 30	पीट्सवर्ग माईन की असफलता	
अगस्त 5	मोवाईल वे का युद्ध	
अगस्त 7	शरीडान को शेनान्दो घाटी का सैनिक नेतृत्व	
सितम्बर 2		हूड का अटलांटा परित्याग
सितम्बर 19	विनचेस्टर का युद्ध	
सितम्बर 22	फिशार्ज हिल का युद्ध	

178/अमरीका का इतिहास

सितम्बर 29		हुड का शर्मन के संचार के विरुद्ध प्रस्थान
नवम्बर 15		शर्मन का अटलांटा से जार्जिया की ओर प्रस्थान और टामस को टेनिसी में ही स्थित रखना
नवम्बर 20		बोरगार का टामस के विरुद्ध हुड को आदेश ।
नवम्बर 30		फ्रैंकलिन का युद्ध
दिसम्बर 15-16		नेशविल का युद्ध
दिसम्बर 21		शर्मन का सेवाना में प्रवेश
1865		

फरवरी 1		शर्मन का कैरोलीना के द्वारा प्रस्थान
फरवरी 9	ली की उच्च सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्ति	
फरवरी 17		शर्मन का कोलम्बिया में आगमन
फरवरी 18		चार्ल्सटाउन की पराजय
फरवरी 22		विलमिंग्टन की पराजय
फरवरी 27	शेरीडन का घाटी की ओर प्रस्थान	
मार्च 19		वेन्टनविले का युद्ध
मार्च 23		शर्मन का गोल्डसवरो में आगमन
अप्रैल 1	फाइव फोक्स का युद्ध	
अप्रैल 2	ली का रिचमाण्ड परित्याग	
अप्रैल 6	सेलस क्रीक का युद्ध	
अप्रैल 9	ली का एपोमैटक्स हाउस में आत्मसमर्पण	
अप्रैल 14	राष्ट्रपति लिंकन की हत्या	
अप्रैल 26		जान्स्टन का ग्रीन्सवरो में आत्मसमर्पण
मई 10	जेफरसन डेविस का बन्दी बनाया जाना ।	



पूँ जीवाद

अध्याय 6

पुर्न निर्माण

देशिक संघर्ष ने दो मुख्य प्रश्नों का समाधान कर अमरीकी पुर्ननिर्माण युग का मार्ग प्रशस्त किया। उपरोक्त दो प्रश्न थे—दासता एवं संघीय शासन की स्थापना यद्यपि दासता उन्मूलन तथा संघीय शक्ति के अधिकार का प्रभुत्व देशिक संघर्ष ने निर्णयात्मक रूप से तय कर दिया किन्तु इसके पश्चात् राज-नैतिक, समाजिक, तथा आर्थिक कार्य प्रणाली के स्वरूप की व्याख्या समुचित रूप से नहीं हो सकी।

अब्राहम लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका को देशिक संघर्ष अथवा गृह युद्ध के द्वारा स्थायित्व प्रदत्त किया और राष्ट्र भविष्य की रूप रेखा पुर्ननिर्माण कार्य में निहित की। दुर्भाग्यवश उस महान अमरीका के राष्ट्रपति की अकस्मात् हत्या ने अमरीका के राष्ट्र प्रेमी देशवासियों को हतप्रभ कर दिया। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात् दक्षिण के प्रति किसी प्रकार के मतभेद, वैमनस्य एवं दंड नीति का प्रयोग नहीं किया जायेगा। राष्ट्रपति लिंकन ने दिसम्बर 8, 1863 को राज्य क्षमता एवं पुननिर्माण की घोषणा कर अपने शब्दों को प्रयोगात्मक रूप देने की चेष्टा की। लिंकन ने सार्वजनिक क्षमता नीति का परिपालन किया किन्तु उन्होंने सरकारी अधिकारियों तथा सैनिक अधिकारियों के प्रति राजभक्ति एवं दासता उन्मूलन की घोषणा को स्वीकृति देकर मान्यता की शपथ को अनिवार्यता प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी घोषणा के अन्तर्गत इस योजना को प्रेषित किया कि यदि राजभक्ति की शपथ लेने वाले 1860 के जनता मताधिकार दस प्रतिशत हो जाये तो उन्हें प्रान्तीय सरकार गठन करने की अनुमति मिल जानी चाहिये। लिंकन की इस दस प्रतिशत योजना को उत्तर ने सामान्य रूप से स्वीकार किया किन्तु उग्रवादी गणतान्त्रीय सदस्यों ने इस योजना का विरोध किया। परिणामस्वरूप इन विरोधी सदस्यों ने जुलाई 2, 1864 को 'वेड-डेविस'

अधिनियम पारित किया जिसके अन्तर्गत वह प्रान्तीय सरकार स्थापित हो सकती थी जिसमें आधे नागरिक राजभक्ति की शपथ ले चुके थे तथा जिन लोगों ने राज्य संघ कॉन्फ़ेड्रेसी की ओर से युद्ध किया था वे समस्त लोग मतदान एवं सरकारी पदों से बहिष्कृत किये जाने चाहिये थे। राष्ट्रपति लिंकन ने इस अधिनियम के विरोध में निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति के इस कार्य ने उग्रवादी गणतंत्रवादियों तथा स्वयं में बृहत् मतभेद उत्पन्न कर दिया था। सम्भवतः यह स्थिति और अधिक गम्भीर हो जाती यदि राष्ट्रपति जीवित रहते। निःसन्देह राष्ट्रपति की मृत्यु ने दक्षिण में अपने दुखान्त समय में अपना एक शक्तिशाली मित्र खो दिया। अप्रैल 15, 1865 में एंड्रू जानसन अमरीका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने लिंकन की दस प्रतिशत योजना के अन्तर्गत लुईसियाना, अरकान्सा तथा टेनिसी को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त वर्जीनिया की रम्प सरकार को भी स्वीकार कर लिया गया। मई 29, 1865 को नव राष्ट्रपति ने दो घोषणायें की—प्रथम राज्य क्षमता तथा द्वितीय उत्तरी कैरोलीना के राजनैतिक पुनः निर्माण सम्बन्धी योजना दिसम्बर, 1865 में जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ तब उपरोक्त चार प्रान्तीय सरकारों की मान्यता के अतिरिक्त राष्ट्रपति जानसन ने उत्तरी कैरोलीना, दक्षिणी कैरोलीना, जार्जिया, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसीपी तथा टैक्सास की सरकारों को मान्यता प्रदान कर स्थापित कर दिया था।

राष्ट्रपति के इस पुर्ननिर्माण कार्य के प्रति उग्रवादियों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस के उग्रवादियों में प्रतिनिधित्व सभा के थेडस स्टीवेन्स तथा सीनेट के चार्ल्स समनथ थे, इनका विरोध दक्षिण से निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर था क्योंकि अधिकतर वहाँ के प्रतिनिधि वह लोग थे जो दक्षिण में राज्य संघ के प्रति सक्रिय रूप से कार्यरत रहे थे।

कृष्ण विधि संग्रह (ब्लैक कोड्स)

इसके अतिरिक्त कृष्ण विधि संग्रह (ब्लैक कोड्स) के कारण भी कांग्रेस के सदस्यों में आक्रोश था। इस विधि संग्रह के अन्तर्गत नीग्रो लोगों के नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। 1866 में दक्षिण के जातीय उपद्रवों ने इस लक्ष्य को स्पष्ट किया कि देशिक संघर्ष के निष्कर्ष का आदर उत्तरवासी नहीं करना चाहते थे। इस नीग्रो समस्या की अग्नि को राष्ट्रपति जानसन के “फ्रीड मैन्सव्यूरो” के अधिकारों के प्रति निषेधाधिकार ने और प्रज्वलित कर दिया। फ्रीड मैन्स व्यूरो नीग्रो लोगों की दासता से स्वतंत्रता परिवर्तीकाल के लिये एक सुरक्षात्मक संस्था थी। राष्ट्रपति जानसन

ने इस संस्था का निषेध किया क्योंकि उनके विचार में यह व्यूरो अपव्यय, अनुपयोगी एवं असंवैधानिक था। इसी मध्य कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम पारित कर नीग्रो जाति को संयुक्त राष्ट्र अमरीका का नागरिक घोषित किया तथा उन्हें समान नागरिक अधिकार प्रदत्त किये। राष्ट्रपति जानसन ने इस पर भी निषेधाधिकार प्रयोग किया किन्तु इसके उपरान्त भी अप्रैल 9, 1866 को यह अधिनियम पारित किया गया। 1883 में इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर नीग्रो लोगों को संघीय सुरक्षा से वंचित किया।

उग्रवादी योजना

अमरीका की कांग्रेस के दोनों सदनों में उग्रवादियों का बहुमत था और एक नियमित योजना के अन्तर्गत उन्होंने राष्ट्रपति जानसन के कार्यक्रमों का विरोध प्रकट करना आरम्भ किया। अपनी योजना को कार्यान्वित करने हेतु दोनों सदनों द्वारा संयुक्त पन्द्रह सदस्यों की समिति संगठित की गई। इस समिति का कार्य दक्षिण सम्बन्धी पूर्ण प्रश्न का अन्वेषण करना था। तत्पश्चात् कांग्रेस ने राष्ट्रपति जानसन के निषेधाधिकारों के उपरांत भी फ्रीडमैन्स व्यूरो बिल पारित किया जिसके द्वारा इस संस्था की अवधि और अधिकार में वृद्धि की गई। संयुक्त समिति ने अनेक स्थानों पर अपने अन्वेषण के पश्चात् ये प्रमाणित किया कि दक्षिण संघ के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता था। तदोपरांत इस समिति ने संविधान में चौदहवाँ संशोधन प्रेषित किया जिसमें किंचित परिवर्तन के पश्चात् कांग्रेस ने पारित कर दिया। इस संशोधन में नागरिक अधिकार समानता, स्वतंत्रता, सम्पत्ति को स्पष्ट किया। इस संशोधन के द्वितीय भाग में चुनाव सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये जिसका राजनैतिक अर्थ दक्षिणीशक्ति को सीमित करना था। जब यह संशोधन प्रांतीय सरकारोंकी स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया तो दक्षिण के राज्यों ने टेनिसी को छोड़कर समस्त राज्य राजनैतिक सरकारों ने इसे अस्वीकृत कर दिया। कांग्रेस ने टेनिसी को पुनः संघ में सम्मिलित कर अन्य दक्षिणी सरकारों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

कांग्रेस योजना

इसी मध्य राजनैतिक समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति जानसन का स्पष्ट विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। अमरीकी कांग्रेस ने अपनी योजना के अन्तर्गत जानसन के विरोध में दो कार्य किये। प्रथम कार्यालय अवधि अधि-

नियम' (टेनयुअर ऑफ आफिस ऐक्ट) जानसन के निषेधाधिकार के उपरान्त भी पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति नागरिक अधिकारियों के निष्कासन के अधिकारों पर अंकुश लगा दिया। वास्तव में यह अधिनियम युद्ध सचिव एडविन स्टैटन के प्रति सुरक्षात्मक उपाय था। एडविन ने उग्रवादियों का पूर्ण सहयोग लिया था। द्वितीय विधेयक 'सेना अधिनियम' (आर्मी ऐक्ट) था जिसका ध्येय राष्ट्रपति की सैन्य सम्बन्धी अधिकारों पर अंकुश लगाना था।

मार्च 1867 में कांग्रेस ने राजनैतिक पुनर्निर्माण हेतु अधिनियम पारित किया। इसके अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया कि टेनिसी के अतिरिक्त राज्य संघ की कोई सरकार न्याय संगत नहीं थी। दक्षिण का समस्त क्षेत्र 5 भागों में विभक्त किया गया और प्रत्येक भाग एक सेनापति (मैजर जनरल) के आधीन किया गया। यह क्षेत्र यदि नीग्रो मताधिकार तथा संविधान के 14वें संशोधन को मान्यता देना स्वीकार कर लेते तो उन्हें पुनः संघ में सम्मिलित किया जा सकता। इसके साथ ही राज्यनिष्ठा की शपथ में इतने कठोर परिवर्तन किये गये कि लगभग दक्षिण के 2 लाख नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया गया। कांग्रेस ने 15वाँ संशोधन के अन्तर्गत नीग्रो मताधिकार को सुरक्षित किया। कांग्रेस के अधिनियमों के प्रति अमरीका के उच्चतम न्यायालय के अधिकारों को सीमित किया सम्भवतया अमरीकी इतिहास में यह प्रथम दृष्टांत था जिसमें कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के वैधानिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया।

महाभियोग :

उग्रवादी गणतंत्रीय दक्षिणी राज्यों में अपने राजनैतिक नियंत्रण हेतु अपने कार्य को संगठित करने में चेष्टारत थे, राष्ट्रपति जानसन के निषेधाधिकार के द्वारा उग्रवादियों ने कार्य प्रणाली में अवरोध उत्पन्न करने की चेष्टा की। राष्ट्रपति जानसन के इस हस्तक्षेप के कारण उग्रवादी राष्ट्रपति से रुष्ट थे उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य संघ का सहयोगी, अनभिज्ञ राजनीतिज्ञ तथा मद्य घोषित किया। उग्रवादियों ने राष्ट्रपति जानसन पर ग्यारह आरोप घोषित किये परन्तु कोई ऐसा भीषण आरोप दृष्टिगोचर नहीं होता था जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग आरम्भ किया जाये। अन्ततः युद्ध सचिव स्टैटन को पदच्युत करने के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रपतिके अभियोग की गतिविधियों से जनता को यह स्पष्ट होने लगा कि पूर्ण समस्या राजनैतिक परिधि में स्थिति थी। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पदच्युत

करने हेतु दो तिहाई मतों की आवश्यकता थी। अमरीका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साल्मन चेज ने सीनेट की अध्यक्षता की और राष्ट्रपति जानसन दो तिहाई मत में एक मत कम होने के कारण दोषमुक्त हो गये। नवम्बर, 1868 में नये राष्ट्रपति के चुनाव में यूलिसिस ग्रांट अमरीका के नये राष्ट्रपति घोषित किये गये।

पुर्ननिर्माण समीक्षा

कांग्रेस की दक्षिण पुर्ननिर्माण की नीति ने नीग्रो जाति को बहुत अधिक सहयोग वास्तविक रूप में प्रदत्त नहीं किया। इसके विपरीत श्वेत वर्गीय लोगों ने अधिक से अधिक दक्षिण में राजनैतिक एवं आर्थिक लाभ की चेष्टा की। इसी मध्य नीग्रो जाति को राजनीति से बहिष्कार करने की चेष्टा कुछ गुप्त संस्थाओं द्वारा की गयी। इनमें प्रमुख गुप्त संस्था 'कूलक्स क्लान' थी। इस संस्था की नीग्रो विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु कांग्रेस ने अधिनियम पारित किये। कांग्रेस के दक्षिण पुर्ननिर्माण के कार्यों में श्वेत वर्गीय लोगों ने पूर्णरूपेण अवरोध उत्पन्न कर दक्षिण पुर्ननिर्माण को अकृतिकरण का स्वरूप प्रदत्त किया। दक्षिण को राजनैतिक स्थायित्व तो न प्राप्त हो सका परन्तु इसके विपरीत दक्षिण का युद्धोपरान्त आर्थिक विकास भी संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं हो सका। फलस्वरूप अमरीका में उद्योगपतियों ने राजनैतिक एवं आर्थिक ह्रास को दृष्टिगोचर कर अमरीका के उद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

अमरीका के इतिहास के छात्रों को गृह युद्ध काल तथा पुर्ननिर्माण युग के वर्षों में विपरीत अन्तर प्रतीत होता है क्योंकि संघर्ष के वर्ष वीरता और आदर्शवाद को प्रस्तुत करते थे तथा देशिक संघर्ष के द्वारा एक नव अमरीकी राष्ट्रियता उभरी जिसने पुरानी प्रादेशिक राज्य भक्ति का स्थान ग्रहण किया। अमरीकी मानव समाज के मतभेद तथा वर्गीकरण और आर्थिक महँगाई ने एक दीर्घ समय तक जनता को त्रस्त किया था। वह देशिक संघर्ष की ज्वाला में भस्म होकर ने अमरीका को एक यथार्थ रूप में संयुक्त राष्ट्र बना कर विश्व के वरिष्ठ राष्ट्र में स्थान प्राप्त करने का अवसर दिया।

इसके पुर्न निर्माण युग का चित्र विल्कुल विपरीत था। यदि युद्ध काल वीरत्व से प्रभावित था तो दूसरी ओर युद्धोत्तर काल कूटता और स्वार्थीपन से समन्वित था; जिसमें लोग देश के हित से वंचित होकर निजी स्वार्थों से अविभूत थे। उन्होंने अंश मात्र भी देश अथवा राष्ट्र के हित की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप उत्तर, दक्षिण, श्वेत तथा नीग्रो उस ज्वाला से

अवगुंठित हो गये जिसके द्वारा ही क्रान्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सकता था। अमरीका को एक सूत्र में बंधित करने हेतु देशिक संघर्ष के अतिरिक्त सम्भवतया कोई अन्य विकल्प न था। बहुत कम इतिहासकार 1890 और 1930 के दो कालों के विपरीत अन्तर को अस्वीकार करते हैं और अधिकतर विद्वान जो इस समय में हुये, उन्होंने पुनर्निर्माण की और भी अधिक कटु व्याख्या की कोलम्बिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम डनिंग ने पुनर्निर्माण इतिहासलेखन शाखा की स्थापना की। इतिहास लेखकों ने इस तथ्य का पुष्टिकरण करना चाहा कि युद्धोत्तर काल त्रासिक एवं करुणता में पूर्ण होने के कारण देश का हित सोचने वाले लोग क्षणिक देर के लिये 'दुष्ट शक्तियों' से पराजित कर दिये गये। अमरीका के इतिहास में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों पर तिष्ठित व्यक्ति कभी भी इतने भ्रष्ट, दम्भी एवं क्रूर न थे जितने संघर्षोपरान्त शासकीय स्थानों पर आसीन थे।

डनिंग विचारधारा की व्याख्या दो व्यक्तियों पर निर्भर है। सर्वप्रथम कार्य था कि विना किसी प्रतिशोध की भावना के दक्षिण को संघ के साथ तुरन्त सम्मिलित किया जाये। तर्क था कि अधिकतर दक्षिणवासियों ने मान्य रूप से अपनी पराजय स्वीकार की और संघ के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। द्वितीय कार्य था कि स्वतंत्र वासियों का उत्तरदायित्व श्वेत दक्षिण वासियों को सौंपा जाये। इतिहासकारों का मत था कि नीग्रो जाति का अमरीकी समाज में समानता का अधिकारों के स्तर पर समन्वय नहीं किया जा सकता क्योंकि नीग्रो जाति को अमरीकी समाजिक व्यवस्था ने दासता तथा अधर जाति स्थिति के कारण अनुकूल समाजिक स्तर प्रदत्त नहीं किया।

उपरोक्त दो विचारधाराओं के अधीन डनिंग मत के इतिहासकारों ने पुनर्निर्माण को साधुता एवं दुष्टता के संघर्ष की संज्ञा दी। इन विद्वानों के अनुसार एक ओर एंड्रू जानसन सहमत गणतन्त्रीय तथा उत्तरी एवं दक्षिणी लोकतन्त्रीय, सच्चरित शक्तियाँ निहित थी और यह लोग समय की गति का ध्यान रखते हुये इस तथ्य की यथार्थता से अवगत थे कि सामाजिक संगठन हेतु दक्षिणी युद्ध एवं वैमनस्य की भावना से निवृत्त हो जाना चाहिये। उनके प्रति एव सदयता सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये। दूसरी ओर अमानवता की भावना से परिपूर्ण उग्रवादी एवं प्रतिशोधी गणतन्त्रीय वर्ग था जो दक्षिण के प्रति किंचित मात्र भी सद्भावना नहीं रखता था। इन दोनों परस्पर विरोधी शक्तियों के मध्य निस्सहाय, असमर्थ एवं अनाभिज्ञ नीग्रो थे जो केवल उग्रवादी गणतन्त्रीय राजवेत्ताओं की स्वार्थी लिप्सा के आर्हेर थे।

तथाकथित विचारधाराओं के फलस्वरूप डनिंग के मतानुयायी इस

निष्कर्ष पर पहुँचे कि दक्षिण में उग्रवादी प्रान्तीय सरकारों की नितान्त असफलता थी क्योंकि इन प्रांतीय सरकारों में अशिक्षित नीग्रो सम्मिलित किये गये थे जो स्वशासन के उत्तरदायित्व से किंचित परिचित नहीं थे। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की सरकारें अत्यधिक व्ययी थी क्योंकि इसके सदस्य भ्रष्टाचार के द्योतक थे और इस विचारधारा के एक इतिहासकार क्लाड बॉउर ने दक्षिण को भ्रष्टाचार, व्यभिचार तथा अनैतिकता का केन्द्र माना। दक्षिण में सभ्य श्वेत वासियों ने नीग्रो तथा दक्षिण में अन्य स्वार्थनिहित लोगों के कारण स्वयं को संगठित किया और अनेक प्रांतों में उग्रवादी सरकारों को भंग कर सरकारों का निर्माण किया। इस प्रकार 1876 के राष्ट्रपति चुनाव के मध्य सुरक्षित केवल तीन प्रांतों में उग्रवादी सरकारों का नियंत्रण रह गया था। चुनाव के तत्पश्चात् हेज ने दक्षिण से संघीय सेना को वापस बुलाकर अन्तिम तीन उग्रवादी शासनों को समाप्त कर दिया और इस प्रकार पुनर्निर्माण के युग के दुखान्त नाटक का अन्त हुआ।

19वीं शताब्दी के पश्चात् तीन दशकों तक डनिंग की विचारधारा को अमरीकी इतिहासकारों ने महत्व दिया। इस विषय में अनेक प्रवन्धों ने दक्षिणी प्रांतों के अध्ययन की व्याख्याओं के व्यक्तिगत मतभेद होने पर भी इस तथ्य को स्पष्ट किया, कि पुनर्निर्माण का युग निराशाजनक एवं एक अधः पतन का युग था। इस पुनर्निर्माण के युग ने न केवल दक्षिणी दो दलीय पद्धति को समाप्त किया वरन इसने कटुता एवं जातीय वैमनस्यता को बनाये रखने में भी योगदान दिया।

एलवर्ट मूर ने डनिंग परम्परा की व्याख्या करते हुए 1865 एवं 1877 के मध्य पुनर्निर्माण के युग को विजयी उत्तर का पराजित दक्षिण को दण्डित करने का साधन बताया। मूर के अनुसार उत्तर का व्यवहार किसी भी रूप में सौम्य एवं सहृदय नहीं था। मूर के विचार में नीग्रो लोगों को मताधिकार देना सन्देहात्मक एवं अविश्वसनीय युग की मुख्य घटना थी क्योंकि इसके द्वारा दक्षिण की आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं में कटुता उत्पन्न होती चली गई। एलवर्ट मूर ने देशिक संघर्ष को अपने अध्ययन में उत्तर की विध्वंसक नीतियों की प्रतिक्रिया बनाया जिसके द्वारा दक्षिण सम्बन्ध विच्छेद एवं युद्ध करने पर बाध्य हुआ। इस इतिहासज्ञ ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि पुनर्निर्माण के युग में अस्त्र शस्त्र की विजय ने वाग्पटुता एवं लेखनी के द्वारा दक्षिण विजय आरम्भ कर दी। अब्राहम लिंकन के दुखांत मृत्युपरांत ईश्वर के रविवार को अनुष्ठाताओं ने अपने धर्मग्रन्थ से जनता को यह आश्वासन दिया कि ईस्टर की इच्छा से वह राष्ट्रपति नहीं रहा जिसका हृदय इतना क्षमाशील

था कि वह दक्षिण को दंडित नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त ईश्वरीय आवरण में धर्मप्रचारकों ने दक्षिण को कठोर दंड देने का आह्वान एवं अश्वासन दिया। प्रोफेसर पॉलवक ने इसका पुष्टिकरण करते हुए कहा कि युद्धोपरांत धर्म स्थानों में असहिष्णुता, वैमनस्य एवं अक्षमाशीलता सर्वाधिक विद्य थी। इस प्रकार प्रोफेसर वक ने अपनी पुस्तक 'द रीड टू रियूनियन' ने पुनर्निर्माण को युद्ध से अधिक विध्वंसक की संज्ञा दी। इन विद्वानों ने पुनर्निर्माण को दक्षिण के प्रति राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक घनिष्टता का द्योतक समझा। उसके अनुसार दक्षिण भी पुनर्निर्माण के अंधकार युग की पैतृकता का भुगतान कर रहा था।

1920 के पश्चात इतिहासकारों ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की घटनाओं को नव दृष्टिकोण से अध्ययन करना आरम्भ किया। इन संशोधकीय विचारधाराओं के इतिहासकारों ने पुनर्निर्माण के युग को उतना अनुपयुक्त नहीं समझा जितना कि इससे पूर्व समझा गया था। इस मत के विद्वान प्रगतिशील अमरीकी इतिहास लेखन से प्रभावित थे और इस प्रकार वह डनिंग मत के अध्ययन से सहमत नहीं थे।

अधिकतर संशोधकीय विचारवालों ने डनिंग मत के मौलिक तथ्यों को तथा उनके अध्ययन की प्राप्ति को स्वीकार किया परन्तु इन दोनों मतों में वैचारिक भिन्नता होने का कारण उनकी दृष्टिकोण एवं व्याख्या में था। डनिंग मत वालों से भिन्न संशोधकीय विचारवाले 1865 और 1877 के मध्य घटित घटनाओं को एक नैतिक नाटक के रूप में मान्यता नहीं देते थे। क्योंकि उनके विचार में पुनर्निर्माण सदयता एवं दुष्टता श्वेत एवं नीग्रो लोकतंत्रिक एवं उग्रवादी गणतंत्रीय के बीच संघर्ष नहीं था। न ही संशोधकीय विचार वाले इस विचार से सहमत थे कि स्वतंत्रवासियों का उत्तरदायित्व श्वेत दक्षिणीवासियों को दिया जाये। इन भिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए यह समझा जा सकता है कि संशोधकीय व्याख्या का स्वरूप डनिंग मत से व्याख्या स्वरूप भिन्न है।

डनिंग दृष्टिकोण के विरुद्ध प्रतिक्रिया फ्रांसिस सिम्किन्स के लेख से प्रकट होती है। फ्रांसिस सिम्किन्स एक प्रसिद्ध दक्षिणी इतिहासकार थे जिन्होंने रावर्ट वूडी के साथ 1932 में लेख लिखा जो संशोधनवादी राज्य अध्ययन के प्रथम लेखों में था। यह सामने लाते हुए कि अधिकतर दक्षिणवासी अपना जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत करते थे, उन्होंने इस युग की कई रचनात्मक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सिम्किन्स इस तथ्य से सहमत नहीं थे कि उग्रवादी योजना उग्रपंथी शब्द के स्वीकार अर्थ में उग्र था। वास्तव में वे इसलिये असफल हुये क्योंकि उन्होंने नीग्रो लोगों को एक स्थाई आर्थिक आधार प्रदत्त नहीं किया।

सिम्किन्स के विचार में दक्षिण के इतिहास लेखन में दक्षिण में राजनैतिक विकास तथा अन्य सुव्यवस्थित आर्थिक नीति को इतिहासकारों ने अपनी पक्षपाती व्याख्या के द्वारा निर्मूल सिद्ध कर दिया। सिम्किन्स के विचार में कृषि सुधार पुनर्निर्माण युग की उपलब्धि थी। इसके साथ ही नवीन व्यापारिक पद्धति ने भी उग्रवादी परन्तु रचनात्मक विकास में सहयोग प्रदान किया। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि समय के साथ दक्षिण में स्वहितों के लिये आने वाले उत्तरवासियों के प्रति 20वीं शताब्दी में व्यवहार परिवर्तन होने लगा। सिम्किन्स ने इतिहासकारों का आह्वान किया कि उनको निष्पक्ष होकर तर्क एवं विवेकपूर्ण अध्ययन के द्वारा पुनर्निर्माण की व्याख्या करनी चाहिये।

यद्यपि संशोधकीय विचारधारा के लेखकों में स्वयं इतना मतभेद था कि जितना वह डनिंग मत के प्रति रखते थे। परन्तु उनके पारस्परिक दृष्टिकोण में एक सीमा तक समानता थी जिसकी परिधि में उनकी एकता का सामंजस्य प्रतीत होता था। अपितु इनके अनुसार इन सरकारों ने कुछ लाभकारी कार्य भी किये। उग्रवादी सरकारों ने सामाजिक सुधार और शिक्षा, न्याय पद्धति तथा नागरिक प्रशासन में विशेष कार्य किये। इसके साथ ही इनके प्रशासन में श्वेत, नीग्रो को राजनैतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता के परिकल्पनिक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की। संशोधकीय लेखकों ने पुनर्निर्माण युग में नीग्रो लोगों का चित्रण एक पृथक रूप में चित्रित किया। क्योंकि इनके अनुसार युद्ध पश्चात् दक्षिणी विकास में नीग्रो लोगों की अनभिज्ञता एवं अशिक्षा के कारण अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। इन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते हुये इस तथ्य को इंगित किया कि दक्षिणी राज्यों में नीग्रो लोग विधान सभाओं का नियंत्रण नहीं करते थे और न ही कोई नीग्रो राज्यपाल वहाँ पर नियुक्त था। केवल दो नीग्रो संयुक्त राज्य सीनेट तथा 15 नीग्रो "प्रतिनिधित्व सदन" (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव) के सदस्य थे। इस सांख्यिकी से यह स्पष्ट था कि पुनर्निर्माण काल में नीग्रो अपने राजनैतिक कार्यों द्वारा कहाँ तक प्रभावित हो सकते थे ?

यदि उपरोक्त विचारधारा के अनुसार नीग्रो वर्ग उग्रवादी सरकारों से प्रभावित नहीं था, तो क्या ये तथाकथित सरकारें इस वर्ग का समर्थन प्राप्त करती रहीं थी। इस प्रश्न के उत्तर में संशोधकीय विचारकों के अनुसार इन सरकारों ने अपनी स्वार्थलिप्सा, तथा राजनैतिक शक्ति क्षुधा को संचित करने हेतु नीग्रो लोगों का चुनाव समर्थन प्राप्त किया। संशोधकीय लेखकों ने इस आक्षेप को भी अस्वीकार किया कि उग्रवादी सरकारें अत्यन्त व्ययी एवं भ्रष्ट थी। निःसन्देह, युद्धोपरान्त व्यय में वृद्धि हुई। परन्तु इसका कारण युद्धोत्तर प्रशासन व्यवस्था की आवश्यक आवश्यकतायें थी। इसी कारण पुनर्निर्माण युग

में आर्थिक प्रणाली नियुक्त हो गयी। इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप राजनैतिक संघर्षों में वृद्धि होती गई।

संशोधकीय अध्ययन में इस बात की भी समीक्षा की गई कि पुर्ननिर्माण युग की इस कठिन एवं जटिल समस्या का कारण जातिवाद ही था। पुर्ननिर्माण के समय भूतपूर्व "विग" सदस्यों ने गणतंत्रीय दल में प्रवेश ले लिया था। इन रूढ़िवादियों ने प्रथम तो नीग्रो लोगों को चुनाव मत के बदले नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार देने का वचन दिया। लोकतांत्रिक दल में निम्न स्तरीय श्वेतवर्गी समुदाय से नीग्रो लोगों ने सामाजिक एवं आर्थिक स्थित के कारण भय-भीत होकर जातिवाद का नारा बुलन्द किया। शनैः-शनैः रूढ़िवादी गणतांत्रिक दल से विकल होकर लोकतांत्रिक दल के प्रति आकर्षित होने लगे। इस राजनैतिक समझौते में नीग्रो लोगों को एकाकी एवं पृथक कर दिया गया। इसके कारण दक्षिणी राजनीति का घुवीकरण, जातीय स्तर पर हुआ और श्वेतवर्गीय लोगों ने लोकतांत्रिक दल को जन्म दिया। निम्न वर्गीय श्वेत वर्गीय लोगों का एकमात्र उद्देश्य दक्षिण को गौरवर्णीय प्रदेश बनाना था। उच्च वर्गीय गोरे भी एक राजनैतिक दल से संतुष्ट थे क्योंकि इसके द्वारा उनको आर्थिक विकास में लाभ पहुँचता था।

संशोधकीय लेखकों के अनुसार पुर्ननिर्माण का अन्त व्यापार एवं उद्योग की उपलब्धि थी। 1877 के समझौते में श्वेतवर्गीय लोगों को राजनैतिक स्वतंत्रता एवं निरहस्तक्षेप की नीति का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार दक्षिण अपने उद्धारक एवं मुक्तिदाता वर्ग के कारण एक राजनैतिक परकोटा बन गया।

पुर्ननिर्माण इतिहास लेखन में 1950 के प्रारम्भिक वर्षों में एक नवीन मत ने जन्म लिया जिसको नव संशोधकीय विचार धारा कहा जाने लगा। इन इतिहासकारों ने पुर्ननिर्माण का आधार आर्थिक न मानकर नैतिकता को इसकी आधार शिला माना। यद्यपि नव संशोधकीय मत के विद्वानों ने संशोधकीय विचारधारा से बहुत अधिक मतभेद प्रकट नहीं किया, अपितु इन्होंने पुर्ननिर्माण युग को संशोधकीय विचारधारा के सदृश आर्थिक आधार पर ही इसकी व्याख्या नहीं की। नव संशोधकीय विचारकों के अनुसार गणतंत्रीय दल केवल व्यापारिक हितों से संगठित नहीं था वरन् इसके अन्तर्गत कुछ व्यक्तिगत तथा ऐसे भी वर्ग थे जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक विचारधाराये सर्वथा पृथक थी। इन लेखकों ने जातिवाद को एक नैतिक समस्या माना और उनके अनुसार अमरीकी समाज में नीग्रों समस्या देशिक संघर्ष के उपरान्त भी एक दुष्कर प्रश्न था जिसका समाधान अत्यन्त कठिन था। नव संशोधकीय विचारधारा ने उग्रवादियों को नैतिकता और आदर्शवाद का द्योतक माना, क्योंकि यह लोग

समाज की कुरीतियों को जनता के समक्ष लाकर समाप्त करना चाहते थे, परन्तु नव संशोधकीय लेखकों ने इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया कि उग्रवादी नीग्रो समस्या का समाधान करने में असफल रहे। केनेथ स्टैम्प के विचार में पुर्ननिर्माण का सर्वप्रथम तथा महत्वपूर्ण प्रश्न नीग्रों समस्या थी। स्टैम्प ने प्रतिशोध के आधार पर समता को उग्रवादी सुधार के प्रथम प्रश्न की मान्यता दी। तत्पश्चात् उनके मत में आर्थिक राजनैतिक एवं सामाजिक समस्यायें थी। स्टैम्प ने इस वास्तविकता को स्वीकार किया कि उग्रवादियों का नीग्रो उद्धार कार्य सर्वाधिक पक्षपात पूर्ण था और न कि लोकोपकारी तथ्य युक्त। इसके अतिरिक्त उन्होंने उग्रवादियों को व्यापारिक हितों से युक्त वर्ग की संज्ञा दी किन्तु यह भी स्पष्ट किया कि उग्रवादियों का केवल लोभी, स्वहितयुक्त, द्वेषजनक एवं पक्षपातपूर्ण वर्गीकरण करना पुर्ननिर्माण के वास्तविक चित्र का विरूपण करना था।

इस प्रकार पुनर्निर्माण का इतिहास लेखन विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने समय में अपने-अपने मतानुसार किया। इन विद्वानों का अध्ययन समयानुसार अमरीकी समाजिक स्थिति, जातिवाद, आर्थिक समस्यायें तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित था। डॉनिंग मत संशोधकीय एवं नव संशोधकीय विचारधाराओं ने अपने अध्ययन में पुर्ननिर्माण को नीग्रो समस्या, वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा जातिवाद के प्रश्नोत्तर पर आधारित किया। डॉनिंग मत 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से प्रारम्भ होकर 20वीं शताब्दी के आरम्भ तक विकसित रहा। इस मध्य अधिकतर अमरीकी बहुमत इस पक्ष में था कि नीग्रो 'जातीयता' समता की श्रेणी में नहीं आ सकता क्योंकि उनका अमरीकी समाज में पूर्ण समन्वय संभव नहीं था। इसका कारण डारविन के उत्पत्ति सिद्धांतों से प्रभावित अमरीकी जीव वैज्ञानिकों के द्वारा उत्पत्ति संबंधी शोधकार्य ने अमरीकी चिंतन को एक नया मोड़ दिया। फलतः डॉनिंग मत को स्वीकार करना ऐसी वैचारिक परिस्थिति में संभव नहीं था।

संशोधकीय विचारधारा, दूसरी ओर, प्रगतिशील नव इतिहास लेखन से प्रभावित थी। इस मत के लेखक निष्पक्ष आनुभाविक उपात्त पर अपने कार्य को आधारित करने के इच्छुक थे और डॉनिंग मत से उनकी कार्य प्रणाली भिन्न थी। नव संशोधकीय विचारधारा समतावाद से प्रभावित थी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् पुनः निर्माण के लेखन एवं अध्ययन में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। इसका एक कारण अन्य विद्वानों की अमरीकी समाज के प्रति अध्ययशील प्रकाशन था। इनमें मुख्य गुनारमंडिल की 'ऐन अमेरिकन डिलेमा, दि नीग्रो प्रावलम एण्ड मार्डन डिमाकरेंसि' मंडिल ने भी नीग्रो समस्या

को एक नैतिक समस्या मात्र, और अमरीकी समाज को कथनी एवं करनी में उलझा हुआ दिखाया।

यद्यपि पुर्ननिर्माण युग को लगभग एक शताब्दी पूर्व माना जाता है परन्तु इतिहासकारों के मत एवं विचार अपने स्थान पर अपने अध्ययन के द्वारा सार्थक है; परन्तु यह भी स्पष्ट है कि अमरीकी सभ्यता एवं समाज में तीव्र प्रश्न अपने स्थान पर यथा कथित समुचित रूप से एक बहत प्रश्न चिन्ह बना हुआ है।

नवयुग

द्वितीय विश्व युद्ध में अक्षीय शक्तियों के पराजय के पश्चात् सयुक्त राज्य अमरीका को वह शक्ति तथा सम्मान प्राप्त हुआ जिसका उदाहरण इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। सैन्यवाद से घृणा होते हुये भी अमरीकी जनता को समय की आवश्यकतानुसार युद्ध में भाग लेना पड़ा और वे पुनः अपने पूर्वकालीन शांतिमय वातावरण में वापिस लौटने के इच्छुक थे परन्तु 1945 के बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि आधुनिक सभ्यता की संकट की घड़ी अभी टली नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय एकता तथा सुविधाविहीन वर्गों तथा जातियों में विश्व सम्पदा के निष्पक्ष वितरण हेतु आवश्यक आंदोलनों की अब भी शाश्वत शान्ति के पूर्व कार्य करना शेष था। अमरीका अपने देश तथा विचारों की सुरक्षा के प्रति तभी आश्वस्त हो सकता था जबकि वह इतिहास के अप्रतिरोधी प्रवृत्ति को मान्यता प्रदान करने के साथ ही साथ विश्व नेतृत्व का उत्तरदायित्व भी स्वीकार कर लेता। इस प्रकार युद्ध के पश्चात् अमरीका ने उस नवीन युग में पदार्पण किया जिससे उसका तत्कालीन इतिहास पूर्ण अनभिज्ञ था।

इस प्रकार विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय नवीन व्यवस्था की स्थापना हेतु सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त करने के लिये रुजवेल्ट के समस्त प्रयास असफल सिद्ध हो चुके थे। प्राचीन रूसी साम्राज्यवाद तथा नवीन साम्यवादी परियोजनायें युग्मित होकर एक सक्रिय तथा विस्तारवादी स्वरूप प्राप्त कर चुकी थीं। इस विश्व मतभेद ने एक अन्य मतभेद को जन्म दे दिया था। पूर्वी यूरोप तथा सुदूरपूर्व में साम्यवादी विस्तार के विरुद्ध कोई भी अवरोध उपस्थित नहीं था। केवल 1947 के पश्चात् ही अमरीका ने साम्यवादी विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोध करने का संकारात्मक प्रयास प्रारम्भ किया। ऐसी परिस्थितियों में दुर्भाग्य से अमरीका को कोई अनुभवी नेतृत्व प्राप्त न हो सका क्योंकि इस संकटकाल के मध्य ही अप्रैल 12, 1945 को रुजवेल्ट की मृत्यु हो



हैरी ट्रूमन अमरीका के तैंतीसवें राष्ट्रपति

गई। वह 1944 में चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन हुये थे और उनकी मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति ट्रूमैन को उनका पद सम्भालना पड़ा।

ट्रूमैन प्रशासन :

ट्रूमैन वास्तव में विश्व के इस सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र का नेतृत्व करने में सफल नहीं था क्योंकि इस समय जब राष्ट्र इतिहास के एक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा था। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन का राष्ट्रपति काल आठ वर्षों तक रहा तथा उसके प्रशासन काल में आंतरिक व वैदेशिक क्षेत्र में अशांति रही। आंतरिक प्रशासन में आर्थिक उपद्रव, नागरिक अधिकार समस्या, राजनैतिक कटुता मुख्य थी, विदेश नीति में ट्रूमैन प्रशासन सुचारु रूप से प्रारम्भ हुआ परंतु धीरे-धीरे पश्चिमी लोकतंत्रिक राज्यों एवं रूसी साम्यवाद के मध्य एक दूसरे को भिन्न राजनैतिक सिद्धान्तों और विचारों के कारण मतभेद बढ़ता गया। इस प्रकार ट्रूमैन प्रशासन के आंतरिक एवं वैदेशिक संश्लेषण के द्वारा राष्ट्रपति के प्रशासन की समीक्षा की जा सकती है।

राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण पद सम्भालने के पूर्व ट्रूमैन को केवल सीनेट का अनुभव प्राप्त था। उसकी योग्यतायें इस महत्वपूर्ण पद हेतु पर्याप्त न थी, वह व्यवसाय से केवल एक साधारण कृषक थे। ट्रूमैन एक सामान्य नागरिक थे। उनकी प्रतिभायें भी विशिष्ट नहीं थी। अपने जीवन के पूर्वार्ध में उन्होंने केवल छोटे-छोटे राजनैतिक पदों पर कार्य किया था। यही एक कारण था कि युद्ध के पश्चात अमरीका की संकट घड़ी में आवश्यक प्रतिभा सम्पन्न नेतृत्व की आवश्यकता की पूर्ति ट्रूमैन न कर सका। उसके आंतरिक व वैदेशिक दोनों ही क्षेत्रों में केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी।

युद्धोपरांत अमरीकी सैनिकों को वापिस स्वदेश बुलाने के लिये प्रशासन पर दबाव पड़ने लगा था। ट्रूमैन ने अन्त में सैन्य विभाजन का आदेश पारित कर दिया। मई 1946 में राष्ट्रपति ने नवीन भर्ती का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। इस सैन्य अनिवार्यता के अनुसार 18 वर्ष के ऊपर सभी नवयुवकों की भर्ती अनिवार्य थी परंतु इस भर्ती के पश्चात भी सैन्य वियोजन का कार्यक्रम लागू रखा गया जिसके परिणामस्वरूप अमरीकी शक्ति निरन्तर घटती गई। सैन्य वियोजन के पश्चात सैनिक उन प्रत्येक विशेष सुविधा का उपभोग करने लगे जो उन्हें रुजवेल्ट के प्रशासन के अन्तर्गत जून 1944 से प्राप्त थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक सैनिक को बेकारी बीमा की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त सैनिकों के लिये गृह निर्माण, लघु उद्योग व शिक्षा

के लिये सरकारी सहायता का प्रवन्ध किया गया था ।

सैन्य वियोजन के इस कार्यक्रम के साथ में आर्थिक क्षेत्र में भी वियोजन का कार्यक्रम लागू कर शान्तिकालीन उत्पादन की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हो गया । इस आर्थिक वियोजन के कारण, उत्पन्न आशंका निर्मूल नहीं थी कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता इस लिये सरकार ने आर्थिक वियोजन की गति को पर्याप्त धीमा रखा । साथ ही साथ विभिन्न करों को कम कर दिया गया तथा पुर्ननिर्माण वित्त निगम के अन्तर्गत उद्योगपतियों को नये उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया गया । इस नये उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ने की आशा की गई । आर्थिक मंदी की आशंका से युद्ध के शेष सामानों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया परन्तु मंदी की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई ।

मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये कांग्रेस ने 1946 में 'मूल्य प्रशासन विभाग' को एक वर्ष और काम करने का अधिनियम पारित कर दिया । राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को मान्यता नहीं प्रदान की जिसके कारण मूल्यों में आशांतीत वृद्धि हुई । अन्त में ट्रूमैन ने इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया परन्तु मूल्यों पर सरकारी प्रतिवन्ध के कारण तत्कालीन विक्रेताओं ने बाजार में कृत्रिम कमी उत्पन्न कर दी । विशेषकर मांस विक्रेताओं ने बाजार में उसका अभाव उत्पन्न कर दिया । इससे उत्पन्न जन आक्रोश के कारण अक्टूबर, 1946 में राष्ट्रपति ने सरकारी नियंत्रण को धीरे-धीरे कम करने की घोषणा की । इसके फलस्वरूप वस्तुओं का मूल्य तीव्रता से बढ़ता गया एवं यह अमरीकी आर्थिक तंत्र का एक स्थायी व महत्वपूर्ण अंग बन गया ।

1946 में ट्रूमैन प्रशासन को अमरीका के इतिहास में महत्वपूर्ण श्रमिक अशान्ति एवं आन्दोलनों का सामना करना पड़ा । इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य श्रमिकों के संघों को बनाये रखने का वचन था । युद्ध समाप्त होते ही श्रमिक वर्ग के आन्तरिक आक्रोश की भावना ने हड़ताल का मार्ग प्रशस्त कर दिया । इन श्रमिक हड़तालों में इस्पात, कोयला, मोटर कारखानों, विद्युत कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी थे । इन श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या 4 लाख थी । अप्रैल, 1946 में खनिज उद्योगों में संयुक्त खनिज संघ द्वारा हड़ताल की गई । राष्ट्रपति ने खदानों को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का आदेश पारित किया एवं इसी आदेश के द्वारा यह हड़ताल समाप्त कर दी गई तथा सरकारी प्रशासन होने के कारण इन श्रमिकों को अत्यधिक लाभ हुआ । इसके पश्चात् रेल श्रमिकों की अखिल राष्ट्रीय हड़ताल से मई, 1946 में पुनः एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई । सरकार ने अन्त में रेल याता-

यात कांभी राष्ट्रीयकरण कर दिया । 1946 के पश्चात् धीरे-धीरे इन श्रमिकों के आन्दोलनों का घनत्व कम होता गया परन्तु इन आन्दोलनों से उत्पन्न जन आक्रोश का राजनैतिक लाभ गणतंत्रवादी दल को प्राप्त हो गया तथा इस दल ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त कर लिया । 1947 में नवीन कांग्रेस में 'नवव्यवहार नीति' (न्यूडील) के अन्तर्गत पारित अधिनियमों के विरुद्ध परम्परावादी प्रतिक्रिया प्रारम्भ कर दी । कांग्रेस ने एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिससे देश के मात्र समृद्धिशाली वर्ग ही लाभान्वित होते थे परन्तु ट्रूमैन ने उक्त अधिनियम को स्वीकृति प्रदान नहीं की । जून, 1947 में कांग्रेस ने टैफ्ट हर्टले के अधिनियम द्वारा पुनः 'नव व्यवहार नीति' के अन्तर्गत पारित वैनर अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को समाप्त कर दिया । इस अधिनियम के द्वारा श्रमिक संगठनों के कई कार्य अवैध घोषित कर दिये गये । श्रमिक संगठनों को हड़ताल पर जाने से साठ दिन पूर्व सूचित करने का आदेश दिया गया । संगठनों को आर्थिक सहायता देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । श्रमिक नेताओं को यह घोषणा करने पर बाध्य किया गया कि वे साम्यवादी नहीं हैं यद्यपि ट्रूमैन ने इस अधिनियम को मान्यता नहीं प्रदान की फिर भी 1947 में यह अधिनियम पुनः पारित हो गया । श्रमिकों ने इस अधिनियम को 'दासता अधिनियम' की संज्ञा प्रदान की । इस अधिनियम को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय श्रमिक सम्बन्ध परिषद (नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड) को एक न्यायालय का स्वरूप प्रदान कर श्रमिक सम्बन्धों दोनों को सामूहिक सौदेवाजी के नियमों का पालन करने के लिये बाध्य किया गया । 1946 के चुनाव में गणतंत्रवादी दल के विजय के कारण यह मान्यता बनने लगी थी कि इस बार 1948 के राष्ट्रपति चुनाव में यही दल सफल होगा । इसके साथ प्रजातंत्रवादी दल में गहन मतभेद का प्रादुर्भाव हो गया था । प्रजातंत्रवादी दल ने गणतंत्रवादियों को उग्र, दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी एवं प्रगति विरोधी सिद्ध किया । उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नागरिक अधिकारों का समर्थन किया । नीग्रो जाति के लाभ के उद्देश्य से संघीय सरकार द्वारा अधिनियमों को बनाने का समर्थन किया गया । इससे प्रजातंत्रवादी दल में पुनः एक मतभेद उत्पन्न हो गया तथा दक्षिण पंथियों ने अपना एक अलग दल बना लिया था । सभी राजनैतिक पर्यवेक्षकों की कल्पनाओं के विपरीत ट्रूमैन पुनः निर्वाचित हो गया । ट्रूमैन की यह विजय अमरीकी इतिहास में आश्चर्यजनक घटना बन कर रह गई तथा यह स्पष्ट हो गया कि अमरीका की जनता उग्र-वामपन्थी तथा उग्र दक्षिणपंथ के विपरीत उदारतावादी मध्य मार्ग की ओर रुचि रखती है ।

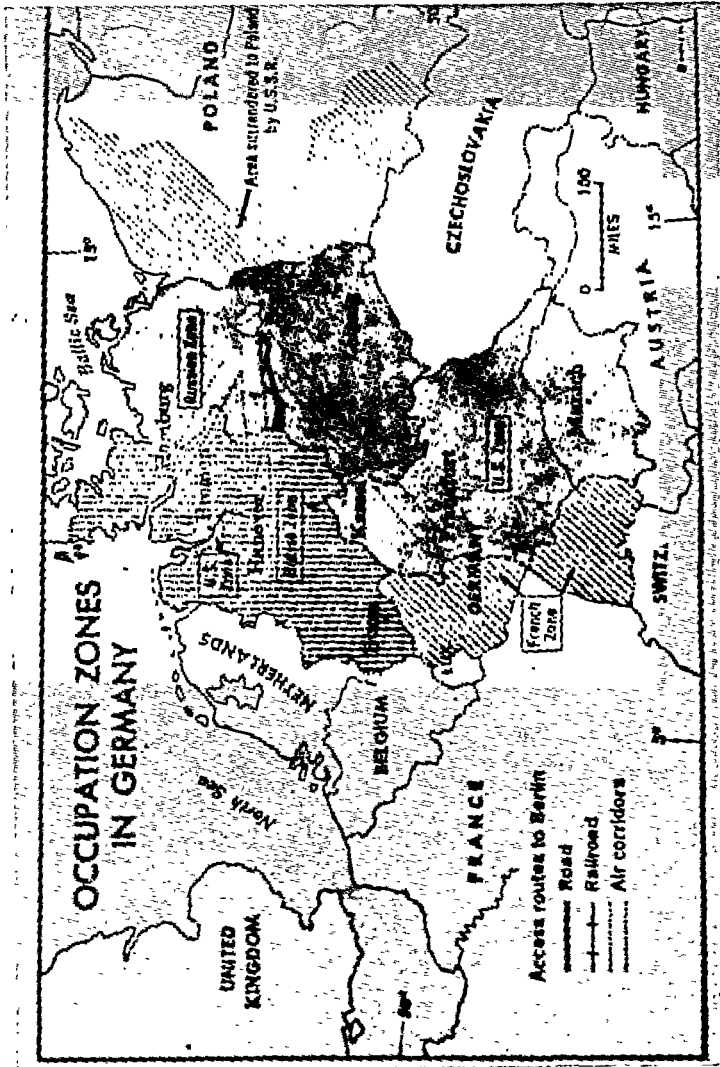
निष्पक्ष व्यवहार नीति :

1948 में पुनः निर्वाचित होने के पश्चात राष्ट्रपति ट्रूमैन ने निष्पक्ष व्यवहार नीति (फ़ेयरडील) के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयत्न आरंभ किया। 1950 तक उसको इस नीति को लागू करने में कुछ सफलता प्राप्त हुई परंतु उसके पश्चात उन्हें प्रजातंत्रवादी तथा गणतंत्रवादी दोनों दलों से विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1838 के 'श्रमिक अधिनियम' में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी की दर चालीस सेन्ट के विरुद्ध पचहत्तर सेन्ट प्रति घंटा कर दी। 1950 में इसने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया। जुलाई, 1950 में राष्ट्रीय आवास नियम के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लिये गृह निर्माण की योजना बनाई गई परंतु कांग्रेस में विरोध के कारण यह नियम लागू नहीं किया जा सका। इसी प्रकार कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा तथा नागरिक अधिकार के नियमों को पारित नहीं किया। इच्छुक होते हुए भी 'टैफ्ट हर्टले अधिनियम' को पूर्ण रूप से समाप्त न करा सके। कांग्रेस ने एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव हेतु केवल दो बार ही चुने जाने की व्यवस्था कर दी। ऐसा संशोधन रूजवेल्ट के चार बार चुने जाने के विरोध में किया गया था। युद्धोपरान्त अमरीकी आर्थिक व्यवस्था में आशा के विपरीत मंदी नहीं आई क्योंकि राजकीय वचत का उपयोग आर्थिक जगत में बढ़ गया था।

मुद्रास्फीति के कारण मूल्य वृद्धि में उत्पन्न तथा उपयोग में भी वृद्धि कर दी। सेवा आयोजन की सम्भावनायें प्रतिदिन बढ़ती गई इसके साथ साथ 1929 के आर्थिक अपनयन किये गये आर्थिक सुधारों ने अमरीकी अर्थ-व्यवस्था को स्थिर एवं सुदृढ़ कर दिया। इस प्रकार युद्ध के पश्चात अमरीका की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो गई और अमरीका ने एक नये आर्थिक युग में पदार्पण किया।

वैदेशिक सम्बन्ध (शीतयुद्ध का युग)

युद्ध के पश्चात सम्पूर्ण विश्व दो आदर्शों में विभक्त हो गया। साम्यवादी दल का नेतृत्व सोवियत संघ के आधीन था। इसके विपरीत पूँजीवादी देशों में अमरीका युद्ध के पश्चात सर्वाधिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय का क्षेत्र भी अमरीका तथा सोवियत संघ की परिधि में ही रहा। अतएव इन दो शक्तियों के प्रतिनिधियों



जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्धोपरान्त अधिकृत क्षेत्र

के रूप में यह दोनों सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रयुद्ध के पश्चात् एक दूसरे के विरुद्ध दो ध्रुवों के रूप में स्थापित हो गये । उनके मध्य सन्देह व वैमनस्य की भावना बढ़ती गई । इस नवीन विकास ने विश्व संबंधों के बीच एक नये युग का सूत्रपात किया जिसे शीतयुद्ध का युग कहते हैं । सोवियत संघ द्वारा अपनी साम्यवादी व्यवस्था का प्रसार ही पूँजीवादी राष्ट्रों के लिये प्रमुख वैमनस्य का कारण था ।

युद्ध के पश्चात् समस्त यूरोप पर अमरीकी, ब्रिटिश, फ्रेंच तथा रूसी सेनाओं का अधिकार था । जर्मनी के विभाजन के प्रश्न पर पूँजीवादी व साम्यवादी सिद्धांतों के प्रतिपादक राष्ट्रों के मध्य द्वेष की भावना ने मतभेद का रूप ले लिया । पोर्ट्स्डैम सम्मेलन के अनुसार जर्मनी का प्रशासन संबद्ध संचालन समिति के अन्तर्गत था । अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स व रूस के सेनाध्यक्ष उसके सदस्य थे । केन्द्रीय शक्ति के सदस्यों ने इटली, बल्गेरिया, रूमानिया, हंगरी व फिनलैंड से फरवरी, 1947 में संधि की । परन्तु जर्मनी जापान के साथ कोई भी संधि होने से पूर्व ही अमरीका एवं सोवियत संघ के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो चुकी थी । 1948 में जर्मनीके प्रश्न पर पुनः मतभेदों ने दोनों शक्तियों के मध्य वैमनस्य को अधिक बढ़ाया । सितम्बर, 1949 में अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अपने अधिकृत क्षेत्रों को राष्ट्र का रूप देकर जर्मनी संघीय गणतंत्र (फेडरेशन रिपब्लिक आफ जर्मनी) की स्थापना कर दी और इसकी राजधानी बान बनाई गई । इसके विपरीत सोवियत संघ ने पूर्वी जर्मनी में जर्मन प्रजातंत्रिक गणतंत्र की स्थापना कर वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था का रूप दिया । उपरोक्त इन महाशक्तियों के मध्य शीत-युद्ध में जर्मनी दो राज-नैतिक विचारमंतों में विभाजित हो गया ।

युद्धोपरान्त जापानी आत्मसमर्पण के बाद जापान के भविष्य निर्माण के लिये राष्ट्रों ने टोकियो में एक समिति गठित की जिसके सदस्य सोवियत संघ, चीन एवं ब्रिटेन थे । अमरीका का प्रतिनिधित्व जनरल मैकार्थर कर रहा था । 1947 मई में एक नवीन लोकतंत्रीय संविधान लागू किया गया । जिसके अन्तर्गत जापान का सम्राट केवल एक संवैधानिक सम्राट ही रह गया । 1951 में जापान के साथ अन्त में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुये ।

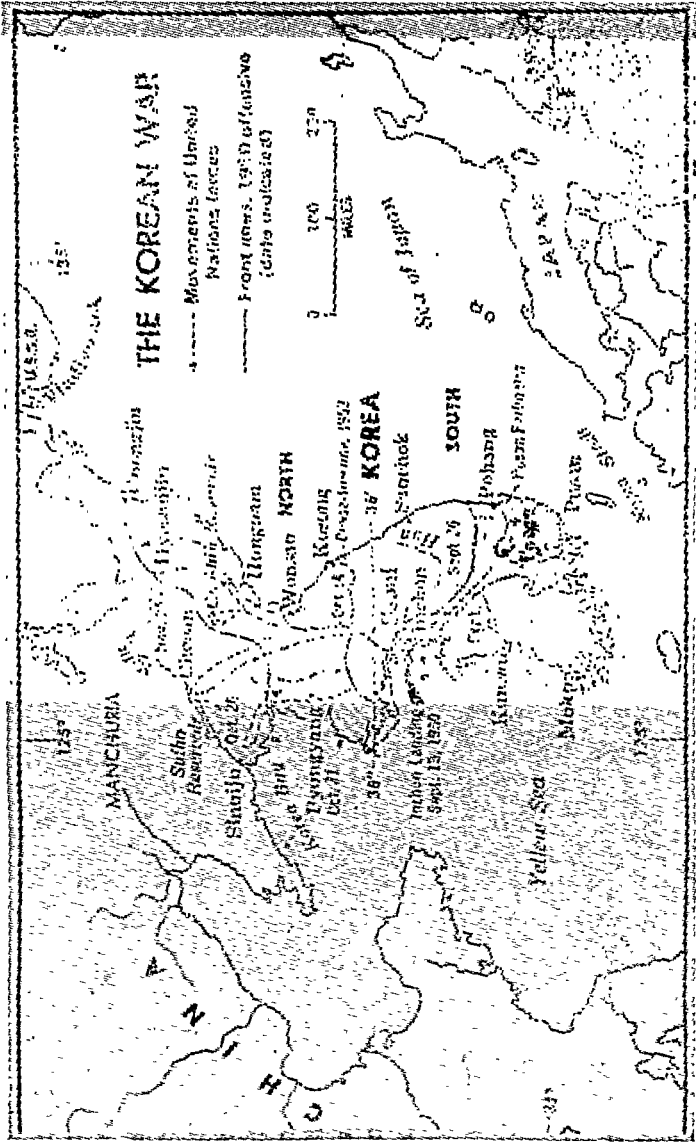
1945 में जापान की पराजय के पश्चात् साम्यवादियों एवं च्यांग काई शेक के मध्य चीन पर शासन हेतु गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया था । इसमें च्यांग काई शेक की पराजय एवं साम्यवादी सरकार की स्थापना ट्रूमैन प्रशासन की महान असफलता थी । वास्तव में अमरीका ने स्वयं इस गृह युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था । इसका मुख्य कारण च्यांग काई शेक की अप-

कीर्ति थी। वह एक अयोग्य, भ्रष्ट, स्वार्थी व राजनीतिक कपटी के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार अमरीका द्वारा चीन को भेजी गई सारी आर्थिक सहायतायें निर्मूल सिद्ध हुईं और वहाँ पर अक्टूबर, 1949 में पूर्णरूपेण साम्यवादी आधिपत्य हो गया। च्यांग काई शेक ताइवान (फारमोसा) नामक द्वीप तक ही सीमित रह गया एवं चीन में 'चीन का जनगणतंत्र' नामक साम्यवादी शासन स्थापित हो गया। यह अमरीकी विदेश नीति की एक महान असफलता थी।

राष्ट्रपति ट्रूमैन ने साम्यवाद एवं सोवियत प्रसार के विरुद्ध प्रभावशाली कदम उठाये तथा यूनान व तुर्की को साम्यवादी प्रभाव के अन्तर्गत आने से रोकने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिये कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखा। ट्रूमैन राष्ट्रीयता की भावना का पक्षपाती था एवं उन सभी राष्ट्रों को सहायता देने के पक्ष में था जो किसी न किसी विदेशी शक्ति से संघर्षरत थे। उसका विचार था कि यदि अमरीका उनको नेतृत्व प्रदान कर सका तो विश्व शान्ति की समस्या उत्पन्न हो जायेगी इससे अमरीका भी प्रभावित हो सकता था। उनके इस विचार को 'ट्रूमैन सिद्धान्त' के नाम से जाना जाता है।

1947 में अमरीका के राज्य सचिव जार्ज मार्शल ने एक पुर्ननिर्माण योजना की घोषणा की। इसके अनुसार अमरीकी बहुत बड़े स्तरपर पर यूरोप के उन सभी देशों के पुर्ननिर्माण हेतु आर्थिक सहायता के लिये एक नीति निर्धारण के पक्ष में था जो युद्ध से अत्यन्त प्रभावित हुये थे। इसके अनुसार पश्चिमी राष्ट्रों में लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना अत्यन्त आवश्यक था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी, बेकारी, अव्यवस्था तथा निराशा को दूर कर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था जिसके अन्तर्गत लोकतांत्रिक शक्तियों की सुरक्षा सम्भव हो सके।

अमरीकी कांग्रेस ने 'मार्शल योजना' की सफलता के लिये 'आर्थिक सहयोग अधिनियम' पारित किया। वास्तव में इस योजना के प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में साम्यवादी प्रसार के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना था। 1949 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 'चार सूत्रीय कार्यक्रम' की योजना निमित्त की। इसके अन्तर्गत भी पश्चिमी राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर वहाँ पर वैज्ञानिक व तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना था। इस प्रकार 'ट्रूमैन का प्रशासन' प्रमुख रूप से साम्यवादी प्रसार के विरुद्ध केन्द्रित हो गया। वे प्रत्येक प्रकार से विश्व में साम्यवाद के विकास को रोकने हेतु कटिबद्ध थे। वास्तव में यह नीति जार्ज एफ केनेन ने दी थी जिसका उद्देश्य साम्यवाद को सीमाबद्ध रखना था। उसकी इन नीति को जार्ज केनेन की सीमाबद्ध रखने



कोरिया युद्ध

की नीति (पालिसी आफ कन्टेंटमेन्ट) भी कहते हैं ।

उत्तरी अटलांटिक संधि (नाटो)

मार्च, 1948 में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रसार से आशंकित होकर ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग ने ब्रसेल्स में एक आर्थिक व सैनिक सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किये । जून 1, 1948 में अमरीकी सीनेट ने मित्रराष्ट्रों के साथ सहयोग कर रक्षात्मक संधियों के द्वारा विश्व शान्ति की स्थापना के प्रयास हेतु एक प्रस्ताव पारित किया । जिसके अनुरूप ट्रूमैन प्रशासन ने उत्तरी अटलांटिक संघ की रूप रेखा तैयार की । इस आधार पर 4 अप्रैल, 1949 को 12 राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये । अमरीका के अतिरिक्त बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, पुर्तगाल तथा इंग्लैंड इस संधि के शेष सदस्य थे । इस संधि के प्राविधानों के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्र आपसी मतभेद शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने हेतु वचनबद्ध हुये परन्तु किसी भी एक सदस्य राष्ट्र पर किसी अन्य राष्ट्र द्वारा आक्रमण की स्थिति में समस्त सदस्य राष्ट्र प्रत्येक प्रकार की सहायता के लिये बाध्य थे । सितम्बर 19, 1949 के 'पारस्परिक सुरक्षा सहायता अधिनियम' के अन्तर्गत अमरीका ने संधिवद्ध राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना स्वीकार किया । 1950 में समस्त सदस्य राष्ट्रों ने एक संयुक्त सेना की स्थापना हेतु निर्णय लिया । उन्होंने एक मत से आईजन हावर को इस संयुक्त सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया । ट्रूमैन ने साम्यवाद के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक सहायता के साथ ही साथ सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रचार को भी पर्याप्त मान्यता प्रदान की । इसी का परिणाम था कि 1947 में चेकोस्लावाकिया में साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात् सोवियत संघ यूरोप के किसी भी अन्य देश को साम्यवादी न बना सका तथा जनै-जनैः पश्चिमी राष्ट्रों से साम्यवाद का प्रभाव कम होता गया ।

कोरिया

अमरीका तथा सोवियत संघ के मध्य शीतयुद्ध ने अभी तक युद्ध का रूप नहीं लिया था परन्तु पूर्वी एशिया में शीतयुद्ध के परिणामस्वरूप युद्ध प्रारम्भ हो गया । इस युद्ध का प्रारम्भ कोरिया में हुआ । वास्तव में जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात्, कोरिया को 38 अक्षांश रेखा पर दो अस्थायी भागों में विभाजित कर दिया था । उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ का अधिकार

था जबकि दक्षिण कोरिया में अमरीका द्वारा प्रभावित लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। उत्तरी कोरिया में सोवियत संघ ने साम्यवादी सरकार की स्थापना कर उसे मान्यता प्रदान कर दी थी। इसी प्रकार दक्षिणी कोरिया की सरकार को अमरीका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान कर दी थी। अमरीका के विदेश सचिव डीन एचीसन ने पूर्वी एशिया की अमरीकी सुरक्षा परिधि में कोरिया तथा फारमोसा को सम्मिलित नहीं किया। इसके अनुसार इन दोनों पर आक्रमण की स्थिति में अमरीका कोई कार्यवाही करने हेतु बाध्य नहीं था तथा उसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास थी अमरीका की इस नीति से प्रोत्साहित होकर उत्तरी कोरिया ने 25 जून, 1950 को दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का उद्देश्य दोनों कोरिया को मिलाकर वहाँ साम्यवादी शासन स्थापित करना था। ट्रूमैन इस युद्ध में भाग लेकर अमरीका को युद्ध से प्रभावित नहीं करना चाहता था परन्तु युद्ध में भाग न लेने का अर्थ पूर्वी एशिया में इस प्रकार के संघर्षों को प्रोत्साहित करना था। जून 27, 1950 को सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से सहायता की अपील की उस समय सोवियत संघ च्यांग काई शेक के सुरक्षा परिषद की सहायता के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर रहा था। अतः यह प्रस्ताव पारित होने में कोई अड़चन न पड़ी। जनरल मैकार्थर को संयुक्त राष्ट्र संघवादी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। कई अन्य देशों ने भी अपनी सेनायें दक्षिणी कोरिया की सहायता हेतु प्रेषित की। प्रारम्भ में अमरीकी सेना को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई परन्तु बाद में चीन द्वारा उत्तरी कोरिया को सहायता के कारण दोनों पक्षों की अत्यन्त हानि का सामना करना पड़ा। जनरल मैकार्थर युद्ध में सफलता हेतु चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण करने के पक्ष में था क्योंकि वहीं से उत्तरी कोरिया को सैन्य सहायता प्राप्त होती थी परन्तु राष्ट्रपति ट्रूमैन किसी भी स्थिति में युद्ध के विस्तारवादी नीति के विरुद्ध था। फलस्वरूप मैकार्थर तथा ट्रूमैन में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गये। अन्ततोगत्वा ट्रूमैन ने मैकार्थर के स्थान पर मैथ्यू रिजवे को नियुक्त कर दिया।

ट्रूमैन के इस कार्य से अमरीका में ऐसे वैचारिक संघ उत्पन्न हो गया क्योंकि जनरल मैकार्थर अमरीका में पर्याप्त लोकप्रिय था उसे गणतंत्रवादियों का सहयोग भी प्राप्त था परन्तु मैकार्थर के आलोचनात्मक भाषणों के कारण उसकी लोकप्रियता धीरे-धीरे कम होती गई तथा ट्रूमैन की नीति को मान्यता भी मिलने लगी। कोरिया सम्बन्धी अमरीकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु ट्रूमैन के शासन काल में कोरिया की समस्या सुलझ न सकी

तथा उसका श्रेय आइजनहावर को प्राप्त होना था ।

साम्यवादी संकट मैकार्थीवाद

चीन में अमरीका की नीतियों की असफलता, कोरिया के युद्ध तथा अन्य सभी क्षेत्रों में अमरीकी नीतियों की पराजय ने अमरीका में एक मनोवैज्ञानिक तथा सैद्धान्तिक संकट उत्पन्न कर दिया । इस संकट का जन्मदाता सीनेट सदस्य जोसेफ मैकार्थी था । उसके विचार में अमरीका की समस्त नीतियों की असफलता के पीछे उन साम्यवादियों का हाथ था जो उच्चपदों पर आसीन थे । उसके विचार में यह पदाधिकारी निरन्तर अमरीकी नीतियों को साम्यवादी पक्ष में प्रभावित कर रहे थे उसने स्थान-स्थान पर इस आशय से वक्तव्य देकर अमरीकी जनता में रोष की भावना उत्पन्न कर दी परन्तु वैदेशिक सम्बन्ध समिति ने अपनी जाँच के पश्चात् इस सभी दोषारोपणों को निर्मूल सिद्ध कर दिया । यद्यपि मैकार्थी दोषारोपण पूर्ण रूपेण आधार रहित सिद्ध हो गये थे परन्तु उसके वक्तव्यों ने अमरीका में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया था जिसका विष वर्षों तक प्रभावशाली रहा । अमरीका के विचारक, लेखक इतिहासकार, राजनैतिक कलाकार तथा अधिकारी कोई भी इस विष की लपेट से सुरक्षित न रह सके । इस वातावरण में शनैः शनैः गणतंत्रवादियों के अनुकूल वातावरण निर्मित हो रहा था जिसने 1952 के चुनावों को पर्याप्त प्रभावित किया ।

युग विकास

यद्यपि अमरीकी क्रान्ति के फलस्वरूप वहाँ के निवासियों में वैचारिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता का विकास हुआ तथापि आर्थिक क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । तत्कालीन संयुक्त राज्य अमरीका अब भी एक कृषि प्रधान देश था तथा वहाँ की आर्थिक प्रणाली अब भी कृषि उत्पादन लघु उद्योगों एवं कृषि जनित उत्पादनों और निर्यात पर आश्रित थी । 1850 तक लघु उद्योग किसी प्रकार भी नीति अथवा लाभ के उद्देश्य से युक्त थे इसलिये आवश्यक वस्तुयें जैसे औजार, चमड़े की वस्तुयें लकड़ी तथा कपड़ों का निर्माण स्थानीय निकायों में सम्पन्न किया जाता था । आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन व्यक्तिगत स्तर पर कर लिया जाता था । व्यापार तथा वाणिज्य भी स्थानीय स्तर पर कच्चे माल एवं तैयार उत्पादनों के परस्पर विनिमय पर निर्भर था ।

इसका आर्थिक लाभ कुछ धनी व्यापारियों, भूमिधरों तथा मध्यस्थों को प्राप्त होता था।

कृषि आधारित उद्योगों से यांत्रिक उद्योगों तक की यात्रा मानव इतिहास की वह लम्बी यात्रा रही है जिसमें उसने प्रत्येक मोड़ पर अपनी शक्ति, बुद्धि तथा विवेक का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। पूँजी केन्द्रित औद्योगिक क्रांति में कच्चे माल, प्रचुर पूँजी, श्रमिकों, तकनीकी तथा विज्ञान का प्रमुख योगदान आवश्यक होता है। प्रारम्भ में इन सबकी अनुपस्थिति के ही कारण अमरीका में औद्योगिक क्रांति का आगमन ब्रिटेन के पश्चात ही सम्भव हो सका। प्राचीन अमरीका कृषकों, शिल्पकारों तथा लघु व्यापारी उद्योग का देश था। अमरीकी यातायात एवं परिवहन नदियों एवं लघुपत्तों के द्वारा होता था परन्तु 1840 के पश्चात अमरीका उद्योगीकरण की ओर अग्रसर हुआ एवं यातायात के साधनों में रेलवे व्यवस्था ने आशातीत योगदान दिया। अमरीका की जनसंख्या में उद्योगीकरण के विस्तार के साथ वृद्धि होने लगी। 1840 में 1 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या 1900 में 7 करोड़ 60 लाख हो गयी यद्यपि नव अमरीका जो कि औद्योगिक क्रांति से प्रतिभूति था, वहाँ लाखों की संख्या में कृषक थे परन्तु इस क्रांति ने उद्योग फैक्टरी प्रणाली, वृहद व्यापार, पूँजी पति तथा विस्तृत रेल पद्धति को जन्म दिया। 1849 में 9 लाख 57 हजार वेतन-भोगी श्रमिक थे। 1889 में इनकी संख्या में वृद्धि होकर 42 लाख 52 हजार हो गई। इसी प्रकार 1840 में रेलवे मार्ग भी तीन हजार मील से बढ़कर 1890 में 1 लाख 67 हजार हो गया। इसके साथ ही अमरीकी नगरों की जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। वस्तुतः अमरीका जो वास्तविक रूप में कृषि राष्ट्र था, द्रुत गति से औद्योगिक नगरीय राष्ट्र में परिवर्तित होने लगा।

अमरीका में औद्योगिक क्रांति के आगमन में विलम्ब होने का मुख्य कारण ब्रिटेन का औद्योगिक प्रतियोगी के रूप में प्रकट होना था। इसके अतिरिक्त अमरीका में अपेक्षाकृत श्रमिकों का अभाव था तथा ब्रिटेन में दास व्यापार एवं उनकी उपलब्धता के कारण न तो श्रमिकों का अभाव था और न ही ब्रिटेन को कच्चे माल की समस्या थी। कच्चे माल का आयात ब्रिटेन अपने एशिया स्थित उपनिवेशों से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेता था। इसके साथ ब्रिटेन को अफ्रीका से दासों की उपलब्धि भी सरल थी। ब्रिटिश साम्राज्य एक वृहद साम्राज्य था और उसे व्यापारिक सुविधा पूर्ण रूपेण प्राप्त थी। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन तकनीकी क्षेत्र में भी निरन्तर प्रगति करता जा रहा था। विशेष अधिनियमों के द्वारा ब्रिटेन ने उन तकनीकी ज्ञान एवं यंत्रों के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया था। 1738 में 'जॉन के' द्वारा निर्मित (अविष्कृत)

पलाइंग शटल द्वारा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। तत्पश्चात् जेम्स वाट के वाष्प शक्ति (1769) एडमण्ड कार्टराइट के पावरलूम (1785) तथा स्टीवेन्सन के भाप इंजन के आविष्कार ने औद्योगिक क्रान्ति को नवीन दिशाओं प्रदान की। ब्रिटेन में उपलब्ध कोयले तथा लोहे की खानों के कारण उर्जा तथा यान्त्रिकी उत्पादन की दर क्रमशः सीमित होती गई। एशिया से उपलब्ध कपास के कारण ब्रिटेन में कपड़े की मिलों में क्रान्तिकारी स्तर पर उत्पादन प्रारम्भ हो गया। मिल के तैयार कपड़ों ने भारत तथा अफ्रीका में खपत के विस्तार के साथ ब्रिटेन की आर्थिक प्रगति को पुनः वहाँ की औद्योगिक क्रान्ति को द्विगुणित किया। परन्तु यह क्रान्ति अधिक दिनों तक ब्रिटेन में ही सीमित न रह सकी। सैमुअल स्लेटर द्वारा स्थापित आर्कराइट जल शक्ति की मशीन के कारण अमरीका में फैक्टरी विद्या का प्रारम्भ हो गया। सैमुअल स्लाटर अमरीकी उद्योग का पिता कहा जाता है। राष्ट्रपति जैफरसन ऐसे लोकतंत्र के स्वप्नदृष्टा थे जिसमें कृपकों को पूर्ण स्वतंत्रता हो, उनके जीवन, उद्योग व विकास पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो। खनिज उद्योग एवं खानों में कार्यरत श्रमिकों के उत्थान का वे स्वप्न साकार करना चाहते थे उन्होंने इंग्लैण्ड, इटली व फ्रांस में दासता की विभिषिका का अवलोकन किया था अतः वे इस दासता के पूर्णतया निर्मूल करना चाहते थे।

जैफरसन ने हैमिल्टन को चुनाव में पराजित किया जिससे कि हैमिल्टन योजना का समाप्तिकरण हो सके लेकिन अंत में हैमिल्टन की विजय हुई और 'रिपोर्ट आन मैनुफैक्चर्स' ही अमरीका की पथ प्रदर्शक बनी।

यद्यपि अमरीका में कच्चे माल एवं बाजार की कमी नहीं थी लेकिन (एम्बारगो ऐक्ट) नान इण्टरकोर्स ऐक्ट 1812 के युद्ध तथा विभिन्न करों के कारण कारखानों, उद्योगों को काफी आघात पहुँचा। 1807 के पश्चात् ही कारखानों में उन्नति प्रारंभ हो सकी। बोस्टन के व्यापारी फ्रांसिस केवेट लोवेल (जो कि 1810 से 1812 तक इंग्लैण्ड का भ्रमण करने के बाद लौटा था) ने सर्वप्रथम अमरीका में पावरलूम की स्थापना की। यह फैक्टरी लोवेल ने कुछ रिश्तेदारों तथा मित्रों की सहायता से वॉलथम (मैसाचुसेट्स) में 1814 में स्थापित की, इस तरह से विश्व में प्रथम बार कताई और बुनाई की मशीनों ने एक साथ कार्य प्रारम्भ किया। इसके बाद अमरीका के अविष्कारों ने नवीन मशीनों का निर्माण कर वस्त्र उद्योग में क्रांति आरम्भ कर दी। 1846 में इलियस हाव द्वारा सिलाई की मशीन का आविष्कार करने से वस्त्र तथा सिलाई उद्योग में क्रांति प्रारम्भ हो गई।

यद्यपि इस देश में तथाकथित औद्योगिक क्रांति, गृह युद्धोपरांत काल से

सम्बद्ध रही है परन्तु उत्पादन के क्षेत्र में इसके विकास की गति 1800 से 1850 के मध्य सर्वाधिक प्रभावशाली रही है। गृहयुद्ध ने केवल इसकी गति के त्वरण की दर को तीव्रता प्रदान की। जैफरसन के प्रशासनिक प्रतिबन्ध तथा 1812 के युद्ध ने अमरीका में उत्पादन की वृद्धि कर दी क्योंकि इस प्रतिबन्ध के कारण ही ब्रिटेन में निर्मित उन उत्पादनों का आयात बन्द हो गया जिनकी आवश्यकता अमरीका को थी एवं जिनका निर्यात ब्रिटेन किया करता था। उद्यमशील उत्पादकों ने यह अनुभव किया कि बहुत से वे सामान जिसका उन्हें ब्रिटेन से क्रय करना पड़ता है उनका स्वयं अमरीका में उत्पादन सम्भव था। यद्यपि अमरीका में 1808 के इस प्रतिबन्ध के पूर्व भी इसका बोध अथवा चेतना उपस्थित थी।

इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से कारणों ने भी गृहयुद्ध के पूर्व उत्पादन हेतु ठोस आधार निर्मित करने में सहयोग प्रदान किया। जैसे आवश्यक कच्चे माल कपास, लोह, खनिज तथा इमारती लकड़ी का अमरीका में कोई अभाव नहीं था। इसके अतिरिक्त पूर्वी सागर तट से सम्बद्ध नदियों ने ऊर्जा के स्रोत का प्रभावशाली कार्य किया। यद्यपि वहाँ पर पूँजी एवं श्रम का अभाव था तथापि 1812 के युद्ध के कारण वाणिज्य एवं व्यापार में संलग्न व्यक्तियों के लिये पूँजी लगाने का उपर्युक्त एवं लाभदायक वातावरण उत्पन्न हो चुका था। लघु प्रयासों से प्राप्त पूँजी को बृहद उत्पादनों में लगाने की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती गई। वस्त्र की मिलों में कृषकों का मजदूर के रूप में प्रयोग प्रारम्भ हो गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न उत्पादकों ने ऐसे यन्त्रों का प्रयोग प्रारम्भ हो कर दिया जिसमें कम से कम श्रम की आवश्यकता पड़ती हो। इसी के साथ ही साथ उत्पादन एवं उद्योग में विकास हेतु यातायात के साधनों के अभाव की पूर्ति भी पर्याप्त हो चुकी थी। नदियों, नहरों तथा रेलवे के कारण यातायात की समस्या लगभग समाप्त प्राय हो गई। अतएव 1810 के पश्चात् मिल पद्धति का अभूतपूर्व विकास प्रारम्भ हो गया। हथकरघा के उद्योग ने स्थापना करना आरम्भ कर दिया। इन परिस्थितियों में श्रमिकों ने मिलों की अपनी स्थिति के सुधार हेतु 1820 में सर्वप्रथम संगठित प्रतिक्रिया व्यक्त की।

जैफरसन उस नागरीय सभ्यता का कटु आलोचक था जिसका उदाहरण उसने यूरोप में देखा था। उसका विश्वास था कि यदि “हमारे पास श्रम हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तो हम क्यों अन्य हानिकारक पद्धति का अनुसरण करें” उसने अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही ग्रामीण प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास किया एवं इसके विकास की आधार शिला के रूप में उससे ‘लुइसियाना’ को क्रय किया। उसने लुइसियाना को क्रय ने पश्चात् यह कहा था, “कि यहाँ

आने वाली हमारी हजारों पीढ़ियों हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।” वह उस हैमिल्टन के विरुद्ध राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ जिसने अमरीका के विकास हेतु तत्कालीन ब्रिटिश मार्ग अपना देने का मत प्रदान किया था। जैफरसन का विचार था कि अमरीका को पश्चिम की ओर बढ़ना है जिस ओर पर्वत, तथा घास के मैदान तथा मैदानी भाग थे न कि पूर्व की ओर जिस तरफ मात्र सागर था। उनके स्वप्नों का उद्देश्य मात्र कृषकों को लाभ पहुँचाना था, न कि उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को। जैफरसन के उत्तराधिकारियों ने भी उनके स्वप्नों को साकार करने की दिशा में ही निरन्तर प्रयास बनाये रखा। जैसे जैसे देश की सीमायें पश्चिम की ओर बढ़ती जा रही थी कृषि का भविष्य उज्ज्वल होता जा रहा था। यही कारण था कि 1860 में भी अमरीका प्रमुखतः कृषि प्रधान देश था। राजनैतिक पर्यवेक्षकों ने गृहयुद्ध को भी ‘कपास सम्राट’ तथा ‘गेहूँ सम्राट’ के मध्य संघर्ष के रूप में देखा न कि ‘कृषि एवं मशीनों’ के मध्य युद्ध के रूप में।

तथापि आर्थिक क्षेत्र में वास्तविक विजय हैमिल्टन की ही हुई। यह उसका उत्पादन पर विवरण नामक सिद्धान्त था जिसे बैंक तथा उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया। यह उसके सिद्धान्तों का ही प्रतिफल था कि केवल एक सदी के ही पश्चात् अमरीका का विश्व के सर्वप्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों में एक स्थान हो गया। विश्व में समस्त राष्ट्रों से अधिक लोहे तथा कोयले की खुदाई, कपास की खेती, तेल का उत्पादन, मशीनों का निर्माण, मिलों का विकास तथा यातायात में तीव्रता से अमरीका में वृद्धि हुई। एक सदी के पश्चात् औद्योगिक विकास में इतनी वृद्धि हो गयी थी कि अमरीका में जहाँ नीतियों का निर्धारण व्यापारियों एवं पूँजीपतियों के इच्छानुसार होने लगा था जिससे किसानों का भविष्य खतरे में पड़ गया था अर्थात् पूँजीपति लाभान्वित होने लगे और कृषक समाज दिन प्रतिदिन शोकग्रस्त होता गया।

यद्यपि अब अमरीकी आर्थिक नीति स्थानान्तरण के पीछे प्राकृतिक कारणों का प्रमुख हाथ था तथा इसमें सरकारी नीतियों ने भी पर्याप्त सहयोग प्रदान किया था। अमरीका के इस आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण थे—कच्चे माल की जल एवं रेल के रूप में उपस्थिति, जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक गृह बाजार का विकास, अप्रवास के कारण श्रम की पूर्ति अन्तर्राज्यों की सीमा शुल्क के अभाव के कारण प्रतियोगिता की कमी तथा परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप में सरकारी सहायता। इन प्रमुख कारणों के अतिरिक्त उत्साह की भावना तथा आशावादिता के वातावरण ने भी प्रमुख भूमिका निभाई।

यह औद्योगिक क्रान्ति कोयले, तेल, लोहे एवं विद्युत ऊर्जा पर आधारित थी। पेन्सिलवेनिया तथा पश्चिमी वर्जीनिया, इलेनॉय के घास के मैदान तथा कॉन्सास, कॉलरेडो एवं टैक्सास में एंथ्रासिट कोयले की अपरिमित खानें थी। केवल मैक्सिको में अमरीका भर की आवश्यकता हेतु 100 वर्षों के लिये पर्याप्त कोयला उपलब्ध था। 1910 तक लगभग 5, 000,000,000 टन कोयला प्रति वर्ष निकाला जाता था परन्तु यह सम्पूर्ण श्रोत का केवल एक प्रतिशत ही भाग था। इसके अतिरिक्त उर्जा के दूसरे श्रोत पेट्रोलियम (तेल) के क्षेत्र में भी अमरीका समान रूप से ही धनी था। 1900 के पश्चात् कदाचित ही अमरीका विश्व के समस्त देशों के पेट्रोलियम उत्पादन से कम पेट्रोलियम उत्पादित कर रहा था। टैक्सास, ओकलहॉमा, कॉन्सास, इलेनॉय तथा कैलिफोर्निया में तेल की खोज के पश्चात् अमरीका पूर्ण रूप से अपने सुदूर भविष्य के प्रति भी आश्वस्त हो गया। इन दोनों खनिजों के अतिरिक्त पश्चिम में कोलोरोडो तथा सुपीरियर झील के निकट से प्राप्त लोह खनिजों के कारण लगभग 200 वर्षों के भविष्य के प्रति आशान्वित हो गया। इसके अतिरिक्त प्रकृति ने स्वयं भी किसी अन्य देश की तुलना में अमरीका को अपेक्षाकृत अधिक जल श्रोत भी प्रदान कर दिया था। इससे उपलब्ध जल शक्ति के कारण अमरीका के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व तीव्रता आ गई।

यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि खनिज सम्पदाओं का इतिहास 1850 के पश्चात् प्रारम्भ होता है। यद्यपि लौह खनिज की खुदाई औपनिवेशिक काल में ही प्रारम्भ हो चुकी थी परन्तु यह मिशेगन तथा सुपीरियर झील के श्रोतों का कारण था कि अमरीका लोहे एवं स्टील के क्षेत्र में सर्वप्रमुख हो गया। एडविन ड्रेक ने 1859 में पश्चिमी पेन्सिलवेनिया में सर्वप्रथम तेल के श्रोत का अन्वेषण किया जिसके 50 वर्षों के पश्चात् अमरीका का तेल उत्पादन 20,000,000 बैरल से अधिक हो गया। ताँबे की खोज भी औपनिवेशिक काल में ही हो चुकी थी परन्तु 18वीं शताब्दी में मोन्टना तथा एरिजोना में खुदाई के पश्चात् इस क्षेत्र में 'ताँबे के सम्राटों' के मध्य एकाधिकारों तथा राजनैतिक शक्ति हेतु अभूतपूर्व संघर्ष प्रारम्भ हो गया। कोलोराडो, नेवादा तथा मोन्टना में चाँदी की खोज के पश्चात् अमरीका का सम्पूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय स्वरूप परिवर्तित हो गया। गृह युद्ध के पूर्व ही शीशे की खानों का उत्खनन भी गैलेना तथा इलेनॉय में प्रारम्भ हो गया था जिसने छपाई के उद्योग को वृद्धि प्रदान करने में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। 1870 में पोर्टलैण्ड के सीमेन्ट एवं 1887 में अल्यूमिनियम के वाणिज्य स्तर पर उत्खनन एवं परिविकरण ने भी अमरीकी वृहद व्यापार का मार्ग प्रशस्त किया। विलियम

एन्थनी के तथा सी. एफ. ब्रश के डायनमो के अन्वेषण में सम्भवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियाँ निहित थी। इनके द्वारा अमरीकी तकनीकियों को जल उर्जा को विद्युत उर्जा में रूपान्तरण कर उद्योग के क्षेत्र में क्रान्ति का श्रेय प्रदान किया गया।

सम्भवतः अमरीकी वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक संख्या में अन्वेषण किये। 1860 से 1900 के मध्य उन्होंने 6,76,000 एकस्व प्राप्त किये इसके पश्चात उनकी संख्या में अतीव वृद्धि हुई। इली विटनी के कपास जिन, (ओटना) राबर्ट फुलटन के वाष्पचालित नौका, इलियस हाव के सिलाई मशीन, चार्ल्स गुडियर के बलकनित (बल्केनाइज) रबर, सीरस मेकॉमिक एवं ओवेद हुसी के फसल काटने की मशीन उपरोक्त अन्वेषणों में प्रमुख थी।

इसी मध्य एफ० वी० मोर्स ने टेलीग्राम (तारयंत्र) तथा 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के अन्वेषण द्वारा अमरीकी उद्योग युग को एक नवीन दिशा प्रदान कर दी।

वस्त्र उत्पादन उद्योग

उन्नीसवीं शताब्दी में वस्त्रोद्योग, अमरीकी उद्योग तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था। 1800 के पश्चात वस्त्रोद्योग में प्रयुक्त यंत्रों को चलाने के लिये जल शक्ति का प्रयोग प्रारम्भ हो चुका था। इस के पश्चात तकनीकी दृष्टि से प्रत्येक दिशा में विकास प्रारम्भ हो गया। 1815 के पश्चात जल चलित तकली का प्रयोग मिलों में प्रारम्भ हो गया। एवं शनैः शनैः विद्युत करघों के प्रयोग में वृद्धि होने लगी। उपरोक्त शताब्दी में विकास के साथ ही साथ वस्त्रों के मिलों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती गई और इसने देश की आर्थिक सम्पदा को भी अत्यधिक त्वरित कर दिया। कपास ओटने के यंत्र (जिन) के अन्वेषण एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण उन कच्चे मालों का उत्पादन भी बढ़ता ही गया जिनकी आवश्यकता औद्योगिक विकास के लिये सर्वाधिक होती हैं। संयुक्त राज्य के वस्त्र उत्पादन का इतिहास अन्य सभी उद्योगों से अधिक विस्तृत है। भौगोलिक दृष्टि से इसने चार प्रमुख क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा है। न्यू इंग्लैण्ड विभिन्न प्रकार के उत्पादक क्षेत्रों में विभाजित है। दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य अमरीकी राज्यों की कपड़ा मिलों में अत्यधिक समानता रही है।

अमरीकी क्रान्ति के तत्काल पश्चात कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में ज्ञान अत्यधिक न्यून था। 1786-87 में मैसाचूसेट्स ने दो बार ब्रिटेन के वैज्ञानिक

अन्वेषणों को वहाँ लागू करने के लिये सरकारी सहायता उपलब्ध कराई। फिलाडेल्फिया ने भी इस क्षेत्र में प्रयास किया परन्तु ब्रिटेन की सरकार ने प्रत्येक प्रकार से नवीन यंत्रों के आगमन एवं तकनीकी ज्ञान में अवरोध उत्पन्न किया तथापि अमरीकी उत्पादकों ने इस क्षेत्र में दो या तीन वर्षों के अन्दर ही वस्त्र उत्पादन से सम्बन्धित लगभग समस्त प्रकार के तकनीकी ज्ञान को प्राप्त कर लिया। यद्यपि यह प्रयोगों तथा आंशिक सफलता का काल था। 1800 के पूर्व के समस्त प्रयासों में से केवल तिहाई भाग को ही सुरक्षित रखा जा सका। यह प्रयास दो प्रकार से किये गये थे। प्रथम जैनी मिल तथा द्वितीय आर्काराइट मिल। दोनों ही शक्ति, यांत्रिक, कच्चे माल तथा उत्पादन के विषय में पर्याप्त विभिन्नता रखते थे। जैनी मिल या तो हस्तचालित थे अथवा घोड़े द्वारा चलाये जाते थे। यह अपेक्षाकृत करघे पर अधिक आधारित था। ये मुख्यता वस्त्र बुनने का कार्य करते थे जबकि दूसरे प्रकार से मोटे सूती वस्त्र बनाये जाते थे। सर्वप्रथम फिलाडेल्फिया में इस प्रकार के मिल का निर्माण 1787 में हुआ।

1800 के पूर्व इस प्रकार के लगभग सभी मिल बन्द हो गये थे। 1790 में सैमुअल स्लेटर ने सर्वप्रथम पोटकीट में आर्काराइट मिल की स्थापना की उनकी तकली जल-चलित थी। इसी प्रकार की मिलों की स्थापना अगले वर्षों में अन्य शहरों में भी हुई। आगामी कुछ वर्षों की असफलता के पश्चात वस्त्र उद्योग में तीव्रता से विकास हुआ क्योंकि आर्काराइट मिलों की सफलता के पश्चात विभिन्न ब्रिटिश तकनीकी भी अपने भाग्य निर्माण हेतु अमरीका आने लगे थे। इसी के साथ साथ नेपोलियन के युद्धों के कारण अमरीका ने युरोप को इस उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त पीछे कर दिया।

व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का दोहरा प्रभाव परिलक्षित हुआ। व्यापारियों ने वाणिज्य पर पूंजी लगाने से अधिक उचित उत्पादन पर लगाना उपयुक्त समझा तथा इसके कारण विदेशी उत्पादनों के आयात पर प्रतिबन्ध लग गया। यद्यपि इस प्रतिबन्ध का कोई प्रभावोत्पादक असर नहीं पड़ा तथापि इससे हानियों के साथ साथ लाभ का अनुभव हुआ। मिलों का विकास भी तदानुसार वृद्धिरत रहा। ब्रिटेन से युद्ध के पश्चात विदेशी वस्त्रों के बाहुल्य ने अमरीका के नवीन उद्योग को अत्यधिक प्रभावित किया। परन्तु हाथ-करघा तथा लघु उद्योगों पर इसका अपेक्षाकृत न्यून प्रभाव ही परिलक्षित हुआ। युद्धोपरान्त संघि के पश्चात कपड़े के उत्पादन को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। अधीरता तथा अपूर्णता से निर्मित उद्योग पूर्णतया समाप्त हो गये थे। परन्तु नवीन सीमा शुल्क अधिनियम, श्रम मूल्य में मन्दी तथा अविरल विश्व-

स्तर पर व्यापार पुनः वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित कर दिया। सर्वप्रथम 1815 में विद्युत करघे का प्रयोग वेथलम (वैथलिहम) में किया गया तत्पश्चात् 1812 तथा 1817 में अन्य नगरों में विद्युत करघे का विकास सम्पन्न हुआ। अन्ततोगत्वा 1820 में बॉल्टेमोर में 30 विद्युत करघों से उत्पादन प्रारम्भ हो गया। दक्षिणी राज्यों में भी वस्त्र उद्योग को प्रारम्भिक असफलता के पश्चात् सफलता प्राप्त हुई। पश्चिमी राज्यों में अपेक्षाकृत वस्त्र के उद्योग में न्यून परिवर्तन हुये। न्यू इंग्लैंड तथा मध्य राज्यों में कपड़े का उद्योग अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर रहा था। 1820 तक इस क्षेत्र ने पर्याप्त वृद्धि कर ली। न्यू इंग्लैंड तथा न्यूयार्क में विद्युत करघे के लिये पूनियों का निर्माण होता था। इस प्रकार के केन्द्रीयकरण के कारण उद्योगों ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। 1829 से 1830 के मध्य रोड द्वीप स्तर पर तकली की संख्या 70,000 से 240,000 हो गई। 1832 तक प्रत्येक 160 तकली के लिये एक मिल की स्थापना हो चुकी थी। मैसाचूसेट्स ने 3,40,000 तकलों का प्रयोग प्रारम्भ करके रोड द्वीप को भी पीछे छोड़ दिया।

इस विकास के इतिहास के दो मुख्य स्वरूप थे। विशेष सामान हेतु वृहद निगमों का दृष्टगत होना तथा वस्त्र की रंगाई का महत्व बढ़ाना 1828 के सीमा शुल्क अधिनियम के पश्चात् मिल निर्माण तथा उत्पादन क्षमता में प्रभाव-गाली विकास देखा गया। 1820 से 1834 के वस्त्र उद्योग ने न्यू इंग्लैंड में नवीन धनोपार्जन अर्जित किया तथा व्यापारियों की रुचि उत्पादन क्षमता में क्रमशः अधिक होती गई इसी प्रकार युद्ध के पश्चात् विभिन्न व्यापारी नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में बस गये क्योंकि उन्हें यह व्यापार अधिक लाभदायी प्रतीत हुआ। इस परिवर्तन के ही कारण नवीन उत्पादक वर्ग का जन्म अमरीका में हुआ जो अगामी वर्षों में एक विशेष लाभदायक स्थापना सिद्ध हुई। इसी प्रकार युद्ध के कारण उत्पन्न युद्ध स्थिति के कारण वोस्टन के व्यापारियों को भी अधिक हानि न उठानी पड़ी। उन्होंने 1815 से 1820 के मध्य तीन मिलों का निर्माण कर लिया था। इसकी सफलता से प्रभावित होकर लावेस में भी वृहद स्तर पर मिल की स्थापना की गई। गृह युद्ध के पूर्व तक यह नगर अमरीका का प्रमुख वस्त्र उद्योग का नगर हो गया। इसी मध्य 1825 में हैमिल्टन कम्पनी ने फ्रेंसी वस्त्रों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया था। 1824 के पश्चात् न्यू इंग्लैंड में प्रिन्टिंग का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था वेथलम के व्यापारियों को विदेशी वस्त्रों का महत्व ज्ञात था। उन्होंने इस अनुभव के आधार पर मिल के वस्त्रों के निर्यात पर अधिक जोर देना उचित नहीं समझा। 1840-1860 के मध्य तकलों की संख्या दुगनी हो गई।

लोहा और इस्पात

वस्त्र उद्योग के सदृश्य लोह इस्पात गृह उद्योग नहीं था। औपनिवेशिक काल के प्रारम्भ से ही लोहे की खुदाई का सूत्रपात अमरीका में हो चुका था। और 1619 में वर्जीनिया के फालिंग क्रीक नामक स्थान पर जान वर्कज ने लोहे की एक भट्ठी बना ली थी। एथेन एलेन नामक ग्रीन माउन्टेन बाँयज के एक नेता ने कैंटकी नामक स्थान पर एक अन्य भट्ठी भी निर्मित कर दी थी। पूर्वी पेनसिलवेनिया ने वार्शिंग्टन को संकटग्रस्त महाद्वीपीय की सहायता की। 1800 के बाद एलेगनी के पश्चिम और पिट्सबर्ग में लोहे के कारखाने बन गये क्योंकि वहाँ कच्चे माल, कोयले, चूना, लकड़ी की अच्छी सुविधा प्राप्त थी।

लेकिन वस्त्र उद्योग के समान एम्बार्गो, नानइण्टर कोर्स ऐक्ट तथा 1812 के युद्ध ने इस उद्योग को काफी क्षति पहुँचाई लेकिन औद्योगिक क्रान्ति युग में राष्ट्र के विस्तार के साथ यह उद्योग भी उन्नति करता गया। 1830 में जब लोहा कोयले के साथ सफलतापूर्वक गलाया गया तथा 1851 में विलियम कैली ने 'वेसमर, परिक्रिया' का अन्वेषण किया तो लोह उद्योग अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया उसके बाद लोहे का प्रयोग कपड़े की मिलों में होने लगा जिससे इसकी माँग बढ़ती गई।

1797 में चार्ल्स न्यूवोल्ड द्वारा लोहे के हल द्वारा खेती का प्रारम्भ हुआ। 1833 में। शीकागो के जान लैन के सुधार के साथ ही लोहे की माँग कृषि क्षेत्र में भी बढ़ गयी थी और 1840 में जब वात्या भट्ठी (फरनेस) का निर्माण हुआ तो लोह उद्योग के लिये भरपूर बाजार उपलब्ध हो गया। इसी वर्ष से रेल की पटरियों के लिये लोहे की माँग बढ़ती गई।

धातु उद्योग को अग्नास्त्रों में उपयोग होने से और भी प्रोत्साहन प्राप्त होने लगा। इस उद्योग में सर्वप्रथम 'स्टैण्डर्डइंजेशन आफ पार्ट एण्ड इंटरचेजेबल मेकानिज्म' का सिद्धांत प्रतिपादित होने से लोहा उद्योग में भी क्रान्तिकारी विकास प्रारम्भ हो गया और शनैः-शनैः अन्य धातुओं का निर्माण होने लगा। युद्धोपरान्त औद्योगिक विकास में अमरीका का मुख्य उद्योग इस्पात (स्टील) था। 1860 तक यह धातु के मूल्याधिक होने के कारण मूल्यवान तथा उत्कृष्ट वस्तुओं में ही प्रयोग होता था। 19 वीं शताब्दी की पंचशती में एक अमरीकन विलियम केली तथा एक अंग्रेज हैनरी धेसमर ने स्वतंत्र रूप से लोहे को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध कर इस्पात को जन्म दिया। 1866 में इन दोनों के आविष्कार को एकस्य अधिकार प्राप्त हुआ

और इस्पात धातु यथार्थता में परिणत हो गया। शनैः-शनै इस्पात निर्माण की कला में वृद्धि एवं निपुणता प्राप्त होती गई। निःसन्देह अमरीकी औद्योगिक क्रान्ति की आधारशिला इस्पात निर्माण से प्रारम्भ हुई। इसके साथ ही धातु मिश्रण तथा मिश्रित धातुओं के द्वारा अनेक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होने लगा।

आवागमन

औद्योगिक क्रान्ति युग में अमरीका में आवागमन के साधनों का विकास होने लगा। रेल, सड़को, नहरों आदि के निर्माण से सामान के यातायात से अमरीकी उद्योगों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त होने लगी।

औद्योगिक क्रान्ति के साथ-साथ ही उत्तरी क्षेत्र निर्माण कार्य के क्षेत्र में भी अग्रसरित होता गया जिसके कारण यह आवश्यक हो गया कि परिवहन में और अधिक सुधार हो।

राष्ट्रीय जनपथ

अब राष्ट्रीय सरकार का उद्देश्य सड़कों का निर्माण करना था। 1792 से 1794 के बीच फिलाडेल्फिया और लां कास्टर के बीच 66 मील लम्बी राष्ट्रीय सड़क का निर्माण हुआ। इस सड़क के सफलतापूर्वक निर्माण के बाद प्रत्येक राज्य में यह कार्य शुरू हो गया। पेन्सिलवेनिया ने 30 वर्षों के अन्दर 86 कम्पनियों के द्वारा 2200 मील लम्बी सड़क का निर्माण करवाया और न्यूयार्क ने 1811 तक 137 कम्पनियों के द्वारा 1400 मील जनपथ का निर्माण करवाया।

1806 में कांग्रेस ने ग्लैटन की रिपोर्ट पर मंथीय सहायता से कम्बर लैण्ड से मेरी लैण्ड ओहायो की पहाड़ियों से होकर 834 मील लम्बी राष्ट्रीय सड़क निर्माण की अनुमति प्रदान की।

नहरों का निर्माण

एक ओर जहाँ नवीन सड़कों के निर्माण से लोगों का आवागमन आसान हो गया वहीं चुंगी एवं परिवहन करों के द्वारा ब्रिटेन की आमदनी भी होने लगी। इंग्लैण्ड में उसी समय औद्योगिक क्रान्ति के क्षेत्र में नहरों का भी निर्माण प्रारम्भ हुआ और उनकी सफलता से ही अमरीका का ध्यान भी इस

तरफ केन्द्रित हुआ। यद्यपि छोटी-छोटी विभिन्न नहरों का निर्माण होने लगा था। परन्तु नहर निर्माण का युग इरी नहर के निर्माण के साथ प्रारम्भ हुआ। एक दीर्घ अन्तराल के भान्दोलन के पश्चात् न्यूयार्क ने 1817 में हडसन को इरी झील से जोड़ने का निर्णय किया। इरी कैनल की सफलता के पश्चात् देश में नहरों का निर्माण युग प्रारम्भ हुआ। 1825 में ओहायो एसेम्बली ने एक नहर निर्माण कार्य पारित किया जिसके दौरान इरी झील तथा ओहायो नदी को दो बड़ी नहरों से जोड़ दिया गया। 1833 में क्लीवलैण्ड से लेकर पोर्ट्स माउथ तक ओहायो तथा इरी नहरें (308 मील लम्बी) बनकर तैयार हुईं। दूसरी ट्रांस ओहायो कैनल, मियामी और इरी के पश्चिमी भाग सिनसिनाटी से डेटान 1832 में तथा टेलीडो से इरी तक 1845 में बनकर तैयार हो गईं।

इसी तरह से न्यूजर्सी के निकट दो नहरें तथा शेष अन्य उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में निर्मित हुईं। एक नहर न्यूजर्सी तथा फिलिप्सबर्ग डेलावेयर के मध्य बनी जो कि पेन्सिलवेनिया से न्यूयार्क नगर तक कोयला ले जाती थी। इसी तरह इल्लिनायस ने मिशिगन झील से लेकर मिसीसीपी को जोड़ते हुये नहरें बनाईं।

रेलवे :

यातायात के विस्तार के प्रति रेलमार्गों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अंग्रेजी यात्री स्टर्लिंग ने रेलवे के विकास को पश्चिमी सभ्यता की आत्मा की संज्ञा दी। यातायात के विकास ने अमरीकी औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में अपार सहयोग प्रदान किया। सड़कों में सुधार एवं नहरों तथा रेलवे के निर्माण ने कच्चे तथा तैयार मालों के स्थानान्तरण में सहायता प्रदान की। ओहायो राज्य में इरी झील तथा ओहायो नदी को दो नहरों के द्वारा जोड़ दिया गया। यह देश का सबसे बड़ा आन्तरिक जल यातायात का साधन था। ओहायो इरी नामक यह जलतंत्र केवल मुख्य नहरों पर नहीं आधारित थे अपितु इनमें से अनेक उप नहरों से भी सम्बन्धित थे। 1851 तक यह तंत्र अपनी चरम सीमा पर यातायात कर रहा था परन्तु उसके बाद निरन्तर बढ़ के कारण ओहायो राज्य मुख्यतया: रेल यातायात पर निर्भर होता गया।

नवीन सड़कों, नहरों तथा वाष्पचालित नौकायानों ने निश्चय ही अपार योगदान प्रस्तुत किया परन्तु उन्नीसवीं सदी के कृषि, वाणिज्य, व्यापार तथा पूंजी चलित अर्थव्यवस्था हेतु प्रयाप्त नहीं थे। अमरीका में अत्यधिक दूरियों पर्वत शृंखलाओं जंगलों तथा जनरहित मैदानों ने उपर्युक्त यातायात के मार्गों

में अनेकों बाधाएँ खड़ी कर दीं। इन समस्याओं का उन्मूलन केवल सस्ते तेल एवं लचीले यंत्रों के द्वारा ही सम्भव था। निश्चय ही अब रेलमार्ग ही केवल एक उपर्युक्त तथा प्रभावशाली साधन शेष था जो तत्कालीन सदी का एक क्रान्तिकारी अन्वेषण था एवं जिसमें उपरोक्त समस्याओं का समाधान भी था। यद्यपि इसका प्रारम्भिक विकास ब्रिटेन में सम्पन्न हुआ था परन्तु इसका पूर्ण विकास अमरीका ने किया। 1840 में जबकि सम्पूर्ण यूरोप ने 1818 मील लम्बा रेल मार्ग विकसित किया अमरीका में लगभग 3000 मील लम्बा रेल मार्ग निर्मित हो चुका था। यद्यपि पश्चिमी यूरोप तकनीकी तथा धातु कर्मी तकनीक में अमरीका से काफी आगे था परन्तु अमरीका की उपरोक्त अवश्यकताओं के कारण इसका विकास वहाँ अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही साथ प्राचीन विश्व की राजनैतिक समस्याओं के सदृश्य वहाँ कोई समस्या नहीं थी। सस्ती दरों पर उपलब्ध विशाल भूमि के कारण भी वहाँ रेल मार्गों का विकास अधिक तीव्रता से हुआ। यद्यपि अमरीका के कुछ राज्यों ने इसके विकास में बाधाएँ उत्पन्न कीं; उनका विचार था कि रेल मार्ग के इस विकास के कारण नहरों पर लगाया गया धन व्यर्थ हो जायेगा। उन्होंने इसको 'चन्द्रमा के समान' व्यर्थ एवं अप्रयोगिक तथा 'शैतानी यंत्र की संज्ञा भी दी। परन्तु इस प्रकार की आलोचनाएँ तथा प्रतिबन्ध केवल अपवाद के रूप में ही उपस्थित थे। अधिकांशतया अमरीका ने इसका स्वागत ही किया। इसके निर्माण में प्रयुक्त उत्साह की कल्पना इसी से की सकती हैं कि उन्होंने भी इसके व्यय वहन करने में अनिच्छा नहीं दिखाई जिन्होंने स्वयं कभी रेल मार्ग ही नहीं देखा था और न ही वाष्प इंजन। वॉल्टेमोर, चार्ल्सटन तथा बोस्टन नामक तीन व्यापारिक नगरों ने इसके विकास में सर्वाधिक रुचि प्रदर्शित की। इसका मुख्य कारण यह भी था कि वहाँ पर नहर मार्गों का अभाव था। सर्वप्रथम 1828 में वॉल्टेमोर से ओहायो तक रेल मार्ग का निर्माण किया गया। तत्पश्चात् 1831-32 में दक्षिणी कैरोलिना के चार्ल्सटन नगर में देश की द्वितीय रेल मार्ग का विकास हुआ। पेन्सिलवेनिया ने इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति की। 1839 में फिलाडेल्फिया एवं रीडिंग के मध्य प्रमुख रेल मार्ग पर कोयले का आवागमन प्रारम्भ हो गया। आने वाले दशक में भी रेल मार्गों का अत्यधिक विकास हुआ यद्यपि ये वर्ष आर्थिक दृष्टि से अवनति के वर्ष थे। 1840 में सम्पूर्ण रेल मार्गों की लम्बाई जो केवल 3,328 मील थी, 1850 तक 8,879 मील लम्बी हो चुकी थी। न्यूयार्क में अकेले 956 मील लम्बे रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। बोस्टन संयुक्त राज्य संघ का, सर्वाधिक प्रचलित रेल मार्ग का केन्द्र था। इस दशक ने

रेल मार्गों के विकास को एक नयी प्रणाली प्रदान की। इसके अनुसार लम्बे तंत्रों में छोटे मार्गों को युग्मित करने की प्रक्रिया अपनायी गई। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न कम्पनियों ने सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार 1860 तक अमरीका में रेल मार्ग का पर्याप्त रूप से विकास हो गया था। यद्यपि भविष्य में अभी पर्याप्त विकास करना शेष था परन्तु औद्योगिक विकास हेतु इन वर्षों के उपरोक्त प्रयासों ने जो योगदान प्रदान किया वह सर्वथा प्रशंसनीय रहा।

सड़कों, नहरों तथा स्टीमबोट ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था लेकिन अमरीका के लिये वह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि अमरीका एक विस्तृत पर्वतीय तथा घने अरण्यो और मैदानी इलाकों का प्रदेश था।

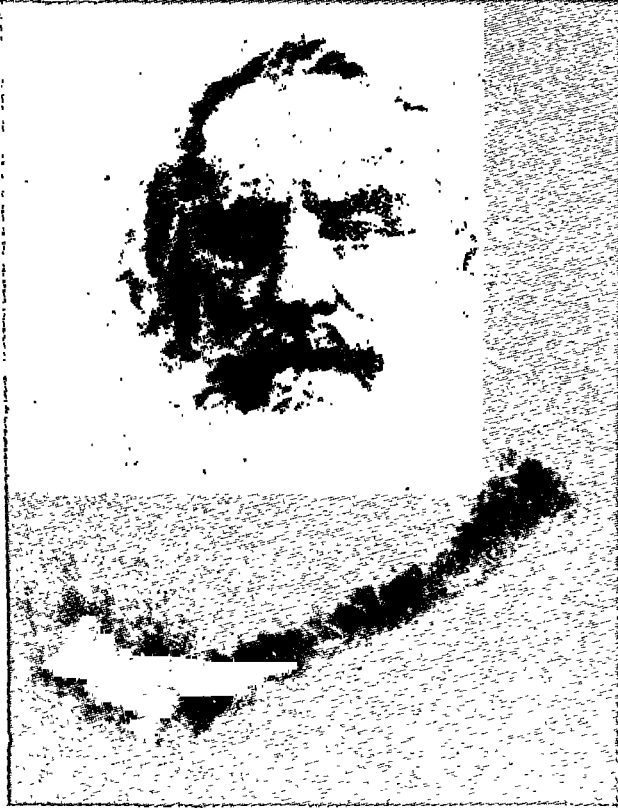
अमरीका की इस भौगोलिक विभिन्नता के कारण रेल मार्ग का विकास ही वहाँ के कृषि तथा औद्योगिक प्रगति का सर्वाधिक उपयुक्त यातायात का साधन हो सकता था। इसके साथ ही साथ नहरों की अपेक्षा रेल की पटरियाँ बिछाना अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक तथा सस्ता पड़ता था। रेलों पर किसी भी प्रकार के मौसम तथा भौगोलिकता का असर नहीं पड़ता था।

4 जुलाई, 1828 को चार्ल्स कॉरेल (आखिरी स्वतंत्रता सेनानी) ने सर्वप्रथम वाल्टेमोर और ओहियो के बीच रेल के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। और प्रथम वाष्प इंजन (9 हार्स पावर) डेलावेयर और हडसन के बीच चला। 1830 तक कई छोटी बड़ी रेल रोड का निर्माण हो चुका था। 1860 तक पूर्वी तथा पश्चिमी अमरीका में 30,000 मील लम्बी रेलवे लाईनों का निर्माण हो चुका था। इस प्रगति से उन सभी प्रदेशों को लाभ प्राप्त हुआ जिन्हें नहरों के निर्माण के कारण हानि हुई थी। रेल की इस प्रगति से प्रत्यक्ष लाभ गृह युद्ध में हुआ जब पूर्व तथा पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभावशाली समन्वय बना रहा।

स्टीम बोट (वाष्प नौका)

औद्योगिक क्रान्ति की आधारशिला यंत्र एवं तकनीकी विकास तथा फैक्टरी प्रणाली के द्वारा रखी गई परन्तु इसको उचित रूप से विकसित करने का श्रेय संचारण साधनों पर था। संचारण के साधनों में उन्नति वाष्प (स्टीम) एवं विद्युत के द्वारा सम्पन्न हो सकी।

गृह युद्ध तक, नदियों से समुद्रों की ओर आवागमन प्रारम्भ हो गया था, जिसमें भाप के इंजन के द्वारा नावें चलाने का श्रेय अमरीका को ही प्राप्त था यद्यपि इंग्लैण्ड और यूरोप के अभियन्ता भी वाष्प नौका चलाने का प्रयत्न



सैमुअल मोर्स (1791-1872)

कर रहे थे परन्तु अमरीका के राबर्ट फुलटोन ने सफलतापूर्वक वाष्प नौका का संचालन किया। 1829 में जार्ज स्टीफेन्सन ने रेल के वाष्प इंजन का सफलतापूर्वक कार्य रूप में परिणत किया। अगस्त 1807 को न्यूयार्क से एल्वेनी तक 150 मील की दूरी 32 घंटे में तय होने लगी। इस समय लोगों का विश्वास था कि यह नाव एक मील से अधिक नहीं चल पायेगी। फुलटोन की इस यात्रा से ही समुद्री जहाज व्यापार का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो गया।

लेकिन इसके पश्चात् भी अमरीकी सागरीय परिवहन व्यापार को उतना लाभ नहीं पहुँच सका जितना कि ग्रेट ब्रिटेन को। लेकिन 1795 से लेकर 1827 के मध्य ऐसा कोई बन्दरगाह नहीं था जहाँ तारे और पट्टियों वाला ध्वज न पहुँचा हो ग्रेट। ब्रिटेन के बाद दूसरी महान सामुद्रिक शक्ति होने के कारण अमरीका ने अपने मतस्य पालन के व्यवसाय में भी पर्याप्त उन्नति की। स्कूपतवारों तथा कोयले के प्रयोग ने सागरीय परिवहन व्यापार में और अधिक उन्नति प्रदत्त की लेकिन गृह युद्ध के कारण अमरीकी जहाजरानी व्यापार को अधिक हानि का सामना करना पड़ा।

टेलीग्राफ (तार यंत्र) व्यवस्था

इस अन्वेषण को अधिक द्रुतगामीं सैमुअल मोर्स के टेलीग्राफ ने प्रदत्त किया। इसके अविष्कार में संचारण को एक नव दिशा का ज्ञान दिया। 1847 तक पूर्वी और मध्य पश्चिमी नगरों को तार यंत्रों के द्वारा सम्बद्ध किया गया। और 1861 में महाद्वीप के पार सैनफ्रांसिस को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस समय तक 50 हजार मील की परिधि में तारयंत्र कार्यरत थे। 1876 में एलकजैंडर ग्राहम ने दूरभाष (टेलीफोन) का अविष्कार कर संचारण के इतिहास में एक नवयुग का सूत्रपात किया। 1380 तक 50 हजार दूरभाष कार्यरत थे और 1890 में इनकी संख्या 17 लाख हो गई। इसके अतिरिक्त विद्युत शक्ति के द्वारा भी संचारण और यातायात ने एक नवीन अध्याय का संयोजन किया।

मानव शक्ति

अमरीका की औद्योगिक क्रान्ति में तीन प्रकार से मानव शक्ति का उपयोग एवं सहयोग रहा, उद्योगों, अविष्कारक तथा श्रमिक। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाध में अमरीका योग्य एवं सफल व्यापारियों से परिपूर्ण था। उनमें से मुख्य फ्रांसिस लोएल पी० टी० जैक्सटन, एवोट

लारेन्स थे । कोई भी ऐसा औद्योगिक नगर नहीं था जिसने बिना वाह्य मदद के नवीन उद्योग प्रारम्भ किया हो ।

अमरीका में उद्योगीकरण का वातावरण अकस्मात् ही नहीं उत्पन्न हो गया था वरन् उसकी पृष्ठ भूमि में शताब्दियों का अनुभव कार्यरत था । प्रारम्भ में तत्कालीन उद्योग धन्धों में हानि की सम्भावना अधिक होती थी । अतः उद्योगी मनुष्यों के पीछे आविष्कारकों का हाथ रहता था । ये आविष्कारक परिश्रमी होते थे तथा इनके वर्षों के परिश्रम के बाद ही इच्छित परिणाम प्राप्त होते थे । इली ह्वीटनी, एलिस हो जान स्टीवन्स, राबर्ट फुलटोन, पौल मूडी और चार्ल्स गुडईयर आदि महान आविष्कारकों के कारण ही अमरीका में औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हो सकी । बाद में इन आविष्कारकों ने अपने उद्योग भी स्थापित कर लिये ।

अमरीका में यद्यपि श्रमिक बहुत पहले से ही थे लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी । यूरोप की तरह यहाँ प्रारम्भ से ही वर्ग भेद नहीं था लेकिन औद्योगिक क्रान्ति ने स्वयं ही समाज को वर्गीकृत कर दिया और श्रमिकों की समस्या का समाधान हो गया । यूरोप की तरह अमरीका में भी फैक्टरी प्रणाली ने भूमिहीन समाज की स्थापना कर दी । सौभाग्य से अमरीका में फैक्टरी प्रणाली ने प्रारम्भ में ही इतना दूषित प्रभाव श्रमिकों पर डाला जितना कि यूरोप में । वस्त्र उद्योग एक पृथक उद्योग के रूप में नहीं रहा । कताई और बुनाई अधिकांशतः औरतों के द्वारा घर में सामान्य घर के कार्य की तरह किया जाता रहा । साथ ही साथ औद्योगिक क्रान्ति के कारण बहुत बड़ा श्रमिक वर्ग कार्य से पृथक नहीं किया गया वरन् इसके अतिरिक्त एक रोजगार का नया अवसर श्रमिक संघ को प्राप्त हुआ । साथ ही पारिश्रमिक तथा श्रमिकों की स्थिति यूरोप की अपेक्षा अमरीका में कहीं अधिक उन्नत व श्रेष्ठ थी ।

श्रमिक वच्चों का प्रारम्भ स्लेटर के प्रथम वस्त्र मिल से हो गया था जिसको 9 वच्चों के द्वारा ही प्रारम्भ किया गया था । दक्षिणी न्यू इंग्लैण्ड में आधे से अधिक वस्त्र निर्माता श्रमिक मजदूर वच्चे ही थे जो कि सूर्य के निकलने के साथ ही कार्य प्रारम्भ करते और रात को देर तक कार्य करते थे । पुराने मिलों में यह स्थिति अपेक्षाकृत अधिक कष्टदायक होती थी क्योंकि उनमें प्रकाश तथा वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाती थी । अतः स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था ।

श्रमिकों की दशा

आधुनिक स्तर से श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय थी। दोनों प्रकार के कारीगरों तथा मिल श्रमिकों को उन्नीसवीं सदी में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। मजदूरी अत्यन्त कम थी तथा काम के घंटे अधिक थे। इसी के साथ-साथ कार्य करने की स्थिति स्वयं अत्यन्त कष्टदायक थी। विशेषकर कपड़े के मिलों में श्रमिकों को अत्यन्त ही भिन्न वातावरण में कार्य करना पड़ता था। अधिकांश मिलों में स्त्रियाँ श्रमिकों के रूप में कार्य करती थीं। न्यू इंग्लैण्ड में ऐसे ही श्रमिक स्त्रियों के रहने के लिये मिल द्वारा संचालित आवासों का प्रबन्ध था। मिल के मालिक इन आवासों को कठोरता से संचालित करते थे। उनके प्रत्येक कार्यकलापों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखी जाती थी। इसके अतिरिक्त शेड तथा पेन्सिलवेनिया के मिल मालिक सम्पूर्ण परिवार को ही ऋण कर उनसे कार्य लेते थे। इस प्रकार उन परिवारों के बच्चों को भी कार्य करना पड़ता था। यद्यपि तत्कालीन परिस्थितियों की आलोचना के लिये अन्य और भी बातें उपलब्ध हैं परन्तु इस प्रकार सम्पूर्ण परिवार द्वारा श्रमिकों का कार्य स्वीकार कर लेना एवं स्त्रियों-लड़कियों के द्वारा भी कार्य किये जाने के पीछे यह तथ्य अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है कि परिस्थितियाँ तत्कालीन कृषक जीवन से अधिक प्रतिकूल तथा अनाकृष्ट नहीं थी। एक यात्री ने अपने वर्णनों में लिखा है कि श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त निशक्त हो गई थी। एवं श्रमिकों की उपलब्धि भी कम होती जा रही थी। प्रत्येक आवास में रहने की व्यवस्था अत्यन्त अस्वास्थ्यकर थी। एक ही कमरे में 5-6 श्रमिकों को सोना पड़ता था। उन कमरों में किसी भी प्रकार वायु, प्रकाश तथा लाभदायक वातावरण के आने का प्रबन्ध नहीं था। यहाँ तक कि वातायनों की अनुपस्थिति होने के कारण वातावरण में वहाँ घुटन रहता था। यह आंशिक रूप से अमरीका में जमींदारी की प्रथा का प्रारम्भ था। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को लगभग 7000-8000 स्त्रियाँ तथा लड़कियाँ कार्यरत थी। श्रमिकों को पूरे 13 घंटे कार्य करना पड़ता था। अनुकूल परिस्थितियों में इस शोषण की दर बढ़ जाती थी जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता था। उन मिलों में अत्यन्त ही कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। इसी प्रकार कार्य न करने की विधि कोई प्रशंसनीय नहीं थी। प्रत्येक लड़की को तीन से चार करघों पर एक साथ कार्य करना पड़ता था जिसका अर्थ था अत्यन्त कार्य कुशलता एवं कार्य की तीव्र गति ऐसी कार्यविधि से 13 घंटे कार्य करने के पश्चात् किसी श्रमिक की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

इसी के साथ-साथ उन मिलों का वातारण स्वयं भी स्वच्छ नहीं रहता था । अमस्त कमरों में कपास के धागे एवं गुच्छे अस्त-व्यस्त पड़े रहते थे ।

यद्यपि श्रमिकों को ऐसी परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता था परन्तु वहाँ पर कुछ आशा की ज्योति भी प्रज्वलित थी जिसके कारण ये श्रमिक ग्रामों से आकर वहाँ कार्य करते थे । अमरीकी मिलों में कार्य करने की शर्तों तथा मजदूरी में अपनयन नहीं हुआ परन्तु प्रतियोगिता के कारण उन पर प्रभाव अवश्य पड़ा । मिल के श्रमिकों की स्थिति अधिकांशतः अनुकूल ही हो गई । विशेषकर उन श्रमिकों की जो स्थायी रूप से नियुक्त थे । उनके सम्मुख अधिक लाभदायक मजदूरी वाले मिलों को चुनने की स्वतंत्रता थी । यही कारण था कि केवल 1860 तक ही उनकी परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन आ चुका था ।

प्रारम्भ से ही अमरीका के श्रमिकों का पारिश्रमिक कम न था । जहाँ यूरोप के श्रमिकों को जीवन यापन की समस्या रहती थी अमरीकी मजदूरों एवं श्रमिकों में रहन सहन के स्तर की समस्या थी । विभिन्न मिलों में विभिन्न अवसरों पर मजदूरी की दर भिन्न रहीं अतएव इस संबंध में कोई निश्चित मत नहीं स्थापित किया जा सकता है, परन्तु यह निश्चित था कि 1860 के पूर्व स्त्रियों के लिये कोई भी अन्य कार्य उतना लाभदायक नहीं था जितना कि मिल मजदूरी । परन्तु स्त्रियों के लिये तब तक आर्थिकरूप से स्वतंत्र होने के अवसर उपलब्ध नहीं थे जब तक कि स्वयं मिल में उपयुक्त अवसर न मिल सके । यद्यपि मिल मजदूरी के अतिरिक्त भी वृद्धिरत जनसंख्या वाले नगरों में, सुदूर प्रान्तों से आई स्त्रियों के लिये, विभिन्नकार्य उपलब्ध थे, जैसे घरेलू कार्य, सिलाई-बुनाई आदि । परन्तु उन्हें अपेक्षाकृत मिलों में कार्य करना अधिक सुविधाजनक लगता था ।

पारिवारिक मिलों में कदाचित ही नकद भुगतान किया जाता था । नकद भुगतान केवल विशिष्ट श्रमिकों को किया जाता था, अन्यथा भुगतान की शैली बिल के रूप में की जाती थी, जिससे श्रमिक अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को मिल की दुकानों से खरीद सकें । यद्यपि इन बिलों का भुगतान कभी-कभी बाहर किये जाने की व्यवस्था होती थी ।

पारिवारिक मिलों की अपेक्षा, अन्य मिलों में श्रमिकों की दशा अपेक्षाकृत न्यून की मिलों का निर्माण इस प्रकार से होता था कि पर्याप्त रूप से पारगामी वायु संचार, प्रकाश, स्वच्छता का अभाव था । यद्यपि ऐसी परिस्थितियाँ सभी मिलों में नहीं होती थी नियुक्ति एवं कार्यमुक्ति का अधिकार मिल मालिकों के पास सुरक्षित रहता था, परन्तु यदि कोई श्रमिक अपनी इच्छानुसार नौकरी से त्यागपत्र देता था तो उसे शर्तों के अनुसार दण्ड भरना पड़ता था ।

श्रमिक संगठन

औद्योगिक क्रान्ति के द्वारा श्रमिक वर्ग नवीन मिलों के पास संगठित होने लगा। 1790 में केवल 3.3 प्रतिशत लोग ही नगरों में निवास करते थे और 1860 में यह संख्या 16.1 प्रतिशत तक पहुँच गयी। इन्हीं मजदूर संगठनों को बनाने के लिये राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई। सार्वजनिक विद्यालयों के द्वारा विभिन्न आविष्कारों की व्याख्या की गई तथा सुदूर श्रमिक वर्ग के लिये संचार व्यवस्था की स्थापना की गई।

इसके पश्चात् भी मजदूर संगठनों को अपने दैनिक कार्यों में प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता था क्योंकि वैधानिक रूप से इन संगठनों को मान्यता नहीं प्राप्त थी। ब्रिटिश अधिनियम के अन्तर्गत ये संगठन उद्योगों के प्रति पड़यंत्रकारी एवं जनकल्याण के विरुद्ध होते थे, लेकिन 1842 में राज्य मंडल के विरुद्ध इन मुकदमों में श्रमिक संगठनों को मान्यता प्रदान कर दी गई। अमरीकी मजदूरों की स्थिति में इसके पश्चात् तीव्रता से परिवर्तन होने लगे। 1837 के वाद प्रामाणिक समय के अनुसार मजदूरी की मान्यता का विरोध प्रारम्भ हो गया।

1837 के संतास से यह स्पष्ट हो जाता था कि प्रारम्भिक श्रमिक संघ विकेन्द्रित थे। 1840 और 50 के मध्य कुछ स्थानीय संगठन, दृष्टिगोचर होने लगे और 1860 तक अल्पसंख्या में राष्ट्रीय संगठनों का उद्भव हुआ। गृह युद्ध के मध्य श्रमिक माँग तथा जीवन साधनों के मूल्यों की वृद्धि के कारण अनेक स्थानीय एवं राष्ट्रीय संगठनों का पुर्ननिर्माण हुआ। इनमें प्रथम 1863 में रेलवे अभियन्ताओं के भ्रातृवाद से युक्त संगठन था। इससे प्रेरणा प्राप्त कर अन्य रेलवे संगठन भी निर्मित होने आरम्भ हुये, और 1870 तक श्रमिक संगठन का सुचारुरूप से स्थापना हो गया।

1790 में स्थानीय श्रमिक संगठनों का निर्माण हो चुका था। यहीं से श्रमिक संगठन का इतिहास प्रारम्भ हुआ। 1837 में स्थानीय तथा 1837 के वाद राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण में स्थायित्व आया। लेकिन इससे पहले संगठनों की स्थापना में विभिन्न माध्यमों से प्रतिरोध उत्पन्न किये गये। अधिक उत्पादन, विविधप्रतियोगिताओं तथा नगरों में अधिकाधिक लोगों के कारण जीवन का स्तर गिरने लगा। इसलिये अमरीका के श्रमिक वर्ग की स्थिति का कभी भी पतन न हो सका। 1840 की परिस्थितियों ने संगठनों को आवश्यक बना दिया तथा 1850 तक श्रमिक संगठनों के श्रमिकों को अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगा। इस समय तक श्रमिकों में एक नव जागृति आ चुकी थी तथा 1860 तक 10 राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक संगठन बन चुके थे।

प्रारम्भिक उन्नीसवीं सदी में उद्योगों के विकास के साथ ही साथ श्रमिक आन्दोलन का भी विकास प्रारम्भ हो गया। जैसे-जैसे नियुक्तिकर्ता अथवा मिल मालिकों एवं श्रमिकों के सहयोगियों एवं स्वार्थों में अन्तर बढ़ता गया, श्रमिकों ने संगठित होना प्रारम्भ कर दिया। उनकी मुख्य माँग कार्य करने की अवधि का कम करना तथा पारिश्रमिक में वृद्धि थी। श्रमिक संगठन साधारण श्रमिकों में नहीं प्रारम्भ हुआ अपितु यह सर्वप्रथम कारीगरों के मध्य प्रारम्भ हुआ। 1800 से 1820 के मध्य कारीगरों ने सर्वप्रथम संगठनों की स्थापना की तथा हड़तालों के आधार पर अपनी माँगों को पूरा कराने का प्रयास प्रारम्भ किया। तथापि इन संगठनों में स्थायी प्रभाव नहीं था। न्यायालयों की विरोधी प्रवृत्ति, जन-आक्रोश तथा मालिकों के विरोध के कारण इन संगठनों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। 1820 के पश्चात श्रमिकों की मनो-वृत्ति राजनीति की दिशा में आकर्षित हुई, तथा 1832 एवं 1837 के मध्य उन्होंने हड़ताल एवं अन्य आर्थिक दवावों द्वारा अपनी माँगों को पूरा कराने का प्रयास किया। 1840 के पश्चात बहुत से श्रमिक अपनी असफलताओं के कारण काल्पनिक युक्तियाँ बनाने लगे, परन्तु अगले दशक में कारीगरों ने साधारण श्रमिकों के अतिरिक्त स्वयं अपना एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया।

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में मजदूरों की राजनैतिक गतिविधियों में तीव्रता आनी प्रारम्भ हो गई। इसका मुख्य कारण था मताधिकारों हेतु पूंजी की योग्यता का अन्त। इस राजनैतिक विकास से लगभग सभी श्रमिकों को मत प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त न्यायालयों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध भी मजदूरों में संगठित होने की भावना ने जन्म लिया। औद्योगिक क्रान्ति के कारण नगरों की बढ़ती जनसंख्या ने संगठनों को एक दूसरे के पास लाना प्रारम्भ कर दिया। अन्त में उनके अन्दर इस भावना ने स्थान प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया कि कार्य करने की अवधि निश्चित ही कम होनी चाहिये।

सर्वप्रथम 1827 में फिलाडेल्फिया के श्रमिकों ने 10 घंटे की कार्यावधि के लिये हड़ताल का प्रारम्भ किया। इस प्रकार की घटनाओं ने तत्पश्चात लगभग सभी औद्योगिक नगरों को अपनी ओर आकृष्ट किया। धीरे-धीरे जनसाधारण के उपयोग हेतु निर्मित एवं संगठित मजदूर संगठनों द्वारा लेखों तथा समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया, जिसने मजदूर संगठनों के लिये एक नवीन जीवन दर्शन का निर्माण किया। शनैः शनैः उनके अन्दर सहयोग की भावना का भी प्रादुर्भाव होने लगा। उनकी माँगों में 10 घण्टे की

कार्यावधि, वच्चों की मजदूरी पर प्रतिबन्ध, मुफ्त एवं समान शिक्षा, कर्ज के लिये सजा का उन्मूलन, तथा इनके साथ साथ अन्य बहुत से सामान्य तथा महत्वहीन संगठन स्थापित करने की भावना जन्म लेने लगी। उन्होंने हड़तालों तथा कानूनी संघर्षों को हथियार के रूप में प्रयुक्त किया।

1837 के महान औद्योगिक अपनयन ने मजदूर संगठनों को अत्यन्त हानि पहुँचायी। इस अपनयन में समस्त अमरीकी औद्योगिक संरचना विनष्ट हो गई तथा मजदूर नेताओं के लिये अब यह सम्भव नहीं रह गया था कि वे वेकारों को संगठित कर सके। समस्त राजनैतिक दर्शन भी मृतप्राय हो गये परन्तु इस औद्योगिक अपनयन के पश्चात् श्रमिकों में एक नवीन चेतना का जन्म हुआ। उनमें यूरोप से आने वाले आप्रावासियों के प्रति आक्रोश की भावना ने जन्म लिया। इसी 1837 की महान औद्योगिक दुर्घटना के कारण अमरीका में सामाजवादी दर्शन का आगमन हुआ। यद्यपि ये श्रमिक संगठन क्रान्तिकारी नहीं थे, उनमें पुनः दार्शनिक चेतना का जन्म प्रारम्भ हो गया। अन्ततोगत्वा 1856 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में एक अखिल राष्ट्रीय मजदूर संगठन का जन्म हुआ। इसके सात वर्षों के पश्चात् 'मोल्डर्स अन्तर्राष्ट्रीय संगठन' तथा तकनीकी एवं लोह कर्मियों का एक राष्ट्रीय संगठन भी बना। इसी प्रकार अन्य छोटे-छोटे संगठनों ने भी जन्म लिया जिन्होंने 1860 के पश्चात् अमरीकी औद्योगिक स्वरूप, श्रमिक संगठन तथा अमरीकी सामाजिक परिवर्तनों को अत्यन्त प्रभावित किया। 1866 में राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने अमरीकी श्रमिक समाज में अपना कार्य प्रभावपूर्ण रूप से आरम्भ किया। इस संघ ने सरकार को अपनी नीतियों में सुधार लाने पर बल दिया। इस संघ का मुख्य उद्देश्य युद्धमान संघवाद न होकर राष्ट्रीय श्रमिकों के प्रति सरकार द्वारा सुविधायें ग्रहण करना था। 1873 के संत्रास के मध्य राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की शक्ति का हास हुआ।

इसी मध्य 1869 में एक गुप्त संस्था का गठन हुआ परन्तु धीरे-धीरे इसका विकास होने लगा। इस श्रमिक संस्था 'नाइट्स आफ लेबर' की सदस्यता 1883 के पश्चात् 7 लाख हो गई। 1886 में राबर्ट एली ने इस श्रमिक संस्था की व्याख्या करते हुये इस श्रमिक संघ को आधुनिक समय की संज्ञा दी। धीरे-धीरे यह संघ भी अपनी नीतियों एवं कार्यों के कारण पतनोन्मुख हो गई और उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अमरीकी श्रमिक संघ का विकास होने लगा।

औद्योगिक क्रान्ति का महत्व

यद्यपि प्रारम्भिक दिनों में फैक्टरी प्रणाली में तीव्रता से विकास हुआ तथापि 19वीं शताब्दी तक संयुक्त राज्य एक औद्योगिक राष्ट्र नहीं बन सका था और 20वीं सदी तक औद्योगिक क्रान्ति का पूर्ण प्रभाव हो चुका था। विद्यार्थी स्वयं ही इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि आज के आर्थिक जीवन और उनके पूर्वजों के जीवन में कितना अन्तर था। प्राचीन मोमबत्तियों तथा विजली के चमचमाते बल्बों के मध्य तथा पुरानी मशीनों और आधुनिक मशीनों में अन्तर स्वयं ही स्पष्ट है।

वास्तविक रूप से औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव केवल हाथ के द्वारा निर्मित माल को मशीनों द्वारा बनाना ही था। जहाँ हाथों से केवल दिनभर में दो जोड़े जूते तैयार हो सकते थे वहीं मशीनों से एक आदमी 500 जूते तैयार कर लेता था।

गांवों का नागरीकरण

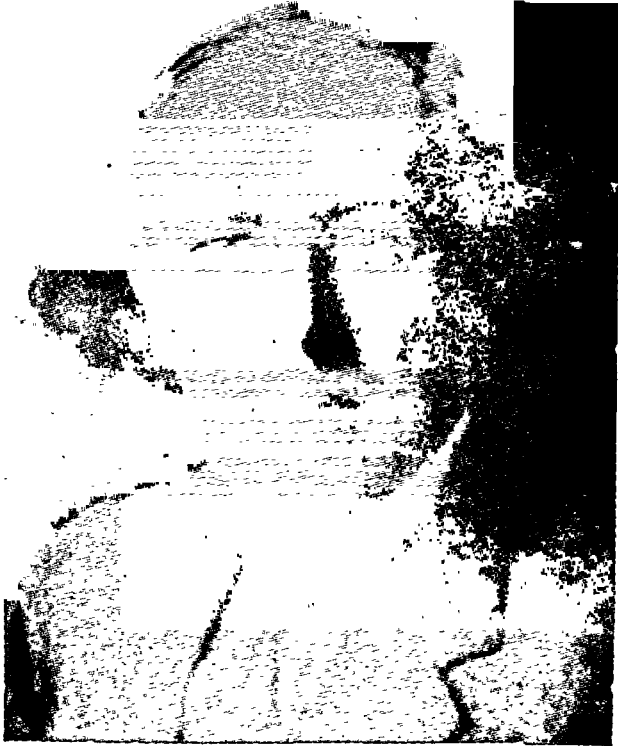
औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव से नागरीकरण बढ़ता गया। जहाँ-जहाँ उद्योग धन्धे खुले वहीं-वहीं जनसंख्या बढ़ती गई। ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या 1800 में 16,00,000 से बढ़कर 1950 में 50,00,000 हो गई। अमरीका की जनसंख्या 1790 में 4,00,000 से बढ़कर 1950 में 1,51,000,000 हो गई। जनसंख्या में यह वृद्धि धन सम्पदा की वृद्धि तथा औद्योगिक क्रान्ति के कारण हुई।

अमरीका की औद्योगिक क्रान्ति ने अमरीकी समाज को नव रूप प्रदत्त किया। इस क्रान्ति ने जन साधारण के जीवन यापन पर अपना पूर्ण प्रभाव अंकित किया। श्रमिकों एवं फैक्टरियों को सूत्रबद्ध कर एक सामाजिक एवं आर्थिक अध्याय को अमरीका के इतिहास में प्रारम्भ किया। यद्यपि उद्योग एवं वितरण की समस्या ने पूंजीपति वर्ग को जन्म दिया परन्तु पूंजीवाद ने भी सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को नवयुग की ओर प्रेषित किया।

इस युग में अमरीका ने विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न आविष्कारों ने तथा उद्योग, हस्तकला, कृषि, सिंचाई, कपड़ा उत्पादन, लोहा, इस्पात आदि के विकास ने अमरीका के सामाजिक एवं आर्थिक पट पर से अज्ञान को दूर कर ज्ञान ज्योति के द्वार अमरीकी नवनिर्माण के प्रति खोल दिये।



साम्राज्यवाद



वुडरो विल्सन (1856-1924)
अमरीका के अट्ठाईसवें राष्ट्रपति

संयुक्त राज्य अमरीका और प्रथम महायुद्ध

संयुक्त राज्य अमरीका को अपनी राजनीतिक विषय परिस्थितियों के मध्य सदैव एक योग्य एवं कुशल नेतृत्व प्राप्त हुआ। स्वाधीनता संग्राम के समय वाशिंगटन जैसा उत्साही, गम्भीर गृह समस्याओं के समय जैक्सन जैसा राजनीतिक योद्धा, गृह युद्ध के गहन राजनैतिक वातावरण के समय लिंकन जैसा कर्मठ नेता तथा प्रथम महायुद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय संकट और विश्व-व्यापी युयुत्सुक वातावरण के समय विल्सन जैसा आदर्शवादी राष्ट्रपति प्राप्त हुआ जो अध्यापक होने के नाते धैर्यवान और विवेकी था। वुडरो विल्सन का 1912 में निर्वाचन मुख्यतया गृह समस्याओं के कारण हुआ था परन्तु 1914 के ग्रीष्म काल में प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ हो जाने के कारण राष्ट्रपति अपने आगामी वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की ओर ध्यानाकर्षित रहे। उनके सम्मुख विभिन्न समस्याएँ थीं जिनमें अमरीकी तटस्थता, अधिकारों के प्रति संघर्ष, यूरोपीय संघर्ष में मध्यस्थता, विश्व में लोकतंत्रिक मूल्यों की सुरक्षा का निर्माण, युद्ध विजय और निरन्तर शान्ति की स्थापना का प्रयास आदि सम्मिलित थे। इन समस्याओं से सम्बन्धित व्यवहार में उन्होंने यथार्थता से अधिक आदर्शवाद का परिचय दिया। फलस्वरूप उन्हें आंतरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय विरोध का सामना करना पड़ा।

राजनीति एवं प्रशासन के गहन अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने अमरीका के प्रशासन और जनता को भली प्रकार से समझ लिया था तथा उनकी शिथिलताओं से पूर्णतया भिन्न था। अपनी पुस्तक 'कांग्रेसनल गर्वन्मेन्ट' तथा अन्य निबन्धों में उसने संघीय प्रणाली की मूल त्रुटियों की ओर इंगित किया है। एक ओर इस प्रणाली में नेतृत्व की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी दूसरी ओर दायित्वों का समन्वय एवं विलियन एक स्वरूप होता है। विल्सन ने अपने प्रशासन में राष्ट्रपति की एक नई परिभाषा दी और यह बताया कि जनतंत्र में भी अधिशासक अपने दल और प्रशासन का निर्विवाद नेता होना

चाहिए। महायुद्ध के समय इन विषम परिस्थितियों में इन नीतियों के परिपालन की आवश्यकता थी।

यूरोपीय देशों में आर्थिक एवं राजनैतिक संघर्ष और व्यवस्था का वातावरण निर्मित हो रहा था। प्रथम महायुद्ध ने इसी असंतुष्टता को प्रतिध्वनित किया। 1914 को ग्रीष्म से अपने दूसरे सत्र तक राष्ट्रपति विल्सन की नीतियाँ मुख्यतः प्रथम महायुद्ध की स्थितियों पर आधारित रहीं। साम्राज्यवादी हितों का संघर्ष और अतीत की त्रुटियाँ ही महायुद्ध के प्रमुख कारण थे। सम्पूर्ण यूरोप में अपना आधिपत्य रखने के लिये एक अखिल जर्मनीवाद की विचार धारा प्रस्फुटित हो रही थी परन्तु युद्ध का तत्कालीन कारण बोस्निया के आरायेवो नगर में, जो अभी तक बहुत कम जाना जाता था, 27 जून, 1914 को राजा फर्दिनन्द की एक स्लाव राष्ट्रपति द्वारा हत्या कर दी गई। यह आस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे और आस्ट्रिया सरकार ने इस हत्या को सर्बिया का षडयंत्र माना। फलस्वरूप विरोध में सर्बिया पर आन्तरिक नियंत्रण की माँग की जो कि स्वाभाविक तौर से अस्वीकृत हो गई। 25 जुलाई, 1914 को आस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया। ऐसे समय में जब कि यूरोप संधियों से परिवद्ध था, राजनैतिक विवाद संघर्ष में परिवर्तित होकर सभी देश एक दूसरे से युद्धरत हो गये।

अमरीका एक व्यापारशील देश था। वाशिंगटन के समय से यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप करने की परम्परा चली आ रही थी, मनरो ने तो इसके लिये अपना सिद्धांत भी स्थापित किया था। महायुद्ध के समय में भी अधिकांश अमरीकी वासी युद्ध से पृथक रहना चाहते थे। 4 अगस्त, 1914 को राष्ट्रपति विल्सन ने अपने देशवासियों को सम्बोधित करते हुये जनता से तटस्थता के नियमों के पालन करने का अनुरोध किया। राष्ट्रपति ने अमरीकी जनता को शान्ति बनाये रखने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि भावनाओं को उत्तेजित करना सरल था, उनको शान्त रखना उतना ही कठिन कार्य था। प्रारम्भ में अमरीकी जनता में विभिन्न मतों का प्रादुर्भाव था, विशेषकर पूर्वी लोग युद्ध में मित राष्ट्रों की सम्पूर्ण सहायता के इच्छुक थे। तत्पश्चात् जर्मनी ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। 6 अप्रैल, 1917 तक अमरीका भावनाओं के विभिन्न सागर में तरंगित होते हुये भी तटस्थ रहा। युद्ध में सम्मिलित होने में प्रमुख श्रेय ब्रिटिश प्रचार गतिविधियों की सफलता थी। ब्रिटेन का अमरीका की प्रचार सेवा पर अधिक प्रभाव था क्योंकि अमरीकी बड़े समाचार पत्रों को समाचार लन्दन स्थित समाचार एजेंसियों द्वारा प्राप्त होते थे जिससे इंग्लैण्ड अपने पक्ष में समाचारों को व्यक्त

करता था। जर्मनी की आक्रामक नीतियों का प्रमाण देने के लिये निरीक्षकों ने युद्ध से पहले के जर्मन साहित्य व प्रलेखों को एकत्र करके उनके आंग्ल अनुवाद का प्रचार प्रारम्भ कर दिया इसमें प्रमुख थी फ्रेडरिक वॉन वर्न-हारदी की पुस्तक 'जर्मनी एण्ड दी नेक्सटवार' वर्नहारदी ने इस युद्ध को जर्मनी को महान बनाने तथा जैविक संतुलन के लिए एक बड़ी आवश्यकता बताया था। जर्मनी ने भी अमरीका में अपने प्रचार के लिये लाखों रुपये खर्च किये तथा अपने एजेन्ट भेजें परन्तु ब्रिटेन का प्रसार अत्यन्त ही प्रभावशाली था इससे अमरीका यह समझने लगा कि विनाश से रक्षा के लिये मित्र राष्ट्रों की सहायता की जानी चाहिये। इधर ब्रिटेन सरकार ने जर्मनी की सीमा निर्धारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय जल यातायात में अवरोध प्रारम्भ कर दिया। फलस्वरूप अमरीका के व्यापार में अवरुद्धता आरम्भ हो गई। अमरीका सरकार ने इसका विरोध किया तथा सामुद्रिक स्वतंत्रता को बल दिया, परन्तु वास्तव में विल्सन की कोई विरोध की इच्छा नहीं थी। फरवरी 1915 में जर्मनी ने अपना अंतःसागरी (पनडुब्बी) युद्ध आरम्भ किया तो अमरीकावासियों में रोष की भावना उत्पन्न हो गई। इसका प्रमुख कारण था कि जर्मनी ने विना सूचना के अनेक बार अमरीकी जलपोतों को जलप्लावित कर दिया तथा चेतावनी के उपरान्त भी अन्य देशों के जलपोतों को जल निमग्न कर दिया जिनमें अमरीकी नागरिक थे। विल्सन ने राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद करने पर बल दिया तो जर्मनी ने यांत्रिक जलपोतों पर आक्रमण न करने की बात को स्वीकार कर लिया किन्तु इस प्रकार की कार्यवाही को अवैध घोषित नहीं किया।

मित्र राष्ट्रों के साथ अमरीका के आर्थिक हित भी सम्मिलित थे। अमरीका के इन देशों से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध थे। अमरीका से इन देशों में लाखों अरबों डालरों का नागरिक व युद्ध का सामान आ रहा था जो कि ऋण के रूप में था। जर्मनी ने अमरीका से युद्ध के सामान पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा जिसे अमरीका ने अस्वीकार कर दिया। अमरीका यदि अपने सामान का विक्रय बन्द करता और यदि वे देश अमरीकी ऋण को वापिस करने से इन्कार कर देते तो अमरीकी कम्पनियों को जो युद्ध में करोड़ों डालर उत्पन्न कर रही थी, भारी क्षति का सामना करना पड़ता। इन परिस्थितियों में अमरीका की पूर्ण तटस्थता लगभग असम्भव सी दीख रही थी। अमरीका के आर्थिक हित मित्र राष्ट्रों की विजय चाहते थे। तटस्थता के नियमों का पालन करते हुये अमरीकी जनता शान्तिमय वातावरण बनाये रखने की इच्छुक थी, परन्तु यूरोप में अग्रित युद्ध के कारण भावनात्मक एवं दौड़िक निष्पक्षता एवं समदर्शिता को सम्पोषित करना एक अत्यन्त कठिन कार्य था। इसके मुख्य कारण ब्रिटेन के प्रति अमरीका

वासियों का घनिष्ठ आर्थिक एवं सांस्कृतिक बंधन, ग्रेट ब्रिटेन का मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य की सत्यता का प्रचार, जर्मनी की सागरीय पोतों के प्रति अमानवता का व्यवहार, तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में केन्द्रीय शक्तियों (धुरी राष्ट्र) द्वारा ध्वंसन कार्य अमरीकी जनता के रोष के उत्तरदायी थे ।

राष्ट्रपति विल्सन और उनके प्रथम राज्य सचिव, विलियम ब्रायन ने राष्ट्र में तटस्थता बनाये रखने के संघर्ष के साथ अमरीकी पोत-भारों के अधिकारों एवं सम्मान की भी माँग की । परन्तु परस्पर विरोधी देशों का यह उद्देश्य था कि अमरीका से युद्ध सम्बन्धी सामग्री मित्र राष्ट्रों को न पहुँच सके । इसके अतिरिक्त जर्मनी सागरीय नियमों का उल्लंघन कर बिना चेतावनी विदेशी जलपोतों पर मनमानी कार्यवाही कर रहा था ।

सर्वप्रथम गम्भीर घटना मई, 1915 में घटित हुई जब जर्मनी अंतःसागरीय यौद्धिक चेष्टा में बिना चेतावनी के ब्रिटिश जलपोत 'लूसीतेनिया' को जल निमग्न कर दिया था । इस घटना के तुरन्त पश्चात् अमरीका के राज्य सचिव ब्रायन ने जर्मनी के विदेश-मंत्रालय को विरोध पत्र बर्लिन स्थित अमरीकी राजदूत के द्वारा प्रेषित किया ।

इस पर भी जर्मनी की ओर से संतोषजनक उत्तर न पा कर राष्ट्रपति ने ब्रायन से तर्जनयुक्त पत्र प्रेषित करने के लिये कहा । इस पर ब्रायन ने जो शान्तिप्रिय प्रकृति का व्यक्ति था ने कहा कि कठोर चेतावनी देने से कहीं विश्वयुद्ध की सम्भावना में वृद्धि न हो जाय । ब्रायन के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी रावर्ट लेनसिंग धीरे-धीरे मित्र राष्ट्रों का और अधिक हितेच्छु बन गया । अभी 'लूसीतेनिया घटना' का समझौता ही नहीं पाया था कि एक अन्य अंग्रेजी पोत 'अरेविक' को जलमग्न कर दिया गया । इस जलपोत में दो अमरीकी यात्री भी मृत्युग्रस्त हुये । इन अप्रत्याशित घटनाओं ने अमरीकी जनता की भावनाओं को उत्तेजित कर दिया और जर्मनी के राजदूत काउन्ट योहान-हाइन्रिक वर्नशटौफ ने अमरीका की 'युद्धभावना' को भाँप लिया । ऐसी परिस्थिति में सम्भावित युद्ध भावना के निवारण हेतु राजदूत ने भविष्य में ऐसी घटनाओं के घटित न होने का आश्वासन दिया । इस आश्वासन ने राष्ट्रपति विल्सन को एक प्रकार से अल्पकालिक राजनयिक विजय प्रदान की । यद्यपि मार्च, 1916 तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई किन्तु फ्रांसीसी यात्रिक पोत 'ससिक्स' पर आक्रमण के द्वारा छह अमरीकी यात्री घायल हो गये । अमरीकी राष्ट्रपति के पुनः चेतावनी देने पर जर्मनी ने 'ससिक्स' वचन के द्वारा तटस्थ देशों के प्रति आक्रमक नीति न अपनाने का वचन दिया तथा तटस्थता के कारण अन्य देशों द्वारा जर्मन हितों की अवहेलना को न सहन करने की माँग को

राष्ट्रपति विल्सन ने 'ससेक्स वचन' के अंतिम अनुबन्धों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें जर्मनी ने अमरीका से अपने सहयोगियों से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत कार्य की मांग की। यद्यपि विल्सन ने जर्मनी के आग्रह को अस्वीकार कर दिया किन्तु ब्रिटेन को राष्ट्रपति ने तटस्थता अधिकारों के अन्तर्गत कार्य करने हेतु पत्र प्रेषित किया। ब्रिटेन ने अमरीकी अनुरोध पत्रों को या तो मान्यता नहीं दी या उनका उत्तर संतोषजनक नहीं रहा।

इसके उपरान्त यह प्रश्न उत्पन्न होता था कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके वशीभूत होकर ब्रिटेन अमरीका के अनुरूप होकर कार्य नहीं कर रहा था? वस्तुतः इसके अनेक कारण थे - (1) अमरीकी व्यापारिक समाज ब्रिटेन की विजय का इच्छुक था परन्तु तटस्थता के नियमों का पालन इसकी सम्भावना को न्यून कर देता था, (2) राजदूत वाल्टरवेज निरन्तर अमरीका के प्रतिवादों का मृदुकरण करते रहे थे, (3) ब्रिटेन के अतिक्रमण के द्वारा अमरीका की जीव हानि नहीं हुई, (4) जब भी ब्रिटेन ने कोई अप्रियकारी कार्य किया तो जर्मनी की ओर से अवश्य ऐसी घटना घटित हुई जिससे अमरीका को ब्रिटेन के कार्य की उपेक्षा करनी पड़ी।

राष्ट्रपति विल्सन ने 1917 के आरम्भ में समझौताकारी नीति अपनाने की चेष्टा की परन्तु उनकी अवहेलना की गई। राष्ट्रपति भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जर्मनी भी वास्तव में शान्ति का इच्छुक नहीं है। जर्मनी ने फरवरी 1917 में 'ससिक्स वचन' का परित्याग कर अप्रतिबन्धित अंतः सागरीय युद्ध आरम्भ कर दिया। संयुक्त राज्य अमरीका ने तटस्थता के अधिकारों की अवहेलना के फलस्वरूप जर्मनी से अपने सम्बन्धों का विच्छेद कर लिया। इसके अतिरिक्त 'जिमरमनपत्र' के रहस्योद्घाटन ने सम्बन्धों में और अधिक कटुता उत्पन्न की। इस पत्र के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हुई कि जर्मनी मैक्सिको एवं जापान को अमरीका के विरुद्ध सम्भावित युद्ध में सम्मिलित करने की चेष्टा कर रहा था। इन सब घटनाओं ने राष्ट्रपति विल्सन के इस निश्चय को दृढ़ता प्रदान की कि अमरीका अब अधिक समय तक सम्मानपूर्वक शान्ति बनाये रखने में असमर्थ था। फलस्वरूप राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल, 1917 को कांग्रेस के दोनों सदनों को अपना ऐतिहासिक युद्ध सन्देश प्रसवित किया। विल्सन ने अपने भाषण में कहा कि तटस्थता की नीति इस युद्धमय वातावरण में अधिक समय तक सम्भव नहीं थी। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इस विध्वंसकारी एवं भयानक युद्ध में शान्तिमय जनता को प्रविष्ट करना एक दुखान्त एवं भययुक्त मार्ग था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने सदन को बताया कि अमरीका सदैव अपने लोकतंत्रीय अधिकारों के प्रति सजग, सतर्क

एवं सजीव रहा था और रहेगा। अपने इन मूल्यों के सम्मान में अमरीकी राष्ट्र युद्ध की ज्वाला में प्रवेश हेतु भयातुर नहीं होगा। इस अकस्मात् युद्ध घोषणा का एक अन्य प्रमुख कारण रूस में साम्यवाद का प्रसार था, जिससे अमरीका अत्यन्त भयभीत हो चुका था। कांग्रेस के सम्मुख राष्ट्रपति ने अमरीका का स्वार्थ रहित होकर युद्ध में सम्बद्ध होना विश्व शान्ति के लिये एक नितान्त आवश्यकता बताई। अमरीकी पूँजीपति भी इसके निरन्तर इच्छुक थे। एक तो युद्ध में वृहद् धनराशि उत्पन्न करने की आशा थी, इसके अतिरिक्त उनका करोड़ों डालर मित्त राष्ट्रों में ऋण के रूप में लगा हुआ था। विल्सन के इस अनुरोध को कांग्रेस में सर्वसम्मति प्राप्त नहीं हुई। नेबरास्का के सीनेट सदस्य जार्ज नोरिस ने विरोधी पक्ष की ओर से तर्क किया। नोरिस एवं उसके सहयोगी सदस्य युद्ध के ज्वार भाटा को रोकने में असमर्थ रहे। सीनेट ने 4 अप्रैल, 1917 को युद्ध घोषणा को बयासी-छः के अनुपात में मान्यता प्रदान की और प्रतिनिधिक सदन ने दो दिवस पश्चात् 50 के अनुपात में 373 मतों से इस घोषणा को पारित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने युद्ध के मध्य मित्त राष्ट्रों को युद्ध सामग्री, खाद्य पदार्थ एवं ऋण देकर पूर्ण सहयोग प्रदान किया, इसके अतिरिक्त अमरीका ने अपने सैनिक एवं युद्धपोत मित्तराष्ट्रों के सहयोग हेतु भेजे।

इसी प्रकार से कालचक्र के परिवर्तन के साथ 1916 के राष्ट्रपति चुनाव आ गये। प्रजातांत्रिक पार्टी ने विल्सन को पुनः मनोनीत किया। उनका नारा था 'विल्सन ने हमें युद्ध की परिधि से बाहर रखा' और यही अमरीका के हित में था। रूजवेल्ट तथा उसके साथी जो गणतांत्रिक दल से बाहर चले गये थे पुनः उसी दल में सम्मिलित हो गये। पुरातन सदस्य जो रूजवेल्ट विरोधी थे, उनके नामांकन का परित्याग कर दूसरे नेता का अनुसंधान करने लगे। अन्त में गणतंत्रवादियों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चार्ल्स इवान ह्यूज को निर्वाचन हेतु मनोनीत किया। इन लोगों ने भी अपने अभियानों में तटस्थता पर पूर्ण जोर दिया किन्तु अन्य सभी नीतियों में विल्सन को एक कायर पुरुष का नाम दिया तथा प्रचारों में अमरीका में प्रवासी जर्मनवासियों के मत प्राप्त करने के लिये उसे मित्त राष्ट्रों का मित्त बताया। लोकतांत्रिकों का अभियान बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचायक था। चुनाव में ह्यूज की अल्पमतों से हार हुई। उसकी पराजय का प्रमुख कारण केलीफोर्निया में हीरम जानसन से उसका संघर्ष था। जानसन इस जगह से गणतांत्रिकों के टिकट पर सीनेट का आकांक्षी व्यक्ति था जहाँ ह्यूज उसके हाथों बहुमत से पराजित हुआ। चुनाव परिणामों में कोई भी दल सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सका परन्तु लोकतांत्रिक दल का सीनेट में पूर्ण नियंत्रण बना रहा। राष्ट्रपति पद पर पुनः

निर्वाचित होते ही विल्सन ने विश्व शान्ति स्थापित करने के लिये सभी प्रयत्न प्रारम्भ किये। विश्व युद्ध में दोनों पक्षों में युद्ध लक्ष्यों में अत्यधिक विषमता होने के कारण किसी शान्ति समझौते को प्राप्त करना लगभग असम्भव था। इस पर भी राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध इच्छुक राष्ट्रों को अपने हितों व युद्ध के लिये विभिन्न पदों का पुनः अवलोकन करने हेतु आह्वान किया। राष्ट्रपति के इस दिसम्बर, 1916 के अनुरोध को किसी भी पक्ष ने समझने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि प्रत्येक पक्ष (मित्र राष्ट्र एवं घुरी राष्ट्र) स्वयं के लक्ष्यों को अन्य से भिन्न एवं तर्क संगत मानते थे। राष्ट्रपति ने जनवरी 1917 में सीनेट को सम्बोधित करते हुये यह आशा व्यक्त की कि "अब यह समय है कि विश्व में सन्तोषजनक निर्विजय शान्ति स्थापित की जाय"। उन्होंने सभी देशों को आत्म निर्णय के अधिकार, सामुद्रिक स्वतंत्रता, शस्त्रों की सीमायें, गुप्त संधियों का परित्याग तथा सामूहिक सुरक्षा प्रबन्ध के विचार दिये। इस प्रकार विल्सन ने मुनरो सिद्धांत को विश्व व्यापी स्वरूप प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय राज्य इसके विपरीत युद्धोक्त होने के लिये कटिबद्ध थे। इन परिस्थितियों में अमरीका के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। 3 फरवरी, 1917 को उसने जर्मनी से सम्बन्ध समाप्त कर दिये। संयुक्त राष्ट्र का युद्ध में सम्मिलित होने का एक तत्कालीन कारण जर्मन विदेश मंत्री 'जिम्मरमन' का एक पत्र था जिसका ब्रिटेन ने तीव्र प्रचार किया था। इसी मध्य जर्मन पनडुब्बी अभियान ने समस्त महासागरों में भारी उत्पात कराने आरम्भ कर दिये। उसका विचार था कि इंग्लैण्ड को क्षुधा से व्याकुल कर दो तो वह शीघ्र आत्म समर्पण कर देगा।

युद्धरत अमरीका

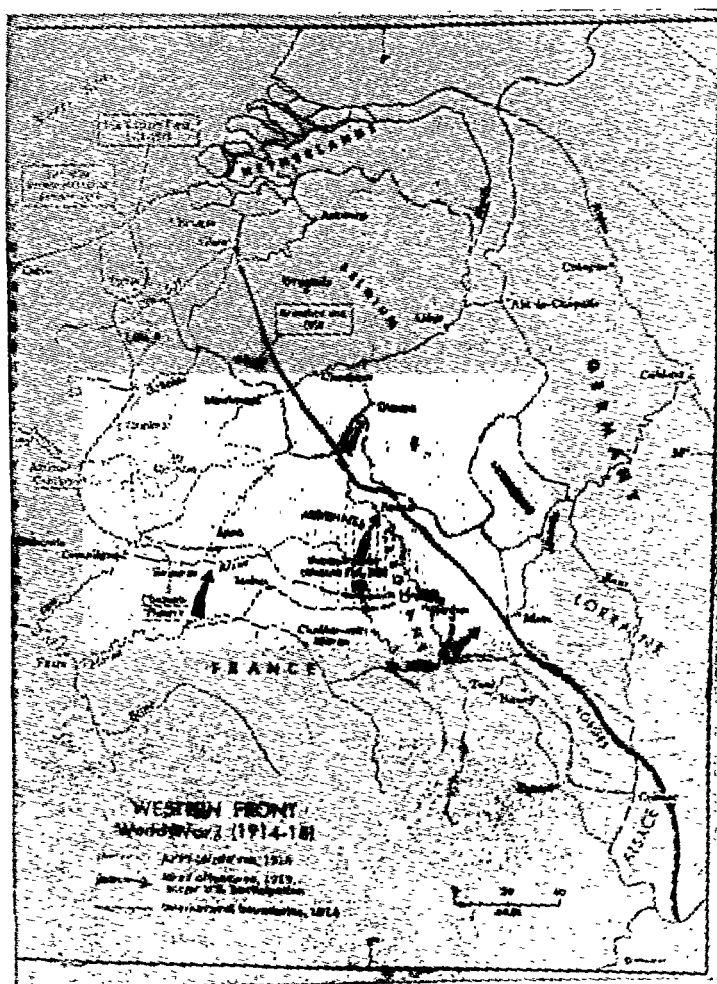
राष्ट्रपति विल्सन की युद्ध घोषणा के पश्चात् अमरीकी कांग्रेस का एक मात्र ध्येय एवं उद्देश्य राष्ट्र को युद्ध के लिये सन्नद्ध करना था। इतने वृहद क्षेत्र में विस्तृत युद्ध में प्रवेश करने हेतु अमरीका को यौद्धिक तैयारी करनी थी। एक सम्पत्तिशाली देश होने के उपरान्त भी अमरीका के पास कोई विशेष प्रबन्धित सैन्य शक्ति न थी। गृह युद्ध के पश्चात् अमरीका किसी युद्ध में रत नहीं हुआ था और अमरीकी जनता आधुनिक युद्ध प्रणाली से अनभिज्ञ थी। युद्ध की तैयारी के लिये सीनेट में एक युद्ध समिति बनाई गई।

आर्थिक संगठन को पुनः स्थापित किया गया तथा एक नये उद्योग मंडल को विशेषकर युद्ध के लिये संगठित किया गया। यातायात के साधनों के उपयोग की वृद्धि की गई तथा नवीन पोत परिवहन कम्पनी की स्थापना की

गई। पोत परिवहन को प्रशासनिक नियंत्रण में लाने के लिये एक मंडल संगठित किया गया। मित्र राष्ट्र खाद्य सामग्री के लिये इस समय पूर्णतया संयुक्त राज्य पर आश्रित थे, अतः उसकी पूर्ति हेतु विशेष कदम उठाये गये। एक खाद्य निगम भी हर्वट हूवर की अध्यक्षता में गठित किया गया। कोयला तथा गैस, (पेट्रोल) के नये भंडार खोले गये तथा समस्त ईंधन को राष्ट्रीय नियंत्रण में लाया गया। वह कारखाने जिनकी कोई विशेष आवश्यकता न थी, बन्द कर दिये गये क्योंकि ईंधन की विशेष आवश्यकता शस्त्र निर्माण उद्योग में थी। श्रमिकों के लिये नये कानून बनाये गये और श्रमिकों की अभावपूर्ति हेतु महिला श्रमिक संघ की स्थापना की गई। श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार की हड़ताल आदि के प्राविधानों को कानून के द्वारा निलम्बित कर दिया गया। शासन को युद्ध व्यय के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। इस व्यय की पूर्ति हेतु नवीन नागरिक करों का अध्ययन किया गया, जनता से अतिरिक्त पूंजी जमा करने का अनुरोध किया गया तथा ऋण लिये गये। युद्ध का समस्त व्यय 35 अरब डालर था।

राष्ट्रपति विल्सन ने युद्ध की घोषणा करते समय जनता को बिना किसी आकांक्षा के देश के प्रति उत्सर्ग की भावना का आह्वान किया। राष्ट्रपति के अनुरोध पर अमरीकी जनता ने एक होकर युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया। एक नयी जन सूचना समिति बनाई गई जिसका कार्य जनभावना को प्रोत्साहित करना था। देशवासियों ने रेडक्रास अभियान, खाद्य एवं औद्योगिक नियंत्रण में पूर्ण सहयोग दिया। देश भक्ति की भावना को जागृत रखने के लिये देश व्यापी प्रचार किया गया। शिक्षा के पाठ्य क्रम से जर्मन विषय को पृथक कर दिया गया एवं जर्मन नाम व प्रणालियों का पूर्णतया बहिष्कार किया गया। यहाँ तक कि आदर्शवादी विल्सन ने भी निर्दयता एवं कठोरता को प्रोत्साहन देते हुये अपने एक मित्र से यह कहा था कि नागरिक प्रवृत्ति की यह कठोरता राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक सूत्र में उपस्थिति होनी चाहिये। युद्ध वातावरण के अनुसार नागरिक व मूल स्वतंत्रताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। कांग्रेस ने मुखवरी अधिनियम 1917 एवं राजद्रोह अधिनियम 1918 को पारित किया। फलस्वरूप लगभग दो हजार व्यक्ति बन्दी बनाये गये जिनमें से अधिकांश को लम्बी कैद की सजायें दी गईं।

पूर्ण सहयोग के होते हुये भी अमरीका की सैनिक कार्यवाही के बिना ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय बनी हुई थी। फलस्वरूप सम्पूर्ण सहायता के लिये वचनबद्ध होने के कारण विल्सन ने अमरीकी नौसेना को मित्र राष्ट्रों की सहायता व जर्मनी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिये। 1918 की



प्रथम विश्व युद्ध का पश्चिमी मोर्चा

ग्रीष्म तक अमरीकी नौसेना ने महासागरों पर नियंत्रण कर लिया था। एटलान्टिक महासागर में जर्मनी के पनडुब्बी अभियान को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया गया। जर्मनी ने पूर्वी यूरोप पर आक्रमण कर युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल दिया। फलस्वरूप रूस में क्रान्ति के वातावरण से जर्मनी की सेनाओं को एक सुअवसर मिला था। पराजित होकर सोवियत संघ ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि द्वारा अपने आपको युद्ध से पृथक कर लिया। इस संधि के द्वारा जर्मनी ने सोवियत संघ के एक बड़े पश्चिमी भाग को अपने अधिकार में कर लिया था। पूर्वी क्षेत्र से मुक्त होकर जर्मनी ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया और युद्ध का निर्णय लेने के लिये 21 मार्च 1918 को पूर्ण शक्ति से पश्चिमी यूरोप व ब्रिटेन पर पुनः आक्रमण कर दिया। मित्र राष्ट्रों की हार निश्चित सी प्रतीत हो रही थी कि एक बड़ी संख्या में अमरीकी सेनाओं ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। इन सेनाओं के युद्ध में प्रवेश मात्र से विजय की दिशा में पूर्ण परिवर्तन हो गया। इतिहासकार समरवेल के अनुसार अमरीकी सहायता के बिना मित्र राष्ट्र किसी भी स्थिति में विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को एक नवीन आत्मबल मिला और उन्हें आशा की नयी ज्योति प्रतीत हुयी। अमरीकी सेनाओं की संख्या के समक्ष जर्मनी की सेनायें अपनी जगह से हटने लगीं और अन्त में रक्षात्मक नीतियों को अपनाने लगीं। युद्ध में धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई। सम्राट कैसर विलियम द्वितीय, मित्र राष्ट्रों जिसको बन्दी बनाने की योजना बना रहे थे, भयभीत होकर हार्लैंड में शरणार्थी के रूप में चला गया। समस्त क्षेत्रों में पराजय के पश्चात् 11 नवम्बर, 1918 को जर्मनी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस प्रकार एक दीर्घकालीन, विध्वंसक और अत्यधिक खूनी मानवीय संघर्ष समाप्त हुआ। अमरीकी जनता में अपनी इस विजय से एक परम उत्साह की लहर फैल गयी। जर्मनी की पराजय के साथ-साथ मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने तुर्की, बाल्कन एवं इटली के मोर्चों पर भी विजय प्राप्त की। इस प्रकार युद्ध में मित्र राष्ट्रों को पूर्ण विजय प्राप्त हुई थी। युद्ध समाप्ति के पश्चात् भी वातावरण में तनाव बना रहा। इसका प्रमुख कारण युद्ध विराम की शर्तों को लेकर अनेक विवाद हो रहे थे। जर्मनी, जहाँ अब सामाजिक लोकतांत्रिक दल का प्रशासन था, के लोगों का विश्वास था कि राष्ट्रपति विल्सन एक आदर्शवादी है तथा शान्ति का समझौता निष्पक्षीय व आदर्शवादके सिद्धान्तों पर होगा। अन्त में नवम्बर 11, 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुये। मार्शल फोश ने इसको आलेखित किया था। युद्ध विराम पर हस्ताक्षर विश्व राजनीति में एक नयी भावुकता के वातावरण को साथ लाये। एक नया युग सा प्रारम्भ

हुआ जिसमें प्रत्येक ओर शान्ति की आशायें प्रतीत हो रही थीं। राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुये अपने भाषण में कहा था "मेरे देशवासियों, आज की प्रातः युद्ध विराम हो गया है, अमरीका ने जिन लक्षणों के लिये युद्ध में प्रवेश किया वह कार्य पूर्ण हो गया। हमारा अब यह परम कर्तव्य होगा कि एक मित्रतापूर्ण वातावरण में एक भौतिक सहायताओं से विश्व में उचित जनतांतीक समाजों की स्थापना की जाय"। वासाइ में युद्ध पश्चात् समझौते के लिये शान्ति सम्मेलन प्रारम्भ हुये। जर्मनी की यह पूर्ण इच्छा थी कि समझौतों को विल्सन के आदर्शों के अनुकूल आलेखित किया जाय, परन्तु युद्धोपरान्त पराजित हुई शक्तियों का हमेशा ही उन्मूलन किया जाता है। जर्मनी ने स्वयं ब्रेस्ट-लिटोस्क की संधि में रूस के साथ अत्यन्त निर्मम समझौता किया था। रूस का लगभग पन्चीस प्रतिशत भाग जर्मनी के हाथों में आ गया था तथा उसे अनेक व्यापारिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। इसकी तुलना में वासाइ की संधि कोई विशेष तौर पर तानाशाही का स्वरूप नहीं थी।

अमरीका के युद्ध में सम्मिलित होने के पूर्व से ही समझौतों एवं शान्ति के आदर्शों को लेकर मित्र राष्ट्रों एवं अमरीका में कई विवाद चल रहे थे। राष्ट्रपति ने मित्र राष्ट्रों की गुप्त संधियों से अपने को अज्ञात बताते हुये (यद्यपि वह उनसे भिन्न था) उनकी कड़ी आलोचना की थी। यूरोप के नेता विल्सन के आदर्शों का उल्लंघन करने की भावनाओं से भरे हुये प्रतिशोध के लिये उद्यत थे। क्लिमेन्सो, विस्मार्क की नीतियों का स्मरण करता था जो फ्रांस, को रक्तहीन करने की योजनायें बनाया करता था। इंग्लैण्ड का प्रधानमंत्री डेविड लायड जार्ज जो प्रतिक्रियावादियों का प्रमुख था, केसर विलियम को फाँसी एवं जर्मनी को पूर्णतया समाप्त करने की योजनायें रखता था। 8 जनवरी, 1918 को सीनेट के सम्मुख अपने वक्तव्य में राष्ट्रपति विल्सन ने इस प्रकार की भावनाओं की कड़ी आलोचना की। अपने भाषण में विल्सन ने विश्व शांति के लिये अमरीका के योगदान का प्रस्ताव रखा। इन आदर्शों के लिये उसने सदन के समक्ष अपनी एक नवीन योजना प्रस्तुत की, जिसे इतिहास में "विल्सन के चौदह तत्त्वों" के नाम से जाना जाता है। प्रथम पाँच तत्त्वों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नये आदर्शों के विलय के रूप थे, फिर बाठ तत्त्व यूरोप की सीमाओं एवं उपनिवेशों के विभाजन से सम्बन्धित थे। अन्त में उसने राष्ट्र संघ की स्थापना का एक विचार दिया था। सदन को सम्बोधित करते हुए उसने कहा था "मैं अमरीका की ओर से यह प्रस्ताव रखता हूँ कि सम्पूर्ण विश्व मानव प्रवास के लिये योग्य एवं सुरक्षित बनाया जाय।" मूलतः उसके

तत्त्व सीमा परिवर्तन के नियमों को सम्बोधित करते थे परन्तु कुछ सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के आदर्शों को एक विधि स्वरूप प्रदान करने के लिये थे। समस्त चौदह तत्त्वों का विवरण निम्नवत् है :—

तत्त्व 1 : गुप्त संधियों समाप्ति और शान्ति के लिये खुले प्रस्ताव।

तत्त्व 2 : समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता, युद्ध और शान्ति में एक समान रूप से होनी चाहिये।

तत्त्व 3 : समस्त आर्थिक प्रतिवन्धों का अन्त कर व्यापार में एक समानता का प्रसार।

तत्त्व 4 : निशस्त्रीकरण।

तत्त्व 5 : उपनिवेशों के सम्बंध में एक निष्पक्षीय समझौता और उपनिवेशीय समाज के अधिकारों को विशेष महत्व प्रदान करना।

तत्त्व 6 : यह रूस से संबंधित था। रूस के साथ सहानुभूति रखते हुये समस्त रूसी सीमा को पुनः निर्धारित करना। रूस के साथ सहयोग और उसे राष्ट्रों के संघ में शामिल होने का निमंत्रण प्रदान करना।

तत्त्व 7 : बेल्जियम का पुनः गठन और उसकी पूर्ण भूमि को स्वतंत्रता प्रदान करना।

तत्त्व 8 : एल्सेस-लारेन को फ्रांस को वापस करना जिससे प्रशासन द्वारा 1871 में फ्रांस के साथ दुर्व्यवहार को ठीक कर लिया जाय।

तत्त्व 9 : इटली की सीमाओं को राष्ट्रीयता के आधार पर पुनः निर्धारित करना।

तत्त्व 10 : अस्ट्रिया-हंगरी के परतंत्र समाज के स्वतः विकास से संबंधित।

तत्त्व 11 : बालकन राज्यों का राष्ट्रीयता के आधार पर पुनः गठन।

तत्त्व 12 : तुर्की और अतुर्की मार्गों को ओटोमन साम्राज्य से पृथक करना।

तत्त्व 13 : नवीन पोलिश राज्य की स्थापना करना जिसमें समुद्री मार्ग सम्बद्ध हो।

तत्त्व 14 : राष्ट्र संघ अथवा राष्ट्रों की एक सामान्य संस्था की स्थापना।

राष्ट्रपति ने इन तत्त्वों को अपने आदर्शों के अनुकूल विना मित्र राष्ट्रों की सहमति के प्रस्तुत किया था। फलस्वरूप जब जर्मनी ने इन तत्त्वों के आधार पर शान्ति समझौता करने की इच्छा प्रकट की तो मित्र राष्ट्रों ने विल्सन की कड़ी आलोचना आरम्भ कर दी। क्लीमेनसो और लायड जार्ज ने अनेकों तत्त्वों का विरोध किया। वास्तव में वे आदर्शों से पृथक हो प्रतिशोध की भावनाओं से शान्ति संधि का अवलोकन कर रहे थे।

स्वयं उसके ही राष्ट्र अमरीका में भी विल्सन का स्पष्ट विरोध हो रहा

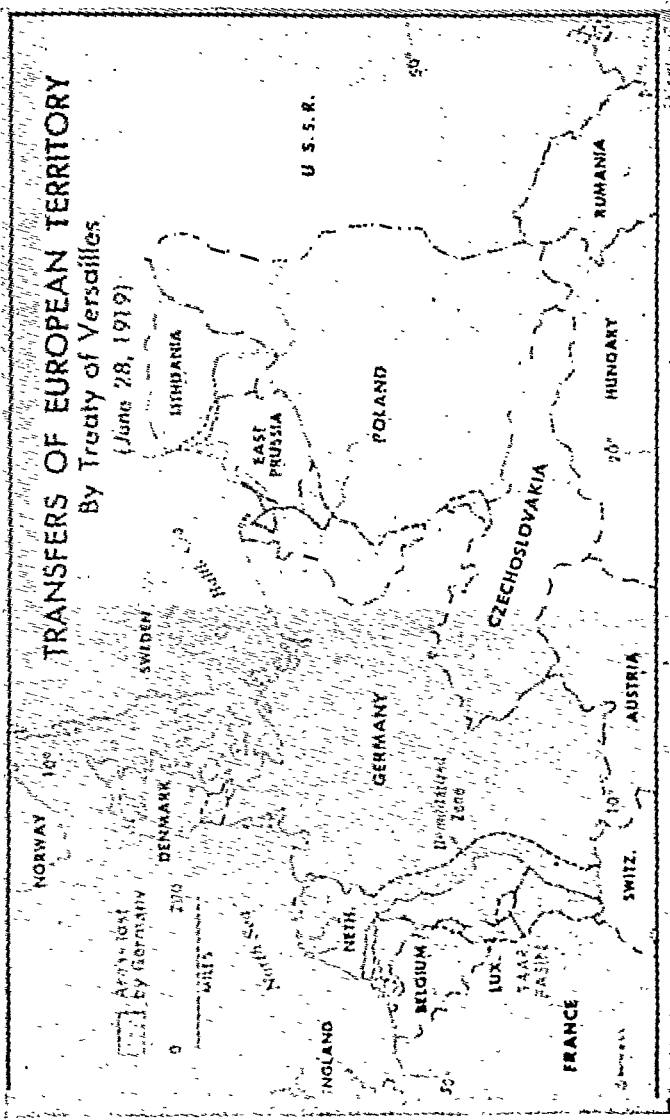
था। नवम्बर, 1918 के कांग्रेस के चुनावों में विल्सन अमरीकी जनता का बहुमत भी प्राप्त न कर सके। यद्यपि अपने चुनाव अभियानों में विल्सन ने गणतंत्रवादियों को प्रशासन के विरुद्ध बताते हुये विदेश नीति को एक राजनैतिक विषय बनाने का सफल प्रयास किया था और अपनी नीतियों के समर्थन में उसने जनता से लोकतंत्रीय दल को विजयी बनाने का अनुरोध किया था। कांग्रेस में लोकतंत्रिक दल के बहुमत होते ही रूलेवेल्ट ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि राष्ट्रपति को अब अमरीकी जनता के भविष्य के विषय में अपने आप कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये फिर भी विल्सन ने अपने को देश का मुख्य अधिशासी बताया और यूरोप के शांति समझौते में अमरीकी विदेश नीति का स्वयं अकेले ही प्रतिनिधित्व करने का निर्णय लिया। वास्तव में यह उनकी एक बड़ी भूल थी। 13 दिसम्बर, 1918 को राष्ट्रपति विल्सन यूरोप पहुँचे। पेरिस के सम्मेलन प्रारम्भ होने से पूर्व ही उन्होंने यूरोप की समस्त राजधानियों का भ्रमण और अपनी नीतियों एवं आदर्शों के विषय में भाषण दिये। सभी स्थानों पर उनका एक महान नेता के रूप में स्वागत किया गया। विल्सन की यह भूल थी। वह इससे अभिन्न थे कि यूरोप के स्वागत करते हुये प्रसन्न जनसमुदाय, पेरिस शांति संधि को अभिपुष्टि प्रदान नहीं करेंगे इसके लिये उन्हें अमरीका की सीनेट के सम्मुख ही प्रस्तुत होना होगा।

जनवरी 18, 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। केवल 32 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। इनमें से 27 स्वतंत्र राष्ट्र एवं पाँच ब्रिटिश उपनिवेशों की सरकारें सम्मिलित थी। समस्त पराजित राज्यों ने अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। प्रतिनिधियों की कुल संख्या 70 थी परन्तु सम्मिलित रूप से उनकी केवल पाँच बार ही सभायें हुईं। संधि का मुख्य कार्य 5 राज्यों की एक समिति ने किया था जिसमें जापान, इटली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका के ही सदस्य थे। जापान एवं इटली के पृथक् हो जाने के पश्चात् संधि का मुख्य कार्य तीन मुख्य शक्तियों ने ही सम्पन्न किया। समिति ने कई विषयों के समाधान व जाँच हेतु अनेक आयोग गठित किये एवं अनेक बार समिति ने इन आयोगों की सूचनाओं पर टिप्पणी की। अमरीका का प्रतिनिधित्व दो विख्यात इतिहासकार प्रोफेसर हार्किंस एवं लार्ड हारवर्ड कर रहे थे। राष्ट्रपति विल्सन के लिये सबसे महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रों की संघ का विषय था। इसके लिये 14 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक आयोग गठित किया गया। 3 फरवरी से 14 फरवरी 1919 के मध्य इन राष्ट्रों की संघ के प्रारम्भिक आलेख का पांडुलेखन किया गया।

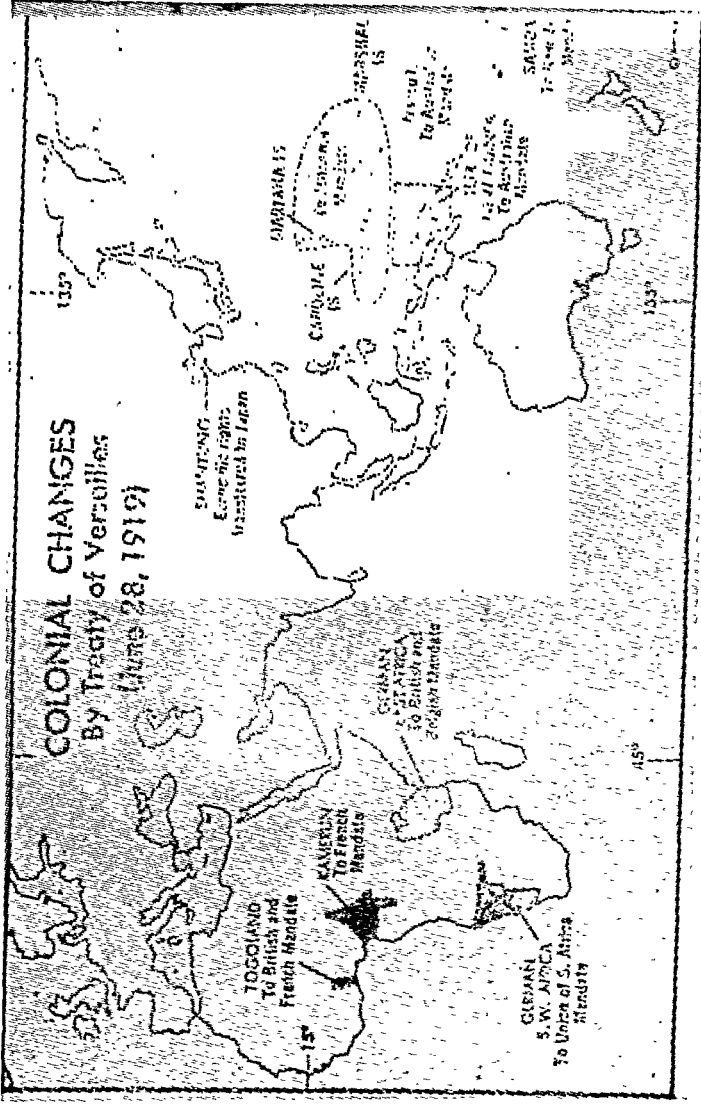
वार्साई की संधि का मुख्य भाग अमरीका से किसी रूप में सम्बन्धित



बायें में दायें—लॉयड जार्ज, ऑरलैंडो, क्लीमेंटो और विल्सन



वर्साई की संधि द्वारा युरोपीय क्षेत्रों का स्थानान्तरण



वर्सॉइ की संधि द्वारा उपनिवेशिक परिवर्तन

नहीं था। संक्षेप में वे नीतियां निम्न प्रकार से थीं। समस्त मित्र राष्ट्र जर्मनी की शक्ति को पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे। युद्ध प्रारम्भ करने का समस्त उत्तरदायित्व जर्मनी पर आरोपित किया गया तथा उससे क्षतिपूर्ति के रूप में एक वृहद् राशि की मांग की गई। 1921 तक 5 अरब डालर की राशि के बराबर सोने की मांग की गई और यह भी निर्देश दिया गया कि इसके पश्चात् क्षतिपूर्ति आयोग द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान भी उसे करना होगा। इस आयोग ने प्रारम्भ में 32 अरब डालर की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित की परन्तु पुनर्वलोकन के पश्चात् इस राशि में पर्याप्त छूट प्रदान करते हुये इस राशि को 71 करोड़ कर दिया गया। क्षेत्रीय और सीमा के विषयों में भी जर्मनी के साथ अत्यन्त कटु व्यवहार किया गया। उससे उसके अफ्रीका, चीन एवं दक्षिणी समुद्रीय सभी उपनिवेश हस्तगत कर लिये गये जिनको जापान तथा ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सम्मिलित कर दिया गया। एल्सेस-लारेन का क्षेत्र फ्रांस को सौंप दिया गया एवं नवीन पोलिश राज्य की स्थापना की गई। राईन नदी का वाम छोर सैनिक शक्तिविहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जर्मनी की सैनिक शक्ति की संख्या एक लाख पर निश्चित कर दी गई, जल सेना में 6 से अधिक लड़ाकू पोत पर पाबन्दी लगा दी गई। जर्मनी को शस्त्र बनाने एवं आयात करने पर रोक लगा दी गई। "आवश्यक सेना सेवा" की प्रथा जो एक शताब्दी से चली आ रही थी, को समाप्त कर दिया गया। सम्पूर्ण संधि का विवरण अत्यन्त गूढ़ एवं विसंगित था। जर्मनी के अतिरिक्त अन्य पराजित धुरी शक्तियों से अलग-अलग संधियां की गईं।

राष्ट्र संघ की स्थापना विल्सन की एक महान उपलब्धि थी। उनके विचार में अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं सम्बन्धों को समझने के लिये इस प्रकार का संघ एक स्थाई व क्रियात्मक कार्य करेगा जिसके उपरान्त सभ्य मानव संसार का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। आक्रमण नीतियों को पूर्णतया समाप्त करने के लिये उन्होंने अपने तत्वों में घोषित किया कि स्वतंत्र उन्मूलन व भूमि-हानी से प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा की जाये। तत्व 12 में शांति मामलों के समाधान के साधनों की व्यवस्था एवं तत्व 16 में आक्रामक राष्ट्रों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों एवं तत्पश्चात् सैनिक कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्र संघ के तीन मुख्य विभाग थे :-(1) जेनेवा में संघ का सचिवालय, (2) सामान्य सभा, (3) सुरक्षा समिति जिसमें कुल 9 सदस्य थे। पांच स्थायी सदस्य एवं चार अन्य सदस्य सामान्य सभा द्वारा समय-समय पर मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी। वास्तव में राष्ट्र संघ विल्सन के मस्तिष्क से उत्पन्न एक आदर्श के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसकी सबसे

बड़ी कमी उसके पास किसी स्थायी सेना का अभाव था। राष्ट्रसंघ का आधार नितान्त नैतिक था और विल्सन जैसे आदर्शवादी पुरुष से अधिक आशा भी नहीं की जा सकती थी। उसकी प्रबुद्धता को कभी भी किसी राष्ट्र ने पूर्णतया स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रसंघ का आधार राष्ट्रों की स्वेच्छा पर ही आधारित था।

अनेक विवादों के पश्चात् जर्मनी ने जून, 1919 ई० में संधि पर हस्ताक्षर किया। उसी के साथ-साथ अन्य पराजित राज्यों के साथ भी संधियाँ हुईं। परन्तु इन संधियों में आदर्शवाद का कहीं भी विलय नहीं था। जुलाई में संधि की संपुष्टि के लिये राष्ट्रपति विल्सन ने उसे सीनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया। विल्सन का विश्वास था कि उसके प्रतिनिधित्व की चर्चा को देखते हुये सीनेट में उसका विरोध न होगा परन्तु आशा के विपरीत सीनेट पूर्ण रूपेण उसके विपक्ष में थी। सीनेट में इस समय तीन प्रमुख दल थे—(1) प्रमुख रूप से चालीस सदस्य जो लोकतांत्रिक दल के थे पूर्ण रूप से विल्सन का समर्थन कर रहे थे (2) दूसरा दल पृथक्तावादियों का था। इसको विलियम ई० वीराह तथा केलीफोर्निया के हाईरक जोन्सन नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। यह सब मिलकर 14 सदस्य थे (3) इसके अतिरिक्त तीसरे दल में गणतंत्रवादी सदस्य थे। हैनरी कैवट लॉज गणतंत्रवादियों का प्रमुख था। इसको वैदेशिक सम्बन्ध समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। हैनरी लॉज ने संधि की संपुष्टि से पूर्व अनेकों संशोधनों की माँग की, जिसपर कई विवाद उठ खड़े हुये। इन आपत्तियों व विवाद को देखते हुये विल्सन ने राजधानी से हटकर देश की यात्रा प्रारम्भ की और जनता में अपना मत प्राप्त करने के लिये भाषणों का एक अभियान आरम्भ किया। परन्तु राष्ट्रसंघ के दुर्भाग्य से 26 सितम्बर, 1919 को जब विल्सन प्यूब्लो में था उसे लकवा हो गया और इस प्रकार राष्ट्रसंघ का एक महान पोषक व समर्थक जीवन भर के लिये पंगु हो गया। 6 नवम्बर, 1919 को वैदेशिक सम्बन्ध समिति के अध्यक्ष सेनेटर लॉज द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इसमें उसने 15 प्रतिबन्ध लगा दिये थे। प्रमुख रूप से आपत्तियाँ इस प्रकार से उल्लिखित थी :—(1) बिना कांग्रेस की अनुमति के संयुक्त राज्य किसी भी देश पर चाहे वह आक्रामक हो या युद्धमय, कोई आर्थिक या अन्य प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता है, न ही इन राष्ट्रों पर कोई सैनिक कार्यवाही की जा सकती थी, (2) मनरो सिद्धान्त के अन्तर्गत आने वाले दायित्वों एवं कर्तव्यों की व्याख्या का अधिकार केवल संयुक्त राज्य को ही होगा न कि किसी अन्य राष्ट्र को, (3) धारा दस के अन्तर्गत दिये गये क्षेत्रीय अखण्डता के आवासन को पूर्णतया अव्यवहारिक बताया गया,

(4) चीन से सम्बन्धित शानहंग क्षेत्र को जापान में सम्मिलित करने के लिये अमरीका विल्कुल सहमत नहीं था (5) भविष्य में यूरोपीय राष्ट्रों के झगड़ों में सम्मिलित होना अथवा ऐसे कर्तव्य को बनाने को विवेकहीनता की संज्ञा दी गई, (6) स्वतंत्र आयरलैण्ड के साथ साथ सहानुभूति एवं कई अन्य मामलों पर प्रतिबन्ध लगाये गये। संधि के विषय को लेकर सीनेट में एक तीव्र दलवन्दी अभियान आरम्भ हो गया। राष्ट्रपति के लिये दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना लगभग असंभव था 19 मार्च, 1920 को अन्तिम वार संधियों पर मतदान हुआ। इसके पक्ष में 49 तथा विपक्ष में 35 मत पड़े। इस अवसर पर लोकतांत्रिक दल भी पूर्णतया विभाजित हो गया। इस प्रकार 19 मार्च के इस मतदान में एक महान आदर्श योजना का अमरीकी इतिहास के लिये सदा के लिये अन्त हो गया। सीनेट ने राष्ट्रपति को संधि वापिस कर दी परन्तु जहाँ तक विल्सन का व्यक्तिगत सम्बन्ध है, उन्होंने अपना कार्यकाल सम्मान जनक रूप से व्यतीत किया। आदर्शों में रहते हुये भी उन्होंने क्रियावाद का सहारा लिया और इतिहास में इन आदर्शों के कारण अमर हो गये। यद्यपि संघ का बिना पुष्टि के वापिस होना उनकी बहुत बड़ी पराजय थी। सन् 1920 के चुनाव में लोकतांत्रिकों ने ओहायो के राज्यपाल कॉक्स को राष्ट्रपति पद हेतु मनोनीत किया और राष्ट्र संघ का समर्थन का नारा दिया परन्तु शायद अमरीकी समाज भी राष्ट्रसंघ के आदर्श को समझ नहीं पाया था। गणतंत्रवादियों के नेता वारेन जी० हार्डिंग, जो ओहायो के सीनेटर थे, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुये और इस प्रकार राष्ट्रसंघ को अमरीका के समर्थन की अंतिम आशा भी समाप्त हो गई।

उपसंहार

प्रथम विश्व युद्ध ने अमरीकी जनता एवं सरकार को दुविधाग्रस्त कर दिया क्योंकि अमरीकी स्वयं को मानवता के शान्ति सन्देश से अवगुण्ठित समझते थे। इसलिये प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ में अमरीका सरकार ने विदेश में हो रही घटनाओं के प्रति रुचि प्रदर्शित नहीं की। राष्ट्रपति विल्सन ने अपने देश निवासियों से तटस्थ रहने का अनुरोध किया और तटस्थता की नीति का विश्लेषण करते हुये राष्ट्रपति ने जनता को विचारों से भी तटस्थ रहने का परामर्श दिया। इस युद्ध ने राष्ट्रपति विल्सन और उनके परामर्शदाताओं को इस असमंजस में डाल दिया कि पूर्वोदाहरण तटस्थता के नियम, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व इस युद्ध के समय उपयोज्य नहीं थे, क्योंकि मित्रराष्ट्र और धुरीराष्ट्र अमरीका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तटस्थता ग्रहण करने के इच्छुक थे। अमरीका की तटस्थता की

नीति के द्वारा दोनों पक्ष लाभान्वित हो सकते थे ।

ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के व्यापारिक जलपोतो के यातायात में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे और दोनों देशों के नौसेना विभाग पारस्परिक वैमनस्य को प्रकट रूप से उदघोषित कर रहे थे । इन आक्रामक नीतियों के कारण राष्ट्रपति विल्सन की स्थित अत्यन्त कठिन कूटनीति में ग्रस्त थी । यदि वे ब्रिटेन के निमंत्रण एवं व्यवस्थापन को मान्यता देते थे तो मित्रराष्ट्रों के प्रति सौहार्दयता का व्यवहार जर्मन सरकार को रूठ कर सकता था । इस प्रकार एक और विशुद्ध एवं प्रमाणिक तटस्थता बनाये रखना असम्भव कार्य था और दूसरी ओर अमरीका स्वयं की पोत अविरोध अतटस्थता की नीति का अहेर बन रहा था ।

उपरोक्त तथ्यों का कूटनीतिज्ञतापूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात् राष्ट्रपति विल्सन ने यह निर्णय लिया कि जर्मनी के अंतः सागरीय (पनडुब्बी) युद्ध के द्वारा अमरीका को ब्रिटेन के प्रतिबन्धों से कहीं अधिक संकटपूर्ण स्थित का सामना करना पड़ेगा । इस प्रकार जर्मनी ने 1916 में अपने राष्ट्रीय हितों से परिपूर्ण अप्रतिबन्धित पनडुब्बी युद्ध को आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया तो राष्ट्रपति के निकट इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था कि वे अमरीकी कांग्रेस से युद्ध की अनुमति माँगें । कांग्रेस ने राष्ट्रपति की युद्ध घोषित करने की याचना को स्वीकृति प्रदान कर दी और 7 अप्रैल, 1917 को अमरीका मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में प्रविष्ट हो गया । यद्यपि अमरीकी देशवासियों ने राष्ट्रपति के निर्णय को बहुमत दिया तथापि कहीं-कहीं देश में साधारण प्रकीर्ण विरोध प्रदर्शित किया गया ।

निःसन्देह, युद्ध के समय अमरीकी सरकार की नीति का विरोध किया गया परन्तु युद्ध पश्चात् अमरीका की युद्ध में स्थित को लेकर अनेकों मत प्रस्तुत किये गये । इनमें प्रथम राजनयिक मत के इतिहासकारों ने 1914-1917 के मध्य अमरीका के कूटनीतिक सिद्धांतों का समर्थन किया । दो मुख्य अध्ययनशील लेखकों वाल्टर पेज तथा कर्नल टउवर्ड हाउस ने राष्ट्रपति विल्सन की हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हुये इस तथ्य को घोषित किया कि यदि अमरीका युद्ध में सम्मिलित न होता तो जर्मनी सैन तंत्र से अमरीका के लोकतांत्रिय सिद्धांतों को संकट उत्पन्न हो जाता परन्तु शनैः-शनैः वार्साय की संधि तथा विल्सन के आदर्शवाद ने भ्रम उत्पन्न कर अमरीका के युद्ध प्रवेश के विषय को पुनःपरीक्षा करने हेतु बाध्य किया ।

1920 के आसपास इतिहासकारों की एक नवीन विचारधारा प्रकट हुई जिसका नामकरण 'संशोधकीय मत' किया गया । इनमें प्रमुख जॉन टर्नर ने विल्सन को कृत्रिम उदारचेत्ता की संज्ञा दी क्योंकि इनके मतानुसार विल्सन

का युद्ध प्रवेश 'बाल स्ट्रीट' के साहूकारों की धनलिप्सा पर आधारित था। टर्नर के विचारों ने अधिक प्रभावित नहीं किया क्योंकि उसके विवादास्पद तर्कों को उस समय की जनता ने विशेष महत्व प्रदत्त नहीं किया। एक ओर संशोधकीय मत के विचारक प्रोफेसर हैरी वानर्स ने अपनी पुस्तक 'जेनीसिस आफ दी वर्ल्ड वार' में इस मत का खण्डन किया कि जर्मनी 1914 के युद्ध का उत्तरदायी था। वानर्स के अनुसार अमरीका के युद्ध में प्रवेश का मुख्य कारण राष्ट्रपति विल्सन की ब्रिटेन के तटवर्ती प्रतिबन्धों के प्रति स्वयं की मौन स्वीकृति तथा मित्र राष्ट्रों को पराजय मुक्त करना था। वानर्स ने अमरीकी शक्ति का युद्ध में ब्रिटेन तथा मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग प्रदान करने को घातक बताया। उनके विचार में यदि अमरीका तटस्थ रहता तो युद्ध पश्चात वर्साइ की संधि से अधिक उपर्युक्त संधि एवं शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध होता। वानर्स ने अपने अध्ययन के द्वारा इसतथ्य को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि अमरीका का युद्ध प्रवेश मित्र राष्ट्रों के प्रति युद्ध सामग्री व्यापार को प्रोत्साहन के कारण हुआ। उनके अनुसार अमरीकी युद्ध का प्रवेश किंचित भी न्याययुक्त एवं नैतिक नहीं था।

इस प्रकार 1920 और 1930 में संशोधकीय मत के लेखकों ने अपनी धारणा विल्सन की अतटस्थता की नीति की परिधि को माना। हार्टले ग्रेटन ने अपने अध्ययन 'वाई वी फौट' में यह विचार व्यक्त किया कि युद्ध के द्वारा किसी राष्ट्र को भी लाभ नहीं पहुँचा और राष्ट्रपति विल्सन की तटस्थता की नीति में परिवर्तन अंग्रेज प्रशासनवाद, पूंजीवादी तथा युद्ध सामग्री निर्माताओं के प्रभाव के कारण हुआ। 1930 के आसपास संशोधकीय विचारधारा के लेखकों को अमरीका की जनता से उनके मत का समर्थन प्राप्त हुआ। इसका कारण विश्व राजनीति की स्थिति का शोचनीय एवं गम्भीर हो जाना था। इटली में मुसोलिनी अपने फासीवाद (फाशिज्म) के द्वारा अधिनायक तंत्र को सशक्त किये हुये था। जर्मनी में हिटलर अपने देश की योद्धिक युयुत्सा को पूर्ण रूपेण निर्मित करने पर बाध्य था और पूर्वी एशिया में जापान अपनी विस्तारवादी नीति के पक्ष में था। इस प्रकार की स्थिति में अमरीकी सरकार एवं जनता विश्व कूटनीति से असंतुष्ट थी। 1917 ने अमरीका में युद्ध में केवल अपने हितों के कारण प्रवेश नहीं किया था, अपितु राष्ट्रपति विल्सन के अनुसार विश्व में लोकतंत्र को सुरक्षित रखना उनका ध्येय था। इसके अतिरिक्त यूरोप में अधिनायक तंत्र अमरीका में उन आदर्शों को परिहास में परिवर्तित कर रहा था जिसके कारण अमरीका प्रथम विश्व युद्ध में प्रविष्ट हुआ था।

उपरोक्त स्थिति में अमरीका प्रथम विश्व युद्ध की नीतियों को पुनः वर्तन का इच्छुक नहीं था। अतः अमरीका ने अर्धपथिक्य की नीति अपनाकर 1930 के मध्य से 1937 तक अनेक तटस्थता अधिनियमों को पारित किया। प्रार्थक्य के साथ ही अमरीका में शांतिवाद का युग प्रारम्भ हुआ क्योंकि देश की जनता इस तथ्य से पूर्णतया अवगत थी कि युद्ध प्रत्येक रूप में अनैतिकता एवं असफलता का परिचायक था। इस मत को चार्ल्स वीयर्ड ने अपनी पुस्तक 'दि ओपेन डोर एट होम' में व्यक्त किया। वीयर्ड ने भविष्य में किसी भी यूरोपीय युद्ध में अमरीका के प्रवेश को निषिद्ध माना। वीयर्ड के अध्ययन ने अप्रत्यक्ष रूप से संशोधकीय विचारधारा का समर्थन किया। 1930 के मध्यकाल में एडविन वोकार्ड तथा पी० लैंग ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक 'न्यूटेलिटी फार दि यूनाइटेडस्टेट्स' 1937 में प्रकाशित की। इसमें राष्ट्रपति विल्सनके प्रशासन को तटस्थता के नियमों का पालन न करने का श्रेय दिया। इन लेखकों के अनुसार अमरीकी प्रशासन ने मित्त राष्ट्रों को विजयी देखने के स्वप्न को साकार करने हेतु अपने तटस्थता अधिकारों का विधिवत पालन नहीं किया। 1938 में चार्ल्स टेन्सिल ने अपनी पुस्तक 'अमेरिका गोज टू वार' में अमरीका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रविष्ट होने के मुख्य कारणों में मित्त राष्ट्रों के प्रति युद्ध सामग्री व्यापार, तटस्थता के नियमों की अनियमितता और राष्ट्रपति विल्सन की अप्रभावित होने की क्षमता को प्रधानता प्रदान की। इसके अतिरिक्त टेन्सिल ने लेनर्सिंग, हाउस तथा पेज के अतटस्थतावादी विचारों को भी दोष दिया। टेन्सिल ने स्पष्ट रूपेण अपने विचार प्रकट करते हुये इस धारणा को व्यक्त किया कि किसी भी रूप में जर्मनी की विजय अमरीका के युद्ध प्रवेश से कम हानिकारक सिद्ध होती। इसके अतिरिक्त 1930 में अनेक इतिहासकारों ने संशोधकीय विचारधारा के विद्वानों के विचारों पर विरोध प्रकट किया। इनमें प्रमुख येल विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स सीमोर थे। इन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपनी पुस्तकों 'दि इन्टिमेट पेपर्स आफ कर्नल हाउस 1926-1928' का चार भाग में संकलन किया तथा 'अमेरिकन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग दि वर्ल्ड वार' एवं 'अमेरिकन न्यूटेलिटी (1914-17) का 1934 और 1935 में प्रकाशन किया। सीमोर ने अपनी रचनाओं में अमरीका एवं प्रथम विश्व युद्ध के विवादस्पद प्रश्न को नैतिकता का आवरण न देकर ऐतिहासिक रूप से उसका अध्ययन किया।

सीमोर ने निःसन्देह राष्ट्रपति विल्सन एवं उनके परामशदाताओं को अंग्रेज प्रशासक की संज्ञा दी परन्तु यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि पालन की पूर्ण चेष्टा की। इसके अतिरिक्त सीमोर ने अमरीका को अनेक

वार ऐसी स्थिति में भी दर्शाया है जब कि अमरीका के जर्मनी के साथ संबंध मित्त राष्ट्रों से कहीं अधिक रुचिकर थे। सीमोर के अध्ययन का मुख्य विश्लेषणात्मक तर्क यह था कि अमरीका का युद्ध प्रवेश जर्मनी की अप्रतिबन्धित अतः सागरीय (पनडुब्बी) युद्ध योजना के फलस्वरूप हुआ। सीमोर ने अपने निष्कर्ष में विल्सन की जर्मनी नीतियों के कारण राष्ट्रपति विल्सन को किसी अन्य विकल्प से रिक्त माना। वाल्टर लिप्पमैन ने अपने प्रकाशन 'यू०एस० फारेन पालिसी: शील्ड आफ दि रिपब्लिक' में अमरीकी युद्ध प्रवेश का मुख्य कारण जर्मन विजय के भय को दिया। लिप्पमैन के अनुसार यदि अमरीका उचित समय पर युद्ध लिप्सा को शान्त करने हेतु मित्त राष्ट्रों को सहयोग प्रदत्त न करता तो अमरीका स्वयं की शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने में असमर्थ होता। इसके साथ ही जार्ज केनन तथा हान्स मॉरगेन्थो ने 1951 में अपने अध्ययन में यूरोपीय शक्ति संतुलन को अमरीका के हित में माना परन्तु इनके अनुसार विल्सन की नीति अमरीका के प्रति राजनैतिक रूप से घातक थी। राष्ट्रपति की नीतियों ने यूरोपीय शक्ति संतुलन को अश्वत कर फासीवाद एवं (नाट्सीइज्य) नाजीवाद को जन्म दिया। इन इतिहासकारों ने विल्सन की नीतियों को उनके आदर्शवाद का द्योतक मानकर विल्सन को अमरीकी राजनीति के हन्ता की संज्ञा दी। यद्यपि मॉरगेन्थो एवं केनन ने यथार्थवादी मत को विल्सन की नीति के प्रति प्रस्तावित किया, परन्तु इन्होंने विल्सन के उस समय के राजनैतिक असमंजस तथा विश्व कूटनीति की अधीरता को यथार्थवाद में परिणित नहीं किया।

इस प्रकार उपरोक्त इतिहासकारों एवं विद्वानों के विचारों का संश्लेषण किसी रूप में एक दूसरे के प्रति समर्थन प्रकट करता है और कहीं पूर्ण विरोधाभास का परिचायक है। विल्सन की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन स्वयं में परिपूर्ण नहीं है। इसका कारण यह प्रश्न है कि अमरीका ने युद्ध प्रवेश क्यों किया। युद्ध प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिये था, युद्ध प्रवेश के अतिरिक्त विल्सन की नीति क्या होनी चाहिये थी तथा अमरीका का हित एवं अहित किन नीतियों में निहित था। यह प्रश्न स्वयं में इतिहासकारों के प्रति सम्बोधित है।



अध्याय 8

महायुद्धोमध्य अमरीका

प्रथम विश्व युद्ध के अन्त (1918) से नव अर्थ नीति (1933) के आरंभ का मध्यकाल राष्ट्रपति वारेन हार्डिंग के अनुसार 'पसमता प्रत्यावर्तन' (रिटर्न टू नारमेलसी) का युग था और राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने इस युग को 'कठोर व्यक्तिवाद' रगेड इन्डिविड्युलिज्ज के काल की संज्ञा दी। इस समय में थियोडोर रुजवेल्ट के प्रगतिवाद एवं विल्सन की 'नव स्वतंत्रता' को शून्य कर व्यक्तिवाद एवं स्वार्थवाद का अपना युग आरम्भ हुआ।

आर्थिक

इस युग में 'मद्य निषेध के' नियमों के असफल प्रयोग के कारण हार्डिंग की अपकीर्ति आरम्भ हुई। मद्य निषेध के सिद्धान्त को अमरीका में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य प्रोत्साहन मिला क्योंकि यह विश्वास किया जाता था कि मद्य निषेध के द्वारा सैनिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अक्टूबर, 28, 1919 को 'राष्ट्रीय मद्य निषेध अधिनियम' पारित किया गया जिसके अन्तर्गत मद्य किण्वन एवं मद्यकरण, मद्यक्रय, मद्य विक्रय, एवं मद्य परिवहन शासकी आज्ञा के विना दण्डनीय था।

इस मद्य निषेध अधिनियम के पारित हो जाने के फलस्वरूप मद्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार की पर्याप्त वृद्धि हुई। मद्य निषेध के कारण अमरीका में अपराध एवं अपराधियों की संख्या बढ़ गई। देश में मद्य की तस्करी तथा अवैध रूप से मद्य का किण्वन होने लगा। मद्य निषेध से उत्पन्न अराजकतावादी तत्वों ने शिकागो को अपना अपराध केन्द्र बनाया। कुछ असामाजिक तत्वों ने संगठित होकर 'जिनमें जॉन टोरियो' और 'एल्कापून' प्रमुख थे। 1924 में टोरियो और एल्कापून ने सिसरो में मेयर के चुनाव को पूर्णरूप से छलयोजित किया। 1924 के चुनाव के पश्चात् सिसरो इन अपराधियों का केन्द्र बन गया।

इन संगठनयुक्त अपराधियों से जनता संतुष्ट हो गई और संघीय, प्रांतीय एवं नागरीय प्रशासन इन अपराधियों पर नियंत्रण रखने में असफल रहा। फलस्वरूप राष्ट्रपति हूवर ने मई, 1929 में राष्ट्रीय विधि आयोग (विकरशैम आयोग) नियुक्त किया। दो वर्षों के पश्चात् इस आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मद्य-निषेध को सामाजिक असंतुलन का मुख्य कारण माना। इसलिये 1932 में लोकतन्त्रीय दल ने विजय प्राप्त की और मद्य निषेध अधिनियम में परिवर्तन किये गये। इस प्रकार संघीय शासन का मद्य निषेध का 'भव्य प्रयास' असफल रहा।

स्त्री मताधिकार

इसी मध्य स्त्रियों के मताधिकार का प्रश्न पुनः जाग्रत हुआ। विश्व-युद्ध से पूर्व एक समाज सेविका एलिस पाल ने जो पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० थी, स्त्रियों के संगठन को कार्यान्वित किया। यह संगठन एक 'युद्धमान स्त्री मताधिकार कांग्रेस संघ' के रूप में था जिसका एकमात्र ध्येय स्त्रियों के मताधिकार के लिये संघर्ष करना था। इसके अतिरिक्त केरी चैपमेनकैट ने 'राष्ट्रीय अमरीकी स्त्री मताधिकार संस्था' की स्थापना कर स्त्री मताधिकार की समस्या को प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस संघ ने व्हाइट हाउस के समक्ष प्रदर्शन किया और 'स्त्री मताधिकार संस्था' ने राजनीतिज्ञों को इस तथ्य से अवगत कराया कि यदि अमरीकी स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया तो इंग्लैन्ड से कहीं अधिक हिंसात्मक वातावरण अमरीकी स्त्रियाँ उत्पन्न करने में सहायक होगी। सीनेट और प्रतिनिधी सदन के वाद विवाद के पश्चात् अगस्त, 1920 को स्त्री मताधिकार को संविधान के उन्नीसवें संशोधन की मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार स्त्री समाज ने अपनी चालीस वर्षों की संघर्ष की उपलब्धि ग्रहण की। राष्ट्रीय अमरीकी संस्था ने विघटित होकर 'स्त्री मताधिकार लीग' को जन्म दिया। इस नव संस्था ने राजनैतिक रूप से सक्रिय स्त्रियों को संयुक्त रूप से एक विचार मंच प्रदान किया। अपने प्रथम राष्ट्रीय चुनाव में स्त्री मताधिकार के फलस्वरूप राष्ट्रपति हार्डिंग निर्वाचित हुये तथापि उन्नीसवें संशोधन ने अमरीकी लोकतांत्रिक अधिकार पद्धति में एक अन्य अध्याय को संलग्न कर उस कार्य को पूर्ण किया जिसको बहुत समय पूर्व ही कार्यान्वित हो जाना चाहिये था।

आप्रवासी समस्या

आप्रवासी प्रतिबन्ध का आन्दोलन सुचारु रूप से आयोजित नहीं था।

आप्रवासी संस्था स्त्रियों के मताधिकार के संगठन की भाँति राजनैतिक शक्ति से परिपूर्ण नहीं था परन्तु एक अवधि के प्रचार के पश्चात् इसका कुछ प्रभाव जनता पर पड़ने लगा था। 1911 में चालीस खंडीय डिलिगम रिपोर्ट ने इस तथ्य की पुष्टि की कि पूर्व एवं दक्षिण यूरोप से आने वाले नव अप्रवासी राष्ट्र के प्रौढ़ वर्ग से बौद्धिक एवं नैतिक मूल्यों में कहीं अधिक न्यून थे। इस धारणा का यह प्रभाव हुआ कि आगामी अप्रवासियों को शैक्षिक परीक्षा अनिवार्य कर दी गई। राष्ट्रपति विल्सन ने इस बात को महत्व दिया कि जो आप्रवासी अवसर प्राप्त के लक्ष्य से अमरीका में आ रहे थे, उनको अपनी शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण करके ही अमरीका आना चाहिये था, परन्तु कांग्रेस ने उनके निषेधाधिकार के पश्चात् भी विधेयक पारित कर दिया।

युद्ध के मध्य और अधिक कठोर नियम आप्रवास के हेतु पारित किये गये। इसका मुख्य कारण शैक्षिक परीक्षण के प्रतिबन्ध की असफलता था। 1919 के मध्य में यह ज्ञात होने लगा कि उपरोक्त प्रतिबन्ध के द्वारा दक्षिण एवं पूर्व यूरोप के अप्रवासियों की संख्या में विशेष कटौती नहीं हुई। इसके समाधान हेतु एक नवीन "नियतांश पद्धति" (क्वोटा सिस्टम) की योजना के अन्तर्गत कार्य करने का निर्णय लिया गया। इस नियतांश पद्धति के अनुसार अमरीका में निर्वासित आप्रवासियों के कुछ अंश को आवास की आज्ञा प्रदान करने का निश्चय हो गया। 1921 के आरम्भ में अमरीकी सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन ने नियतांश सम्बन्धी विधेयक को पारित करने का निश्चय किया। इसके अन्तर्गत आप्रवासी कार्यालय को 1921 और 1922 के मध्य अमरीका में रह रहे आप्रवासियों के अतिरिक्त तीन प्रतिशत और आप्रवासियों को अमरीका में प्रवास करने की आज्ञा प्रदान करना था। यद्यपि राष्ट्रपति विल्सन ने इस विधेयक को लघु निषेधाधिकार द्वारा समाप्त कर देना चाहा परन्तु कांग्रेस ने इसे पुनः पारित किया और मई, 1921 को इस विधेयक को 'देश विधि' में पारित कर दिया गया।

1924 में कांग्रेस ने आप्रवासियों पर और कठोर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ किये। इस नवीन विधान के अनुसार 1927 के पश्चात् एक वर्ष में अप्रवासियों की संख्या एक लाख 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। अमरीकी जनता के मिश्रित उद्भव के कारण उपरोक्त प्रयोग 1930 से पूर्व सफल न हो सका। यद्यपि 'देशिक विधि' के द्वारा चीन से आप्रवास 40 वर्षों से बन्द था, 1924 के अधिनियम में एक प्राविधान जापान आप्रवास सम्बन्धित भी था। अमरीकी कांग्रेस ने कई वर्गों के एवं संसद सदस्यों के संघर्ष के उपरान्त भी जापानी अप्रवास को समाप्त करने का निश्चय किया। उपरोक्त 1921 एवं

1924 के अधिनियमों ने अमरीका के भावी एतिहासिक मार्ग को प्रभावित किया ।

लगभग 300 वर्षों से अमरीका के द्वार नव आगंतुकों के लिये खुले रहे । ओस्कर हूण्डलिन ने अपनी पुस्तक "अपरटिड" में सम्भवतः इस उपयुक्त कथन का श्रेय लिया है कि 'अप्रवासी ही अमरीकी इतिहास थे' । इसमें संशय नहीं कि अमरीका का नगरीयकरण एवं उद्योगीकरण उन्हीं लोगों ने किया था जो अन्य क्षेत्रों से आये थे । अमरीका की स्वतन्त्रता एवं समानता प्रतिशीलता एवं लोक-तन्त्रता को सार्थक सिद्ध करने में आप्रवासियों का योगदान था परन्तु कांग्रेस ने देश के विकास और परिवर्तन के हितों को एक अन्य दिशा की ओर अग्रसर किया । अमरीका की इस नवनीति में प्रकृति का परिवर्तन चक्र एक अन्य लक्ष की ओर लक्षित था ।

सहसा वृद्धि और प्रस्फोट

अमरीका की आर्थिक स्थिति में युद्ध पूर्व युद्ध मध्य एवं युद्धोपरांत एक अनन्य परिवर्तन आया । युद्ध पूर्व अमरीका में आर्थिक क्षेत्र में विकास एवं वृद्धि की योजनाओं पर विचार कर उन्हें प्रयोगात्मक रूप देने की चेष्टा की गयी परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ के साथ अमरीका में एक कृत्रिम सम्पन्नता का विकास दृष्टिगोचर होने लगा । युद्ध में कृषि, परिवहन, तथा उद्योग का विकास गतिशील प्रतीत होता था परन्तु 1920 और 1921 में आर्थिक निपात का अध्याय प्रारम्भ हुआ । युद्धोपरान्त केवल अमरीका ही अपस्फीति एवं आर्थिक प्रतिरोध का लक्ष्य नहीं था परन्तु इसका प्रभाव पूर्ण विश्व में विस्तृत था । युद्ध ने कृषि बेरोजगारी वेतन में कमी तथा विदेशी व्यापार के संक्षेपण ने विश्व आर्थिक स्थिति को अनेक गम्भीर प्रश्नों से ग्रस्त कर लिया था । इस युद्धोपरान्त आर्थिक मंदी से अमरीका अवश्य प्रभावित हुआ परन्तु शीघ्र ही अपने उद्योगीकरण के द्वारा उसने अपना समनुत्थान कर लिया । इसका मुख्य कारण अमरीकी उद्योग एवं उपभोक्ता में सामंजस्य तथा अमरीकी वस्तुओं का विदेशी निर्यात था ।

अमरीकी आर्थिक सम्पन्नता को पुनः स्थापित करने का श्रेय परिवहन उद्योग को था । उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक के आरम्भ में मोटरकार उद्योग ने अभूतपूर्व उन्नति की । इस उद्योग ने लगभग चालीस लाख व्यवसायिक पद सृजित किये । परिवहन उद्योग के विकास के साथ यातायात निर्माण में भी वृद्धि हुई । इस यातायात साधनों की वृद्धि में नवीन सड़कों के निर्माण कार्य से बेरोजगारी की समस्या का कुछ समाधान किया । इस कार्य पर लगभग दो

अरब डालर का व्यय प्रतिवर्ष किया गया। यातायात साधन युक्त होने के कारण भारी उद्योग में भी वृद्धि हुई। इसके साथ रेडियो एवं अन्य विद्युत यंत्रों के विकास ने अमरीकी औद्योगिक एवं सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन दिया।

अमरीका में सदैव सहसा वृद्धि के युग में भवन निर्माण का कार्य भी लक्षित हुआ। भवननिर्माण कार्य 1925 में 1916 से चार गुना अधिक हो गया था। परिवहन, यातायात एवं भवन निर्माण के विकास के साथ विज्ञान के क्षेत्र में हुई परिवृद्धि ने भी अमरीका के आर्थिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाई। अमरीका की 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक की आर्थिक समृद्धि सार्विक नहीं थी। इसका मुख्य प्रमाण युद्धोपरान्त कृषि, कोयलाखान, कपड़ा एवं चमड़े के उत्पादन की गतिहीनता थी। संघीय आरक्षित एवं प्रतिन्यास अधिनियमों की असफलताओं का कारण केवल आर्थिक प्रतिक्रिया ही नहीं थी वस्तुतः न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पूर्ण सहयोग इसे प्राप्त न हो सका। 1920 में उच्चतम न्यायालय ने अमरीकी इस्पात निगम को समाप्त करना अस्वीकार कर दिया क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार आकार, एकाधिकार एवं अधिकृत शक्तियों के आधार पर किसी संस्था को अमान्यता नहीं प्रदत्त की जा सकती थी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उच्चतम न्यायालय किसी भी रूप में भी वृहद व्यापार के प्रतिकूल नहीं था। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने व्यापारिक समितियों को भी संरक्षण प्रदान किया। कूलिज एवं हूवर प्रशासन ने भी प्रतिन्यास (एन्टी ट्रस्ट) अधिनियमों की ओर ध्यान नहीं दिया। राष्ट्रपति कूलिज ने अपने प्रशासन काल में संघीय "व्यापार निगम" में उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जो प्रतिन्यास (एन्टी ट्रस्ट) अधिनियमों के प्रति प्रतिक्रियावादी थे। हूवर काल में वाणिज्य विभाग ने व्यापार में होड़ के स्थान पर सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन दिया। इस काल में वृहद व्यापार की वृद्धि का मुख्य कारण निवेशी न्यासों (इनवेस्टमेंट ट्रस्ट) कम्पनियों एवं निदेशालयों पर पूर्ण नियंत्रण था।

श्रमिक अपसरण

जिस समय राष्ट्र में व्यापारिक समेकन एवं पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा था उस समय श्रमिक संगठन की शक्ति का ह्रास हो रहा था। अमरीकी प्रशासन एवं न्यायपालिका ने श्रमिकों को सुविधा एवं उनकी कठिनाइयों के निवारण करने के लिये कोई कार्य नहीं किया। अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने 1918 और 1922 के मध्य संघीय बाल श्रम कानून को असंवैधानिक ठहराया यद्यपि श्रमिकों

की निष्ठा एवं स्वामिभक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापारिक संस्थाओं ने रुग्ण एवं आवकाश प्राप्त वेतन का प्रयोजन किया परन्तु श्रमिकों की संगठन शक्ति क्षीण होने का कारण नेतृत्व का अभाव था। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को समयानुकूल विकास एवं नवीन पद्धति के मध्य समन्वय करने के अनुभव का पर्याप्त अभाव था।

एक ओर तो युद्धोपरान्त के निकट वर्षों में परिवहन एवं यातायात के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई। परिवहन के साथ ही रेलवे को यातायात ने तथा रेलवे के निर्माण ने अमरीका में आर्थिक विकास की दिशा में एक नवीन चरण स्थापित किया। पोत परिवहन ने भी अमरीका की आर्थिक उन्नति में सहयोग दिया। दूसरी ओर कृषक अवनति का अध्याय आरम्भ हुआ। 1897 से 1919 तक अमरीकी कृषकों ने अमरीकी इतिहास में एक समृद्ध कृषि युग का स्वप्न देखा। इस युग में कृषकों ने अपने ऋणों से मुक्ति पाकर एक नव विकास योजना को जन्म दिया था। राष्ट्रपति विल्सन के प्रशासन ने 'कृषि उद्योग ऋण अधिनियम' के द्वारा बारह नगरों में संघीय भूमि बैंकों को स्थापित किया जिसने कृषकों को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् कृषि भाग्य चक्र में परिवर्तन हुआ। कृषि उत्पादन के मूल्यों में भारी कमी के कारण कृषि वस्तुओं की उत्पादन की अधिकता के कारण तथा आर्थिक मंदी ने कृषकों को हतोत्साहित कर दिया। इसके अतिरिक्त अप्रवास की नीति ने, श्रमिक मूल्यों की अधिकता ने, तथा वाहन शुल्क ने भी कृषकों के लिये इस आर्थिक मंदी काल को घोर संकट मय कर दिया। प्रत्येक आर्थिक मंदी से अनेक राजनैतिक प्रतिध्वनियां भी सम्बद्धित होती हैं। कृषि के इस आर्थिक संकट ने प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित किया। सीनेट एव प्रतिनिधि सदन में कृषि प्रधान प्रान्तों के अनेक सदस्य थे। उन्होंने एक मत होकर कृषि व्यवस्थापन के लिये अनेक योजनायें दीं। इस दशक में कृषकों की मुख्य माँग प्रशासनिक सहायता एवं संरक्षण थी, जिसमें उनके आर्थिक हित संलग्न थे। तत्पश्चात् हुये व्यवस्थापनों ने कृषि उद्योग में अनेक परिवर्तन किये। सीमा शुल्क को नवीन संरक्षण प्रदान किया गया तथा साख नियंत्रण में सुधार लाया गया। इस प्रकार की नीतियों से मूल्यों में एक कृत्रिम वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कृषि व्यवस्थापनों का मूल्य लक्ष्य उत्पादको विपणन में वृद्धि करता था। गणतंत्रवादियों ने सीमा शुल्क के निर्धारण हेतु कांग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया। इस समस्या के समाधान हेतु अधिनियम पारित किये गये परन्तु किसी भी प्रकार से इन प्रशासकीय नियमों द्वारा कृषि वर्ग को उनकी मूल समस्या में सुविधा प्राप्त नहीं हुई - अमरीकी प्रशासन ने निसन्देह कृषकों को ऋण प्रदत्त करने की योजना हेतु

विधेयक एवं विधान पारित किये किन्तु इसके प्रयोजन से साहुकार और कृषक के सम्बन्ध का प्रश्न अपने स्थान पर बना रहा ।

अमरीकी कांग्रेस के उग्रवादी सदस्यों ने शासन को इस तथ्य से अवगत कराया कि शासन को एक वृहद सरकारी निगम की स्थापना करनी चाहिये । इस निगम के द्वारा ऋय की हुई वस्तुओं से कृषकों को लाभ मिलेगा । इस प्रकार कृषि मन्दी के प्रति गणतन्त्रीय दल ने अपना सीमा शुल्क सम्बन्धी सर्वविदिति वाण चलाया ।

राष्ट्रपति हूवर निर्धनता समापन का लक्ष्य लेकर अपने पद पर आसीन हुये । उनका कहना था कि ईश्वर की कृपा से वह दिवस भी निकट था जब अमरीकी राष्ट्र से निर्धनता का लोप हो जायेगा । हूवर आठ वर्ष पूर्व की नीतियों के परिपालन के इच्छुक थे क्योंकि इन नीतियों को उन्होंने ही प्रोत्साहित किया था । हूवर का चुनाव अमरीका की माल विनिमय के प्रस्फुटन के मध्य हुआ था । इन परिस्थितियों में व्यापारियों के निवेशकों को अत्यधिक लाभ उठाने का सुअवसर मिला । हूवर के कथन में कुछ समय तो यथार्थता एवं वास्तविकता प्रतीत हुई परन्तु शेयर बाजार एवं आढ़तियों के आर्थिक लाभ के स्वार्थ ने शासकीय प्रणाली को मंदी की ओर अग्रसर किया । आढ़तियों के लाभालाभ ने बैंक के ऋणों में कई गुना वृद्धि कर दी । ऐसी स्थिति के सर्वेक्षण के पश्चात् संघीय रिजर्व परिषद को आढ़तियों की सट्टेवाजी से चिन्ता व्याप्त होने लगी तथा इसके अतिरिक्त विश्व आर्थिक स्थिति योद्धिक ऋण, विदेशी व्यापार निजी व्यवसाय के व्याज की घोर समस्याएँ भी चिन्ता विषयक थीं । सहसा वृद्धि के युग में भी समृद्धि का वातावरण कहीं-कहीं चिन्हित था और कृषि व्यवसाय पूर्वत मंदी पथ पर था । इसी मध्य बेरोजगारी ने भी आर्थिक मंदी को अपना सक्रिय योगदान दिया । युद्धोपरान्त एकत्रित धनराशि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के पास थी और उपभोक्ता के ऋय सम्बन्धी क्षेत्र में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी । सर्वोपरि सार्वजनिक एवं निजी ऋणों की आशातीत वृद्धि ने ऋणक नीति को महान क्षति पहुँचाई ।

फलस्वरूप अक्टूबर, 1929 में महान आर्थिक विस्फोट हुआ जिसके कारण शेयर बाजार मालसंचकों की विपुल हानि हुई इस कुंडलित आर्थिक मंदी ने राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास क्षेत्रों को अवगुंठित कर लिया । आर्थिक मंदी के प्रवाह ने 1928 से 1932 के मध्य चौबीस हजार से 32 हजार व्यापारिक असफलताओं को ग्रहण किया और पाँच हजार बैंकों के द्वार बंद कर दिये । फलतः 1930 में तीस लाख बेरोजगार हुये और 1933 तक एक करोड़ से ऊपर बेरोजगार हो गये । राष्ट्रपति हूवर ने राष्ट्र को मंदी से मुक्त करने का आह्वान

किया। अमरीकी कांग्रेस तथा राष्ट्रपति 'पुर्ननिर्माण वित्त' निगम की स्थापना कर अमरीकी उद्योग, व्यापार, रेल, यातायात, बैंक तथा कृषि संस्थाओं को नवीन प्रोत्साहन दिया। यद्यपि उपरोक्त निगम ने समयानुकूल सहायता प्रदत्त कर अमरीका को इस भयंकर आर्थिक ग्रहण से मुक्ति देने की चेष्टा की किन्तु केवल इस प्रकार के एक ही कार्य से अमरीका का इस महान आर्थिक विपत्ति से पुनरुत्थान होना सम्भव नहीं था।

विल्सनोपरान्त आन्तरिक दशा

राष्ट्रपति विल्सन की आकस्मिक मृत्यु से अमरीकी समुदाय विस्मय में पड़ गया था। निःसन्देह राष्ट्रपति अपने जीवन उद्देश्यों की पूर्ति कर चुके थे परन्तु उनके आदर्शों का पूर्ण समीकरण अमरीका की नीतियों में यथोचित रूप से नहीं हो सका था। कांग्रेस में अपने लक्ष्यों को स्वीकार न करा पाने की असफलता के पश्चात् भी विश्व राष्ट्रों में उसके आदर्शवाद को प्रयाप्त सम्मान मिला। अमरीका के ऐतिहासिक गगन में वह ऐसे प्रकाशपुंज थे जिसकी परिधि से सम्पूर्ण विश्व आलोकित हुआ था। विल्सन के पश्चात् बारह वर्षों तक सभी राष्ट्रपतियों में व्यक्तिगत योग्यता का अभाव रहा। हार्डिंग, कूलिज एवं हरवर्ट हूवर इस काल में क्रमानुसार एक-एक सत्र के लिये राष्ट्रपति हुये। बारह वर्षों तक शासन दल के प्रमुख अल्पजनों के एक वर्ग के आधीन रहा। बारह वर्ष के इस गणतंत्रवादियों के प्रशासन में तीनों राष्ट्रपति कठपुतलियों के समान इन दलीय नेताओं के इशारों पर कार्य करते रहे। इसका प्रमुख कारण इनमें स्वार्थहीन-कर्मशीलता व आदर्शों की कमी थी।

1920 के राष्ट्रपति निर्वाचन में जनता में कोई उत्साह व उमंग न प्रदर्शित हुई। दोनों ही दल नीतियों के स्थान पर आक्षेपों के सहारे अभियान कर रहे थे। लोकतांत्रिक दल ने इस बार ओहायो के भूतपूर्व राज्यपाल जेम्स एम० कॉक्स को सर्व सम्मति से मनोनीत किया था। फ्रेंकलिन रूजवेल्ट जो इस समय मात्र एक युवा राजनीतिज्ञ थे, उप राष्ट्रपति पद के लिये नामांकित हुये। चुनाव अभियान में लोकतांत्रिकों का सम्पूर्ण दल राष्ट्रसंघ के समर्थन के नाम पर जनमत की माँग कर रहा था। इसके विपरीत गणतंत्रवादियों की कोई विशेष नीति सृजित नहीं हो पाई थी। इस दल में पृथक्तावाद एवं प्रतिबन्धवाद की विचारधाराओं को लेकर अनेक विवाद भी चल रहे थे। सम्पूर्ण दल विल्सन की नीतियों के प्रतिकूलता के विरोध में ही झंडा उठाये हुये था। अपनी नीति की घोषणा में गणतंत्रवादियों ने विल्सनवाद के अन्त

का नारा दिया और यह घोषित किया कि ऐसी किसी संस्था को मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी जिससे अमरीका की विश्वव्यापी प्रभुता की हानि का भय प्रतीत होता हो। गणतंत्रवादियों के नामांकन समारोह में नेतृत्व के विषय को लेकर दल के नेताओं में संघर्ष आरम्भ हो गया। अन्त में ओहायो से सीनेट के सदस्य वारेन जी० हार्डिंग को दल में बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि हार्डिंग एक अर्चित नेता ही था। हार्डिंग ने पृथक्तावाद की विचारधारा के प्रचार के साथ अपने चुनाव अभियान का श्रीगणेश किया। उनका प्रमुख नारा क्रान्तिमय समाज का पुनः सृजन करना था। अमरीकी समुदाय भी महायुद्ध की संघर्षमयी ज्वालाओं से व्याकुल होकर इसी प्रकार की विचारधाराओं की इच्छुक थी। वास्तव में विल्सन की नैतिकता एवं आदर्शवाद की समस्त नीतियां अपने युग में असफल ही सिद्ध हुई थी क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों की समस्त नीतियां स्वार्थयुक्त एवं द्वेषपूर्ण विचारों पर आधारित होती थी। राष्ट्रपति चुनाव में हार्डिंग को लोकतांत्रिक दल के कॉक्स की अपेक्षा अत्यधिक मतों से विजय प्राप्त हुई और इसके साथ-साथ कांग्रेस में भी गणतंत्रवादियों का बहुमत स्थापित हो गया। इस प्रकार नवीन गणतांत्रिक पृथक्तावाद के युग का प्रारम्भ हुआ। बारह वर्षों के इस गणतंत्रवादियों के प्रशासन में राष्ट्रसंघ जैसी किसी भी आदर्शवादी योजना का विदेश विभाग की नीतियों में नाम भी नहीं लिया गया।

नवीन राष्ट्रपति ओहायो राजनीति से अनुभव तो अवश्य प्राप्त कर चुके थे परन्तु राजनीति में उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान कभी नहीं रहा था। उनमें उदारवाद का अभाव था, वह एक अच्छे समर्थक तो अवश्य थे परन्तु एक श्रेष्ठ नेता कभी भी नहीं रहे। साधारण योग्यता के होते हुये भी उन्होंने अपने मंत्रों मंडल में योग्य एवं बुद्धिमान प्रशासकों का चयन किया। चार्ल्स इ० ह्यूज को राज्य व विदेश सचिव के पद पर नियुक्ति की गई। पिट्सवर्ग का करोड़पति एवं बैंकिंग कार्य का कुशल ज्ञाता एण्ड्रू मेलन कोपागार सचिव के पद पर आसीन हुआ। हरवर्ट हूवर को वाणिज्य सचिव एवं विलियम डब्ल्यू हेज को डाकपाल महानिरीक्षक का पद प्राप्त हुआ। उन्होंने अन्य पदों की नियुक्तियों में मितता पर विशेष ध्यान दिया जिस कारण कुछ अयोग्य व्यक्ति भी प्रशासन में आ गये। इनमें से प्रमुख एल्बर्ट वी० फाल, जो न्यू मेक्सिको का सीनेटर एवं अत्यन्त रूढ़िवादी प्रकृति का था, गृह सचिव के पद पर आसीन हुआ। इसके अतिरिक्त एक अत्यन्त भ्रष्टाचारी हैरी एम० डर्गट को न्याय विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। हार्डिंग काल की भ्रष्टाचार युक्त दो उद्धृत घटनायें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। खनिज तेल के नियंत्रण में रिश्वतखोरी ने प्रशासन को सर्वाधिक कुख्यात किया। प्रथम महायुद्ध से पूर्व 1912 में राष्ट्र

पति टैफ्ट ने केलीफोर्निया में नौसेना की आपूर्ति हेतु एल्क पर्वतीय प्रदेश में प्रशासनिक आज्ञा के द्वारा एक राजकीय खनिज तेल श्रोत क्षेत्र नियत किया था। विश्व युद्ध के कठिन समय में इस क्षेत्र के खनिज तेल ने अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी महत्वता को देखते हुये 1915 में राष्ट्रपति विल्सन ने वायोमिंग (टी पाँट डोग) में एक अन्य खनिज तेल श्रोत क्षेत्र की स्थापना की थी। 1921 में आन्तरिक (गृह) सचिव फाल ने नौसेना का नियंत्रण हटा कर इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में करवा लिया। तद्पश्चात् इन क्षेत्रों को उसने राज्यकीय नियंत्रण से पृथक करके व्यक्तिगत पट्टेदारी में रख दिया। वास्तव में उसने अवैध अनुतोषण (घूसखोरी) के द्वारा दोनों खनिज तेलों के क्षेत्रों को अपने मित्रों को सौंप दिया था। संघ गुप्तचर विभाग ने अपनी जाँच में यह सूचना भी दी कि नौसेना सचिव डेनवी ने भी रिश्वत ली थी। अन्त में दोनों सचिवों को पद त्यागना पड़ा। इसी प्रकार की एक अन्य घटना भी कलंक स्वरूप थी। इसका प्रमुख केन्द्र डार्गट था। महाधिवक्ता डार्गट का एक मित्र टामस मिलर 'वाह्यरीय सम्पत्ति अभिरक्षक' विभाग का अध्यक्ष था। दोनों ही मित्रों ने सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के कार्यों में रिश्वत खोरी को प्रचुर प्रोत्साहन दिया। जाँच के पश्चात् मिलर को कारावास भेज दिया गया। इन समस्त घटनाओं ने हार्डिंग के चरित्र व शासन को अत्यन्त कलंकित किया, परन्तु इतना [होते हुये भी उन्हें पूर्ण रूपेण असफल कहना इतिहासोचित न होगा।

वैदेशिक नीति

राष्ट्रपति हार्डिंग के युग में अमरीका की एक नव वैदेशिक नीति ने जन्म लिया। थियोडोर रूजवेल्ट के युग में अमरीका अपने मनरो सिद्धान्त एवं जैफरसन के पृथकतावाद पर आधारित वैदेशिक नीति से हटकर अन्तर्राष्ट्रीय-वाद की ओर अग्रसरित हो गया था। टैफ्ट एवं विल्सन के युग में अमरीकी व्यापार, विश्व-व्यापी प्रसार, एवं नवीन पूंजीवाद के जन्म से इस नीति को और प्रोत्साहन मिला। परन्तु महायुद्ध की समाप्ति पर देश की परिस्थितियों के कारण वैदेशिक नीति में परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक था। युद्ध के पश्चात् की आर्थिक समस्याओं एवं अन्य दयनीय परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिये गणतंत्रवादी राष्ट्रपति ने नवीन पृथकतावाद को जन्म दिया। मार्च 1921 को हार्डिंग ने अपने उद्घाटन समारोह के भाषण में वैदेशिक नीति में परिवर्तन की योजना देते हुए कहा था "महायुद्ध ने हमें एक नयी शिक्षा और अनुभव प्रदान

किया है। राष्ट्र की समस्याओं को सुलझाने एवं राष्ट्रीयता की ज्वाला को खज्वलित रखने के लिये हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतियों से पृथक होना चाहिये। हमारा देश अब यूरोपीय राजनीति के निदेशन एवं विश्व का भाग्य निर्माता का स्वरूप नहीं लेगा।” फ्रैंकलिन रूजवेल्ट काल के प्रारम्भ तक अमरीका इन्हीं नीतियों का अनुसरण करता रहा जिनकी नींव राष्ट्रपति हार्डिंग ने डाली थी। इस मूल नीति के सृजन के पश्चात् भी अमरीका शक्तों के प्रसार के नियंत्रण, जल शक्ति, सुदूरपूर्व आदि समस्याओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमित रूप से भाग लेता रहा। इसका प्रमुख कारण इन समस्याओं से अमरीका का शीघ्र सीधे सम्बन्ध था। वार्शिंगटन सम्मेलन हार्डिंग युग की सबसे महान उपलब्धि थी। सुदूर पूर्व की समस्याओं को लेकर 1921-22 में वार्शिंगटन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति हार्डिंग के मंत्री मंडल में राज्य सचिव चार्ल्स ह्यूज ने प्रशासन काल में कई सराहनीय कार्य किये, वास्तव में वार्शिंगटन का सम्मेलन उसी की योजना थी। जनमत में राष्ट्रसंघ के प्रति कड़ी प्रतिकूलता थी भावना की, परन्तु ह्यूज के विचार में सीनेट द्वारा राष्ट्र संघ को निरस्त करना विश्व शान्ति के स्थापन की योजना को तीव्र आघात पहुंचा था। 1921 की ग्रीष्म में हुये इस सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त वेल्जियम, हॉलैंड, पुर्तगाल एवं चीन के प्रतिनिधि भी उपरोक्त पांच शक्तियों के साथ प्रशान्त व सुदूरपूर्व की समस्याओं के समाधान हेतु सम्मिलित हुये। सम्मेलन का नेतृत्व चार्ल्स ह्यूज ने किया। ह्यूज ने निरस्त्रीकरण हेतु बड़े युद्ध पोतों के निर्माण पर दस वर्षों के लिये पूर्ण निषेध लगाने का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त ह्यूज ने 1878के पूर्व निमित्त युद्ध पोतों, जिसमें आधे से अधिक अमरीका के थे, के नष्ट करने की एक योजना भी दी। एक समकालीन ब्रिटिश संवाददाता के अनुसार राज्य सचिव ने अपने पैंतीस मिनट के वक्तव्य में इतने युद्ध पोतों को ध्वस्त कर दिया जितने की जल सेना के कैंप्टनों ने कई शताब्दियों में नष्ट किये होंगे। पाँचों महाशक्तियों ने राज्य सचिव के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये 6 फरवरी 1922 को एक समझौता किया जिसमें दस वर्षों के पूर्ण निषेध के पश्चात् बड़े युद्ध पोतों का पुनः निर्माण 5 : 5 : 3 : 1-2/3 : 1-2/3 के अनुपात में आरम्भ करना था। इसी सम्मेलन में नौ राष्ट्रों एवं चार राष्ट्रों की पृथक-पृथक दो अन्य संधियाँ भी हुईं। इन संधियों द्वारा महाशक्तियों ने चीन के प्रति अपनी नीतियों को निश्चित किया। इसके अतिरिक्त प्रशान्त महासागर में उपनिवेशों के स्वामित्व की समस्या का समाधान भी किया गया। चीन के लिये पुनः मुक्तद्वार नीति अपनाई गई, और यह निश्चय हुआ कि किसी प्रकार

की शान्ति के भंग होने की सम्भावना पर सभी राष्ट्र विचार विमर्श के द्वारा ही संकट अवस्था का समाधान करेंगे ।

इन संधियों के पश्चात पूर्व मान्य आंग्ल-जापानी संधि के प्राविधानों को निरस्त कर दिया गया । एक अन्य संधि के द्वारा चीन को उसके समस्त सीमा शुल्कों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदत्त किया गया । वार्शिंग्टन सम्मेलन में हुई संधियाँ प्रारम्भ में शान्ति के लिये सराहनीय कदम का स्वरूप थीं, परन्तु इसकी नींव सुदृढ़ न थी । बड़े युद्ध पोतों के निर्माण में निषेध के पश्चात महाशक्तियों ने छोटे पोतों एवं अन्य युद्ध शस्त्रों का निर्माण आरम्भ कर दिया । संधि के प्राविधानों को विस्तृत करने लिये 1927 में राष्ट्रपति कूलिज ने एक अन्य सम्मेलन के हेतु निमंत्रण प्रेषित किया परन्तु ब्रिटेन व जापान के अतिरिक्त अन्य महाशक्तियों ने इसे अस्वीकार कर दिया जिस कारण जेनेवा में हुये सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका । 1930 में हूवर प्रशासन के समय ग्रेट ब्रिटेन ने महाशक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया । लंदन में हुये इस सम्मेलन में वार्शिंग्टन संधि के प्राविधानों की अवधि 1936 तक बढ़ा दी गई । इसके अतिरिक्त छोटे युद्ध पोतों एवं अन्य शस्त्रों के निर्माण पर अवधि हेतु कई निर्णय लिये गये । 1921 को वार्शिंग्टन संधि एवं 1930 के लंदन सम्मेलन की सभी नीतियां, 1936 में हुये द्वितीय लंदन सम्मेलन में अस्वीकृत कर दी गई । गणतन्त्रवादी प्रशासक के अंतिम चरण में राष्ट्र संघ ने 1932 में जेनेवा विश्व (निरस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन किया । राष्ट्रपति हूवर ने भी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने की अपनी भावना को प्रदर्शित करते हुये कई प्रस्तावों को जून 22, 1932 में सम्मेलन के प्रतिनिधियों के समक्ष भेजा । चुनाव के पश्चात नये राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इन्हीं प्रस्तावों का समर्थन करते हुये सम्मेलन के प्रति अपनी उत्सुकता प्रदर्शित की । परन्तु इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप शस्त्रों के निर्माण की इस प्रतिस्पर्धा में कोई गति अवरोध न आ सका । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय राष्ट्रों में एक भय की भावना जाग्रति हो गई थी ।

विश्व शान्ति को स्थिर रखने के लिये 1921 में शिकागो के विधिवक्ता लेविनसन ने बहुमूल्य सुझाव दिया था । उनके अनुसार युद्ध के परित्याग हेतु सभी राष्ट्रों को संधि सम्बद्ध हो जाना चाहिये । सीनेट के अनेक सदस्यों ने लेविनसन के इस सुझाव पर तीव्र अनुकूलता दिखाई । तदपश्चात 1927 में फ्रांसीसी विदेश मंत्री ब्रीयां ने अमरीका व फ्रांस के मध्य इसी विचारधारा पर आधारित एक संधि की योजना दी । फलस्वरूप राज्य सचिव केलॉग के अन्य प्रयत्नों से 27 अगस्त 1927 को पन्द्रह राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की पेरिस में एक

सभा हुई एवं केलॉग त्रीयाँ समझौते पर हस्ताक्षर हुये ।

प्रथम विश्व युद्ध एवं उसके बाद के पुनः निर्माण के समय में अमरीका ने दस अरब डालर की राशि यूरोपीय देश सम्मिलित बीस राष्ट्रों को ऋण के रूप में प्रदत्त की थी स्थिति के सुदृढ़ होने पर फ्रांस के नेतृत्व में ऋणी राष्ट्रों ने इन धनराशि के भुगतान को समाप्त करने अथवा कम करने की माँग की । अमरीका ने इन राष्ट्रों की माँग को अस्वीकार करते हुये ऋण के व्याज में परिवर्तन हेतु 6 फरवरी, 1922 को कांग्रेस में विश्व युद्ध ऋण आयोग अधिनियम पारित किया । तदपश्चात् वासठ वर्षीय दीर्घ भुगतान की योजना द्वारा ऋणों की राशि में भारी कटौती की गई ।

इसी मध्य अमरीका लैटिन अमरीकी राष्ट्रों से अपने सम्बन्ध सुदृढ़ करने की योजनाओं में लीन हो गया । 1923 में सन्तीयागो में एक अन्तर अमरीकी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें गोंड्र सम्मेलन के प्राविधानों का समर्थन किया गया । 1928 में हवाना सभा में अमरीकी देशों की पारस्परिक कटुता व आक्रामक नीति को समाप्त करने पर विचार विमर्श किया गया । 1929 में वाशिंगटन में हुयी एक विशेष सभा में इक्कीस अमरीकी राष्ट्रों ने पेरिस समझौते के अनुरूप एक अन्तर अमरीकी समझौते का विचार प्रेषित किया । 1924 में राष्ट्रपति कूलिज ने अमरीकी जलपोतों को डेभिनेकन गणतन्त्र से वापस बुला लिया, इसके फलस्वरूप डालर कूटनीति का अन्त हुआ । 1928 में राष्ट्रपति कूलिज के प्रस्तावपर 'क्लार्क विज्ञप्ति' द्वारा मनरो सिद्धान्त में भी अनेक परिवर्तन किये गये । इस प्रकार अन्तर अमरीकी सम्बन्धों का एक नया युग प्रारम्भ हुआ । हवर काल में यह सम्बन्ध मित्रता की चरम सीमा पर पहुँच गये ।

पश्चिमी देशों के समस्त प्रयासों के फलस्वरूप भी अमरीका ने अपनी पृथकतावाद की मूल नीति को बनाये रखने के लिये सोवियत संघ को राष्ट्रीय मान्यता देने से इन्कार कर दिया । इस काल में अप्रवासियों के आगमन पर भी अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये । गणतंत्रवादियों के प्रशासन के अन्तिम दिनों में जापान अमरीकी सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न होने लगी थी । इसका मुख्य कारण जापान की साम्राज्यवादी लालसा और इस के कारण दोनों देशों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी । 1931 की सितम्बर में जब जापान ने चीन पर आक्रमण कर मनचूरिया को अपने अधिकार में कर लिया तो अमरीकी प्रशासन ने अपने सभी सम्बन्ध लगभग समाप्त कर लिये ।

1932 में चुनाव अभियानों का दौर पुनः प्रारम्भ हो गया । रूजवेल्ट की विजय के फलस्वरूप चारह वर्षीय गणतंत्रवादी प्रशासन का अन्त हुआ । इसके साथ साथ अमरीकी विदेश नीतियों में भी कई परिवर्तन हुये । विश्व राजनीति

में भी अनेक प्रतिकूल विचारधारार्यें उत्पन्न हो रही थीं ।

राज्य सचिव ने विदेश विभाग के प्रशासन में भी कई परिवर्तन व सुधार किये । उसने 1924 के "रोजर्स अधिनियम" के द्वारा एक व्यवसायिक वैदेशिक सेवा की योजना आरम्भ की, जिसमें अर्हताओं के निर्धारण के पश्चात सीधी भर्ती की योजना प्रस्तुत की गई । इस प्रकार ह्यूज ने वैदेशिक नीति के परामर्शदाताओं का एक नया निकाय स्थापित कर लिया था । अमरीका की इस राजनैतिक दूतवर्ग संस्था ने द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ा सराहनीय कार्य किया ।

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात यूरोप के प्रति अमरीकी विदेश नीति 'पार्थक्य नीति' के सिद्धान्त से निर्देशित थी परन्तु किसी भी रूप में अनम्य नहीं थी । अमरीका ने युद्धोपरान्त ऋण समस्या, पारस्परिक सहयोग तथा शान्ति समझौते के प्रति अपना पूर्ण सहयोग दिया । सुदूर पूर्व में भी अमरीका ने जापान तथा फिलीपीन को स्थायित्व प्रदान करने की चेष्टा की । हार्डिंग ने रूजवेल्ट काल की सीमा-शुल्क नीति में भी उग्रवादी परिवर्तन किये । लेकिन अमरीका में भी 'डालर कूटनीति' और रूजवेल्ट, टैफ्ट एवं विल्सन की पनामा नीति का स्थिर गति से निर्वर्तन होने लगा ।

यद्यपि अमरीका की शान्ति योजना के अन्तर्गत विश्व में संधि समझौते का युग आरम्भ हुआ था और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में एक नवीन चैतन्यता उत्पन्न हुई, किन्तु विश्व राजनीति में सैन्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा ने तथा देशों के सैन्य बजट से अमरीका भी सतर्क हुआ । अमरीका का पुनःशस्त्रीकरण का मुख्य कारण अन्य देशीय सैन्य साधनों का विकास था । तथापि इस नव सैन्य पुनःशस्त्रीकरण की नीति ने सम्पूर्ण विश्व की युद्धोपरान्त शान्ति स्थापना के विचार को धूमिल कर दिया ।

प्रत्याक्रमणवाद



फ्रैंकलिन रूजवेल्ट (1882-1945)
अमरीका के बत्तीसवें राष्ट्रपति

अध्याय 9

द्वितीय विश्वयुद्ध

अमरीकी तटस्थता

1 सितम्बर, 1939 को हिटलर ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्वयुद्ध के यूरोपीय चरण का आरम्भ किया। हिटलर के इस आक्रमण ने इंग्लैण्ड और फ्रांस को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिये बाध्य किया, और इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण महाद्वीप अवदाह ग्रस्त हो गया। अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित करते हुये कहा कि मुझे विश्वास के विरुद्ध विश्वास था कि किसी चमत्कार के द्वारा यूरोप में यह विध्वंसक युद्ध रोक दिया जायेगा परन्तु इस युद्ध की प्रगति ने हमारे विचारों पर तुषारापात किया। इसके उपरांत भी राष्ट्रपति ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि देश में शांति स्थापित किये रखना हमारा परम कर्तव्य है और इस विस्तारवादी युद्ध के मध्य हम लोगों को अपनी मौलिक राष्ट्रीय नीति, नैतिकता, धैर्य तथा शांति बनाकर अपंग हो रही मानव जाति को सहायता प्रदान करनी चाहिये। इस प्रकार अपने महान सिद्धान्तों पर अटल रहकर अमरीका यौद्धिक शक्ति के तर्जन के मध्य भी मानवता को शांति का सन्देश देता रहा।

राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य कथन एक अत्यन्त कठिन कार्य है और यह भी सत्य है कि यह युद्ध सहस्रों मील दूर रहा है परन्तु अमरीका को युद्ध की प्रत्येक गति से अवगत रहना आवश्यक है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से अमरीका इस युद्ध से प्रभावित नहीं है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूपेण किसी भी समय अमरीका राज-नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से प्रभावित हो सकता है।

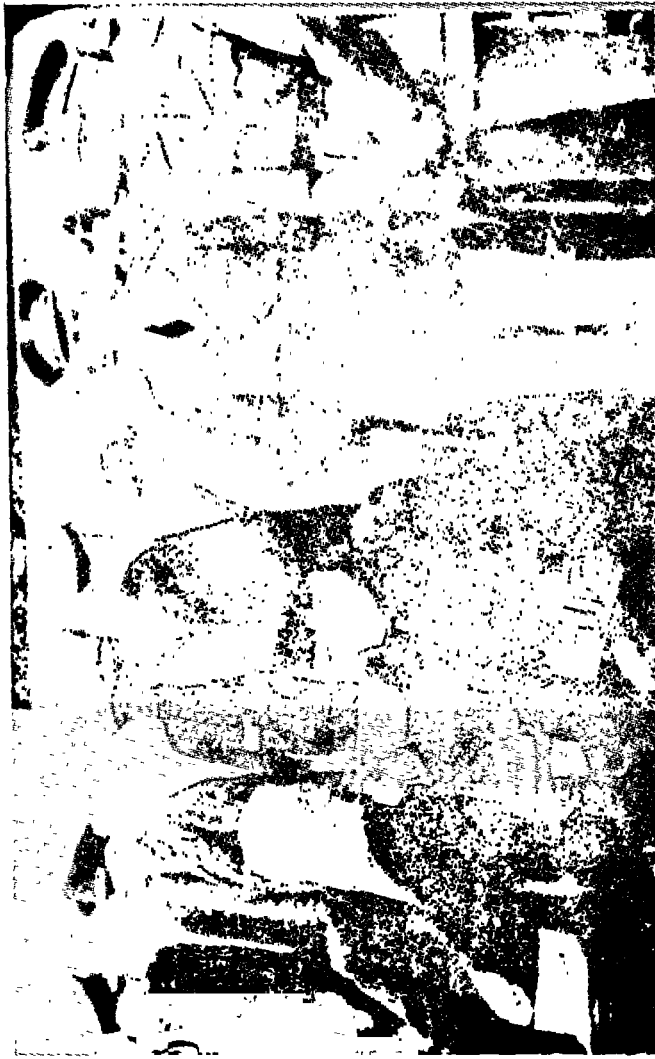
राष्ट्रपति ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि अमरीका शांति में विश्वास रखता है और युद्धचक्र हमारे समीप है, हमें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिये जो पूर्णरूप से जानकारी प्राप्त किये बिना हमारी

नीतियों के भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रति अधिकारपूर्ण ढंग से वार्ता करते हैं ।

राष्ट्रपति ने पुनः अपने देशवासियों से तटस्थ रहने का अनुरोध किया और राष्ट्रपति विल्सन से भिन्न यह मत प्रकट किया कि तटस्थता का अर्थ मानसिक तटस्थता नहीं है अर्थात् देशवासियों को अन्य स्थान पर हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिये । क्योंकि उदासीनता तथा तटस्थता की विचारधारा को मान्यता देने वाले को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह वास्तविकता तथा विवेक के ज्ञान से विज्ञ हो । इसी के साथ राष्ट्रपति ने अमरीका के निवासियों को आश्वासन दिया कि मैंने युद्ध देखा है और मुझे युद्ध से घृणा है, और मैं अपनी पूर्ण शक्ति अमरीका को युद्ध से परे रखने में लगा दूँगा ।

तत्पश्चात् नवम्बर 8, 1939 को तटस्थता अधिनियम पारित किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि विदेशी राज्यों में युद्ध की स्थिति होने के कारण यह आवश्यक है कि अमरीका के देशवासियों के जीवन को सुरक्षा प्रदत्त की जाय तथा देश में आन्तरिक शांति बनाये रखी जाय । ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्य में शांति तथा सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु घोषणाधिकार दिया गया । इस तटस्थता अधिनियम ने राष्ट्र में एक सीमित आपातकालीन स्थिति का प्रादुर्भाव कर दिया । इसी मध्य पश्चिमी क्षेत्रीय गणतन्त्रीय राज्यों की बैठक पनामा में हुई, जिसमें यूरोप की शांति को भंग करने वाले युद्ध में तटस्थता की नीति को मान्यता दी गई । परन्तु इस बात की आशा प्रकट की गई कि इस युद्ध के अप्रत्याशित परिणाम भी निकल सकते हैं जिनके द्वारा अमरीका के मूल हितों को आघात पहुँच सकता था और ऐसी स्थिति में युद्धोत्सुक देशों को तटस्थ देशों के अधिकारों पर अविभावी होने का कोई भी अधिकार न्यायोचित नहीं है । राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रथम विश्वयुद्ध के समय घटित हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुये समय पूर्व सुरक्षा पद्धति पर विचार विमर्श किया । इस पर पूर्ण सहमति प्रकट की गई कि युद्ध को अपनी सीमाओं से दूर रखने हेतु उचित स्वरक्षा साधनों का समय पर प्रयोग किया जाय । इसी अन्तराल में अमरीका के सुरक्षा क्षेत्र पर सैनिक गश्त का पूर्ण उत्तरदायित्व आ गया । तथापि युद्धरत देशों ने अमरीका की चेतावनी के प्रति कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया ।

1939-40 के मध्य में यूरोप में 'कृत्रिम युद्ध' का ही चरण रहा परन्तु 1940 में हिटलर के हालैंड, बेल्जियम और फ्रांस पर आक्रमण करने के साथ ही मुसोलनी ने भी हिटलर का पक्ष लेकर रोम वलिन अक्ष की स्थापना की ।



एटलांटिक चार्टर के समय फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट और विन्स्टन चर्चिल ।
चर्चिल दाहिनी ओर तथा रूजवेल्ट बायीं तरफ हैं पीछे खड़े हैं जनरल जार्ज मार्शल
(अमरीका के सेनाध्यक्ष)

राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी फ्रांस पर कपटपूर्ण प्रहार के कारण मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की और सामयिक समस्याओं पर पुनर्विचार करने हेतु 30 जुलाई, 1940 को अमरीका के विदेश मंत्रियों की बैठक की गई। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले अखिल अमरीकी संघ के 21 गणराज्यों ने इस विषय पर एकमत प्रकट किया कि यदि 'न्यू वर्ल्ड' (पृथ्वी गोलक का पश्चिमी भाग जिसमें उत्तरी एवं दक्षिणी अमरीका, उनके द्वीप तथा प्रतिवेशी जलमार्ग भी सम्मिलित है) के किसी भी क्षेत्र पर आक्रामक भय की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो अमरीकी गणराज्य उस पर सामूहिक प्रशासन स्थापित करेगा। इस हवाना अधिनियम के अन्तर्गत अमरीका सहित तीन गणतंत्रों ने सूरीनाम पर संरक्षित राज्य स्थापित किया और अमरीका ने ग्रीनलैण्ड पर क्षेत्राधिकार किया इसके अतिरिक्त अमरीकी सरकार ने विद्रोही तत्वों के कार्य कलापों एवं गतिविधियों पर नियंत्रित दृष्टि रखना प्रारम्भ किया।

यद्यपि अमरीका व ब्रिटेन के 'ध्वंसक आस्थान समझौते' के कारण व्यापक आलोचना की गई, परन्तु यह समझौता पश्चिमी गोलार्ध को युद्ध से दूर रखने के सहायतार्थ समझा गया। 27 सितम्बर, 1940 को जर्मनी, इटली, और जापान के त्रिपक्षीय समझौते ने रोम, बर्लिन, टोकियो अक्ष को स्थापित कर अमरीका के लोगों को युद्ध की गम्भीरता व विकटता का परिचय दिया। फलस्वरूप प्रेसीडेंट रूजवेल्ट पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। राष्ट्रपति ने अमरीका की तटस्थता की नीति को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु वचन दिया, परन्तु 11 मार्च, 1941 को "ऋण पट्टा अधिनियम" के पारित किये जाने के साथ ही अमरीकी तटस्थ नीति की नींव हिलने लगी क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अमरीका किसी भी ऐसे राष्ट्र को युद्ध सामग्री सहायतार्थ दे सकता था जिस राज्य की सुरक्षा अमरीका के लिये अति आवश्यक थी, इस प्रकार अमरीका "लोकतांत्रिक शास्त्रागार" का केन्द्र बन गया। इसके अतिरिक्त अमरीकी सरकार ने 'धुरी राष्ट्रों' की सम्पत्ति एवं जलपोतों को जब्त कर लिया तथा धुरी राष्ट्र के वाणिज्य दूतावासों को अवरुद्ध कर दिया। 21 मई, 1941 को एक व्यापारी अमरीकन जलपोत 'रॉबिन मूर' के जलग्रस्त हो जाने पर राष्ट्रपति ने असीमित राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इससे भी निश्चित न होकर अगस्त, 1941 में लोकतांत्रिक उद्देश्यों को लेकर एक बैठक बुलायी गयी (किसी सागरीय क्षेत्र में) जो "अटलांटिक घोषणा पत्र एवं अधिकार पत्र" के नाम से जानी जाती है। इस द्विपक्षीय सम्मेलन में राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री विस्टन चर्चिल ने भाग लिया।

उपरोक्त प्रलेख में निम्नलिखित सूत्र थे :—

264/अमरीका का इतिहास

1. क्षेत्रीय विवर्धन का त्याग,
2. ऐसे क्षेत्रीय परिवर्तनों का विरोध करना जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित लोगों की इच्छा के विरुद्ध हों,
3. जनसाधारण को स्वयं अपनी सरकार चयन करने के अधिकार का समर्थन करना,
4. व्यापार तथा कच्चे माल पर प्रत्येक राज्य को समान अधिकार प्रदत्त करना,
5. राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना ।
6. नाजी (नात्सी) अत्याचार के समाप्त होने पर राष्ट्रों को अभाव एवं भय से मुक्त करना ।
7. सामुद्रिक स्वतंत्रता प्रदत्त करना ।
8. आक्रामक देशों का निरस्त्रीकरण एवं स्थायी शांति की स्थापना का प्रयास ।

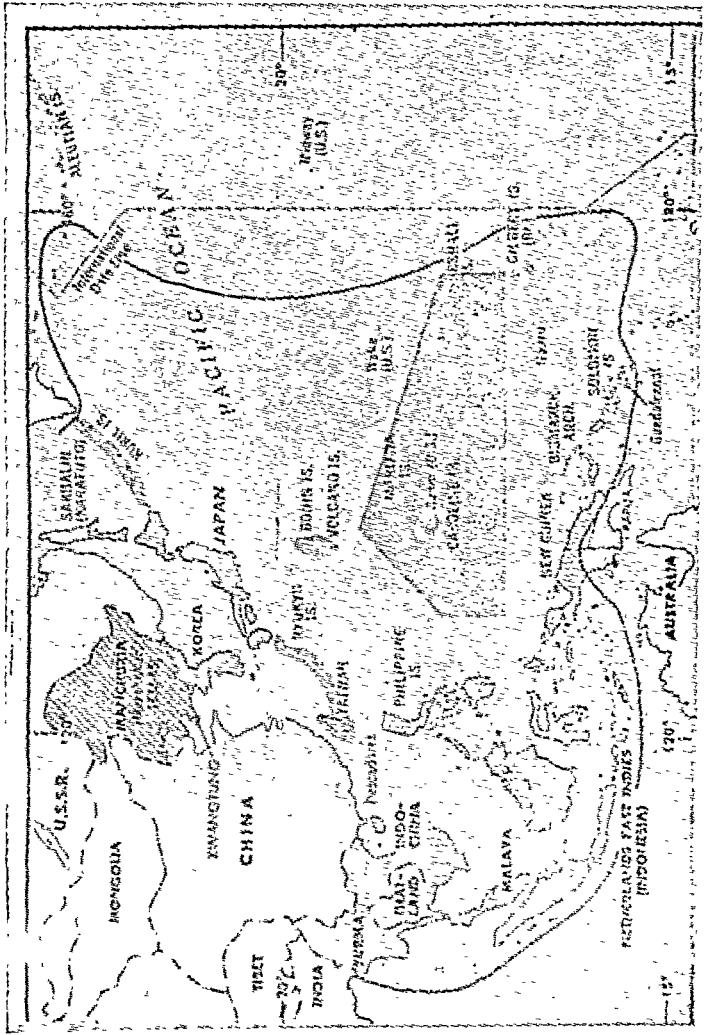
उपरोक्त उद्देश्यों में राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्र अपने नव एवं सरल परिधान में स्पष्ट प्रतिबिम्बित थे और इसके अतिरिक्त इस संयुक्त घोषणा का विशेष उद्देश्य नाजी (नात्सी) जर्मनी का विनाश था । इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध की प्रगति के मध्य राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तटस्थता की नीति अपनाये रखने का प्रयास करने का प्रयत्न किया परन्तु पर्लहार्बर के आक्रमण ने अमरीका को सर्वसत्तावाद के विध्वंस करने पर बाध्य किया ।

द्वितीय विश्व युद्ध और अमरीका

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में अमरीका में तटस्थता की भावना विद्यमान थी, परन्तु युद्ध की निरन्तरता ने इस वास्तविकता को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया कि अमरीका के लिये तटस्थता की नीति को बनाये रख पाना अत्यन्त दुष्कर प्रतीत हो रहा था । राष्ट्रपति रूजवेल्ट की पारस्परिक सहयोग की नीति पाँच सूत्रों पर आधारित थी:-

1. अपने देश की रक्षा हेतु जल थल और वायुसेना का विकास ।
2. अपने देश के उद्योग एवं व्यापार को यौद्धिक एवं आर्थिक नीति पर पुनर्गठित करना ।
3. पाश्चात्य देशों से सम्बन्धों का पुनर्गठन करना ।
4. स्व-मित्रराष्ट्रों को युद्ध के मध्य पूर्ण सहायता के लिये योजनाबद्ध करना ।
5. स्थायी रूप से शांति स्थापित करने हेतु योजनाओं को बनाना ।

इसीलिये इसका स्पष्टीकरण करते हुये राष्ट्रपति ने जनवरी 6, 1941 को अमरीकी कांग्रेस के सदन को सम्बोधित करते हुये कहा, 'अमरीका लोक-



तांत्रिक देशों से इस वास्तविकता को स्पष्ट कर देना चाहता है कि अमरीका इन देशों की स्वतंत्रता बनाये रखने में अपनी पूरी शक्ति एवं सहयोग देने के लिये सदैव तत्पर रहेगा ।' राष्ट्रपति ने अपने मित्र राष्ट्रों और स्वतंत्रता प्रेमी देशों को चार सूत्री स्वतंत्रता सिद्धांत पर चलने का आह्वान किया ।

राष्ट्रपति के चार सिद्धान्त थे :-

1. वाणी और भाषा की स्वतंत्रता
2. धार्मिक स्वतंत्रता
3. आर्थिक स्वतंत्रता
4. निःशस्त्रीकरण (निरस्त्रीकरण की योजना अर्थात् यौद्धिक भय से मुक्ति ।

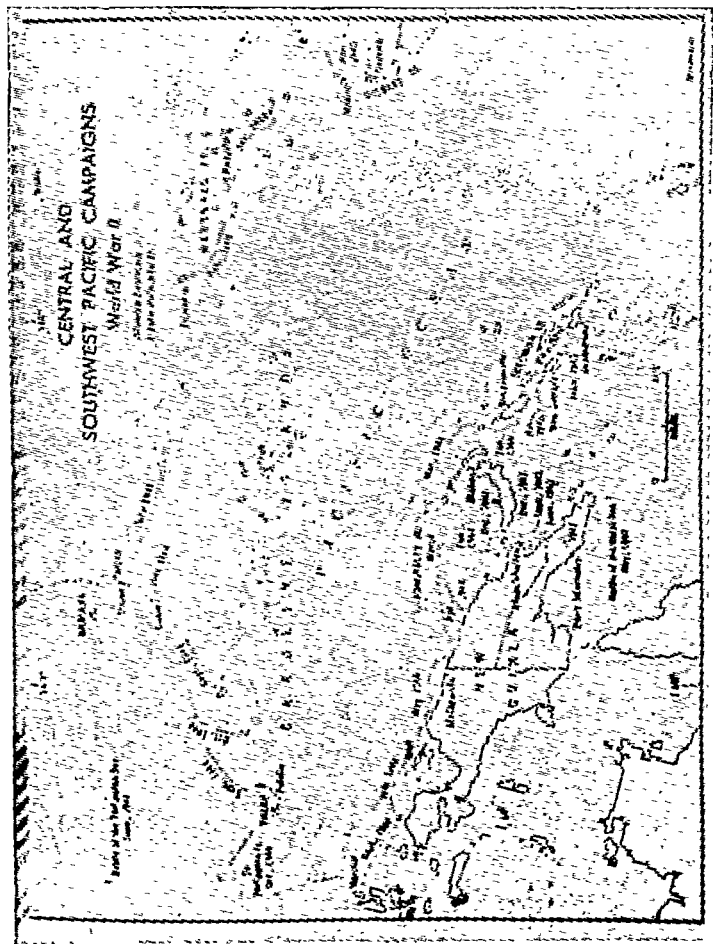
7 दिसम्बर, 1941 में जापान ने अमरीका के नौसैनिक अड्डे पर अप्रत्याशित आक्रमण कर उसे द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्णरूपेण युद्धरत होने के लिये बाध्य किया । प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न अमरीका इस युद्ध पर अपनी विजय पताका फहरा सकता था । इसके पास इस्पात एवं तेल की इतनी अधिक मात्रा थी जितनी कि किसी भी युद्धरत देश के पास नहीं थी । प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त स्वचलित यंत्रों के क्षेत्र में भी अमरीका की औद्योगिक शक्ति सभी राष्ट्रों से अग्रिम थी । 1941 के पश्चात अमरीका ने अपनी यांत्रिक शक्ति को पूर्णतया यौद्धिक उत्पादन में संबद्ध कर दिया । पर्लहार्बर घटना के एक वर्ष पश्चात ही अमरीका औद्योगिक यंत्र युद्ध का सामान इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न कर रहा था कि अन्य राष्ट्र मिलकर भी उसकी तुलना में कम उत्पादन कर पा रहे थे ।

युद्ध से सम्बन्धित प्रयत्नों में अमरीका एवं ब्रिटेन की पारस्परिक सहयोग की नीति और प्रशासनिक कुशलता के कारण भी उन्हें सफलता मिली । कुछ ही समय पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि लोकतांत्रिक देशों की युद्ध सम्बन्धी योजना एवं प्रशासन तानाशाही (अधिनायकीय) देशों से अधिक उत्तम था । इसके अतिरिक्त जहाँ एक ओर घुरी राष्ट्रों के यौद्धिक प्रयत्नों में पारस्परिक मूल सहयोग की भावना का पूर्णतया अभाव था, वहाँ दूसरी ओर लोकतांत्रिक देशों में पूर्णसमन्वय विद्यमान था । राष्ट्रपति रूजवेल्ट एवं प्रधानमंत्री चर्चिल के पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास ने इन प्रयत्नों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 1942 के प्रारम्भ से ही अमरीका और ब्रिटेन के प्रशासकों ने युद्ध के संचालन और नीतियों के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लिये जिनके द्वारा युद्ध के परिणाम पर व्यापक प्रभाव पड़ा । इसके अतिरिक्त 1942 में ही एक अन्य निर्णय भी लिया गया कि अमरीका और ब्रिटेन यूरोप में अन्य घुरी राष्ट्रों को परास्त करने, के पश्चात उनके युद्धतंत्र को विनष्ट कर

प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जापान की शक्ति को रोकने तथा क्षीण करने का प्रयास करेंगे । ब्रिटेन एवं सोवियत यूनियन को धुरी राष्ट्रों के भयानक प्रहार के कारण विनष्ट होने से बचाना ही इस निर्णय का आधार था । यह निर्णय इस बात का भी द्योतक था कि अमरीका के लिये जर्मनी एवं इटली जापान से अधिक संकटकारक सिद्ध हो सकते थे । इसके अतिरिक्त नाजी युद्धतंत्र को विनष्ट करना अमरीका की सुरक्षा के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण था । अमरीका में दो प्रकार की विचारधारायें विद्यमान थीं । अमरीकी जनता का एक भाग सर्वप्रथम जापान की शक्ति को ही पूर्णतया विनष्ट करने के पक्ष में था, पर अमरीकी शासन ने व्यापक परि-प्रेक्ष्य में जापान की सैन्यशक्ति पर धीरे धीरे प्रहार करने के निर्णय को अधिक समीचीन समझा । तत्पश्चात् की घटनाओं ने इस निर्णय को काफी बुद्धिमत्ता पूर्ण सिद्ध किया । जापान को परास्त करना जर्मनी एवं इटली की पराजय के पश्चात् काफी सामान्य माना गया ।

प्रशांत महासागरीय दो युद्धों के द्वारा जापान की यह आवश्यकता प्रकट हो गई कि उसकी उन्नति के द्वार को अवरुद्ध किया जा सकता है । 4 सितम्बर 1942 से 1944 के मध्य तक जनरल मैकार्थर को न्यूगिनी पुनः प्राप्त करने के कार्य का उत्तरदायित्व दिया गया । इसमें अधिकृत क्षेत्र का इतना महत्व नहीं था जितना इसमें मैकार्थर की सामरिक नीति थी । इसके अतिरिक्त मैकार्थर ने ने 'पोर्ट्सबी' में जलस्थलीय सैनिक अभियान कर जापानी संकट को दूर रखा । अमरीका और आस्ट्रेलिया की सम्मिलित नौसैनिक शक्ति को जापानी नौसेना से कोरल समुद्र में सामना करना पड़ा । इस युद्ध में अमरीकी वायु-सेना ने भी अपनी रणकुशलता का परिचय दिया । अमरीका और जापान के मध्य मिडवे द्वीप युद्ध ने प्रशांत सागरीय क्षेत्र में एक नया मोड़ लिया । अमरीकी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल निमिट्स ने जापान के साथ नौसैनिक युद्ध में विजय प्राप्त कर मध्य प्रशांत क्षेत्र में जापानी प्रसार को रोका । इस युद्धकी विशेषता यह भी थी कि यह प्रायः पूर्णतया नौसेना तथा वायुयानों का युद्ध था । इस प्रकार अमरीका ने जापान की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया । अमरीकी राष्ट्रीय युद्ध ने विश्व युद्ध के मध्य आशातीत उत्पाद्य सफलता प्राप्त की । अमरीकी जनता एवं उद्योगपति युद्ध मध्य युद्ध सामग्री के उत्पादन के द्वारा योगदान प्रदान करते रहे । सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई । इसके लिये 18 से 45 वर्ष की अवस्था निर्धारित की गई । स्त्रियों को भी सैनिक प्रशिक्षण प्रदत्त किया जाने लगा ।

युद्ध प्रसार के साथ ही अमरीकी उत्पादन भी द्रुत गति से बढ़ने लगा ।



द्वितीय विश्व युद्ध में केन्द्रीय एवं दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागरीय अभियान

राष्ट्रीय उत्पादन विश्व युद्ध के मध्य 91 अरब डालर से बढ़कर 166 अरब डालर हो गया । अमरीकी पोत निर्माण का उत्पादन कई गुना अधिक हो गया । इस युद्ध में अमरीका ने 2 लाख छियानवें हजार 6 सौ एक वायुयानों का निर्माण किया और इसमें से 40 हजार मित्र राष्ट्रों को दिये । अमरीका ने टैंक निर्माण में भी अभूतपूर्व वृद्धि की । ग्रेट ब्रिटेन को 4 हजार 300 टैंक दिये गए । इसके अतिरिक्त 86 हजार जीपें भी ब्रिटेन को प्रदत्त की गईं । अमरीका ने अपने उत्पादन उद्योग को एक नवगति प्रदान कर मित्र राष्ट्रों को महान सहयोग दिया । अमरीका ने युद्ध के तीव्रीकरण के साथ अपनी वैज्ञानिक प्रभुता का भी परिचय दिया । अमरीकी प्रशासन ने वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अनेक प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थापना की । इन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने युद्ध में उपयोगी विधि यंत्रों का आविष्कार किया ।

अमरीकी वैज्ञानिकों की सर्वोपरि उपलब्धि अणुबम का निर्माण था । जर्मनी के वैज्ञानिकों के आणविक विखण्डन में असफल हो जाने पर 1939 में जर्मनी में ही उत्पन्न हुये अमरीकी वैज्ञानिक एलवर्ट आइनस्टाईन, लियो सिलार्ड एवं यूजीन विग्नर ने इस बात की सूचना राष्ट्रपति रूजवेल्ट को दे दी थी कि वे अणुबम का निर्माण कर सकते हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने गुप्त रूप से दो अरब डालर की धनराशि स्वीकृति की । शिकागो विश्व-विद्यालय, कोलम्बिया विश्वविद्यालय एवं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक साथ प्रयोग प्रारम्भ किये गये । इसके अतिरिक्त अमरीका तथा ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने मिलकर न्यू मैक्सिको राज्य के लास् अलांमोस नामक स्थान पर प्रोफेसर राबर्ट आप्पन हाइमर की अध्यक्षता में अणुबम बनाने के कार्य को प्रारम्भ किया । 16 जुलाई 1945 में प्रयोग के लिये अणुबम का सफल विस्फोट न्यू मैक्सिको में ही एल्मेगार्डों नामक स्थान पर किया गया । विश्वयुद्ध में अणुबम का प्रयोग जापान में हीरोशिमा-नागासाकी पर किया गया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को विध्वंसक युद्ध का स्वरूप दिया ।

युद्ध सम्बन्धी उत्पादन के कारण अमरीका में बेकारी की समस्या समाप्त सी हो गई । स्त्रियों ने भी भारी मात्रा में कारखानों व प्रतिष्ठानों में कार्य करना प्रारम्भ किया । युद्धजन शक्ति आयोग (वार मै पावर कमीशन) के द्वारा आवश्यकतानुसार श्रमिकों का स्थानान्तरण भी होता था । युद्ध के कारण श्रमिकों की आय में भी वृद्धि की गई । 1939 में श्रमिकों की आय करीब 24 हजार डालर प्रति सप्ताह थी । वह बढ़ कर 46 हजार डालर हो गई । प्रारम्भ में श्रमिकों की राष्ट्रीय संस्थाओं (ए० एफ० एल० तथा सी० आई० ओ०) ने हड़ताल न करने का निश्चय किया । बाद में जब सामानों के मूल्यों में वृद्धि

होने लगी और युद्ध के संकटकालीन दौर भी समाप्त हो गये। तब हड़तालों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। यह हड़तालें अधिकतर उन कारखानों में होने लगीं जहाँ युद्ध से सम्बन्धित उत्पादन नहीं होता था। युद्ध जनित उत्पादन ने अमरीका में एक नये धनिक वर्ग को जन्म दिया।

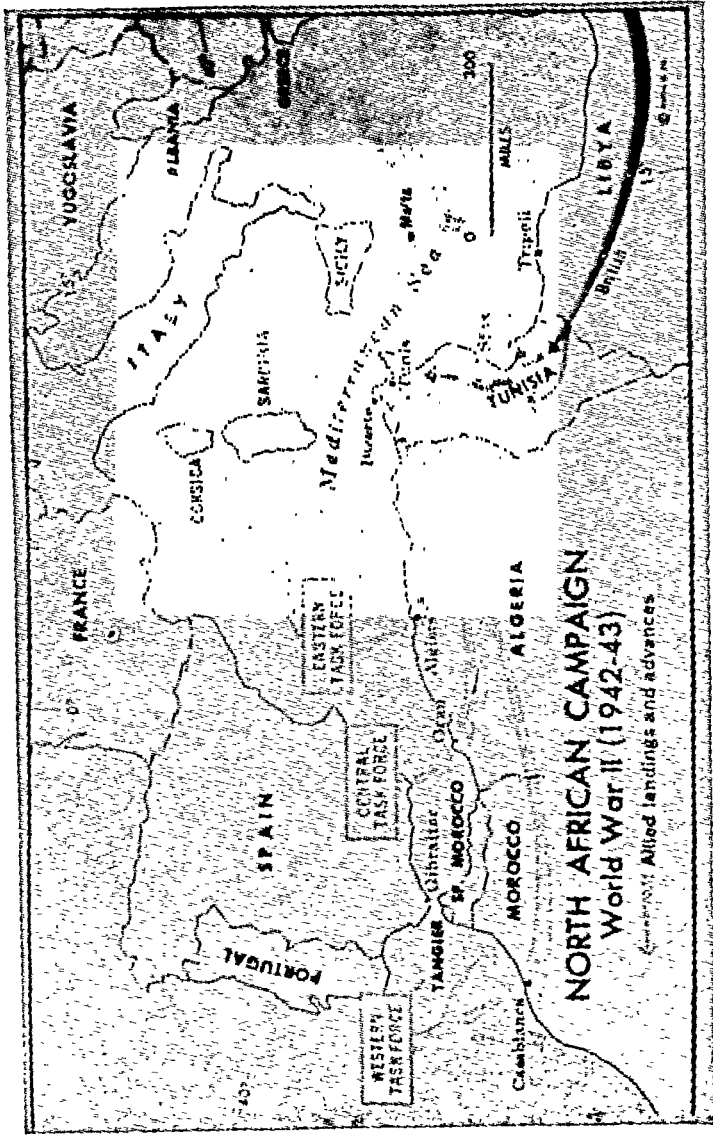
इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी उत्पादन एवं मुनाफे में कई गुना वृद्धि हो गई। मक्के की उपज दो अरब अट्ठावन करोड़ नौ लाख चौवन हजार बुशेल से बढ़कर दो अरब अट्ठासी करोड़ नौ लाख चौवन हजार बुशेल हो गई। इसी प्रकार गेहूँ की उपज भी पचहत्तर करोड़ बारह लाख दस हजार बुशेल से बढ़कर एक अरब दस करोड़ बयासी लाख चौबीस हजार बुशेल हो गई।

मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये प्रशासन द्वारा मूल्य निर्धारण के बहुत से उपयोग किये गये। उपभोग्य वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिया गया तथा चीनी, काफी तथा मांस पर राशन व्यवस्था लागू कर दी गई। 1942 के बाद भी मूल्यों में अभिवृद्धि हुई, पर मूल्यों को उग्र रूप धारण करने से रोका गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के संचालन के लिये अमरीका को बहुत खर्च उठाना पड़ा। अमरीका को द्वितीय विश्व युद्ध में 350 अरब डालर खर्च करना पड़ा। यह प्रथम विश्वयुद्ध के खर्च से दस गुना अधिक था।

अमरीकी राजनीति भी युद्ध से प्रभावग्रस्त हुई। 1942 में कांग्रेस के चुनाव में सैनिक पराजयों के कारण व्याप्त असंतोष की भावना से रिपब्लिकन पार्टी को लाभ प्राप्त हुआ। 1944 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय परिस्थितियाँ विपरीत हो चुकी थीं। युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर विजय श्री प्राप्त करते हुये राष्ट्रपति रूजवेल्ट की लोकप्रियता बढ़ रही थी। रिपब्लिकन पार्टी (गणतांत्रिक दल) इस लोकप्रियता का सामना करने में अक्षम थी। अतः प्रजातांत्रिक (डेमोक्रेटिक) पार्टी ने 1944 में पुनः चतुर्थ बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट को अपना प्रत्याशी तथा उप राष्ट्रपति पद हेतु मिसौरी के सीनेटर हेरी एस० ट्रूमैन को घोषित किया। गणतांत्रिक (रिपब्लिकन) पार्टी ने न्यूयार्क के गवर्नर थामस ई० ड्यूवी को राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी चुना। रूजवेल्ट को जनता के 2 करोड़ 56 लाख 2 हजार मत प्राप्त हुये और ड्यूवी को 2 करोड़ 20 लाख 6 सौ मत प्राप्त हुये।

संयुक्त राज्य अमरीका ने द्वितीय विश्वयुद्ध में पदार्पण तथा युद्ध में पूर्ण-रूपेण कार्यरत होने के लिये युद्ध सम्बन्धी साधनों को एकत्रित किया। अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस तथा अन्य मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के



उत्तरी अफ्रीकी अभियान द्वितीय विश्व युद्ध (1942-43)

विरुद्ध युद्ध निश्चय को वास्तविकता प्रदत्त करने हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये। इन राष्ट्रों का ध्येय स्वतंत्रता, स्वाधीनता, न्याय, धर्म तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा करना था। प्रत्येक राष्ट्रीय शासन ने इस बात का वचन दिया कि युद्ध मध्य वे आर्थिक, सैन्य तथा अन्य आवश्यक सामग्री के द्वारा एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

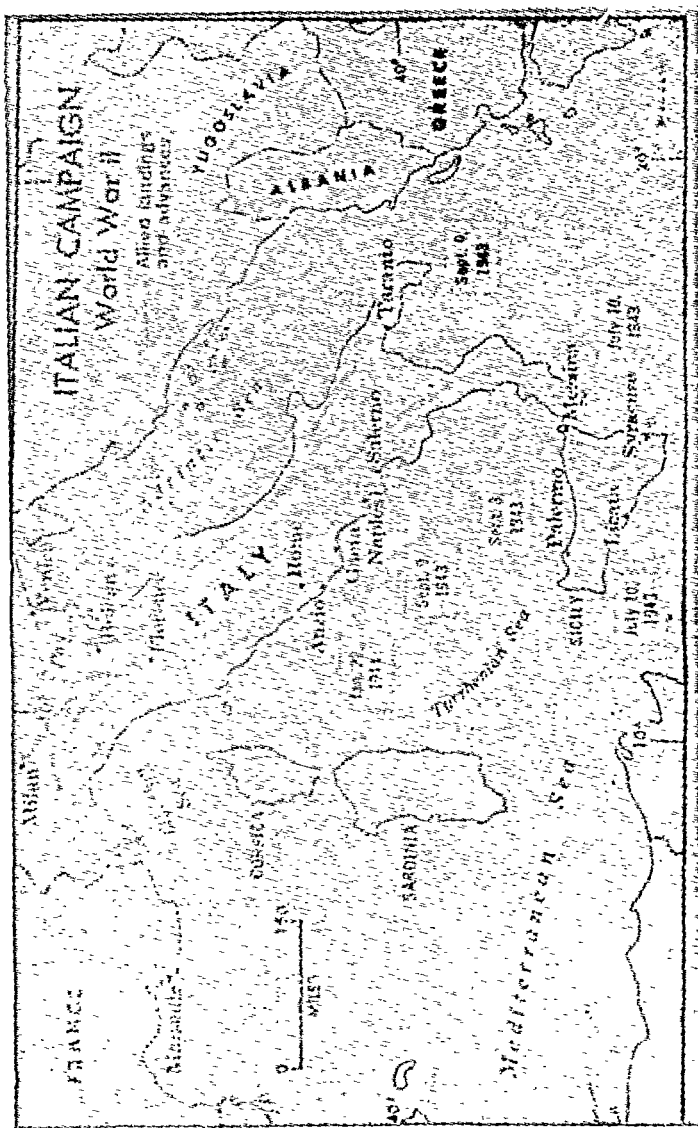
अमरीकी राज्य सचिव कोर्डेलहल ने 2 जनवरी, 1942 में संयुक्त राष्ट्रों के संगठन की व्याख्या करते हुये कहा कि इतिहास में प्रथमवार 26 स्वतंत्र राष्ट्रों का संगठन मानव शक्ति एवं उनके मूल्यों के हेतु किया गया था। हल ने संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों की ओर इंगित करते हुये यह भी कहा कि इन राष्ट्रों का संगठन इस तथ्य का द्योतक है कि मानवता के मूल सिद्धान्तों की सुरक्षा प्रत्येक स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्र का कर्तव्य था। सैन्य गठबंधन के साथ अमरीकी जनता तथा प्रशासन ने युद्ध सम्बन्धी सामग्री के उत्पादन के प्रति आशातीत प्रयत्न करने आरम्भ कर दिये। इस कार्य हेतु 1942 में एक करोड़ पचहत्तर लाख व्यक्तियों ने कार्य करना आरम्भ किया। इसके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा संगठन ने एक करोड़ स्वयं सेवकों को तैयार किया। यौद्धिक व्यय हेतु आर्थिक संचय विभिन्न करों द्वारा किया गया। अमरीकी युद्ध सूचना विभाग जो युद्ध के मध्य निर्मित अनेक विभागों में से एक था, समय-समय पर अमरीकी प्रशासन एवं जनता को युद्ध कालीन सेवाओं एवं उपलब्धियों से परिचित कराता था।

प्रथम मुख्य अमरीकी अभियान नवम्बर, 1942 में अफ्रीका में हुआ जिसमें अमरीकी सेना ने सफलतापूर्वक भाग लिया। इसके दो माह पश्चात् राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने काँसाब्लांका में भेट कर यूरोपीय मुख्य क्षेत्र पर आक्रमण की योजना पर विचार किया। इसी सम्मेलन में उन्होंने भविष्य में युद्ध विराम पश्चात् शांति योजना की रूप रेखा बनाई। काँसाब्लांका सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही सिसली और इटली पर आक्रमण हुआ। इसी मध्य जब मित्र राष्ट्र सेनायें उत्तर की ओर से रोम की ओर अग्रसर थीं, रूस, ब्रिटेन, अमरीका तथा चीन के विदेश मंत्रियों ने अक्टूबर, 1943 को मास्को में सभा की। इस मास्को घोषणा में जो अक्टूबर 30, 1943 को की गयी, यह कहा गया कि मित्र राष्ट्र प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहयोग प्रदत्त करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त युद्धोपरान्त स्थिति में भी एक मत होकर कार्य किया जायेगा। तत्पश्चात् नवम्बर, 1943 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चर्चिल तथा चीन के चांग काई शेक काहिरा में सम्मिलित हुये। इस सम्मेलन में जापान के साथ शांति सम्बन्ध होने के कारण रूस के मार्शल स्टालिन ने भाग

नहीं लिया। इस सम्मेलन में प्रशान्त क्षेत्र एवं पूर्वी एशिया में युद्ध नीति पर विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में जापान की आक्रामक योजनाओं के प्रति कार्यवाही पर भी विचार व्यक्त किया गया। इसके पश्चात् राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल, रूस के मार्शल स्टालिन से मिलने तेहरान गये। इस सम्मेलन में हुई वार्ता को राष्ट्रपति ने 1943 की क्रिसमस की सायं को जनता के प्रति सन्देश में प्रसारित किया। उन्होंने यह बताया कि संयुक्त राष्ट्र जर्मनी को अधीन करने में रुचि नहीं रखता था परन्तु उसको तथा वहाँ की जनता को नाजीवाद एवं सैन्यवाद से मुक्त करना अपना कर्तव्य समझता था। राष्ट्रपति ने मार्शल स्टालिन से अपनी भेंट की चर्चा करते हुये कहा कि स्टालिन दृढ़ निश्चयी एवं साहसी होने के कारण हम लोगों का साथ देने में सक्षम होंगे।

यूरोपीय क्षेत्रों में प्रथम बार स्वतंत्र रूप से अमरीका ने 17 अगस्त, 1942 को अपने लड़ाकू विमानों द्वारा बम वर्षा की। यह बम वर्षा वायु सेना के बी० 17 विमानों द्वारा रेल पटरियों पर रूआन के समीप की गई। इसके अतिरिक्त मिस्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका में फील्ड मार्शल रोमेल को अल एलामेन (4 नवम्बर 1942) के युद्ध में पीछे हटाकर इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु जनरल आइजनहावर तथा एडमिरल सर ऐड्रू कनिंघम को उत्तरी अमरीका भेजा। दिसम्बर, 1942 तक उन्होंने वहाँ पर कई सफलताएँ प्राप्त की। जनवरी, 1943 में कासाब्लांका सम्मेलन, फ्रेंच मोरक्को में हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा प्रधान मंत्री विस्टन चर्चिल ने इस बात की घोषणा की, "हम तब तक युद्धरत रहेंगे जबतक कि हमारे शत्रु बिना शर्त समर्पण नहीं कर देंगे"। इसके अतिरिक्त अमरीकी अधिकारियों ने यूरोपीय महाद्वीप में फ्रांस के द्वारा आक्रमण का समर्थन किया। अंग्रेजों ने इटली और बाल्कन क्षेत्रों में युद्धरत होने की योजना प्रकट की। इस सम्मेलन में जनरल आइजनहावर को उत्तरी अफ्रीका युद्धमंच का सर्वोच्च सेनाधिकारी नियुक्त किया गया। 13 मई, 1943 तक जनरल पेटन और जनरल मांटगोमरी के अप्रत्याशित आक्रमणों द्वारा उत्तरी अफ्रीका के जर्मन अधिकृत क्षेत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो गये। इस अभियान से अफ्रीका एवं भूमध्य सागर पर धुरीराष्ट्रों के आधिपत्य का अन्त हो गया।

एंग्लो-अमरीकन सेनाओं ने सिसली पर आक्रमण कर जुलाई, 1943 में शासक विक्टर ऐमैनुअल द्वितीय को फासीवादी दल को भंग करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये बाध्य किया। परन्तु जर्मनी के पुनः रोम पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात् मुसोलिनी ने फासी गणतंत्र शासन स्थापन करने की चेष्टा की।



द्वितीय विश्व युद्ध में इटली अभियान मित्र राष्ट्रों का अवतरण एवं प्रगति

1944 के आरम्भ में ही मित्रराष्ट्रों ने इटली पर आक्रामक नीति का पूर्णरूपेण परिपालन किया। इसी मध्य जनरल आइजनहावर सर्वोच्च सेनाधिकारी का कार्यभार संभाल चुके थे। और इस प्रकार इटली में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने अपनी सफलतायें प्राप्त करना पुनः आरम्भ कर दिया और 4 जून, 1944 को अमरीका की 5वीं सेना ने रोम को स्वतंत्र करा दिया। इसके अतिरिक्त अमरीकी सेना ने ब्रिटेन और कनाडा की सेवाओं के साथ फ्रांस, बेल्जियम और लक्जबर्ग को स्वतंत्र कराया। मित्रराष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में 2, 086,000 सेना और 3,466,000 टन युद्ध सामग्री भेजी। 12 सितम्बर, से 3 दिसम्बर तक जर्मनी क्षेत्र में मित्रराष्ट्रों के साथ अमरीका की प्रथम सेना तथा तृतीय सेना ने कई सफलतायें प्राप्त कीं। बल्ज के युद्ध में मित्रराष्ट्रों को भारी हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध में अमरीका की लगभग 77,000 सेना दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 8000 लगभग मृत्युग्रस्त हुये, 48000 घायल हुये, 21,000 या तो बंधक बनाये गये अथवा लापता हो गये।

इस युद्ध के पश्चात् यह निश्चय करना आवश्यक था कि जर्मनी के आक्रमणों को किस प्रकार से रोका जाय तथा हिटलर की विस्तारवादी नीति को समाप्त करने हेतु अंतिम सफल चरण किस प्रकार से पूर्ण किया जाय। इस समस्या के समाधान हेतु जनवरी, 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ जिसमें मित्र राष्ट्रों के समस्त सेनाधिकारियों ने हिटलर के विरुद्ध अंतिम युद्ध योजनाओं को सफलबद्ध करने हेतु विचार किया।

याल्टा सम्मेलन

फरवरी, 1945 में याल्टा सम्मेलन जो कि क्रीमिया में हुआ, राष्ट्रपति रूज्वेल्ट, प्रधान मंत्री चर्चिल और रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने अपने उच्च कूटनीतिज्ञों और सैन्य विशेषज्ञों के साथ भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मित्र राष्ट्रों की विजय का पूर्वानुमान करके नाज़ी जर्मनी के अप्रतिबद्ध आत्म समर्पण के कार्य को कार्यान्वित करना था। इस कार्य को किस प्रकार से सम्पन्न किया जायेगा इसको जर्मनी की अंतिम पराजय से गोपनीय रखने की घोषणा की गई। परन्तु कुछ तथ्यों को स्पष्ट किया गया। इस योजनानुसार जर्मनी को तीन खण्डों में विभक्त करने पर विचार किया गया और बर्लिन में एक पृथक समन्वित प्रशासन एवं नियंत्रण आयोग की स्थापना का प्रयोजन किया गया। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि यदि फ्रांस की इच्छा हो तो उसे भी आमंत्रित किया जा सकता है।

इस सम्मेलन के सम्मिलित सदस्यों ने अपना उत्तरदायित्व प्रकट करते हुये नाजी जर्मनी के सैनिकवाद का उन्मूलन अपना प्रथम कर्तव्य बताया। इसके अतिरिक्त जर्मनी तथा जर्मन के सैनिक प्रभाव को प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी में पूर्णतया विनष्ट करने का निश्चय किया गया। इस बात को स्पष्ट किया गया कि जर्मनी की जनता को नष्ट करने का उनका उद्देश्य नहीं है परन्तु नाजीवाद एवं सैनिकवाद का उन्मूलन उनका प्रथम लक्ष्य है।

उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त इस सम्मेलन में अमरीका और ब्रिटेन ने बाह्य मंगोलिया को स्वायत्त शासन देने पर समझौता किया, पूर्वी पोलैण्ड, रूस को देने पर विचार किया गया और पोलैण्ड की पूर्वी सीमा कर्जनरेखा पर आधारित की गई। यह स्वीकार किया गया कि पोलिश सरकार को प्रजातांत्रिक आधार पर पुनः स्थापित किया जाय। रूस ने माँग की थी कि जर्मनी उसे बीस मिलियन डालर जुमाने के रूप में दे। पहले यह माँग अस्वीकृत हो गई किन्तु बाद में उसे 'जुमाना आयोग' में रखे जाने का निर्णय किया गया।

अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन का मुख्य उद्देश्य जर्मन यौद्धिक नीति को समाप्त करना था। इन तीन शक्तियों ने 'बिना शर्त समर्पण' के नियम को माना और स्वतंत्र यूरोप के स्पष्टीकरण को पारित किया, जिसमें इन तीन महान शक्तियों ने प्रण किया कि युद्ध के पश्चात् वे स्वतंत्र राज्यों में मुक्त रूप से चुनाव कराने में सरकार का सहयोग करेंगे। सम्मिलित देशों ने यह घोषणा की कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के चुनाव से सम्बन्धित रूपरेखा व नियम तैयार किये हैं, और संयुक्त राष्ट्र विधान की वृद्धि करने का सम्मेलन 25 अप्रैल को सैन फ्रैंसिस्को में होगा। यह गुप्त रूप से स्वीकार किया गया कि यूक्रेन और 'बॉयलो-रण' को स्वतंत्र राष्ट्रों की भाँति पूर्ण और समान रूप से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया जायेगा। इस सम्मेलन में 'अटलांटिक चार्टर' में पूर्ण आस्था व्यक्त की गई तथा युद्ध में विजय, विश्वशांति के लिये परमावश्यक मानी गई।

याल्टा सम्मेलन (समझौता) राष्ट्रपति रूजवेल्ट का अंतिम मुख्य कार्य था जिसका विश्व की स्वतंत्रता प्रेमी जनता ने स्वागत किया। यद्यपि इस समझौते के गुप्त निर्णयों के ज्ञान होने पर बहुत से अमरीकी लोगों ने विचार प्रकट किया कि रूजवेल्ट स्टालिन के द्वारा क्य कर लिये गये हैं। परन्तु इस विचारधारा में अधिक तथ्य नहीं पाया गया जब अप्रैल, 1945 में याल्टा सम्मेलन के वे तथ्य जो गोपनीय नहीं थे, जनता के समक्ष आये तो स्वतंत्रता प्रेमी देशों ने इसका स्वागत किया।

उपसंहार

द्वितीय विश्व युद्ध अमरीका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण वर्तन बिन्दु था, जिसने अमरीका की गृह नीति को अपनी महत्वता के कारण प्रसित कर लिया ।

अमरीकी विदेश नीति की प्रथम आलोचना द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण से आरम्भ हो गई थी । राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नीतियों के प्रति अमरीकी इतिहासकारों, राजनीतिक लेखकों एवं बौद्धिकवेत्ताओं की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी । अमरीका में प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के पश्चात बौद्धिक एवं ऐतिहासिक वाद-विवाद हुये हैं और विविध विचार मत प्रकट किये गये हैं ।

सर्वप्रथम संशोधकीय मत के लेखकों ने अपने विचार रूजवेल्ट के प्रति उद्घोषित किये । इनमें सर्वप्रथम हैरी वॉन्स और चार्ल्स वीयर्ड थे । हैरी वॉन्स ने रूजवेल्ट की नीति के प्रति विरोधी मत प्रकट किया और कहा कि जो इतिहासकार उनसे सहमत थे वह 'दरवारी इतिहासकार' थे क्योंकि उनको प्रशासन से सुविधायें प्राप्त करनी थी । संशोधकीय मत के विचारकों का कुछ मूल सिद्धान्तों पर मतव्य था । प्रथम संशोधकीय विचारकों के अनुसार धुरी राष्ट्रों ने अमरीका के मर्मस्थलों को संकट उत्पन्न नहीं किया, जर्मनी का पश्चिमी गोलार्ध पर आक्रमण करने का कोई विचार नहीं था, जापानी केवल एशिया तक ही सीमित थे । इस प्रकार रूजवेल्ट का यह कहना कि अमरीकी जनता ने संकट उत्पन्न हो जाने के कारण युद्ध में प्रवेश किया, तथ्यहीन था ।

द्वितीय रूजवेल्ट को यह ज्ञात था कि उसकी विदेश नीति यूरोप और एशिया में युद्ध का कारण बनी । कुछ संशोधकीय विचारकों ने यहाँ तक अपनी धारणा व्यक्त की है कि रूजवेल्ट ने सुविचारित रूप से जापान को युद्ध करने के लिये बाध्य किया ।

तृतीय रूजवेल्ट ने अमरीकी जनता को शांति की वार्ता कर भ्रमित रखा जब कि वह स्वयं युद्ध के इच्छुक थे । अपने 1940 के राष्ट्रपति चुनाव के भाषण में उनका यह प्रचार कि अमरीकी विदेशी क्षेत्र पर युद्ध नहीं करेंगे उनकी युद्ध लिप्सा एवं चतुरता का एक उदाहरण था ।

चतुर्थ व अंतिम संशोधकीय निष्कर्षों के अनुसार अमरीका के द्वितीय विश्व-युद्ध में प्रवेश से यदि महाघातक नहीं वरन् नकारात्मक परिणाम निकले । अमरीका ने यूरोप के शक्ति संतुलन को अपरिमित कर दिया और 'सत्ता शून्यता' को जन्म देकर सोवियत रूस को उन्नति का अवसर दिया जो नाजी जर्मनी से अधिक संकटपूर्ण था ।

चार्ल्स वीयर्ड ने रुजवेल्ट की नवअर्थ नीति की आलोचना करते हुए उनकी तटस्थता की नीति को परिहासजनक बताया। वीयर्ड के कथनानुसार रुजवेल्ट तटस्थता की नीति के साथ-साथ इंग्लैण्ड को युद्ध सामग्री देते रहे। इसका अर्थ वीयर्ड ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट किया। वीयर्ड ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति के पास असीमित अधिकार हैं कि जनता और व्यक्तिगत दोनों रूप से विदेश नीति एवं युद्ध अधिकारों का मिथ्यानिरूपण कर सके। वीयर्ड की इस अवधारणा को अन्य संशोधकीय विचारधारा के लेखकों ने प्रति-ध्वनित किया। 1953 में विलियम चैंबरलेन ने अपना विचार व्यक्त किया कि रुजवेल्ट की अमरीका को विदेशी यौद्धिक परिधि से बाहर रखने की नीति केवल अपने चुनाव के प्रति प्रचार की द्योतक थी।

यद्यपि संशोधकीय लेखक रुजवेल्ट की यूरोपीय कूटनीति के आलोचक थे, परन्तु सर्वाधिकार आलोचना का केन्द्र उन्होंने रुजवेल्ट की पूर्वी-एशिया की नीति को बनाया। इन इतिहासकारों के मतानुसार रुजवेल्ट ने जापान के विरुद्ध मुनियोजित, राजनैतिक एवं सामरिक नीति का परिपालन किया जिसके फलस्वरूप जापान को युद्धरत होना पड़ा। संशोधकीय मतानुसार रुजवेल्ट शान्ति का इच्छुक था ही नहीं क्योंकि उसकी जापान की ओर आर्थिक नीति, चीन नीति तथा अमरीका में जापानी परिसम्पत्ति को अवरुद्ध करना उसके मुनियोजित युद्ध लिप्सा की परिचायक थी।

उपरोक्त विचारधारा के इतिहासज्ञों ने पर्ल हार्बर के आक्रमण को भी रुजवेल्ट की नीतियों के परिणाम की संज्ञा दी। इन विचारकों ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि नवम्बर, 1941 में राज्य सचिव कॉर्डेल हूल ने चीन एवं हिन्दचीन की समस्या को लेकर जापान को विचार विमर्श करने के वजाय अन्तिम चेतावनी दी। कुछ संशोधकीय मत के समर्थकों ने रुजवेल्ट को दोष दिया कि उन्होंने स्थिति से अभिज्ञ होकर भी पर्ल हार्बर पर अमरीकियों के जीवन से खिलवाड़ किया।

एक अन्य मत जो कि संशोधकीय विचारधारा के विपरीत था, अन्तर्राष्ट्रीयतावाद मत के अनुयायियों का मत था। इनमें डैक्सटर पकिन्स एवं हर्वर्ट फीस मुख्य थे। इन लेखकों के अनुसार रुजवेल्ट ने शान्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहा परन्तु जर्मनी की युद्ध विजय की लिप्सा ने तथा जापान की एशिया, विजय के लक्ष्य ने अमरीका को शान्ति नीति का अवसर प्रदत्त नहीं किया। इस मत के समर्थकों ने संशोधकीय विचारधारा का खंडन किया, यद्यपि इस विचारधारा के इतिहासज्ञों में पारस्परिक मतभेद था परन्तु संशोधकीय विचारधारा का सबने वहिष्कार किया। फीस एवं पकिन्स के अनुसार

जापान और जर्मनी के तथ्यों को एक ओर कर संगोष्ठीय विचारधारा के लेखकों ने ऐतिहासिक पूर्ण धारणा एवं पूर्वकल्पना को अपने लेखन का आधार माना ।

उपरोक्त इतिहासकारों का मतभेद अपनी-अपनी धारणाओं पर आधारित है । इतिहास में घटनाओं की व्याख्या विद्वानों की प्रौढ़ता, कल्पना ऐतिहासिक तथ्यों एवं उस समय की परिपालित कूटनीति पर आधारित है, इसलिये इतिहासजों का मतभेद आवश्यक है । प्रत्येक घटना इतिहास में कुछ प्रश्न छोड़ देती है जिसका अध्ययन, विवेचन एवं विश्लेषण हुआ करता है, इसी प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध ने अनेक प्रश्न, जिनमें रूजवेल्ट की नीति, हिटलर की व्यवहारिक पद्धति एवं युद्ध लिप्सा, जापान की एशियाई आकांक्षा, तथा यूरोपीय राजनीति की यथार्थता उत्पन्न किये जिनकी ऐतिहासिक व्याख्या वर्तमान काल तक हो रही है और सम्भवतया होती रहेगी ।

युद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, घोषणायें एवं समझौते (1941-45)

1. चर्चिल-रूजवेल्ट वार्ता (1941)

युद्ध के प्रवाह के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन व मंथियों का एक नया वातावरण उत्पन्न हो गया । अटलांटिक तट पर एक बड़ी शक्ति होने के कारण विश्व का हर राष्ट्र गांति व मित्रता के लिये अमरीका से सम्बद्ध होने का इच्छुक था । मित्रराष्ट्रों को अमरीका से आर्थिक व नैतिक सहयोग की भी आशा रहती थी । इन्हीं आकांक्षाओं के साथ ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, चर्चिल अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ कई सम्मेलन व सभाओं के लिये 22 दिसम्बर, 1941 को वर्गिन्टन पहुँचे । उनका प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय शक्तियों की यूरोप में पराजय को निश्चित करने के लिये अमरीका के साथ एक संयुक्त मोर्चे के निर्माण के निर्णय को प्राप्त करना था । यह शक्तियाँ ही युद्ध में ब्रिटेन के लिये प्रमुख खतरा बनी हुई थीं, इनके अतिरिक्त पूर्व एशिया में जापान के प्रसार को रोकने के लिये अवरोध, नीति को भी अपनाना था, विशेषकर जब तक कि मित्र राष्ट्रों को केन्द्रीय शक्तियों पर विजय प्राप्त न होती । इस दौर की अंतिम बैठक 14 जनवरी, 1942 को हुई थी जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा का पाँडुलेखन किया गया । संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सेनानायकों व युद्ध

सम्भरण सामग्री के लिये दो परिषदों की स्थापना की गई ।

2. आगामी वर्ष 1942 के प्रथम दिवस 1 जनवरी को ही वार्शिंग्टन में संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये इसमें अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, चीन व सोवियत संघ सहित छब्बीस राष्ट्र सम्मिलित थे । अटलांटिक घोषणा पत्र के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया । एकत्रित राष्ट्रों ने अपने सैनिक व आर्थिक स्रोतों को केन्द्रीय शक्तियों के विरुद्ध सम्मिलित रूप से उपयोग करने का निश्चय किया । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रमुख शत्रु देशों से कोई भी राष्ट्र अलग से समझौता नहीं करेगा ।

वर्ष 1942 में इन्हीं सिद्धांतों को आधार रूप मानकर प्रमुख निम्न सम्मेलन व समझौते किये गये ।

27 जनवरी को कच्चे माल के उद्योग हेतु एक संयुक्त आंग्ल अमरीकी परिषद् का वार्शिंग्टन में गठन किया गया ।

6 फरवरी को संयुक्त आंग्ल-अमरीकी युद्ध परिषद् की स्थापना की गयी ।

23 फरवरी अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड ने पारस्परिक 'ऋण सहायता पट्टा' समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

26 मई को सोवियत संघ व ग्रेट ब्रिटेन ने आपसी सहायता हेतु बीस वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये इससे पूर्व 29 अप्रैल को केन्द्रीय शक्तियों के दो प्रमुख स्थापक हिटलर व मुसोलिनी ने साल्जबर्ग में एक गुप्त सभा भी की थी ।

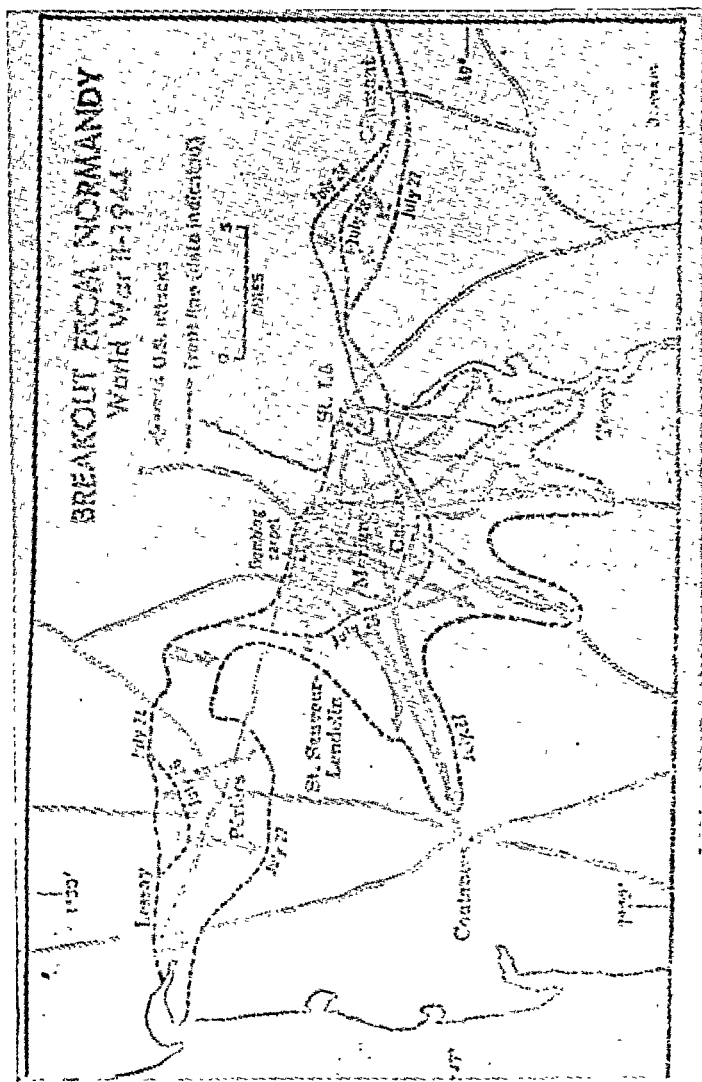
29 मई, 1942 को रूसी विदेश मंत्री व्योचेस्लाव मोलोटोव, अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा अन्य अधिकारियों के साथ सम्मेलन हेतु, अपने दल के साथ वार्शिंग्टन पहुँचे । रूस व अमरीका के मध्य सामग्री के आदान प्रदान हेतु ऋण पट्टे की शर्तें निर्धारित की गईं और 1 जुलाई, 1942 से यह समझौता कार्यान्वित किया गया ।

9 जून को अमरीका व ग्रेट ब्रिटेन के मध्य सामूहिक उत्पादन स्रोतों एवं खाद्य परिषदों का गठन किया गया ।

18 से 27 जून तक वार्शिंग्टन में एक आंग्ल-अमरीकी सम्मेलन हुआ । इसमें युद्ध की ब्यूह रचना व कूटनीति के विषय में निर्णय लिये गये । तदोपरान्त जुलाई में सेनाध्यक्षों की एक सभा में उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर आक्रमण की योजना बनाई गई ।

प्रथम मास्को सम्मेलन

12 से 15 अगस्त तक प्रथम मास्को सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटेन के



द्वितीय विश्व युद्ध में नॉरमेन्डी अभियान (1944)

प्रधान मन्त्री चर्चिल, रूस के मार्शल स्टालिन और अमरीकी प्रतिनिधि एवेरल हेरेमन ने भाग लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप में केन्द्रीय शक्तियों के विरुद्ध एक दूसरे मोर्चे की असम्भावना को निश्चित करना था। आगामी वर्ष 1943 भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व समझौतों से घिरा रहा। सम्पूर्ण वर्ष में मित्र राष्ट्रों ने जगह-जगह विचार सभायें की और युद्ध की गतिविधियों व भविष्य के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिये। इनका विवरण तिथि अनुसार निम्न है :-

कासाब्लाँका सम्मेलन (1943)

14 से 24 जनवरी, 1943 तक कासाब्लाँका, फ्रांसीसी मेरोक्को में एक ग्यारह दिन का सम्मेलन हुआ जिसमें रुजवेल्ट और चर्चिल ने यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय शक्तियों के आत्मसमर्पण तक युद्ध जारी रखा जायेगा। इस सम्मेलन में यूरोप युद्ध का एक दूसरा मोर्चा आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।

आंग्ल-अमरीकी सम्मेलन (1943)

12 से 25 मई तक वाशिंगटन में एक आंग्ल-अमरीकी सम्मेलन हुआ जिसमें नोरमेन्डी क्षेत्र पर आक्रमण व उसकी तिथि (1 मई, 1944) निश्चित की गई। इसके अतिरिक्त वायुयानों को मिलने वाले खनिज तेल की मात्रा को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।

कृषि व खाद्य सामग्री की समस्या व विकास के लिये वर्जीनिया में राष्ट्र संघों का एक सम्मेलन 18 मई से 3 जून, 1943 तक हुआ, इसके परिणाम-स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग 'खाद्य तथा कृषि संगठन' की स्थापना की गई।

प्रथम क्विवेक सम्मेलन (1943)

11 से 24 अगस्त तक एक महत्वपूर्ण प्रथम क्विवेक सम्मेलन हुआ। इसमें राष्ट्रपति रुजवेल्ट, प्रधान मंत्री चर्चिल, सेना के अध्यक्ष एवं प्रमुख कूटनीतिज्ञ सम्मिलित थे। सम्मेलन में नोरमेन्डी आक्रमण को पुनः निश्चित किया गया। लार्ड लुईस माउन्टबेटन के नेतृत्व में एक दक्षिणी पूर्व एशिया प्रभुत्व स्थापित किया गया। जल सेना अध्यक्षों ने 'एटलांटिक युद्ध' में मित्र राष्ट्रों की विजय की सूचना प्रदान की।

मास्को विदेश मंत्री सम्मेलन

19 से 30 अक्टूबर तक मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का मास्को में एक सम्मेलन हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध काल में तीन मित्र राष्ट्रों के बीच प्रथम सभा थी। इसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्री एन्थोनी एडन, अमरीका के सचिव कॉरडेल हल व रूसी विदेश मंत्री मोलोटोव ने भाग लिया। सभा में तीनों राष्ट्रों के सेना अधिकारी भी सम्मिलित थे। सभा में प्रमुख प्रश्न वहिष्कृत पोलैंड की सरकार की मान्यता का विषय था, जिसे सोवियत संघ पूर्णतया अमान्य कर रहा था। स्टालिन ने जर्मनी की पराजय के पश्चात् जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा का वचन दिया। एक यूरोपीय परामर्शी आयोग का गठन किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य युद्धोपरान्त जर्मनी की संरचना व स्थिति के लिये नीति तैयार करना था। मास्को में “संयुक्त राष्ट्रसंघ” की आवश्यकता व सिद्धान्तों की भी घोषणा की गई।

9 नवम्बर को वाशिंगटन में चवालीस देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघ राहत एवं पुर्नवास प्रशासन की स्थापना हुई। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य युद्ध पश्चात् युद्ध प्रसित जनता के लिये राहत कार्यों व योजनाओं को प्रारम्भ करना था।

प्रथम कैरो सम्मेलन

22 से 26 नवम्बर तक प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय कैरो सम्मेलन हुआ। इसमें पूर्व एशिया में युद्ध की स्थिति व व्यवहरचना के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इस सम्मेलन में चीन के जनरल च्यांगकाई शेक, प्रधान मंत्री चर्चिल व अमरीकी राष्ट्रपति ने भाग लिया और 1 दिसम्बर को हुई “कैरो घोषणा” में तीनों राष्ट्रों ने जापान के साथ अनिश्चित कालीन युद्ध का निर्णय लिया जब तक कि जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं कर देता। जापान को उसके अधीनस्थ प्रशांत महासागर के समस्त द्वीप समूहों से अलग कर देने का निश्चय किया गया तथा कोरिया को भविष्य में एक स्वतंत्र स्तर प्रदत्त किया जाने का निर्णय लिया गया।

द्वितीय कैरो सम्मेलन

प्रथम कैरो सम्मेलन के तुरन्त बाद (4 से 6 दिसम्बर) कैरो में ही टर्की के साथ ग्रेट ब्रिटेन व अमरीका के बीच दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें



तेहरान सम्मेलन में मार्शल स्टालिन और रुजवेल्ट (1943 में)

टर्की के राष्ट्रपति इस्मत ईनोनी भी सम्मिलित थे। टर्की व ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक मैत्री संधि हुई एवं टर्की, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका व रूस के बीच मैत्री सम्बन्धों की घोषणा की गई। सम्मेलन में कुछ सैनिक निश्चय भी लिये गये जिसके फलस्वरूप जनरल ड्वाइट आइज़नहावर को पश्चिमी यूरोप क्षेत्र से आक्रमण करने के आदेश दिये गये।

तेहरान सम्मेलन (1943)

28 नवम्बर से 1 दिसम्बर तक तेहरान सम्मेलन आयोजित किया गया। यह द्वितीय विश्वयुद्ध काल का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्मेलन था। प्रथम बार सोवियत संघ के प्रधान मंत्री जोसफ स्तालिन ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा में भाग लिया था। इस सभा का प्रमुख विषय युद्ध की गतिविधियाँ एवं अन्य मोर्चों के प्रारूप निश्चित करना था।

वर्ष 1943 के समान 1944 व 1945 में भी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन व सभायें हुईं। इन वर्षों में अन्तर-राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रमुख विषय युद्धोपरान्त विश्व की स्थिति को निश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, के अन्य अंगों की स्थापना के लिए अमरीका ने ठोस कदम उठाये।

ब्रिटेन-वुड्स सम्मेलन (1944)

1 जुलाई से 22 जुलाई, 1944 तक "संयुक्त संघ एवं वित्तीय (ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन) सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सभा में 44 राष्ट्रों ने भाग लिया इसके निर्णयानुसार 8.8 अरब डालर की प्रारम्भिक धनराशि से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर का निर्धारण एवं व्यापार को विकसित करना था। इसके साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना भी की गयी। इन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा वित्तीय संस्थाओं के निर्माण में अमरीका का महत्वपूर्ण योगदान था।

27 जुलाई, 1944 को मास्को ने "पोलिश राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे" को मान्यता प्रदान की।

डम्बर्टन-ओक्स सम्मेलन (1944)

21 अगस्त से 7 अक्टूबर के मध्य वाशिंगटन के पास डम्बर्टन-ओक्स सम्मेलन हुआ। इसमें अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ एवं चीन के प्रति-

निधियो ने भाग लिया परन्तु चीन व सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने सभा में पृथक रूप से भाग लिया । इसका प्रमुख कारण रूस व जापान के बीच शान्ति समझौता था । सम्मेलन में विश्व युद्ध के पश्चात् स्थाई शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिये घोषणा पत्र का पांडुलेखन किया गया तत्पश्चात् यही घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का आधार बनी ।

द्वितीय विववेक सम्मेलन (1944)

11 से 16 सितम्बर तक हुये द्वितीय विववेक सम्मेलन में राष्ट्रपति रूज-वेल्ट एवं प्रधान मन्त्री चर्चिल ने जापान एवं जर्मनी पर विजयोपरान्त सामरिक योजनाओं पर विचार विमर्श किया । इसी सम्मेलन में वित्त सचिव हेनरी मॉरगैन्थो जूनियर ने जर्मनी की अर्थ व्यवस्था को कृषि पर ही निर्भर करने की एक योजना प्रेषित की परन्तु इसे एक माह पश्चात् राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अस्वीकृत कर दिया ।

द्वितीय मास्को सम्मेलन (1944)

9 से 18 अक्टूबर के मध्य महत्वपूर्ण द्वितीय मास्को सम्मेलन आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में प्रधान मंत्री चर्चिल व रूसी प्रधान मंत्री जोर्जफ स्टालिन ने दक्षिणी यूरोप व 'बालकन क्षेत्र' में अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र के विषय में निर्णय लिये । फलस्वरूप रूमनिया,बल्गेरिया एवं हंगरी सोवियत संघ के साथ सम्मिलित हुये और यूनान पर ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार रहा । अमरीका ने स्वयं को इन निर्णयों से अनुबंधित करना अस्वीकार कर दिया ।

वर्ष 1945 के प्रथम माह में ही याल्टा में मित्र राष्ट्रों के सेनाध्यक्षों ने संयुक्त बैठक में हिटलर के विरुद्ध अंतिम अभियान का निर्णय लिया ।

याल्टा सम्मेलन (1945)

4-11 फरवरी, 1945 के मध्य कृष्ण सागर में स्थित याल्टा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया । इसके बहुत से समझौतों को युद्ध काल तक गुप्त रखा गया । राष्ट्रपति रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिलने इसमें भाग लिया इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में उनके प्रमुख कूटनीतिज्ञ व सेनाध्यक्ष भी सम्मिलित थे । रूस को जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा के उसके वचन के फलस्वरूप 'कूरिल द्वीप समूह' 'साखालिन' व 'कोरिया' के एक भाग पर पूर्ण आधिपत्य के अधिकार दिये गये। इसके अतिरिक्त अमरीका व ब्रिटेन ने वाह्य मंगोलिया को भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करना स्वीकार कर लिया । मंगोलिया अब चीन से पृथक



याल्टा सम्मेलन (1945 में) विन्स्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और जोजफ स्टालिन

होकर रूसी प्रभाव में आ गया था। कर्जन रेखा के द्वारा पोलैण्ड को जर्मनी की पराजय के पश्चात् पुनः सीमा निर्धारित होने की आशा थी। रूस की जर्मनी से 20 अरब डालर की क्षतिपूर्ति माँग को क्षतिपूर्ति आयोग को प्रेषित कर दिया गया। तीनों बड़ी शक्तियों ने विना शर्त आत्म समर्पण की माँग पर दृढ़ निश्चय लिया और यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र हुये राष्ट्रों में जनमत के अनुसार सरकारें बनाई जायेंगी। सुरक्षा परिषद् में मतदान प्रणाली को सुनिश्चित किया गया।

21 अप्रैल को सोवियत संघ ने सामयिक पोलैण्ड की सरकार से वीस वर्षीय पारस्परिक सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किये।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन (1945)

25 अप्रैल से 26 जून, 1945 के मध्य संयुक्त राष्ट्र संघ की योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिये सैन फ्रांसिस्को में एक विश्व व्यापी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पचास देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रपत्र को आलेखित किया गया और निषेधाधिकार शक्ति का स्वरूप निश्चित हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा पत्र में संघ को छः अंगों में स्थापित करने की योजना थी जो इस प्रकार हैं :-

- (1) सामान्य सभा,
- (2) सुरक्षा परिषद्,
- (3) सामाजिक व आर्थिक परिषद्,
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय,
- (5) सचिवालय तथा
- (6) निक्षेपधारी परिषद्।

5 जून, 1945 को यूरोपीय परामर्शीय आयोग ने जर्मनी के विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की।

पोट्सडैम सम्मेलन (1945)

युद्ध की समाप्ति के साथ-साथ 17 जुलाई से 2 अगस्त तक बर्लिन के निकट पोट्सडैम में भिन्न राष्ट्रों ने एक सम्मेलन किया। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका तथा सोवियत संघ तीन प्रमुख शक्तियों के प्रधानाध्यक्षों के अतिरिक्त विदेश सचिव व अन्य सैनिक अधिकारी भी सम्मिलित थे। 26 जुलाई को सम्मेलन ने जापान से 'विना शर्त आत्मसमर्पण' के लिए घोषणा की। सम्मेलन

का प्रमुख उद्देश्य जर्मनी की व्यवस्था, अन्य यूरोपीय समस्याओं का समाधान कराना था। विभिन्न संधियों के आलेखन हेतु विदेश सचिवों की एक परिषद् का गठन किया गया। युद्ध के अपराधी व दोषी व्यक्तियों के मुकदमों का भी प्राविधान प्रेषित किया गया। हंगरी, पोलैण्ड व चेकोस्लावाकिया में प्रवासी जर्मन निवासियों के देशान्तर के प्राविधान का भी निश्चय लिया गया। इन जन समुदायों को पुनः जर्मनी में निवासित करना था। जर्मनी विषय में आर्थिक समझौते भी हुये। प्रमुख रूप से जर्मनी की अर्थ व्यवस्था में कृषि विकास व घरेलू उद्योग की योजनायें 14 अगस्त, 1945 को मास्को में रूसी-चीन संधि पर हस्ताक्षर हुये। चीन ने याल्टा सम्मेलन में रूस को दी गई स्वीकृतियों को स्वीकार कर लिया।

राष्ट्रपति रूजवेल्ट और उनका प्रशासन (1932-1944)

अमरीका के इतिहास में 1929 का युग आर्थिक मंदी के कारण अपने समय का एक संकटमय युग था। हर्बर्ट हूवर के राष्ट्रपति काल में अमरीका की आर्थिक एवं राजनैतिक दशा शोचनीय थी। अधिकारी तंत्र स्वयं अधिनायकतंत्र में परिवर्तित होता जा रहा था। इन्हीं सब कारणों से 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में जन समुदाय कुछ खिन्न था। गणतंत्रिय दल ने शिकागो में अपना सम्मेलन किया और हूवर को पुनः राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव हेतु मनोनीत किया गया। दल के नेताओं का विचार था कि हूवर को चुनाव में न लाने का अभिप्राय केवल अपने प्रशासन की पराजय को स्वीकार करना है।

लोकतांत्रिक (लोकतंत्रिक) दल में इस वार एक रोग ग्रस्त, किन्तु बुद्धिमान राजनीतिज्ञ का प्रादुर्भाव हो रहा था। वे थे न्यूयार्क के राज्यपाल फ्रैंकलिन डलेनो रूजवेल्ट जो कि पुराने राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दूरस्थ सम्बन्धी थे परन्तु उनकी प्रकृति उनसे भिन्न थी। वह एक सम्बेदनशील राजनीतिज्ञ थे। और अपनी प्रशासनिक सक्षमता का परिचय अपने पुराने पद कार्यों में दे चुके थे। 1921 में पोलियो के रोग से उन्होंने अपने आपको किसी तरह चलने योग्य बना लिया था और इस प्रकार यह विश्वास और धीरता उनके व्यक्तित्व में समा गई थी। वह अत्यन्त मधुर एवं तीव्र ध्वनि के वक्ता थे। उन्होंने अपने व्यंग्युक्त भाषणों से जनता को प्रत्येक स्थान पर आकर्षित किया। रूजवेल्ट ने हूवर प्रशासन की आर्थिक असफलताओं को घोषित कर उसने एक नवीन अर्थ-नीति का प्रचार किया और “भूले हुये लोगों” के उद्धार के विषय में अपनी



राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट

योजनायें दी । मद्य निषेध और आवकारी के लिये नयी नीतियाँ दी और संतुलित वज्रट व कई आर्थिक सुधारों का वचन दिया । आर्थिक संकट से त्रस्त जनता ने प्रत्येक स्थान पर रुजवेल्ट का हार्दिक अभिनन्दन किया । उन्होंने अपने को शरीर से असमर्थ होते हुये भी पूर्ण सक्षम बताया और इसके लिये 25 हजार मील का चुनाव दौरा किया । चुनाव अभियान के इस दौर ने देश की शोचनीय अवस्था में जागृति उत्पन्न की । हूवर यद्यपि अपनी पराजय का अवलोकन कर रहा था परन्तु एक धैर्यवान व्यक्ति की तरह ह्वाइट हाउस में निरन्तर कार्यरत रहा । गणतंत्रीय दल ने भी अपने भावपूर्ण नारे शुरु किये । उनका कथन था कि संकट के दिन व्यतीत हो चुके हैं और किशती किनारों तक पहुँच रही है, अतः उन्हें एक अवसर और मिलना चाहिये ।

चुनाव में रुजवेल्ट की भारी मतों से विजय हुई । जनमत में रुजवेल्ट ने 22, 809, 638 मत प्राप्त किये जब कि हूवर को केवल 15, 758, 901 मत मिले । चुनाव मत में रुजवेल्ट ने 59 के मुकाबले 472 मत प्राप्त कर एक बड़ी विजय प्राप्त की । हूवर को पश्चिमी भाग के छः गणतांत्रिक राज्यों के ही चुनाव मत मिले । चुनाव मत की प्रमुख बात यह थी कि नीग्रो मतों का स्थानापन्न दृष्टिगोचर हुआ । काले लोगों (नीग्रो) के मत लिंकन काल से लिंकन की गणतांत्रिय दल की ही ओर जाते थे । इन मतों के परिवर्तन का प्रमुख कारण यह था कि आर्थिक संकट के समय इन काले वर्ण के लोगों को सर्वाधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा । आर्थिक संकट की विपम परिस्थितियों से जन-समुदाय संतुस्त हो चुका था और वह प्रशासन में परिवर्तन चाहता था । हूवर की पराजय का प्रमुख कारण भी सम्भवतया यही था । जनता हूवर के विरुद्ध अधिक थी, रुजवेल्ट के साथ कम और परिवर्तन के लिये लोकतांत्रिक दल को लाना स्वाभाविक था । प्रतिष्ठापन दिवस मार्च 4, 1933 से पूर्व के चार माहों में चुनाव पराजित राष्ट्रपति हूवर ही प्रशासन में रहे, परन्तु रुजवेल्ट के सहयोग के बिना वह किसी भी दीर्घकालीन नीति को निर्धारित नहीं कर सकते थे । उन्होंने कई बार नीतियों के लिये चुनाव में मनोनीत राष्ट्रपति रुजवेल्ट के सहयोग की आकांक्षा व्यक्त की, परन्तु रुजवेल्ट ने कोई भी निर्णय लेने से इन्कार कर दिया । वास्तव में रुजवेल्ट बिना अधिशासी हुये किसी भी नीति में फँसना नहीं चाहता थे । इन चार माहों में प्रशासनिक दशा का और अधिक ह्रास हो गया एवं आर्थिक संकट की वृद्धि होती गई । बैंकों ने अपनी शाखायें बन्द करना शुरु कर दी, मुद्रा का मूल्य निरन्तर गिरता गया । अब लोग रुजवेल्ट को अपने राष्ट्र रक्षक की दृष्टि से देख रहे थे । लोकतांत्रिक दल के इस राष्ट्रपति ने देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने का संकल्प किया । उन्होंने नवीन

अर्थनीति को लाने का निश्चय कर लिया था। वह धार्मिक और दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे। आदर्शवाद पर उनके सामाजिक दृष्टिकोण आधारित थे। वह एक जन्मजात नेता थे। उन्होंने समस्त समुदाय को पर्याप्त रूप से पहले से ही प्रभावित कर लिया था। चुनाव में उन्होंने समय की पुकार को समझा और अभिव्यक्त किया। अपने प्रतिष्ठापन दिवस पर उन्होंने नवीन अर्थ नीति को व्यक्त किया और जनता को नव आशा के साथ संकट के युद्ध को प्रारम्भ करने का आह्वान दिया। उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों में कहा कि हमारे भीतर एक भय ही ऐसी भावना है जो भयभीत कर रही है वरन् हम सर्वविजित होंगे।

अब सम्पूर्ण राष्ट्र का भार रूजवेल्ट पर था। उन्होंने संकट मय स्थिति को देखते हुये समस्त बैंकों में 6 से 10 मार्च, 1933 तक के लिये अवकाश घोषित कर दिया जिससे बैंकों का पुनः आरम्भ सुदृढ़ एवं सुचारु रूप से किया जा सके। राष्ट्रीय संकट कालीन स्थिति के लिये। उन्होंने कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जो अमरीकी आधुनिक इतिहास में "सौ दिन" (9 मार्च से 15 जून तक) के नाम से जाना जाता है। इन सौ दिन में कांग्रेस ने जन सम्पन्नता के लिये कई व्यवस्थापन किये और योजनाओं का 'विधि रूपेण' कर उन्हें नवदिशा प्रदत्त की। रूजवेल्ट ने अब अपना नवीन अर्थ नीति का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इसको अंग्रेजी के तीन 'आर' अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है (रीलीफ, रिक्वरी एवं रिफार्म) अर्थात् उन्मुक्ति, प्रतिलाभ एवं सुधार। वास्तव में रूजवेल्ट ने लघु काल वाली योजनाओं को कार्यरत किया। उनका उद्देश्य था, कि राहत और पुनः उद्धार से जन समुदाय की स्थिति में परिवर्तन लाया जाय फिर सुधार के नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाय। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ दीर्घ काल वाली स्थाई शान्ति व सुधार की योजनाओं का भी प्रारम्भ किया। समय की पुकार के साथ रूजवेल्ट ने कांग्रेस में अपना पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। वास्तव में कांग्रेस उनकी रबर की एक मुहर मात्र रह गई थी। यहां तक कि कांग्रेस ने उन्हें असाधारण हस्ताक्षर चेक के अधिकार भी दे दिये थे। इतिहासकार डलेस ने रूजवेल्ट-कांग्रेस सम्बन्ध पर व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है 'कि यदि राष्ट्रपति कांग्रेस से कहता कि वह आत्महत्या कर ले तो शायद यह भी सम्भव हो जाता'। डलेस के अनुसार नवीन अर्थ नीति प्रगतिवादी आन्दोलन की निरन्तरता थी। इसमें थियोडोर रूजवेल्ट व वुडरो विलसन की नीतियों का मिश्रण था। नवीन अर्थनीति का उद्देश्य कुछ सुधारों द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को बनाये रखना था। इस 'सौ दिन' के अधिवेशन में कांग्रेस ने कई नये कानून पारित किये, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से कीमतों को कम

करना, मजदूरी की दरों और उपभोक्ता की क्रय शक्ति को वर्धित करना था। इससे मुद्रा विनिमय, संकुचन और दिवालियेपन की प्रक्रिया को अवरुद्ध किया जा सकता था। मुख्य रूपेण निम्न अधिनियम पारित हुये और ये कार्य नवीन अर्थ नीति काल के व्यवस्थापन के रूप में माने जाते हैं:-

(अ) कृषि सम्बन्धी

कृषि एकीकरण अधिनियम पारित हुआ। इसमें उत्पादन को कम करने व कृषि पदार्थों की कीमतों की वृद्धि का प्रयास किया गया ताकि उपभोक्ता व उत्पादन में संतुलन आ सके। जिन कृषकों को यह कार्यक्रम स्वीकार करना था उनको मूल उत्पादनों से भूमि कम करनी थी। इस भूमि निरूपण व कम करने में जो हानि थी उसका नकद भुगताद सरकार को देना था। जनवरी, 1936 में इस कानून पर अनेक समस्यायें उठीं, कृषकों ने उच्चतम न्यायालय में इसे गैर संवैधानिक बता दिया।

1936 में एक दूसरा अधिनियम पारित हुआ। यह भूमि संरक्षण व गृह आवंटन अधिनियम था। सरकार ने इसके द्वारा कृषकों को व्यापारिक फसलों की अपेक्षा भूमि का कुछ भाग संरक्षण कार्यों के उपयोग के लिये कहा और इस कार्य के लिये विशिष्ट सहयाता का आश्वासन दिया।

(ब), मुद्रा विनिमय व बैंकिंग सम्बन्धी

राष्ट्रीय संघ सरकार मुद्रा व जमानत के मामलों में निजी बैंकों का रूप लिये हुये थी। इसके लिये, रूजवेल्ट सरकार ने कई कानून पारित किये। 1933 में बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ और संघीय बीमा निगम ने जमा धनराशि की प्रत्याभूति दी। इसी वर्ष एक दूसरा अधिनियम प्रतिभूति (सेक्योरिटी) के लिये पारित हुआ। 1934 के 'प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम' ने आर्थिक संकट की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने का सफल प्रयास किया।

(स) श्रम व उद्योग सम्बन्धी :

1938 में 'कार्य समय कानून व श्रम माप दंड अधिनियम' पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम श्रमिक वेतन व अधिकतम कार्य का समय निश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रमिक कार्य लेनेपर पूर्णतया पाबन्दी लगा दी गई। किसी भी उद्योग में

उपरोक्त आयु से कम के बच्चों को रोजगार व श्रम में नहीं लगाया जा सकता था। एक अन्य अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान 'राष्ट्रीय औद्योगिक पुर्नलाभ अधिनियम' (एन.आई.आर.ए.) 1933 में पारित हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यवसायिक उद्यमों की सहायता करना था। इसके लिये कीमतों को स्थिर करने व स्पर्धा पर नियंत्रण रखने के लिये कानून बनाये गये थे। एक राष्ट्रीय पुर्नलाभ प्रशासन (एन.आर.ए.) की स्थापना भी की गई। इस संगठन को प्रत्येक उद्योग के लिये न्यायोचित प्रतियोगिता संहिता के निर्धारित करने का अधिकार दिया गया।

(द) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी :

1935 में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिये 'सामाजिक सुरक्षा अधिनियम' पारित किया गया और 'बेरोजगारी क्षतिपूर्ति' की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले समस्त मजदूरों को पेंशन के भुगतान का कानून बनाया गया। इन बेरोजगार व्यक्तियों के राहत के लिये रूजवेल्ट प्रशासन ने कई कदम उठाये। 1935 में लगभग 55 लाख व्यक्ति सहायता कार्यों पर ही निर्भर थे। बेरोजगारी एक स्थाई समस्या बनती जा रही थी। कांग्रेस ने इसके लिये नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत एक कार्य प्रगति प्रशासन की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार कार्यों को बढ़ाना था। इस प्रकार प्रत्यक्ष सहायता के कार्यों को स्थानीय प्रशासन पर निर्भर कर दिया गया।

इन व्यवस्थाओं के पश्चात् शीघ्र ही राष्ट्रपति ने इन अधिकारों का उपयोग सहायता कार्यों के लिये आरम्भ कर दिया था। नागरिक संरक्षण दल में सहस्रों युवकों ने नामांकन कराना प्रारम्भ कर दिया और सेना के अधिकारियों की अध्यक्षता में वे वृक्षारोपण व अन्य सभी कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जाने लगे। सहायता अधिनियम के आने के पश्चात् शीघ्र ही संघीय संकटकालीन सहायता प्रशासन ने हैरी हॉपकिन्स के निर्देशन में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस ने पचास करोड़ डालर की राशि सहायता कार्यों के लिये स्वीकृत की। इस सभी अनुदान का उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता था। इस पर भी हॉपकिन्स ने केन्द्रीय नियंत्रण उचित समझा और सहायता कार्यों को स्थानीय निकायों द्वारा सम्पन्न कराया। इसके अतिरिक्त हॉपकिन्स ने अमरीकी जनता की भावनाओं को समझते हुये सहायता केन्द्रों को यह निर्देश दिये कि वे लघु व्यवसाय कार्यों को गुरु करें ताकि जनता यह न महसूस करे कि उन्हें भिक्षा

अनुदान दिया जा रहा है। अनेक भवनों व इमारतों, गलियों आदि की स्वच्छता के कार्य दैनिक रूप से किये गये। इससे भोजन व वेतन ले जाने वाले अपने को भिक्षुक नहीं समझ सकते थे। हॉपकिन्स ने इसका भी पूर्णतया ध्यान रखा कि सहायता किसी प्रकार का राजनैतिक रूप न लेने पाये। इसके लिये उसने गणतंत्रीय दल के लोगों को भी नियुक्त किया।

कृषि समस्याओं के निवारण के लिये राष्ट्रपति ने प्रशासनों की स्थापना की। प्रथम प्रशासन तो मुख्यता ऋण के कार्य हेतु था और प्रथम छः माह में ही इसके ऋणों से दो लाख परिवारों का कल्याण हुआ। कृषि एकीकरण प्रशासन, जो एकीकरण अधिनियम के पश्चात् स्थापित किया गया था, मुख्यतः कृषि की दीर्घ कालीन 'समस्याओं' के लिये था। जार्ज पीक को इस प्रशासन का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया था। वे एक विख्यात कृषि अर्थशास्त्री थे। उनका मुख्य कार्य उत्पादन को अवरुद्ध कर मूल्यों का नियंत्रण करना था। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उत्पादन के कारण अन्य विक्री क्षेत्र का अन्वेषण भी इस प्रशासन द्वारा किया गया और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। कपास की स्थिति सर्वाधिक विपन्न थी। 1933 में उत्पादन में सबसे अधिक न्यूनता थी। बाजार उपयोगिता को संतुलित किया जाना था अन्यथा दक्षिण के कपास राज्य पूर्णतया समाप्त हो जाते। एकीकरण प्रशासन ने संकटमय स्थिति की घोषणा करते हुये कृषकों को शीघ्र ही खेती के कुछ भाग तक समाप्त करने का कहा और इस प्रकार एक करोड़ एकड़ से अधिक जमीन को फसल से अलग कर दिया गया। इस प्रकार कपास के मूल्यों को नियंत्रित कर दिया गया। तम्बाकू की खेती भी एक और बड़ी समस्या बनी हुई थी। सिगार पत्ती का उत्पादन पिछले वर्षों में अत्याधिक हो गया था और जन समुदाय के पास उपभोग के लिये धन ही नहीं था। फलस्वरूप जार्जिया और कैरोलिना के उपभोक्ताओं ने नीलाम के पश्चात् एकीकरण प्रशासन के नियोक्ताओं किसानों को शीघ्र ही फसल रोक देने को कहा और उनके लिये लाभ भुगतान का प्रवन्ध किया गया। इस प्रकार अनाज, गेहूँ व उनके उत्पादन तथा उपभोक्ता संतुलन को निश्चितता एवं नियमितता के द्वारा नियंत्रण करने की चेष्टा की गई।

इस प्रकार प्रशासन ने इस व्यवस्थित एवं गम्भीर स्थिति को अपनी उन्मुक्त नीतियों के द्वारा सुधारान्वित करने की चेष्टा की। परन्तु नियोजित अर्थ व्यवस्था को स्याई रूप देने हेतु राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्लाभ प्रशासन की स्थापना का आदेश दिया। प्रथम विश्व युद्ध के 'ओवरमेन अधि-नियम के सदृश' औद्योगिक पुनर्लाभ अधिनियम ने भी मुख्य अधिजानी एवं विभिन्न कार्यकारिणी समितियों को, समुचित रूप से स्थापित करने तथा अधि-

कार प्राप्त करने का कार्य दिया गया। औद्योगिक समानता को नियमित करने हेतु व्यापारिक संहिताओं का प्राविधान किया गया, जिससे लघु उद्योगों एवं कृषकों को किसी प्रकार की कठिनाई तथा हानि का सामना न करना पड़े। कृषकों को अपने उत्पादन विक्रय के व्यक्तिगत अधिकारों को स्वेच्छित रखा गया। अधिनियम की धारा 7 (अ) के अन्तर्गत श्रमिकों को किसी भी श्रमिक संघ में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोजित रूप से मूल्यों को बढ़ाना और नियोजित अर्थ व्यवस्था को जन्म देना था।

राष्ट्रपति ने ह्यू जॉन्सन को इस प्रशासन का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया और इस प्रकार पुर्नलाभ प्रशासन “आर्थिक युद्ध” का मुख्य केन्द्र बन गया। जॉन्सन ने नियुक्ति के पश्चात शीघ्र ही वेतन क्रम में वृद्धि व सेवा-योजन के अन्य द्वार खोलने के लिये एक अभियान प्रारम्भ कर दिया। पुनः सेवायोजना एवं न्यूनतम वेतन का एक समझौता किया गया और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों को एक “नीले गरुड़” का चिन्ह दिया गया जॉन्सन ने जनता से यह अनुरोध किया कि वे उन्हीं उद्योगपतियों तथा व्यापारियों से समझौता करें, जो “नीले गरुण” अभियान में राज्य के भागीदार हैं।

नव-अर्थनीति (न्यू डील) : सार संक्षेप

संघीय सरकार ने रूजवेल्ट के अर्थनीति की कार्यक्रमों की सहायता से इस आर्थिक मंदी के विरुद्ध एक युद्ध का सूत्रपात कर ही दिया था, राज्यों की सरकारों और स्थानीय निकायों ने भी उपरोक्त कार्यक्रम में रुचि प्रकट करना आरम्भ कर दिया। कुछ राज्यों ने श्रमिकों के क्षतिपूर्ति कानूनों को लागू कर दिया और और कुछ राज्यों ने सहायता कार्यों के हेतु विभिन्न कार्य समितियाँ स्थापित कर दी। इस प्रकार राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नव-अर्थनीति ने विभिन्न राज्यों में जन-सहायतार्थ योजनाओं का परिपालन करना आरम्भ कर दिया। इन योजनाओं के अन्तर्गत व्यस्क लोगों की रोजगारी एवं बच्चों के अस्पताल तथा सेवायोजना केन्द्रों को स्थापित कर उपरोक्त आर्थिक योजना को कार्यान्वित किया गया। यद्यपि उपरोक्त व्यवस्था एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसाधारण सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की भावना से प्रेरित हुआ परन्तु इसके उपरान्त भी कुछ क्षेत्रों की जनता इस प्रकार की नवीन नीति के प्रति उदासीन थी। 1934 के कांग्रेस के चुनावों में विरोधियों और प्रतिक्रियावादियों को भी स्थान प्राप्त हुये तथा यह भी प्रतीत हुआ कि गणतान्त्रिक दल के लोग इस

परिवर्तन विरोधियों के साथ प्रचार हेतु संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। “चैलेन्ज टू लिबर्टी” में भूतपूर्व गणतांत्रिक राष्ट्रपति हूवर ने नव आर्थिक नीति (न्यू डील) की कटु आलोचना की और इसको साम्यवाद तथा फासीवाद से युक्त बनाया। इसी प्रकार प्रतिक्रियावादी समाचार पत्रों ने भी रूजवेल्ट के विरोध में प्रचार करना आरम्भ कर दिया तथा लोकतांत्रिक दल के एक व्यापार प्रभावित समुदाय ने राष्ट्रपति की नीति का आलोचनात्मक विरोध प्रारम्भ कर दिया। उपरोक्त लोकतांत्रिक नेताओं ने अमरीकी स्वतंत्र संघ की स्थापना कर राष्ट्रपति की नीति का उन्मुक्त रूप से विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। मिशीगन में चार्ल्स कोफ्लिन नामक एक पादरी ने ‘नेशनल यूनियन फार सोशल जस्टिस’ संस्था की स्थापना कर ली और रूजवेल्ट की ‘न्यू डील’ और अन्य कार्यक्रमों के विरुद्ध अपनी योजनाओं का प्रचार शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे 1936 का चुनाव निकट आ रहा था, नयी-नयी संस्थायें तथा संघ निर्मित होने प्रारम्भ हो गये थे। रूजवेल्ट 1935 तक किसी भी प्रकार के विरोधी प्रचार से प्रभावित नहीं थे उन्होंने न्यू डील के कार्यक्रमों को अवरोध गति से हटाकर अपने प्रसार की ओर अग्रसर किया। संघों के कारण एक संकट अवश्य समक्ष था। यद्यपि समाजवादी एवं सामन्तवादी दलों को 1932 के चुनाव में आंशिक मत प्राप्त हुये थे और श्रमिक संघों के कारण प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसके अतिरिक्त नीग्रो जाति की विभिन्न समस्यायें उत्पन्न हो रही थीं। ऐसे वातावरण में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील से प्रभावित जन साधारण से प्रेरणा प्राप्त कर अपनी उत्साह पूर्ण योजनाओं के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया। प्रशासन ने जन लाभ हेतु अनेक अधिनियम एवं कानून पारित किये जिसके कारण व्यापारिक चोर बाजारी, व्यापारिक ठेकेदारी तथा प्रभावशाली व्यापारिक कम्पनियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखा गया।

टेनेसी घाटी व नदी योजना:

न्यू डील काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य टेनेसी नदी की योजना थी। विद्युत शक्ति की क्षमता को बढ़ाना राष्ट्र के हित में आवश्यक था और गरीबी से प्रताड़ित बेरोजगारों को कार्य देने हेतु एक दीर्घ कालीन वृहद योजना की शीघ्र आवश्यकता थी। अपनी समस्त शाखाओं के साथ टेनेसी नदी का फैलाव पूरे त्रिटेन से भी बड़े भाग पर था। पच्चीस लाख से अधिक जनता इसी नदी की तरफ घाटियों में निवास करती थी। वाशिंगटन में जन विद्युत की एक परि-योजना तैयार की गई और मसलशोल्स नामक स्थान, जो प्रथम विश्व युद्ध

से संघीय सरकार के अधीन था, से इस योजना का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। 1933 में 'टेनेसी घाटी प्राधिकार' के लिये एक अधिनियम पारित हुआ और इस नदी व इसकी सहायक नदियों पर बाँध निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया। इस दूरदर्शी व साहसी योजना का मुखिया सीनेटर जार्ज नोरिस था जिसके नाम को स्थाई रूप देने के लिये एक बड़े बाँध का नाम नोरिस बाँध रखा गया। इस प्रकार विद्युत की मूल्य दर व्यक्तिगत कम्पनियों की अपेक्षा कम आई। इस पर मंडलीय संस्थाओं ने कई आक्षेप किये और संघीय सरकार उनकी आलोचनाओं का केन्द्र बन गई। उनका विचार था कि प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण नीति के द्वारा सरकार अपने समाजवादी लक्ष्य को को पूर्ति करने में लीन थी। उपरोक्त किसी भी आलोचना के प्रति जनता आकर्षित नहीं हुई। वास्तव में टेनेसी बाँध योजना जनता के प्रति समृद्धि, उन्नति एवं सफलता की प्रतीक थी।

आवास योजनायें एवं सामाजिक सुरक्षा:

न्यू डील के प्रारम्भिक चरण में जन जीवन आवासीय कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया। जनता को आवास विकास सहायता प्रदत्त करने हेतु रूजवेल्ट ने "संघीय आवास प्रशासन" की स्थापना की। इस अधिकरण को कांग्रेस से अधिकार प्राप्त थे। गृह उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु लघु ऋणों की योजनायें तैयार की गईं। राष्ट्रपति शासन के प्रथम चरण में इस योजना की प्रत्येक रूप से प्रशंसा की गई। 1937 में कांग्रेस ने एक नयी बड़ी योजना को जन्म दिया और संयुक्त राष्ट्र आवास अधिकरण की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य सामूहिक समुदायों व राज्यों को आवास योजनाओं के लिये ऋण प्रदान करना था। यद्यपि उपरोक्त जन जीवन व आवास विकास हेतु सरकारी कार्यों की व्यक्तिगत एवं पूँजीपति वर्ग ने आलोचना की परन्तु अमरीका के इतिहास में मलिनावास के जीवन को आधुनिक आवासीय जीवन में परिवर्तित इसी युग में किया गया।

राष्ट्रीय पुर्नलाभ प्रशासन ने श्रमिकों के लिये "नीले गरुड़" चिन्ह आन्दोलन का आरम्भ किया था परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। रूजवेल्ट की कांग्रेस जो श्रमिक संघों को प्रोत्साहन देती थी, इस कमी को पूर्ण करने के लिये नयी योजना में लग गई और 1935 में नवीन "राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध अधिनियम" पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक "राष्ट्रीय परिषद्" की स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्य श्रम सम्बन्धी

कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण करना था। इस प्रकार श्रमिकों के संगठन बनाने व सामूहिक व्यापार करने के अधिकार पुनः प्राप्त हुये। सीनेट सदस्य वांगनर (वांगनर) की अध्यक्षता में उपरोक्त अधिनियम पारित किया गया था और इस लिये इसको "वांगनर अधिनियम" भी कहा जाता है। यह अमरीकी श्रमिक आन्दोलन का एक सशक्त एवं प्रभावशाली प्रथम चरण था। श्रमिक नेताओं ने औद्योगिक संगठन समिति का निर्माण किया तथा इसके पश्चात् भाँति-भाँति के संगठन बनने लगे और उन्हें अपने नियोक्ताओं से व्यापार करने का उचित श्रमिक अधिकार मिला। श्रम स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये 1938 के दूसरे चरण में (रुजवेल्ट के) कांग्रेस ने "स्पष्ट श्रम प्रमाणिकता अधिनियम" पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम के घंटों व श्रमिक वेतन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणिक करना था। लोगों की आशाओं के विपरीत श्रमिक संगठनों ने आगामी चुनाव में रुजवेल्ट का पूर्ण रूप से साथ दिया। सभी श्रमिक संगठनों ने पारस्परिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिये परन्तु उनके अन्दर साम्यवादियों एवं समाजवादियों के लिये थोड़ी भी सहानुभूति नहीं थी। रुजवेल्ट दिग्भ्रमित जन समुदाय का यथार्थ में नेता था। इन्हीं नव अर्थनीति की योजनाओं व कार्यक्रमों के मध्य 1936 के राष्ट्रपति चुनाव आरम्भ हुये। लोकतांत्रिक दल के लोगों के उत्साहपूर्ण समर्थन के द्वारा राष्ट्रपति की विजय भविष्य सूचक थी। लोकतांत्रिक दल ने फिलाडेल्फिया में अपना एक सम्मेलन आयोजित किया और रुजवेल्ट को पूर्ण उत्साह के साथ पुनः मनोनीत किया। यह केवल एक औपचारिक उत्सव था। दल में किसी ने भी रुजवेल्ट का विरोध नहीं किया। चुनाव की नीति की घोषणा भी पूर्णतया न्यू डील पर ही आधारित थी।

इसके विपरीत गणतांत्रिक दल में उपयुक्त नेता का अन्वेषण किया जा रहा था। दल के सदस्यों को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो रुजवेल्ट के विरोध में भाग ले सके। क्ली-लैंड में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया और अन्त में कान्सास के राज्यपाल एलफर्ड लेनडन को बहुमत से मनोनीत किया गया। लेनडन एक उदार प्रकृति तथा स्वतंत्र विचार धारा का नेता था और आय-व्यय संतुलन के लिये अर्थ शास्त्रियों व आम जनता में प्रसिद्ध था। इस दल ने रुजवेल्ट के विरुद्ध एक शक्तिशाली चुनाव अभियान आरम्भ किया। उन्होंने रुजवेल्ट की आर्थिक नीति का विरोध किया तथा उसकी नीतियों को प्रतिक्रियावादी बताया इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता व उदारवाद से संतुलित बजट द्वारा राहत प्रदान करने का विश्वास दिलाया। लेनडन वास्तव में एक कुशल व ईमानदार प्रशासक था। उसने देश भर में भ्रमण के द्वारा भाषणों का एक दौर आरम्भ किया और राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को संतुलित रखते हुये नई उन्मुक्त

योजना का वचन दिया परन्तु उसके भाषणों में ओज नहीं था। चुनाव में इन सब प्रचारों के होते हुये भी रूजवेल्ट को अत्यधिक बहुमत से विजय प्राप्त हुयी। चुनाव मत में उन्हें केवल दो राज्यों के आठ मत मिले जबकि रूजवेल्ट ने शेष अड़तालिस राज्यों से 523 मत प्राप्त किये। यह पिछले 115 वर्षों में सबसे बड़ी विजय थी। जनमत में भी रूजवेल्ट को 270.76 लाख मत मिले जबकि लेनडन को केवल 166.8 लाख मत ही प्राप्त हुये। रूजवेल्ट की विजय का मुख्य कारण उसकी नीतिवद्ध योजनाओं का पूर्ण कार्यान्वयन ही था। वास्तव में जैसा कि एक समकालिक इतिहासकार ने कहा है कि “सान्ता क्लाज के हाथ कौन काटता है।” इस विजय की जन समुदाय को भी एक बड़ी आवश्यकता थी। दूसरे चरण में राष्ट्रपति ने न्यू डील को पुनः प्रोत्साहन दिया।

इस बार पुरानी प्रथा को तोड़ते हुये 4 मार्च के स्थान पर जनवरी 20, 1937 को ही रूजवेल्ट ने अपना शपथग्रहण समारोह आयोजित किया। 20वें संवैधानिक संशोधन से कांग्रेस का सत्र भी जनवरी में आरम्भ करना था और इस प्रकार पुरानी प्रथा, जिसमें हारा हुआ राष्ट्रपति भी अपना अन्तिम सत्र मार्च तक करता था, समाप्त हो गई। न्यू डील कार्यक्रम अभियान को पुनः आरम्भ करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निर्णय लेना नितान्त आवश्यक था। रूजवेल्ट प्रशासन को अनेक निर्णयों में उच्चतम न्यायालय से पराजय मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार संवैधानिक अधिकार के सम्बन्ध में देश की उन्नति में अवरोध उत्पन्न किये थे। सभी न्यायधीन सत्तर से अधिक आयु वर्ग के थे और बहुत ही रुढ़िवादी थे। उनको विश्वास था कि वे कांग्रेस के कार्यों पर पूर्ण न्यायिक नियन्त्रण रखते हैं। रूजवेल्ट ने कांग्रेस से ऐसे विधेय के अधिकार मांगे जिसमें सत्तर से ऊपर न्यायधीनों को सेवा निवृत्त किया जा सके। बहुमत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और रूजवेल्ट की इस नीति की अत्यन्त भर्त्सना की गई। वह अधिनायकत्व की नीतियों का पोषक कहा जाने लगा, तथा ऐसा कोई भी विधेयक पारित न हो सका। कांग्रेस में (अपने ही दल में) रूजवेल्ट की यह प्रथम पराजय थी। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय को अमरीकी समुदाय पवित्र गाय का रूप देती थी। परन्तु 1937 के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय की धारणा में भी परिवर्तन आने लगा और इस प्रकार रूजवेल्ट की नीतियों को समर्थन मिलने लगा। ‘राष्ट्रीय श्रम सम्बन्धी अधिनियम’ एवं ‘सामाजिक सुरक्षा अधिनियम’ को भी न्यायालय से स्वीकृति मिल गई। कांग्रेस ने वाद में एक “न्यायालय सुधार अधिनियम” बनाया परन्तु वह केवल अवर (लोवर कोर्ट) न्यायालयों के लिये था।

1933 से 1937 तक राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट को लगभग पूर्ण

नियंत्रित कर लिया था। इस कार्य में मुख्य सहयोग कांग्रेस ने प्रदान किया, जिसने एक विपुल धनराशि के द्वारा इस आर्थिक नीति को सहायता प्रदान की। राष्ट्रपति अपने प्रशासन के दूसरे चरण में नवीन योजनाओं को कार्यान्वित करने में रत था। परन्तु प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण वजट तथा अर्थव्यवस्था में अनियमितता के आगमन से जन साधारण रुजवेल्ट को उत्तरदायी समझने लगा। इस संकट का मुख्य कारण वजट में सुधार कार्यों के लिये आवश्यक मुद्रा के न्यूनीकरण था। रुजवेल्ट ने राष्ट्रीय प्रशासन के पुर्नगठन के लिये कांग्रेस से अधिकार मांगे। परन्तु अब उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन नहीं प्राप्त था। सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित समस्या में उसकी नीतियों पर तानाशाही का आरोप लगाकर सदन के अधिकांश सदस्य उसके विरोधी हो चुके थे। अतः "पुर्न संगठन अधिनियम के मामले में रुजवेल्ट को पुनः पराजित होना पड़ा। दो वर्ष पश्चात् 1939 में कांग्रेस ने उसे इस अधिनियम को पारित करते हुये प्रशासनिक सुधार के कुछ संतुलित अधिकार दे दिये।

गणतांत्रिक दल ने रुजवेल्ट पर अब तीव्र आरोप लगाना आरम्भ कर दिया था। उनका कथन था कि न्यू डील के नियोजकों की चुनाव अभियान के समय में गतिविधियाँ तीव्र हो जाती हैं और जन समुदाय की भावनाओं का लाभ उठाया जाता है। कांग्रेस में भी गणतांत्रिक सदस्यों ने तीव्र विरोध आरम्भ कर दिया फलस्वरूप 1939 में कांग्रेस ने "हैच अधिनियम" पारित किया। इसमें चुनावों में पूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य व कर्तव्य परिभाषित थे तथा प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को चुनाव अभियान में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया। चुनावों में राजनैतिक उद्देश्यों से सरकारी धन को खर्च करने का विरोध किया गया तथा राहत धनराशि प्राप्त संस्थाओं से चुनाव अभियान के लिये चन्दा वसूलने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 1938 के अन्त तक न्यूडील योजनाओं की संगति लगभग समाप्त अथवा अतिमंद पड़ चुकी थी। 1938 के कांग्रेस के चुनावों में गणतांत्रिक दल को एक प्रभावशाली विजय प्राप्त हुई थी। इधर प्रशासन का ध्यान गृह नीतियों से हटकर अन्तर्राष्ट्रीय संकट की तरफ जा रहा था जो कि एक एक गम्भीर समस्या उत्पन्न कर रहा था। साहित्यिक वर्ग, गणतांत्रिक नेताओं तथा व्यापारी समुदाय ने तीव्रता से न्यूडील विरोधी अभियान आरम्भ कर दिया। सभी समाचार पत्रों में इस प्रकार के आक्षेप तथा आरोप आने लगे थे। इसके अतिरिक्त भी उपरोक्त संकट काल की न्यूडील योजनायें अमरीकी इतिहास में अत्यन्त महत्व रखती हैं।

हिटलर की बढ़ती हुयी अभिलाषाओं, तानाशाही की नीतियों तथा केन्द्रीय शक्तियों के आपसी गठबंधन से यूरोप में युद्ध का वातावरण

निर्मित हो चुका था। 1940 तक यूरोप में पूर्ण युद्ध प्रारम्भ हो चुका था और अमरीका में नये राष्ट्रपति चुनाव का अभियान प्रारम्भ हुआ। 1940 के चुनाव तक नीतियों में अत्यन्त परिवर्तन आ चुका था। गणतांत्रिक दल इस बार पूरी शक्ति से विजय की भूमिका तैयार कर रहा था। अमरीकी जन-समुदाय इस युद्ध से अत्यन्त प्रभावित था। मनरो के तटस्थता के सिद्धान्तों को अब मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती थी। गणतांत्रिक दल में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिये तीन नेता प्रमुख थे, सीनेट सदस्य रावर्ट टॉफ्ट जो पुराने राष्ट्रपति विलियम टॉफ्ट का पुत्र था और ओहियो से सीनेट का सदस्य था, दूसरा न्यूयार्क का प्रमुख वकील थामस ड्यूवी तथा अन्य एक और नेता प्रमुख था जो कि दल में नवागंतुक था। वह कभी प्रशासन में नहीं आया था परन्तु उसकी ख्याति व्यापारी वर्ग में बहुत व्याप्त थी। यह दक्षिणी निगम व अमेरीकी राष्ट्र मंडल का अध्यक्ष वेण्डेल विल्की था। अभियानों का एक दौर प्रारम्भ हुआ और दल को अचंभित करते हुये अत्याधिक प्रसिद्ध हो गया। अन्त में 24 जून के समारोह में विल्की की नामकरण के लिये विजय हुई और राष्ट्रपति पद के लिये मनोनीत हुआ। गणतांत्रिक दल ने चुनाव घोषणापत्र में विदेश नीति में मनरो सिद्धान्त को अपनाया परन्तु साथ ही साथ अमरीका ने सुरक्षा के लिये सहयोग का वचन दिया। उन्होंने बेरोजगारी समस्या के लिये व्यक्तिगत उद्योगों की वृद्धि करने को कहा और कृषकों की सहायता के लिये श्रम, उद्योग व कृषि में एक समान संतुलन लाने का वचन दिया। इससे उत्पादन के मूल्य में भी कमी आयेगी, ऐसा उनका कथन था।

इधर लोकतांत्रिक दल में इस बार भय का वातावरण था, परन्तु सदैव की भांति रुजवेल्ट पूर्ण उत्साहित और आश्वस्त प्रतीत हो रहे थे। इसीलिये उन्होंने दल समारोह का समर्थन कर, दो चरणों के सिद्धान्त का विखण्डन करते हुये तीसरे चरण के लिये चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। सम्पूर्ण दल ने समर्थन कर रुजवेल्ट को पुनः मनोनीत कर दिया।

रुजवेल्ट का प्रतिविम्ब अपने दल पर इतना गहन था कि उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण उत्साह के साथ पूरी हो जाती थी। रुजवेल्ट ने इस बार अपने उप-राष्ट्रपति पद के लिये पुराने कृषि सचिव हैनरी ए० वैंलेस को चुना। प्रतिनिधियों ने शीघ्र उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रुजवेल्ट के साथ हैनरी वैंलेस को भी मनोनीति कर दिया। इस बार वातावरण में गृह नीतियों का परित्याग कर विदेश नीतियों का चुनाव अभियानों में अधिक प्रभाव था। लोकतांत्रिक दल ने अपने मंच से अमरीकी तटस्थता की घोषणा की और जब तक बाह्य शक्तियाँ आक्रामक न करें। तब तक विदेशी युद्धों में हस्तक्षेप न करने

का वचन दिया गया। यद्यपि मनरो सिद्धांत में उनका भी पूर्ण विश्वास था परन्तु उन्होंने उन यूरोपीय देशों को पूर्ण सहायता देने की नीति अपनाई जो आक्रमण-कारियों व प्रचारवादियों के लक्ष्य बन रहे थे। परन्तु वे यह सहायता अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत ही देने के पक्ष में थे। लोकतांत्रिक दल केवल राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के पक्ष में नहीं था क्योंकि मानवतावाद अमरीका का प्राचीन सिद्धांत रहा है। अहस्क्षेप की नीतियों के अतिरिक्त अन्य नीतियों में दल की आर्थिक नीतियों की सुरक्षा संभावित थी क्योंकि उनसे एक विशिष्ट वर्ग के अतिरिक्त आम अमरीकी समुदाय के लाभ की संभावना अधिक थी। 1940 के घोषणा पत्र में इस प्रकार के प्राविधान थे। इस अभियान में कोई नवीनता नहीं थी क्योंकि दोनों दलों की लगभग सभी नीतियाँ समान थी अतः एक आलोचनात्मक वातावरण समस्त अभियान काल में बना रहा। विल्की केवल सार्वजनिक ऋण को कम करके व्यक्तिगत व्यापार द्वारा उत्पादन में वृद्धि की नई नीति देने के पक्ष में थे। तत्कालीन चुनाव में अपेक्षाकृत जनता ने अधिक रुचि ली और यही कारण था कि 1940 के चुनावों में मतदान प्रतिशत सर्वाधिक था। रूजवेल्ट को चुनाव में 27,243,466 मत प्राप्त हुये और विल्की को केवल 22,304,755 मत ही प्राप्त हुये। इस विजय के साथ ही रूजवेल्ट का राष्ट्रपति काल का तीसरा चरण आरम्भ हुआ और यह समय उसके राष्ट्रपति काल की व्यस्तता से पूर्ण युग था। रूजवेल्ट के प्रशासन का यह समय विश्व-युद्ध के समकालिक होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संकटकालीन क्षणों से परिपूर्ण था। इस प्रकार अमरीका के आर्थिक हितों एवं सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर था।

अमरीका में चुनाव अभियान का दौर चल रहा था कि हिटलर की आक्रामक एवं आतंकवादी नीति ने यूरोप की स्थिति को गम्भीर कर दिया था। इस महायुद्ध के प्रथम चरण में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गयी थी। और धुरी राष्ट्रों ने संगठन कर विश्व में अक्षरेखा खींच दी थी।

ऐसी विश्व स्थिति होने के कारण तथा ब्रिटेन के आर्थिक ह्रास के नाते अमरीका के लिये यह अनिवार्य हो गया था कि वह इस गम्भीर विश्व वृथाति का पुनरावलोकन कर इस नवीन उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने की योजना बनावे। रूजवेल्ट के परामर्शदाताओं ने इस नवीन स्थिति के लिये काँग्रेस का अधिवेशन बुलाया। 1939 के तटस्थता अधिनियम के अन्तर्गत किसी राष्ट्र को ऋण देने का कोई नियोजन नहीं था परन्तु निरन्तर युद्ध के कारण तथा विश्व राजनैतिक परिस्थितियों ने अमरीका को अपनी राजनैतिक विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिये बाध्य किया। इसी मध्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विन्स्टन

चर्चिल के अमरीकी राष्ट्रपति के पुनरावेदन एवं अनुरोध ने भी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को ब्रिटेन को आर्थिक एवं युद्धोपकरण की सहायता देने के लिये बाध्य किया। इसी अवसर पर राष्ट्रपति चुनाव भी आरम्भ हो गया था और रूजवेल्ट तीसरे चरण के लिये पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। राष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण में अपने 4 स्वातंत्र्यतय को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत थे—भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अभाव के लिये स्वतंत्रता अर्थात् अभावरहित होना, तथा भयमुक्त होने के लिये स्वतंत्रता। राष्ट्रपति ने अपने तृतीय चरण के प्रारम्भ में उपरोक्त ब्रिटेन सम्बन्धी राजनैतिक एवं आर्थिक पक्षों पर पुनः विचार कर अमरीका तथा ब्रिटेन के नौसैनिक अधिकारियों की गुप्त वार्ता को प्रोत्साहित किया। इन गुप्त बैठकों के मध्य ब्रिटेन को अमरीकी सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया गया। युद्ध के प्रसार के कारण अमरीकी सीनेट ने ऋग्ग पट्टा अधिनियम पारित किया जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति युद्ध काल में किसी भी युद्धग्रस्त देश की सहायतायें धनराशि एवं युद्ध सामग्री दे सकता था। इसके साथ ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के अतिरिक्त कनाडा से भी यौद्धिक परिचर्चा आरम्भ की और इसको राजनैतिक रूप से परिपक्व करने हेतु कनाडा के प्रधानमंत्री मैकेंजी किंग से युद्ध के मध्य पारस्परिक सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वासन दिये।

1941 में जब अमरीका एवं जर्मनी में परस्पर संघर्ष चल रहा था, उसी मध्य जापान के साथ अमरीका की एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। जापान ने 1939 में अपनी प्रसारीय नीति को कार्यान्वित किया। इसी मध्य 1940 में जापान ने जर्मनी और इटली के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जिसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा एवं पारस्परिक नीतियों को मान्यता देना था। इस समझौते से जापान को चीन के साथ हो रहे युद्ध में विजय प्राप्ति के लिये अत्यधिक बल मिला क्योंकि वह किसी अन्य बड़ी शक्ति (विशेषकर अमरीका) की मध्यस्ता से भयभीत व आंशकित था। युद्ध के इन क्षणों में भी अमरीका अपनी तटस्थता की नीतियों को बनाये हुये था दूसरी ओर जापान अपनी प्रसारवादी व आक्रमणकारी नीतियों को अपना रहा था। जापानी नेताओं जो मुख्यतः सेना के अधिकारी थे, को यह आशा थी कि वे एशिया में यूरोपीय समाज को शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लें साथ ही साथ चीन पर भी विजय प्राप्त कर एक 'एशियाई साम्राज्य' की स्थापना कर सकते हैं। अमरीका युद्ध से तटस्थ होते हुये भी ग्रेट ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों को अपनी सहायता प्रदान कर रहा था। इसी आशा से प्रधान मन्त्री चर्चिल ने एक संदेश में अमरीका से जापान की प्रशान्त महासागर में प्रसारीय

नीतियों को रोकने के लिये सहायता की याचना की। इधर अमरीका भी जापान के चीन में प्रसार से अत्यन्त क्रुद्ध था और इस प्रकार दोनों देशों के सम्बन्धों में पूर्ण स्थिति का प्रादुर्भाव हो गया। एटलांटिक महासागर में जर्मनी और इटली की नौसेना की शक्ति अत्यन्त बढ़ गई थी। इन परिस्थितियाँ व अपनी नीतियों के कारण अमरीका युद्ध में किसी भी स्थिति में सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं था। इन सब कारणों से अमरीका ने जापान के साथ शक्ति समझौते के लिये अपने कूटनीतिज्ञों को भी भेजा। जापान का सम्राट कोनोये भी युद्ध के पक्ष में नहीं था परन्तु जापान की गृह परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न थी वास्तव में वह सैनिक शासकों के आधीन आ चुका था। जनरल तोजो, जो प्रशासन को अपने हाथों में केन्द्रित किये था, युद्ध के लिये बराबर अग्रसर था। कूटनीतिज्ञों की असफलता और उनके बिना किसी निर्णय के वापस आ जाने पर, अमरीका ने आर्थिक प्रतिबन्धों व दबाव की नीति को अपनाया। युद्ध काल के प्रारम्भ से ही अमरीका में शास्त्रागार और शस्त्रों के निर्माण का कार्य बड़ी संख्या में प्रारम्भ हो गया। 25 जुलाई, 1940 को एक अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति ने जापान को सभी कच्चे मालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसमें कच्चे लोहे और पेट्रोलियम की सामग्री प्रमुख थी। कुछ दिनों पश्चात् राष्ट्रपति ने गैसोलीन के अतिरिक्त सभी वस्तुओं का व्यापार बन्द कर दिया। गैसोलीन, जो वायुयानों के उपयोग में आती थी, केवल अमरीकी महाद्वीपीय देशों के लिये निर्यात हो रही थी। इन आर्थिक प्रतिबन्धों से जापान को बहुत आघात पहुँचा और वह अमरीका से समझौते की चेष्टा करने लगा। चीन को अमरीका से एक बड़ी सहायता अभी भी प्राप्त हो रही थी। इन परिस्थितियों को देखते हुये जापान ने अपनी सेनाओं का मुख दक्षिणी पूर्व एशिया की ओर मोड़ दिया। दोनों देशों में तनाव को कम करने के लिये पुनः वाशिगटन में बातचीत आरम्भ हुई। जापान की दक्षिणी पूर्व एशिया से तटस्थ रहने के लिये दो मुख्य माँगें थी। प्रथम वह अमरीका के आर्थिक प्रतिबन्धों के हटाने की माँग कर रहा था, दूसरे वह चीन के साथ हो रहे युद्ध में किसी वाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के विरुद्ध था। दोनों ही मांगे अमरीका के हित में नहीं थी। अतएव अमरीका ने उपरोक्त जापानी माँगों को स्वीकार नहीं किया आर्थिक पक्षों पर, पुनः विचार कर उसने अमरीका तथा ब्रिटेन के नौसैनिक अधिकारियों की गुप्त वार्ता को प्रोत्साहित किया। इन गुप्त बैठकों के मध्य ब्रिटेन को अमरीकी सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया गया। युद्ध के प्रसार के कारण अमरीकी सीनेट ने ऋण पट्टा अधिनियम पारित किया जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति युद्ध

काल में किसी भी युद्धग्रस्त देश की सहायतायें धनराशि एवं युद्ध सामग्री दे सकता था। इस प्रकार सम्बन्धों में तनाव बना ही रहा परन्तु युद्ध का अभी कोई वातावरण नहीं था, न ही अमरीका युद्ध का इच्छुक था।

इधर यूरोप में हिटलर ने 1941 में सोवियत रूस पर आक्रमण कर महायुद्ध में एक नया अध्याय शुरू किया। रूस के पश्चिमी द्वार पर भीषण युद्ध शुरू हो जाने से साईबेरिया छोड़ से जापान के सभी भय समाप्त हो गये। अब उसने एशिया में अपने आक्रमणों एवं आंतक का वातावरण बना दिया। उसने हिन्द चीन एवं थाईलैण्ड पर अपना आधिपत्य कर लिया और हिन्देशिया और सिंगापुर पर आक्रमण की योजना बनाई। इन विजयों के पश्चात् अमरीका की जापानी व्यापारों में लगी धनराशि पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार अमरीका और जापान के बीच आर्थिक युद्ध का प्रादुर्भाव हो गया। परन्तु आंतरिक रूप से जापान युद्ध के लिये स्वयं को सक्षम बना रहा था।

6 सितम्बर, 1941 को जापान में गृह नीतियों को निर्धारित करने के लिये टोकियों में एक सम्मेलन किया गया और यह निश्चय किया गया कि समझौते की बातचीत की असफलता के पश्चात् वह मित्र राष्ट्रों से पूर्ण रूपेण युद्ध प्रारम्भ कर देगा। 18 अक्टूबर, 1941 को मंत्रिमण्डल में एक परिवर्तन हुआ। सेनाध्यक्ष जनरल तोजो जो कि अभी तक युद्ध मंत्री था, प्रधान मंत्री के पद पर आसीन हुआ। किन्तु जापान की विदेश नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा 5 नवम्बर, 1941 को दूसरे साम्राज्यिक सम्मेलन में कूटनीतिज्ञ सावुरो कुरुसु को समझौते की बातचीत को जारी रखने के लिये वाशिंगटन भेजने का निर्णय लिया गया। 1941 में जापान के साम्राज्यिक सभा ने युद्धरत होने की सम्भावना प्रकट की। जापान के राजनैतिक परामर्शदाताओं ने तथा राजदूतों ने अमरीका की सरकार से इस बात का अनुरोध किया कि यदि वह अपने व्यापारिक प्रतिबन्धों को समाप्त कर दें तथा चीन में जापान के सैनिक अभियान में अवरोध उत्पन्न न करें तो जापान दक्षिण पूर्ण एशिया में सैनिक अभियान रोक देगा। अमरीका की सरकार ने इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर निर्णय लेने से इंकार कर दिया जब तक जापान हिन्द चीन से आक्रमण अभिशून्यता की नीति को नहीं अपनायेगा। इसके अतिरिक्त अमरीका ने जापान को अपने अन्य सैनिक सम्बन्धों का पुनरावलोकन करने का परामर्श दिया। परन्तु जापान ने पर्लहार्बर पर 7 दिसम्बर, 1941 को आकस्मिक आक्रमण कर पूर्ण विश्व को स्तब्ध कर दिया और विशेष कर अमरीका को ऐसे युद्धोत्तेजक चरण पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ अमरीका को युद्ध की प्रज्वलित ज्वाला को शमन करने के अतिरिक्त

कोई अन्य विकल्प नहीं था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस विश्वासघाती जापानी आक्रमण के आह्वान को स्वीकार कर गोलार्ध एकता एवं पारस्परिक निर्भरता का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने यौद्धिक गतिशीलता तथा सैन्य संगठन को तीव्र गति से प्रारम्भ किया। राष्ट्रपति ने अमरीका में युद्धकालीन अनेक संगठनों का गठन किया तथा राष्ट्र की समस्त साधन एवं सम्पत्ति को युद्ध कार्यों की ओर प्रवाहित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अणुवम विकास योजना को त्रिगेडियर जनरल लेसलेग्रोवज के नेतृत्व में स्थापन करने का आदेश दिया। न्यू मैक्सिको के लॉस अलमास में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक राबर्ट ऑपेन हाइमर के निरीक्षण में अणु परीक्षण आरम्भ हुये और प्रथम अणुवम का सफल परीक्षण 16 जुलाई, 1945 को न्यू मैक्सिको में आलमागोदों में हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने युद्ध कालीन स्थिति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने हेतु आंतरिक सुरक्षा उपायों को भी पूर्ण रूपेण लागू किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की 12 अप्रैल, 1945 को आकस्मिक मृत्यु के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णयात्मक चरण में तथा युद्ध उपरान्त शान्तिवार्ता में अमरीका उनके नेतृत्व द्वारा लाभान्वित नहीं हो सका।

उपसंहार

फ्रेंकलिन डेलैनो रूजवेल्ट अमरीका के इतिहास में सम्भवतः सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रपति था। अपने बारह वर्ष के काल में उसने अमरीका का दो महत्वपूर्ण, गम्भीर, निर्णायक एवं संकटकालीन स्थितियों में मार्ग निर्देशन किया। अपने प्रशंसकों के प्रति उसका व्यक्तित्व एक नायक विरोचित था जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं के सत्तावादी एकाधिकरण सिद्धान्तों के विपरीत सशक्त एवं सिद्धान्त पूर्ण था। अपने शत्रुओं के प्रति रूजवेल्ट एक विभ्रान्त एवं नैतिक सिद्धान्तों के परिपालक के रूप थे उनके विरोधियों के विचार स्वरूप वह अमरीका के लोकतंत्र को अपनी राज कल्याणकारी नीति के मार्ग पर लाना चाहते थे वह जो वास्तव में समाजवाद का द्योतक था। रूजवेल्ट में मनोभाव उत्सित करने की अलौकिक प्रतिभा थी। उनके व्यक्तित्व में विशेषता थी कि या तो उन्हें प्रेम किया जा सकता था अथवा ईर्ष्या, परन्तु उनकी ओर उदासीन रहना सम्भव नहीं था।

रूजवेल्ट मनोवेग उत्पन्न करने में समर्थ क्यों थे ? वैसे तो यह प्रश्न साधारण है और इसका उत्तर उनके बहुमुखी व्यक्तित्व में निहित है।

फ्रांसिस परकिंस जो काफी समय तक उसका श्रम सचिव रहा, रूजवेल्ट

के प्रति उसका कहना था कि वह एक अत्याधिक उलझे हुये व्यक्तित्व का स्वामी थे। रूजवेल्ट का राष्ट्रपति काल जितना ही विवाद का विषय है उतना ही लेखन कार्य उनके प्रतिमित्रों, शत्रुओं एवं उसके सम्बन्धित लोगों द्वारा हुआ है।

रूजवेल्ट के विवादास्पद राष्ट्रपति काल का श्रेय उनकी 'नव अर्थनीति' को ही समझा जाता है क्योंकि उनकी नवीन नीति के परिपालन ने उनके प्रति विभिन्न विचारधाराओं को जन्म दिया। उनके 1936 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के मध्य अल स्मिथ जैसे लोकतांत्रिक ने कहा कि यदि रूजवेल्ट प्रशासन स्वयं को नारमन टामस, कार्ल मार्क्स और लेनिन अथवा इस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित माने तो ठीक है परन्तु उनके कार्य को जैफरसन, जैकसन एवं क्लीवलैण्ड की ध्वजा के अन्तर्गत मान्यता नहीं दी जा सकती।

रूजवेल्ट की नव अर्थ नीति (न्यू डील) की आलोचना दक्षिण एवं वाम-पंथ दोनों ओर से की गयी। अनेक विचारकों का मत था कि अमरीकी परम्परावादी व्यक्तिगत मान्यताओं को राष्ट्रीय औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति ने अविकसित छोड़ दिया था। इन आलोचकों का प्रतिनिधित्व रेक्सफोर्ड टगवेल ने किया जो अर्थशास्त्री होने के साथ साथ 'न्यू डील' प्रारम्भिक काल का 'विज्ञ मंडलीय' सदस्य भी था। टगवेल के अनुसार अमरीकी आर्थिक प्रतियोगी नीति कदापि सफल नहीं रही और न ही उसमें लघु परिवर्तन करना पर्याप्त था। उनके अनुसार सरकार द्वारा पूर्णरूपेण आर्थिक व्यवस्था को नियोजित करने पर ही आर्थिक नीति को स्थिरता प्रदान की जा सकती थी एवं भविष्य में "आर्थिक मंदी" को अवरोधित किया जा सकता था। रूजवेल्ट की नीति टगवेल के विचार में सुनियोजित एवं बुद्धियुक्त नहीं थी। उपरोक्त विचारधारा के विपक्ष में वामपंथी आलोचकों ने नव अर्थनीति को अत्यन्त रूढ़िवादी बताया। उनके मतानुसार अमरीकी आर्थिक व्यवस्था की पुनः कल्पना तथा समाजवादी राष्ट्र की स्थापना ही आर्थिक मंदी रोकने का विकल्प था।

इस प्रकार मंदी युग में नव अर्थ नीति पर विभिन्न दृष्टिकोणों से आक्षेप लगाये गये, और इसे उग्रवादी, रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी की संज्ञा दी गयी। इन आलोचकों ने एक ओर उस समय की जनभावना की अभिव्यक्ति की और दूसरी ओर भविष्य के इतिहासकारों तथा अन्य विद्वानों के लिये भी एक रूपरेखा तैयार कर दी जिस पर विभिन्न मतों ने आश्रय लिया।

इनमें प्रगतिशील मत के इतिहासकारों ने नव अर्थनीति को रूढ़िवाद एवं उदारवाद के संघर्ष की संज्ञा दी अर्थात् न्यूडील का समय एकाधिकार, विशेषाधिकार तथा निहित स्वार्थ के विरुद्ध द्वन्द था। नवअर्थनीति को इन

विद्वानों ने यथापूर्व हुए उन्हीं सुधार आन्दोलनों के समान माना जिनमें जैफरसन एवं जैक्सन का लोकतंत्र, उदारवाद एवं लोकवाद सम्मिलित था और इन सब का ध्येय था, लोगों के संघर्ष को राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समानता के प्रति जागरूक बनाये रखना यद्यपि नव अर्थनीति का क्रांतिकारी चरित्र दर्शाया गया है, परन्तु यह नीति विगत आन्दोलनों से प्रभावित नीतियों से भिन्न नहीं थी। लुई हेकर ने नव अर्थनीति को 1940 के मध्य "तृतीय अमरीकी क्रांति" की संज्ञा दी। हेकर ने क्रांति की संज्ञा देकर भी नव अर्थनीति के प्रति किसी नवीन मत को प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उन्हीं सब सिद्धांतों की व्याख्या पर बल दिया जो मध्य 19वीं शताब्दी से आरम्भित थे।

हेनरी स्टील कॉमेजर ने नव अर्थनीति के क्रांतिकारी स्वरूप को मान्यता नहीं दी परन्तु इसको केवल पुराने पत्तों की नयी बाँट बताया। कॉमेजर के अनुसार नव आर्थिक नीति केवल दो कारणों से उग्र सुधारवादी प्रतीत होती थी। प्रथम जिस शीघ्रता से इस नीति का अधिनियमन किया गया और द्वितीय हार्डिंग कूलिज तथा हूवर की कोई कार्य न करने की प्रणाली की तुलना में नव अर्थ-नीति को उग्रवादी समझा गया। यदि उपरोक्त नीति की उपसमानता 19वीं शताब्दी वींशती से न कर प्रगतिशील युग से की जाय, तो असाधारण समरूपता दृष्टिगोचर होगी। कॉमेजर ने रुजवेल्ट की उपलब्धियों में आत्मविश्वास का पुनः उन्नयन, लोकतंत्र में आस्था तथा राष्ट्र की मानवीय एवं नैसर्गिक साधनों के पुनः स्थापन को मुख्य बताया। उपरोक्त समस्त नीतियाँ एवं उपलब्धियाँ अमरीका में हुये पूर्वसुधार आंदोलनों के समान थीं। सम्भवतः अर्थ-नीति के प्रति अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण तर्क आर्थर श्लेसेजर ने दिया। श्लेसेजर के अनुसार नवअर्थनीति अमरीका के पूर्व उदारवादी इतिहास की निरन्तरता की द्योतक थी। आर्थर श्लेसेजर ने अपने प्रतिभावान भौतिक अध्ययन में अमरीकी इतिहास को उदारवादी एवं रुढ़िवादी आन्दोलनों का चक्रिय परि-क्रमण काल की संज्ञा दी है क्योंकि उनके अनुसार जैफरसन लोकतंत्र का पतन ही जैक्सन लोकतंत्र था। रोवरबैरनस के पश्चात् प्रगतिशील युग तथा 19वीं शताब्दी वींशती के नीरस रुढ़िवादी काल उपरान्त नव अर्थनीति युग आरम्भ हुआ। श्लेसेजर की धारणा में इस चक्रिय प्रजनन का कारण सामाजिक संघर्ष था, जो यथासमय अमरीकी समाज में आन्तरिक रूप से उत्पन्न होता रहा। अपने इस अध्ययन को श्लेसेजर ने अपने अनेक लेखों के अतिरिक्त अपनी पुस्तक 'दि एज आफ रुजवेल्ट' में स्पष्ट किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने नव अर्थनीति को अमरीकी उदारवाद के इतिहास का अनिवार्य अंग की मान्यता दी है और इसे उदारवादी रुढ़िवादी चक्र का एक विशिष्ट चरण बतलाया है।

उनके मत में नव अर्थनीति की उत्पत्ति का एक मात्र कारण आर्थिक मंदी नहीं था, वरन इस आर्थिक मंदी ने नव अर्थनीति को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदत्त किया। यदि आर्थिक मन्दी का काल न आया होता तब भी वह नीति किसी न किसी रूप में निर्मित होती। श्लेसेंजर ने नव अर्थनीति को व्यवहारिक वास्तविक एवं क्रियाशील की संज्ञा दी क्योंकि इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं आर्थिक विकास का सम्मिश्रण सम्भव था।

श्लेसेंजर की इस धारणा को अन्य इतिहासकारों ने भी प्रतिष्ठित किया जिनमें मुख्य फ्रैंक फ्रीडेल था। फ्रीडेल ने नव अर्थनीति को उन व्यक्तियों का कार्य बतलाया जो प्रगतिशील युग में प्रौढ़ता एवं नैतिक मूल्यों से प्रभावित हो चुके थे उनके अनुसार ये मानवीय सुधारवादी सरकारी राजतंत्र के द्वारा साधारण जनता को लाभान्वित करना चाहते थे। फ्रीडेल ने प्रगतिशील युग के उद्देश्यों तथा प्रथम विश्व युद्ध के अनुभव को नव अर्थनीति का आधार माना अर्थात् रूजवेल्ट की योजना अमरीकी परिपाटी की परिधि में ही सीमित थी।

उपरोक्त इतिहास वेत्ताओं ने नव अर्थनीति को अमरीकी उदारवादी एवं प्रगतिशील परम्परा में ही संयोजित रखा, परन्तु इसकी कड़ी आलोचना भी की। इसके साथ ही इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि नव अर्थनीति का विकल्प अधिनायक तंत्र ही हो सकता था।

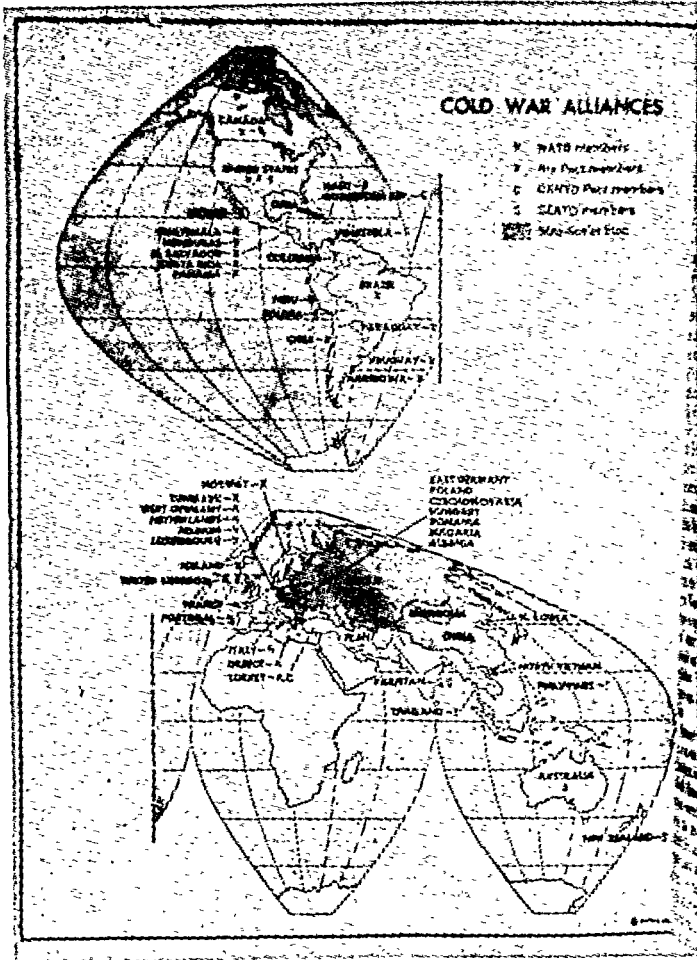
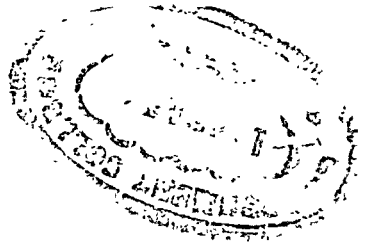
इसके विपरीत रूढ़िवादी इतिहासकारों ने नव अर्थनीति को पारम्परिक अमरीकी मान्यताओं के विरुद्ध माना क्योंकि उनके विचार में यह नीति अमरीका के मानवीय अधिकारों के सिद्धांत के विपरीत थी। जान पिलन ने अपनी पुस्तक 'दि रूजवेल्ट मिथ' में नव अर्थनीति को स्थाई संकट तथा शस्त्रीकरण अर्थ व्यवस्था की संज्ञा दी। उनके अनुसार इस नीति के द्वारा प्रादेशिक सरकारों तथा अमरीकी कांग्रेस के अधिकारों का ह्रास हुआ और राष्ट्रपति को असीमित अधिकार प्रदत्त किये गये। इस नीति ने संघीय ऋण में वृद्धि की।

रूजवेल्ट की नव अर्थनीति की आलोचना इतिहासकार रिचर्ड होफस्टाटर ने अपनी पुस्तक 'दि एज आफ रिफार्म: फ्राम ब्रायन टू एफ०डी० आर० में की है। होफस्टाटर के अनुसार अर्थ नीति पूर्व सुधार आन्दोलनों से हटकर थी, क्योंकि इस नीति के सुधारकों ने अमरीकी समाज को दूषित एवं रोगग्रस्त समझकर कार्य किये। इस नीति ने जन-सरकार के उत्तरदायित्व से पृथक होकर संघीय सरकार की शक्तियों को केन्द्रित कर दिया। होफस्टाटर के मतानुसार नव अर्थनीति में कोई दार्शनिक तत्व नहीं था, और न ही इसका लक्ष्य प्रगतिशील एवं सुधारवादी था। यह नीति राजनीतिज्ञों, प्रशासकों एवं

तकनीकियों के संतुष्टीकरण की नीति थी । इसके अतिरिक्त विलियम लूरान-वर्ग जैसे इतिहासकारों ने रूजवेल्ट की नीति को व्यवहारिक एवं परिणामवादी बताया है, परन्तु इसका रचनात्मक पक्ष राष्ट्रपति हूवर के शासन काल और वामपन्थियों के विरोधाभास में है । इस प्रकार नव अर्थनीति की उपलब्धि को निष्पादित करना इतना सहज और सुगम नहीं है क्योंकि इस नीति ने अमरीकी इतिहास में एक ऐसा बौद्धिक मतभेद उत्पन्न कर दिया है, जिसको इतिहासवेत्ता एवं विद्वान अपने अपने दृष्टिकोण से मूल्यांकित करते रहेंगे ।



सिद्धान्तवाद



शीत-युद्ध गठबन्धन

शीत युद्ध पारस्परिक अविश्वास एवं राजनैतिक व कूटनैतिक शंकाओं पर आधारित था और शनैः-शनैः मतभेदों की उग्रता एवं राजनायिक कठिनाइयों ने महाराष्ट्रों को एक दूसरे के प्रति ग्रहित प्रणालियों के द्वारा संदिग्धता प्रदत्त की। शीत युद्ध ने यूरोप की राजनीति में एक विशेष स्थान उत्पन्न कर उसे सांस्कृतिक एवं सामरिक रूप से अमरीका एवं रूस से प्रभावित कर दिया। इसके साथ ही शीत युद्ध ने एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप मिस्र, इसराएल, भारत एवं पाकिस्तान अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गये।

सैद्धांतिक गुट शिविर

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही पश्चिमी देशों ने अपना ध्यान केन्द्रीय देशों की परिघ से हटाकर सोवियत संघ द्वारा प्रेरित साम्यवाद की क्रान्तिमय शक्ति के विस्तार को रोकने में लगा दिया था। पूर्वी यूरोप व बाल्कन में हिटलर की निर्दयता ने एक आतंक का वातावरण उत्पन्न कर, दिया था। युद्धोपरान्त जर्मनी का स्वरूप दयनीयता की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। जर्मन जनसमुदाय में सामाजिक विकेन्द्रीयता तथा अस्थिरता का वातावरण व्याप्त था। सोवियत संघ की साम्यवादी सेनाएँ पूर्वी यूरोप को अपने साम्यवादी साम्राज्यवाद के प्रभावी क्षेत्र में लाने का तीव्र प्रयास कर रही थी। सोवियत संघ ने एल्वे तक अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। इस क्षेत्र के गैर साम्यवादी भी सोवियत संघ को सहयोग प्रदान कर रहे थे क्योंकि उनका विचार था, कि सोवियत संघ स्वतंत्रता के संघर्ष में उनका पथ-प्रदर्शन कर सकता था। उनका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनता व सामंतवाद का पूर्णतया अंत करना था। साम्यवाद की समयिक धारा ने पश्चिमी देशों के व्यापार

एवं उद्योग के प्रति संकट सूचक का कार्य किया, क्योंकि पोलैण्ड, रूमानिया, बुल्गारिया, हंगरी अलबानिया इससे पूर्व साम्यवाद के द्वारा अवगठित हो चुके थे ; आरम्भ में युगोस्लाविया भी इसमें सम्मिलित था परन्तु बाद में मार्शल टिटो ने स्वयं को इससे पृथक कर लिया था । इटली और फ्रांस में भी लोग लाखों की संख्या में साम्यवादी दल के सदस्य बन रहे थे । इस प्रकार दो विभिन्न विचारधाराओं के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न आदर्शों एवं सिद्धांतों को लेकर विश्व का विभाजन दो भागों में हो गया था । विश्व युद्ध के पश्चात् का यह काल दो भिन्न विचारधाराओं एवं सिद्धांतों के मध्य ग्रस्त होकर एक नव काल का सूत्रपात कर रहा था । इस मध्य कालीन समय को शीत युद्ध का काल कहा जाता है । पश्चिमी एशिया व एशियाई देशों में भी रूस का प्रभाव विस्तृत हो रहा था । रुजवेल्ट ने याल्टा सम्मेलन में पोलैण्ड, रूमानिया व बुल्गारिया में पूर्ण साम्यवादी लाल सरकार की स्थापना का विरोध किया तथा इसके अतिरिक्त जार के साम्राज्याधीन पूर्व कालीन प्रदेशों को पुनः सोवियत संघ में सम्मिलित करने का भी विरोध किया । 12 अप्रैल, 1945 को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन भी उन्होंने पोलैण्ड की समस्या में चर्चिल को दृढ़ रहने के लिये एक सुझाव पत्र भेजा था ।

साम्यवादियों का विचार था कि प्रथम विश्वयुद्ध के ही समान इस बार भी अनेक जनतांत्रिक देश विनाश की योजना निमित्त कर रहे हैं । उन्होंने अमरीका पर यह भी आरोप लगाया कि वह जापान व जर्मनी का पुनर्शस्त्रीकरण कर रहा है । इसी प्रकार ट्रूमैन द्वारा अणुशक्ति सूचनाओं को गुप्त रखने की घोषणा से भी साम्यवादियों में भय तथा आशंका की वृद्धि हुई । ट्रूमैन ने अपनी नयी नीति में एशिया तथा यूरोप में सेना तथा नौसेना के अड्डे बनाने की योजनाएँ भी दीं । उनका कथन था कि इससे उन्हें विश्व शांति बनाये रखने में सहायता मिलेगी । उन्होंने प्रशान्त महासागर में जापान से मिले द्वीपीय समूहों में भी हवाई अड्डों को बनाने का विचार दिया । इन गतिविधियों को देखते हुये रूसियों ने अपने आरोपों को और तीव्रतर कर दिया ।

साम्यवाद के प्रसार और प्रभाव को सीमित करने के लिये कांग्रेस में विश्व देशों की सहायता के लिये नये प्रस्ताव रखे गये । प्रथम विश्व युद्ध की भांति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भी यूरोप और एशिया की राजनैतिक एवं मानवीय स्थिति शोचनीय हो गयीं थी । भूख और अस्थिरता से व्याकुल जनता को साम्यवाद की ओर जाने से रोकने का एक मात्र उपाय उनकी यथार्थ सहायता में निहित था । उनकी सहायतार्थ जून 5, 1947 को विदेश सचिव, जार्ज मी० मार्शल ने अपनी योजना प्रेषित की । ट्रूमैन ने अपने खाद्य परामर्शदाता

से अमरीका में खाद्य नियंत्रण के लिये कहा और दूसरे देशों को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। ऐसे संकट काल में विश्व का कोई भी देश आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं था। यहाँ तक कि स्वयं विजयी देश भी निर्धनता के संकट से दूर नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र 'संघ सहायता तथा राहत प्रशासन' (नवम्बर, 1943) ने प्रारम्भ में 4 अरब डॉलर की अग्रिम सहायता की योजना निर्मित की जिसमें अमरीका की सहयोग राशि 72% (प्रतिशत) थी। अमरीका ने अपने यूरोप में स्थित सैनिक अधिकारियों एवं विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, उदाहरणतया रेड क्रॉस आदि के द्वारा एक यूरोपीय सहायता योजना प्रारम्भ की। इन योजनाओं से सम्बन्धित सहायता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन समस्त कार्यक्रमों ने अमरीका की अर्थ व्यवस्था में एक नवीन परिवर्तन किया परन्तु यूरोपीय देशों की दयनीय अर्थ व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं प्रतीत हुआ। फलस्वरूप नवीन योजनाओंपर विचार किया गया और हावर्ड विश्वविद्यालय में एक व्यक्तव्य में बोलते हुये विदेश सचिव जार्ज मार्शल ने 5 जून, 1947 को एक विस्तृत दीर्घ कालीन सहायता की योजना प्रस्तुत की। अपने भाषण में विश्व स्वतंत्र समुदाय की स्थापना के लिये अमरीका की नवीन विदेश नीति में सहायता योजना की महत्ता को व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा, "हमारी नीति किसी सिद्धांतवादी उपायों से सम्बद्ध नहीं है, न ही हम किसी राष्ट्र विशेष के विरुद्ध हैं। हम गरीबी, असन्तोष से पीड़ित दयनीय, मानवीय व्यवस्थाओं के विरुद्ध हैं और इनके निवारण के लिये हमें पूर्ण प्रयास करना है। हम विश्व की अर्थ व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहते हैं जिससे समाज में जनतंत्र और स्वतंत्र सिद्धांत सम्पन्न रहे।"

अमरीकी सहायता योजनाओं का मुख्य ध्येय इन राष्ट्रों की स्थिति सुदृढ़ कर उनकी उपभोक्ता शक्तियों को बढ़ाना था। वास्तव में पश्चिमी यूरोप की अर्थ व्यवस्था की अस्थिरता से अमरीका के व्यापार को अत्यन्त हानि हो रही थी। विदेश सचिव ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया कि अमरीका उन सभी सहायताओं पर विचार करने के लिये वचनबद्ध है जिनकी यूरोपीय देश उससे आशा करते हैं। इन सहायता विवरणों पर विचार करने हेतु उसने समस्त मित्र राष्ट्रों से उनकी सहायता माँगों के विवरणों की सूची प्रेषित करने को कहा। सोवियत संघ एवं उनके समर्थक राष्ट्रों ने मार्शल की इस नवीन योजना को अमरीकी पूंजीपतियों के प्रसार एवं साम्राज्यवाद के नवीन स्वरूप की संज्ञा प्रदान की परन्तु अन्य यूरोपीय राष्ट्रों ने जो इस प्रकार की योजनाओं को लालायित दृष्टि से देखते थे, मार्शल योजना का भव्य स्वागत किया। सितम्बर, 1947 में 16 यूरोपीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने, जिसमें आंग्ल-अमरीकी-जर्मनी

के भी सदस्य सम्मिलित थे, पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विदेश सचिव जार्ज मार्शल की योजना के ऊपर विचार विमर्श किया गया। सोवियत संघ ने इसे पश्चिमी देशों के गठबंधन, का स्वरूप बताया एवं विरोध में अपने साथ स्लाविक राज्यों और फिनलैंड को सम्मेलन से पृथक रखा। इस सम्मेलन के फलस्वरूप एक 'यूरोपीय आर्थिक सहकारी समिति' का गठन किया गया तथा प्रत्येक राष्ट्र ने सम्मिलित रूप से अपने कृषि और औद्योगिक उत्पादन में कमी का व्यौरा तथा इससे सम्बन्धित सहायता माँग का आय-व्ययक अमरीका के समक्ष प्रस्तुत किया। इस सहायता के लिये एक चार वर्षीय कार्यक्रम की योजना तैयार की गयी। कुल '21, 780' मिलियन डालर के ऋण और अनुदान बनाये गये इसमें से '15,810 मिलियन डालर' की राशि अमरीका के कोष से प्राप्त होनी थी। शेष राशि की कनाडा (केनेडा) तथा लैटिन अमरीका देशों से माँग थी। नवसंगठित अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अनुदानों में भी अमरीका का मुख्य भाग था। विदेश सचिव जार्ज मार्शल ने राष्ट्रपति ट्रूमैन के सहयोग के साथ कांग्रेस में अपनी योजना प्रस्तुत करते हुये वक्तव्य दिया जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि इन प्रतिनिधि राष्ट्रों को साम्यवाद तथा आर्थिक संकट से सुरक्षित रखने के लिये मार्शल योजना की आवश्यकता अपेक्षित थी। इस प्रकार मार्शल योजना को स्वीकार कर लिया गया। मार्शल योजना अपने वर्तमान युग के इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। इसे युग प्रवर्तक घटना का स्वरूप भी दिया गया है। मार्शल योजनापरान्त सोवियत संघ एवं उसके समर्थक देशों के निर्यात में भारी कमी आ गयी थी। आवश्यक कच्चे माल की यूरोप से आपूर्ति निरन्तर चल रही थी और इससे अमरीकी सहायता को थोड़ा संतुलित किया गया। इस योजना ने पश्चिमी यूरोप को साम्यवाद के भीषण आघात से बचा लिया। मार्शल योजना को अमरीका ने शीतयुद्ध में शक्तिशाली शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। रूस के उपग्रहित राज्य मार्शल योजना को लोलुपता पूर्ण दृष्टि से देखते थे। फलस्वरूप इटली तथा फ्रांस में जहाँ साम्प्रदायी संघर्ष था, सदस्यों की संख्या न्यून हो गयी। संयुक्त राज्य को पश्चिमी देशों की नेतृत्वता प्राप्त हो चुकी थी फलस्वरूप अमरीकी डालर की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में स्थिति सुदृढ़ हो गयी।

इतिहासकार स्मिथ के मतानुसार मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा पूर्व प्रचलित अवरोधक नीति के सहयोग से अमरीका के संरक्षण में पश्चिमी यूरोप की अर्थ व्यवस्था को अत्यन्त सुदृढ़ करना था। इस प्रकार अमरीका अब यूरोप की नीतियों में पूर्णतया सम्बद्ध हो चुका था। इस प्रार्थकवाद का अन्त भी कहा जा सकता है। इस योजना के द्वारा

अमरीका में स्वयं को यूरोप में हस्तक्षेप के लिये वचनबद्ध कर लिया था परन्तु वर्तमान युग में इसकी एक नितान्त आवश्यकता भी थी ।

चार सूत्री कार्यक्रम

राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल योजना के विस्तार में एक अन्य चार सूत्रीय कार्यक्रम नियोजित किया । उनके अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व जनहित था । उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में उपरोक्त योजना के मुख्य तत्वों का उल्लेख करते हुये इसको विश्व कल्याण के द्वारा जीवन के स्तर वृद्धि का परिचायक माना ।

कार्यक्रम के मुख्य सूत्र निम्नवत् थे :-

1. विश्व की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्व-व्यापी समर्थन ।
2. विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये अमरीका द्वारा पूर्ण सहायता ।
3. विकासशील एवं अर्ध विकसित देशों के उत्थान के लिये अमरीका की वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता ।
4. स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों को साम्यवाद तथा आक्रामक राष्ट्रों से बचाना तथा उन्हें सुदृढ़ करना ।

विदेशों में तकनीकी सहायता से राष्ट्रपति ट्रूमैन का उद्देश्य अमरीकी व्यक्तिगत पूंजी और व्यापार को भी विदेशों में प्रोत्साहन देना था । विदेश विभाग ने अनुमान लगाया कि इस प्रकार व्यक्तिगत पूंजी की लागत को लगभग तीन गुना बढ़ाया जा सकता है । अमरीकी व्यक्तिगत पूंजी की राशि उस समय एक अरब डालर थी ।

दक्षिण पूर्व एशिया में भी कृपक व मजदूर वर्ग की स्थिति सदैव की भाँति अत्यन्त दयनीय बनी हुई थी । इन परिस्थितियों में भी 20-25 डालर की आय वाले ये श्रमिक और कृपक समुदाय किसी के भी नेतृत्व से चैतन्य होकर साम्यवाद की ओर जा सकते थे । चार सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य इन देशों के स्तर को ऊँचा करना था । इस प्रकार ट्रूमैन का यह कार्यक्रम मानवतावाद एवं विश्व हितकारी ध्येयों से परिपूर्ण था । मई, 1952 में कांग्रेस ने पैंतीस मिलियन डालर का एक वर्षीय अनुदान तकनीकी सहायता हेतु अनुमोदित किया इसका एक तिहाई भाग 'संयुक्त राष्ट्र संघ तकनीकी सहायता समिति' के द्वारा प्रदत्त किया गया था । जून, 1952 में भूमि संरक्षण परियोजना हेतु बीस मिलियन डालर की राशि स्वीकृत की गयी । इस धनराशि को पचास

देशों में तकनीकी सहायता हेतु वितरित किया गया। अमरीकी जन समुदाय ने भी इस कार्यक्रम को सर्व मान्यता प्रदान की। सोवियत संघ एवं उसके समर्थक साम्यवादी देशों ने इसे पूंजीवादी राष्ट्रों का षड़यंत्र कहकर आरोपित किया।

जर्मनी का नियंत्रण

शीत युद्ध के इस राजनैतिक तनाव में जर्मनी की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। शक्ति परीक्षण की इस, राजनीतिक शतरंज में, जर्मनी दोनों शक्तियों के प्रति सन्देह युक्त सम्बन्ध बनाये हुये था। यद्यपि जर्मनी युद्ध के पश्चात् विध्वंस हो गया था फिर भी उसके बुद्धिजीवी उत्साही एवं अनुशासिक नागरिक अपने औद्योगिक एवं सामाजिक निर्माण की आकांक्षा रखते थे। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् भी विश्व को जर्मनी के लोगों में यही लगन और विश्वास देखने को मिला था। जर्मनी के लोगों के इस पुनस्तथान का रूस ने सदैव विरोध किया था। इसलिये रूस ने पूर्वी जर्मनी जो विश्व युद्ध के पश्चात् उसके साथ था वहाँ पर क्रान्ति युक्त कार्य एवं प्रति साम्राज्यिक भावनाओं को उत्तेजित करना आरम्भ कर दिया था। अतः जर्मनी की इन गतिविधियों से पश्चिमी जगत भयभीत हो गया था और भूतकालीन अनुभव के आधार पर किसी प्रकार के शांति समझौते के लिये तत्पर नहीं था। पश्चिमी जगत का विश्वास था कि केवल एक साम्यवादी जर्मनी सम्पूर्ण यूरोप को गम्भीर स्थिति में डाल सकता है और विश्व के अन्य देशों के प्रति भी संकट-पूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

जर्मनी के समर्पण के दो मास पश्चात् ट्रूमैन ने स्टालिन तथा चर्चिल के साथ 1945 में पोट्सडैम में जुलाई 17 से जुलाई 25 के मध्य एक सम्मेलन वार्ता की। इस सम्मेलन में जर्मनी, युद्ध पश्चात् यूरोपीय स्थिति एवं संधियों के विषय पर विचार विमर्श किया गया। पाँच महाराष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों की एक समिति बनाई गई थी जिसमें इटली, रूमानिया, बुल्गारिया, हंगरी तथा फिनलैण्ड के साथ संधियों हेतु आलेख्य बनाने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व सितम्बर, 1944 में वयूवेक सम्मेलन में चर्चिल तथा रुजवेल्ट ने यह निश्चय किया था कि जर्मनी को एक भूसम्पदा युक्त राष्ट्र बनाया जाय जिससे कि उसके भारी उद्योगों में कटौती कर युद्ध सामग्री निर्माण पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय। यह योजना सचिव मर्गिन्थो ने प्रेषित की थी। पोट्सडैम सम्मेलन में मर्गिन्थो की योजना को अस्वीकृत कर दिया गया, परन्तु जर्मनी के उद्योगों के नियंत्रण हेतु बहुराष्ट्रों का मुख्यतः 'मित्र राष्ट्र नियंत्रण आयोग' का गठन किया

गया। यह निर्णय लिया गया कि कृषि तथा घरेलू उद्योगों को ही विशेष बढ़ावा दिया जाय, आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीयकरण को निरस्त करने का प्रयोजन किया गया। क्योंकि बड़े उद्योगपतियों ने नाजियों के आक्रमणशील कार्यों को प्रोत्साहन दिया था। पोट्सडैम सम्मेलन में यह विचार भी व्यक्त किया गया कि जर्मनी को केवल एक आर्थिक इकाई के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिये, इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो सकी क्योंकि रूस पाश्चात्य देशों के प्रति सन्देहात्मक दृष्टि रखता था।

इससे पूर्व याल्टा सम्मेलन में इस समस्या पर निर्णय लिया जा चुका था कि पोलैंड को जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्र से प्रतिकारित करना था। इसका कारण यह था कि रूस ने पोलैंड के पूर्वी क्षेत्र को हस्तगत कर लिया था। रूस ने पुनः यह माँग रखी कि नाजी आक्रमण से रूस को एक गम्भीर क्षति उठानी पड़ी थी अतः जर्मनी उस क्षति की पूर्ति के रूप में दस मिलियन डालर की राशि का भुगतान करे। याल्टा सम्मेलन में तो रूजवेल्ट इस विषय पर विचार करने को तैयार थे, परन्तु प्रथम युद्ध की भाँति पश्चिमी देश क्षतिपूर्ति अनुदानों को स्वीकार करने को तैयार न थे। उनका विचार था कि जर्मनी को इतनी सहायता अवश्य प्रदान की जाय कि बिना वाह्य सहायता के जर्मनी आत्मनिर्भर हो सके। पोट्सडैम सम्मेलन में तीन महाराष्ट्रों ने इस तथ्य के अंगीकरण करने की योजना का निर्माण किया था कि भविष्य में जर्मनी के नाजीवाद (नात्सीवाद) एवं सैन्यवाद को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। इस हेतु इन राष्ट्रों ने स्वयं में वचन बद्ध होना चाहा कि जर्मनी की शांति भंग नीति को अवरोधित करने में राष्ट्रों को एक दूसरे से सदैव परस्पर संधि युक्त रहना चाहिये। मित्र राष्ट्रों का जर्मनी को समाप्त करने अथवा जर्मनवासियों को परतंत्रता प्रदान करने का कोई विचार नहीं था। उनके विचार में जर्मन समाज को वह सभी सुविधायें प्रदान की जाएँ जिनसे उनका पुनरुत्थान हो सके, एवं वे शांतिमय व जनतांत्रिक वातावरण युक्त नया जीवन प्रारम्भ कर सकें।

नाजी (नात्सी) सेनाओं द्वारा हस्तगत समस्त भूमि क्षेत्रों को जर्मनी से पृथक कर दिया गया। पूर्वी प्रशा के भाग को रूस में तथा अन्य महत्वपूर्ण जर्मन क्षेत्र वहाँ की 'ब्रेड वास्केट' को पोलैंड में मिला दिया गया। इसके पश्चात अन्य क्षेत्रों में प्रवासी जर्मनवासियों को जर्मनी की नियंत्रित सीमाओं में जाने को कहा गया। चार बड़ी मित्र राष्ट्रीय शक्तियों ने सम्पूर्ण जर्मनी क्षेत्र को विभाजित कर अपने में वितरित कर लिया। विभाजन के फलस्वरूप जर्मनी का दक्षिणी पश्चिमी भाग अमरीका के जनरल जोजफ मेकनारने के आधीन कर

दिया गया। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ब्रिटेन के आधीन आ गया। कृषि प्रधान पूर्वी अंश रूस के अधिकार क्षेत्र में आ गया। फ्रांस जिसकी पोद्सडैम सम्मेलन में उपेक्षा की गयी थी, उसको राईन नदी के तट पर सारवेसन को नियंत्रण करने में ही संतोष करना पड़ा। बर्लिन को शासित करने में चारों राष्ट्रों को समान भूमिका प्रदत्त की गयी। इस प्रकार जर्मनी के क्षेत्रीय विभाजन से आंग्ल-अमरीकी योजनाओं को, आर्थिक सहकारिता की इच्छुक थी, आघात पहुँचा। इसका कारण रूस की स्वेच्छाचारी नीति थी। 1946 में अंग्रेजों तथा अमरीकियों ने आर्थिक सहकारिता हेतु अपने क्षेत्रों का संयोजन किया। इस कार्य में भी रूस और फ्रांस ने साथ नहीं दिया।

मित्र राष्ट्रों का एक अन्य मतभेद स्टील उत्पादन के कारण उत्पन्न हुआ। एक ओर रूस और फ्रांस जर्मनी औद्योगीकरण के निम्न स्तर पर ले आना चाहते थे और दूसरी ओर अमरीका और ब्रिटेन को रूसी साम्यवाद के प्रसार का भय था। अतः वे जर्मनी की आर्थिक शक्ति का ह्रास नहीं करना चाहते थे उन्होंने जर्मनी के स्टील उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। सितम्बर, 1946 में सचिव वर्न्स ने जर्मनी में एक अस्थायी सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। जर्मनी की जनता में स्वयं अपने पुराने नेताओं के प्रति एक घृणा सी बन गई थी। इसी-लिये सनसनीखेज न्यूरनबर्ग के अभियोगों पर जनता ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित की। इन कार्यों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हुये भी अब नाजी-वाद को समाप्त करने की एक लहर सी फैल गयी थी।

अप्रैल, 1947 में विदेश सचिवों के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। अमरीका के नये विदेश सचिव मार्शल ने यह घोषणा की कि उनका देश, ब्रिटेन तथा फ्रांस, के सहयोग से संघीय प्रणाली पर आधारित जर्मनी के प्रशासन की स्थापना करने का इच्छुक है। इससे संघीय राज्यों में सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना हो सकेगी। तथा संविधान द्वारा सभी मुख्य अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार शक्ति का केन्द्रीयकरण भी नहीं हो सकेगा और तानाशाही संस्थायें केन्द्रित नहीं हो सकेगी। इसके विपरीत रूस ने केन्द्रित सरकार का विचार दिया। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के इस विचार को संदेहात्मक मानकर उसका खंडन किया। केन्द्रित सरकार किसी भी समय साम्यवाद का समर्थन कर सकती थी। सोवियत संघ के भय के निवारणार्थ विदेश सचिव जार्ज मार्शन ने एक योजना प्रेषित की जिसमें जर्मनी को चालीस वर्षों के लिये गैर अर्सेनिक क्षेत्र घोषित करने का विचार किया गया। सोवियत संघ के प्रधान मंत्री स्टालिन ने इस योजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार भी किया, परन्तु विदेश सचिव मोलोटोव ने कोई सह-मति प्रदान नहीं की। वह किसी भी रूप में अमरीकी सेना को यूरोप में रखने

के पक्ष में नहीं थे ।

अतः आगामी वर्षों में पूर्वी जर्मनी पूर्णतया एक 'रूसी उपग्रह' राज्य बन गया था, एवं पश्चिमी जर्मनी में जनतंत्र प्रणाली आ गयी थी । इन दोनों विभाजित जर्मन राज्यों में कोई व्यापारिक सम्बन्ध न स्थापित हो सके । बर्लिन में प्रायः लघु सम्बन्धों के रूप में पारस्परिक विरोध का प्रदर्शन होता रहा । साम्यवाद में विश्वास न रखने वाले पूर्वी जर्मनी के प्रवासी पश्चिमी भाग में शरणार्थी के रूप में प्रविष्ट हुये । जर्मनी से सम्बद्ध, शीत युद्ध काल, की सबसे गम्भीर और संकटमय घटना 1948-49 में बर्लिन की नाकेबंदी थी । इस घटना से तीसरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने का भी आतंक व्याप्त हो गया था । सोवियत संघ और अमरीका के पारस्परिक सम्बन्धों में निरन्तर कटुता विद्यमान थी । पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी में मुद्रा सुधार का कार्य प्रारम्भ किया । इन सुधारों को बर्लिन में भी लागू किया गया । इन समस्त घटनाओं को सोवियत संघ ने अपने अहित के पक्ष में देखकर जून 24 को पश्चिमी बर्लिन व पश्चिमी जर्मनी के मध्य मार्ग (काँरीडॉर) को चारों ओर से अवरुद्ध कर लिया । इस गतिविधि से मित्र राष्ट्रों के अधीनस्थ बर्लिन क्षेत्र में प्रवास कर रहे लगभग 20 लाख लोगों को खाद्य एवं पेय आदि की सामग्री दुर्लभ हो गयी । सोवियत संघ का विश्वास था कि जनता में इस प्रकार यूरोपीय देशों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जायेगी । परन्तु आशा के विपरीत अमरीका ने उनकी गतिविधियों को विफल कर दिया । नव सृजित कॉरगो वायुयानों का भली-भाँति प्रयोग किया गया । इस प्रकार मित्र राष्ट्रों ने समस्त सामग्री को बर्लिन वासियों तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की । इस सफलता से मित्र राष्ट्रों को बर्लिन में अत्यन्त सम्मान प्राप्त हुआ । अमरीका व ब्रिटेन ने इस नाकेबन्दी की भत्संता की, और इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उलंघन की संज्ञा दी । नाकेबन्दी के विरोध में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों से सभी औद्योगिक व व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त कर दिये । पूर्वी यूरोप व रूस के उद्योग जर्मनी से आयात किये हुये कच्चे माल की आपूर्ति पर आधारित थे । फलतः अप्रैल, 1949 में रूस ने अत्यन्त दबाव में आकर नाकेबन्दी हटा ली ।

23 मई, 1949 को चारों अधिकृत देशों के विदेश सचिवों का पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जर्मनी तथा आस्ट्रिया के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय विदेश नीति को निर्धारित करने हेतु विचार प्रस्तुत किये गये जर्मनी के प्रशासन के निश्चय के प्रति अभी भी विवाद थे । पश्चिमी देश इच्छुक थे कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराये जायें तथा मौलिक अधिकारों को जनता में बनाये रखा जाये । इसके विपरीत रूस पूर्वी जर्मनी के सदृश्य प्रशासन का इच्छुक था ।

रूस ने 'हर क्षेत्र' के मुख्य औद्योगिक प्रशासन को अपने अधिकार में लेने की इच्छा, व्यक्त की, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। इसी वर्ष जर्मन संघीय गणराज्य (पश्चिमी) तथा 'जर्मन प्रजातंत्र गणराज्य' (पूर्वी), दो राष्ट्रों की स्थापना की गयी। तत्पश्चात्, एक समझौते द्वारा, पश्चिमी जर्मनी को पूर्ण सर्वाधिकार दे दिया गया। इनके साथ ही 3-4 लाख की सैन्य शक्ति की स्थापना भी रूस के प्रभाव को रोकने हेतु की गयी। अमरीका ने पश्चिमी जर्मनी के विकास का मुख्य पथ प्रदर्शन किया। उसने जर्मन सेना को प्रोत्साहन दिया एवं उत्तरी अटलांटिक संधि संघ (नाटो) के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा नीति में जर्मनी को भी सम्मिलित किया। 4 अप्रैल, 1949 को सामूहिक सुरक्षा हेतु वाशिंगटन में एक संधि हुई जिसमें 12 राज्य सम्मिलित थे। इसे उत्तरी एटलांटिक सन्धि संगठन का नाम दिया गया। यह शीत युद्ध काल में रूस के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन था। 1954 तक पश्चिमी जर्मनी को एक वायुसेना की स्थापना के भी अधिकार प्रदान किये गये। पश्चिमी जर्मनी ने सदैव मित्र राष्ट्रों को सहयोग प्रदान किया इसका मुख्य कारण पश्चिमी जर्मनी की जनता का साम्यवाद के विरुद्ध होना था।

शीतयुद्ध काल में जर्मनी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी स्थिति का अवलोकन करते हुये अमरीका ने सोवियत संघ के प्रभाव से बचाने के लिये पुनरुत्थान हेतु विजय दिवस से 30 जून, 1952 तक 3630 मिलियन डालर की राशि अनुदान की थी। सम्बन्धों में सुदृढ़ता के पश्चात् विदेश सचिव एचिसन ने सांस्कृतिक विनियम को प्रोत्साहन प्रदान किया। फोर्ड संस्था ने 1.3 मिलियन डॉलर की धनराशि देकर 'पश्चिमी बर्लिन, फ्री विश्वविद्यालय को स्थापित करने में सहयोग दिया।

पूर्वी यूरोप

साम्यवाद के प्रसार के अवरोध के लिये चर्चिल ने पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के मध्य 'लोह पट' खींचने की संज्ञा दी। 1945 से 1948 के बीच रूसी अधिपत्य पूर्वी यूरोप में व्याप्त हो गया। यूरोप में साम्यवाद के आगमन पर अमरीका ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया। हंगरी का प्रधान मंत्री फेरेंक नेगी भी रूसियों को सहयोग प्रदान कर रहा था। बुल्गारिया में असाम्यवादी नेताओं का दमन किया जा रहा था। दिसम्बर, 1947 में रमानिया के साम्यवादियों ने वहाँ के राजा मडकिल को हटाकर सत्ता हस्तगत कर ली। साम्यवाद का प्रसार सर्वत्र हो रहा था। यूगोस्लाविया के

मार्शल टीटो ने भी आरम्भ से साम्यवादियों के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित की परन्तु 1948 में उन्होंने अपने देश की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुये अपने देश को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से पृथक कर दिया। टीटो ने पश्चिमी देशों से सम्बन्ध सुदृढ़ करने की चेष्टा की। इसके फलस्वरूप यूगोस्लाविया तथा अमरीका के बीच एक आर्थिक समझौता किया गया और ब्रिटेन फ्रांस को सम्मिलित कर अमरीका ने 99 मिलियन डॉलर की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की।

इस प्रकार पश्चिमी देशों की यह एक महत्वपूर्ण विजय थी। इससे रूस तथा यूरोप एवं रूस तथा टर्की और यूनान के मध्य एक व्यवधान उत्पन्न हो गया। इसी मध्य इटली तीस्ते क्षेत्र के कारण यूगोस्लाविया से युद्धरत था। मित्र राष्ट्रों ने इन दोनों देशों में एक संधि समझौता करा दिया क्योंकि इटली का वृहद् भाग उससे हस्तगत कर लिया गया था। इसलिये 1950 में राष्ट्रसंघ ने उसे 10 वर्ष के लिये सोभालिया का प्रशासन सौंप दिया। तदुपरान्त नाटो की सदस्यता के कारण इटली ने अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर लिया। यूगोस्लोवाकिया भी पूर्व और पश्चिम विचार धाराओं के मध्य 'उदासीन सेतु' का स्वरूप लिये हुये था। उसकी संसद में साम्यवादी सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था, जिस कारण राष्ट्र को सोवियत गठबंधन की ओर आश्रित होना पड़ा। 1948 में साम्यवादियों ने सत्ता को स्वयं के अधीन कर सम्पूर्ण पश्चिमी जगत को फिर से भयभीत कर दिया। भूतपूर्व राष्ट्रपति के सुपुत्र मसारिक ने आत्महत्या कर ली। फलस्वरूप वहाँ जनतंत्र की आशा के अन्तिम चिन्ह भी समाप्त हो गये। इन नवीन संकटों की उपज के कारण अब अमरीका को अन्य कदम उठाने के लिये बाध्य होना पड़ा।

यूनान और ट्रूमैन का सिद्धान्त

यूनान के गृह युद्ध से पश्चिमी देश अत्यन्त क्षुब्ध हो चुके थे। इस गृह युद्ध से सम्पूर्ण भूमध्य क्षेत्र की साम्यवाद की ओर अग्रसर होने की आशंका बनी हुई थी चर्चिल इंग्लैण्ड की पराजित परिस्थितियों से भलीभाँति भिन्न था इस कारण उसने अपने 5 मार्च, 1946 के वक्तव्य में अमरीका से सम्पूर्ण सहायता का आग्रह किया। राष्ट्रपति ट्रूमैन के पास भी सोवियत साम्यवाद के अवरोध हेतु अब यूरोपीय सहायता में वृद्धि के अतिरिक्त कोई विकल्प न था। 12 मार्च 1947 को राष्ट्रपति ने कांग्रेस के सम्मुख चार सौ मिलियन डालर का विधेयक यूनान और टर्की को अनुदान प्रदान करने के लक्ष्य से रखा इसमें

से सौ मिलियन डालर की धनराशि टर्की की सेना शक्ति को बढ़ाने के लिये अपेक्षित थी। ट्रूमैन का यह सिद्धान्त था कि विश्वजन समुदाय का विकास स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा ही होना चाहिये। इस सिद्धान्त की समस्त स्थानों पर सराहना की गई। सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की निरन्तर अवहेलना का अमरीका सदैव विरोध करता रहा। ट्रूमैन सिद्धान्त काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1949 की उत्तरी एटलांटिक संधि थी। इस संधि पर हस्ताक्षरों के द्वारा अमरीका के पश्चिमी यूरोप के देशों से विशेष सैनिक सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। 1953 तक अंतर्रीय एटलांटिक संधि संगठन केवल सामुहिक सुरक्षा ही नहीं बरन् सामुहिक रूप से विकास का भी अंग बन गया था, 1947 की मार्शल योजना का भी इस गठबंधन को सुदृढ़ बनाने में विशेष योगदान है। इस योजना के द्वारा सम्पूर्ण पश्चिमी जगत एक बड़ी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित हो गया। चार सूत्री कार्यक्रम ने ट्रूमैन सिद्धान्त को विश्व व्यापी बनाने में विशेष सहायता प्रदान की। इन समस्त योजनाओं को कार्य शील करने की नितान्त आवश्यकता को व्यक्त करते हुये विदेश सचिव एचिसन ने कहा कि सोवियत संघ साम्यवाद एवं साम्राज्यवाद के भेष में नवीन साम्राज्य की स्थापना कर रहा है।

यूनान में नाजी (नात्सी) तथा इटली के सैनिकों ने अत्यन्त अत्याचार किये थे। जनतांत्रिक लोग नवीन गणराज्य की स्थापना से भयभीत थे किन्तु जनमत में इसी को प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि साम्यवाद को रोकने का अन्य कोई विकल्प नहीं था। यूनान और टर्की ने पश्चिमी जगत के महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच में अपना स्थान बना लिया था उसके बाद उन्होंने कोरिया युद्ध में अपनी सेनायें भी भेजी। अमरीका द्वारा यूनानी हस्तक्षेप की सोवियत गठबंधन ने तीव्र आलोचना की। ट्रूमैन सिद्धान्त की विश्वव्यापी कार्यकारी योजनाओं के होते हुये भी संयुक्त राष्ट्र संघ में रूसी निपेधाधिकार के कारण उसे कभी भी मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी। वाणिज्य सचिव हेनरी ने 12 सितम्बर, 1946 के अपने वक्तव्य में ट्रूमैन सिद्धान्त के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। उसका कथन था कि अनावश्यक हस्तक्षेपों से दोनों समुदायों में कटुता और भी अधिक तीव्र होगी जिससे पुनः युद्ध का वातावरण उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। वाणिज्य सचिव के विचारों पर बिना कोई ध्यान दिये हुये उसे 'प्रशासन का विरोधी कहकर पदच्युत कर दिया गया। परन्तु 1950 में वास्तव में कोरिया में युद्ध जारी हो गया। 1947 में अमरीका अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस सेना में भी एक मुख्य हिस्सेदार के रूप में सम्मिलित हो गया।

फिलीस्तीन प्रश्न और मध्य एशिया

शीत युद्धकाल की एक अन्य जटिल समस्या फिलीस्तीन का प्रश्न एवं मध्य एशिया की स्थिति थी। फिलिस्तीन यहूदियों की धर्मभूमि कहलाती है। यह लोग धन, एवं संस्कृति की दृष्टि से अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक उन्नतशील थे। इस कारण अधिवेश (मेनडेट) पद्धति से अलग हटकर अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात फिलिस्तीन को ब्रिटेन के संरक्षण में स्थापित किया गया था। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को अत्यन्त विकसित कर दिया। धन के साथ-साथ 1917 की बालफुर घोषणा के द्वारा लाखों यहूदियों को वहाँ पर बसने की इजाजत दे दी गयी। फिलिस्तीन में अरब लोगों की संख्या अधिक थी। अंग्रेजों द्वारा यहूदियों की संख्या बढ़ाना एवं फिलिस्तीन को यहूदियों की धर्म भूमि घोषित करना मित्र राष्ट्रों द्वारा दिये गये आश्वासनके विपरीत था। साथ ही फिलिस्तीन की शासन पद्धति लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत थी। अंग्रेजों ने यह वचन दिया कि अरब के लोगों के धार्मिक और मौलिक अधिकार बने रहेंगे परन्तु आपसी कटुता के कारण वहाँ पर संघर्षमय वातावरण बन गया। ब्रिटेन की स्थिति भी 1918 के बाद ऐसी ही हो गयी थी, कि यहूदी गृह भूमि के सभी कार्य सम्पन्न न हो सके। अब ब्रिटेन अरब के हितों के कारण यहूदियों का देशान्तर प्रवास भी रोक रहा था। फलस्वरूप हिटलर काल में हजारों यहूदियों को निर्दयता और मौत का सामना करना पड़ा।

अमरीका ने इस देशान्तर प्रवास में निदेश लगाने का निरन्तर विरोध किया। 1947 में ब्रिटिश विदेश मंत्री बेविन ने यह घोषणा की कि उनके देश के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से इस समस्या के निदान का आग्रह किया। वास्तव में अमरीका भी अरब के द्वारा प्राप्त हितों की बात भली भाँति समझता था, जिसके कारण अरब देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना विशेष रूप से अनिवार्य था। हिटलर नाजीवाद काल में यहूदियों पर अत्यधिक अत्याचार हुये। फलस्वरूप अमरीका के पचास लाख यहूदी अल्प संख्यक समुदाय ने विद्रोह कर दिया और 'यहूदी भूमि' को मान्यता देने के लिये एक आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। सुरक्षा सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि एक लाख देशान्तरवासी यहूदियों को फिलिस्तीन में लाने पर अरब युद्ध आरम्भ हो जायेगा क्योंकि यहूदी अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पायेंगे। अतः अमरीका को युद्ध में प्रवेश करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन विभाजन योजना का गठन करना चाहा परन्तु अरब लीग ने इसका विरोध किया। इसी मध्य

यहूदी राज्य राष्ट्रीय परिषद ने यहूदी राज्य (इसराएल) की घोषणा कर दी और 14 मई, 1948 को नवीन राज्य स्थापित हो गया जिसको राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मान्यता दे दी। फलतः आंग्ल-अमरीकी शस्त्रविरोध के कारण अरब देशों ने सम्मिलित रूप से इसराएल पर आक्रमण कर उसे हतप्रभ करना चाहा। इसराएल ने इस आक्रमण का इतना शक्तिशाली प्रत्युत्तर दिया कि अरब देशों को युद्ध विराम का आश्रय लेना पड़ा। तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता ने 1949 में पूर्ण विराम कराया। अरब राज्यों ने इस पर भी 'इसराएल अवरोध' को समाप्त नहीं किया और न ही निर्णायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये तैयार हुये। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसराएल के साथ राजदूतिक सम्बन्ध स्थापित कर इसराएल अरब मतभेद को समाप्त करने की चेष्टा की। अमरीका ने इसराएल को आर्थिक सहायता के रूप में अपार धनराशि का ऋण दिया जिससे इसराएल की कृषि, उद्योग, संचारण एवं विद्युत शक्ति के विकास में वृद्धि हुई। इस के विकास में अमरीकी प्रशासन एवं अमरीकी पूंजी निवेशक भी अत्यन्त रुचि रखते थे।

दूसरी ओर अरब क्षेत्र के शताब्दियों से अप्रगतिशील होने के कारण वहाँ युवा पीढ़ी को पश्चिमी देशों के विकास का ज्ञान होने लगा था। इस नवोदित युवा शिक्षित वर्ग के लिये साम्यवाद एक उर्वर क्षेत्र था। इस स्थिति के अवरोध हेतु अमरीका ने अरब क्षेत्र को भी सैन्य एवं तकनीकी विकास हेतु ऋण एवं कार्य नियोजित किये।

जापान

युद्धोपरान्त जापान पर भिन्न राष्ट्र सेना के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष जनरल मैकार्थर का जापान पर पूर्ण रूपेण शासन था। उसने जापान को लोकतन्त्री मार्ग पर लाने हेतु कठोर कार्यवाही आरम्भ की। इस 'अमरीकन सिविल' के कार्यों ने जापान में ब्लैक ड्रेगन जैसी विद्रोहात्मक देश-प्रेमी संस्थाओं को समाप्त कर दिया। जापान के सम्राट हीरोहीतो ने भी मैकार्थर की 'शिंटोवाद' के विस्थापन की नीति को समर्थन दिया। इस नीति के अनुसार जापानवासी स्वयं को अन्य जातियों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ समझते थे और विश्व में राज्य करना उनके भाग्य में निर्धारित था। मैकार्थर ने इस मनोवृत्ति का खंडन कर जापान में 1947 के संविधान निर्माण में सहयोग दिया। इस संविधान के अन्तर्गत जनता को लोकतांत्रिक सुविधाओं एवं कार्यों की ओर सम्बोधित किया गया। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया गया। भु-स्वामी प्रथा को समाप्त कर 20 लाख छोटे

कृषकों को भू-स्वामी बनाया गया, भूमिहीनों को प्रति भूमि वितरण का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। नियति में जापान अत्यन्त हानि उठा चुका था और चीन के साम्यवाद से उसके व्यापार पर आर्थिक प्रहार हुआ। अपनी वित्तीय दशा को सुधारने के लिये जापान को अमरीका का आश्रय लेना पड़ा।

रूस के साम्यवादी राजनैतिक प्रसार के कारण अमरीकी राजनीतिज्ञों जिसमें डीन एचिसन एवं जॉन फॉस्टर डलिस प्रमुख थे, जापान को अपना संधि-बद्ध राष्ट्र माना। इससे पूर्व यह धारणा थी कि जापान का पुनरुत्थान लोकतन्त्र के लिये संकट बन जायेगा। 1949 में रूस तथा अन्य देशों को क्षतिपूर्ति भी समाप्त कर दी गयी क्योंकि इस प्रति पूर्ति के द्वारा जापान में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो रही थी। इसके अतिरिक्त जापान का विदेश में तीन अरब (मिलियन) डॉलर की परि सम्पत्ति का अधिहरण हो चुका था। जापान की 28 अप्रैल, 1952 की शान्ति संधि के द्वारा जापान को अपनी जनता की खाद्य एवं अन्य पूर्ति समस्याओं के निवारण हेतु अमरीकी कर-दाताओं ने एक अरब से ऊपर की धनराशि व्यय की थी।

अमरीका ने उपरोक्त संधि के अतिरिक्त एक अन्य संधि के द्वारा जापान में अमरीकी सैन्य व्यवस्था को, स्थित रखने का प्रयोजन किया। इस अमरीकी कार्य को जापानी जनता ने 'साम्राज्यवादी नीति' के रूप में नहीं लिया क्योंकि जनमत मतगणना ने भी अमरीकी सैन्य अड्डों का समर्थन किया। 1950 में जापान स्थित इन अमरीकी आस्थानों ने ही कोरिया के साम्यवादी प्रसार को रोकने में सहायता प्रदान की।

फिलिपीन (फिलेपीन्स) एवं प्रशांत सुरक्षा व्यवस्था :

फिलिपीन द्वीप समूह जो 1901 में अमरीकी प्रशासन के आधीन था, 4 जुलाई, 1945 को स्वतंत्र कर दिया गया। इस प्रकार अमरीका ने राष्ट्रपति विल्सन के वचन को सम्मानपूर्वकपूर्ण किया। फिलिपीन (फिलेपीन्स) के अमरीकी शासन के आधीन होने से अमरीका को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इसके विपरीत अमरीकी प्रशासन की 'फिलिपीनीकरण की योजना के कारण एक विपुल धनराशि वहाँ पर व्यय की। अमरीका ने फिलिपीन में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तकनीकी विकास में पूर्ण योगदान दिया। अमरीका ने इस क्षेत्र की कृषि सम्बन्धी समस्याओं को स्वदेशी शासकों पर निर्भर किया हुआ था। द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण फिलिपीन में लगभग 800 मिलियन डॉलर की सम्पत्ति विध्वंस हो गई थी और आधा मनीला विनष्ट हो चुका था।

फिलिपीन की अर्थ व्यवस्था मौलिक रूप से उपनिवेशिक थी क्योंकि इसके मुख्य व्यापारिक पदार्थ चीनी, नारियल, तम्बाकू इत्यादि अमरीका को निर्यात होते थे। 1946 के (फिलेपीन्स) 'फिलिपीन व्यापारिक अधिनियम' ने 1954 तक मुक्त व्यापार स्थापित किया। फलतः प्रति वर्ष मूल्य में वृद्धि होती गई। इस अधिनियम के एक प्राविधान के अनुसार अमरीकनों को फिलिपीन के प्राकृतिक साधनों में समान अधिकार थे, इस प्राविधान ने फिलिपीनी राष्ट्रवादियों में आक्रोश की भावना उत्पन्न कर दी। इस अधिनियम को मान्यता देने के उपलक्ष्य में अमरीकी कांग्रेस ने फिलिपीन पुनः स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत 600 मिलियन डॉलर से ऊपर सहायता देने का वचन दिया। राष्ट्रवादियों की आलोचना के उपरान्त भी फिलिपीन सदन ने 'वैल्ल अधिनियम' को पारित किया।

द्वितीय विश्व-युद्ध ने फिलिपीन में निर्धनता के प्रकोप में वृद्धि कर साम्यवादी प्रचार को अवसर प्रदत्त किया। इन विद्रोहियों ने 'फिलिपीन जन-स्वाधीनता सेना' का संगठन किया और प्रशासन को उलट देने की चेष्टा की। 1950 में अमरीकी विशेषज्ञों के दल के अध्यक्ष डेनियल वैल्ल (वैल्ल अधिनियम के रचयिता नहीं) ने फिलिपीनी स्थिति का पूर्ण दोषारोपण वहाँ के प्रशासन को दिया। इसके अतिरिक्त वैल्ल ने फिलिपीन को 250 मिलियन डॉलर प्रदान करने की अनुशंसा की।

इसी मध्य फिलिपीन द्वीप समूह को 'प्रशांत सुरक्षा व्यवस्था' के द्वारा संगठित किया गया। इसके अन्तर्गत अमरीका को फिलिपीन में सैन्य अस्थान योजित करने की अनुमति दी गई एवं अमरीका तथा फिलिपीन के मध्य अगस्त, 1951 में पारस्परिक सुरक्षा समझौता भी पारित हुआ। इसी समय अमरीका हिन्द चीन में भी युद्ध सामग्री भेजने लगा।

चीन में साम्यवाद

दिसम्बर, 1950 में कोरिया युद्ध में साम्यवादी चीन (लाल) ने हस्तक्षेप की नीति प्रारम्भ कर दी। इन घटनाओं से अमरीका स्तम्भित हो गया। प्रथम विश्व युद्ध से 1949 तक चीन आर्थिक संकट की स्थिति में था। चियांग की सेना की सहायता के लिये अमरीका ने अरबों डॉलर खर्च किये थे। इसके अतिरिक्त अमरीका सदैव 'उन्मुक्त द्वारा नीति' का समर्थक रहा था। युद्धोपपूर्व संघर्षों में भी दोनों पक्षों ने चीन में अनेकों प्रकार के सामाजिक व आर्थिक सुधार किये। परन्तु लाल साम्यवादी नेता प्रत्येक सुधार को मार्क्सवादी विचार-धाराओं के अन्तर्गत प्रवाहित करना चाहते थे। दिसम्बर, 1945 में जार्ज

मार्शल विशेष राजदूत के रूप में चीन आये और गृहयुद्ध का अन्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने युद्ध विराम को कार्यान्वित कराया, परन्तु इस अल्पकाल समझौते से विशेष लाभ नहीं हुआ। युद्ध पुनः तीव्र गति से आरम्भ हो गया। अमरीका की युद्ध सामग्री पूर्ववत् राष्ट्रवादी चीन को प्राप्त होती रही। परन्तु चियांग की सेना की आयोग्यता के कारण युद्ध सामग्री साम्यवादियों ने हस्तगत कर ली। तत्पश्चात् लाल साम्यवादी चीन ने चियांग की सेनाओं को नष्ट कर अमरीकी नागरिकों को उत्पीड़ित करना आरम्भ कर दिया। 15 फरवरी, 1950 को रूस के विदेश मन्त्री यानुआर्यविच विशिस्की और चीन के माओतसे तुंग (माओद्जे डुंग) के मध्य एक तीस वर्षीय संधि हुई जिसमें मैत्री युक्त गठबंधन एवं सहायता का वचन दिया गया। यह संधि अमरीका के लिये एक शताब्दी से अधिक 'चीन अमरीकी' सम्बन्धों की पराजय थी। शीतयुद्ध काल के प्रारम्भिक चरण में यह साम्यवाद की एक महान विजय थी।

कोरिया

जापान ने 1910 में कोरिया का सम्मेलन कर लिया था और कोरिया काहिरा(कायरो)सम्मेलन के उपरान्त भी स्वतंत्रता ग्रहण करने में असफल रहा था। युद्धोपरान्त सैन्य निरस्त्रीकरण करने हेतु रूस और अमरीका ने कोरिया को दो भागों में विभाजित कर दिया था। दक्षिण कोरिया अमरीका के आधीन तथा उत्तरी भाग रूस के आधीन कर दिया गया। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीक्षण में चुनाव कराकर दोनों देशों के एकीकरण के लिये भी प्रयास किया परन्तु रूस ने इसे अमान्यता प्रदान कर उत्तरी कोरिया में एक साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी। राष्ट्र संघ ने नवम्बर, 1947 में एक आयोग द्वारा दक्षिणी कोरिया में चुनाव कराये। उत्तरी कोरिया में अत्यधिक आर्थिक परिवर्तन किये गये परन्तु अमरीका ने दक्षिणी कोरिया में विशेष हस्तक्षेप नहीं किया वरन् विपुल धनराशि को राहत योजनाओं में देकर जनजीवन के स्तर में उन्नति कर दी। अमरीका ने दक्षिण कोरिया की सैन्य शक्ति की ओर भी कोई विशेष ध्यान न देकर केवल साधारण ध्यान दिया। फलस्वरूप 25 जून, 1950 को साम्यवादी कोरिया ने एक अचानक आक्रमण कर लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रहार किया। परिस्थितियों के अनुसार अमरीका भी इस युद्ध में सम्मिलित होगया। जापान जो कि अशक्त था, उसे भी आक्रमण का भय हो सकता था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी भी भयभीत हो गया कि इसी प्रकार आक्रमण पूर्वी जर्मनी का भी हो सकता है। यह ट्रूमैन सिद्धान्त व अवरोध नीति

की सीधी परीक्षा थी ।

सुरक्षा परिपद ने इस आक्रमण की बहुत निन्दा की और समस्त राज्यों से दक्षिणी कोरिया की रक्षा के लिये कहा । 27 जून, को सुरक्षा परिपद की आज्ञा पर जनरल मैकार्थर के नेतृत्व में एक संयुक्त राष्ट्र सेना दक्षिण कोरिया के सहायतार्थ भेजी गयी । कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड व टर्की तथा यूनान ने भी अपनी-अपनी सेनायें भेजीं । कुछ ही दिनों के पश्चात् मैकार्थर की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया के लोगों को भगा दिया । मैकार्थर का विश्वास था कि "सम्यवादी चीन" इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा लेकिन नवम्बर में चीनी सेनाओं ने अचानक संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया । एक प्रकार से यह तीसरे विश्व युद्ध का आमंत्रण था । शनैः-शनैः मैकार्थर तथा दक्षिणी कोरिया की सेनाओं ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया । राष्ट्र संघ ने चीन को आक्रमणकारी कहकर भत्सना की परन्तु कोई विशेष परिवर्तन न हुआ । अमरीकी कांग्रेस ने मनचूरिया के क्षेत्रों पर वायुयान आक्रमण करने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह और सभी पश्चिमी देश तीसरे विश्व युद्ध से बचना चाहते थे । इस प्रकार यह एक सीमित संघर्ष था ।

नवम्बर 28, 1950 को जनरल मैकार्थर ने यह घोषित किया कि कोरिया में अमरीका एक नवीन युद्ध का सामना कर रहा था । मैकार्थर ने अमरीकी गणतन्त्रीय अल्पसंख्यक नेता जोजफ मार्टिन को एक खुले पत्र में लिखा कि अमरीका को आर्थिक आक्रामक नीति अपनानी चाहिये और 'च्यांग-काई-शेक' को और अधिक सहायता प्रदत्त करनी चाहिये । इससे पूर्व राष्ट्रपति पद प्रत्याशी सीनेट सदस्य टाफ्ट ने भी इसी प्रकार की नीति की मांग की थी । राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मैकार्थर की प्रशासकीय आलोचना को अनुचित बताया और इस विश्वविख्यात सेनाध्यक्ष को पदच्युत कर दिया । मैकार्थर ट्रूमैन विवाद के अन्तर्गत राज्य प्रशासन एवं सेना के नियंत्रण का सिद्धांत था ।

1951-53 के मध्य संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने उत्तरी कोरिया के सैनिक संस्थानों पर पुनः वायुसेना एवं नौसेना द्वारा गोलाबारी की । जिससे भविष्य में किसी भारी आक्रमण का संकट न रहे । जुलाई 1951 में युद्ध विराम की घोषणा हुई क्योंकि माओ ने जो अपेक्षा की थी वह पूर्ण न हो सकी । यह विराम संधि वार्ता अनेक प्रश्नों को लेकर, जिनमें युद्धवन्दियों की समस्या मुख्य थी, समाप्त हो गई । जून, 1952 में संयुक्त राष्ट्र सेनाओं ने यालू नदी विद्युत संयंत्र ग्रहों पर गोलाबारी की । इधर यह भी आरोप लगाये गये कि संयुक्त राष्ट्रों की सेना जीवाणु युद्ध नीति अपना रही थी । इस पर अमरीका ने 'अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास' द्वारा निष्पक्ष जाँच को स्वीकार किया, परन्तु साम्यवादियों ने इसको

स्वीकार नहीं किया ।

इस प्रकार कोरिया के युद्ध की स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात् अमरीकी जनता ने 1953 में युद्ध विराम हेतु आइजनहावर को राष्ट्रपति बनाने का निश्चय किया । 27 जुलाई, 1953 को कोरिया में युद्ध विराम के साथ ही सोलह संयुक्त राष्ट्रीय मित्र देशों ने साम्यवादियों को चेतावनी दी, कि यदि इस संधि का उल्लंघन हुआ, तो इसके परिणाम भयंकर होंगे । इस युद्ध में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से अधिक नरसंहार हुआ ।

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय समाज व्यवस्था का संगठन

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व, राष्ट्रों में, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्, एक शान्ति स्तम्भ बनकर युद्ध से त्रस्त जनता को 'शांति की ज्योति' को स्थिर रखने का आह्वान किया । संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकारपत्र का प्रारूप जून, 1945 में सैनफ्रांसिसको के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था । इस अधिकार पत्र की वास्तविक शिला 'डम्वारटन-ओक्स समझौते' पर आधारित थी । विश्व के सभी मानवतावादी जन इसमें एक नयी आशा देख रहे थे । इन लोगों का विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र संघ मनुष्यों की 'विश्व लोक सभा' तथा 'विश्व सभा' की कल्पना होगी । प्रारम्भ में पचास राष्ट्रों ने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर, संघ की सदस्यता ग्रहण की थी । सोवियत संघ ने यूक्रेनियन एवं श्वेत रूस के लिये पृथक रूप से प्रतिनिधि भेजे थे । विघटित राष्ट्र संघ के संगठन के अनुरूप इस नव सृजित संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वही व्याप्त विभाग थे । एक सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद् और आर्थिक और सामाजिक परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक सचिवालय एवं निक्षेपधारी परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख विभाग थे । इसके अतिरिक्त इस संघ से सम्बद्ध अन्य विशेष कार्य-कारिणी संस्थायें भी थी ।

सामान्य सभा में प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि को मात्र एक मत देने का अधिकार था । समस्त मुख्य प्रश्नों पर निश्चय के लिये दो तिहाई बहुमत की सहमति अनिवार्य थी । सुरक्षा परिषद् का संगठन ग्यारह सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था । समस्त कार्यों व निर्णयों को कार्यशील करने के लिये सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र की एक मात्र संस्था है । इस परिषद् का उद्देश्य संकटकालीन स्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के वातावरण में अविलम्ब निर्णय लेने हेतु है । ग्यारह सदस्यों में से पाँच स्थायी रूप से विश्व की बड़ी शक्तियाँ होती हैं एवं छः अन्य अस्थायी सदस्य दो वर्षों के लिये सामान्य सभा

के द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पाँच बड़ी शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र, इंग्लैण्ड, सोवियत रूस, फ्रांस तथा चीन थी। इन्हीं राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता प्रदान की गयी। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि सभी स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद् में विचारशील किसी भी प्रश्न पर जो उस समय क्रम में हों, किसी निश्चय पर निदेश हेतु विशेष निषेधाधिकार प्राप्त था। इस 'निषेधाधिकार' का प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना था। तत्पश्चात् इसके प्रयोग की एक धारणा बन गयी तथा प्रत्येक छोटी-छोटी घटनाओं पर निश्चय हेतु प्रतिनिषेध होने लगा। यहाँ तक कि नवम्बर, 1947 में रूस ने एक मात्र प्रश्न पर बीस बार इस अधिकार का प्रयोग किया। अमरीका के विदेश सचिव मार्शल ने विशेषाधिकार के इस अनुचित प्रयोग, जिससे कि विश्व शांति कार्यों में विलम्ब होता था, की तीव्र आलोचना की उन्होंने अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु एवं प्राविधानों में संशोधन करने हेतु एक नवीन प्रस्ताव रखा। उन्होंने अविलम्बता की माँग वाले सभी निर्णयों पर विचार हेतु एक विशेष लघु सभा की संरचना का विचार दिया। सोवियत रूस ने इस प्रस्ताव पर तीव्र विरोध प्रकट किया। इस पर भी सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को मान्यता दे दी। फलस्वरूप एक विशेष समिति की संरचना की गई जिसे शान्ति अवरोधक प्रश्नों की समस्त छानबीन एवं सम्बन्धित परामर्श करने के अधिकार दिये गये।

प्रचलित 'विश्व न्यायालय' के समरूप एक नवीन 'अन्तर्राष्ट्रीय विश्व न्यायालय' की स्थापना की गई। इस विश्व न्यायालय का मुख्यालय भी हेग में स्थित था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णयों को मानने के लिये बाध्य थे। समस्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पारस्परिक झगड़ों को समाधान हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत करते थे।

विशेष कार्य हेतु सृजित की गई समस्त संस्थायें एवं समितियाँ उदाहरणतया 'आर्थिक व सामाजिक समिति' आदि सुरक्षा परिषद् के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आती थी।

नवम्बर, 1945 में एक विशेष समिति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की स्थापना की गई। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इस संगठन को एक विशेष महत्व प्रदान किया। उनके विचार में यह संगठन विश्व में शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान व विकास के कार्यों में एक नयी क्रान्ति का स्वरूप होगा। इस प्रकार उनके विचार में इस संस्था द्वारा सम्पूर्ण विश्व में स्वतंत्र विचारों के प्रसार में सहयोग मिलेगा। इस

संस्था का प्रमुख ध्येय रचनात्मक विकास का सम्पूर्ण विश्व में संचार करना था जिसके द्वारा शिक्षा व विज्ञान का उपयोग सभी मानव जाति के लोग समान रूप से कर सकें। यूनेस्को के संविधान में यह अंकित किया गया “कि युद्ध के विचार मनुष्य के मस्तिष्क में स्वयं उत्पन्न होते हैं, अतः शांति की सुरक्षा के विचारों की उत्पत्ति भी मानव मन में स्वयं करनी होगी।” समस्त सदस्य राष्ट्रों को अपने देश में यूनेस्को के कार्यों के प्रसार हेतु एक आयोग का गठन करना था। संगठन के प्रमुख कार्य इस प्रकार से थे। प्रशिक्षित अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के कार्य सौंपना, तकनीकी सहायता, छात्रवृत्तियाँ एवं श्रमिक विधियों की शिक्षा का विकास, पुस्तकों आदि पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिपि अधिकार, पुस्तकालयों एवं सामूहिक संस्थान की स्थापना हेतु सहायता आदि। इस प्रकार जनतांत्रिक आदेशों की शिक्षा का विकास एवं साक्षरता का विकास, तथा शिक्षा राहत के कार्य इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे। विश्व में राजस्व वित्त व्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार हेतु एवं अविकसित देशों के विकास कार्यों में वित्तीय सहायता तथा ऋण कार्यों के लिये एक ‘अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व मुद्रा संगठन’ की नितान्त आवश्यकता थी। यह विचार भी साम्यवादियों के व्यापार प्रसार के विरुद्ध एक संगठन की संचरचना हेतु था। संगठन से ‘मुक्त विश्व’ में अपने व्यापार को विस्तृत करने में अमरीका तथा पश्चिमी देशों को अत्यन्त सुविधा प्राप्त होती। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर 1944 में ‘ब्रैटन-वुड’ नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में आयात की नयी नीतियों व व्यापार विकास के कार्यक्रमों व योजनाओं पर विचार विमर्श, किया गया। ब्रैटन-वुड सम्मेलन के फलस्वरूप एक ‘अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एवं विश्व बैंक’ की स्थापना के विचारों पर निश्चय लिया गया। तत्पश्चात् एक नयी योजना के द्वारा इस बैंक की शाखा के रूप में ‘अन्तर्राष्ट्रीय विकास व पुनर्निर्माण बैंक’ की स्थापना भी की गई। विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों का ‘कोष संगठन’ था, साथ ही यह राष्ट्रों के परस्पर ऋण, बीमा व प्रतिभूति के कार्यों की एक संस्था भी था। विश्व के उन विकासशील देशों ने जहाँ, गरीबी व जीर्ण समाज व्यवस्था थी एवं समाजवाद के प्रसार का विशेष भय था, ऋण सहायताओं को अनुमोदित करने में विश्व बैंक ने पूर्ण सहयोग दिया। इन समस्त संगठनों के होते हुये भी सहायता योजनाओं व ऋण कार्यों को मई, 1947 से पूर्व प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसके उपरान्त भी तनाव-पूर्ण वातावरण एवं शीतयुद्ध निरन्तर बढ़ता ही गया। सोवियत संघ ने अपने गुप्तचर व अन्य संस्थाओं के द्वारा नवीन विश्व व्यापी साम्यवादी आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। एशिया व अफ्रीका में साम्यवादी लालिमा आने का विशेष

भय उत्पन्न हो गया ।

उपरोक्त सब परिस्थितियों का अवलोकन करते हुये अमरीकी प्रशासन ने सहायता एवं ऋण कार्यों को बढ़ाने के लिये कई नये कदम उठाये । 15 अक्टूबर, 1952 तक 1.5 विलियन डालर की धनराशि विश्व बैंक द्वारा अट्ठाइस राष्ट्रों को विभिन्न विकास कार्यों व योजनाओं हेतु ऋण रूप में अनुमोदित की गई । विश्व बैंक निरीक्षकों ने इन समस्त राष्ट्रों की योजनाओं का अध्ययन किया और अनुमानित व्यय प्रस्तुत किया । मुख्यतः ऋण विद्युत, सिंचाई, रेलवे, कृषि व औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के लिये दिये गये थे । यह सभी ऋण दीर्घ कालीन भुगतान के रूप में अनुमोदित थे तथा इनके व्याज की दर विशेष रूप से कम निर्धारित की गई थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय विश्व बैंक से सम्बद्ध एक दूसरा संगठन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था । इसमें भी अमरीका के निदेशक को 31.68 प्रतिशत का मताधिकार प्राप्त था । इस कोष संगठन का मुख्य अभिप्राय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा विचलन, विनिमय व आदान प्रदान को निर्धारित करना था । राष्ट्रों के विनिमय अवरोधों को कम करके एवं मुद्रा कोषों को स्थिर रखकर उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने में सहायता प्रदान करनी थी । इस प्रकार व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त रूप से विकसित एवं प्रसारित करना था एवं दो राष्ट्रों के मध्य गुप्त संकीर्ण व्यापार समझौतों का प्रतिरोध अथवा अन्त करना था ।

इन संस्थाओं ने स्पष्ट व्यापार कार्यों एवं विश्व सेवा योजन योजनाओं में भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया । इन समस्त प्रशंसा युक्त कार्यों के होते हुये भी अमरीका का यूरोप एवं एशिया में पूर्ण रूप से स्थिरता व दृढ़ता लाने का उद्देश्य भलीभाँति सम्पन्न न हो सका । फलस्वरूप उद्देश्य को और सुसज्जित करने के लिये पश्चिमी जगत के समर्थक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने 'स्पष्ट व्यापार' नीतियों को प्रोत्साहन देने के लिये एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की योजना प्रस्तुत की । सामान्य रूप में, सर्व सम्मति के पश्चात्, इस संगठन को स्थापित किया गया । सोवियत संघ एवं उसके समर्थक साम्यवादीयों ने इस नव संगठित संस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट किया । जिस प्रकार पूर्व समय में भी उन्होंने अन्य संस्थाओं के प्रति किया था । इस व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य चुंगी में न्यूनता प्रदान करने एवं अंशों के एकीकरण को कम करने आदि की नयी नीतियों का आलेखन करना था । इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्याप्त पक्षपातों को समाप्त करने में सहयोग मिलता । अमरीकी समाचार पत्रों ने इस संगठन के उद्देश्यों का भव्य स्वागत किया परन्तु

कांग्रेस में सदस्यों ने कोई विशेष रुचि नहीं प्रदर्शित की।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व समुदाय की सबसे बड़ी समस्या खाद्य सामग्री का अभाव था। एशिया और अफ्रीका के निर्धन देशों की दशा अत्यन्त दयनीय थी। यूरोप के वह राष्ट्र जो विश्व युद्ध में विजित कहे जा सकते थे, वे भी खाद्य सामग्री के अभाव से पीड़ित थे। अनुपयुक्त भोज्य सामग्री के कारण अनेक प्रकार के रोगों के फैलने का भय था तथा आने वाली पीढ़ियों के लिये यह एक गम्भीर संकट बना हुआ था। इन परिस्थितियों को देखते हुये संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक नयी संस्था की स्थापना हेतु सामान्य सभा में प्रस्ताव रखा जिसके फलस्वरूप 'खाद्य एवं कृषि संगठन' की स्थापना हुई। अमरीकी अनुदान का इसमें प्रमुख योगदान था। कांग्रेस ने इस संस्था हेतु तथा यूरोप, एशिया व अफ्रीका के 34 देशों की, वित्तीय सहायता राशि बढ़ा दी। 1945 के निर्यात आयात बैंक अधिनियम द्वारा बैंक का ऋण अधिकार 700 मिलियन डॉलर से बढ़कर 3.5 बिलियन डॉलर कर दिया गया। कुछ समय के लिये लेटिन अमरीका को ऋण न देकर यूरोप और एशिया में विशेष सहायतायें प्रारम्भ हो गईं। अमरीका ने फ्रांस को विशेष सामयिक वित्तीय सहायता प्रदान की। इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के साम्यवादी दल की पराजय में निहित था। ऐसे राष्ट्रों में ऋण व अनुदानों को अवरुद्ध किया गया जहाँ यह निश्चय हो गया था कि राष्ट्र साम्यवाद के पथ पर अग्रसर हो रहा था। अमरीकी प्रशासन ने देश में राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण की योजना बनाई, इसके लागू होने के बाद अमरीकी खाद्य सहायता एशिया तथा अफ्रीका के क्षुधाग्रस्त क्षेत्रों में पहुँचाई जाने लगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ और निःशस्त्रीकरण

राष्ट्र संघ ने अपने स्थापना के आरम्भ से ही विश्व शांति के लिये सेवा प्रारम्भ कर दी थी। ईरान में सोवियत संघीय सेना का निष्कासन व वहाँ फैल रहे गृह युद्ध को शान्त करना, राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। सामान्य सभा में अब यह विचार विमर्श होने लगा कि विश्व राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण के द्वारा ही युद्ध के भयंकर परिणामों को रोका जा सकता है। इस कार्य के लिये राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण अंग था। विलियम जैम्स ने अपनी पुस्तक 'युद्ध नैतिक संतुलन' में बताया था, कि युद्ध मनुष्य की स्वाभाविक व आक्रामक प्रवृत्ति का स्वरूप है, परन्तु फिर भी इसे एक नवीन दिशा प्रदत्त की जा सकती है। अन्य दार्शनिकों व इतिहासकारों के विचार भी निःशस्त्रीकरण के पक्ष में

थे। सभी लोगों का विचार था, कि युद्ध प्रत्येक स्थिति में अत्यन्त दुःखोत्पादक है अतः विजित राष्ट्रों को भी यौद्धिक प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिये।

राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम विवाद आणविक अस्त्रों पर प्रारम्भ हुआ। 1 दिसम्बर, 1945 को मास्को में एक सम्मेलन हुआ जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमरीका, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस ने मुख्य रूप से भाग लिया था। विचार विमर्श के पश्चात् तीनों बड़े राष्ट्रों में राष्ट्र संघ के अधीन एक परमाणु शक्ति आयोग के गठन के लिये समझौता हुआ। उस समय तक अमरीका ही एक मात्र राष्ट्र था, जो इस अणु बम की तकनीक से ज्ञातव्य था, अतः रूस ने इसके प्रतिबन्ध पर कई विचार प्रेषित किये। अमरीका ने भी स्वयं इस दिशा में नवीन पग उठाये और एचिसन-लिलियनथॉल के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रिपोर्ट तैयार करवाई जिसका मुख्य उद्देश्य अणु बम के प्रयोग को रोकना था। बर्नार्ड बारुक जो अमरीकी परमाणु शक्ति आयोग में प्रतिनिधि था, ने जून 14, 1946 को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में इस घातक आवणिक शस्त्र की तीव्र निन्दा की गई थी तथा यह निर्णय दिया गया, कि किसी भी दशा में सुरक्षा परिषद में इस शस्त्र के प्रयोग में वीटो निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग करना पूर्णतया अमान्य होगा। विश्व में परमाणु ऊर्जा का केवल राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय हित कार्यों में ही उपयोग होना है तथा इसके लिये रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु विकास अधिकरण के संगठन का प्रस्ताव दिया गया था। अधिकरण के कार्यों को भी रिपोर्ट में विस्तृत रूप से व्यक्त किया गया था। मुख्य रूप से तीन दिशाओं में कार्य होना था।

1. समस्त परमाणु ऊर्जा कार्य विधियों का, जो विश्व समुदाय के लिये हानिकारक हो सकती थी, पूर्ण प्रबन्धीय-नियन्त्रण या पूर्ण आधिपत्य।

2. अन्य सभी परमाणु गतिविधियों का नियन्त्रण, जाँच व अनुज्ञापत्र का अधिकार प्रदत्त किया जाय।

3. परमाणु ऊर्जा के लाभदायक प्रयोग के विस्तार के कर्तव्य।

अधिकरण के सुरक्षा की समस्त परिस्थितियों को निश्चित करने की अपेक्षा की गई। इसके बाद अमरीका जो उस समय तक इस आणविक शस्त्र युक्त एक मात्र राष्ट्र था, के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया, कि अणुबमों का निर्माण तुरन्त बन्द कर दिया जाये तथा अब कोई भी राष्ट्र अणु बमों का निर्माण नहीं करेगा। यह प्रस्ताव सफल न हो सका। इसका बहुत कुछ कारण सोवियत (रूस) ही था। उस समय सोवियत संघ के प्रतिनिधि ग्रोमिको ने इस अधिकरण के प्रति अपने देश का मतभेद स्पष्ट किया और कहा कि रूस यह निर्णय स्वीकार नहीं करेगा, कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के नियमों पर सोवियत संघ रूस अपने निषेधाधिकार को समाप्त कर दे तथा इसमें नियमबद्ध होकर

वह आणविक अस्त्र निर्माण में पीछे रह जाये। उसने अणु अनुसंधान सूचना हेतु एक विशेष समिति की स्थापना की बात स्वीकार कर ली। अणु उल्लंघन के प्रति प्रत्येक राष्ट्र को अपने अलग समझौते करने थे। यह राष्ट्रों की स्वनीति पर निर्भर था कि वह ऐसे राष्ट्रों के प्रति कैसे सम्बन्ध रखे? अमरीका ने सोवियत संघ के मन्तव्य को देखते हुये वाद में रूस द्वारा दिये गये हर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। वास्तव में अमरीका के पास रूस की जन-शक्ति के संतुलन हेतु मात्र अणु शस्त्र ही एक विकल्प था।

1953 में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात सोवियत संघ ने कुछ नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिसमें अमरीका की स्थिति को पूर्ण ध्यान में रखा गया था परन्तु नियंत्रण विधि पर तब भी कोई समझौता नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त न कोई नियम लिपि बन सकी। जनवरी, 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामान्य सभा में मत द्वारा परमाणु शक्ति (ऊर्जा) आयोग को समाप्त कर दिया और एक नये निशस्त्रीकरण आयोग का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य रीतिबद्ध निशस्त्रीकरण एवं अणु नियंत्रण पर एक साथ विचार करना था परन्तु पुनः पूर्व पश्चिम विचार विमर्श के पश्चात भी कोई समझौता न हो सका जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण का व अणुवम नियंत्रण की सन्तोपजनक विधि के बिना अमरीका अपने अणुवमों को समाप्त करने को तैयार नहीं था। सोवियत संघ अणु शस्त्रों के समाप्ति पर समर्थन कर रहा था। इस सभाओं के पूर्व ही राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 23 सितम्बर, 1949 को यह घोषणा की कि 'पूर्ण विश्वास के साथ वह यह बात कह सकता है कि सोवियत संघ ने अणु परीक्षण किया है, अमरीका के पास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।' इनके साथ ही अमरीका के गुप्तचर विभाग ने यह सूचना दी थी कि सोवियत संघ के गुप्तचर परमाणु सूचना के लिये अमरीका, कनाडा तथा इंग्लैण्ड में अपनी कार्य विधि बढ़ाये हुये हैं। इस प्रकार की कई गुप्तचर शृंखला को बन्दी भी बनाया गया। डा० क्लास फुक्स जर्मनी में जन्में एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने न्यू मैक्सिको के परमाणु केन्द्र में भी कार्य किया था तदुपरान्त यह ज्ञात हुआ कि वे 1942 से रूसियों को अमरीका की परमाणु नीतियों की सूचना प्रदान कर रहे थे। इन गुप्तचर गतिविधियों के पश्चात फिर से परमाणु शस्त्रागार के निर्माण का नया संघर्ष प्रारम्भ हो गया। 1952 में यह सूचना प्राप्त हुई कि एनीबीटोक क्षेत्र में अमरीकी परमाणु परीक्षण वास्तव में हाइड्रोजन बम के परीक्षण थे। यह अणुवम से भी कई सौ गुना अधिक विनाशकारी शस्त्र था। 1954 तक रूस ने भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया। इस प्रकार शीत-युद्ध सब शस्त्रों व शस्त्र तकनीकी दौड़ के रूप में आ गया था।

अमरीका महाद्वीपीय व्यवस्था एवं रियो सुरक्षा समझौता

अमरीका में एक पराम्परा हमेशा प्रचलित रही है कि सम्पूर्ण पश्चिमी जगत जिसे 'नवीन विश्व' की संज्ञा दी गई है अर्थात् उत्तरी और दक्षिणी अमरीकी महाद्वीपीय, एटलांटिक तट के दूसरी ओर स्थित पूर्वी विश्व से पूर्ण-तया भिन्न है। अमरीकी विदेश विभाग ने अपनी नीतियों में हमेशा इस तथ्य को स्वीकार किया और समय-समय पर लैटिन व उत्तरी अमरीका महाद्वीप ने सामुहिक सुरक्षा के विचार प्रदर्शित किये।

द्वितीय विश्व युद्ध के घटना काल में दोनों महाद्वीप स्थित समस्त राष्ट्रों ने पारस्परिक मित्रता से एक दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जिससे इस अन्तर अमरीकी सहयोग की धारणा को अत्यन्त बल प्राप्त हुआ। युद्धोपरान्त अमरीका के प्रयत्नों से सामुहिक सुरक्षा की धारणा और प्रबल हुई। मनरो सिद्धान्त में भी अदृश्य रूप से इस प्रकार की विचार धारा के तत्व विद्यमान थे। पाँचवें दशक के अन्तिम वर्षों में अर्जेंटीना की गतिविधियों के कारण इस धारणा में परिवर्तन आया। अर्जेंटीना की निष्ठुरता का प्रदर्शन ही साम्यवाद का इन महाद्वीपों में प्रवेश का प्रथम चरण था। तत्पश्चात् बोलिविया के विद्रोह व क्रांति के द्वारा साम्यवाद के प्रसार का आरम्भ हुआ। अन्तिम चरण में क्यूबा के विद्रोह व क्रांति ने इस प्रचलन को गहरा आघात पहुँचाया। अमरीकी विदेश विभाग ने अरब अर्ध विश्व की सुरक्षा व एकाग्रता हेतु नयी नीतियों पर आधारित कई अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये। कांग्रेस में "चापुलटेपेक" अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के प्राविधानों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अमरीकी महाद्वीपीय व्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों में नितान्त आवश्यकता है। दोनों महाद्वीपों के समस्त अमरीकी राष्ट्र चाहे वह आर्थिक दृष्टि से दुर्बल अथवा क्षेत्रों में न्यून क्यों न हो, सामुहिक रूप से एक दूसरे से सुरक्षित होंगे। किसी भी राष्ट्र पर वाह्य शक्ति के द्वारा हस्तक्षेप अथवा आक्रामक योजनाओं द्वारा प्रसार की गतिविधियों को एकत्रित रूप से समस्त राष्ट्रों पर आक्रमण माना जायेगा एवं उस राष्ट्र की सुरक्षा हेतु महाद्वीप के सभी राष्ट्र सामुहिक रूप से कदम उठायेगें। कांग्रेस में थोड़े विवाद के पश्चात् मार्च 1945 को यह अधिनियम पारित कर दिया गया।

क्षेत्रीय शांति के स्थापन हेतु राष्ट्रों ने भी प्रचलित मनरो सिद्धान्त में भी संशोधन किया। अब तक मनरो सिद्धान्त केवल वाह्य आक्रमणकारी शक्ति के प्रति सुरक्षा की नीतियों को ही निर्धारित करता था। संयुक्त राष्ट्र के युग में यह एक विचित्र प्रयास था परन्तु यह सिद्धान्त राष्ट्र संघ के अध्यादेश का

अनुमोदित करता था। संयुक्त राष्ट्र संघ अध्यादेश में क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को विश्व शान्ति के स्थापन के लिये एक आवश्यक प्रबन्ध बताया गया था। अधिनियम के पारित होने के पश्चात् अमरीका के सभी प्रयासों के फलस्वरूप भी, महाद्वीपीय शान्ति व सुरक्षा हेतु अन्तर अमरीकी सम्मेलन शीघ्र न हो सका। इसका मुख्य कारण अमरीका, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पेरोन के साथ किसी भी समझौते पर सहमत न होना था परन्तु बाद में विदेश विभाग ने यह निर्णय लिया, कि लैटिन अमरीका की पारस्परिक सहयोग व सुरक्षा की संधि रूसी साम्यवाद के प्रतिरोध के लिये नितान्त आवश्यक है। फलस्वरूप सितम्बर, 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन व विदेश सचिव जार्ज मार्शल ने रियो डेजेनीरो की यात्रा की। अत्यन्त विचार विमर्श के पश्चात् 1947 में एक 'अन्तर अमरीकी सुरक्षा संधि प्रतिपादित हुई। 'युद्ध काल के दौरान 1942 में रियो में हुये (अखिल) पैन-अमरीकी सम्मेलन में भी धुरी राष्ट्रों से सम्बन्ध विच्छेद का सामूहिक निर्णय लिया गया। रियो समझौता आन्तरिक और वाह्य आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा नीति को निर्धारित करता था। बाद में इस समझौते में कई अन्य संशोधन किये गये। 1948 में बोगोटा में एक दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत ही एक विशेष अन्तर अमरीकी संस्थान की स्थापना की गयी।

अमरीकी विश्व-युद्ध के समय में कर्नल जुआन पेरोन के नेतृत्व में अर्जेंटीना में एक राष्ट्रवादी क्रान्ति हुई थी। 1943 की इस क्रान्ति में पेरोन ने अपने राष्ट्र की दृढ़ उदासीनता की नयी नीति की घोषणा की थी। युद्ध के अन्तिम चरण में इन्हीं राष्ट्रवादी नेताओं ने नाजियों (नात्सियों) के नायकत्व में फाशिज्म (फासीवाद) विचारधारा का प्रचार प्रारम्भ किया था। फलस्वरूप सम्पूर्ण महाद्वीप में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। अमरीकी प्रशासन ने पेरोन की नीतियों पर तीव्र प्रतिरोध प्रकट किया एवं पेरोन के विरुद्ध शासकीय घोषणा की। इतना होने पर भी पेरोन राष्ट्रपति के चुनाव में विजित हुआ तथा अर्जेंटीना में जनतंत्र के विपरीतराष्ट्रवादी प्रशासन स्थापित हो गया। युद्धो-परान्त परिस्थितियों के अललोकन के पश्चात् विदेश सचिव वर्न्स ने अमरीकी नीतियों में परिवर्तन कर लिया इसका एक अन्य प्रमुख कारण यह भी था कि अर्जेंटीना द्वारा बड़ी मात्रा में विश्व राहत समस्या के लिए अपने गेहूँ की आपूर्ति का कार्यक्रम भी था। इसके अतिरिक्त प्रथक होने पर अर्जेंटीना साम्यवादी संगठन से भी सम्बद्ध हो सकता था। लैटिन अमरीका के राष्ट्रों से अमरीका के सम्बन्धों में कई नई विचारधारायें भी उत्पन्न हो रही थीं। साम्यवादी आदर्शों का इन लैटिन अमरीकी देशों में प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा था। शीत युद्ध के इस

युग में ऐसी गतिविधियाँ अमरीका के लिये जटिल समस्या बन गयी थी। दिसम्बर, 1946 में ब्राजील में चुनाव हुये। लगभग पाँच लाख लोगों ने साम्यवादियों को मत देकर उनके प्रति अपना समर्थन प्रदर्शित किया। साम्यवादियों का नेतृत्व लुईसकार्लोस नामक एक अत्यन्त प्रभावशील व्यक्ति के हाथों में था। उसने अमरीका विरोधियों से युक्त कई अभियान प्रारम्भ किये। साक्षरता की कमी एवं गरीबी के वातावरण के कारण इन देशों में साम्यवादी 'अमरीका विरोधी समूहों' का संगठन कर रहे थे। यहाँ के नेतागण अर्जेन्टीना के नायक पेरोन का समर्थन करते थे। इस प्रकारके संघर्षमय वातावरण में रियो की संधि अमरीका के लिये अत्यन्त आवश्यक सिद्ध हुई। इस संधि के द्वारा अमरीका ने समस्त महाद्वीपीय देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक द्वार प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त अधिकांश राष्ट्र भी अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। 1954 के जब गॉटेमाला में साम्यवादी गुटवंदी प्रारम्भ हुई तो शीघ्र ही काराकस में एक बीस राष्ट्रों का अन्तर अमरीका सम्मेलन आयोजित किया गया और साम्यवाद के प्रसार के प्रबल अवरोधन के लक्ष्य से एक "सामूहिक क्रिया समिति" का गठन किया गया।

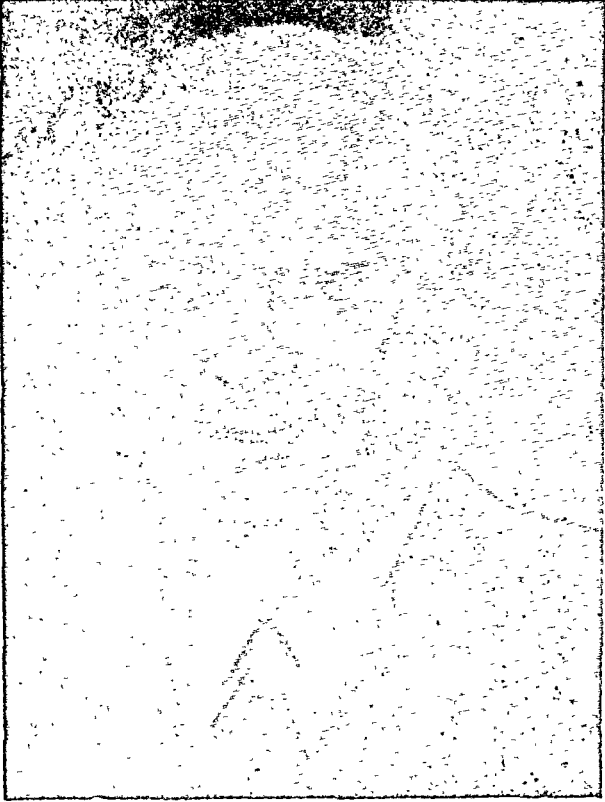
समस्त प्रयासों के फलस्वरूप भी अमरीका रूस के साथ कोई सीधा एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित न कर सका। शीतयुद्ध की ज्वाला निरन्तर बढ़ती गयी। निशस्त्रीकरण की नीतियों के निर्धारण हेतु सोवियत संघ के साथ कोई सम्बन्ध न हो सके। फलस्वरूप सोवियत संघ की निरन्तर प्रसारित होती हुई शक्ति के अवरोध के लिये अमरीका ने विश्व समुदाय के नायकत्व का नवीन अध्ययन प्रारम्भ किया। इस प्रकार अमरीका के पृथकतावाद के प्रचलन के अन्त का सोवियत संघ ही उत्तरदायी था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात-वर्ती इस युग में ट्रूमैन प्रशासन का मुख्य ध्येय सोवियत साम्यवाद के प्रसार के प्रति सुरक्षा नीतियों को गतिशील करना था। उन्नीसवीं शताब्दी के 5वें दशक के अन्तिम वर्षों तक की समस्त घटनायें इसी संघर्ष की द्योतक हैं। ट्रूमैन के पश्चात भी अमरीका की विदेश नीति की परम्परा प्रचलित रही। वास्तव में स्टालिन की नीतियों ने 'स्वतंत्र विश्व समुदाय' को एक संधीय रूप प्रदान कर दिया था। साम्यवादी प्रसार की नीति ने विश्व के इन दो समुदायों को आदेशों व सेना शक्ति के रूप में पूर्णतया विभाजित कर दिया था।

अमरीका के जटिल संघर्षमयी प्रयत्नों एवं त्याग व दान की नीतियों ने निश्चय ही सोवियत प्रसार को पश्चिमी सीमा पर रोक दिया। इटली व फ्रांस में साम्यवाद का भय पूर्णतया समाप्त हो गया। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में

स्वतंत्र देशों ने नवीन गठबंधन स्थापित कर लिया । प्रशान्त महासागर व दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में भी आर्थिक व सैन्य शक्ति के सुरक्षा गठबंधनों ने साम्यवाद के अवरोध में पूर्ण सहायता प्रदान की । जापान, दक्षिण कोरिया, मलाया, फिलीपाइन्स, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड के साथ अमरीका के प्रगाढ़ सम्बन्ध इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण थे ।



अस्तित्ववाद



डिवाइट आइजनहॉवर
अमरीका के चौंतीसवे राष्ट्रपति

अध्याय 11

आइजनहावर का प्रशासन काल

अमरीका के इतिहास के राजनैतिक पृष्ठ पर 1952 के वर्ष का अपना एक महत्व है। इस वर्ष अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव ने मैकार्थीवाद के द्वारा एक नवीन करवट ली। ट्रूमैन प्रशासन की शीत युद्ध की नीतियों, सुदूर पूर्व के लिये विदेश नीति तथा साम्यवादियों के प्रति एक उदार नीति की चर्चा चुनाव अभियानों में अत्यन्त उत्साहपूर्ण एवं आलोचनात्मक रूप से प्रस्तुत की गई। मैकार्थीवाद ने जन वर्गों को इस तथ्य से अवगत कराया कि लोकतांत्रिक दल देशद्रोहियों का शरण स्थल था ट्रूमैन प्रशासन के प्रति भ्रष्टाचार के आरोप स्थापित करने की पूर्णतया चेष्टा जनता एवं राज्य वेत्ता दोनों ओर से की गई और इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि गणतांत्रिक दल ही केवल शासन एवं देश को स्वच्छ प्रशासन प्रदत्त कर सकता था परन्तु कोरिया के युद्ध ने इतना असंतोष व्याप्त कर दिया था कि 1952 का वर्ष गणतंत्रिक वर्ष सम्भावित प्रतीत होने लगा। इस दल के प्रमुख राजनीतिज्ञों ने आन्तरिक एवं बाह्य शांति हेतु एक सैनिक राष्ट्रनायक डिवाइड आइजनहावर को दल का कर्णधार माना।

अपने चुनाव अभियान के भाषणों में उन्होंने देश की गम्भीर समस्याओं की ओर पूर्णतया ध्यान दिया तथा आदर्शवाद की नीतियाँ दी। ऐसी विचार-धारायें चुनाव अभियान में विल्सन के पश्चात् अभी तक नहीं मिली थी यहाँ तक कि उसके विरोधियों ने भी उसके महानतापूर्ण विचारों को स्वीकार किया। तत्कालीन राजनैतिक वातावरण तथा जनता की आशाओं के पूर्ण अनुरूप आइजनहावर प्रजातांत्रिक दल के मनोनीत उम्मीदवार स्टीवेन्सन के विरुद्ध विजयी हुये। तत्पश्चात् कांग्रेस के दोनों सदनों में भी गणतंत्रवादी दल विजयी हुआ। अतः दो दशकों के लम्बे अन्तराल के पश्चात्, प्रजातांत्रिक शासन प्रवृत्ति, का अन्त हो गया। बौद्धिक वर्ग के अनुसार यह परिवर्तन

अमरीका में आइजनहावर ने कोरिया में गतिरोध को समाप्त करने, तथा अनैतिक असफल अवरोधन की नीति को स्थापित करने, संघीय व्यय को न्यून करने, अर्थ व्यवस्था में शासन के हस्तक्षेप को कम करने, तथा अमरीका में सम्भावित साम्यवाद भय को समाप्त करने आदि की नीतियों का परिपालन किया।

आधुनिक गणतंत्रवाद

अपनी गृह नीति में आइजनहावर ने अपने पूर्वाधिकारियों की परिपालित नीतियों से हटकर आन्तरिक नीति निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। ह्वाइट हाउस में तीन वर्ष प्रशासनिक अनुभव के पश्चात् आइजनहावर इस तथ्य के यथार्थ से भली भाँति परिचित हो चुके थे कि अमरीका अभी भी निर्धनता, अभाव एवं बेरोजगारी का वृहद् द्वीप है। इसके अतिरिक्त जनवृद्धि के कारण उत्पन्न शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य, नीग्रो समस्या तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रोत्साहन का प्रश्न भी उनके समक्ष था। अपने प्रथम सत्र में तो राष्ट्रपति आइजनहावर ने नवीन गणतंत्र को विशेष स्वरूप प्रदत्त नहीं किया परन्तु द्वितीय सत्र में यह स्वरूप प्रायः स्पष्ट होने लगा।

राष्ट्रपति आइजनहावर की आन्तरिक नीति में एक मूल प्रश्न नागरिक अधिकारों का था। 1957 में यह प्रश्न एक वृहद् प्रश्न चिन्ह बन समक्ष आया, जिसका समाधान राष्ट्रपति के लिये निर्णायक था। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने 'अर्लवोरेन' (वॉरेन) को अमरीका का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था जिन्होंने 1954 में अपने ऐतिहासिक निर्णयों में शिक्षा संस्थानों में जातिभेद को असंवैधानिक घोषित किया। यद्यपि राष्ट्रपति ने नीग्रो जाति को नागरिक अधिकार प्रदत्त करने का श्रेय प्राप्त किया परन्तु सितम्बर, 1957 में दक्षिण में 'आर्कान्सो' में प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो गई। वहाँ के राज्यपाल 'आर्वल फावस' ने नीग्रो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आज्ञा निषेध पारित कर दी। अपनी आज्ञा के पालन हेतु राज्यपाल ने राष्ट्रीय रक्षकों को तैनात कर दिया।

ऐसी स्थिति का संकेत विमोचन करने हेतु राष्ट्रपति ने फावस से अनुरोध किया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य न किया जाय जिसके द्वारा न्यायालय की मान-हानि हो परन्तु राष्ट्रपति का यह अनुरोध निष्फल रहा। जब नीग्रो छात्रों को शिक्षा संस्थान में जाने से रोका गया तो राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस बात की, घोषणा की कि संघीय न्यायालय

के निर्णय के दंडाभाव के कारण निरापद प्रदान किया जाय, यह सम्भव नहीं था। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 500 सैनिकों को वहाँ पर उतारा, और नीग्रो छात्रों को शस्त्रों की छाया में शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराया। इस घटना के कारण सीनेट सदस्य 'रिचर्ड रसल' ने राष्ट्रपति 'आइजनहावर को हिटलर' की संज्ञा दी। नीग्रो जाति ने इसका विश्वास किया कि जातीयता के भेदभाव को समाप्त करने में राष्ट्र शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता था।

आर्थिक नीतियाँ

नवीन प्रशासन को बड़े उद्योगपतियों व व्यापार का मित्र कहा जा रहा था। बृहद व्यापार के समर्थकों को मंत्रिमंडल से विशेष स्थान मिला था। इनमें से प्रमुख जार्ज हम्फ्री (वित्त सचिव) एवं चार्ल्स विल्सन (सुरक्षा सचिव) थे। कोरियन युद्ध के समय के लगाये गये अनेक मूल्य नियंत्रण प्रतिबन्धों को हटा दिया गया। प्रशासन, उद्योग व उर्जा के स्रोतों को प्रोत्साहन देना चाहता था। ट्रूमैन प्रशासन से विशेष परिवर्तन वित्त नीति में लाना था। गणतंत्रवादियों ने प्रशासन में आते ही सुरक्षा और विदेशी सहायता के बजट पर नियंत्रण करना प्रारम्भ कर दिया और सरकारी व्यय को रोका। उनका उद्देश्य कराधान को कम करना एवं बजट को संतुलित करना था। यह उद्देश्य वित्तीय वर्ष 1955-56 से पारित किये गये थे। सरकारी व्यय को कम करके 64 बिलियन डॉलर (60% इसमें सुरक्षा हेतु था) कर लिया गया जबकि पिछले वर्ष ट्रूमैन काल में यह 73 बिलियन डॉलर था। यद्यपि प्रशासन व्यक्तिगत उद्योग की उन्नति का इच्छुक था, फिर भी प्रशासकों ने स्पष्ट कर दिया कि अर्थ व्यवस्था के अनियमित स्थिति में वह न्यूडील की समस्त नीतियों को अपनाकर व्यवस्था को नियंत्रित करेंगे। अतएव उन्होंने गत दो दशकों से प्रचलित लोकतांत्रिक नीतियों को अपने प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया, यद्यपि संघीय राजनीतिज्ञों द्वारा 'टॉपट हार्टले अधिनियम' को संशोधित करने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी तथापि संगठित मजदूरों के अधिकारों तथा शक्तियों को न्यून करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 1954 में दस मिलियन से अधिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा तंत्र का विकास किया गया तथा मजदूरी की दरों की अत्यधिक वृद्धि की गई। 1956 में पुनः कांग्रेस ने इनमें वृद्धि के लिये मत प्रदान किये। आइजनहावर का दर्शन 'स्वतंत्र उद्यम' 'संतुलित बजट' तथा 'न्यूनतम शासकीय हस्तक्षेप' को प्रतिपादित करता था। इसी के आधार पर तत्काल ही स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक कल्याण के विभाग प्रस्थापित किये गये। आइजनहावर स्वयं एक नर्म

पंथी, संतुलित, संयमी मित्ताचारी एवं मध्यमार्गी व्यक्ति थे। उन्होंने सदन में सदैव सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाये रखने में रुचि रखी क्योंकि वहाँ गणतंत्रवादियों का बहुमत अत्यन्त अल्प था। आइजनहावर ने अपने प्रशासन में सार्वजनिक निर्माण योजनाओं को अत्यन्त महत्व प्रदान किया। इनमें 33 बिलियन डॉलर की सोलह वर्षीय जनपथ परिवहन परियोजना प्रमुख थी। जिसे कांग्रेस ने 1956 में स्वीकृति प्रदान की। 1955 के पश्चात व्यय की मात्रा में पुनः वृद्धि हुई, जो 1957-58 में 72 बिलियन डालर तक पहुँच गई। आइजनहावर प्रशासन ने यद्यपि आर्थिक नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया तथापि कृषि परियोजना परिवर्तन के लिये बाध्य थी। तत्कालीन अधिनियमों के अन्तर्गत सरकार इस बात पर सहमत थी कि वह 10% तक मूल्यों में समानता के लिये अतिरिक्त उपज को सुरक्षित रखे। कृषि सचिव एजरा टॉफ्ट बेन्सन की संस्तुति पर आधारित 1954 के कृषि समायोजन अधिनियम ने प्रचुर उपज की परिस्थिति में मूल्यों को 75% तक समान करने का अनुमोदन कर दिया। और यह आशा की गई कि इससे कृषक मुख्य फसलों की पैदावार में कटौती कर देंगे तथापि प्रचुर उपज समान रूप से होती रहें। सरकार को वृहद व्यापार में अतिरिक्त फसलों को सुरक्षित रखना पड़ा। इससे मूल्यों में ह्रास आता गया एवं भूमि की आय भी 17 बिलियन डालर से कम होकर 13 बिलियन डॉलर तक हो गई परन्तु उपभोक्ता मूल्यों में कोई अन्तर नहीं पड़ा। अतएव प्रशासन ने स्थिर मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों को प्राथमिकता देना प्रारम्भ कर दिया तथा किसानों को केवल 40% भूमि पर खेती करने और शेष स्थानों पर भूमि का कटाव रोकने वाले वृक्षों को आरोपित करने के लिये प्रेरित किया। इस 'भूमि बैंक परियोजना' को कांग्रेस ने 1956 में स्वीकार कर लिया। इस परियोजना तथा न्यूडील योजना में कोई विशेष अन्तर नहीं था।

आइजनहावर का प्रथम सत्र अन्य सभी आर्थिक क्षेत्रों में सम्पन्नता का युग रहा। 1953-54 के एक नवीन अध्ययन के पश्चात राष्ट्रीय उत्पादन, आय तथा रोज़गार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। इस काल में मजदूर विद्रोह अल्प मात्रा में हुये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृषि उत्पादन में मूल्य वृद्धि के कारण क्रान्ति की सम्भावनायें 1956 में समाप्त हो गई। सम्पन्नता एवं समृद्धता के तत्कालीन युग में सामान्य नागरिक के पास प्रशंसाओं के अतिरिक्त आलोचनाओं के लिये कोई स्थान नहीं था। इसके अतिरिक्त आइजनहावर प्रशासन ने 'जल मग्न भूमि अधिनियम' को पारित किया। यह अधिनियम इसके पूर्व ट्रूमैन के विशेषाधिकार द्वारा अवरोधित कर दिया गया था। इस अधिनियम

के अन्तर्गत प्रदेशों को तेल और खनिज पदार्थ अपनी-अपनी ऐतिहासिक सीमाओं में सीमित रहकर सागरीय तट से लाभान्वित कर सकता था। इस नवीन प्रशासन ने 1932 में राष्ट्रपति हूवर द्वारा प्रदत्त 'पुनः निर्माण नैतिक निगम' को समाप्त कर दिया तथा विभिन्न उद्योगिक निर्माणों को निजी संस्थानों को विक्रय करना निश्चित किया। इसमें संश्लेषित रबर का निर्माण प्रमुख था। इस प्रशासन ने नाम मात्र की कटौती की तथा बजट को सन्तुलित किया एवं विभिन्न व्यवसायों को समाप्त कर दिया।

विभिन्न विरोधों के पश्चात् भी कांग्रेस परमाणु ऊर्जा पर शासकीय एकाधिकार को समाप्त करने में सफल हो गयी तथा परमाणु विकास को निजी उद्योगों के अधीन निहित कर दिया गया। इसने सेन्ट लारेन्स जलमार्ग योजना के लिए भी स्वीकृति प्राप्त कर ली तथा अमरीका में विदेशी शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए भी एक अधिनियम पारित किया। इसके साथ ही साथ पारस्परिक व्यापारिक समझौते को भी समर्थन प्रदान किया गया। तथा सामाजिक सुरक्षा तन्त्र द्वारा लाखों नवीन अप्रवासियों को लाभान्वित किया गया।

आइजनहावर प्रशासन को इस तिरासिर्षी कांग्रेस में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका कारण न तो सदन में प्रजातन्त्रवादियों का अल्पमत में होना था और न ही गणतन्त्रवादियों का विभाजित होना था। अपितु इसका मुख्य कारण रुजवेल्ट के पूर्णकालीन शक्तियों को प्राप्त करने में निहित था। यही कारण था कि ब्रिक्कर ने संविधान को संशोधित कर विदेश नीति को कांग्रेस के अन्तर्गत समाहित करने का प्रस्ताव रखा। प्रजातन्त्रवादियों के विरोध तथा गणतन्त्रवादियों के आपसी मतभेद के कारण यह प्रस्ताव पारित न हो सका। सीनेट सदस्य मैकार्थी द्वारा प्रशासन की तीव्र आलीचना में भी उपरोक्त असफलता के कारण निहित थे।

आइजनहावर की आधुनिकता की योजना के लिये प्रमुख बाधा साम्यवादी विचारधाराओं के विरोध में निहित थी। आइजनहावर की असफलता से उदारवादियों में अत्यन्त निराशा व्याप्त थी। इसका मुख्य कारण यह था कि आइजनहावर ने मैकार्थी के राजनीतिक कार्यों में किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं की। इसके विपरीत आइजनहावर सदैव समझौते के पक्ष में रहे। अपने जीवन के अधिकांश काल में सैनिक तथा कूटनीतिक भूमिका निभाने के कारण वह गृह नीति की जटिलताओं से अनभिज्ञ थे। उन्होंने मैकार्थी द्वारा इंगित सुरक्षा समस्याओं में भी सार्थकता का उपस्थिति की संभावनाओं को अस्वीकार नहीं किया। राष्ट्रपति आइजनहावर अपने अतीत के अनुभव के द्वारा समझौते को मान्यता देते थे और अपने दृष्टिकोण अथवा

विचारों को किसी अन्य पर लागू करना, उनके स्वभाव में नहीं था। अपने इस स्वभाव के कारण आइजनहावर मैकार्थी की कार्यप्रणाली को समझने में असमर्थ रहे, परन्तु मैकार्थी ने 'प्रति साम्यवादी' एवं 'सैंसर व्यवस्था' में राष्ट्रपति की उदारवादी नीति की अवहेलना कर स्वयं की ख्याति को आघात पहुँचाया। मैकार्थी की इस साम्यवाद विरोधी नीति ने सेना एवं लब्ध प्रतिष्ठित अमरीकी वैज्ञानिकों पर आरोप लगाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित कर लिया। फलस्वरूप मैकार्थी ने पंचशती के अन्तिम चरण में अपने कार्य कलापों द्वारा स्वयं कुख्याति अर्जित कर ली और 1957 में उनका देहान्त हो गया।

1957 में मैकार्थी की मृत्यु के पश्चात् स्वतन्त्रता प्रेमी अमरीकी निवासियों को काफी शान्ति महसूस हुई परन्तु यह समस्या तदनुसार बनी रही कि नागरिक अधिकारों एवं शासकीय नैतिकता को सुरक्षित रखते हुए साम्यवादियों से शासन की सुरक्षा हेतु कैसे सतर्कता बरती जाय? ट्रूमैन का प्रशासन इस समस्या को यथाचित समाधान खोजने में असफल रहा था तथापि आइजनहावर के प्रशासन को भी कोई विशेष सफलता न प्राप्त हुई थी। इसी मध्य गणतन्त्रवादी शासन में वामपन्थियों के नागरिक अधिकारों पर अत्यधिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। यद्यपि इस बात को बारम्बार दोहराया गया कि सतर्कता हेतु लगाये गये उक्त प्रतिबन्ध पूर्णतः नैतिक थे एवं उनका चरित्र कदापि भी राजनैतिक नहीं था तथापि यह सत्य है कि जिन लोगों को इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत विदेशी यात्राओं से वंचित किया गया था उनके समक्ष अपनी सफाई देने का कोई भी मार्ग शेष नहीं था।

यद्यपि इसमें संशय नहीं है कि 1930-40 के मध्य अमरीका में साम्यवादी शक्तियां सरकार के विभिन्न शाखाओं में अत्यधिक सक्रिय थी। तत्कालीन वर्षों में अमरीकी निवासी यह समझ पाने में असफल रहे कि पूर्ण सतर्कता (सुरक्षा अनुसन्धान) एक असफल प्रयास था एवं उसकी सफलता ने दो शासकीय शाखाओं 'वैज्ञानिक अनुसंधान' एवं 'विदेश सेवा', के कार्यकलापों की दक्षता, को विनष्ट कर अमरीकी शक्ति को और अधिक हानि पहुँचायी।

राजनैतिक दल

आइजनहावर के काल में राजनैतिक शक्तियां भी अत्यधिक विभाजित थीं। स्वयं आइजनहावर अपने दल में गणतन्त्रवादियों के मतभेदों को समाप्त न कर सके थे। उनके अपने ही दल में दक्षिणपन्थियों ने उनकी योजनाओं का विरोध लोकतंत्रिकों से अधिक किया था। सीनेट सदस्य टॉफ्ट की मृत्यु के

पश्चात उनके सहयोगियों ने सरकार की राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय नीतियों का निरन्तर विरोध किया। आइजनहावर प्रत्यक्षतः समस्त गणतन्त्रीय प्रतिनिधियों को समर्थन प्रदान कर रहे थे, परन्तु अपरोक्ष रूप में वह एक नवीन राजनैतिक दल के निर्माण की योजना पर विचार मग्न थे। इसके साथ ही लोकतंत्रिक दल भी उत्तरी विकासशील एव दक्षिणी रूढ़िवादी दलों में विभक्त हो चुका था। उनके मध्य इस विभाजन का मुख्य कारण नीग्रों लोगों के नागरिक अधिकारों का मूल प्रश्न था। यद्यपि आइजनहावर को कांग्रेसके 1954 के चुनाव के पश्चात सदन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, परन्तु उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण अपने राजनैतिक दल के पतन को एक सीमा तक सीमित किया।

1956 के आम चुनाव में गणतन्त्रीय एवं लोकतन्त्रीय दल के नामांकित सदस्यों का चुनाव संघर्ष बाह्य रूप से घनिष्ठ प्रतीत होता था, परन्तु आइजनहावर की बहुमतीय विजय ने गणतंत्रिक दल को विजयश्री प्रदत्त की। इस विजय का पूर्ण श्रेय आइजनहावर की लोकप्रियता, चुम्बकीय व्यक्तित्व तथा जनप्रिय नीतियाँ थी।

इस असाधारण राजनैतिक विजय के पश्चात भी प्रशासन में सामंजस्य स्थापित न रह सका। 1957 में अमरीका की आर्थिक व्यवस्था का निरन्तर ह्रास हुआ तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई। 1957-58 के राष्ट्रीय बजट में भी एक वृद्ध हानि प्रदर्शित की गई, तथा इसके साथ ही आन्तरिक समस्याओं की जटिलता में पर्याप्त वृद्धि हो रही थी परिणामस्वरूप एक सशक्त एवं सुचारु केन्द्रीय सरकार को आवश्यक समझा जाने लगा जो देश को नियन्त्रित आर्थिक नीति की ओर अग्रसर कर सके। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमरीका को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही थी और उसे पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया जाने लगा।

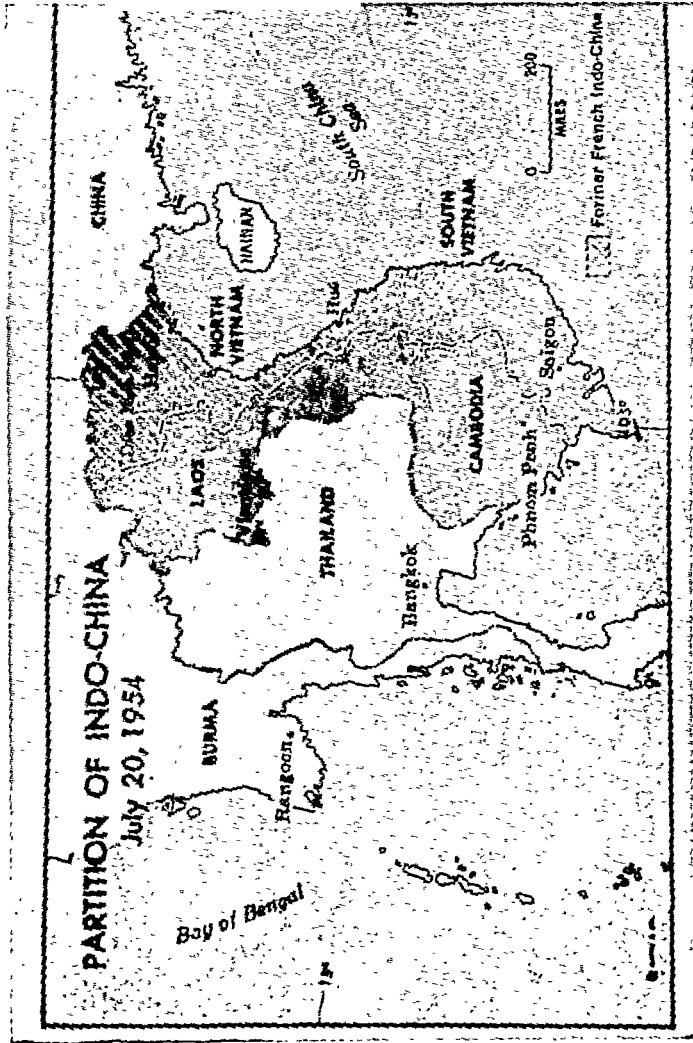
विदेश नीति

अमरीका 1952 के चुनाव के समय भी कोरिया समस्या के प्रति चिन्ताग्रस्त था और कोरिया में 'आरक्षी कार्यवाही' ने चुनाव गति में द्रुतता उत्पन्न कर दी थी। चुनाव अभियान में डिवाइट आइजनहावर जो द्वितीय विश्व-युद्ध के जनप्रिय विरोचित नायक थे और यूरोप में नाटों (उत्तरी एटलान्टिक संधि संघ) के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे, अपनी इस योग्यता एवं लोकप्रियता के आधार पर गणतन्त्रीय दल के राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित प्रत्याशी थे। राष्ट्रपति पद सम्भालने के पश्चात आइजनहावर

प्रशासन ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वैत नीति का परिपालन किया। राष्ट्रपति शान्ति का वातावरण निर्मित कर वार्ताओं के इच्छुक थे, किन्तु उनके राज्य सचिव जॉन फॉस्टर डलस को साम्यवादी राष्ट्रों के साथ समझौते का प्रश्न अनैतिक था। डलस ने 1956 में 'लाईफ' पत्रिका की भेंट वार्ता में अपनी नीति को स्पष्ट करते हुये कहा कि यदि युद्ध से भयभीत कोई देश हुआ, तो वह 'पूर्व पराजय' का प्रतीक था। आइजनहावर सम्भवतः एक व्यवसायिक सैनिक होने के कारण अनेक रक्तरंजित युद्धों एवं रक्तपात के योद्धिक अनुभव के परिपालन का संकट नहीं उठाना चाहते थे। यद्यपि जॉनफॉस्टर डलस को राष्ट्रपति पूर्ण सम्मान देते थे, उनके विचार में साम्यवादी तथा असायम्वादी अपने अनवरत संघर्ष को त्याग कर शान्तिमय वातावरण का निर्माण कर सकते थे। इसके फलस्वरूप आइजनहावर प्रशासन ने 'शीत गृह-युद्ध' में 'कठोर एवं सुलभ' नीति का पालन किया। फलतः आइजनवाहर ने अपने चुनाव अभियानों में कोरिया में शांति स्थापना करने के जो आश्वासन दिये, वह उन्होंने चुनावोपरान्त तथा स्ववचनानुसार कोरिया में स्वयं पदार्पण कर 1953 के हुये युद्ध-विराम के द्वारा अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण किया। इस युद्ध विराम के उपरान्त कोरिया की सीमाओं तथा युद्ध वन्दियों की समस्याओं से सम्बन्धित वार्ता कई माह तक चलती रही।

कोरिया युद्ध के समाधान का यह अर्थ कदापि नहीं था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक स्थिति पूर्णतया सुगम एवं सुस्पष्ट हो गई थी क्योंकि राजनैतिक पद पर अशान्ति की छाया आच्छादित थी। इस स्थिति को विक्षेपित करने हेतु आइजनहावर तथा उनके राज्य सचिव जॉन फॉस्टर डलस ने कठिन परिश्रम किया। राष्ट्रपति ने शान्ति व्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु अपने भाषणों द्वारा विश्वजन को सम्बोधित किया। जॉन फॉस्टर डलस ने विश्व भ्रमण कर अमरीकी नीति का विश्लेषणात्मक तर्क प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष भाषण में कहा कि विश्व में नवीन राजनैतिक भाषा 'परमाणविक' युद्ध शैली की भाषा है। राष्ट्रपति ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि निसन्देह अमरीका परमाणु अस्त्रनिर्माण कर रहा था, परन्तु अमरीका शांति के लिये सदैव प्रयत्नशील रहा था, और रहेगा। राष्ट्रपति ने परमाणु शांति व्यवस्था योजना का आह्वान किया, और विश्वजन को आत्मिक एवं मानसिक रूप से भयमुक्त करने का आश्वासन प्रदत्त किया।

यद्यपि गणतंत्रवादी अधिवक्ताओं ने चुनाव से पूर्व निरन्तर ट्रूमैन की विरोधी योजनाओं को अत्याधिक सौम्य तथा प्रजातान्त्रिक बताते हुये, 'लोह पट' के उस पार के लोगों की स्वतंत्रता के लिये साम्यवादी चीन के विरुद्ध सैनिक



हिन्द-चीन विभाजन (जुलाई 20, 1954)

कार्यवाही करने की माँग की; चुनाव के पश्चात उन्होंने भी विरोधी योजनाओं का ही पालन किया क्योंकि वे स्वयं भी तृतीय विश्व युद्ध के संकटीय संशय में भयग्रस्त थे । इन्हीं कारणों से इसके अधिवक्ताओं ने दक्षिणीपंथी गणतंत्रवादियों के विरोध के पश्चात भी समझौता संधियों को स्वीकार कर कोरिया युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया । इसी मध्य उन्होंने सुरक्षा संधि-तंत्र का विकास किया जिसके ऊपर ही निरोधी योजनायें आधारित थी । कांग्रेस ने भी प्रतिवर्ष कई करोड़ डालर की सहायता पारित की । इस प्रशासन की प्रमुख समस्या कोरिया युद्ध को समाप्त करना था । निरन्तर वार्तालापों के कारण जून, 1953 में युद्ध बंदियों के विनिमय पर तथा जुलाई में युद्ध बन्द करने हेतु संधि पर हस्ताक्षर हो गये ।

कोरिया को तत्कालीन सैन्य स्थित के अनुसार विभाजित कर दिया गया । संधि के मार्ग में मुख्य बाधा उत्तरी कोरिया की युद्ध बंदियों को वापस कर देने की अनवरत माँग में निहित था । संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगभग 20 हजार युद्ध बंदियों को रोक रखा था और वह युद्ध बंदी पुनः साम्यवादियों के पास वापस नहीं जाना चाहते थे । अन्ततोगत्वा यह निर्णय लिया गया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध बंदियों को वापस नहीं भेजा जायेगा तथा इस समस्या का समाधान पाँच असम्बद्ध राष्ट्रों की मध्यस्थता द्वारा किया जायेगा । उसी समय 1946 में फ्रांस के उपनिवेश में भी युद्ध चल रहा था । वियतमिन्ह साम्यवादी शक्तियों ने लगभग सम्पूर्ण उत्तरी वियतनाम पर अधिकार कर लिया था । हिन्दचीन पर साम्यवादी अधिकार से सुरक्षा हेतु 1954 में जॉन फॉस्टर डलस ने साम्यवादी चीन को यह चेतावनी दी कि वह वियतमिन्ह की किसी भी प्रकार से सहायता न करे । जुलाई, 1954 में जेनेवा संधि ने दोनों वियतनाम को अस्थायी रूप से विभाजित कर दिया । तथा वहाँ की जनता-को उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम में रहने का अधिकार दिया गया । यह निर्णय लिया गया कि 1956 के राष्ट्रीय चुनाव द्वारा दोनों वियतनाम के पुर्नगठन पर विचार किया जायेगा परन्तु अमरीका ने फ्रांस के उपनिवेशी कार्य को स्वयं करना आरम्भ कर दिया इसमें आर्थिक व व्यापारिक सहायता निहित थी । अमरीका नवीन प्रधान मंत्री नो दीन्ह-दाँयम को सहायता प्रदान करने लगा, परन्तु उसने 1956 के प्रस्तावित चुनाव की घोषणा नहीं की । आइजनहावर के अनुसार यह निश्चित था कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की ही विजय हुई होती तथा इस प्रकार भविष्य के लिये दुर्घटनाओं का मार्ग खोल दिया गया । सुदूर पूर्व में अमरीका का तीसरा लक्ष्य फारमोसा था । आइजनहावर ने राष्ट्रवादी चीन के च्यांग-काई-शेक को यह आश्वासन देना प्रारम्भ कर दिया कि वे

ट्रूमैन की नीतियों के विपरीत उनको सहायता प्रदान करेंगे। अमरीका में इस नीति को प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ परन्तु इससे यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं फारमोसा भी साम्यवादी चीन के द्वारा न अधिकृत कर लिया जाये। 1955 में आइजनाहावर ने कांग्रेस से सेना के प्रयोग का अधिकार प्राप्त कर लिया किन्तु सितम्बर, 1958 में साम्यवादी चीन द्वारा फारमोसा में स्थित राष्ट्रवादी चीन के पड़ोसी द्वीपों 'किमोई' तथा 'मात्सू' (माडजू) पर आक्रमण से समस्या पुनः गंभीर हो गई। अमरीका ने साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश देने तथा राजनैतिक मान्यता देने से अस्वीकार कर दिया। अमरीकी शासन ने एशिया में साम्यवादियों के प्रगति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये यूरोप जैसे उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन (नाटो) की सुरक्षात्मक तंत्र के निर्माण की कल्पना की, परन्तु एशियाई क्षेत्र के प्रमुख देश विशेषतया भारत ने असम्बद्ध नीति का पालन किया। सितम्बर, 1953 में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संघ (सीटो) की स्थापना की परन्तु एशिया के तीन देश पाकिस्तान, थाईलैण्ड तथा फिलीस्तीन ने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की जिसके कारण यह एक अप्रभावशाली संघ बन कर रह गया।

यूरोप तथा पश्चिमी एशिया

ट्रूमैन प्रशासन ने पश्चिमी यूरोप में जो प्रमुख समस्या उत्पन्न कर दी थी, वह पश्चिमी जर्मनी को सुरक्षात्मक संधितंत्र में लाने की थी। अमरीकी सैन्य विशेषज्ञ, रूसी विस्तारवादी नीति के विरुद्ध पश्चिमी यूरोप को सुरक्षा प्रदान करने में विश्वास रखते थे परन्तु इसके लिये जर्मनी का सहयोग आवश्यक था और फ्रान्स जर्मनी के पूर्व सैन्यीकरण नीति के विरुद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति के कारण फ्रांस का चिन्तित होना आश्चर्यजनक नहीं? डलस के प्रयत्नों के फलस्वरूप उसके इस लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव हो सकी और अन्ततोगत्वा 23 अक्टूबर, 1954 को पेरिस में जर्मन संघीय गणतंत्र 'नाटो' (उत्तरी एटलांटिक संधि संघ) का सदस्य बना लिया गया। इसी मध्य मार्च, 1953 में स्टालिन की मृत्यु के कारण सोवियत संघ में उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई परन्तु खुर्रुचेव की विजय के साथ ही विवादग्रस्त मतभेद समाप्त हो गये। नवीन रूसी शासन ने स्टालिन युग की सर्वसाधारण रूप में कटु आलोचना की, तथा सुधारों का आश्वासन प्रदान किया, यद्यपि अभी भी यह निश्चित नहीं था कि नवीन परिवर्तन वास्तविक थे अथवा प्रचारों में निहित थे। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में सोवियत संघ

की मैत्रीपूर्ण नीतियों का उदाहरण केवल मई, 1955 के आस्ट्रिया के साथ शान्ति सम्झौते में प्राप्त होता है। तत्पश्चात् जुलाई में जेनेवा के 'शिखर सम्मेलन' ने पुनः आशा का संचार किया परन्तु इसके कोई ठोस परिणाम प्राप्त न हो सके। 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी के साथ जो दर्वर व्यवहार किया वह अमरीका के लिये निराशाजनक सिद्ध हुआ। अमरीका केवल हंगरी के शरणार्थियों को ही स्थान प्राप्त करा सका।

1956 में अमरीकी विदेश नीति पश्चिमी एशिया की दिशा में आकर्षित होने लगी। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की भौगोलिकता तथा खनिज तेल के प्रचुर भंडार थे। इस क्षेत्र के अरब निवासी धीरे-धीरे राष्ट्रवादी होने लगे थे। अमरीका द्वारा उनकी मित्रता प्राप्त करने के प्रयास में इजराएल-अरब मतभेद अवरोधित था। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन व फ्रांस से भी अरबों का मतभेद था। 1955 में ब्रिटेन ने 'पश्चिमी एशिया सुरक्षा संधि' की स्थापना करने का प्रयत्न किया, परन्तु केवल ईराक ही ऐसा अरब राज्य था जिसने इस संगठन की सदस्यता स्वीकार करने में रुचि प्रदर्शित की। इसके अन्य सदस्य-ईरान, तुर्की, व पाकिस्तान थे। अन्य अरब राज्यों ने इस संगठन के प्रति अपनी निजी अरुचि प्रकट की जिसमें मुख्य समस्या, मिस्र, के नासिर ने उत्पन्न की थी। जुलाई 1956 में डलिस ने नील नदी पर 'आस-वान बांध निर्माण हेतु आर्थिक सहायता देना अस्वीकार कर दिया। इसका कारण मिस्र एवं सोवियत संघ की मित्रता, सैन्य एवं आर्थिक सहायता था। नासिर ने इसके विरोध में स्वेज नहर का 'राष्ट्रीय करण' कर दिया। अब तक स्वेज नहर पर 'अन्तर्राष्ट्रीय' निगम का अधिकार था जिसने ब्रिटेन तथा फ्रांस के पक्ष में नासिर पर दवाव डालना स्वीकार नहीं किया। अक्टूबर में इजराएल ने ब्रिटेन तथा फ्रांस की सहायता से मिस्र पर आक्रमण कर दिया। अमरीका ने इस कार्य का समर्थन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार 'विश्व मत' को मान्यता देकर इजराएल, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपनी सेनाओं को पुनः लौटने को कहा तथा नासिर ने भी किसी प्रकार की सुविधा प्रदान किये बिना स्वेज नहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन घटनाओं ने पुनः अरब राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया तथा पश्चिमी एशिया में ब्रिटेन के प्रभाव को और अधिक न्यून कर दिया। इन कारणों से ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्धों में कटुता उत्पन्न हो गई। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के फलस्वरूप फ्रांस तथा ब्रिटेन ने अपनी सेना को हटा लिया और स्वेज संकट के विस्तार को रोक दिया परन्तु पश्चिमी एशिया में साम्यवाद के 'अन्तः स्पदन' (घुसपैठ) के

कारण अमरीका का ध्यान एशिया के इस क्षेत्र की ओर केन्द्रित था। इस समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी नीति को स्पष्ट किया। राष्ट्रपति ने कहा, कि निस्सन्देह पश्चिमी एशिया इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है, परन्तु 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक नवीन एवं संकटपूर्ण स्थिति का विस्फोट इस क्षेत्र में हो रहा है। रूस अपनी 'शक्ति राजनीति' के प्रयास हेतु पश्चिमी एशिया पर अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था अमरीका किसी भी अन्य 'शक्ति के द्वारा पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, आर्थिक विकास का तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहन नहीं देगा। इसके विपरीत अमरीका पश्चिमी एशिया के राज्य क्षेत्रों को आर्थिक विकास हेतु सहायता प्रदत्त करेगा और सैनिक सहायता की भी योजना प्रस्तुत करेगा। अमरीकी सदैव प्रत्येक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी एशिया की सरकारों को प्रत्येक रूप से सहायता हेतु तत्पर है। राष्ट्रपति के इन राजनीतिक प्रयोजनों को आइजनहावर सिद्धान्त भी कहा जाता है। इसके उपरान्त भी राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को पूर्ण रूपेण सुरक्षित बनाए हुये थे।

इस मध्य अमरीका व सोवियत संघ युद्ध के नवीन अस्त्रों के निर्माण में व्यस्त थे। इसमें से कुछ हिरोशिमा व नागासाकी पर डाले गये परमाणु बमों से अधिक क्षतिग्रस्त करने की क्षमता रखते थे। अक्टूबर नवम्बर, 1957 में सोवियत संघ द्वारा अन्तरिक्ष पर भेजे गये मानव निर्मित उपग्रहों के कारण अमरीका को अपने तकनीकी ज्ञान के विकास पर गहरा आघात लगा। यह निश्चित हो चुका था कि दोनों शक्तियों के पास ऐसे शस्त्र एकत्रित हो चुके थे जिनकी क्षतिकारक शक्ति सीमित नहीं थी। युद्ध अब केवल राष्ट्रीय नीति के निर्धारक नहीं रहे थे। जो कोरिया युद्ध से स्पष्ट था। अस्त्रपरिसीमन के समस्त प्रयास 1957 तक असफल सिद्ध हो चुके थे।

नवम्बर, 1958 में 'लोकतांत्रिक दल' ने कांग्रेस में बहुमत प्राप्त कर लिया यद्यपि आइजनहावर अभी भी उतना ही लोकप्रिय थे, उनके नेतृत्व में विश्वास धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। अन्त में उन्होंने अपने विकासशील आधुनिकता के सिद्धान्तानुसार सोवियत संघ से मित्रता स्थापित करने की चेष्टा की फलस्वरूप खुर्र्शेव ने अमरीका की यात्रा की, परन्तु किसी सामंजस्य स्थापित होने से पूर्व ही सोवियत संघ में अमरीका के युद्ध विमान (यूटू) के मार गिराने की घटना घटित हो गई। इस घटना को रूस की सरकार ने

अपने सैन्य राष्ट्रों के प्रति अमरीकी सैन्य गुप्तचर की आयोजित क्रिया समझा। इससे पूर्व रूस के प्रधानमंत्री निखिता खुरश्चेव के अमरीका आगमन के द्वारा जो रूस अमरीकी राजनैतिक वातावरण में सहजता उत्पन्न हुई थी, वह पुनः धूमिल हो गई। इसके अतिरिक्त इस घटना का तत्कालिक महत्व यह हुआ, कि रूसी प्रधानमंत्री खुरश्चेव को प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को स्थगित करने का अवसर प्राप्त हो गया तथा अमरीकी राष्ट्रपति को रूस यात्रा के प्रति आमंत्रण का निर्वर्तन कर दिया।

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अतिरिक्त राष्ट्रपति आइजनहावर को अफ्रीका एवं क्यूबा में भी अमरीकी वैदेशिक नीति का कठिनाई एवं संकट पूर्ण परिस्थिति में निदेशन करना पड़ा। आइजनहावर अपने शासन काल में अत्यधिक सफल नहीं हो सके क्योंकि उनकी गोलार्ध नीति ने अंतिम चरण में एक ऐसी कटुता उत्पन्न कर दी, कि जिसके द्वारा आइजनहावर कूटनीतिक क्षेत्र में एक सफल नायक नहीं कहे जा सकते थे। यद्यपि आइजनहावर एक लोकप्रिय नायक थे परन्तु विशिष्ट राष्ट्रपति की श्रेणी में उनकी गणना नहीं की जा सकती। उनकी गृह एवं विदेश नीति ने अपनी जनता एवं अन्तर्राष्ट्रीय पद पर विशेष ख्याति अर्जित नहीं की।

आइजनहावर ने गृह नीति के क्षेत्र में आर्थिक नागरिक, शैक्षिक, एवं प्रशासनिक क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण कार्य किये परन्तु अपनी वैदेशिक नीति में पश्चिमी एशिया बगदाद समझौता तथा दक्षिण पूर्व एशिया संधि संघ (सीटो) के संगठन के द्वारा अमरीकी विदेश नीति को विशेष प्रौढ़ता एवं परिपक्वता प्रदान नहीं की। इन्हीं सब कारणों ने आइजनहावर के लोकप्रिय व्यवितत्व को भी धूमिल कर दिया।

आर्थर लार्सन ने अपनी पुस्तक 'ए रिपब्लिकन लुक्स एट हिज पार्टी, में इस अभिधारणा की अभिव्यक्ति करते हुये इस तथ्य को समर्थन दिया कि आइजनहावर के नेतृत्व में गणतन्त्रीय दल प्रथम बार अमरीकी राजनीति का हृदय स्थल बना। आइजनहावर युग को लार्सन ने 'अमरीकी मतैक्य' का युग माना। आइजनहावर के प्रशासन पर प्रशंसा एवं अप्रशंसा के रूप में दोनों प्रकार से आलोचनात्मक प्रहार हुये। इसका मुख्य कारण यह था, कि आइजनहावर के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के समय अमरीका गम्भीर आन्तरिक एवं वाह्य राजनीति से ग्रस्त था। कुछ इतिहासकारों ने आइजनहावर को लोकप्रिय एवं समस्त समस्या निवारण युग के निर्माता की संज्ञा दी। परन्तु राज-

नैतिक लेखकों ने आइजनहावर युग को गिथिलता, भौतिकवाद तथा स्वसंतुष्टि का युग बताया । सम्भवतया आइजनहावर की उपलब्धियाँ एवं उसकी त्रुटियाँ अन्य सफल राष्ट्रपतियों की भाँति थी परन्तु उसके अवगुणों अथवा दोषों को ही अधिक महत्व प्रदान किया गया । इसके उपरान्त भी वाल्टर लिप्पमैन के अनुसार '1952 में आइजनहावर का होना उतना ही अनिवार्य था, जितना 1789 में जार्ज वाशिंग्टन का होना' । सम्भवतः उपरोक्त कथन में यथार्थता थी क्योंकि आइजनहावर ने अपने प्रथम चरण में वह कार्य किये जो लोकतांत्रिक प्रशासन से सम्भावित नहीं थे ।



अध्याय 12

नव निर्माण युग :

सन् 1960 में राष्ट्रपति आइजनहावर के कार्यकाल का दूसरा चरण समाप्त हुआ। अपने शासन के आठ वर्षों को व्यतीत करने के पश्चात् वह अभी भी कार्यकुशल एवं योग्य थे परन्तु संविधान के बाइसवें संशोधन के द्वारा उन्हें तीसरे सत्र के चुनाव से वंचित कर दिया गया था। अपने इस प्रशासन काल में अमरीकी समाज की वैदेशिक नीति का सामान्य उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार का अवरोध करना था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर एक ओर चीन व सोवियत संघ का संयुक्त मोर्चा, दूसरी ओर अमरीका की विश्वव्यापी शक्ति थी, परन्तु इस महाशक्ति के होते हुये भी आइजनहावर काल के अन्तिम दिनों में अमरीकी वैदेशिक नीति निरन्तर असफल होती रही। विश्व में नवीन प्रवृत्तियों के उत्पन्न हो जाने से वातावरण भी अमरीका के अनुकूल नहीं था। साम्यवाद की लहर अन्य राष्ट्रों में तरंगें लेने लगी थी। इन असफलताओं के होते हुए भी आइजनहावर का युग एक सफल युग कहा जाता है। 1960 के प्रारम्भ में ही अमरीका में नये राष्ट्रपति के चुनाव का उत्साहमय वातावरण आ गया था।

चुनाव

1960 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान में गणतन्त्रवादियों में निराशा की भावना व्याप्त थी। इससे पूर्व 1958 के कांग्रेस के मध्यवर्ती चुनाव में लोकतांत्रिक दल ने बहुमत प्राप्त किया था। 1957-58 के आर्थिक अवरोधन, शेरमन आडमस पडयन्त्र एवं कृषि तथा विदेश नीतियों में तनावों के कारण अधिकांश अमरीकी जनसमुदाय में गणतन्त्रवादियों के प्रति खिन्नता की भावना उत्पन्न हो गयी थी। गणतन्त्रवादियों ने उपराष्ट्रपति निक्सन को राष्ट्रपति पद के लिये मनोनीत किया था। निक्सन गहन बुद्धि के एक तीव्र राजनीतिज्ञ थे तथा

अपनी नीतियों के कारण अमरीकी समाज में अत्यन्त लोकप्रिय हो चुके थे। 1959 में खुरुश्चेव के साथ मास्को की "किचिन वहस" में उन्होंने अमरीकी जनतन्त्र की नयी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उनके दल के लोगों ने उन्हें सोवियत संघ के समक्ष खड़े होने वाला पहला व्यक्ति बताया एवं उन्हें पूर्ण बहुमत से गणतन्त्रवादियों के नेतृत्व के लिये राष्ट्रपति पद के लिये मनोनीत किया गया। लोकतांत्रिक दल ने इस बार पूर्व दो सत्रों में नामांकन के लिये पराजित सदस्य जॉन एफ कॅनेडी को पद हेतु मनोनीत किया। नामांकन के लिये उन्होंने अपने तीन प्रमुख प्रतिनिधियों को भारी मतों से पराजित किया। दल में पर्याप्त समर्थन होते हुए भी स्टीवेंसन ने इस बार नामांकन अभियान में भाग नहीं लिया। जॉन कॅनेडी एक मेघावी एवं सम्पन्न परिवार द्वारा पोषित राजनीतिज्ञ था। वे मैसाचुसेट्स के एक करोड़पति व्यक्ति थे एवं अपने राज्य से सीनेट के एक सदस्य थे। उनके पिता जोजफ कॅनेडी बैंकिंग का रोजगार करते थे, तथा कई वर्षों तक अमरीका के राजदूत के रूप में यूरोपीय देशों में भी रह चुके थे। जॉन कॅनेडी का जन्म 29 मई, 1917 को हुआ था। इस प्रकार चुनाव के समय उनकी अवस्था केवल 43 वर्षों की ही थी। जॉन कॅनेडी रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के व्यक्ति थे तथा उनके कुल के पुरातन लोग आयरलैंड के रहने वाले थे। 1960 में रोमन कैथोलिक अमरीका के अल्पसंख्यक के रूप में प्रवासी थी। गणतन्त्रवादियों ने उन्हें पोप का पुरुष कह कर बदनाम भी किया था। नामांकन चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वन्दी लिडन जॉनसन को प्रथम बैलट पर बहुमत से पराजित किया, बाद में उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत करके अपनी ओर मिला लिया। चुनाव अभियान के समय में धर्म के आरोपों को लेकर उत्तरी व दक्षिणी राज्यों में कई विवाद उठ खड़े हुये। निक्सन जहाँ अपनी वैदेशिक नीति में सक्षमता के कारण विख्यात हो रहे थे। कॅनेडी ने आइजनहावर के खोखले प्रशासन तथा सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में गणतन्त्रवादियों की विफलता पर आलोचना करते हुए अपने अभियान को आरम्भ किया था। उनके "कर्म और त्याग" के नारे ने अभियान में एक नया समाँ बना दिया था। व्यक्तित्व की एक तीव्र टक्कर 1960 के राष्ट्रपति चुनाव में थी। निक्सन ने जनता में गणतन्त्रवादियों पर कम विश्वास देखते हुये जनमत पर अच्छे अनुभवी व्यक्ति चुनने का अभियान चलाया। उनकी पराजय का एक कारण उनकी टेलीवीजन पर कॅनेडी के साथ वहस होड़ भी थी। इस वहस होड़ से कॅनेडी को अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त हो गयी। जॉन कॅनेडी को 303/219 के अनुपात में चुनाव में तथा 34.22 मिलियन की अपेक्षा 34.10 मिलियन के अनुपात में जनमत से



राष्ट्रपति कॅनेडी और उनकी पत्नी (नवम्बर 22, 1963, डलेम
हवाई अड्डे पर) अमरीका के पैतीसवें राष्ट्रपति

विजय प्राप्त हुयी। इस प्रकार नये देशक के साथ अमरीका के इतिहास का एक नया युग प्रारम्भ हुआ। जान एफ० कॅनेडी अमरीका के सबसे कम उम्र के तथा प्रथम कैथोलिक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति आइजनहावर का युग अमरीका के इतिहास में संघर्षमयी काल भी कहा जा सकता है यद्यपि उनको लोकतन्त्रियों ने “गप्पी और गोल्फ” का व्यक्ति बताया और वदनाम किया, फिर भी वह अपने लगन व साहस के लिये हमेशा स्वदेश व विदेश में प्रशंसा के पात्र बने रहे। उनके प्रशासन के दूसरे सत्र में लोगों ने यह विश्वास किया कि वाइसेवं संशोधन में तीसरे सत्र में वंचित होने के कारण वह कार्य में अधिक ध्यान नहीं देंगे परन्तु उनके प्रशासन काल के अन्तिम क्षण सर्व तीव्र गतिविधियों से भरे हुए थे। 19५5 से 1961 तक कांग्रेस में लोकतांत्रिक सदस्य की अधिकता थी, परन्तु आइजनहावर का कांग्रेस पर पूर्ण नियन्त्रण बना रहा। अपने शासन काल में उन्होंने एक सौ उन्हत्तर बार राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग किया उनके युग में अमरीकी अर्थव्यवस्था की उन्नति हुई। आय व्ययक हमेशा संतुलित बना रहा तथा मूल्यों में न्यूनता बनी रही। उत्तरी राज्य में एक बहुत बड़े सेन्टलारेंस जल सम्वाहन योजना का कार्य सम्पन्न हुआ जो कि कनाडा के साथ संयुक्त रूप में बनायी गयी थी एवं बड़ी झीलों के शहरों के समुद्र पोतों में परिवर्तित करती थी। पुरातन गौरव में अब पूरे पचास तारे विद्यमान हो गये थे। 1959 में हवाई एवं अलास्का राज्यों को अमरीकी राज्य संघ में सम्मिलित कर लिया गया था।

जॉन एफ कॅनेडी

20 जनवरी, 1961 को स्वतंत्रता, शांति एवं जनतंत्र के संरक्षक के रूप में जॉन फिट्सजेराल्ड कॅनेडी अमरीका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुये। अपने उद्घाटन समारोह के भाषण में उन्होंने वर्तमान युग की नवीन नीतियों से देश को परिचित किया। उन्होंने अमरीका को एक गम्भीर परिस्थिति से गुजरता हुआ बताया तथा विदेश नीतियों में नवगति लाने का विश्वास दिलाया। राष्ट्रपति कॅनेडी ने अपने प्रशासन में युवा एवं विवेकी लोगों को स्थान दिया। स्वयं अपने छोटे भाई रावर्ट को एटोर्नी जनरल पद पर नियुक्त किया। रावर्ट कॅनेडी अनुभवहीन तो अवश्य थे परन्तु अपने ज्ञान के लिये सर्व विख्यात थे। सुव्यवस्थित शासन होने के लिये योग्य व्यक्तियों का होना अति आवश्यक था। कॅनेडी ने योग्य और युवा व्यक्तियों को लाने के लिये ‘दल गुट’ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। यह एक आश्चर्यपूर्ण घात थी

कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अधिकांश पद विरोधी दलों को दिये थे। विदेश सचिव डीन रस्क बने। यह राँकफैलर न्यास के अध्यक्ष भी थे। आइजनहावर काल के उपसचिव एवं न्यूयार्क के वैंक नीतिज्ञ डगलस डिलन को कोप सचिव बनाया। प्रसिद्ध फोर्ड कार की कम्पनी के अध्यक्ष राबर्ट स्ट्रेज्मेकनमारा जो एक अत्यन्त कुशल प्रशासक थे, व सुरक्षा अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे, उनको सुरक्षा सचिव का पद मिला। आडिजोना के पुराने प्रतिनिधि स्टीवर्ट ली यूडोल को गृह सचिव तथा मिनिसोटा के भूतपूर्व राज्यपाल ओरवील एल० फ्रीमेन को कृषि सचिव बनाया। आर्थर जे० गोल्डेनवर्ग जो श्रम विधि के ज्ञाता व श्रम के एक प्रसिद्ध वकील थे, श्रम सचिव बने। इस प्रकार सम्पूर्ण मंत्रिमंडल, सक्षम, युवा व योग्य लोगों से परिपूर्ण था।

कैनेडी ने सामाजिक क्षेत्र में अस्पताल की नयी बीमा योजनायें बनाई, एवं स्कूलों की सहायता धनराशि में आवश्यक वृद्धि के आदेश दिये परन्तु वह एक कैथोलिक समुदाय के राष्ट्रपति थे इसलिये धर्म के नाम पर कांग्रेस में उन्हें कई विषयों पर सहयोग नहीं प्राप्त हुआ।

प्रारम्भिक कार्यकाल में कैनेडी ने शीत-युद्ध की ज्वाला को रोकने के प्रयास किये तथा देश की अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये अंतरिक्ष एवं अन्य सुरक्षा व वैज्ञानिक उन्नति की नवीन योजनायें आरम्भ कीं। उन्होंने एक "शान्ति दल" जो मुख्य रूप से 'कैनेडी सेना' कहलाती थी, की स्थापना की। जिसमें नारी-पुरुष दोनों को ही सेवा योजित किया गया था। इस दल को विश्व के पचास गरीब व दयनीय परिस्थितियों वाले देशों में जाकर गरीबी मिटाने एवं विकास के विभिन्न तरीकों की शिक्षा प्रदान करने का कार्य दिया गया था। व्यापार में व्यर्थ के व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करने के लिये कैनेडी ने कांग्रेस के सम्मुख अक्टूबर, 1962 में एक नया 'व्यापार विस्तार अधिनियम' प्रस्तुत किया। थोड़े वाद-विवाद के उपरान्त कांग्रेस ने इस अधिनियम को पारित कर दिया।

राष्ट्रपति की यह चिर अभिलाषा थी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में मानव चन्द्रमा तक पहुँचे। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिये उन्होंने कांग्रेस से एक दीर्घकालीन योजना पर हस्ताक्षर भी करवाए। इस योजना में 25 हजार मिलियन डॉलर व्यय का एक दस वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया था। टैलस्टार संचार उप-ग्रह कैनेडी प्रशासन की एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसके द्वारा सुदूर विश्व से दूरभाष एवं टेलीवीजन संचार के कार्य सम्पादित हो सके।

अगस्त, 1962 में कांग्रेस के एक विधेयक के द्वारा इस उपग्रह प्रणाली को सरकारी नियंत्रण में एक निगम के अर्न्तगत स्थापित कर दिया गया। कॅनेडी प्रशासन के प्रारम्भिक दिनों में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य स्टील के मूल्यों पर सरकारी नियंत्रण था।

क्यूबा अमरीका की नासिका पर एक छोटा सा राष्ट्र है, जो साम्यवादियों की ग्रस्त में आ चुका था। रूसी सहायता से क्यूबा फीडल कैस्ट्रो (कॉस्ट्रो) के नेतृत्व में अमरीका की प्रति नीति का स्वरूप बना हुआ था। आइजनहावर के समय में ही यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध कला का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया था। इन गतिविधियों से लैटिन अमरीका के अन्य छोटे राष्ट्रों में जनतंत्र के लिये अत्यन्त एक भय स्थापित हो गया था। कॅनेडी ने राष्ट्रपति पद पर आसीन होते ही संकट के निवारण के लिये दृढसंकल्प किया और इसका अवसर अमरीका की गुप्तचर एजेंसी की योजना ने प्रदत्त किया। वह प्रत्यक्ष रूप से युद्ध प्रारम्भ नहीं करना चाहता था, इस कारण अप्रैल, 1961 में परिवर्तित नयी गुप्त योजना तैयार की गयी। इस योजना के अर्न्तगत 'बे ऑफ पिंग्स' पर क्यूबा के निर्वासित जन की प्रशिक्षित सेना को भेजा गया, यह अभियान नितान्त असफल रहा। यद्यपि कॅनेडी ने इस असफलता को स्वीकार किया, सोवियत संघ ने अमरीका के इस कार्य को कूटनीतिज्ञ असभ्यता की संज्ञा दी एवं क्यूबा की सरकार को समस्त सहायता देने का वचन दिया।

अमरीका की उदारनीति के होते हुये भी सोवियत संघ की सहायता एवं 'पक्षपात उष्णता' के कारण क्यूबा निरन्तर अमरीका के विरुद्ध रहा। अक्टूबर, 1962 में जब राष्ट्रपति कॅनेडी का ध्यान एशियाई समस्याओं की ओर आकर्षित था, अमरीका के 'यूटू' वायुयानों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि क्यूबा में रूसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकर्ता मिसाइल्स एवं युद्ध सामग्री के निर्माण में संलग्न हैं। इन मिसाइलों में अणु अस्त्र लगे हुये थे एवं इनके लक्ष्य अमरीका के बड़े एवं प्रमुख स्थान थे। यह गतिविधियाँ मनरों सिद्धांत के विल्कुल विपरीत थी। अमरीकी समुदाय इस प्रकार की योजनाओं से अत्यन्त आश्चर्य चकित हो गया। राष्ट्रपति ने 1962 के क्यूबा के इस संकट में अपनी कूटनीतिक बुद्धि एवं साहस का अतुल उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने एक दीर्घ योजना के द्वारा क्यूबा पर पूर्ण अधिकार कर लेने का निश्चय किया। 22 अक्टूबर 1962 को एक रूसी जहाज जो शस्त्रागार से लदा हुआ क्यूबा की ओर जा रहा था, अमरीकी जल सेना ने अपने अधिकार में कर लिया। यह प्रत्यक्ष रूप

से युद्ध चिन्ह था। राष्ट्रपति ने यह चेतावनी दी कि यदि रूसी मिसाइल नही हटाई गई तो अमरीका क्यूबा पर तुरन्त आक्रमण कर देगा। एक सप्ताह के घोर वाद-विवाद एवं उष्ण वातावरण के पश्चात् 28 अक्टूबर को सोवियत संघ ने अमरीका की समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया। कैंनेडी की यह विजय उनके प्रशासन काल का बहुत ही सराहनीय कार्य था। रूस की सहायता के प्रति क्यूबा के फीडल कास्ट्रो ने अपने अस्थिर व चंचल स्वभाव का परिचय देते हुये भिन्न वक्तव्य दिये। उन्होंने जनवरी 1963 को क्यूबा में कहा, कि मिसाइल आयात रूसी विचार था। यही वक्तव्य उन्होंने मार्च 1963 में 'ला मान्ड' के क्लॉड जूलियन तथा अमरीकन ब्राडकास्टिंग कम्पनी के लीसा हार्वड को दिया। इसके विपरीत अक्टूबर में 'न्यूयार्क टाइम्स' के हरवर्ट मैथ्यूज को कास्ट्रो ने कहा, कि युद्ध सामग्री संग्रह नितान्त क्यूबा की निजी नीति थी, नवम्बर में 'ल' एक्सप्रेस के जीन डेनियल को इसे रूस की नीति बताया। जनवरी 1964 में पुनः जब मैथ्यूज ने उनसे डेनियल की समाचार विज्ञप्ति के प्रति पूछा, तो कास्ट्रो ने फिर इसे क्यूबा की नीति ही बताया। अक्टूबर 1964 में 'न्यूयार्क टाइम्स' के सीरस सलजवर्गर को उन्होंने इसे रूस-क्यूबा की संयुक्त नीति उद्घोषित किया। इससे पूर्व अगस्त, 61 में "वर्लिन दीवार" की गतिविधियों में अमरीकी प्रशासन को भीषण आघात पहुँचा था।

उपरोक्त तथ्य कास्ट्रो की मानसिक एवं वैचारिक प्रणाली के द्योतक हैं। खुरश्चेव ने रूस की सुप्रीम सोवियत को अपने वक्तव्य में कहा, कि रूस ने क्यूबा की माँग पर युद्ध सामग्री का निर्यात किया है।

क्यूबा संकट के निवारणके पश्चात् अणु शस्त्रों के निर्माण की एक दौड़ प्रारम्भ हो गई। सितम्बर, 1961 में सोवियत संघ ने कई परमाणु परीक्षण किये जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय वायु मंडल में अत्यन्त प्रदूषण का वातावरण उत्पन्न हो गया था। अमरीका ने इसका तीव्र विरोध किया। राष्ट्रपति कैंनेडी के प्रस्ताव पर क्यूबा की पराजय को ध्यान में रखते हुये सोवियत संघ ने एक 'परमाणु परीक्षण निषेध संधि' पर विचार करने के लिये आमंत्रण स्वीकार कर लिया। मास्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया तथा अत्यन्त गम्भीर विचार विमर्श के पश्चात् 5 अगस्त, 1963 को 'इस परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर किये गये। इसके द्वारा अन्तरिक्ष, वायु मंडल एवं थल क्षेत्रों में किसी प्रकार के अणु प्रयोग पर जिसमें प्रदूषण की सम्भावना व्याप्त थी, पूर्णतया निषेध लगा दिया गया था। संधि में केवल भूमि गर्भ में अणु परीक्षण की अनुमति दी गयी थी। 24 सितम्बर को सीनेट ने इस संधि को पारित कर दिया इसके पक्ष में अस्ती

एवं विरोध में उन्नीस मत पड़े थे । कुछ सदस्यों को सोवियत संघ द्वारा धोखा देने की सम्भावना थी ।

‘परमाणु परीक्षण निषेध संधि’ प्रदूषण के अवरोध के अतिरिक्त निशःस्त्रीकरण के लिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । यद्यपि उस समय तक निर्मित किसी भी शस्त्र को नष्ट नहीं किया गया एवं 3 माह की पूर्व सूचना पर परीक्षणों में उनका प्रयोग किया गया फिर भी इस संधि को विश्व के कई राष्ट्रों ने सम्मानित कर मान्यता प्रदान की । फ्रांस तथा चीन जो उस समय परमाणु शस्त्रों पर प्रयोग कर रहे थे इससे विशेष रूप से प्रभावित हुये । इस प्रकार इस संधि ने वातावरण के प्रदूषण के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक तनाव को भी कम किया ।

शीत युद्ध के ऊष्ण वातावरण को मापने के लिये अन्य कई योजनायें भी कौनेडी प्रशासन द्वारा बनाई गई । अगस्त 1963 में मास्को तथा वाशिंगटन के मध्य उष्ण संचार रेखा के द्वारा दूर संचार के प्रयत्न किये गये । इसके स्थापन का प्रमुख उद्देश्य विघेप संकट की परिस्थितियों में दोनों देशों में भ्रम अथवा मिथ्या पूर्ण नीतियों के शीघ्र निवारण करने के लिये था, जिससे भविष्य में विना सूचना के अचानक युद्ध न छिड़ सके । इसके दो माह पश्चात् राष्ट्रपति ने अमरीका एवं सोवियत संघ के सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करने के लिये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया । रूस में कई वर्षों से सूखा पड़ने व कृषि की हानि के कारण खाद्य सामग्री की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई । कौनेडी ने दो सौ पचास मिलियन डालर की कीमत के अमरीकी एकत्र गेहूँ को सोवियत संघ के हाथों विक्रय करना स्वीकार कर लिया । कांग्रेस एवं अमरीकी जन समुदाय में इस गेहूँ की विक्री पर अत्यन्त विवाद हुये, एवं आलोचनायें की गई । रूसियों के साथ जो अमरीका का गला घोटने को व्याकुल थे, दया का कार्य करना कोई बुद्धिमानी का कदम न था, फिर भी अधिकांश जनमत ने इस कार्य को स्वीकार भी किया । मानवता एवं उदारवाद की नीति अमरीका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग थी । एकत्र गेहूँ का संचय और भण्डारीकरण करना एक व्यययुक्त कार्य था इसके लिये अतिरिक्त रूसी स्वर्ण की प्राप्ति यूरोपीय व्यापार में अमरीका की स्थिति को अत्यन्त सुदृढ़ करती थी तथा अमरीका की बाहरी व्यापार में लगी पूंजी की स्थिति का भी संतुलन हो रहा था । अगले पृष्ठ दी गई सारणी से अमरीका की स्वर्ण स्थिति को समझाया जा सकता है:—

भुगतान कमी का संतुलन

(मिलियन डालर में)

	1955	1959	1960	1961
स्वर्ण स्थिति (भंडार)	21,754	19,507	17,804	16,947
वार्षिक कमी	1,145	3,743	3,881	2,370
		1962	1964	
स्वर्ण स्थिति (भंडार)		16,057	15,550	
वार्षिक कमी		2,186	2,660	

अमरीका का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार 1949 में चौबीस मिलियन डालर था, 1957 से प्रति वर्ष उसमें तीव्र कमी आती रही।

यूरोप में नयी नीतियाँ

शीतयुद्ध की लहरों के साथ-साथ अमरीकी सहायता अभियान के द्वारा यूरोप के अधिकांश देशों की स्थिति सुदृढ़ हो गयी थी। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति कॅनेडी ने अब सोवियत रूस के साथ सम्बन्ध भी अच्छे कर लिये थे। यूरोपीय राष्ट्रों की उन्नति विश्व शांति एवं स्वतंत्र संस्थानों के लिये अत्यन्त आवश्यक थी, परन्तु अब यूरोप में एक नवीन वातावरण उत्पन्न हो रहा था। यूरोप के स्वतंत्रता प्रेमी जनसमुदाय आर्थिक व मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने पर अब अमरीकी स्वामित्व को कम करना चाहते थे। अमरीका ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप की नीतियों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया था, एवं एक नीति निर्देशक के रूप में यूरोप का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया था। युद्ध पश्चात के सभी अमरीकी राष्ट्रपतियों ने विभिन्न एवं पृथक विचारधाराओं को

प्रेषित करते हुये भी यूरोप के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाई थी। राष्ट्रपति कैंनेडी ने भी अपने प्रशासन काल में उपरोक्त नीति को स्थान दिया था। उन्होंने 'उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन' के समस्त चौदह राष्ट्रों को समय-समय पर इन्हीं नीतियों पर आधारित विभिन्न परामर्श एवं विचार दिये। वह सदैव संयुक्त पश्चिमी यूरोप' की कल्पना करते थे जो राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से समृद्धि हो तथा अमरीका की अध्यक्षता में साम्यवाद प्रसार के अवरोध के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हो। अनेक राष्ट्र अमरीका की इस उदार प्रकृति की संरक्षता को सदैव स्वीकार भी करते थे क्योंकि अमरीका को उन क्षेत्रों में सुख सम्पन्नता प्रदान करने का मुख्य श्रेय प्राप्त था। वस्तुतः फ्रान्स में राष्ट्रपति चार्ल्स डे गॉल जो कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष थे, फ्रान्स की प्राचीन गौरव, गरिमा मान व प्रतिष्ठा की कल्पना करते थे। उनका हृदय राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत था और वे अमरीका के इस स्वमित्व के प्रशंसक नहीं थे। 1962 में डे गॉल ने अपने देश की किसी भी नीति में, चाहे वह यूरोपीय सुरक्षा का कितना ही संगठित मामला, हो, अमरीका के हस्तक्षेप को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया। उन्होंने देश हित के लिये अपने देश के परमाणु विकास को प्रोत्साहन दिया और फ्रान्स अणु शक्ति के रूप में उभर आया। अमरीका की निरन्तर आलोचना व दबाव पर भी उन्होंने द्विस्तरीय सम्बन्ध स्थापित किये। उन्होंने यह निर्णय दिया कि भविष्य में किसी संकटमय स्थिति के मध्य अमरीका अपने राष्ट्रीय हित में फ्रान्स को साम्यवादियों के समक्ष, जिसमें सोवियत रूस मुख्य हैं, अकेला छोड़ सकता है। उनका विचार था कि अमरीका पर ही निर्भर रहने की निरन्तरता, ने यूरोपीय देशों को आत्मनिर्भरता से सदैव वंचित रखा था। डे गॉल ने यूरोपीय देशों को स्वावलम्बी होने का परामर्श दिया। वास्तव में वह यूरोपीय नीतियों में फ्रांस की विचारधाराओं को समन्वित करना चाहते थे, उन्होंने ब्रिटेन के उन विचारों को भी अस्वीकृत कर दिया, कि अमरीका के साथ यूरोप में एक नया अभिदर्शक का स्वरूप बनाया जाये जिसमें फ्रांस को भी यथोचित स्थान प्राप्त हो सके किन्तु ब्रिटेन अभी भी अमरीका की शक्ति व सहायता को आवश्यक व औचित्यपूर्ण समझता था। राष्ट्रपति डे गॉल ने उत्तरी एटलांटिक संधि संघ (नाटो) से सम्बद्ध देशों की संयुक्त परमाणु सेना का विचार भी प्रथम कर दिया, क्योंकि उनका कथन था, कि इस प्रकार की शक्ति का अंकुश सदैव संयुक्त राष्ट्र अमरीका अपने हाथ में रखेगा। जनवरी, 1963 में उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटेन की अमरीका समर्थन नीतियों का खंडन किया और ब्रिटेन के यूरोपीय कॉमन मार्केट (ई०सी०एम०) की सदस्यता प्रार्थना पत्र पर भी अपना

निपेधाधिकार लगा दिया। डि गॉल की इन कूटनीतियों से राष्ट्रपति कॅनेडी, अत्यन्त चिन्तित हुये किन्तु यूरोपीय व्यापार के हित में वह केवल मौन ही रह सकते थे।

एशियाई नीति

सोवियत संघ और चीन के सम्बन्ध अभी तक अत्यन्त सुदृढ़ एवं प्रगाढ़ थे। दोनों ही देश साम्यवाद की लालिमा से पूर्णतया रंजित थे तथा एक ही सिद्धान्त को लेकर अनुशासित थे। परन्तु आधिक रूप से समृद्ध होने पर रूस लेनिनवाद के साथ-साथ पश्चिमी पूंजीवाद के साथ का भी कोई मार्ग चाहता था। रूस के इस आकर्षण का मुख्य कारण व्यापार एवं विश्व राजनीति थी। दूसरी ओर चीन कट्टर सिद्धान्तवादी के रूप में विश्व क्रान्ति की कल्पना में रत था। चीन के साम्यवादी नेताओं ने क्यूवा में अमरीका की धमकी पर रूस के नीति नियंत्रण करने पर रूस की अत्यन्त निन्दा की थी। रूस को पूंजीवाद का साथी बनाकर 'संशोधनवाद' का द्योतक बताया। चीन की विस्तारवादी गति-विधियों एवं योजनाओं को देखते हुये रूस के प्रधानमंत्री खुरश्चेव ने अनेक समय पर चीन को चेतावनी दी थी। इस प्रकार साम्यवादी राष्ट्र पारस्परिक मतभेद से भी खिन्न थे।

उपरोक्त परिस्थिति में चीन एक ऐसे अवसर की खोज में था जहाँ बल प्रयोग द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। तिब्बत की समस्या को लेकर भारत व चीन के सम्बन्धों में तनाव चल ही रहा था। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण 'मैकमोहन रेखा' को भी मान्यता नहीं देता था। अक्टूबर, 1962 में अकस्मात् हिमालय के संकीर्ण मार्गों से चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत उस समय युद्ध की स्थिति में सर्वथा नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने पंचशील सिद्धान्त द्वारा एक नवीन एशिया का स्वप्न संजो रहे थे। इस स्थिति में भारत भी अप्रत्याशित आक्रमण के लिये पूर्ण रूपेण युद्ध युक्त नहीं था। फलस्वरूप भारत ने इस आकस्मिक आक्रमक स्थिति का सामना करने के लिये अमरीका से सहायता माँगी। राष्ट्रपति कॅनेडी ने साम्यवादियों की गुप्त योजना की आलोचना करते हुये भारत को सम्पूर्ण शस्त्र सहायता का आदेश दिया। युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया परन्तु भारत चीन सीमा विवाद एक चिर समस्या बनकर रह गया।

यूरोपीय देश चीन की सैन्य शक्ति में वृद्धि देखकर उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में लाना चाहते थे। उनका विचार था कि इस प्रकार चीन सुरक्षा परि-

पद के आधीन हो जायेगा और उसकी गतिविधियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमाबद्ध किया जा सकता था। वास्तव में सत्तर करोड़ की जनसंख्या वाला यह देश चीन अभी तक विश्व में किसी प्रकार की मान्यता न मिलने कारण खिन्न था। अमरीका अन्य देशों के विचारों से सहमत नहीं था। अमरीका के राष्ट्रपति कैंनेडी का कथन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रपन्न केवल शांति प्रिय देशों को ही मान्यता देता था। भारत पर आक्रमण के पश्चात् तो चीन को मान्यता देना साम्यवादियों के आगे घुटने टेकना जैसा है। 1964 में चीन अणु शक्ति के रूप में भी उभर आया। लाल चीन के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें राष्ट्रसंघ की सदस्यता तब तक स्वीकार नहीं, जब तक उन्हें पूर्ण मान्यता नहीं दी जाती। इसके साथ राष्ट्रीय चीन के च्यांग-काई-शेक के राज्य को अमान्य करके उसकी सदस्यता भंग करने की माँग भी चीन ने प्रेषित की। अमरीका को चीन का यह सुझाव मान्य नहीं था।

राष्ट्रपति कैंनेडी ने विकसित देशों की राजनैतिक विचार धाराओं में अधिक हस्तक्षेप की नीति का परिपालन नहीं किया। उनके विचार में “तृतीय विश्व” अप्रत्यक्ष रूप से इसी कारण लोकतांत्रिक एवं साम्यवादी सिद्धान्तों का संघर्ष स्थल बना हुआ था। कैंनेडी के विचारानुसार ऐसी परिस्थिति में जॉन फॉस्टर डलैस के कथन, करनी एवं मार्ग निर्देश को उचित स्थान नहीं दिया जा सकता था। राष्ट्रपति सम्भवतः इससे अवगत थे कि यदि अविकसित देशों की तटस्थता की नीति में अधिक हस्तक्षेप किया गया तो वे मास्को एवं पीकिंग से गठबंधित हो जायेंगे। कैंनेडी ने लाओस में भी एक प्रकार से तटस्थता की नीति अपनाते पर रूस को भी वाध्य किया उन्होंने 1963 में व्यक्तिगत राजदूत के रूप में एवरेल हरेमन को भेजा जिसमें रूसी प्रधानमंत्री निकिता खुरश्चेव को अपने इस विचार पर पुनरवलोकन करने के लिये कहा गया जिसके अन्तर्गत उन्होंने लाओस को तटस्थ क्षेत्र की संज्ञा दी थी। अपने प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रपति ने लाओस को ‘विजय पराजय’ की परिधि से दूर ही नहीं रखा वरन् महाशक्तियों का संघर्ष स्थल बनने से सुरक्षित रहने का भी अवसर प्रदान किया। कैंनेडी अपनी वैदेशिक नीतियों में उपनिवेशवाद को पूर्णतया समाप्त करना चाहते थे अतः उन्होंने अपने प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सभा में अंगोला प्रस्ताव का समर्थन भी किया।

एशिया के विकसित देशों में सर्वाधिक संतुलित देश भारत था। डच एवं फ्रांसिसीयों ने अंग्रेजों की भाँति अपनी राजनैतिक परम्परा एवं संस्थाओं को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में सुचारु रूप से गठित नहीं किया था इसीलिए दक्षिण-पूर्वएशिया में भारत की भाँति विवेक पूर्ण एवं संतुलन युक्त राज-

नैतिक वातावरण उत्पन्न नहीं हो सका। हिन्देशिया को 1949 में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और सुकार्णों द्वारा निर्देशित लोकतन्त्र धीरे-धीरे निरंकुशतावादी सत्ता में परिवर्तित होने लगा। राष्ट्रपति कैंनेडी ने रावर्ट कैंनेडी को भेजकर हिन्देशिया और अमरीका के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की परन्तु सुकार्णों अपनी अविश्वसनीय प्रकृति के उपरान्त भी अमरीका की वार्ता परिधि में बने रहे। मलेशिया के प्रश्न को लेकर सुकार्णों और अमरीका में मत भेद उत्पन्न हुआ, जिसके द्वारा हिन्देशिया साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो गया। इस पर, भी यह कहना उचित है कि कैंनेडी युग में अमरीका ने हिन्देशिया के प्रति एक राजनैतिक वार्ता का वातावरण उत्पन्न किया और उसे स्थिर करने में चेष्टारत रहा।

वियतनाम में भी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की समस्या को लेकर अमरीकी प्रशासन की नीतियों में मतभेद था। राष्ट्रपति कैंनेडी बीसवीं शताब्दी के पांचवें दशक से ही वियतनाम समस्या का अध्ययन कर रहे थे। उनके विचार में अमरीका दक्षिण पूर्व एशिया में आवश्यकता से अधिक राजनैतिक रूप से अभिभूत था। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात् कैंनेडी को भी वियतनाम में युद्धरत रहने पर वाध्य होना पड़ा। 1962 में रावर्ट मेकेनमारा एवं मेक्सवेल टेलर के आश्वासनों पर कि अमरीका युद्ध जीत रहा था, राष्ट्रपति को प्रोत्साहन मिला।

हिन्द चीन में अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा

दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीनी साम्यवाद के प्रसार का भी एक बड़ा संकट बना हुआ था। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा वियतनाम इत्यादि क्षेत्रों को भयांकित करना चाहता था। अमरीका को इसका पूर्ण भय था कि लाओस व वियतनाम (दक्षिणी) में चीन के प्रभाव क्षेत्र स्थापन द्वारा पूर्ण भाग चीन के प्रभाव में आ जायेगा। लाओस एक कच्छीय व जंगलों से भरा क्षेत्र था जिसको अमरीकी डालर की पूर्ण निर्भरता मिली हुई थी। वहाँ की साम्यवादी संस्थाओं के द्वारा समयानुसार विरोधात्मक संघर्ष उत्पन्न हो जाता था। उन्हें पीकिंग द्वारा शस्त्रों एवं गोरिल्ला युद्ध की सहायता प्राप्त थी। राष्ट्रपति कैंनेडी ऐसी किसी युद्धसमस्या में ग्रस्त नहीं होना चाहते थे। जिसके द्वारा जनसंहार हो। इसके अतिरिक्त चीन को भी संतुलित रखना आवश्यक था वरन वह अपने समीपवर्तीय क्षेत्रों में सहायता हेतु पदार्पण कर सकता था। उन्हें कोरिया युद्ध का पूर्ण अनुभव था। उन्होंने चौदह राष्ट्रों का जेनीवा में सम्मेलन बुलाया जो कि पन्द्रह माह तक चलता रहा। 23 जुलाई

1962 को सम्मेलन ने पूर्ण तटस्थता व लाओस को स्वतन्त्र करने का विचार व्यक्त किया। लाल साम्यवादियों ने इस निर्णय का सदैव उल्लंघन किया। फलस्वरूप अमरीका ने भी अपने दक्षिणी एशिया के सैन्य आस्थानों से वायुयान आक्रमण आरम्भ कर दिये। चीन की गतिविधियों की वृद्धि को देखते हुये राष्ट्रपति कैंनेडी ने जो अपने साहसिक कार्यों के लिये प्रसिद्ध थे, उन्होंने तत्कालिक हस्तक्षेप का निर्णय लिया। उनका निश्चय था, कि अमरीका की शक्तिशाली वायुसेना व जलसेना, एक निर्णयात्मक युद्ध कर सकती है। मानवशक्ति के अत्यधिक होते हुए भी, चीन शस्त्र शक्ति में, अभी भी काफी पीछे था। परन्तु दक्षिणी वियतनाम के साम्यवाद विरोधी उत्तरी वियतनामी व चीनियों के सहायता से गोरिल्ला युद्ध विधियों द्वारा अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर रहे थे। आइजनाहावर प्रशासन ने भी दक्षिणी वियतनाम का पूर्ण समर्थन किया था। डॉलर व शस्त्र सहायता के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अमरीकी परामर्श दाता भी वियतनाम में आये थे।

1961 के अन्त में, पूर्ण निर्णय के पश्चात्, कैंनेडी ने अमरीकी सैन्य परामर्शदाताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। उन्होंने दक्षिणी वियतनाम के निकट अमरीकी सैन्य आस्थान बना दिये, परन्तु अमरीका को अपनी विजय की आशा कहीं भी नहीं दीख रही थी। नवम्बर, 1963 अर्थात् राष्ट्रपति कैंनेडी अन्तिम दिनों तक अमरीका के पन्द्रह हजार पाँच सौ परामर्शदाता वियतनाम में आ चुके थे। इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया में महाशक्तियों का हस्तक्षेप प्रारम्भ हो गया था।

उच्चतम न्यायालय : नये नागरिक अधिकार

विश्व युद्ध के पश्चात् साम्यवाद का प्रसार अमरीकी विदेश विभाग का एक मुख्य विषय बन गया था। समस्त वैदेशिक नीति की विचारधाराएँ केवल इसी के अवरोधन पर आधारित थी। इस समय अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने मानव के मूल अधिकारों पर अपने नवीन निर्णय को प्रस्तुत कर अमरीका में एक वैधानिक द्वन्द उत्पन्न कर दिया। 1953 में अर्ल वॉरेन अमरीका के नये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुये। उनके वाद उच्चतम न्यायालय अर्ल वॉरेन न्यायालय कहा जाने लगा था। अर्ल वॉरेन का व्यक्तित्व सौम्य एवं मानवतावादी था। वह मानवीय अधिकारों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझते थे। उनके काल में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने अमरीका में एक विशेष उल्लासजनक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों को

संविधान का एक अति आवश्यक अंग बताया तथा इन अधिकारों के लिये ऐसे निर्णय लिये गये कि राष्ट्र सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया। अमरीका में अन्य देशीय गुप्तचरों एवं विदेशी एजेंटों द्वारा की जा रही गतिविधियों से अराजकतावादी एवं साम्यवादी तत्वों को अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अवसर प्राप्त हो रहा था। इससे अमरीकी समाज असंतुष्ट था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से देश को इन साम्यवादियों पर नियंत्रण करना कठिन हो गया। यह भी स्पष्ट था कि यह प्रतिक्रियावादी वर्ग के सदस्य समाज में विध्वंसक कार्य करने लगे थे, जिससे जनसाधारण असंतुष्ट था। न्यायालय ने अमरीका के कई राष्ट्रीय कानूनों को अवैध घोषित कर दिया। 1964 में न्यायालय में यह निर्णय दिया कि पारपन्न (पासपोर्ट) व्यक्ति विधेय का एक मूल अधिकार था अतः विदेश विभाग किसी भी व्यक्ति को चाहे वह समाजवादी हो या साम्यवादी, उसके व्यक्तिगत अधिकारों पर अनाधिकृत चेष्टा नहीं कर सकता था। 1963 में ग्रीदियां वनाम वेनराइट के अभियोग में अभियोक्ताओं को व्यक्तिगत सुरक्षाधिकार से पर्याप्त रूप में युक्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त एस्काविडो के 1964 के तथा मिराडाँ के 1966 के अभियोगों में जो अपने समय में दृष्टांतक बन गये थे, उच्चतम न्यायालय ने अभियोगी को मौन रहने के व्यक्तिगत अधिकारों का भी अधिकार दे दिया। इस प्रकार पुलिस द्वारा प्रयोगिक दंड प्रणाली द्वारा यह भी प्रतिबन्ध लग गया। जनता में उच्चतम न्यायालय की आलोचना करते हुये यह मत प्रकट किया कि सुप्रीम-कोर्ट अधिकारियों के स्थान पर पुलिस को हथकड़ियाँ पहनाना चाहता था।

इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने अन्य नागरिक मामलों में भी इसी प्रकार के निर्णय दिये। संविधानिक अधिकारों को इतना बल प्रदान कर दिया गया कि सामान्य व्यक्ति ने राष्ट्र हित का ध्यान ही देना बन्द कर दिया। प्रथम संविधानिक संशोधन के द्वारा धर्म तथा चर्च को राज्य कानूनों से पृथक कर दिया गया। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने 1962 तथा 1963 में दो अन्य आश्चर्यजनक निर्णय दिये। उसने पब्लिक स्कूलों में बाईबिल के अध्ययन का अनिवार्य होना अनुचित बताया एवं किसी प्रकार की धर्म सम्बन्धी प्रार्थना सभा में उपस्थिति की अनिवार्यता पर निषेध लगा दिया। जनता ने इन निर्णयों की तीव्र आलोचना की। इन निर्णयों से साम्यवादियों की वास्तविकता का प्रचार करने में और बल मिला। अमरीका के संघीय संविधान में राज्यों को अपने पृथक अधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संघ का प्रान्तों के कानूनों एवं अधिकारों पर कोई अधिपत्य नहीं होगा।

दक्षिण में श्वेतवर्ण एवं नीग्रो वर्ग के मध्य प्रजाति द्वेष सम्बन्ध और

पृथकता की भावनाएँ अभी तक प्रचलित थी। 1954 में उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा स्कूलों में नीग्रों के नागरिक अधिकारों का समर्थन करते हुये पृथकता के विरुद्ध 'व्यक्ति एक रूपता' का निर्णय दिया। इससे राष्ट्र के सभी दक्षिणी प्रदेशों में एक तीव्र असंतोष की भावना व्याप्त हो गयी। दक्षिण के विधान मंडलीय सदस्यों ने इस निश्चय पर अत्यन्त क्रोध प्रकट किया, तथा पाँच दक्षिणी विधान मंडलों ने अधिकारिक रूप से इन निर्णयों को मानने से इन्कार कर दिया। तत्पश्चात् एक उच्च अधिकरण के द्वारा इन विधान-मंडलों के निश्चय को गलत सिद्ध कर दिया गया। सामान्य रूप से यह निश्चय हुआ कि कोई भी राज्य उन अधिकारों से नीग्रों को वंचित नहीं कर सकता, जो अधिकार उन्हीं राज्यों द्वारा श्वेतवर्ण के सदस्यों को प्रदान किये गये थे। इस निश्चय की दक्षिण में कटु आलोचनायें की गईं। इन लोगों ने यह आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय संविधान व्यवस्था नहीं, बरन संविधान का पुनः लेखन कर रहा था, तथा इस लेखन में न्यायालय राज्यों के अधिकारों के प्रति द्वेष एवं पक्षपात की भावना रखता था। सीनेट तथा कांग्रेस में भी दक्षिणी सदस्यों ने कई प्रश्न उठाये। उनके कथनानुसार 'वॉरेन न्यायालय' एक न्यायिक संस्था न होकर विधि रूपेण संस्था का स्वरूप था।

अर्ल वॉरेन के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय की संस्था कौन्डी काल में चर्चा की मुख्य विषय बन गयी थी। न्यायालय ने प्रान्तों के कुछ गलत निर्णयों को भी बल दिया। कृषि समृद्धि एवं चरागाह क्षेत्रों का प्रान्तीय विधान मंडलों में अत्यधिक प्रतिनिधित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है जबकि नगरीय क्षेत्र अपना विस्तार कर रहे थे। न्यायालय ने राज्यों के मताधिकार सिद्धान्त को लेते हुए 1962 में एवं 1964 में दो बार विधान मंडलों से भी हस्तक्षेप किया। उसने "एक व्यक्ति एक मत" सिद्धान्त पर बल दिया और प्रतिनिधित्व के विषय को लेकर यह निर्णय दिया कि मण्डलों के दोनों सदनों में जनसंख्या के आधार पर पुनः विभाजन होना चाहिये। इस निर्णय के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों के लिये अनेक 'विधि ज्ञाता' संघर्षरत थे। उन्होंने सीनेट में जनसंख्या पर न आधारित प्रतिनिधित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया एवं उच्चतम न्यायालय से क्रुद्ध होकर अर्ल वॉरेन के दोषारोपण व हटाने की माँग की। परन्तु इसके विपरीत विधान मंडलों को पुनः विभाजन का कार्य आरम्भ करना ही पड़ा।

अर्ल वॉरेन की नियुक्ति के पश्चात् से उच्चतम न्यायालय में मानवीय अधिकारों को विशेष स्थान दिया गया। इस कारण न्यायालय की तीव्र आलोचना भी हुई एवं कांग्रेस में प्रत्यावेदन व विलों द्वारा उसके अधिकारों को कम

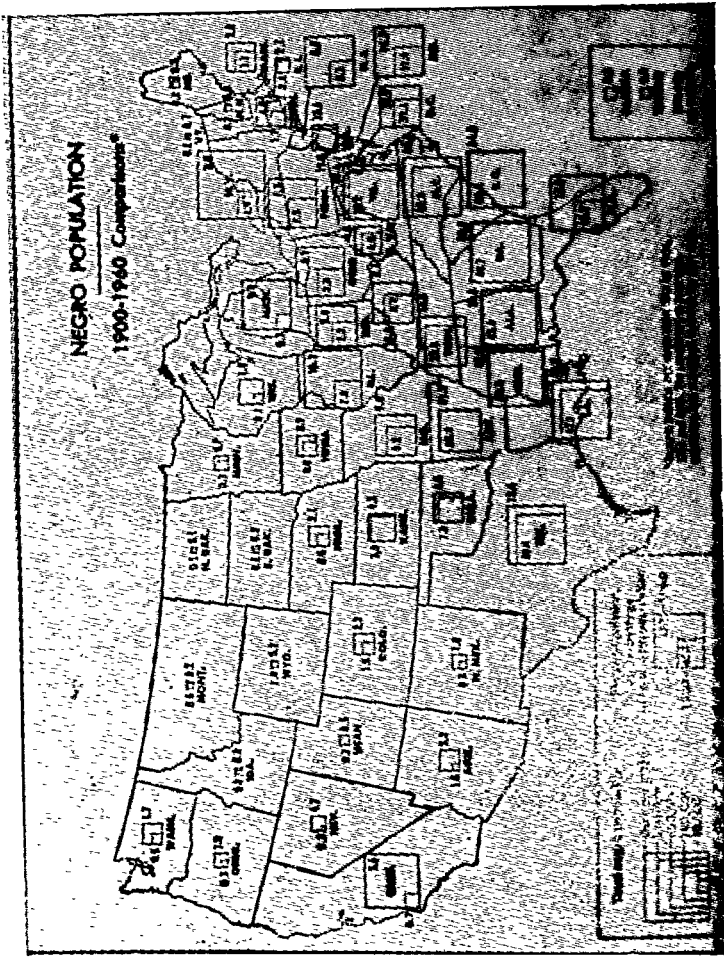
करने के अनेक प्रयास हुए। संविधानिक संशोधन भी किये, गये परन्तु उच्चतम न्यायालय अपने स्थान पर अडिग रहा। न्यायाधीशों ने व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा के नियमों व कर्तव्यों का पालन किया। उनके कथनानुसार जनतन्त्र का पहला उद्देश्य यह है कि चाहे कोई श्वेतवर्ण हो या श्याम, बहुमत के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार प्रत्येक के लिये समान हैं। इसके अतिरिक्त बहुमत किसी व्यक्ति विशेष पर तानाशाह का रूप नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि यदि व्यक्ति विशेष असमाजिक है, तो भी संविधानिक अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता था, अब उसके लिये अलग दण्ड संहिता तक दण्ड नियमों की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्ल वॉरिन के सभी निर्णय जनतन्त्र के लिए विश्व-विख्यात निर्णयों के रूप हैं।

राष्ट्रपति कैंनेडी और दक्षिण नीग्रो क्रान्ति

जॉन एफ कैंनेडी मानव अधिकारों के सुरक्षक थे। अमरीका के समकालीन इतिहास में उन्हें एवं उनके अनुज रावर्ट कैंनेडी को "मानवता का प्रेमी" का स्वरूप प्रदान किया जाता है। उन्होंने अपने इतने अल्प समय के प्रशासन काल में अपने त्याग के भाषणों एवं नीतियों से अमरीकी समुदाय के मध्य एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। नीग्रो वर्ग के समर्थन के कारण दक्षिणवासी उनसे अत्यधिक क्रुद्ध थे।

यद्यपि शिक्षा स्कूलों में पृथकता की भावना व नीतियों की समाप्ति के आदेश उच्चतम न्यायालय ने 1954 में दे दिये थे, फिर भी दक्षिण के रूढ़िवादी लोगों ने इसे मानने से इन्कार कर दिया था। इस कारण नीग्रो समुदाय के लोगों के साथ दक्षिण में अत्यन्त पक्षपात अभी भी व्याप्त था जिससे इस वर्ग में विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो रही थी। मत-निवन्धन कार्यालयों में, यातायात व परिवहन में, सार्वजनिक आवासों के आवंटन में, सेवायोजन में, तथा अन्य सभी स्थानों पर नीग्रो जाति के लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। इस प्रकार के पक्षपात के उदाहरण उत्तरी भागों में भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। यह समस्या अमरीकी राष्ट्र में विवेक एवं मानवता पर आधारित नहीं थी। मार्टिन लूथर किंग ने नीग्रो क्रान्ति को प्रगति की ओर अग्रसर होने की बजाय संकीर्ण एवं दुर्गम मार्ग पर प्रेरित बताया। उनका मत था कि नीग्रो समस्या को प्रगतिशील अमरीकावासी अपनी आन्तरिक नीति के सिद्धान्तों में एक उचित स्थान प्रदत्त करेंगे, परन्तु उनकी यह आशा धूमिल होती प्रतीत हुई।

दक्षिण प्रान्तों में हिंसाप्रद कार्यों में वृद्धि होने लगी। 1963 की ग्रीष्म



नीग्रो जनसंख्या

में दक्षिण में अत्यधिक नृशंस घटनाएँ घटित हुईं। सभी स्थानों पर नीग्रो वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। 'अलाबामा' में एक भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस अधिकारीगण अपना सन्तुलन खो बैठे, और निशस्त्र प्रदर्शनकारियों पर उन्होंने गोली चला दी। इसके पश्चात् 'वर्मिगंम' में अन्य घटनाएँ घटित हुईं।

श्वेत वर्णों की "कू क्लक्स क्लान" की गुप्त संस्था फिर से कार्य शील हो गयी थी। मिसिसीपी तथा अलाबामा में अनेक 'नीग्रो गिरजाघरों' को बमों से ध्वस्त कर दिया गया। सितम्बर, 1963 में वर्मिगंम में चार नीग्रो लड़कियाँ जो "प्रेम जो क्षमा करता है" पाठ का अध्ययन कर रही थी, एक चर्च में उनकी हत्या कर दी गयी। इस प्रकार के वातावरण से पुनः गृह युद्ध तक छिड़ सकता था। जातीय हिंसक घटनाओं का प्रतिरोध कॅनेडी प्रशासन का प्रमुख कार्य हो गया था। संघीय गुप्तचर विभाग ने अपनी जाँच में सूचना दी कि श्वेत वर्णों के न्यायधीशों ने दक्षिण में किसी हिंसाप्रद कार्य पर श्वेतवर्ण अपराधियों को कोई सजायें नहीं दीं। उत्तरी प्रदेशों में भी 1964 में नृशंस घटनाएँ हुईं। 'हारलेम', 'रोचेस्टर' तथा 'जर्सी नगर' की घटनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समय के साथ-साथ श्याम वर्णीय नीग्रो समुदाय अब अधिकारों के लिये पूर्ण चैतन्य हो चुके थे। अनेकों स्थानों पर, राष्ट्रपति कॅनेडी, जो नीग्रो के अधिकारों को महत्व प्रदान करते थे, प्रारम्भिक काल से ही नवीन सीमा योजनाओं व विदेश नीतियों में ग्रस्त हो गये। इसी कारण इन विषयों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाये। उनका एक अन्य प्रमुख कारण कांग्रेस में दक्षिणी सदस्यों की संख्या आधिक्य था। दक्षिणी सदस्यों की अधिकता से उन्हें सदन में अनेक प्रस्तावों में भी सहयोग की आशा थी। उन्होंने नीग्रो लोगों को अनेक कार्यालयाध्यक्षों के पदों पर नियुक्त किया तथा अनेक संघीय वित्त से संचालित सेवाओं में नीग्रो लोगों को विशिष्ट स्थान प्रदत्त किये। 20 नवम्बर, 1962 को एक अधिवासी आदेश में उन्होंने संघीय कोष द्वारा आवासीय योजनाओं में समस्त जाति मतभेद व पक्षपातों को दूर कर देने का वचन दिया।

सौ वर्षों के अन्यायों से सन्नस्त नीग्रो लोगों ने एक नृशंस क्रान्ति को प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि उनका प्रमुख उद्देश्य असहयोग आन्दोलन ही था, इसके उपरान्त भी राष्ट्रपति कॅनेडी उस समस्या में ग्रस्त हो गये। नीग्रो लोगों ने आर्थिक पक्षपात, जेल यात्रा, प्रदर्शन व हिंसा, समस्त साधनों को प्रारम्भ कर दिया था।

डाक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर नीग्रो लोगों में एक युवा, विद्वान व

ओजस्वी भाषणों वाला नेता उभर आया था। डा० मार्टिन लूथर किंग एक धर्म शास्त्री थे और मानवतावादी सिद्धान्तोंको, मान्यता देते थे। 1964 में उन्हें मानव सेवा के कारण नोबेल शांति पुरस्कार से भी सुशोभित किया गया था। मार्टिन लूथर किंग ने नीग्रो जाति के प्रति किसी प्रकार के जातीय भेदभाव एवं प्रतिस्पर्धा को मानवीय दृष्टिकोण से कदापि उचित नहीं समझा। उन्होंने नीग्रो जाति के भेदभाव की नीति का खंडन किया। उन्होंने श्वेत-वर्ण के लोगों से, जो उदारवादी सिद्धान्त के परिपालक थे, 'नीग्रो-श्वेतवर्ण प्रथकवाद' को समाप्त करने के संघर्ष में योगदान का आह्वान किया। 1962 में मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक अधिकारों को अमरीकी गृहनीति के अन्तर्गत विस्थापित होने की संज्ञा दी। उनके अनुसार नीग्रो लोगों ने हिंसक एवं अहिंसावादी दोनों विधियों से अपने अधिकारों के लिये आन्दोलन किया। जातीय सम्बन्धों की यह स्थिति एक नवीन दिशा की ओर अग्रसर हो रही थी। इस स्थिति की विस्फोटकता को समझते हुये कैंनेडी प्रशासन पूर्ण रूप से इनमें संलग्न हो गया था। नीग्रो समुदाय की अर्थर्यता का मुख्य कारण उनके अपने ही राष्ट्र में द्वितीय श्रेणी की नागरिकता का स्वरूप प्रदान किया जाना था। संविधान के चौबीसवें संशोधन के द्वारा मतदान की नीति को और अधिक उदारवादी बनाया गया, इस प्रकार राष्ट्रपति एवं कांग्रेस के चुनावों के मतदाताओं के ऊपर कराधान की प्रतिक्रिया को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, परन्तु यह सभी संशोधन तथा सुधार के कार्य स्थानीय निकायों तथा प्रान्तों के चुनावों पर लागू नहीं होते थे। इन स्तरों पर प्रचलित 'चुनाव कर' अभी भी बहुत से गरीब नीग्रो वर्ग समुदायों को मतदान कार्य से वंचित करता था।

इन सुधारों के अतिरिक्त राष्ट्रपति कैंनेडी ने, देश में व्याप्त असंतोष एवं स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु, 28 फरवरी, 1963 को कांग्रेस में यह संदेश प्रेरित किया, कि असमानता की नीति, शिक्षा, मतदान तथा नागरिक समस्याओं में लज्जा का विषय थी। राष्ट्रपति ने कहा, कि जातीयता के मतभेद के द्वारा अमरीका की विश्व राजनीति एवं आर्थिक नीति को हानि पहुँच रही थी। उन्होंने "नागरिक अधिकार आयोग" को स्वतंत्र विचार प्रेषित करने की अनुमति दी, किन्तु राष्ट्रीय तथ्यों से अवगत रहने का परामर्श भी दिया।

अमरीका में नीग्रो समस्या को लेकर अनेक राष्ट्रीय संघर्ष युक्त समस्याएँ उत्पन्न हो गयी थी। इसमें उत्तरी एवं दक्षिणी अमरीका के नीग्रो की समस्याएँ भी थीं। 1963 तक नीग्रो क्रान्ति में विश्व विद्यालय, धार्मिक संस्थाएँ, श्रमिक एवं अमरीकी न्याय भी संघर्षरत हो गया था। एक पीढ़ी पूर्व राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने श्रमिक क्रान्ति का नव अर्थनीति में समन्वय किया था। इसी प्रकार

राष्ट्रपति कॅनेडी ने 1963 में नीग्रो क्रान्ति को लोकतांत्रिक पद्धति के अन्तर्गत सम्मिलित कर अमरीका की स्वतंत्रता के भविष्य को कीर्तिमान करने की चेष्टा की।

कॅनेडी पटाक्षेप

राष्ट्रपति के सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप भी कांग्रेस के अवरोधों के कारण नागरिक अधिकारों एवं कर-व्यवस्थापन के कार्य तीव्र गति से सम्पादित नहीं हो पा रहे थे। इसी मध्य जॉन कॅनेडी का ध्यान 1964 के आगामी राष्ट्रपति चुनाव के विषय पर केन्द्रित हो गया। अमरीकी इतिहास को एक नयी दिशा प्रदान करने के पश्चात वह अब दूसरे सत्र के लिये भी पूर्णरूप से उत्सुक थे। कांग्रेस में नयी औपधि-प्रणाली, उच्च शिक्षा सहायता के अनुदान, नीग्रो अधिकार अधिनियम एवं कराधान में कमी, आदि विषयों पर पर अभी तक मंदगति से ही कदम उठाए गए थे। इसके अतिरिक्त इधर कई वर्षों से आय-व्ययक में भारी कमी प्रदर्शित हो रही थी। इस कारण करों में कमी करना एक संकटमय कदम भी हो सकता था। राष्ट्रीय आय में वृद्धि मात्र से ही इस आय-व्ययक की कमी को दूर कर उसे संतुलित किया जा सकता था, परन्तु कांग्रेस में दोनों ही दलों के सदस्य किसी विशेष एवं जटिल कदम उठाने के पक्ष में नहीं थे। अमरीका के सार्वजनिक ऋण की ऐतिहासिक गति को निम्न सारणी से दर्शाया जा सकता है:-

अमरीका के सार्वजनिक ऋण

वर्ष	राशि (मिलियन डालर में)	प्रति व्यक्ति (डालर)
1809	83	15.87
1860	65	2.06
1865	2,678	75.01
1900	1,263	16.60
1920	24,299	228.23

वर्ष	राशि (मिलियन डॉलर में)	प्रति व्यक्ति (डॉलर)
1929	16,931	139.04
1939	40,440	308.98
1945	258,682	1,849.00
1956	276,200	1,625.00
1961	296,170	1,612.00
1962	303,470	1,625.00
1963	309,350	1,633.00
1969	353,720	1,741.00

जनसंख्या में प्रवासियों के निरन्तर आगमन से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई, इस कारण 1956 से प्रति व्यक्ति ऋण की राशि में विशेष परिवर्तन नहीं प्रदर्शित हुआ। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमरीका के नीग्रो की समस्याएँ भी थीं। 1963 तक नीग्रो क्रान्ति में विश्व विद्यालय, धार्मिक संस्थाएँ, श्रमिक एवं अमरीकी न्याय भी संघर्षरत हो गया था। एक पीढ़ी पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने श्रमिक क्रान्ति को नव अर्थ नीति में इसका समन्वय किया था। इसी प्रकार राष्ट्रपति कैंनेडी ने 1963 में नीग्रो क्रान्ति को लोकतंत्रिक पद्धति के अन्तर्गत सम्मिलित कर अमरीका की स्वतंत्रता के भविष्य को कीर्तिमान करने की चेष्टा की। मुद्रा कोषागार में एकत्र करने से पुनः निर्मित अथवा व्यय करने का कार्य राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था के लिये स्वाभाविकतः अधिक उचित था। निर्वाचन का समय निकट आने के साथ-साथ इन सब मामलों में निश्चय लेने में काफी तीव्रता लाई गयी। कई नयी सिनेट सीमितियाँ सृजित की गयी। इसके अतिरिक्त देश की उन्नति एवं अन्य कार्यों की गति का व्यौरा लेने के लिये राष्ट्रपति कैंनेडी ने देश भ्रमण करने का कार्यक्रम बनाया। इसका एक अन्य प्रमुख कारण चुनाव के लिये अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना भी था। विशेष रूप से पश्चिमी प्रान्तों में जहाँ 1960 के चुनाव में गणतंत्रवादी निक्सन को सर्वाधिक मत प्राप्त हुये थे। परन्तु कैंनेडी ने अपने इस दौरे को पूर्णतया अराजनैतिक बताया। इधर दक्षिणी प्रान्तों में नागरिक अधिकारों के विषयक को लेकर हुये आन्दोलनों में कैंनेडी की शक्तों द्वारा दमन प्रतिक्रिया के कारण एक विरोध का वातावरण बना हुआ था।

एक नवीन "के के के", अर्थात् "केयो कॅनेडी क्लान" का नारा पोस्टरों द्वारा चारो तरफ प्रचलित किया जा रहा था। इसी विरोध पूर्ण वातावरण में जब राष्ट्रपति टैक्सास पहुँचे तो 22 नवम्बर, 1963 को सम्पूर्ण विश्व को चौंका देने वाली एक घटना घटित हुई। प्रान्तीय शहर डलास में जाते समय एक कार्यालय भवन-से किसी ने राष्ट्रपति की खुली कार पर राइफल से गोली चलाई और वंदूक की यह गोलियाँ राष्ट्रपति के मास्तिष्क में प्रवेश कर गयी। इसी कारण अमरीका का महान राष्ट्रपति सदैव के लिये चिर निन्द्रामय हो गया। पुलिस ने इस सम्बन्ध में ली हारवे ओस्वाॅल्ड नामक व्यक्ति को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया, परन्तु किसी निश्चय पर पहुँचने से पूर्व ही हारवे ओस्वाॅल्ड की हत्या भी जैक रूबी नामक एक दूसरे व्यक्ति ने कर दी। हत्या की जाँच हेतु मुख्य न्यायधीश वॉरेन की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया गया।

इस अल्पकालिक लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु अमरीका के इतिहास की एक अत्यन्त दुःखमय घटना थी। रुजवेल्ट की मृत्यु और पर्ल हार्बर के आक्रमण के पश्चात् इतनी चौंका देने वाली यह पहली घटना हुई। यद्यपि कॅनेडी अल्पमत से ही चुनाव में विजयी हुये थे, परन्तु अपनी नीतियों और तीव्र कार्यशीलता के कारण सम्पूर्ण अमरीकी समुदाय के वह एक प्रिय नेता बन गये थे। उनके विरोधी भी उनका आदर करते थे। बहुत लोगों ने उनकी मृत्यु को इतिहास की सबसे अधिक दुःखद घटना बताया। रुजवेल्ट एवं लिंकन की मृत्यु लगभग उनके लक्ष्यों की पूर्ति पश्चात् हुई थी, परन्तु कॅनेडी ने अपना युग अभी प्रारम्भ ही किया था। तैंतीस महीनों के प्रशासन काल में उन्होंने अमरीका को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया स्थान दिया। उसकी युवा पत्नी जैक्यूलीन ने भी विभिन्न कलाओं को प्रशासनिक संरक्षण प्रदान करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये। राष्ट्रपति जॉन कॅनेडी ने यह सिद्ध कर दिया कि एक कैथोलिक भी अमरीकी समुदाय का कुशल प्रशासक हो सकता था।

राष्ट्रपति, जॉन फिट्स जेराल्ड कॅनेडी की इस आकस्मिक हत्या ने सम्पूर्ण विश्व को हतप्रभ कर दिया। कुछ पल तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसी घटना का घटित होना असम्भव है। जॉन कॅनेडी विश्व राजनीतिक क्षेत्र में एक उल्कामय नक्षत्र की भाँति देदीप्तमान हुये और अपने राजनैतिक मूल्यों के प्रकाश को विकीर्ण करते हुये अस्त हो गये। कॅनेडी ने भय ग्रस्त, संतप्त एवं राजनैतिक प्रतिस्पर्द्धा युक्त वातावरण में एक नवीन स्वस्थ एवं आशापूर्ण वातावरण को निर्मित किया था। उन्होंने नीग्रों समस्या, आर्थिक क्रांति, तार्किक राजनीति, अविकसित देशों के प्रति सहृदयता एवं स्वाधीनता प्रिय देशों को एक नव

आश्वासन, नव राजनीति एवं नव राजनायिक गठबंधनों की प्रेरणा दी। मानवतावाद का यह द्योतक एवं परिचायक अपने उद्घाटन समारोह में जिस हिम झंझावात की तरह आया था उसी प्रकार प्रकृति ने भी उसके अवसान समारोह पर हिमवृष्टि कर मानो अपने दुःख को अभिव्यक्त किया।

जॉन कॅनेडी अपनी प्रसन्न मुद्रा, वाक पटुता, प्रबुद्धता एवं राजनैतिक विवेक के द्वारा सदैव विभिन्न राजनयिक क्षेत्र में अविस्मरणीय रहेंगे।





राष्ट्रपति लिडन जॉनसन राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुये नवम्बर 22, 1963)

अमरीका के छत्तीसवें राष्ट्रपति

अध्याय 13

लिनडन बेन्ज (बेन्स) जॉनसन का युग और विस्तृत अमरीकी समाज

विविध समस्याएँ

राष्ट्रपति कैनेडी के आकस्मिक निधन के पश्चात् प्रगति एवं समृद्धता की ओर गतिशील प्रशासन में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उप राष्ट्रपति लिनडन बेन्ज जॉनसन इस रिक्त पद पर आसीन हुये। राष्ट्रपति कैनेडी के पार्थिव शरीर के साथ राजधानी आते समय वायुयान में ही उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की थी। नये राष्ट्रपति जॉनसन ने इस प्रकार एक विस्मयपूर्ण शान्ति के वातावरण में प्रशासन को अपने हाथों में लिया था। इससे पूर्व भी उप राष्ट्रपति के रूप में सदन के सदस्यों व दल के लोगों में जॉनसन लोकप्रिय हो चुके थे, शान्तिमय विचार-विमर्श के द्वारा समस्याओं को सुलझाने का उनका ढंग निराला था। इसी कारण सीनेट में वे बहुमत के नेता माने जाते थे। राष्ट्रपति जॉनसन विवाद के स्थान पर सदैव समझौते के पक्ष में रहते थे। प्रशासन को अपने हाथों में लेते समय जॉनसन ने भूतपूर्व राष्ट्रपति की नीतियों पर कार्य करने का वचन दिया। कैनेडी काल के सभी व्यवस्थापनों को पुनः सुसज्जित किया गया। कराधान में न्यूनता लाने की प्रतिक्रिया को तीव्र करने के लिये कांग्रेस में अनेक नवीन विधेयक प्रस्तुत किये गये। कराधान में कमी के द्वारा, व्यक्तिगत और निगम आधीन दोनों ही प्रकार के व्यवसायों में, परिवर्तन लाना था। राष्ट्रपति जॉनसन के प्रारम्भिक कार्यों में विशेष प्राथमिकता आय-व्यय के संतुलन की थी, जो कि पुनः असंतुलन की ओर अग्रसर था।

राष्ट्रपति जॉनसन के प्रारम्भिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य "नागरिक अधिकार अधिनियम" को पारित हो जाना था। पुनः निर्माण युग के पश्चात् के अमरीकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना नागरिक अधिकारों की व्यवस्थानिक मान्यता थी। दक्षिणी प्रदेश टैक्सास के निवासी राष्ट्रपति जॉनसन कैनेडी युग से ही नागरिक अधिकारों के लिये अपने सम्बन्ध दक्षिणी सीनेट

सदस्यों से विवाद में उलझे हुये थे। कांग्रेस में दक्षिणी सदस्यों ने पुनः इसके प्रति विरोध करते हुये तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट की। 75 (पचहत्तर) दिनों के तीव्र विवाद पूर्ण अधिवेशन के पश्चात् कांग्रेस में यह विधेयक पारित हो गया। 2 जुलाई, 1964 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् अधिनियम ने एक राष्ट्रीय कानून का स्वरूप ले लिया। इस अधिनियम के विच्छेद के अनुसार ऐसे किसी भी होटल व सार्वजनिक भोजनालयों को मान्यता नहीं मिलनी थी जो नीग्रो वर्ग के लोगों के आगमन पर निषेध लगा रहे थे। दक्षिणवासियों ने इस विच्छेद को असंवैधानिक बताते हुये पृथक भोजनालयों व होटल खोलने के अधिकारों पर बल दिया, परन्तु उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी अपीलों को निरस्त कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इन कार्यों में मुक्त रूप से 'अन्तर प्रान्तीय वाणिज्य' सम्मिलित था, जिसपर किसी-भी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये जा सकते थे।

राष्ट्रपति कौनेडी के स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में जॉनसन प्रशासन के समस्त माह आर्थिक योजनाओं से घिरे रहे; फ्रेंकलिन रूजवेल्ट, जिनको कि राष्ट्रपति जॉनसन अपना राजनैतिक पितामह मानते थे, के अन्ध अनुयायी के रूप में इन्होंने नव आर्थिक नीति के प्राविधानों को पुनः प्रशासन में कार्यान्वित किया। गरीबी व बेरोजगारी एवं मुद्रा अवचयन के निवारण का एक बड़ा अभियान प्रारम्भ किया गया। इन दिनों लगभग तीन करोड़ अमरीकी जन निर्धनता रेखा की अन्धेरी छटा में निवास कर रहे थे। इस बढ़ती हुई गरीबी को समाप्त करने हेतु प्रशासन ने एक आयोग का गठन किया। कोयला उद्योग के अकस्मात् पतन के कारण हजारों जन बेरोजगार हो गये थे जिनका तुरन्त नियंत्रण करना एक अत्यन्त आवश्यक कार्य था। राष्ट्रपति जॉनसन ने 3.4 बिलियन डालर की विदेशी सहायता की राशि को भी नियंत्रित किया। कांग्रेस में बहुमत होने के कारण इनकी सभी योजनायें सफल होती चली गईं। रेल कर्मचारियों की एक बड़ी हड़ताल चल रही थी, इस कारण अमरीकी उद्योग को अत्यन्त हानि हो रही थी। राष्ट्रपति ने स्वयं रेलवे परिषद से सहयोग व संघ के कार्यकर्ताओं से वाद विवाद करके इस समस्या को सुलझाया।

इन समस्याओं के मध्य पनामा राष्ट्र में अमरीकी द्वेष भावना युक्त एक क्रान्ति उठ खड़ी हो गई। जनवरी, 1964 में अमरीकी प्रशासन का पनामा नहर नियंत्रण का विरोध प्रकट करते हुये अनेक नृशंस घटनायें हुईं। अमरीका का, 1903 की 'एक पक्षीय सन्धि' के प्राविधानों द्वारा पनामा नहर पर शताब्दी के प्रारम्भ से ही नियंत्रण चल रहा था। राष्ट्रपति जॉनसन ने परिस्थिति का अवलोकन करते हुये पनामा प्रशासन को सान्त्वना व सहायता प्रदान की।

तत्पश्चात् दिसम्बर, 1964 में अमरीका ने इस आशंकनीय संधि के प्राविधानों में परिवर्तन लाने का वचन दिया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति जॉनसन ने एक नवीन समुद्र तटीय नहर के निर्माण की भी योजना प्रस्तुत की। पुरानी नहर आधुनिक व्यापार यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। इसके अतिरिक्त इस नहर में हड़तालियों को ध्वंसता के कार्य करने में भी अत्यधिक सहायता मिलती थी।

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जॉनसन का योगदान सराहनीय रहा। इसी मध्य 1964 के चुनाव के दिन निकट आ गये। लोकतांत्रिक दल के निस्कात नेता के रूप में जॉनसन ही उभर रहे थे। दल के सभी नेतृत्वकारी सदस्यों ने सर्वसम्मति से जॉनसन के नामांकन के लिये सहमति प्रदर्शित की। फलस्वरूप अगस्त, 1964 में अटलांटिक नगर में हुये लोकतांत्रिक समारोह में जॉनसन को जन्मदिन उपहार स्वरूप राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु मनोनीत किया गया परन्तु उप राष्ट्रपति पद के चुनाव पर अत्यन्त वाद-विवाद उठ खड़े हुये। पिछले राष्ट्रपति का अनुज रावर्ट कैनेडी (बावी), जो अपनी संगठन शक्ति, योग्यता एवं तीव्र कार्यविधियों के लिये प्रसिद्ध था, इस पद हेतु पूर्णरूप से योग्य व इच्छुक था। परन्तु राष्ट्रपति जॉनसन के सम्बन्ध बावी कैनेडी से सदैव कटुतापूर्ण रहे थे। जब जॉनसन ने हवर्ट हम्फ्री को अपने उप राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत किया तो सीनेटर कैनेडी ने चुनाव अभियान में भी सक्रिय भाग लेने से इन्कार कर दिया। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 1960 की जॉन कैनेडी की चुनाव विजय में उनके अनुज बावी कैनेडी के संगठन का बहुत बड़ा योगदान था। यद्यपि सीनेटर कैनेडी हमेशा ही मंत्री मंडल में महाधिवक्ता जैसे उच्च पद पर आसीन रहे, यह सम्बन्ध 1968 तक बराबर कटु बने रहे।

चुनाव अभियान में राष्ट्रपति जॉनसन ने अमरीकी समुदाय को नवीन विस्तृत समाज की स्थापना के लिये आह्वान किया एवं समृद्धि, गरीबी निवारण, शान्ति, दूरदर्शिता एवं उन्नति से युक्त नवीन समाज के निर्माण का वचन दिया। राष्ट्रपति जॉनसन ने दिशाओं के दृष्टिकोणों से पृथक हो, अमरीकी प्रशासन को सीधे मार्ग पर चलाने का वचन दिया। एक ओर तो जॉनसन के चुनाव कार्यक्रमों में उनकी नीतियों का जोर जोर से प्रचार हो रहा था, दूसरी ओर गणतंत्रवादी दल में नेता के चुनाव हेतु अनेक वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे। गणतंत्रवादी समारोह को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया। राज्यपाल राँकफेलर एवं सीनेटर वेरी गोल्डवाटर के मध्य एक तीव्र चुनाव बहस हुई। यहाँ तक कि दल में विभाजन की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। अन्त में सीनेटर गोल्डवाटर का पद हेतु नामांकन हुआ और दल में एकाग्रता एवं संघता बनी

रही। सीनेटर वेरी गोल्डवाटर रूढ़िवादी प्रकृति के थे। उन्होंने अमरीकी समाज को परिवर्तन के स्थान पर आईजनहांवर काल की सफल नीतियों की ओर अग्रसर होने को कहा, जिसमें साम्यवाद के विरुद्ध जटिल संघर्ष की नीति भी सम्मिलित थी। प्रारम्भ से ही चुनाव अभियान में लोकतांत्रिक दल का पासा भारी रहा। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक नेताओं ने जनता में गणतंत्रवादियों द्वारा तीसरे विश्वयुद्ध जैसे संघर्ष के भय की बात प्रचलित कर दी। सीनेटर गोल्डवाटर से नीग्रो समुदाय भी खिन्न था। इन्होंने नागरिक अधिकार विधेयक का तीव्र विरोध किया था। इसके अतिरिक्त गोल्डवाटर कैंनेडी काल की परमाणु परीक्षण निषेध संधि के भी विरुद्ध थे। 3 नवम्बर, 1964 के चुनाव दिवस को जॉनसन ने सीनेटर गोल्डवाटर को अत्याधिक मतों से पराजित किया। केवल दक्षिण के पाँच प्रान्त एवं अपने गृह के अरीजोना प्रान्त के मत ही गोल्डवाटर को प्राप्त हुये। दोनों सदनों में भी लोकतांत्रिक दल का बड़ा बहुमत स्थापित हो गया था। प्रचलित रूढ़िवादी दक्षिणी लोकतांत्रिक सदस्यों एवं उत्तरी गणतंत्रवादियों का संयुक्त मोर्चा भी टूट चुका था। इस प्रकार नव समाज के निर्माण के लिये सभी विधायिका मार्ग स्वतंत्र हो गये थे। लोकतांत्रिक दल की इस बड़ी विजय के अनेक कारण थे। जॉनसन जो उदार नीतियों के अनुयायी थे, एकाएक साम्यवादियों के कट्टर विरोधी हो गये थे। वर्ष 1964 की अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें भी चुनाव अभियान के समय जॉनसन के पक्ष में घटने लगी। चीन ने परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। ब्रिटेन के चुनाव में श्रमिक दल को भारी बहुमत प्राप्त हो गया। रूस के प्रधानमंत्री खुरश्चेव के निर्गमन पश्चात् कट्टर साम्यवादी दल पुनः सत्ता में आ गया। इसके अतिरिक्त जब उत्तरी वियतनाम की पनडुब्बियों ने अमरीकी जहाजों पर आक्रमण करना आरम्भ किया तो जॉनसन ने तुरन्त पूर्ण शक्ति के प्रयोग की आज्ञा दे दी। इन कार्यवाहियों से जॉनसन की प्रतिबिम्ब जनता में गहरी हो गई। इसके अतिरिक्त बड़े व्यापारी संघ के नेतागण जॉनसन के पक्षीय एवं मित्र थे। तथा नीग्रो समुदाय अपने अधिकारों को प्राप्त करने के पश्चात् राष्ट्रपति जॉनसन से अत्यधिक प्रभावित था इस प्रकार सभी घटनायें एक दूरदृष्टिता वाले राष्ट्रपति की माँग कर रही थी।

जनवरी, 1965 में नवासीवीं कांग्रेस के मध्य विजित राष्ट्रपति जॉनसन ने अपनी विस्तृत समाज के निर्माण की योजना रखी और उसके अनेक कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया। लोकतांत्रिक बहुमत से भरे हुए इस कांग्रेसी अधिवेशन ने इन कार्यक्रमों के लिये अत्यधिक नये व्यवस्थापनों की माँग की। इस कांग्रेस अधिवेशन की तुलना आधुनिक इतिहासकारों ने रुजवेल्ट के सौ

दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन से की है। इस प्रकार विस्तृत एवं महान समाज की योजना नव अर्थ नीति का एक दूसरा स्वरूप ही थी।

जॉनसन प्रशासन काल के आरम्भिक व्यवस्थापनों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों को प्राथमिकता थी। आर्थिक हीनता की स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिये कांग्रेस ने लगभग दो अरब डालर की नई योजना पारित की। इसके पश्चात् कैंनेडी काल से अनिश्चित पड़ी हुई 'मेडिकेयर' योजना के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। इस योजना में प्रौढ़ अवस्था वाले समस्त नागरिकों को अमूल्य एवं अनिवार्य चिकित्सा का प्रवन्ध था। इस योजना को ट्रूमैन काल में भी आलेखित किया गया था। इस समाजवादी योजना ने अमरीकी मेडिकल संघ को भी आघातित किया। तत्पश्चात् 1965 में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण "नीग्रो मताधिकार अधिनियम" पारित हुआ। यह एक प्रकार से "नागरिक अधिकार अधिनियम" का विस्तृत स्वरूप था। अलाबामा में इसके पश्चात् डा० मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में एक स्वतन्त्र जुलूस निकाला गया। कई स्थानों पर "के के के" संस्था के कारण नृशंस घटनाएँ भी हुईं। इस अधिनियम के पश्चात् नीग्रो समुदाय को पूर्ण रूप से प्रथक नागरिक का स्वरूप प्राप्त हो गया था। आवास समस्या को सुधारने हेतु कई नयी योजनाएँ बनाई गईं। कांग्रेस में एक कम मूल्य की आवासीय योजना हेतु एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया।

सामाजिक सुधार

शिक्षा के विकास एवं शिक्षा की आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 1965 की कांग्रेस अधिवेशन में दो अन्य विधेयक भी पारित हुये। 1.3 अरब डॉलर की एक वसिक्त शिक्षा योजना तैयार की गई जिसमें गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त 2.3 अरब डॉलर की एक अन्य योजना उच्च शिक्षा हेतु भी प्रस्तुत की गई जिसमें छात्रवृत्ति इत्यादि के प्राविधान थे। प्रशासन के अन्तर्गत शिक्षा परिषद का भी विस्तार किया गया। व्यक्तिगत संस्थाओं के शिक्षा संस्थान को वित्तीय सहायता में संवैधानिक प्रथम संशोधन, जिसमें राज्य और धर्म कार्य को पृथक किया गया था, के कारण अन्य बाधाएँ उत्पन्न हुईं परन्तु राष्ट्रपति जॉनसन ने विधेयक में उचित परिवर्तन करके उसे अनुकूल बना दिया। शिक्षा की महत्वता पर प्रकाश डालते हुये अपनी बहत्तर (72) वर्षीय जीवन की प्रथम शिक्षिका के समक्ष टैक्सास के अपने प्रथम स्कूल में राष्ट्रपति जॉनसन ने इस विधेयक पर

हस्ताक्षर किये थे ।

राष्ट्रपति जानसन की अध्यक्षता में हो रहे 1965 के इस कांग्रेस अधिवेशन में प्रवास एवं पुर्नसंगठन जैसी गहन समस्याओं के समाधान हेतु भी विचार विमर्श किया गया । अप्रवासियों के आगमन पर कोई निषेध न होने के कारण यह समस्या अत्यन्त जटिल होती जा रही थी । साक्षरता एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण के कार्यक्रम भी असफल हो चुके थे । राष्ट्रीय उत्पत्ति पर आधारित अप्रवासियों की संख्या के अंश स्थिरता की प्रणाली को पूर्णतया समाप्त कर दिया ।

इस समस्त व्यवस्थापनों को पारित करने के पश्चात आगामी अधिवेशन में कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद पर किसी आकस्मिक समय में पदासीन होने एवं उत्तराधिकार की प्रतिक्रिया को निखित करने हेतु भी विचार विमर्श हुआ । उप राष्ट्रपति द्वारा उत्तराधिकार को निश्चित करने हेतु एक संवैधानिक समिति का गठन हुआ । तत्पश्चात तीन चौथाई प्रान्तीय सदस्यों एवं विधान मण्डलीय सदस्यों के बहुमत द्वारा (किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिये इस प्रकार का बहुमत का निर्णय नितान्त अनिवार्य है ।) संवैधानिक संशोधन पारित हुआ । 1667 के इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति की प्रशासन काल के मध्य मृत्यु हो जाती है अथवा अपाहिज या अपंग हो जाता है, अथवा उससे सम्बद्ध किसी षडयंत्र का आरोप सिद्ध हो जाता है या वह अपने आपको स्वयं पद हेतु अयोग्य घोषित कर देता है तो सभी मामलों के पश्चात राष्ट्रपति के रिक्त पद पर उस प्रशासन काल के समय के लिये उपराष्ट्रपति उत्तराधिकारी होगा । इसी के साथ नवीन उपराष्ट्रपति का चयन शीघ्र ही होना चाहिए । उपराष्ट्रपति पद के लिये नामांकन राष्ट्रपति करता है तथा उसकी पुष्टि दोनों सदनों में बहुमत के द्वारा होती है ।

जॉनसन प्रशासन की 1965 के इस कांग्रेस अधिवेशन में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हुई । नगरीय क्षेत्रों की बढ़ती हुई शिथिलता एवम् अस्थिर जीवन का अवलोकन करते हुए कांग्रेस ने एक कैबिनेट स्तर के अन्य विभाग का सृजन किया । यह कार्यालय "आवास एवम् नगरीय विकास" विभाग के नाम से कार्यशील हुआ तथा इसके मंत्री पद पर नीग्रो अर्थशास्त्री डा० रावर्ट सी० वीवर का चयन हुआ । अमरीकी इतिहास में प्रथम बार एक नीग्रो को मन्त्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर का पद मिला । इस प्रकार नीग्रो समुदाय अपने आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित तथा प्रथम स्तर का अमरीकी नागरिक मानने लगा था ।

प्रशासन के इन सभी व्यवस्थापनों एवम् उनके कुशल अधीक्षण के पश्चात

जॉनसन के 'विस्तृत समाज' का स्वप्न लगभग साकार ही हो रहा था, कि अमरीकी समाज में नये उपद्रव एवं विपमतायें उत्पन्न होने लगीं। कांग्रेस के 1966 के अधिवेशनों के समय समाज में नव आवेश-पूर्ण लहर आ गयी थी नीग्रो समुदाय यद्यपि अनेक नागरिक अधिकारों को प्राप्त कर चुका था परन्तु फिर भी अल्पसंख्यकीय असन्तोषके रूपमें अभी भी अनेक मार्गों को लेकर आन्दोलन कर रहा था। इस आन्दोलन और प्रदर्शनों के कारण अनेक शहरों में नृशंस घटनायें भी हो रही थी। इसके अतिरिक्त अमरीका अब अपनी नयी दक्षिणी पूर्वी एशियाई नीतियों के कारण वियतनाम युद्ध में भी पूर्णतयाः उलझ गया था। इस युद्ध में अत्यधिक राजकीय व्यय के कारण आय-व्ययक एवम् कोष भी असंतुलित हो रहा था, जिस कारण राष्ट्रपति जॉनसन की गरीबी निवारण एवं नगरीय विकास की योजनायें विफल सी होने लगी थी।

सेना बजट में अत्यधिक वृद्धि के कारण राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था भी असंतुलित होनी आरम्भ हो गई। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण जीवन तथा रहन-सहन में परिवर्तन आने लगा था। बाह्य व्यापार में नयी ज्वालायें उत्पन्न हो गई, स्वर्ण भंडार में स्वर्ण मुद्रा के बाहर जाने के कारण कमी आने लगी। (अमरीकी स्वर्ण भंडार की स्थिति सारणी राष्ट्रपति कॅनेडी अध्याय में उपलब्ध है)। कांग्रेस में विरोधी दल के सदस्य विदेशी सहायता में कटौती की मांग कर रहे थे। सीनेट के अनेक सदस्य राष्ट्रपति जॉनसन की नीतियों का विरोध कर रहे थे। 1966 के अधिवेशन में लोकतांत्रिक दल के समर्थन के पश्चात् जॉनसन ने एक नया नागरिक अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में आवासीय सम्पत्ति की विक्री, पट्टेदारी अथवा किराये के मामलों में जातीय भिन्नता की कार्य विधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्राविधान था। अवर सदन में तो विधेयक थोड़े विवादपूर्ण भाषणों के पश्चात् पारित हो गया, परन्तु सीनेट में इसको पूर्ण पराजय मिली। गणतन्त्रवादियों एवं दक्षिणी लोकतांत्रिक सदस्यों ने यह विचार किया कि नीग्रो समुदाय के पड़ोसी होने के कारण श्वेत वर्णीय लोगों की सम्पत्तियों के मूल्य घट जायेंगे, तथा इस प्रकार का विधेयक असंवैधानिक विचारों से युक्त था। जॉनसन प्रशासन की एक अन्य असफलता 'टाँफ्ट हार्टले अधिनियम' के संशोधन के विषय को लेकर हुई। 1947 के इस अधिनियम के खण्ड 14 (ब) के अनुसार श्रमिक संघ की अनिवार्य सदस्यता से श्रमिकों को वंचित किया गया था। सीनेट में जॉनसन के सभी प्रस्तावों को बहुमत से अस्वीकृत कर दिया गया। इस पराजय से खिन्न होकर राष्ट्रपति जॉनसन ने श्रमिकों के हित के लिए नया 'न्यूनतम श्रम वेतन अधिनियम' का विधेयक प्रस्तुत किया। इसके अनुसार सम्पूर्ण संघ में समान रूप से 1.25 डॉलर

से 1.60 डॉलर का न्यूनतम श्रम वेतन निश्चित किया गया था। थोड़े विवाद के पश्चात् वह विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर 1966 में एक कानून बन गया। इसके कारण अस्सी लाख कम वेतन पाने वाले श्रमिक जिनमें मुख्य रूप से कृषि श्रमिक थे, लाभान्वित हुए।

पेट्रोल की गाड़ियों की अत्यधिक किस्में आने के कारण तथा मार्ग-नियमों की अज्ञानता के कारण नगरीय एवं राष्ट्रीय मार्गों पर प्रतिदिन सैकड़ों दुर्घटनायें होती थीं। रॉल्फ नादर नामक एक विधिवक्ता ने 1966 में गाड़ियों के उद्योगी एवं निर्यातों की समाचार पत्रों में कड़ी आलोचनायें की। उसके अनुसार निर्मातागण अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की शैलियों एवं गतिवाली गाड़ियों का निर्माण करते हैं तथा इस कार्य में संलग्न हो वे गाड़ियों में किसी प्रकार के सुरक्षा यन्त्रों का प्रबन्ध भी नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति जॉनसन ने इन दुर्घटनाओं का अवलोकन करते हुये प्रतिदिन की सैकड़ों मृत्युओं के अवरोधण हेतु 1966 की कांग्रेस में दो नये विधेयक प्रस्तुत किये जिसके फलस्वरूप दो नये अधिनियम विधि रूप में प्रत्यक्ष हुये। प्रथम, 'यात्री सुरक्षा अधिनियम' में राष्ट्रीय कानून के रूप में मोटर एवं अन्य गाड़ियों में न्यूनतम सुरक्षा प्रबन्ध के मानकों का निश्चय किया गया था, जो प्रत्येक उद्योगी तथा गाड़ियों के निर्माताओं के लिये अनिवार्य था। दूसरा "राष्ट्रीय मार्गसुरक्षा अधिनियम" था, जिस के अन्तर्गत वे प्राविधान थे जो राज्यों पर नागरिक सुरक्षा हेतु लागू होते थे। इन प्राविधानों को प्रत्येक राज्य द्वारा समान रूप से मानना अनिवार्य था। यातायात एवं व्यापार परिवहन की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुये इसी कांग्रेस में एक नये विभाग के सृजन का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके बहुमत से पारित होने के फलस्वरूप कैबिनेट स्तर का "परिवहन एवं यातायात विभाग" पृथक रूप से कार्यशील हुआ। इस प्रकार राष्ट्रपति मंडल में इस बारहवें सदस्य की नियुक्त हुई।

गणतंत्रवादियों का पुनः उदय

अमरीकी इतिहास में प्रायः यह देखने को मिला है कि मध्य में होने वाले कांग्रेस सदनों के सदस्यों के चुनाव में, सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य अवश्य ही पराजित होते रहे हैं परन्तु 1966 के निर्वाचनों में गणतंत्रवादियों ने आश्चर्य युक्त विजय प्राप्त की। इस दल के सीनेट में तीन एवं अवर सदन में सैंतालिस नये सदस्य-निर्वाचित हो सम्मिलित हुये थे। इस प्रकार गोल्डवाटर की पराजय के

समय दल की स्थिति जिसमें गणतंत्रवादियों ने अड़तीस सदस्य खोये थे, को भी पुनः संगठित कर लिया। यद्यपि दल अभी भी सदनों का नियंत्रण नहीं कर सकता था, परन्तु विरोधी पक्ष अत्यन्त सुदृढ़ हो गया था। राज्यों एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भी गणतंत्रवादियों को विजय प्राप्त हुयी थी। 'विरोधी मोर्चा' 1968 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तीव्र गति से कर रहा था। जॉनसन की वियतनाम युद्ध की नीति, नगरीय अपराधों में वृद्धि एवं जातीय भिन्नता के क्लेशों के कारण लोकतंत्रिक दल के प्रति जनता में प्रतिकूल भावनाएँ उत्पन्न होने लगी थी। यहाँ तक कि मैसाचूसेट्स के गणतंत्रवादी नीग्रों महाधिवक्ता एडवर्ड वुक श्वेत वर्णीय मतों के द्वारा विजयी हुये थे। पुनःनिर्माण युग के पश्चात सीनेट के यह प्रथम नीग्रों सदस्य थे। इन निर्वाचनों के पश्चात अपने सत्र के अंतिम चरण में (90वीं) कांग्रेस के अन्तर्गत राष्ट्रपति जॉनसन को अपनी नीतियों को कार्यशील करने में अनेक प्रतिबन्धों एवं प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। मुद्राप्रस्फुटन को कम करने के लिये राष्ट्रपति ने आयक के अन्तर्गत दस प्रतिशत अतिरिक्त कराधान की माँग की परन्तु उनका तीव्र विरोध किया गया। इसके अतिरिक्त विरोधी पक्ष ने विदेशी सहायता में बड़ी कटौतियों की माँग की। इस कटौती के फलस्वरूप जॉनसन की वैदेशिक नीति में परिवर्तन आने लगा।

1968 में विदेशी सहायता की मात्रा 1.7 अरब डॉलर मात्र ही रह गई थी जो पिछले बाईस (22) वर्ष में सबसे कम संख्या थी। जॉनसन की इस कांग्रेस में दूसरी पराजय मुख्य न्यायाधीश के नामांकन के विषय को लेकर हुई। मुख्य न्यायाधीश वॉरेन के त्यागपत्र के पश्चात जॉनसन ने न्यायाधीश के पद हेतु एक नया नाम प्रेषित किया, परन्तु कांग्रेस में तीव्र विद्रोह उठ खड़ा हुआ, फलस्वरूप यह नामांकन प्रशासन को वापस लेना पड़ा। इस प्रकार नव अर्थ नीति का अनुयायी राष्ट्रपति जॉनसन की "महान समाज" की नीति अब प्रतिदिन शिथिल हो रही थी। इन प्रतिरोधों के होते हुये भी "महान समाज" की नीति के कुछ आवश्यक व्यवस्थापन किसी तरह कांग्रेस में पारित हो ही गये। 1968 के आरम्भिक अधिवेशन में सर्वव्यापी "समाजिक सुरक्षा अधिनियम" पारित हुआ। इसके फलस्वरूप प्रस्फुटन से पीड़ित दो करोड़ चालिस लाख पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के भुगतानों में वृद्धि की गई। एक अतिरिक्त नागरिक अधिकार का विधेयक, जो 1966 में पारित न हो सका था, नीग्रो नेता डा० लूथर किंग की हत्या के पश्चात नयी भावना के कारण पारित हो गया। इस अधिनियम के अनुसार आवासीय सम्पत्ति की पट्टेदारी एवं विक्री में जातीय भिन्नता पर निषेध लगा दिया गया था इसी अधिनियम से संलग्न

एक अन्य विधेयक "आवासीय एवं नगरीय विकास" अधिनियम भी पारित हुआ। इस अधिनियम के फलस्वरूप 5.3 अरब डालर की एक तीन वर्षीय सार्वजनिक आवास एवं नगर विकास की योजना तैयार की गई। अपराधों को कम करने व कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रपति जॉनसन ने एक अपराध अवरोधक कानून भी निर्मित किया। सुप्रसिद्ध नेताओं व महान व्यक्तियों की हत्याओं के पश्चात् जनता में पिस्तौल आदि जैसे अस्त्रों की विक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग उठी। 1963 में जॉन कॅनेडी, फिर लगातार डा० लूथर किंग, जार्ज रॉकवेल, राबर्ट कॅनेडी, व अन्य नेताओं की हत्याओं से अमरीकी समाज खिन्न हो गया था। इस प्रकार के अस्त्रों से शताब्दी के प्रारम्भिक वर्ष से 1968 तक अमरीका में सात लाख पचास हजार हत्याएँ हो चुकी थी जो कि अमरीका की युद्धरत मानव क्षति से भी अधिक थी। इन सभी परिस्थितियों के अवलोकन के पश्चात् अग्निअस्त्रों के नियंत्रण हेतु कांग्रेस में एक नया विधेयक प्रस्तुत हुआ। 'राष्ट्रीय राईफल संघ' जैसी अनेक बड़ी संस्थाओं ने इसका विरोध किया। वे लोग अग्नि अस्त्र को स्वयं सुरक्षा का एक आधार मानकर इसके धारण के स्वतंत्र अधिकार की माँग कर रहे थे। इन सब विरोधों के पश्चात् भी "अग्नि अस्त्र नियंत्रण अधिनियम" पारित हो गया। यह राष्ट्र में पिछले तीस वर्षों में पहला इस प्रकार का कानून था। सभी प्रकार के घातक एवं तीव्र अग्नि अस्त्रों का निबंधन अनिवार्य हो गया था।

नीग्रो विद्रोह

अनेक नागरिक अधिकार व्यवस्थापनों के फलस्वरूप भी कॅनेडी काल से चली आ रही नीग्रो क्रान्ति की ज्वाला राष्ट्रपति जॉनसन के सत्त में भी भड़कती रही। अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित अब तक हो रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शनों के स्थान पर नये नेताओं व भावनाओं के आगमन से अब हिंसाकारी गतिविधियाँ अत्याधिक प्रचलित हो गई थीं। नीग्रो जाति के उग्रवादी ने ताफ्लॉयड विंक्सलर मेकिस्सिक तथा स्टोकली कॅरमाइकल असमानता व्यवस्थापनों के विरुद्ध पूर्ण समानता की माँग कर रहे थे। "ब्लैक पावर" उनका मुख्य नारा बन गया था और इस ब्लैक पावर के भीतर इतनी एकाग्रता तथा संघता व्याप्त थी कि नीग्रो समुदाय अपनी सभी माँगों को पूरी करवा लेते थे। नीग्रो वर्ग के व्याकुलता एवं विद्रोह के अनेक कारण थे। अशिक्षित श्रमिक की माँग कम होने के कारण इस वर्ग में बेरोजगारी अत्यधिक थी। कार्यहीनता, निराशावाद के कारण नीग्रो वर्ग मद्र व नशीली दवाइयों का सेवन अत्यधिक करता था, इस

कारण नीग्रो अपराध भी प्रचल थे। आवासीय जातीय भिन्नता अभी भी प्रचल थी, इस कारण नीग्रो समाज गन्दगी व दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा था। एक ओर श्वेत वर्णीय युवकों के देशान्तर प्रवासपर प्रतिबन्ध लगाये जाते थे, दूसरी ओर सांस्कृतिक भिन्नता के कारण नीग्रो समुदाय के युवकों को विदेश जाने की खुली छूट थी। सैकड़ों की संख्या में नीग्रो युवक वियतनाम जा रहे थे। सैन्य कार्यों में भी नीग्रो वर्ग को अनिवार्य रूप से कार्य करना पड़ता था। सातवें दशक के इस अंतिम चरण में भी श्वेत वर्णीय लोगों से भरे हुये इस अमरीकी समाज से नीग्रो समुदाय सांस्कृतिक मिलाप की चेष्टा करता था परन्तु ब्लैक मुसलिम समाज इसके विपरीत पृथकतावाद का नारा दे रहा था। 1965 की मालकोम एक्स की हत्या के पश्चात इस जातीय भिन्नता में हिंसावाद का आगमन हुआ। इसके पश्चात अगस्त, 1965 में 'लास ऐन्जिल्स' नगर में एक श्वेत वर्ण पुलिस अधिकारी द्वारा एक नीग्रो युवक को गिरफ्तार करने के पश्चात जातीय युद्ध भड़क गया। एक सप्ताह के हिंसा, लूट व अग्निकांड के वातावरण में चौंतीस व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त सैकड़ों घायल हुये और चौदह करोड़ डालर की सार्वजनिक क्षति हुई। उदार प्रकृति लोगों ने प्रशासन से जातीय पक्षपातों को समाप्त करने की माँग की। इसके बाद 1966 का वर्ष किसी तरह व्यतीत हुआ परन्तु 1967 के आरम्भ से ही पुनः हिंसा पूर्ण गति-विधियाँ आरम्भ हो गईं। डिट्रॉयट नगर में एक माह तक दुर्घटनायें होती रही जिसके फलस्वरूप दो सौ मिलियन डालर की क्षति और अनेक लोगों की मृत्यु हुई। पुनः 4 अप्रैल, को 'मेमफिस', टेनेसी में महान नीग्रो नेता 'डा०मार्टिन लूथर किंग' की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात नीग्रो समस्या का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो गया जिसमें नीग्रो लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति और सक्रियता दर्शाना आरम्भ कर दिया।



नव्य उपनिवेशवाद

अध्याय 14

एशिया में अमरीका

नव्य उपनिवेशवाद की ओर

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने तक मध्य एशियाई शक्तियों में केवल ब्रिटेन ही ऐसा राष्ट्र था जो पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी स्वार्थों को उस क्षेत्र में प्रस्तुत कर रहा था। परन्तु जब यूरोपीय राजनैतिक स्तर पर ब्रिटेन की इस साम्राज्यवादी नीति एवं स्वार्थों की अवहेलना होने लगी तो इससे ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति को त्रिकोणीय चुनौती का आभास हुआ। प्रथम हिटलर के विश्व विजय की अभिलाषा, द्वितीय मुसोलनी की फाशिज्म (फासीवाद) नीति तथा तृतीय पश्चिमी एशिया के देशों का ब्रिटेन की नीति के प्रति वितृपणा। इसके अतिरिक्त पश्चिमी एशिया में रूस ब्रिटेन की नीतियों का घोर विरोधी था यद्यपि बॉलशेविक क्रान्ति के पश्चात् रूस की नीतियों में अत्यधिक परिवर्तन आ गया था परन्तु फिर भी रूस पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाये रखने का इच्छुक था। इसके साथ-साथ अमरीका भी अपने तेल स्वार्थों के हित में पश्चिमी एशिया में अपनी रुचि प्रदर्शित करने में प्रयत्नशील था। इस इच्छा को पूर्ण करने का सुअवसर अमरीका को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् प्राप्त हुआ। पश्चिमी एशिया में ब्रिटेनकी सैन्य शक्ति के ह्रास के साथ ही 'सत्ता शून्यता' उत्पन्न हो गई और इस अभाव के प्रति अमरीका ने पश्चिमी एशिया की समस्याओं में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। पश्चिमी एशिया में अमरीका के निम्नलिखित ध्येय थे :—

1. पश्चिमी एशिया में स्थिरता एवं शान्ति की स्थापना।
2. नवनिर्मित इसराएल राज्य की सुरक्षा।
3. क्षेत्रीय सुविधायें प्राप्त करने का प्रयास तथा प्राकृतिक साधन एवं सम्पत्ति का उपयोग।

4. सोवियत रूस के प्रभाव को पश्चिमी एशिया में सीमित करना ।

यद्यपि दो दशकों से भी अधिक काल तक उपर्युक्त ध्येय अधिकतर पारस्परिक विवाद के कारण बनते रहते । इसका ज्वलंत उदाहरण अमरीका की इसराएल के प्रति नीति थी । अमरीका ने इसराएल की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के प्रयास में अन्य अरब राष्ट्रों को अपना विरोधी बना लिया, जिससे पश्चिमी एशिया की शान्ति एवं स्थिरता भंग हो गई । इसके अतिरिक्त, अमरीका ने 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' प्रतिमान पर 'संयुक्त सुरक्षा संगठन' का गठन किया । इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी एशिया में रूसी प्रभाव को सीमित करना था । परन्तु इस संगठन ने ईराक में पश्चिम समर्थक सरकार को निर्बल कर दिया । फलस्वरूप सोवियत रूस के प्रभाव की वृद्धि में यह सहायक सिद्ध हुआ ।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् पश्चिमी एशिया में अमरीकी नीति पारस्परिक विरोध एवं दुविधा का सम्मिश्रण थी । एक ओर अमरीका इस क्षेत्र में रूसी प्रभाव को सीमित करने हेतु अरब राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा संगठन में सम्बद्ध करना चाहता था, परन्तु दूसरी ओर फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के निर्माण के पश्चात् अमरीका ने अन्य देशों पर इसराएल को मान्यता प्रदान करने हेतु कूटनीतिक दवाव डालना आरम्भ कर दिया । अमरीका की इस नीति का अरब वासियों ने घोर विरोध प्रारम्भ किया । इससे पूर्व अरब राज्य दो विश्व युद्धों में पश्चिमी साम्राज्यवाद के अहेर बन चुके थे । अतः अरब देश किसी भी पश्चिमी साम्राज्यवाद नीति के समर्थन में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते थे । इसी मध्य दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् इसराएल की समस्याओं ने और गहन रूप धारण कर लिया । अमरीका फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के निर्माण का समर्थक अवश्य था परन्तु अरब देशों को भी इस विश्वास पर अपने साथ बनाये रखना चाहता था कि फिलिस्तीन की समस्याओं पर कोई निर्णय अरब नेताओं के परामर्श के बिना नहीं किया जायेगा ।

अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, अरब वासियों एवं यहूदियों के मध्य समझौते के प्रति, आशान्वित थे । इस कारण वह दोनों देशों की मध्यस्थता करने के इच्छुक थे । द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमरीका की राजनैतिक नीति पश्चिमी एशिया में कुछ-कुछ स्पष्ट होने लगी । इसका एक मात्र कारण हिटलर के नृशंस अत्याचारों से द्वस्त यहूदियों के प्रति अमरीका की सहानुभूति थी । द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के द्वारा संतुप्त यहूदी शरणार्थी फिलिस्तीन में आना चाहते थे अमरीका ने ब्रिटेन की सरकार से फिलिस्तीन में एक

लाख शरणार्थियों के प्रवास हेतु सहायता मांगी। अमरीका की इस नीति का प्रबल विरोध अमरीका के ही प्रशासक वर्ग में उत्पन्न हुआ, क्योंकि अमरीका के संयुक्त सेना अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी वर्ग अमरीका की इस नीति के विरोध में थे। चूँकि अमरीका की जल सेना विभाग की यह धारणा थी कि अरब राज्यों के तेल की सहायता के बिना अमरीका कोई बड़ा युद्ध लड़ने में असमर्थ है, इसलिये उनके मतानुसार अरब सहयोग आवश्यक था। अतः अमरीका की फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के निर्माण के समर्थन की नीति, अमरीका को अरब सहयोग से वंचित कर सकती थी। इस 'तेल समूह' का मुख्य प्रवक्ता एवं प्रवर्तक अमरीका का प्रतिरक्षा सचिव जेम्स फोरस्टॉल था। इसके अतिरिक्त अमरीका की इस नीति का विरोध, इस आधार पर भी किया गया, कि उपर्युक्त अमरीकी कार्य के कारण अरब राष्ट्र रूस की सहायता प्राप्त कर सकते थे। रूस भी फिलिस्तीन में यहूदी राज्य निर्माण का समर्थक था। अमरीकी अधिकारियों की यह धारणा थी कि रूस की 'यहूदी समर्थक नीति' फिलिस्तीन में ब्रिटिश प्रभाव को नष्ट करने हेतु थी और अरब राष्ट्रों में राजनैतिक अवसर प्राप्त करने की कूटनीतिक चाल थी। इसका परिणाम यह दृष्टिगोचर हुआ कि अरब राष्ट्रों में रूसी प्रभाव को रोकने की पश्चिमी देशों की नीति असफल हो जायेगी तथा अरब राष्ट्रों से तेल प्राप्त करना कठिन हो जायेगा। इस संदेह का मुख्य प्रवक्ता लायड हेन्डरसन था जो अमरीका के निकट पूर्व प्रभाग का अध्यक्ष था। इसके विपरीत अमरीका में यहूदी समर्थकों की संख्या विरोधी समूहों से अधिक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि अमरीका में सियोनवादी संगठन के निर्माता काँइम वाँइजमान (वाइट्समान) का अमरीकी जनता पर प्रभाव था एवं जन साधारण अमरीका इस नीति के समर्थन में थे। इसके अतिरिक्त अमरीका की काँग्रेस एवं सिनेट भी यहूदी राष्ट्र की समर्थक थीं।

उपरोक्त विरोध एवं समर्थनके पश्चात अमरीका ने ब्रिटिश अधिदेश पद्धति को यहूदी समर्थक नीति के परिपालन पर बल दिया कि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित एक लाख यहूदियों को फिलिस्तीन में प्रवास करने की अनुमति प्रदत्त करेगा। ब्रिटिश सरकार ने अमरीका की सरकार को इस तथ्य से अवगत कराया कि 'ब्रिटिश अधिदेश शासन' एक लाख यहूदियों को फिलिस्तीन में प्रवास करवाने में असमर्थ है। इस पर अमरीका के राष्ट्रपति ब्रिटिश सरकार से पुनः अपनी नीति में परिवर्तन कराना चाहते थे और इस हेतु राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उत्पीड़ित यहूदियों की सहायतार्थ उदारचित्त नीति के परिपालन की माँग की। इस पर ब्रिटिश सरकार ने अमरीकी सरकार को एक सम्मिलित आयोग बनाने का परा-

मर्ण दिया, जिसके द्वारा फिलिस्तीन की राजनैतिक स्थिति का समुचित रूप से अध्ययन किया जा सके।

उपरोक्त आधार पर 'आंग्ल-अमरीकी आयोग' स्थापित किया गया जिसका मुख्य कार्य फिलिस्तीन की तत्कालिक राजनैतिक स्थिति का अवलोकन करना था। इस आयोग ने अपनी जाँच करने के पश्चात् इस तथ्य को स्पष्ट किया कि फिलिस्तीन में अधिदेश पद्धति नितान्त असफल थी और इस आधार पर संयुक्त राष्ट्रीय पद्धति का समावेश करना उचित था। तदोपरान्त एक "यूनाइटेड नेशन्स स्पेशल कमीशन ऑन पैलिस्टाईन" का गठन किया गया, और इसके द्वारा फिलिस्तीनी समस्याओं के समाधान करने की चेष्टा की गई। इस आयोग ने भी विशेष सफलता प्राप्त नहीं की। अन्ततः संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में फिलिस्तीन में इसराएली राष्ट्र की मांग को रखा गया। संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में जब सदस्य गण फिलिस्तीन के विभाजन व 'ट्रस्टीशिप' पर वाद विवाद कर रहे थे, वेन गुरियाँ एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने 14 मई, 1948 को स्वतन्त्रता घोषित कर दी।

सर्व प्रथम इसराएल को मान्यता राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दी।

अरब-देश (1951-1958)

अमरीका के अरब राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने के दो प्रमुख ध्येय थे:-
क- मध्य-पूर्व एशिया में अमरीका अपना प्रभाव क्षेत्र इसलिये विस्तृत करना चाहता था क्योंकि वह रूसी हस्तक्षेप में अवरोध उत्पन्न करने हेतु अरब देशों के साथ राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गठबन्धन करने का इच्छुक था।

ख- अरब इसराएल संघर्ष का कूटनीतिक समाधान। इस ध्येय की पूर्ति अमरीका दोनों देशों की आर्थिक सहायता एवं एरिक जोस्टन कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता था। एरिक जोस्टन कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों देशों के मध्य सहयोग भावना के विकास पर बल दिया गया था।

अरब राष्ट्रों के साथ अमरीकी नीति के निर्धारण में अत्याधिक समस्याएँ थीं। प्रथम मिस्र, ईराक एवं सीरिया में समस्याओं का स्वरूप अन्य अरब राष्ट्रों से भिन्न था, अतः समाधान एक समान नहीं हो सकते थे। द्वितीय, अमरीका की अरब राष्ट्रों के प्रति नीति अमरीका के विदेश सचिव, जॉन फॉस्टर डलेस के व्यक्तित्व, से प्रभावित थी। 1953-58 के मध्य यह नीति विदेश सचिव डलेस एवं मिस्र के गेमल अब्दुल नासिर के विश्वासों एवं अभिलाषाओं पर आधारित थी। मिस्र के प्रति अमरीका की नीति इस बात पर आधारित थी

कि या तो वह अरब राष्ट्रवाद का समर्थन करे अथवा 'अरब राष्ट्रों की एकता' से सहानुभूति रखे। अरब राज्य में ब्रिटेन की उपस्थिति, तथा मिस्र में नासिर सरकार के अविश्वासपूर्ण व्यवहार के कारण, अमरीका अरब राष्ट्रों में गम्भीर रूप से रुचि लेने का इच्छुक नहीं था। इसके अतिरिक्त अमरीका ने ब्रिटेन के सहयोग से अरब यहूदी संघर्ष का अन्त, सुरक्षा संगठन के निर्माण, ब्रिटिश सेनाओं की स्वेज क्षेत्र से वापसी एवं अरब-राष्ट्रों की आर्थिक सहायता करने का यथा सम्भव प्रयत्न किया। 1950 में एक 'त्रिपक्षीय घोषणा' हुई जिसपर ब्रिटेन, फ्रांस एवं अमरीका तीनों ने हस्ताक्षर किये। इसके अनुसार तीनों राष्ट्रों ने अरब राष्ट्रों एवं इसराएल के मध्य 'अस्त्र-प्रवाह सीमाओं' के उलंघन का विरोध किया तथा ऐसे किसी कार्य के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी। 1951 में संयुक्त राज्य अमरीका ने ब्रिटेन, फ्रांस एवं तुर्की के मध्य 'पश्चिमी एशिया सुरक्षा संगठन' का गठन किया। यद्यपि अमरीका का यह प्रयास अल्पकालिक ही सिद्ध हुआ, परन्तु इस दशक में अरबों का सहयोग प्राप्त करने का अमरीका ने यथासम्भव प्रयत्न किया। इस काल में मध्य अमरीका और मिस्र के सम्बन्ध प्रगाढ़ मित्रतापूर्ण रहे। जुलाई 23, 1952 को शाह फारूख के विरुद्ध सैनिक विप्लव से पूर्व अमरीका ने मिस्र में समाजिक एवं आर्थिक सुधारों हेतु सहायता दी। तत्पश्चात् सैनिक परिपद् से भी अमरीका के सम्बन्ध अच्छे रहे। 1954 में अमरीकी नीति में एक परिवर्तन हुआ। 1953 में जॉन फॉस्टर डलेस की विदेश सचिव पद पर नियुक्ति के पश्चात् अमरीका के विदेश मंत्रालय में यह आशा व्यक्त की गई, कि यदि इसराएल एवं अरबों के मध्य सन्तोपजनक समझौते हो जाय, तो अरब राष्ट्रों के साथ सुरक्षा समझौता आसानी से किया जा सकता है। इस दिशा में राष्ट्रपति आइजनहावर ने प्रयास किये। अरब राष्ट्रों एवं इसराएल के मध्य तनाव कम कराने हेतु उन्होंने जार्डन नदी के पानी के विभाजन पर समस्या निवारण हेतु सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त नासिर को सैनिक सहायता देने हेतु विचार विमर्श प्रारम्भ किया, परन्तु फरवरी, 1955 में इसराएल ने गाजा पट्टी पर आक्रमण करके इन प्रयासों को असफल कर दिया। अमरीका के अथक प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने 1956 में इस क्षेत्र का भ्रमण किया।

इसी बीच 1955 में ईराक एवं तुर्की के मध्य 'वगदाद समझौते' पर हस्ताक्षर हुए। नासिर चूँकि इस समझौते के विरुद्ध थे, अतः उन्होंने इसका सारा दोष अमरीका को दिया। इसके परिणामस्वरूप 1955 में नासिर ने सोवियत रूप के साथ सैन्य सामग्री की प्राप्ति हेतु एक संधि कर ली। अमरीका ने अपने प्रयासों में और अधिक वृद्धि करने के लिए दिसम्बर, 1955 में 'आसवान

वाँध कार्यक्रम में आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया एवं मिस्र के साथ सम्बन्ध बनाये रखने हेतु बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। परन्तु जब मिस्र ने अमरीका द्वारा आसवान वाँध के निर्माण कार्यक्रम में सहायता का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया, अमरीका ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया इससे रुष्ट होकर नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नासिर के उपर्युक्त निर्णय के कारण ब्रिटिश प्रधान मंत्री एन्थोनी ईडेन ने नासिर को पदच्युत करने का निश्चय किया। दूसरी ओर फ्रांस ने नाइजीरिया में नासिर का उन्मूलन करके अपनी समस्याओं को सुलझाने का एक स्वर्ण अवसर पाया। इसराएल को भी 'गाजा पट्टी' से गुरिल्ला केन्द्रों को नष्ट करने एवं तिरान के जलडमरूमध्य (स्टेट्स) को इसराएली समुद्री जहाजों के लिए खोलने हेतु मिस्र पर ब्रिटेन एवं फ्रांसके सहयोग से आक्रमण का सुअवसर मिला। पल-स्वरूप 1 नवम्बर, 1956 को ब्रिटेन, फ्रांस एवं इसराएल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से अमरीका रुष्ट हो गया। इसके कई कारण थे। प्रथम, इस आक्रमण के एक दिन पूर्व लन्दन स्थित अमरीकी राजदूत को ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उसे इस प्रकार के किसी आक्रमण की जानकारी नहीं थी। इसे अमरीकी सरकार ने विश्वासघात माना। द्वितीय, जॉन फास्टर डलेस एवं आइजनहावर को ब्रिटेन की पाउण्ड सुरक्षा हेतु सहायता की माँग ने अत्यधिक उत्तेजित कर दिया। तृतीय, डलेस ने एक न्यायविद होने के कारण इसे संयुक्त राष्ट्र घोषणा का उल्लंघन माना। इसके परिणामस्वरूप अमरीका ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा जो शीघ्र ही पारित हो गया। अमरीका ने इस स्वेज-युद्ध के परिणामों के प्रभाव को नगण्य करने हेतु इसराएल को 'साइनाई क्षेत्र' से पीछे हटने के लिये वाध्य कर दिया। अमरीका की इस नीति का अरब देशों में भव्य स्वागत किया गया।

इसी, समय अक्टूबर, 1956 में जार्डन में नासिर समर्थक सरकारकी स्थापना हुई। फलस्वरूप अमरीका ने सुल्तान हुसेन का समर्थन किया। इस कारण सुल्तान हुसेन ने कुछ समय पश्चात जार्डन में अपना नियंत्रण स्थापित किया और इस प्रकार इस समस्या का अन्त हुआ।

शीघ्र ही एक अन्य समस्या सीरिया में उत्पन्न हो गयी जब रूस समर्थक सेनाधिकारी को सीरिया का मुख्य सेनाधिकारी नियुक्त किया गया। तुर्की एवं ईराक में इसका विरोध किया गया। परन्तु इसी समय सीरिया की नीति में परिवर्तन के कारण सीरिया की समस्या का अन्त हुआ जबकि सीरिया ने देश में अराजकता को दूर करने एवं साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिये मिस्र के साथ संयुक्त होने का निर्णय कर लिया।

इसके विपरीत लेबनान में स्थित गम्भीर थी। 1958 में लेबनान में गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया था। इसका कारण यह था कि लेबनान के पश्चिम समर्थक राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल को बढ़ाने का प्रयास किया जो असंवैधानिक था। यद्यपि अमरीका लेबनान के राष्ट्रपति को सहायता देने का इच्छुक था परन्तु फिर भी प्रत्यक्ष रूप से अमरीका ने उसकी कोई सहायता नहीं की। जुलाई के उत्तरार्द्ध में संघर्ष का अन्त हो गया। 14 जुलाई, 1958 को ईराक में पश्चिम समर्थन सरकार का विप्लव के द्वारा शासन-परिवर्तन कर दिया गया। फलस्वरूप साम्यवादी प्रभाव का संकट पुनः उत्पन्न हो गया। परिणामस्वरूप लेबनान में अमरीकी सेना भेजी गयी जिससे वहाँ की पश्चिम-समर्थक सरकार की रक्षा की जा सके। लेबनान में अमरीकी सैनिकों के आगमन का एक अन्य कारण यह था कि अमरीका मध्य-पूर्व एशिया में ईराक की क्रांति की प्रतिक्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता था एवं जार्डन सरकार की सुरक्षा के लिये चिन्तित था, क्योंकि जार्डन में सरकार बदलने के कारण इसराएल को जार्डन के पश्चिमी तट पर प्रभुत्व का अवसर मिल सकता था यह इसराएल अरब के मध्य युद्ध का एक कारण बन सकता था। अमरीका अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ।

अरब देश (1959-1967)

सन 1958 के पश्चात् पश्चिमी एशिया में अमरीकी नीति के निम्न-लिखित ध्येय थे:-

- क- संयुक्त राज्य अमरीका एवं सोवियत रूस के मध्य प्रत्यक्ष संघर्ष को रोकना। इसका कारण यह था, कि दोनों देशों के मध्य संघर्ष में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग भी सम्भव था।
- ख- अरब इसराएल के मध्य सन्तोपजनक समझौते का प्रयास, क्योंकि इन देशों के मध्य संघर्ष रूस एवं अमरीका के मध्य युद्ध का एक कारण बन सकता था।
- ग- उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु प्रयास करना।

1958 के पश्चात् ईराक सरकार नासिर के विरुद्ध हो गयी थी तथा सोवियत संघ से इसके सम्बन्ध मधुर हो गये थे। नासिर साम्यवादियों का कटु विरोधी हो गया था। सीरिया एवं मिस्र के मध्य हुई संधि 1961 में भंग हो गयी। 1957 के अन्त में इसराएल साइनाई क्षेत्र से पीछे हट चुका था, फलस्वरूप मिस्र-इसराएल सीमा पर अपेक्षतया शांति थी। इसी समय

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अमरीका ने नासिर से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके अन्तर्गत अमरीका ने 1959 में नासिर को वृहद् मात्रा में खाद्य पदार्थ प्रदान किया। 1959 से 1963 तक यह नीति एक सीमा तक सफल रही।

सन् 1960 के पश्चात् राष्ट्रपति जॉन एफ. कॅनेडी ने नासिर के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने हेतु प्रयास प्रारम्भ किये। कॅनेडी ने अपने प्रयासों का शुभारम्भ अरब शरणार्थी समस्या को लेकर किया। 1961 में कॅनेडी प्रशासन ने अपने अथक प्रयासों द्वारा शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र के एक विशिष्ट प्रतिनिधि को मध्य-पूर्व एशिया भेजने की व्यवस्था की। जोजफ ई. जॉनसन को संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन समाधान आयोग का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। जॉनसन ने 1962 में अपना विवरण प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अरब शरणार्थियों के देश प्रत्यावर्तन अथवा क्षति-पूर्ति के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी तथा इसराएल में जाने को इच्छुक अरबवासियों की संख्या को निर्धारण के लिए इसराएल सरकार की मान्यता को आवश्यक बताया। परन्तु यह कार्यक्रम असफल हो गया। इस असफलता का मुख्य कारण यहूदियों द्वारा जॉनसन कार्यक्रम का विरोध करना था। यहूदियों के अनुसार अरब शरणार्थियों की समस्या का समाधान अरब एवं इसराएली शान्ति-संधि के बिना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त अमरीकी जनता ने इसमें कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की।

1962 में अमरीका ने जार्डन एवं सऊदी अरब की इच्छा के विरुद्ध यमन गणराज्य को मान्यता प्रदान कर दी। शीघ्र ही यमन में सऊदी अरब के सुल्तान एवं नासिर के मध्य संघर्ष का अन्त करने हेतु अमरीका ने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। अमरीका ने नासिर को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी फलतः अमरीका एवं मिस्र के संबंध तनावपूर्ण हो गये। 1963 और 1964 तक मध्य पूर्व में अमरीका की नीति में कई परिवर्तन हुए।

प्रथम : नासिर के साथ मधुर सम्बन्धों की अनुरक्षण-नीति में ह्रास हुआ क्योंकि अमरीकी संसद यमन में मिस्र के सैनिकों द्वारा संघर्षों में भाग लेने के कारण नासिर को अधिक सहायता प्रदान करने हेतु सहमत नहीं थी।

द्वितीय : 1963 में अमरीका ने इसराएल को 'हाक' प्रक्षेपास्त्र प्रदत्त किये जिसके फलस्वरूप अमरीकी-इसराएली सम्बन्ध अत्याधिक सुदृढ़ हो गये। इसके पश्चात् 1964 एवं 1965 के मध्य वियतनाम में संघर्ष प्रारम्भ होने के कारण अमरीका का ध्यान पश्चिमी एशिया से हट गया।

छह दिवसीय युद्ध :

1966 के पूर्वार्द्ध में अरब-इसराएल संघर्ष का प्रादुर्भाव हुआ जबकि इसराएल ने नवम्बर, में जार्डन के एक क्षेत्र अस-सामू पर आक्रमण कर दिया तत्पश्चात् अप्रैल 1967 में इसराएल का सीरिया की हवाई सेना के साथ संघर्ष हुआ। इस तनाव पूर्व वातावरण में 22 मई को मिस्र ने तिरान के जलडमरूमध्य को इसराएली युद्धपोतों के लिये बन्द कर दिया, जिसने इस तनाव में अत्यन्त वृद्धि की। अमरीका ने इसराएल से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने का निवेदन किया। इसी समय इसराएल के विदेश मंत्री 26-27 मई को वाशिंगटन पहुँचे, परन्तु इस समस्या का कोई समाधान न हो सका। फलस्वरूप 5 जून को इसराएल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया।

अरब-इसराएल युद्ध के प्रारम्भ होते ही अमरीकी सरकार के विदेश मंत्रालय में इस युद्ध के परिणामों पर चिन्ता व्यक्त की गई। इसराएली पराजय की स्थिति में अमरीका को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ता जिससे इस युद्ध का स्वरूप परिवर्तित होकर सम्भवतः अमरीकी-रूसी युद्ध हो सकता था। परन्तु इस युद्ध में इसराइल की विजय ने अमरीका को उपर्युक्त चिन्ता से मुक्त कर दिया। इस युद्ध का पूर्ण उत्तरदायित्व नासिर पर डाला गया। भविष्य में अरब-इसराएल संघर्ष में अमरीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता को न्यून करने के लिए दो निर्णय लिये गये प्रथम, इसराएल को सैनिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली बना दिया जाय कि उसको सैनिक सहायता की आवश्यकता ही न पड़े, एवं द्वितीय, उद्देश्य, अरब राष्ट्रों के साथ शान्ति संधि से पूर्व इसराएल का विभिन्न प्रदेशों से निष्क्रमण रोकना था। अमरीका के इस निर्णय का जनता में भव्य स्वागत किया गया।

22 नवम्बर, 1967 को राष्ट्रपति जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद में अपनी शान्ति समझौते की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें निम्नलिखित माँगें थी :—

- (क) अन्तर्राष्ट्रीय जल-मार्गों पर स्वतंत्र आवागमन।
- (ख) शरणार्थी समस्या का समाधान।
- (ग) प्रत्येक राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा एवं शान्ति को मान्यता।
- (घ) युद्ध के मध्य इसराइल द्वारा अधिकृत क्षेत्र से वापसी आदि।

इस प्रस्ताव पर सहमति हेतु डा. गुन्नार यारिंग को मध्यस्थता हेतु नियुक्त किया गया। परन्तु जॉनसन प्रशासन के 19 मास तक इस समस्या के समाधान में अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई तत्पश्चात् जॉनसन प्रशासन ने

कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे अमरीका द्वारा इसराएल को सैनिक रूप से सुदृढ़ रखने की इच्छा की पुष्टि हुई जून युद्ध के पश्चात् जार्डन एवं इसराएल ने अमरीका से अस्त्र-शस्त्र के क्रय हेतु इच्छा प्रकट की। जार्डन की इच्छा को अमरीका ने पूर्ण कर दिया, परन्तु 1958 के पूर्वार्ध तक अमरीका की जॉनसन सरकार इसराएल के निवेदन पर कोई निर्णय नहीं ले सकी थी। अन्ततः इसराएली प्रधान मंत्री के अमरीका भ्रमण के पश्चात् जॉनसन ने इसराएल को हथियारों की बिक्री की घोषणा कर दी। तत्पश्चात् मध्य पूर्व में स्थायी शान्ति की स्थापना हेतु ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमरीका द्वारा प्रयास जारी रहे। अन्ततः 1969 में अमरीका ने संघर्ष का अन्त करने हेतु एक प्रस्ताव रखा। इसमें शान्ति स्थापना के लिये दो तत्व आवश्यक बताये गये प्रथम : इसराएल द्वारा युद्ध में विजित प्रदेशों की वापसी एवं द्वितीय : अरब राज्यों द्वारा पूर्ण शान्ति का वचन। परन्तु यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। परिणामस्वरूप इसराएल ने संयुक्त अरब गणराज्य के क्षेत्रों में बमबारी जारी रखी। इसी मध्य मिस्र को रूस द्वारा सेम द्वितीय एवं सेम तृतीय प्रक्षेपास्त्र दिये जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और गम्भीर हो गई एवं अमरीका पर इसराएल को शस्त्र देने हेतु दबाव डाला गया। जून, 1970 में अमरीका ने एक अन्य शान्ति प्रस्ताव रखा जिस पर दोनों ही देश सहमत हो गये और उन्होंने युद्ध-विराम की स्वीकृति दे दी। सितम्बर, 1970 में जार्डन में गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया एवं मिस्र के राष्ट्रपति नासिर की मृत्यु हो गयी। इसी वातावरण में अमरीका ने इसराएल को अत्यधिक हथियार आपूर्ति का वचन दिया।

ट्रूमैन का सिद्धान्त

ट्रूमैन का सिद्धान्त सर्वप्रथम 1947 में यूनान-टर्की की संकट व्यवस्था के कारण घोषित हुआ। यूनान में वाम पन्थियों और दक्षिण पंथियों के कारण राजनैतिक अव्यवस्था उपस्थित थी। स्टालिन यूनान में हस्तक्षेप कर टर्की को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाता चाहता था। डार्डेनेल्स क्षेत्र में रूस सदैव अपने प्रभुत्व-स्थापन का इच्छुक था। यूनान में गृहयुद्ध के कारण वहाँ की सरकार ने ब्रिटेन से सहायता मांगी परन्तु ब्रिटेन स्वयं आर्थिक रूप से संकटग्रस्त होने के कारण सहायता प्रदान करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में रूस के प्रभाव को रोकने के लिये तथा उस क्षेत्र में राजनैतिक रिक्तता की पूर्ति हेतु अमरीका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्च 12, 1947 को एक घोषणा की जिसमें राष्ट्रपति ने स्पष्टतया यह उल्लेख किया कि अमरीका सदैव स्वतंत्र देशों का हितैषी रहा और वह हर

प्रकार के वाह्य प्रभाव के द्वारा अधीनीकरण का विरोधी रहा है। यह अमरीका की हस्तक्षेप-विरोधी नीति थी। अंतएव अमरीका की इस नीति को ट्रूमैन सिद्धान्त कहा गया। अमरीका की इस नीति ने यूनान और टर्की को नवीन उत्साह प्रदान किया तथा रूस की 'हस्तक्षेप प्रभाव' की नीति को असफल किया। इस सिद्धान्त की नीति की व्याख्या में राष्ट्रपति ने कहा कि यदि अमरीका स्वतंत्र देश की जनता की सहायता नहीं करेगा तो विश्वशान्ति के लिए संकट उत्पन्न हो जायेगा। राष्ट्रपति ने इसके अतिरिक्त विश्व राजनीति का उल्लेख करते हुये कहा कि घटनाओं की तीव्रता के कारण अमरीका अपना निर्णय लेने पर बाध्य है, तथा यूनान और टर्की में सहायता पहुँचाना उसका कर्तव्य है। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा कि सर्वसत्तात्मक शासन ने जो स्वतंत्र जनता पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आक्रमणों के द्वारा सौंप दी गई है, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की बुनियाद को दुर्बल कर दिया है जिससे अमरीका की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसी उद्देश्य से प्रभावित होकर उसने संसद (कांग्रेस) को यूनान एवं टर्की को अनुदान देने के लिए प्रेरित किया। यह भी सुझाव रखा गया कि अमरीकी सैन्य एवं प्रशासकीय अधिकारी, टर्की के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करें। वास्तव में पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनर्निवेश अमरीकी अनुदान का प्रथम कार्यक्रम था। तथापि सोवियत रूस एवं कुछ पूर्वी यूरोप के देशों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया यद्यपि प्रतिग्राहक देशों के पुनर्निवेशन के इस कार्य में कुछ असुविधा अवश्य हुई, क्योंकि रूस की सीमित आर्थिक नीति को अमरीका की उदार आर्थिक नीति के साथ समाविष्ट करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। तदुपरान्त अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के विदेश मंत्री जनरल जार्ज मार्शल ने अपनी एक योजना (जून 1948) के पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये प्रोत्साहित किया, यूरोपीय देश अपनी आर्थिक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप साम्यवाद को अंगीकार न करें। इस प्रकार ट्रूमैन का सिद्धान्त तथा मार्शल की योजना ने अमरीका में एक नई विदेशी नीति का मार्ग दर्शन किया जो संतुष्टि के सिद्धान्त की आधार शिला पर स्थित था। सोवियत रूस की साम्यवादी नीति का आशय ही विस्तार से सम्बन्धित था। इस विस्तारात्मक नीति को रोकने के लिये अन्य राष्ट्रों की सहायता आवश्यक हो गयी थी। यद्यपि सीमा के चारों ओर सैन्य तैयारियाँ नहीं की जा सकती थीं, परन्तु सोवियत रूस ने अपने समस्त सामरिक स्थलों की सुरक्षा हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिये। इसके साथ-साथ रूस एवं अमरीका में आपसी वैमनस्य बढ़ता गया। रूसी नीति के परिणामस्वरूप सितम्बर के अन्त तक इसके निर्देश पर नौ (9) साम्यवादी (कम्युनिस्ट) देशों का पोलैण्ड

में सम्मेलन हुआ तथा 'केन्द्रिय सूचना केन्द्र' अर्थात् 'कम्यून फार्म' की स्थापना पर विचार किया गया। रूस के प्रतिनिधि जडन्वय ने कहा कि पश्चिमी देशों की विदेशी नीति का आधार रूस को प्रत्येक क्षेत्र से पृथक करने में निहित है। अतः 'कम्यून फार्म' की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी नीतियों की अवहेलना करना ही था। ट्रूमैन के सिद्धान्त ने यूनान एवं टर्की को सोवियत रूस के प्रभाव से अलग रखा तथा भूमध्यसागर एवं मध्य एशिया में रूस के प्रभाव का अन्त किया और इसी नीति के फलस्वरूप सैन्य सुदृढीकरण हेतु पश्चिमी यूरोप के समस्त देशों (कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नार्वे, आइसलैण्ड, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, बेल्जियम, सबसेमबर्ग तथा पुर्तगाल) ने मिल कर अप्रैल 4, 1949 को वार्शिंगटन में रक्षात्मक सन्धि अर्थात् 'नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आरगेनाइजेशन' की स्थापना की।

मध्य-पूर्व एशिया सुरक्षा संगठन एवं मिस्र

इसराएल देश की स्थापना ने अरब में पश्चिमी देशों के विरुद्ध राष्ट्रवादी आन्दोलनों को तीव्र कर दिया। जनवरी, 1950 में मिस्र में वफद दल के शासनारूढ़ होने के साथ ही, मिस्र में अंग्रेजी आधिपत्य की समाप्ति के लिये कार्य प्रारम्भ हो गये। मध्य पूर्व एशिया में रूस के प्रभाव का अन्त करने हेतु पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य तैयारियाँ होने लगी, साथ ही पश्चिमी देशों द्वारा मध्य एशिया में रूस के बढ़ते हुये प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा हेतु नये-नये तरीकों एवं संगठनों का निर्माण आवश्यक हो गया।

इस नये संगठन के निर्माण के लिये अमरीका प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो गया। इसके अतिरिक्त 'नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आरगेनाइजेशन' (नाटो) को अन्य यूरोपीय देशों में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। मई, 19, 1950 को वेविन एवं अमरीका के विदेश मंत्री एचिसन ने अपने विचारों द्वारा व्यक्त किया कि उनका देश टर्की, ईरान एवं यूनान की स्वतंत्रता के लिये अत्यधिक प्रयत्नशील है। अतः मई 25 को फ्रांस, इंग्लैण्ड एवं अमरीका ने मध्य पूर्व एशिया में शान्ति एवं स्थिरता बनाये रखने हेतु अपनी-अपनी रुचि प्रदर्शित की एवं इन शक्तियों ने यह भी घोषणा की कि वे इस कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी इसकी स्थिरता को बनाये रखने हेतु कार्य करेंगे। इन्हीं त्रिराष्ट्र समझौते ने मध्य एशिया के देशों को अपनी सुरक्षा हेतु सचेत भी किया।

इसी उद्देश्य के परिणाम स्वरूप नवम्बर, 1950 में मिस्र की सरकार ने 1936 की आंग्ल-मिस्र संधि की पुनरावृत्ति की माँग की, जिसके आधार पर

ब्रिटेन को शान्ति काल में 'मिस्र' पर से अपनी सैन्य शक्ति को हटा लेना था। अतः ब्रिटिश सरकार ने मिस्र की सरकार को उसकी सुरक्षा हेतु नये प्रस्ताव प्रस्तुत किये परन्तु मिस्र की सरकार ने इसके विरुद्ध 1936 के आंग्ल-मिस्र संधि की समाप्ति का ही प्रस्ताव रखा। अक्टूबर-18 को सैन्य कार्यवाही की अपेक्षा ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर आंग्ल-मिस्र वैमनस्य की समाप्ति हेतु नये प्रस्ताव रखे। ये प्रस्ताव मिस्र के सम्मुख फ्रांस, टर्की, इंग्लैण्ड, एवं अमरीका ने मध्य-पूर्व एशिया में सुरक्षा संगठन हेतु रखा। इन समस्त चार शक्तियों ने मिस्र को एक समान शक्ति के रूप में सम्मिलित किया। बाद में इस सुरक्षा संगठन में कामनवेल्थ की अन्य तीन शक्तियाँ अर्थात् आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित हो गयी। परन्तु 1954 में 'सीटो' (साउथ ईस्ट एशिया ट्री आरगेनाइजेशन) की स्थापना के साथ ही 'नाटो' एवं सीटो को सम्बन्धितकर, मीडो' का निर्माण तर्कसंगत प्रतीत हुआ। इससे पूर्व 1951 तक मीडो असफल रहा।

दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन

प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में भारत, वर्मा एवं इंडोनेशिया की तटस्थता की नीति के कारण शक्ति-संतुलन को बनाये रखने हेतु, अन्य शक्तियों ने सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टि के फलस्वरूप तय की सुरक्षा एवं सामाजिक दृष्टि से सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु इस योजना का निष्पादन सुचारु रूप से न हो सका क्योंकि अमरीका ने फारमोसा जपान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, तथा न्यूजीलैण्ड के साथ मिस्रकर एक पृथक सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी थी। साथ ही सिंगापुर का महत्वपूर्ण समुद्री तट ब्रिटेन के आधिपत्य में था तथा मलाया पर भी ब्रिटिश सेना का आधिपत्य था। अतः इन उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप प्रशान्त महासागर के इस क्षेत्र में एक सुव्यवस्थित संगठन, ('उत्तरी अटलान्टिक संधि संगठन' की भाँति) निर्मित हो पाना कुछ कठिन अवश्य था। इस कारण एक सुरक्षा समिति के अन्तर्गत, मिस्र एशियायी देश, प्रशान्त के अधिकृत देशों एवं पश्चिमी सम्मिलित देशों के नेताओं को संगठित करना था जो सुरक्षा के लिये कार्य कर सकते थे। यद्यपि पश्चिमी शक्तियों एवं प्रशान्त सागर शक्तियों के संघ की सहायता के बिना इस प्रकार का सुरक्षा संगठन सम्भव नहीं था परन्तु एशियायी मिस्र देशों की अनुपस्थिति ने अमरीका के इस क्षेत्र में प्रभाव को और भी प्रबल कर दिया। सितम्बर 8, 1954 को आस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन, अमरीका, फिलीपाइन्स थाईलैण्ड तथा पाकिस्तान से मिलकर, मनीला नामक स्थान पर चिर-

स्थाई एवं स्वतः सुरक्षा हेतु समझौता किया, जो दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन के नाम से विख्यात है। यह संगठन उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन एवं अन्य सुरक्षा संगठनों का पूरक है, और प्रशान्त महासागर की शक्तियों में मध्य-पूर्व सुरक्षा संगठन का प्रतिरूप है। दक्षिण वियतनाम लाओस तथा कम्बोडिया के साम्यवादी हस्तक्षेपों के कारण ये देश इस सुरक्षा संगठन में सम्मिलित नहीं किये गये, यद्यपि इन देशों को अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवादसे बचाने हेतु इस संगठन में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके विपरीत फिलीपाइन्स, थाईलैण्ड और पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में सुरक्षा हेतु कोई वास्तविक कार्य नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान तथा फिलीपाइन्स सैन्य सूत्रों में पश्चिमी देशों से सम्बन्धित थे। ये समस्त सुरक्षा संगठन साम्यवादी सिद्धांतों को रोकने हेतु किये गये थे।

बगदाद समझौता

1955 तक अमरीका के साथ पाकिस्तान-तुर्की समझौता एवं पाकिस्तानी पारस्परिक समझौता सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात् फरवरी 24, 1955 को तुर्की एवं ईराक के मध्य भी एक पारस्परिक सहयोग समझौता सम्पन्न हुआ। वास्तव में यही बगदाद समझौता था, जिसमें ब्रिटेन, पाकिस्तान तथा ईरान उसी वर्ष क्रमशः मार्च, सितम्बर एवं नवम्बर में इस बगदाद समझौते में सम्मिलित हो गये। इस बगदाद सुरक्षा संगठन (फरवरी 24, 1955) के अनुच्छेद (एक) के अनुसार यह निश्चित हुआ कि संगठन के प्रत्येक सदस्य सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के लिये दूसरे सदस्य की सहायता करेगा। इस संगठन के इस रक्षात्मक रूप ने अमरीका को भी सदस्यता ग्रहण करने के लिये विवश कर दिया और इस प्रकार अमरीका ने भी विश्व-शान्ति हेतु इन सम्मेलनों में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु इस बगदाद समझौते का मुख्य लक्षण बाद में दृष्टि-गोचर होने लगा जब अमरीका ने, जो संगठन के प्रत्येक सदस्य को सैन्य एवं अनुदान प्रदान करता था, अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। इस प्रकार अमरीका के इस दृढ़तापूर्ण निश्चय से ब्रिटेन की स्थिति मध्य एशियायी क्षेत्रों में सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण हो गयी।

बगदाद समझौते की तटस्थता की, एशियायी देशों में कटु आलोचना हुई तथा रूस ने इसे अपनी सुरक्षा हेतु एक भय का कारण बताया। साथ ही रूसी सरकार ने अरब के उन देशों के प्रति अपने सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जो बगदाद समझौते के आलोचक थे। रूस ने इन क्षेत्रों में पश्चिमी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से लीबिया, सऊदी अरेबिया तथा यमन

आदि राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिए। रूस ने इसराएल पर भी आक्षेप किया क्योंकि उसका विश्वास था कि यह अरब राष्ट्र के विरुद्ध पश्चिमी देशों के हाथों का खिलौना है। रूस ने अगनी स्थिति अरब राष्ट्रों में सुदृढ़ करने हेतु, उसे असीमित आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही मिस्र की ओर भी रूस ने अपनी रुचि प्रदर्शित की। रूस ने मिस्र को यह आश्वासन दिया कि वह अपनी सुरक्षा हेतु किसी भी साम्यवादी राष्ट्र से आयुद्ध सम्बन्धी वस्तुएँ क्रय कर सकता था, तथा उसने राष्ट्रपति नासिर को सोवियत रूस की यात्रा हेतु आमन्त्रित भी किया।

आइजनहावर सिद्धान्तः-

वाशिंगटन के राजनीतिज्ञों को मध्य-पूर्व एशिया में आंग्ल-फ्रांसीसी प्रभाव के समापन के कारण यह शंका होने लगी कि यदि मध्य एशिया के इन क्षेत्रों पर से पश्चिमी देशों का प्रभाव समाप्त हो जायेगा, तो ये क्षेत्र अवश्य ही सोवियत रूस के प्रभाव में आ जायेंगे। परिणामस्वरूप अमरीका ने तत्कालिक 'सैद्धान्तिक नीति के द्वारा अरब देशों को रूसी प्रभाव की समाप्ति हेतु 'सैन्य, अनुदान' देने का वचन दिया। अमरीका को पूर्ण विश्वास था कि अरब राष्ट्रवाद साम्यवाद के विरुद्ध है। अतः इस सिद्धान्त के अन्तर्गत अमरीका ने पश्चिमी एशिया के प्रत्येक ऐसे राष्ट्र को, जो साम्यवाद से आताङ्कित थे, सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। अमरीका का उद्देश्य मध्य एशिया में रूस के प्रभाव को अवरोधित करने में निहित था। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत मध्यपूर्व एशिया के राज्यों की अखण्डता को बनाये रखने का अमरीका को स्वयंसिद्ध अधिकार था और यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो अमरीकी राष्ट्रपति किसी भी देश के अनुरोध पर सैनिक प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत था। अमरीका की यह 'सैद्धान्तिक नीति' 'आइजनहावर सिद्धान्त के नाम से विख्यात है। इस प्रकार आइजनहावर सिद्धान्त ने मध्य एशिया में अत्यधिक तनाव का वातावरण उत्पन्न कर दिया। नवम्बर 29, 1956 को स्वेज युद्ध के पश्चात् अमरीका के विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा कर दी थी कि, यदि बगदाद समझौते के राष्ट्रों अर्थात् ईरान, टर्की एवं पाकिस्तान की सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिये भय उत्पन्न हुआ, तो अमरीका इसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगा।

आइजनहावर सिद्धान्त का मुख्य ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रभाव को मध्य-एशियायी क्षेत्रों में समाप्त करना था। राष्ट्रपति नासिर ने इस सिद्धान्त का अध्ययन करने के पश्चात् कहा, कि रूस ने मिस्र को सैन्य सहायता प्रदान

की जबकि पश्चिमी देशों ने मित्रों के उत्थान हेतु कुछ कार्य नहीं किया, अपितु अपनी असमर्थता को ही व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों ने आयुध सहायता हेतु असमर्थता व्यक्त की जबकि रूस ने सहायता प्रदान की, रूस ने स्वेजिनहर की अन्तर्राष्ट्रीयता में असमर्थता प्रदान किया जबकि पाश्चात्य देशों ने अपनी व्यग्रता ही प्रकट की, इसके अतिरिक्त जब पाश्चात्य देशों ने मित्र पर आक्रमण किया तो रूस ने आक्रमणकारी देशों को धमकी दी तथा जब अन्य देशों ने अनाज सम्बन्धी सहायता प्रदान करने से इन्कार कर दिया तो रूस ने न केवल अनाज का अनुदान दिया अपितु तेल का भी अनुदान दिया। रूस के राजनीतिज्ञों ने 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन,' 'दक्षिण-पूर्व एशिया संधि संगठन,' तथा 'वगदाद समझौते' आदि की कंटु आलोचना की क्योंकि 'इन संगठनों ने शान्ति के सूत्रों को भंग कर दिया तथा इन समझौते ने मध्य-एशिया में शान्ति की अपेक्षा युद्ध की सम्भावना अधिक उत्पन्न कर दी थी।'

इन समस्त उपर्युक्त राजनैतिक संगठनों के कारण आइजनहावर सिद्धांत के लक्षण 'पूर्णतया स्पष्ट' होने लगे। केवल 'छह माह' के पश्चात् ही तटस्थिती राष्ट्र एवं 'जॉर्डन' की मित्र पन्थी सरकार को हटा दिया गया। जैसे ही पश्चिमी देशों से प्रभावित नयी सरकार का गठन हुआ, अमरीका ने आयुध सहायता प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। सितम्बर, 1957 में अमरीका द्वारा मध्य-पूर्व के मित्र राष्ट्र 'जॉर्डन' को सैन्य सहायता प्रदान करना आइजनहावर सिद्धांत का जबलन्त उदाहरण था, जबकि रूस, सीरिया को आयुध सहायता प्रदान कर रहा था। मित्र तथा रूस ने सैन्य सहायता प्रदान करने का यह आधार माना कि टर्की अमरीकी सहायता के फलस्वरूप अपनी सेना सीरिया के विरुद्ध मोर्चा पर भेज रहा है। राष्ट्रपति नासिरुद्दीन भी पश्चिमी खडगता के विरुद्ध अरब एकता की प्रीमार्णिकता से प्रभावित होकर सीरिया को सैन्य सहायता प्रदान करने का प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार मध्य-पूर्व एशियायी क्षेत्र विश्व की राजनीति में एक कठिन एवं संकट का कारण था, क्योंकि सैन्य संधियों धार्मिक उन्नति एवं अखण्डता को नहीं बनाये रख सकती थी और मध्य एशिया के निवासी भी इस बात से पूर्णतया अभिन्न थे कि ये संधियाँ एवं समझौते केवल शान्ति एवं सुरक्षा के लिये प्रहसन हैं। वे इस परिणाम पर पहुँचे कि मध्य एशिया की अखण्डता एवं विश्व की शक्तियों के द्वन्द्व को रोकने के लिये उन्हें तटस्थता की नीति का परिपालन करना चाहिये। मध्य एशिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सुरक्षा एवं अखण्डता का नहीं अपितु वहाँ पर शान्ति को बनाये रखने का था। यह शान्ति केवल अरबवासियों की स्वतंत्रता पर ही निर्भर थी।

अध्याय-15

पेट्रोलियम साम्राज्यवाद

आधुनिक युग की उन्नति पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर है तथा इनके महत्व की अपेक्षा वर्तमान युग में कदापि नहीं की जा सकती। वास्तव में इस युग की उन्नति ही इन पदार्थों पर निर्भर है। पेट्रोलियम की आवश्यकता जीवन में उसकी अनिवार्यता से ज्ञात होती है। अतएव ये पदार्थ देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हो गये हैं।

विश्व के शक्ति संघर्ष में पेट्रोलियम पदार्थ निर्णयात्मक भाग ले रहा है तथा वर्तमान युद्ध प्रणाली में यह उसका आवश्यक अंग बन गया है। लड़ाकू एवं बमवर्षक वायुयान, युद्धपोत, वाहन तथा टैंक आदि सभी किसी न किसी रूप में पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर रहे हैं क्योंकि इस संघर्षमय जीवन में इन पदार्थों के अभाव से जीवन अस्तित्वहीन है। अतः इन पेट्रोलियम पदार्थों से युक्त क्षेत्रों की अपनी अलग सामरिक महत्ता है और आर्थिक उन्नति एवं युद्ध की तैयारी के लिये पेट्रोलियम पदार्थ जीवन को प्रभावित करने वाले अन्यन्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के कारण मध्य-पूर्व एशिया (पश्चिमी एशिया) के पेट्रोलियम युक्त क्षेत्र सामरिक दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण हैं।

तेल :

इन उपर्युक्त उद्देश्यों से प्रेरित होकर विश्व शक्तियों ने मध्य-पूर्व एशिया के पेट्रोलियम युक्त क्षेत्रों की खोज एवं उनके उपार्जन हेतु अपनी रक्ति-प्रथम विश्व-युद्ध तक कोई विशेष नहीं प्रदर्शित की, मरन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के साथ ही ब्रिटेन ने अधिक उन्नति हेतु तेल की बढ़ती आवश्यकता एवं महत्ता पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया। कई वर्षों के प्रश्नात् एक अमरीकी निवासी ने इसका सामरिक महत्व बताते हुये कहा कि विश्व-युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण

उपयोगी वस्तु सामरिक दृष्टि से तेल का उपार्जन ही है ।

मध्य-पूर्व एशिया के देशों में सर्वप्रथम ब्रिटेन ने पर्शिया में तेल उपार्जन हेतु सुविधाएँ प्राप्त की । ब्रिटेन के अभियांत्रिक विलियम डीआर्की को 1901 में 60 वर्ष तक के लिये यह सुविधा प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत ब्रिटेन को तेल तथा प्राकृतिक गैस आदि के उपार्जन हेतु पर्शिया के साम्राज्य में सुविधाएँ प्राप्त थी । 1910 में भारत के वाइसराय ने पर्शिया से एक 'कर विवाद' के संदर्भ में विलसन को तेल उपार्जन हेतु संस्तुति प्रदान की जिसने बाद में इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किये । विन्सटन चर्चिल ने 1911 में तीन वर्षीय समुद्रीय विस्तार कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसके परिणामस्वरूप आंग्ल-पर्शिया समझौते के आधार पर, तेल उपार्जन कार्य, तेल कुओं की खुदाई तथा उसके शुद्धीकरण हेतु यंत्रों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो गया । युद्ध के दौरान लगभग लाखों ईरानियों की मृत्यु हुई । अतएव ब्रिटेन की सरकार ने 1919 के आंग्ल-पर्शिया समझौते के आधार पर पर्शिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की । पर्शिया के राष्ट्रवादियों ने इस प्रकार के समझौते का अत्यधिक विरोध किया तथा फरवरी 1921 में रजाशाह के प्रति राज्य विद्रोह के फलस्वरूप इस समझौते का अन्त हो गया ।

मध्यपूर्व एशिया में दूसरी महत्वपूर्ण तेल उपार्जन की सुविधा ब्रिटेन की एक तेल कम्पनी को ईराक में प्राप्त हुई । यह सुविधा हस्तक्षेप के फलस्वरूप राष्ट्रवादियों का दम भरने के पश्चात् प्राप्त हुई । सीरिया में भी राष्ट्रवादियों के आन्दोलनों को समाप्त कर ब्रिटेन ने एक नवीन युग का सूत्रपात किया ।

मध्य-पूर्व एशिया पश्चिमी एशिया तेल हेतु अमरीकी प्रयत्न

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अमरीका की रुचि मध्यपूर्व एशिया के तेल हेतु बहुत तीव्र थी । परन्तु युद्ध काल में असीमित व्यय के कारण देश में 'शक्ति संकट' उत्पन्न हो गया । इसी उद्देश्य के परिणामस्वरूप तेल उपार्जन हेतु समुद्री विस्तार योजनाओं का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया । 1920 में राष्ट्रपति विल्सन ने लिखा था कि "हम राष्ट्रवासी समय के आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं तथा मुझे इस बात का भय है कि कहीं ब्रिटेन भी जर्मनी की भाँति अपनी आर्थिक व्यग्रता को प्रदर्शित न करने लग जायें । देश की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था भी तेल उत्पादकों के कारण पूर्णतः पेट्रोलियम सम्बन्धी पदार्थों पर आश्रित होती जा रही है ।" अतएव इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप मध्य-पूर्व एशिया में तेल उपार्जन के प्रश्न को लेकर अमरीका एव ब्रिटेन में संघर्ष होना स्वाभाविक

हो गया था। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति तक तेल उपार्जन का यह कार्यक्रम अमरीका की नीति का प्रमुख अंग बन गया था क्योंकि इस तेल उपार्जन कार्यक्रम के द्वारा अमरीका ने अपनी आर्थिक स्थिरता को सुव्यवस्थित कर लिया था। 1917 में युद्ध उद्योग मंडल के अन्तर्गत एक 'राष्ट्रीय तेल युद्ध सेवा समिति' का संगठन किया गया। इस समिति की स्थापना ने अमरीका में आधुनिक पूंजीवाद संसृष्ट राज्य का शिलान्यास किया। युद्ध के पश्चात यह तेल समिति, अमरीका पेट्रोलियम संस्था (ए.पी.आई.) में परिणत हो गई। इसी के पश्चात अमरीका की नीति का मुख्य उद्देश्य विदेशी तेल कम्पनियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में केन्द्रित हो गया तथा रिपब्लिकन दल की सरकार ने भी इस नीति का स्वागत किया। परन्तु कुछ राजनैतिक स्थलों से इस नीति की अवहेलना हुई।

अमरीका की औद्योगिक नीति के आधार पर ईराकी तेल संबंधी कम्पनियों की मंडली सरकार के द्वारा बनायी गई। इस नीति से प्रेरित होकर अप्रैल 1921 में अमरीकी वाणिज्य मंत्री हूवर ने कहा कि "हम एक ऐसी पेट्रोलियम संबंधी नीति का परिपालन कर रहे हैं जो भविष्य में राष्ट्र के लिये लाभप्रद होगी"। अमरीका विदेश मंत्रालय, अमरीकी आंग्ल पेट्रोलियम समझौते के प्रति सतर्क था। इसने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक सुव्यवस्थाओं में समानता को आधारभूत मानना चाहिये। अतः इस संदर्भ में व्यर्थ ही किसी भी प्रकार का अपवाद एवं विवाद उत्पन्न किये हुये, अमरीकी राजनीतिज्ञों ने इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान कर दी।

यद्यपि अमरीका के कुछ स्थलों पर तेल की खोज हुई, परन्तु इस कार्य ने प्रमुख पेट्रोलियम कम्पनियों को कार्य विमुख नहीं किया। 1924 में पेट्रोलियम सुरक्षा संयुक्त मंडल' की स्थापना सरकार एवं तेल कम्पनियों में घनिष्ठता स्थापित करने हेतु हुई। इस पेट्रोलियम सुरक्षा संयुक्त मंडल ने पेट्रोलियम के औद्योगिकरण हेतु अत्याधिक कार्य किया एवं पेट्रोलियम को अनासार ही व्यर्थ होने से बचाया और साथ ही इस पर लाभप्रद मूल्यों की स्थिरता को बनाये रखा। अतः इस सुरक्षा मंडल की स्थापना से यह ज्ञात हुआ कि आन्तरिक स्थिति का अवलोकन केवल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संदर्भ में ही किया जा सकता है।

द्वितीय विश्व-युद्ध एवं मध्य-पूर्व एशिया (पश्चिमी एशिया) में अमरीकी तेल स्वार्थों का एकीकरण :

द्वितीय विश्व-युद्ध में मध्य पूर्व एशिया पश्चिमी एशिया के अन्तर्गत ईरान

एवं उत्तरी अफ्रीका का सैन्य दृष्टि से बड़ा ही सामरिक महत्व था। सर्वप्रथम पर्शिया की खाड़ी के क्षेत्रों में अपार मात्रा में तेल संजय था। फलस्वरूप अमरीका को विवश होकर इन समस्त तेल संचित क्षेत्रों को पूर्णतयः अमरीकी तेल कम्पनियों के आधिपत्य में करने के लिये प्रेरित किया, परन्तु आर्थिक एवं सैन्य अव्यवस्थाओं के कारण इन क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करना कुछ कठिन अंशय था। अतएव इन तेल संचित क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के लिये यह आवश्यक था कि इसे तब तक भूमिगत रहने दिया जाये जब तक इसकी अंतिम आवश्यकता न पड़े। इसी आवश्यकता को बताते हुये युद्धकालीन अर्थ परामर्शदाता ने बताया कि अमरीका को इन पेट्रोलियम युक्त क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करने में सदैव कठिनाइयों एवं असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के अवरोध तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक अमरीका इन पेट्रोलियम युक्त क्षेत्रों पर अपना अधिकार नहीं स्थापित कर लेगा। द्वितीय विश्व-युद्ध ने पेट्रोलियम के उत्पादन में अवरोध अवश्य उत्पन्न किया। इसने स्थानीय एवं मित्र राष्ट्रों की आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व न छोड़ा, यह अनुमान लगाया जाने लगा कि जैसे ही जर्मनी एवं उसके मित्र राष्ट्रों का भय मध्यपूर्व एशिया पर से समाप्त हो जायेगा समस्त तेल कम्पनियाँ अपनी अस्तित्व सुरक्षा हेतु तत्पर हो जायेगी। अतएव विश्वयुद्ध के पश्चात् इन समस्त तेल कम्पनियों ने इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम के उपार्जनार्थ कार्य प्रारम्भ कर दिया तथा यह पूर्णतया विदित होने लगा कि इन क्षेत्रों का पेट्रोलियम उपार्जन कुछ तेल कम्पनियों में केन्द्रित हो जायेगा।

अमरीका के राजनीतिज्ञों ने सर्वप्रथम अपनी रुचि सऊदी अरेबिया में प्रदर्शित की तथा फरवरी 1943 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तेल उपार्जन में रुचि प्रदर्शित करते हुये उसकी सुरक्षा को भी अधिक महत्व दिया।

युद्धोपरान्त अमरीकी योजना

अमरीकी युद्ध नीतियों एवं राजनीतिज्ञों ने जर्मनी एवं उसके मित्र राष्ट्रों के मध्य पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर से भय समाप्त होने के पश्चात् अपनी नीतियों को इन क्षेत्रों पर सूत्रबद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। विश्व राजनीतिज्ञों ने अमरीकी स्वार्थों के आधार पर अर्थ व्यवस्था को सामरिक महत्व के अन्तर्गत परिणत कर दिया। अमरीकी विदेश मंत्री ने लिखा कि "हम ब्रिटेन की नीति के पक्ष में हैं तथा उसके द्वारा मध्य पूर्व एशिया में तेल उपार्जन के लिये पूर्णतया

तत्पर हैं क्योंकि ब्रिटेन का यह कार्य अमरीका को उत्पादन कार्य में मुक्ति दिलाता है ।”

“विदेशी पेट्रोलियम नीति अमरीकी युद्धोपरान्त योजना के अनुसार निम्न थी :—

1. विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का व्यापार मध्य-पूर्व एशिया की भाँति पश्चिमी देशों में भी होना चाहिये ।
2. ब्रिटेन की पेट्रोलियम सम्बन्धी नीतियों से समन्वय स्थापित करना चाहिये ।
3. अमरीकी तेल सम्बन्धी सुविधाओं हेतु उन समस्त अवरोधों का समाधान करना चाहिये जिनसे असुविधा उत्पन्न होने की सम्भावना है।

ट्रूमैन सिद्धान्त एवं मध्य-पूर्व एशियायी तेल

ट्रूमैन के सिद्धान्त के अन्तर्गत अमरीका एवं यूरोपीय देशों की सुरक्षा हेतु यूनान एवं तुर्की को सैन्य सहायता प्रदान की गयी। यह सहायता वास्तविक तौर पर यूनान एवं तुर्की की भौगोलिक दृष्टि के कारण प्रदान की गयी थी। ट्रूमैन सिद्धान्त ने यह भी स्पष्ट किया था कि मध्य पूर्व एशिया का क्षेत्र आर्थिक उन्नति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है; क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण है। अतः इस क्षेत्र पर प्रत्येक राष्ट्र का समान आगमन का अधिकार होना चाहिए और साथ ही यह किसी एक विशेष राष्ट्र के आधिपत्य में नहीं रहना चाहिये। यद्यपि ट्रूमैन का यह सिद्धान्त मार्च 1947 में प्रतिपादित किया गया था परन्तु इस सिद्धान्त को कई वर्षों पश्चात् कार्यान्वित किया गया। इसके विपरीत द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् अमरीका की नीति का मुख्य आधार ब्रिटेन को आर्थिक दृष्टि से पछाड़ना था तथा साथ ही यूनान, ईराक, जार्डन तथा लीबिया में ब्रिटेन की सैन्य सहायता को बनाये रखना था।

ईरान तेल पेट्रोलियम आपूर्ति की दृष्टि से अमरीका के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि इसी के द्वारा सऊदी अरेबिया में स्थित पेट्रोलियम कम्पनियों को सामरिक दृढ़ता प्राप्त होती थी। द्वितीय विश्व-युद्ध में सर्वप्रथम अमरीका एवं सोवियत रूस के मध्य मुकाबला ईरान के क्षेत्र में हुआ। साथ ही ईरान में रूसी अमरीकी संघर्ष का ही प्रश्न सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघ की सूची में रखा गया परन्तु इस विवाद का अन्त ईरान पर से ब्रिटिश एवं रूसी सेनाओं को वापस बुलाने से हुआ। इन समस्त राजनैतिक विप्लवों के कारण ईरान ने 1946 में अंग्ल-ईरानी पेट्रोलियम समिति एवं सरकार के विरुद्ध

हड़ताल हो गयी, साथ ही ईरान के कुछ क्षेत्रों में भी हड़ताल प्रारम्भ हो गयी। यह ईरानी हड़ताल ईरान की ही भाँति कुछ राजनीतिक तत्वों के ही कारण उत्पन्न हुई थी क्योंकि इन तत्वों की उपस्थिति ने ब्रिटेनवासियों को संकट में डाल दिया था।

इस प्रकार 1947-48 में पैलेस्टाइन (फिलिस्तीन) के प्रश्न को लेकर 'ट्रूमैन सिद्धान्त' असफल रहा क्योंकि अमरीका की नीति के आधार स्वरूप पैलेस्टाइन में किसी भी शक्ति का हस्तक्षेप टुफ़कर था। अमरीका यह नहीं चाहता था कि इस क्षेत्र में ब्रिटेन अथवा रूस हस्तक्षेप करे तथा न ही इन क्षेत्रों में शान्ति स्थापित करने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ ब्रिटेन अथवा रूस की सेना भेजे। 1960 के लगभग अमरीका की मध्य-पूर्व एशिया की नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी सामरिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना था। इस उद्देश्य के ही कारण राष्ट्रपति कैंनेडी ने मिस्त्र के राष्ट्रपति नासिर से अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी स्थापित किये एवं मिस्त्र को कई प्रकार की सुविधायें एवं अनुदान भी दिये। परन्तु कैंनेडी के द्वारा स्थापित समस्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को राष्ट्रपति जॉनसन ने 1965 में भंग कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि अमरीका वियतनाम एवं कांगो में सैन्य हस्तक्षेप कर रहा था तथा 1965 में इसराएल को अमरीकी सैन्य सहायता प्रदान करने के कारण यह सम्बन्ध और भी अधिक खराब हो गये। रूस ने इन सम्बन्धों को व्यग्रता ही प्रदान की क्योंकि मध्य-पूर्व एशिया में रूसी हस्तक्षेप था और वह सदैव अपनी स्थिति को मध्य-पूर्व एशियायी क्षेत्रों में सुदृढ़ करना चाहता था।

ईरान

18 वीं शताब्दी के अन्त तक ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी पेट्रोलियम नीति के कारण ईरान में भी रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि ईरान, भारतवर्ष के समीप था। पश्चिम की खाड़ी में ब्रिटिश आगमन का अति स्वागत हुआ क्योंकि सिंहासनारूढ़ शाह का तुर्की एवं पुर्तगालवासियों से वैमनस्य था। ब्रिटेन ने समय के अनुसार अपने समस्त प्रतिद्वन्दियों अर्थात् पुर्तगाल, डच तथा फ्रांसीसीयों को अपनी नीसेना से पराजित कर दिया और इस प्रकार 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक पश्चिम की खाड़ी में केवल ब्रिटेन का ही आधिपत्य रह गया।

1814 में ब्रिटेन ने पश्चिम से एक सन्धि समझौता किया तथा 1872 में ब्रिटेन के निवासी बैरन डी राँयटर ने शाह से देश के प्राकृतिक साधनों के उपार्जन हेतु सुविधा प्राप्त कर ली। कुछ वर्षों पश्चात् 'डी आरकी' ने 6 लाख

पौण्ड की पूंजी से प्रथम पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना की। जब इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का उपार्जन अधिक होने लगा तो डी आर्की ने 'वर्मा आयल कम्पनी' की स्थापना की।

अगस्त 1, 1919 की आंग्ल-पश्चिम सन्धि का मुख्य उद्देश्य पश्चिम को ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बनाना था परन्तु बाद में इस संधि की अत्यधिक अवहेलना होने लगी।

मध्य-पूर्व एशिया में ईरान ही केवल एक ऐसा देश था जहाँ अमरीका प्रत्यक्ष रूप से पेट्रोलियम का उपार्जन न कर सका। अमरीका की यह नीति ईरान में अपने स्वार्थों की कमी के कारण नहीं थी, यद्यपि 'ऋण पट्टा' देने की व्यवस्था का कार्यभार ब्रिटेन ने अमरीका को हस्तान्तरित कर दिया था। ब्रिटेन ने हस्तांतरण उन क्षेत्रों पर अमरीका के सैन्य मिशन को दृढ़ता प्रदान करने हेतु किया था। मई 1951 को 'न्यूयार्क टाइम्स' ने अपने अग्रलेख में मध्य-पूर्व एशिया के तेल के महत्व का वर्णन किया तथा उसने यह भी लिखा, कि मध्य-पूर्व एशिया के तेल उपार्जन हेतु पूंजीवादी एवं समाजवादी राष्ट्रों में शीत युद्ध है। उसने यह भी लिखा कि निकट पूर्वी एशिया के तेल का उपार्जन रूस अपने लिये एवं अपने मित्र राष्ट्रों के लिये कर सकता है, जैसे कि अमरीका तथा यूरोप के अन्य राष्ट्र मध्य-पूर्व एशिया में तेल उपार्जन का कार्य कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अमरीका तथा यूरोप के अन्य राष्ट्र किसी भी प्रकार यह देख नहीं सकते कि निकट पूर्वी एशियायी स्थलों के तेल उपार्जन का अधिकार रूस को राष्ट्रीयकरण के पश्चात् प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो।

ईराक

मध्य-पूर्व एशिया के पेट्रोलियम युक्त क्षेत्रों में ईराक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन ने आटोमन साम्राज्य के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप ईराक राज्य की स्थापना हुई। ईराक पर से ब्रिटेन ने अधिदेश का दायित्व अपनी पेट्रोलियम नीति के कारण हटा लिया था।

पश्चिम के शाह ने सुल्तान अब्दुल हमीद को अत्याधिक प्रभावित किया। शाह ने 'डी आरकी' को अपने देश की आर्थिक उन्नति हेतु पेट्रोलियम सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की थी, अतः इसी उद्देश्य से प्रभावित होकर अब्दुल हमीद ने भी पेट्रोलियम के लाभ को आर्थिक उन्नति का एक प्रमुख स्रोत माना तथा 'डी आरकी' को अपने देश में भी पेट्रोलियम उपार्जन हेतु आमंत्रित किया अप्रैल 24

1930 को सैन रेमी समझौते के अनुसार 'टर्की पेट्रोलियम कम्पनी' के 25 प्रतिशत जर्मनी के अंश को फ्रांस को दे दिया गया। इस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुसार यह निश्चय हुआ कि यह पेट्रोलियम कम्पनी पूर्णतया ब्रिटेन के अधिकार में रहेगी। अमरीका के विदेश मंत्रालय ने आंग्ल-फ्रांसीसी समझौते का विरोध किया जिसके द्वारा जर्मनी को प्राप्त सुविधाएँ फ्रांस को हस्तान्तरित करने की पड़ी। इस विरोध की वास्तविकता अमरीका के मध्य पूर्व एशियायी क्षेत्रों में पेट्रोलियम के लिये सुविधाएँ प्राप्त करने में निहित थी। 1928 में अथक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप मध्य पूर्व एशिया में पेट्रोलियम सुविधा के मार्ग अमरीका के लिये खुल गये तथा परिणामस्वरूप टर्की पेट्रोलियम कम्पनी का पुनर्गठन हुआ। 1929 में जब टर्की पेट्रोलियम कम्पनी ईराकी पेट्रोलियम कम्पनी में परिणत हो गई इसमें अन्य समस्त कम्पनियों का अंश समानता के आधार पर बाँटा दिया गया। ईराक में पेट्रोलियम का उत्पादन ईराकी पेट्रोलियम कम्पनी के द्वारा 1930 से प्रारम्भ हुआ था। 1931 में अमरीका की समस्त पेट्रोलियम कम्पनियों को 'स्टैण्डर्ड आयल' तथा 'साकनीबैकुअम' व्यापार संघ में आत्मसात् कर दिया गया।

ईराक में ईराकी पेट्रोलियम कम्पनी का व्यवस्थापन ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार ईरान में आंग्ल-ईरानी कम्पनी का व्यवस्थापन चल रहा था। जुलाई 14, 1958 की ईराकी क्रान्ति की उत्पत्ति किसी पेट्रोलियम नीति के फलस्वरूप नहीं हुई थी। पेट्रोलियम नीति ने केवल इस क्रान्ति की पृष्ठभूमि ही तैयार की थी।

सऊदी अरेबिया

मध्य-पूर्व एशिया में अमरीका ने अरेबिया के रेगिस्तान से पेट्रोलियम के उपार्जन का कार्य प्रारम्भ किया। ब्रिटेन ने मध्य-पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों पर अपनी कोई विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की। इब्न सऊद ने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलियम के उपार्जन का कार्य अमरीका को दिया क्योंकि उसका विचार था कि इस कार्य में अमरीका महत्वपूर्ण कार्य करेगा। अतः 1933 में कैलिफोर्निया की स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी ने सुल्तान इब्न सऊद से 6 वर्ष का अनुबंधन किया। 1944 में यह कम्पनी 'अरेबियन-अमरीकन-आयल कम्पनी' अर्थात् 'अरमैको' में परिणत हो गयी तथा 1948 में दो अन्य अमरीकी पेट्रोलियम कम्पनियाँ (न्यू-जर्सी की स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी तथा सोकानी बैकुअम कम्पनी) 'अरमैको' में सम्मिलित कर दी गयीं। ये दोनों कम्पनियाँ क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के स्वामित्व पर साझेदार थीं।

बाँहराइन तथा कुवैत

बाँहराइन प्रायद्वीप पश्चिम की खाड़ी से लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित है तथा कुवैत पश्चिम की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। ये दोनों ही क्षेत्र पेट्रोलियम पदार्थों की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के शेख ब्रिटेन पर आश्रित हैं अतः यह स्वाभाविक था कि इन देशों पर पेट्रोलियम सम्बन्धी सुविधाएँ ब्रिटेन को ही प्राप्त होतीं, यद्यपि इन सुविधाओं के प्रति ब्रिटेन शेख लोगों को राजस्व देता रहा। प्रारम्भ में 1925 से 1926 तक बाँहराइन ने ये सुविधाएँ ब्रिटेन को ही प्रदान की थीं परन्तु बाद में ये सुविधाएँ यूनाइटेड स्टेट्स ईस्टर्न गल्फ कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर दी गयीं। तत्पश्चात् 1928 में स्टैंडर्ड आयल कम्पनी ने इसे अपने अधिकार में लेकर बहरीन पेट्रोलियम कम्पनी की स्थापना की।

समृद्धि-युक्त वर्ष 1948-1960

आज के युग में किसी देश की समृद्धि पेट्रोलियम उद्योग पर ही पूर्णतया आश्रित रहती है यद्यपि इस समृद्धि में कण्ट भी हैं परन्तु इन समस्त कठिनाइयों के उपरान्त भी प्रत्येक देश पेट्रोलियम उपार्जन हेतु सदैव कार्यरत रहता था। इन समस्त समस्याओं एवं अवरोधों के होते हुये भी मध्य-पूर्व एशिया के तेल उद्योग में लाभ अधिक तथा भय की शंका अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा शून्य के बराबर थी। इस तेल उद्योग में वृद्धि का मुख्य कारण था कि इस उद्योग में कम आर्थिक व्यय पर, लाभ आपार मात्रा में होता था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यूरोप तथा जापान ने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु पेट्रोलियम को ही आर्थिक स्थिति का आधार माना क्योंकि इन देशों का विश्वास था कि पेट्रोलियम के द्वारा देशों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। यूरोप के अन्य राष्ट्रों तथा जापान को अमरीका की अपेक्षा समृद्धि हेतु त्रिदेशी तेल स्रोतों पर निर्भर होना था और इस कार्य हेतु इन राष्ट्रों को कुछ सीमा तक मध्य-पूर्व एशिया के देशों पर ही आश्रित रहना था। 1944 में पेट्रोलियम विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी अरेबिया को लिखा कि वर्तमान स्थिति में विश्व में तेल उपार्जन के कार्य का केन्द्र-बिन्दु कैरिबियन-क्षेत्र से हटकर मध्य-पूर्व एशियायी क्षेत्रों में आ रहा है और यह कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक पाश्चात्य देशों का मध्य-पूर्व एशिया के इन क्षेत्रों पर पूर्णतया अधिकार स्थापित नहीं हो जायेगा।

अमरीका के आर्थिक सहयोग प्रशासन ने अमरीकी पेट्रोलियम का यूरोप में निर्गम होने से बचाये रखा जो अन्य स्थितियों में दुष्कर था तथा यह भी

सम्भव था कि अमरीका को इन क्षेत्रों में हानि उठानी पड़ती। एक अमरीकी अर्थ विशेषज्ञ ने कहा कि यह अत्यन्त दुष्कर एवं कठिन कार्य है कि विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कम्पनियाँ अपनी स्थिति को सुव्यवस्थित एवं समान बनाये रखें क्योंकि बिना अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के यह कार्य कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। यद्यपि आर्थिक सहयोग प्रशासन ने अमरीका के पेट्रोलियम सम्बन्धी स्वार्थों को बनाये रखा परन्तु फिर भी इसे उद्योगों के मूल्य निर्धारण का कठिन कार्य सम्पन्न करना पड़ा। ईरानी तेल के मूल्यों का निर्धारण यूरोपीय देशों के लिये 2.22 डालर प्रति पीपे की दर पर निश्चित किया गया इसके विपरीत अमरीका मध्य-पूर्वी एशिया के पेट्रोलियम 1.75 डॉलर प्रति पीपे की दर पर प्राप्त करता था। इस प्रकार मूल्यों के निर्धारण में यह विभिन्नता एवं असमानता लगभग 1950 तक चलती रही। वास्तव में मूल्यों के निर्धारण में भिन्नता अन्तर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योगों की संरचना के कारण थी। इस विभिन्नता का निवारण प्रत्येक मुख्य कम्पनी को समस्त क्षेत्रों में अधिकार देकर ही किया जा सकता था।

पेट्रोलियम राजनीति एवं आर्थिक राष्ट्रवाद

मध्य-पूर्व एशिया में 1950 तक समृद्धि के वर्ष थे क्योंकि इन वर्षों में पेट्रोलियम के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि एवं समृद्धि हुई, परन्तु इन्हीं वर्षों में जहाँ समृद्धि हुई वहाँ कुछ क्षेत्रों को लेकर अव्यवस्था भी हुई क्योंकि पेट्रोलियम कम्पनी की राजनीति एवं आर्थिक अधिकारों को लेकर कुछ आपत्तियाँ भी हुई यद्यपि इन अव्यवस्थाओं का समापन कर दिया गया था परन्तु फिर भी आर्थिक राष्ट्रवाद ने कुछ अव्यवस्था अवश्य उत्पन्न कर दी थी।

इन आर्थिक एवं पेट्रोलियम सम्बन्धी अव्यवस्था ने मध्य-पूर्व एशिया में दो बार पश्चिमी देशों को सैन्य हस्तक्षेप करने के लिये विवश किया। यह पश्चिमी देशों द्वारा मध्य-पूर्व एशिया में हस्तक्षेप अपने स्वार्थों को बनाये रखने हेतु हुआ था। प्रथम बार यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् हुआ था जबकि 1956 में मिस्र पर आंग्ल-फ्रांसीसी इसराएली आक्रमण हुआ था तथा दूसरी बार इन यूरोपीय शक्तियों द्वारा मध्य-पूर्व एशिया के क्षेत्रों में हस्तक्षेप जुलाई, 1958 की ईरानी क्रान्ति के पश्चात् हुआ था, जिसके कारण अमरीकी एवं ब्रिटिश सेनाओं ने लेबनान एवं जार्डन में सैन्य हस्तक्षेप किया था। इन घटनाओं के पश्चात् भी अमरीका ने आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता को बनाये रखने का प्रयास किया, क्योंकि उसको इस बात की शंका थी कि उसका यह कार्यकलाप जार्डन, ईराक एवं अन्य क्षेत्रों में

विरोधी परिणाम न उत्पन्न कर दे और साथ ही सम्भवतः नासिर की प्रतिष्ठा एवं गौरव में वृद्धि न कर दे। फलस्वरूप मिस्र ने अमरीका से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर लिये जिसके फलस्वरूप अमरीका ने मिस्र को सभी प्रकार के अनुदान देना समाप्त कर दिया। अमरीका ने व्यक्तिगत एजेन्सियों जैसे 'केयर' आदि पर भी अवरोध लगा दिया कि मिस्र को किसी भी प्रकार की सहायता न प्रदान करे। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अमरीका की इस नीति का विरोध किया तथा यह कहा, कि अमरीका पेट्रोलियम सम्बन्धी सहायता हेतु भयादोहन का कार्य कर रहा है।

1960 तक मध्य-पूर्व एशिया में पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य बढ़ता ही रहा तथा 1963 तक पेट्रोलियम उत्पादक कम्पनियों को लाखों डॉलर का लाभ हुआ :-

- क. ईरान-243 लाख डॉलर का जबकि अमरीका को 169.2 लाख डॉलर का लाभ हुआ।
- ख. ईराक-322.9 लाख डॉलर का लाभ हुआ जबकि अमरीका को 76.685 लाख डॉलर का लाभ हुआ।
- ग. सऊदी अरेबिया-363.7 लाख डॉलर का लाभ हुआ जबकि अमरीका को शत-प्रतिशत लाभ हुआ।
- घ. कुवैत-596.4 लाख डॉलर का लाभ हुआ जबकि अमरीका को 298.2 लाख डॉलर का लाभ हुआ।

अतः इन उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट होता है कि इस पेट्रोलियम उपार्जन के कार्य में कुल 1.7 अरब डॉलर का लाभ हुआ, जिसमें अमरीका के लाभ का अंश लगभग 914 लाख डॉलर था। इसी प्रकार 1969 के लाभ की गणना से वह विदित होता है कि इन वर्षों में कुल 1.6 अरब डॉलर का लाभ हुआ था जिसमें अमरीका को 1 अरब डॉलर का लाभ हुआ।

विश्व तेल समस्या दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों का आकर्षण केन्द्र बनती चली गई क्योंकि 1960 में 'तेल निर्यातक संगठन' के पश्चात् तेल राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय देशों में एक नये अध्याय का सूत्रपात हुआ। तेल समस्याओं में अमरीका का प्रभाव 1973 की 'अरब-इसराएल युद्ध' तथा 'अरब तेल प्रतिबन्ध' ने और लाभयुक्त कर दिया। अमरीका एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के द्वारा लाभ अर्जित कर रहा था, और दूसरी ओर अमरीकी अर्थनीति तेल आयात पर अत्याधिक निर्भर नहीं रही थी।

समय के साथ तेल राजनीति परिवर्तनशील रही है, और रहेगी। तेल समस्या भविष्य के लिये एक प्रश्न चिह्न है ?

अध्याय 16

दक्षिण पूर्व एशिया एवं अमरीका

दक्षिण पूर्व एशिया एशियाई उपभागों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया की उपजाऊ भूमि तथा कच्चे माल की उपज ने अन्य पश्चिमी देशों को अपने आर्थिक लाभ हेतु आकर्षित किया। ब्रिटेन, फ्रांस तथा हालैंड ने समय-समय पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अमरीका ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व 19वीं शताब्दी के अन्त में फिलिपीन में स्थापित किया। निःसन्देह दक्षिण पूर्व एशिया में अमरीकी शासन अन्य यूरोपीय शासन से अधिक उद्वादादी एवं स्वदेशी धींसियों के हितों से परिपूर्ण था। अमरीका की तीतियों ने सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण की भावना को जागृत किया और प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रपति विल्सन के स्व निर्णय के सिद्धान्त और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में स्वायत्त शासन की माँग को दृढ़ता प्रदान की।

समय की विवशता के अनुसार यह आवश्यक हो गया था कि अमरीकी हस्तक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में सामान्य रूप से तथा हिन्द चीन में विशेष रूप से केन्द्रित रहा। वास्तव में हिन्द चीन में शांतिपूर्ण स्थिति स्थापित होने की संभावना उत्पन्न हो गयी थी परन्तु अमरीका ने युद्ध को बढ़ाते के विचार से शांति संधि का विरोध किया। इसके अतिरिक्त अमरीका ने फ्रांस को सैन्य सौमग्री देने में भी वृद्धि की और 1955 में आर्थिक सहायता का भी आश्वासन दिया जो कि लगभग 385 लाख डॉलर का था। साथ ही अमरीका ने हिन्द चीन में अपने हितों की रूति हेतु सामाजिक महत्व की ओर ध्यान दिया तथा वहाँ के खनिज पदार्थों की ओर भी दृष्टि डाली। इसके अतिरिक्त अमरीका इस क्षेत्र में समस्त द्वन्द, अणुगोलों को भी प्रयोग में लाने के उद्देश्य से हस्तक्षेप के लिये तैयार था।

इस समस्त वातावरण के फलस्वरूप अमरीका ने न केवल 'जिनेवा सम्मे-

लन के पक्ष में हस्ताक्षर करने से इनकार किया अपितु वे समस्त कदम अमरीका की विदेशी-नीति में वृद्धि के उद्देश्य से उठाये जो साम्यवाद के पक्ष में थे। तथापित यह नीति साम्यवाद के विस्तार के लिये अवरोधक थी और यह इन्हीं नीतियों का परिणाम था कि जॉन फॉस्टर डलेस ने जिनेवा सम्मेलन की शर्तों से क्षुब्ध होकर दक्षिणी वियतनाम के डीम प्रशासन को जिनेवा सम्मेलन के विरोध में उत्तेजित किया था।

सन् 1956 के चुनाव से यह भली-भाँति प्रतीत होने लगा कि वियतनाम का एकीकरण उत्तर के साम्यवादी प्रशासन के नेतृत्व में सफल हो जायेगा परन्तु जब हो ची मिन्ह ने शान्तिपूर्ण चुनाव के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफलता पायी तो उसने देश के एकीकरण हेतु सैन्य तरीकों को अपना ही उचित समझा। इसके विपरीत अमरीका की विदेश नीति के अनुसार यह आवश्यक हो गया था कि वह दक्षिण वियतनाम की सुरक्षा हेतु सैन्य सामग्री से उसे परिपूर्ण कर दे। परिणाम स्वरूप वियतनाम की आर्थिक एवं सैनिक सहायता के लिए 25 अरब डालर प्रतिवर्ष उसे व्यय करने पड़ रहे थे। इस समस्त व्यय के लिए अमरीकी जनता को करों के रूप में भार सहना पड़ता था जिसके कारण जनता में एक असन्तोष की भावना जागृत होने लगी।

परिणाम स्वरूप 1968 में राष्ट्रपति जॉनसन ने पेरिस में अमरीका एवं उत्तरी वियतनाम के मध्य शान्ति स्थापित करने हेतु सम्मेलन की रूपरेखा बनायी और यह भी घोषणा कर दी कि वह भविष्य में पुनः राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्याशी होंगे। तथापि राष्ट्रपति जॉनसन के इन वचनों का अमरीकी जनता द्वारा स्वागत किया गया। परन्तु यह विश्वास किया जाता था कि शान्ति के पक्ष में अनेक अवरोध थे, क्योंकि अमरीका में नवम्बर में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित था तथा पेरिस शान्ति समझौते की वार्ता हेतु कार्य अति मन्द गति से हो रहा था। हनोई एवं साइगॉन के प्रशासन का ध्यान अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव की ओर केन्द्रित था।

1968 के चुनाव द्वारा अमरीकी प्रशासन जॉनसन के हाथों से हट कर निक्सन के हाथों में केन्द्रित हो गया। उसने नवम्बर 1969 में देश के नाम सन्देश में अपनी विदेश-नीति की रूपरेखा प्रकट की जिसके आधार पर विश्व की राजनीति में अमरीकी हस्तक्षेप 'निक्सन - सिद्धान्त' के नाम से विख्यात हुआ।

निक्सन सिद्धान्त के अन्तर्गत समस्त संधि-शर्तों को बढ़ावा दिया गया तथा यह घोषणा की गयी कि अमरीकी हस्तक्षेप केवल तभी समाप्त हो सकता है जबकि अमरीका को यह आश्वासन मिल जाये कि उसके हटते ही साइगॉन

का अपना प्रशासन समाप्त न होगा ।

यदि अमरीका अपना हस्तक्षेप वियतनाम से समाप्त कर देता तो यह सम्भावना थी कि वियतनाम में पुनः पूर्वस्थिति स्थापित हो जाती और इसके लिए न केवल अमरीकी सैन्य सामग्री आवश्यक थी अपितु मास्को, पेकिंग एवं विश्व की अन्य राजधानियों में अमरीकी प्रसिद्ध एवं कीर्ति बनी रहने की भी आवश्यकता थी ।

1969 में जब अमरीका की विदेश-नीति की दागडोर हेनरी किंसिजर के हाथ में आयी तो यह अनुमान किया जाता था कि इसी के साथ अमरीका-वियतनाम युद्ध का समापन हो जायेगा अमरीका दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में भी अपना हस्तक्षेप समाप्त कर देगा । कुछ राजनायिक नेताओं का यह अनुमान था कि हेनरी किंसिजर मूलतः यूरोप से प्रभावित होने के कारण अमरीकी विदेश-नीति में भी परिवर्तन करेंगे, परन्तु किंसिजर कुछ स्तर तक अपनी नीति में असफल ही सिद्ध हुये । तत्पश्चात उन्होंने अप्रैल, 1973 में 'यूरोप वार्षिक' भाषण में यूरोप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया । परन्तु समय बीत जाने के कारण यूरोपीय देश एक अन्य 'विस्मार्क' का नेतृत्व नहीं प्राप्त करना चाहते थे । इसी संदर्भ में एक अंग्रेज राजदूत ने व्यंग्यात्मक रूप में यह कहा कि यह कैसी विडम्बना है किंसिजर मूल रूप से आप्रवासी होते हुये भी यूरोपीय देशों के भाग्य का निर्णय कर रहा है ।

इन समस्त प्रक्रियाओं के फलस्वरूप किंसिजर ने वही रास्ता अपनाया जिसकी आशा की जाती थी । यदि वह अपनी नीति में सफल नहीं हो सके तो इसका मुख्य कारण उनकी कूटनीति में नहीं निहित था अपितु वह यूरोप की राजनीति में कार्यरत शक्तियों का ही परिणाम था । वास्तव में यह वियतनाम युद्ध का ही प्रकोप था जो आन्तरिक एवं बाह्य अवरोधों के फलस्वरूप किसी भी विदेशी नीति-वेत्ता के कार्यक्षेत्र के परे था । यद्यपि किंसिजर राष्ट्रपति निक्सन के विश्वास रक्षक थे पर वह रूस एवं चीन के विषय-क्षेत्रों में स्वतन्त्र विचारों के थे । इस प्रकार अमरीका ने उसकी विदेशी नीति का पालन उसके प्राथमिक दिग्दर्शकों की समुचित विचारधाराओं से परिपूर्ण होकर किया था बाह्य रूप से इस नीति की आधारशिला, निक्सन-किंसिजर व्यक्तित्व का ही रूप था ।

निक्सन किंसिजर वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप को कदापि समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे । वे भविष्य में एशियायी समस्याओं में अमरीका को स्वतन्त्र रखने के भी पक्ष में थे । यद्यपि विश्व अमरीकी सेना द्वारा कम्बोडिया पर अप्रैल, 1970 में आक्रमण से विचलित हो गया था तो भी यह अनुमान

किया जाता था कि अमरीका का नवीन प्रशासन अमरीका एवं हिन्द-चीन के निवासियों के दुःखों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेगा। राष्ट्रपति निक्सन ने जुलाई, 1969 में अमरीका की विदेश नीति की समीक्षा करते हुए कहा था कि सर्वप्रथम अमरीका अपनी संधि-शर्तों के प्रति उत्तरदायी रहेगा। द्वितीय, अमरीका अपने मित्र राष्ट्रों को उन देशों से सुरक्षित रखेगा जो उसे अणु शक्ति के आधार पर चेतावनी त्तस्त रखेंगे। और जिनका अस्तित्व अमरीका की सुरक्षा में निहित था। तृतीय, अन्य प्रकार के आक्रमणों से, अमरीका समस्त सम्भव प्रयत्न करेगा, कि संधि शर्तों के अनुसार उसे आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान की जाये।

वास्तव में अमरीका की विदेश-नीति में काफी अन्तर था अर्थात् नवीन प्रशासन के द्वारा क्या अनुमान किया जाता था ? तथा नवीन प्रशासन ने क्या कार्य किया ? यह अनुमानित अन्तरों के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सका। यह आश्चर्यजनक बात है कि निक्सन 1972 के चुनाव में पुर्ननिर्वाचित हुआ जब कि वह वियतनाम युद्ध का समापन नहीं कर पाया था। तथापि 1972 का वर्ष राष्ट्रपति के लिए कुछ अन्य ही उपलब्धियां लाया। उसने दो दशकों से चली आ रही नीति का समापन कर चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए। साथ ही अमरीका ने सोवियत रूस से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया।

तथापि 1973 में अमरीका के पक्ष में वियतनाम युद्ध का समापन दृष्टि-गोचर हुआ। इस युद्ध-विराम घोषणा के अन्तर्गत दक्षिण वियतनाम से अमरीकी सेना वापस हो गयी परन्तु इन समस्त कार्यवाहियों के उपरान्त भी अमरीकी हस्तक्षेप वियतनाम एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में समाप्त न हुआ। वास्तव में अमरीका की विदेश-नीति के नेताओं ने, समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, ये समस्त कदम उठाए थे।

राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनाम की स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि अमरीकी जनता भी वियतनाम की स्थिति के प्रति जागरूक है। 1972 के चुनाव के कारण राष्ट्रपति ने वियतनाम से चार मास के अन्दर समस्त अमरीकी सेना को वापस बुला लेने का निर्णय लिया तथा युद्ध-विराम हेतु प्रस्ताव रखा जिसको कि हनोई ने पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। हनोई के प्रसाशन ने यह प्रस्ताव रखा कि जब तक साइगॉन की सरकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, हनोई युद्ध-विराम की ओर कदापि नहीं उन्मुख होगा। इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण में यह प्रतीत हो रहा था कि सम्भवतः कोई निर्णयात्मक समझान नहीं हो पायगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय

स्तर पर कुछ विवाद एवं स्पष्ट घटनाएँ घटित होने लगी थीं। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमरीका एवं वियतनाम को विवश होकर जनवरी 1973 में युद्ध-विराम की घोषणा करनी पड़ी। 1976 तक अमरीका ने वियतनाम में पूर्ण निष्क्रमण कर भविष्य में वियतनाम एकता का मार्ग प्रशस्त किया।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका एवं थाइलैण्ड में सम्बन्धों का सिलसिला 'दक्षिण-पूर्व एशिया संधि-संगठन (सीटो)' के परिणामस्वरूप आरम्भ हुआ। यह सुरक्षा संगठन 1954 में आपस में बहुमुखी सुरक्षा हेतु किया गया था। इस संगठन की रूपरेखा का निर्माण संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विदेश सचिव जान फॉस्टर डलेस ने हिन्द-चीन में फ्रांसीसी पराजय के पश्चात् किया था। तथापि इस संगठन के निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य संगठन के सदस्य आस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, फिलीपीन, थाइलैण्ड, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका के मध्य किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण से रक्षा करना था।

परन्तु वास्तविकता कुछ भिन्न थी और यह दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ते हुये चीन के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करने हेतु निर्मित हुआ था। परिणाम-स्वरूप संगठन के समस्त सदस्य एक होकर संधि-शर्तों के अन्तर्गत कम्बोडिया, लाओस तथा वियतनाम की सुरक्षा हेतु कार्यरत हो गये। कालान्तर में कम्बोडिया ने इस सुरक्षा-संगठन का परित्याग अपनी तटस्थता बनाये रखने हेतु कर दिया। लाओस को 1962 के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्तर्गत 'तटस्थ' घोषित कर दिया गया। अतः इस प्रकार केवल वियतनाम ही एक ऐसा देश रह गया था जो सुरक्षासंगठन की शर्तों के अन्तर्गत सहायता चाहता था और परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने दक्षिण वियतनाम के पक्ष में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया।

यह सुरक्षा-संगठन प्रारम्भ से ही गतिशील नहीं हो पा रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने इस सुरक्षा-संगठन का विरोध चीन-विरोधी नीति के कारण किया था। इसके साथ ही संगठन के प्रत्येक सदस्य अपने हितों की पूर्ति हेतु कार्यरत थे। ब्रिटेन, हांगकांग एवं मलाया के, प्रति पाकिस्तान भारत के विरुद्ध तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका वियतनाम के कार्यकलापों के प्रति चिन्तित रहते थे। इन समस्त कारणों के फलस्वरूप इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र अमरीका एवं थाइलैण्ड के मध्य सम्बन्ध स्थापित हुये और इससे अमरीका को दक्षिण-पूर्व एशिया के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ तथा वियतनाम के मामलों में सैन्य संचालन हेतु भी अवसर मिला। इस प्रकार इस सुरक्षा-संगठन की दुर्बलता विश्व के सम्मुख आती गयी। थाइलैण्ड ने तब दूसरी सुरक्षा संधि करने का प्रयत्न किया।

1962 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विदेश-सचिव 'डीन रस्क' ने थाईलैण्ड के विदेश-मंत्री से एक नवीन संधि की' जिसके आधार पर अमरीका ने थाईलैण्ड पर किसी अन्य शक्ति के द्वारा आक्रमण करने के विरुद्ध सहायता करने का आश्वासन दिया। थाईलैण्ड ने इस प्रकार की संधि को आर्थिक दृष्टि से दृढ़ एवं शक्तिशाली पाया और इसके विपरीत अमरीका के लिये भी थाईलैण्ड वियतनाम के मामलों में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ। अमरीका ने इसी स्थान से अधिकांशतः अणुगोलों के आक्रमण उत्तरी वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया पर सफलतापूर्वक किये। यद्यपि यह सत्य है कि अगस्त 1973 में थाई सरकार ने अमरीकी सैन्य उपस्थिति का विरोध किया परन्तु अमरीकी सरकार ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि पटेपो स्थिति एक अमरीकी सैन्य अधिकारी ने समय की आवश्यकता के विषय पर प्रकाश डालते हुये कहा था, कि पटेपो स्टोहिप अनिश्चित रूप से अमरीकी सरकार के हाथों में रहेगा। चाहे हिन्द-चीन में शांति स्थापित हो अथवा न हो।

इसी प्रकार थाईलैण्ड के ये तटवर्ती प्रदेश थाईलैण्ड तथा अमरीका के लिये अत्यधिक सामरिक महत्व के थे। इसके अतिरिक्त अमरीका के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा अमरीकी विशेष सेना के लिए भी अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए क्योंकि इन स्थानों से जो गुप्त सूचनाएँ एकत्रित की जाती थी उन्हें पूर्ण रूप से अमरीका एवं थाईलैण्ड ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाया। इसी के साथ थाई सरकार ने सी.आई.ए. के द्वारा उन अराजक एवं देशद्रोही तत्वों पर भी कड़ी दृष्टि रखी और उन्हें पथभ्रष्ट होने से बचाया। 1960 के लगभग सी.आई.ए. की गतिविधि इन प्रदेशों में शिथिल थी, परन्तु कालान्तर में इन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना एकछत्र अधिकार स्थापित कर लिया था और विशेष सैन्य टुकड़ी ने समय की आवश्यकता पर ध्यान देते हुये कम्बोडिया का सैन्य संचालन भी प्रारम्भ कर दिया। थाईलैण्ड के स्वयं सेवकों को लाओस में युद्ध करने हेतु प्रशिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र अमरीका की संसद ने सी.आई.ए. की इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध किया तथा यह आरोप लगाया कि इसने गुप्त रूप से वहाँ की राजनीति में भाग लिया परन्तु इस प्रकार का आरोप उसकी गतिविधि में बाधक नहीं बन सका।

अंततः थाईलैण्ड से समस्त विशेष सेना वापस बुला ली गई। इसी के साथ यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि थाई सरकार अमरीकी सरकार से अपने देश से सेना की वापसी का अनुरोध करेगी परन्तु अमरीकी सरकार ने इस अनुरोध के विपरीत कार्य किया और थाईलैण्ड में सेना रखना अपना एक

आवश्यक कर्तव्य समझा क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीकी हस्तक्षेप अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था तथा अमरीकी सरकार के लिये यह एक कठिन कार्य हो गया था कि वह अपने को इन क्षेत्रों से पृथक रख सके ।

हिन्द महासागर में स्थायी नौसेना केन्द्र बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति ने संसद से 29 करोड़ डॉलर सैन्य सामग्री के लिये देने की संस्तुति करने का अनुरोध किया । एक गुप्त संदेश के माध्यम से गृह विभाग को यह बताया गया कि अमरीकी सरकार का हिन्द-महासागर में हस्तक्षेप करने का मुख्य कारण वहाँ पर सोवियत रूस के प्रभाव को समाप्त करना था । यह सर्वविदित था कि स्वेज नहर के खुलने से इन क्षेत्रों पर सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ जायेगा । अतः अमरीकी सरकार का हित इसी में था कि वह इन क्षेत्रों को अपनी प्रभाव-परिधि के अन्तर्गत रखे ।

इसी कारण अमरीका ने हिन्द-महासागर में भारत के दक्षिण में नौसेना को प्रबलता प्रदान करने के लिये 'डायॉगो-गॉरसिया द्वीप समूह को चुना । यह भारत के दक्षिण में लगभग 3000 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित है तथा 'रॉगास द्वीप समूह' का ही एक भाग है । अमरीकी सरकार ने अपनी रुचि 1960 के लगभग इस क्षेत्र में प्रदर्शित की जबकि ब्रिटेन ने हिन्द-महासागर से अपनी सेना हटा लेने का निश्चय कर लिया था । परिणामस्वरूप 1966 में संयुक्त राष्ट्र अमरीका एवं ब्रिटेन के बीच 50 वर्षीय सुरक्षा समझौता सम्पन्न हुआ ।

ब्रिटेन ने इस सुरक्षा समझौते के अनुसार इस द्वीप समूह को अमरीका को संयुक्त सुरक्षा हेतु प्रदान किया था । प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की द्वीप समूह पर केवल संचारण व्यवस्था ही थी परन्तु हिन्द महासागर पर बढ़ते हुये सोवियत रूस के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करने लिये आवश्यक हो गया था कि अमरीका भी इस क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभाव में वृद्धि करे । परिणाम-स्वरूप अमरीका ने समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ऐसा ही किया । अक्टूबर, 1973 को राष्ट्रपति नक्सन ने सोवियत रूस के सैन्य प्रभाव का मध्य पूर्व एशिया में हनन करने के उद्देश्य से हिन्द महासागर में एक अमरीकी समुद्री जलयान भेजा परन्तु जब मध्यपूर्व एशिया पर से रूसी भय समाप्त हो गया तो भी अमरीकी सुरक्षा सचिव ने हिन्द महासागर से नौ-सेना को वापस बुलाना तर्क संगति एवं उचित नहीं समझा और यह घोषणा कर दी कि भविष्य में इन क्षेत्रों पर युद्धपोत सुरक्षा हेतु भ्रमण करते रहेंगे । इस घटना के पश्चात अमरीका को हिन्द महासागर पर स्थाई रूप से अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये अवसर प्राप्त हो गया क्योंकि फिलीपीन के क्यूवेक की खाड़ी के जहाजों पर नियन्त्रण स्थापित करने, एवं इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाये रखने के

लिए आवश्यक हो गया था कि अमरीका इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाये ।

अमरीकी संसद को इस बात का अनुमान था कि कालान्तर में यहाँ का द्वीप समूह स्थायी रूप से अमरीकी नौ-सेना एवं अन्य प्रकार की सैन्य गति-विधियों का अड्डा बन जायेगा । कुछ अमरीकी संसद सदस्यों का यह अनुमान था कि भविष्य में 'डयांगो गॉरसिया विदेश में एक बड़े स्तर पर अमरीकी नौ-सेना का केन्द्र बन जायेगा । यही कारण है कि हिन्द महासागर के प्रत्येक तटीय राष्ट्र को वस्तुतः अमरीकी उपस्थिति से भय था । इन तटीय राष्ट्रों में भारत ही एक ऐसा देश है कि जिसने हिन्द महासागर में संयुक्त राष्ट्र अमरीका की उपस्थिति का विरोध किया और तत्पश्चात् अन्य देश मलाया, हिन्देशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका तथा रूस ने भी अमरीकी उपस्थिति का विरोध किया । साथ ही इन समस्त तटीय देशों ने 1971 में संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक प्रस्ताव भी रखा जिस का मुख्य उद्देश्य यह था कि संयुक्त राष्ट्रसंघ हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित कर दे । परन्तु इन समस्त विरोधों के उपरान्त भी विश्व के महान् राष्ट्रों ने इन तटीय देशों की भावनाओं की ओर कोई विशेष ध्यान न दिया और उनकी मांगों का पूर्ण रूप से खण्डन कर दिया । इस प्रकार निक्सन एवं किंसिजर की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप एक नवीन शक्ति संतुलन सिद्धान्त का निर्माण हुआ जिसका श्रीगणेश वियतनाम की युद्ध-विराम संधि की शर्तों के परे था और जो वास्तव में चीनी एवं रूसी प्रभाव के खण्डन के फलस्वरूप अमरीकी हितों का स्वरूप था ।

फिलीपीन—एक सर्वेक्षण

दक्षिण-पूर्व एशिया में फिलीपीन एक ऐसा देश है जो अपने प्राप्त गौरव, गरिमा, ऐतिहासिक प्रतिष्ठा के प्रति विनम्र और निरहंकारी है । इसका मूल कारण इस देश में केन्द्रित सरकार की स्थापना का अभाव तथा आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के परिपूर्ण विकास से पहले ही पश्चिमी देशों के उपनिवेशवाद का शिकार हो जाना था । इस तथ्य के व्यापक परिणाम हुए जिनसे फिलीपीन को दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों से विमुख कर दिया ।

फिलीपीन के निवासी अधिकतर दूसरे देशों के भ्रमणकारी है जो दूसरे देशों से आकर यहाँ बस गये हैं । ईसा से कुछ शताब्दी पूर्व इण्डोनेशिया से आने वाले आप्रवासियों ने फिलीपीन के स्थानीय वासियों को इस द्वीप के सुदूर भागों में जाने हेतु विवश कर दिया तथा उत्तरी द्वीप में मुख्य चावल उत्पादकों की तरह रहने लगे । ईसा से प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी पूर्व मलाया से कुछ

आप्रवासी बोरनिया होकर केन्द्रीय विस्थान द्वीप में निवास करने लगे। ये आप्रवासी लोहे एवं पत्थर के बर्तनों एवं आयुधों की भली-भाँति प्रयोग करना जानते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें पोर्सलीन बनाने की कला का ज्ञान था तथा उनका अपना एक कानून था, एक वर्णमाला थी कुछ कला का भी ज्ञान था। फिलीपीन वासियों ने हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता से काफी कुछ सीखा था तथा धार्मिक क्षेत्र केवल पौराणिक एवं प्राकृतिक देवताओं की पूजा तक ही सीमित था। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में मलाया से आने वाले आप्रवासी समूह ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचलन प्रारम्भ किया।

फिलीपीन के चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध अनुमानतया दशवीं शताब्दी के अन्तिम चरणों में प्रारम्भ हुये थे जिसके फलस्वरूप फिलीपीन वासियों को निर्माण कला, बारूद, धातु विज्ञान, चाँदी पर कारीगरी तथा गहने बनाने की कला का ज्ञान हुआ। फिलीपीन के निवासियों पर चीन में प्रचलित धर्म का भी प्रभाव पडा। फिलीपीन में चीन में प्राचीन काल से प्रचलित कुछ देवी देवताओं की पूजा के प्रमाण प्राप्त हुये हैं। इसका यह परिणाम हुआ कि ईसाई धर्म प्रचारको (मिशनरियों) को अपने धर्म का प्रचार करने का बहाना प्राप्त हो गया।

फिलीपीन का सांस्कृतिक विकास प्रारम्भिक चरण में ही पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि फिलीपीन में दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी अन्य देश की अपेक्षा पश्चिमी आचार व्यवस्था का अधिक प्रचलन प्रारम्भ हुआ। इसके अतिरिक्त पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने फिलीपीन निवासियों को दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक बना दिया परन्तु शान्तिपूर्ण ढंग से स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण फिलीपीनवासियों में राष्ट्रवादी भावना का अत्यधिक विकास न हो सका। फलस्वरूप फिलीपीन में डच, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश उपनिवेशों की अपेक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति से सम्बन्धित सामाजिक उथल पुथल की मात्रा सर्वाधिक थी।

फिलीपीन में स्पेनिश जाति के आगमन के समय भोलाय जाति के लोगों का वास था। इसमें कुछ अहेरी (शिकारी) थे, कुछ ऊँचे भागों में कृषि करते थे तथा नीचे भागों के निवासी धान की खेती किया करते थे। इसी समूह के साथ स्पेन वासियों का सबसे अधिक सम्बन्ध रहा। इस समय सबसे बड़ी एवं स्थिर राजनैतिक इकाई 'वैरावी' थी जो कि लगभग एक गाँव के बराबर होती थी तथा इसका शासक दातू कहलाता था। ये दातू अन्य राजाओं के साथ अधिकतर संघों का निर्माण करते थे परन्तु वियतनाम एवं धाना की भाँति धान की खेती पर संयुक्त अधिकार नहीं रखते थे। दातू अथवा भूस्वामी अपनी

भूमि में कार्य करवाने हेतु दास रखते थे। इसके अतिरिक्त एक वर्ग 'कृषक' दासों का था जो उपज का अर्धभाग अपने स्वामी को दिया करते थे तथा विभिन्न उत्सवों पर अपने स्वामी के लिये विभिन्न सेवा कार्य करते थे। उपर्युक्त समुदायों में झगड़ो को निपटाने हेतु दण्ड का कोई विधान नहीं था, परन्तु क्षतिग्रस्त दल की क्षतिपूर्ति हेतु न्यायिक प्राविधान था।

दक्षिण पूर्व एशिया में हिन्देशिया के श्रीविजय एवं भजापहित साम्राज्यों ने फिलीपीन पर अपना कुछ सांस्कृतिक प्रभाव अंकित किया परन्तु चीन एवं भारत की संस्कृति का प्रभाव फिलीपीन पर विशेष महत्वपूर्ण नहीं था। इसका मुख्य कारण फिलीपीन वासियों की हिन्दू अथवा बुद्ध धर्म की ओर अरुचि थी। वास्तव में फिलीपीन वासियों का धर्म ब्रह्मवाद था। 15 वीं शताब्दी में इस धर्म के प्रचलन में परिवर्तन आया जबकि मक्का से इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार फिलीपीन में प्रारम्भ हुआ। इस्लाम का सर्वप्रथम प्रसार सालू एवं भिण्डानों में हुआ। सोलहवीं शताब्दी तक दो सल्तनतों की वहाँ स्थापना हुई। मनीला का सरदार भी मुसलमान हो गया था। इसी समय स्पेनवासियों का फिलीपीन में आगमन हुआ। फिलीपीन में स्पेनी अधिकार का मुख्य ध्येय व्यापारिक नहीं, प्रत्युत सैनिक था।

फिलीपीन पर स्पेनिश अधिकार एवं शासन

फिलीपीन द्वीप पर मैगलन के अभियान की वापसी के पश्चात सर्वप्रथम 1522 में चार्ल्स पंचम ने अपने अधिकार की घोषणा की परन्तु 1529 में इस घोषणा को वापस ले लिया गया जबकि अनेक महँगे अभियानों के पश्चात भी स्पेनवासी इस क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित करने में असफल रहे। 1542 में सर्वप्रथम इस द्वीप का नाम चार्ल्स पंचम के पुत्र फिलिप के नाम के कारण 'फिलिपिनास' रखा गया परन्तु चार्ल्स द्वितीय के शासन काल के प्रारम्भ तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। 1559 में इस द्वीप पर आधिपत्य के लिये उपक्रम किया जाने लगा। 1564 में पाँच युद्ध पोतों ने, जिनमें लगभग चार सौ स्पेनिश सैनिक थे, इस द्वीप की ओर प्रस्थान किया। इस दल के नेता नौसेनापति (एडमिरल) लेगास्पी थे। इस अभियान का ध्येय अन्वेषण करना, स्थानीय जनता को ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा क्षेत्रीय व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करना था। स्पेन ने पिसयान क्षेत्र में सीपू द्वीप पर सर्वप्रथम अपना अड्डा स्थापित किया। इस क्षेत्र में मिन्दानी से आयात हेतु केवल दालचीनी ही एकमात्र वस्तु थी जिसका उत्पादन मोरी जाति के विरोध

एवं इस द्वीप वासियों की निर्धनता के कारण लगभग समाप्त हो गया था। परन्तु इस द्वीप से चीन के साथ व्यापार के अच्छे अवसर थे। इस द्वीप के वासी लेगास्पी का विरोध करने में असफल रहे। फलस्वरूप उसने एक अन्य स्पेनी अड्डे की नींव रखी। 1571 में मनीला नगर को स्पेनी राजधानी बनाया गया जिसके विरोध स्वरूप मोरी की बाल सेना ने आक्रमण किया। 1574 में चीनी जलसेना ने एक अन्य संकट उत्पन्न किया परन्तु स्पेनी सेना को सहायता मिल जाने के कारण सफलता प्राप्त हुई। इसके पश्चात् चीनियों के साथ व्यापार बड़े पैमाने पर प्रारम्भ हो गया क्योंकि चीनी व्यापारियों को अपने वर्तनों के बदले चाँदी मिलने लगी थी। 1572 तक फिलीपीन के समुद्री किनारों पर स्पेनी अधिकार पूर्ण रूप से हो गया था।

मैक्सिको में प्रचलित स्पेनी प्रशासनिक पद्धति को फिलीपीन में भी कार्यान्वित किया गया। इस प्रशासन की महान सफलता यह थी कि इससे सहयोगी द्वीपों का एकीकरण कर दिया। इस प्रशासन के अन्तर्गत गवर्नर जनरल, न्यायालय (आडिन्शिया) एवं कोषाधिकारी स्पेन के राजा के प्रतिनिधि थे। आडिन्शिया का मुख्य कार्य फिलीपीन प्रदेशों का धार्मिक समूह के अतिक्रमण से रक्षा करना था। प्रदेश के जिले एवं नगरों का प्रशासन स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया जो कि पुलिस एवं सेना के नियंत्रक थे तथा सार्वजनिक निर्माण एवं सड़कों के निर्माण सुधार का कार्य करते थे। वे सीमाओं पर धर्म प्रचार कार्यक्रमों का समर्थन करते थे। जनता पर प्रशासन हेतु सामन्ती की स्थापना की गई जो कि कर एवं किरायों की वसूली करते तथा न्यायिक निर्णय लिया करते थे। इनकी नियुक्ति स्पेन का राजा करता था।

प्रथम बीस वर्षों के शासन काल में मुख्यतः खाद्य पदार्थों का अभाव बना रहा परन्तु मनीला में व्यापार एवं उत्पादन वृद्धि के साथ ही उपर्युक्त कमी की पूर्ति की गयी। 1591 में फिलीपीन में ईसाइयों को दास बनाना अवैध घोषित कर दिया गया परन्तु गैर ईसाइयों से इसके उपरान्त भी बलपूर्वक कार्य लिया जाता था। 1595 एवं 1604 के सुधारों में इस प्रथा का भी अन्त कर दिया गया। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में डच लोगों ने कई बार मनीला पर आक्रमण किया। 1609, 1621 तथा 1648 के डच आक्रमणों के समय फिलीपीन वासियों को बलपूर्वक कार्य करने एवं डच सैनिकों को खाद्य पदार्थ देने हेतु बाध्य किया गया। 1648 में स्पेन एवं हॉलैण्ड के मध्य मन्सटर की संधि हुई जिसके अन्तर्गत स्पेन ने हॉलैण्ड की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। इसके बदले हॉलैण्ड ने मनीला पर अपने आक्रमण स्थगित कर दिये। फलतः मनीला में स्पेनिश सैनिक दबाव काफी कम हो गया।

फिलीपीन में स्पेनवासियों के आगमन के पश्चात भी ग्राम प्रमुख के अधिकारों में ज्यादा कमी नहीं आयी। स्थानीय मुखियाओं की सरकार को कर देने से मुक्ति दे दी गयी तथा उन्हें गाँवों एवं कस्बों का गवर्नर बनाया गया। परन्तु यूरोपीयों ने इन ग्राम प्रधानों को कुछ राजकीय शक्तियों से वंचित कर दिया था। इस समय भी गाँववासी अपने ग्राम प्रमुख की फसल काटने, मकान बनाने में सहायता करते थे तथा अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग उसे कर स्वरूप दिया करते थे। अतः फिलीपीन में एक सामन्तवादी स्थानीय राजाओं के वर्ग का विकास हुआ जो कि स्पेनिश अधिकारियों एवं फिलीपीन की जनता के मध्य आवश्यक सूत्र का कार्य करते थे।

धार्मिक समूह की बढ़ती हुई शक्ति ने केन्द्र में तथा गाँवों में जन सरकार की शक्तियों को अत्यधिक प्रभावित किया। धार्मिक समूह का राजनैतिक प्रभाव 1700 के पश्चात अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। मनीला के गवर्नर के पश्चात पादरी ही सर्वशक्तिमान अधिकारी होता था। 1725 में एक घोषणा के द्वारा गवर्नर की मृत्यु के समय पादरी को ही अंतरिम गवर्नर नियुक्त किये जाने का प्राविधान बनाया गया था। प्रारम्भ से ही धार्मिक समूह गवर्नर के अधिकारों को कम करने की चेष्टा में रत था तथा अपने इस प्रयास में उन्होंने कई बार जनता को आक्रोश दिलाकर सरकारी कर्मचारियों पर आक्रमण हेतु भी उकसाया जैसाकि 1719 की एक घटना से स्पष्ट है। स्थानीय अधिकारी भी इस धार्मिक समूह के विरोध के शिकार थे। स्थानीय भाषा से परिचित होने के कारण इस धार्मिक समूह का सरकारी संचार व्यवस्था में एकाधिकार था। अतः फिलीपीन में वास्तव में स्थानीय शासकों एवं धार्मिक समूह का ही नियंत्रण था।

फिलिपीनी विद्रोह एवं ब्रिटिश आधिपत्य

भाषा में अन्तर होने के कारण, तथा सरकार द्वारा फिलीपीन को कई सौ द्वीपीय इकाइयों में बाँटने के फलस्वरूप समय समय पर जनता अपने रोप एवं असंतोष की अभिव्यक्ति स्थानीय विद्रोहों के माध्यम से करती रही। परन्तु इन स्थानीय विद्रोहों का तत्कालिक कारण आर्थिक कठिनाइयाँ थीं जिसमें ग्राम प्रधान को जनता द्वारा कर देना, ग्रामवासियों से बलपूर्वक कार्य करवाना एवं कर न देने की स्थिति में भूमि से वंचित किया जाना प्रमुख थे। कुछ विद्रोहों का कारण राजनैतिक एवं धार्मिक भी था लगभग सभी विद्रोहों का नेतृत्व धार्मिक गुरुओं ने किया जो जनता से भगवान के नाम पर विद्रोह की अपील

किया करते थे । 1621 में इसी प्रकार का एक विद्रोह हुआ । 1649 में लूजान में एक विद्रोह हुआ । इसका कारण मनीला पर डच आक्रमण के भय के फल-स्वरूप स्पेन सरकार द्वारा स्थानीय जनता से वलपूर्वक कार्य कराया जाना था । सर्वप्रथम मनीला के बन्दरगाह के कर्मचारियों ने विद्रोह किया जो कि शीघ्र ही उनके निवास द्वीप समर में फैल गया जहाँ लड़ाई के मध्य निवासियों ने मकान छोड़ दिये । एक अन्य विद्रोह लूजान के पंपंगा क्षेत्र में 1660-61 में हुआ । इसका कारण डच युद्ध के पश्चात् उत्पन्न कठिनाइयाँ थी । यह विद्रोह अन्य द्वीपों तक फैल गया जहाँ स्थानीय राजाओं की स्थापना की गई, चर्च को लूट लिया गया एवं पादरियों को मार डाला गया । परन्तु उपर्युक्त सभी विद्रोहों का दमन कर दिया गया । अठारहवीं शताब्दी में तीन विद्रोहों का उल्लेख किया जा सकता है । प्रथम 1744 में बोहोल द्वीप पर प्रारम्भ हुआ । इस विद्रोह में नेताओं एवं उनके कई हजार अनुयायियों ने पास के पहाड़ों में शरण ली तथा अगले अस्सी वर्षों तक आक्रमणों का प्रतिरोध करते रहे । द्वितीय विद्रोह 1745-46 में टेगालोग में प्रारम्भ हुआ । इसका मुख्य कारण साम्प्रदायिक भूमि पर पादरियों द्वारा आधिपत्य स्थापित करना था । तीसरा विद्रोह मनीला पर ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के आधिपत्य के समय 1762-63 में प्रारम्भ हुआ । यह ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटेन एवं स्पेन के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध के अन्तिम काल में स्पेन विरोधी अभियान का परिणाम था । चतुर्थ फिलीपीन विद्रोह लूजान के इलोकना क्षेत्र तक ही सीमित रहा तथा प्रथम बार इस विद्रोह ने स्पेन के नियंत्रण का गम्भीर खतरा उत्पन्न कर दिया था । परन्तु गाँव के प्रमुख एवं पंपंगा पुलिस की सहायता से इसको दबा दिया गया ।

मनीला पर ब्रिटिश भारतीय सैनिकों का आधिपत्य बीस मास तक रहा । अक्टूबर, 1762 में वह आधिपत्य प्रारम्भ हुआ परन्तु एडमिरल कॉर्निश एवं जनरल ड्रेपर के नेतृत्व में विजयी सेना फिलीपीन वासियों के विरोध के कारण मनीला शहर की दीवारों के बाहर अपना नियंत्रण स्थापित करने में असफल रही । फरवरी 1763 में पेरिस की संधि के फलस्वरूप मनीला पर पुनः स्पेन का अधिकार स्थापित हो गया । परन्तु ब्रिटिश सैनिक मनीला से वापसी के समय सभी मूल्यवान वस्तुओं को अपने साथ ले गये । फलस्वरूप दस अन्य द्वीपों में विद्रोह प्रारम्भ हुये परन्तु गवर्नर ने उन्हें कुचल दिया ।

सुधारात्मक प्रयास

इन विद्रोहों की शृंखला के फलस्वरूप स्पेनिश अधिकारियों को सुधार

कार्यक्रम अपनाने पर विवश होना पड़ा। इस समय स्पेन का राजा चार्ल्स तृतीय था, जो उदारवादी था। तत्कालीन गवर्नर 'डिल टोरे' ने मनीला में हुई हानि को पूरा किया तथा स्पेन की सरकार को कुछ व्यापक सुधार क्रियान्वित करने का सुझाव प्रदान किया। प्रथम सुधार कार्यक्रम स्वतन्त्र विचारधारा एवं आर्थिक रूप से प्रभावशाली धार्मिक वर्ग के लिए निर्देशित था। 1786 में जेसुइट सभा को देश से निष्कासित कर दिया गया तथा शीघ्र ही पोप की शक्तियों का अन्त कर दिया गया। 1770 में 'साइमन डे एण्डा' फिलीपीन का गवर्नर बना तथा उसने भिक्षुओं के विरुद्ध अपना अभियान प्रारम्भ किया। एण्डा ने भिक्षुओं पर व्यापारिक कार्यों में रुचि लेने, सार्वजनिक मामलों में हस्तक्षेप, अध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा, फिलीपीनों पर अत्याचार एवं स्पेनी भाषा के फिलीपीन में पढ़ाये जाने के विरुद्ध होने का आरोप लगाया। 1774 में भिक्षुओं की सम्पत्ति को धर्म प्रान्तीय करने की आज्ञा दी गयी परन्तु राजाज्ञा के उपरान्त भी इसे पूर्ण रूपेण क्रियान्वित न किया जा सका। 1776 में 'साइमन डे एण्डा' की मृत्यु हो गयी और इस कार्यक्रम को मध्य में ही समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त चार्ल्स तृतीय ने ग्राम प्रमुखों की वंशानुगत प्रणाली का अन्त करने का असफल प्रयास किया। उन्होंने एक राजाज्ञा के द्वारा गाँव के मजिस्ट्रेट का चुनाव कराने की घोषणा की तथा वसूली को अधिक सफल बनाने का प्रयास किया परन्तु वे असफल रहे।

याजक वर्ग सम्बन्धी उक्त अभियान में असफलता के पश्चात् द्वीप को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु एक कार्यक्रम निमित्त किया गया। 1778 में जोज वॉस्को वरगॉस' फिलीपीन का गवर्नर नियुक्त किया गया। और उसने आर्थिक स्वलम्बन हेतु कृषि' उद्योग एवं वाणिज्य में विकास हेतु प्रस्ताव रखे। डान जॉस ने रूई, चीनी, तम्बाकू, नील, भाँग चरस, गाँजा तथा शहतूत के उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन किया तथा खानों से धातु निकालने एवं पोर्सलीन के उत्पादन को भी प्रोत्साहन प्रदान दिया। 1781 में उसने राजा की सहमति से 'एकोनामिक सोसायटी ऑफ द कन्ट्री की स्थापना की। यह सभा 1811 तक चलती रही, 1820 में इसका पुर्ननिर्माण किया गया 1861 में इस सभा ने मनीला में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा इसके प्रयासों से 1881 में मनीला विश्वविद्यालय में कृषि विभाग में एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गयी। तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्र इस कार्यक्रम से सर्वाधिक प्रभावित हुये। 1780-82 में तम्बाकू के उत्पादन एवं विक्रय पर सरकारी एकाधिकार की स्थापना की गई जिससे सरकार को अत्याधिकलाभ हुआ। आगामी वर्ष में फिलीपीन तम्बाकू का सर्वधिक उत्पादक देश हो गया परन्तु इससे भी उत्पादकों को कोई

विशेष लाभ नहीं हुआ तथा अन्य भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के फलस्वरूप 1881-82 में सरकार को एकाधिकार समाप्त करने पर बाध्य होना पड़ा। तम्बाकू एवं वारूद तथा शराब पर एकाधिकार का फिलीपीन निवासियों ने अत्यधिक विरोध किया।

वाणिज्य में सुधार हेतु 17८9 में नई व्यापार संहिता के अंतर्गत 'व्यापारिक निगम' की स्थापना की गई जिसे विभिन्न व्यापारों के निरीक्षण का कार्य सौंपा गया। 1785 में 'रायल कम्पनी ऑफ फिलीपीन' का संगठन किया गया। इस कम्पनी ने कैंटन, भारत तथा 'केप आव गुड होप', के रास्ते स्पेन के साथ व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। 1789 में मनीला विश्व के अन्य देशों के जहाजों हेतु एशिया के उत्पादनों को लाने और ले जाने के लिये माल दिया गया 1810 तक इस कम्पनी के व्यापार का पाँचवाँ भाग भारत के साथ था, परन्तु भारतीय वस्तुओं के बदले उन्हें मैक्सिको को चाँदी देनी पड़ती थी। परन्तु 1806 में नेपोलियन का इस द्वीप पर अधिकार हो जाने के पश्चात् इन सुधारों की श्रृंखला भंग हो गई।

मैक्सिको में स्पेनी साम्राज्य के अन्त के फलस्वरूप उन्नीसवीं शतब्दी से चाँदी का आगमन पूर्ण रूपेण बन्द हो गया। परिणामस्वरूप फिलीपीन को अपना व्यापार यूरोप की दिशा में मोड़ना पड़ा। इसके उपरान्त भी मनीला के व्यापार में भारी गिरावट आयी। 1818 में मनीला में लगभग एक दर्जन व्यापारिक संस्थाएँ कार्य कर रही थीं परन्तु 1842 में ब्रिटेन एवं चीन के मध्य व्यापारिक संधि के कारण दक्षिण चीनी समुद्र में पाँच नये बन्दरगाह खोल दिये गये, फलस्वरूप चीनी एवं विदेशी जहाजों का मनीला आना जाना स्थगित हो गया। 1850 तक मनीला लगभग दिवालिया हो चुका था। यद्यपि कृषि के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई तथा तम्बाकू एकाधिकार स्थापित रहा, परन्तु सामान्यतया आर्थिक दशा में अवनति हुई।

19 वीं शताब्दी के दूसरे एवं तीसरे दशकों में याजक वर्ग की गतिविधियाँ अत्यन्त तीव्र हो गयी थीं। जेसुइट सोसायटी की पुनः स्थापना हुई। तथा यह फिर भिन्डानों में अपने कार्य में लग गयी। 1835 में स्पेन ने कई मठों का दमन किया। फलस्वरूप याजक वर्ग फिलीपीन की ओर अधिक आकर्षित हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि नवीन याजक वर्ग तथा परम्परावादी याजक वर्ग के मध्य तनाव पूर्ण स्थित में वृद्धि हुई। 1843 में फिलीपीन में स्थानीय याजक वर्ग ने एक विद्रोह का सूत्रपात किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण, स्पेनियों द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति का परिपालन, शिक्षा के प्रसार में कमी एवं फिलीपीनवासियों हेतु नियुक्तियों के अवसर न प्राप्त होने में निहित थे।

फिलिपीन क्रान्ति:-

1815 के पश्चात् फिलीपीन का, स्पेनिश अमरीका के अधीन रहकर, स्पेन के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों द्वारा गठबन्धन हो गया। भिक्षु तथा याजक वर्ग ने मलीना को अपना कार्यस्थल बनाया। 1835 में स्पेन ने भिक्षु स्थानों का दमन करने का प्रयत्न किया।

फिलीपीन की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था याजक वर्ग के कारण और अधिक शोचनीय हो गई थी। 1849 के पश्चात् फिलीपीन शिक्षक वर्ग ने याजक वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाना आरम्भ किया। दो पत्रों- 'एल मनीला' 'एल कामर्शियों', ने 1848 और 1850 में चर्च की धर्म निरपेक्षता की नीति का पालन करने का प्रयत्न किया।

याजक वर्ग से कृषक त्रस्त था। इस वर्ग ने स्पेनवासी जमींदारों तथा याजक वर्ग के सामन्तवादी याजकों के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्य आरम्भ किया।

1869 के पश्चात् फिलीपीन में राजनीतिक अशांति और अधिक तीव्रता से बढ़ने लगी। सरकार ने 1872 से 1898 के मध्य निरन्तर दमनकारी नीति, का प्रयोग किया। 1897 में स्पेन के शासन की तीव्र आलोचना जोज रिजाल ने प्रारम्भ की। रिजाल ने याजक वर्ग के सामन्तवाद तथा स्पेन के शासन का विरोध किया। यूरोप में उसने 'डेल पाइलर' से भेंट की जो फिलीपीन के राष्ट्रीय आन्दोलन का संस्थापक माना जाता है।

रिजाल अपने कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करना चाहता था और भूमि सुधारों का इच्छुक था। उसने अपने कार्य के लिये लेखन का सहारा लिया और अनेक उपन्यास तथा लेख लिखे। उसका अत्यन्त महत्वपूर्ण उपन्यास "टच मी नाट" अथवा "दि सोशल कैसर" था जो बर्लिन में 1887 में प्रकाशित हुआ। उसने इस उपन्यास के द्वारा पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अन्याय, रूढ़िवाद भ्रष्टाचार, अनाचार तथा मिथ्याचार आदि समाज की प्रचलित कुरीतियों का उल्लेख किया। इस उपन्यास ने स्थानीय लोगों में नवचेतना की जागृति की ओर इस कारण यह उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। उसका दूसरा उपन्यास "द रेन आव ग्रीड" 1880 में प्रकाशित हुआ। यह भी उसके प्रथम उपन्यास की भाँति परिपक्व और प्रभावशाली था।

यद्यपि रिजाल ने ही राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ किया परन्तु काती पूनान नाम की संस्था ने राष्ट्रवादी आन्दोलन को नवीन जीवन दिया। इसका नेतृत्व एमीलियो गवीनाल्डो नामक व्यक्ति ने किया। इस संस्था ने अपना हिंसात्मक तथा विद्रोहात्मक रूप धारण कर स्पेन की प्रशासनिक नीति को और

अधिक दमनकारी बनाने पर बाध्य कर दिया। 1869 में रिजाल को प्राणदण्ड दिया गया और विद्रोह को दमन करने की चेष्टा की गयी। इसका परिणाम स्पेनिश शासन को भुगतना पड़ा और स्पेनिश शासन का अन्त निश्चित हो गया। इसके साथ ही फिलीपीन राष्ट्रवाद को विच्छेदकारी धार्मिक आन्दोलन से भी बल मिला। इस आन्दोलन का नेतृत्व 'फादर एगलीये' ने किया। फिलीपीन के लोग अभी अपने इस संघर्ष में ही रत थे, जब 1898 में अमरीका ने इस देश का समामेलन कर लिया। इस पर भी फिलीपीन राष्ट्रवादियों का यही मत था कि स्पेनिश लोग इस क्षेत्र से जायें और भिक्षु भूस्वामियों से भूमि वापस ली जाय।

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में याजक वर्ग में परस्पर मतभेद, व्यापार की कमी के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाईयों, स्पेन के प्रशासकों द्वारा किये गये अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण तथा गरीब किसानों की जमीन पर बड़े जमींदारों द्वारा अतिक्रमण के कारण फिलीपीन में क्रांति हुई।

इस क्रांति के लिये आवश्यक शिक्षा 19वीं शताब्दी के लगभग अन्त तक कैथोलिक संस्थाओं ने दी थी। स्वेज नहर के निर्माण के फलस्वरूप सस्ती यात्रा ने फिलीपीन के युवकों को यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने का एक सुअवसर प्रदान किया। यूरोप में इन विद्यार्थियों को उदारवाद एवं राष्ट्रवाद के सिद्धांतों ने अत्यधिक प्रभावित किया।

फिलीपीन क्रांति के पथ प्रदर्शन में बुद्धिजीवियों का प्रमुख योगदान था, जो कि यूरोपीय शिक्षा प्राप्त थे। उन्होंने क्रांति अथवा स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार नहीं किया परन्तु उन्होंने केवल फिलीपीन को स्पेन राज्य के एक प्रदेश के रूप में मान्यता देने की माँग की तथा जनता की स्वाधीनता तथा सुधारों पर बल दिया। कुछ प्रचारवादियों ने स्पेनी भिक्षुओं को निष्कासित करने की माँग की तथा इनका फिलीपीन के पादरी वर्ग ने समर्थन किया। इन प्रचारवादियों में जोस रिजाल प्रमुख था। 1887 में स्पेनी अधिकारियों ने जोस रिजाल को सशस्त्र क्रांति का प्रयास करने का आरोप लगाकर गोली से उड़ा दिया, उसके अन्य साथियों को जेल में बन्द कर दिया तथा उनकी सम्पत्ति जप्त कर ली। 1896 में मनीला के आस पास कई प्रदेशों में विद्रोह भड़क उठा। स्पेनिश अधिकारियों ने क्रांतिकारियों को पहाड़ों में शरण लेने पर बाध्य कर दिया। 1897 में एक युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किये गये। इसी समय अमरीका एवं स्पेन में युद्ध प्रारम्भ हो गया। जिसके एक माह के पश्चात् 1 मई, 1898 को अमरीकी जल सेना ने मनीला की खाड़ी में स्पेनी समुद्री सेना को पराजित किया। फलस्वरूप क्रांतिकारियों ने पुनः संगठित होकर सैनिक अभियान

प्रारम्भ किया और जून में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी ।

इस क्रान्ति के नेता प्रचारवादियों के लेखों से 1896 से 1898 तक लाभान्वित होते रहे । इन लेखों से क्रान्ति के दो प्रमुख नेता अत्यधिक प्रभावित थे । प्रथम थे 'आन्द्रे बोनीफेसियों' जिसने 'कातीपुनान' नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी तथा 1896 में क्रांति को भड़काया । द्वितीय एमील्यों एग्वीनाल्डों' जो क्रांतिकारी सेना के मुख्य संचालक थे तथा बाद में तो क्रांतिकारी सरकार के अधिनायक एवं 1 जनवरी, 1898 को घोषित गणतंत्र के राष्ट्र-पति बने ।

इन नेताओं को चर्च के अन्तर्गत भूमि पर कार्य करने वाले कृषकों ने अत्यधिक समर्थन दिया । फलस्वरूप 1898 में क्रान्तिकारी सरकार ने चर्च भूमि का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की तथा स्पेनी भिक्षुओं को फिलीपीन से चले जाने की आज्ञा दी । यह स्पष्ट है कि इस क्रान्ति के राष्ट्रीय तथा सामाजिक दोनों ही उद्देश्य थे परन्तु दोनों ही उद्देश्य कुछ घटनाओं के कारण असफल हो गये । प्रथम फिलीपीन के अमीर वर्ग ने क्रान्तिकारी गणतन्त्र का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया तथा द्वितीय, फिलीपीन में अमरीकी आधिपत्य स्थापित करने की नीति थी । स्पेन की पराजय के पश्चात् फिलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य स्थापित हो गया । यद्यपि फिलीपीनवासियों ने इसका विरोध किया परन्तु उनके नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात् यह प्रतिरोध समाप्त हो गया ।

इस प्रकार फिलीपीन में गणतन्त्र की घोषणा ने फिलीपीन को दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे प्रथम राष्ट्र का पद प्रदान किया जिसमें कि विदेशी उपनिवेशवाद के उन्मूलन का प्रयास किया । राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ साथ फिलीपीन में कुछ राजनैतिक भावनाओं का भी विकास हुआ था क्योंकि उन्होंने एक संविधान का भी निर्माण किया था जिससे यह सिद्ध होता है कि अमरीका एवं अन्य देशों के संविधानों का उन्हें पूर्ण ज्ञान था । इस संविधान के प्राविधानों के अनुसार उन्होंने सरकार एवं प्रदेशों में प्रशासकों की स्थापना की थी ।

फिलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य

फिलीपीन में अमरीका के शासन का आरम्भ टॉफ्ट के द्वारा हुआ । विलियम टॉफ्ट 1901 से 1904 तक आयुक्त रहा । इस समय में उसने कूप अधिनियम (1902) के द्वारा 1903 में स्थानीय चुनाव कराया । जिसके फलस्वरूप स्वदेशी निवासियों को प्रशासन कार्य में उचित सम्मति देने का अवसर दिया गया । इसके अतिरिक्त नवीन न्याय-संहिता बनायी गयी जिसके द्वारा

फिलीपीन के न्यायाधीश न्याय करते थे ।

धीरे धीरे फिलीपीन के लोगों को और वैधानिक सुविधायें प्रदान की जाने लगीं । तदर्थ राजकीय परिषद 1909 में बनायी गयी जो महाराज्यपाल की परामर्शदाता परिषद का कार्य करती थी । मन्त्रिमंडल में भी अधिक फिलीपीनी थे परन्तु पूर्ण प्रशासन का उत्तरदायित्व महाराज्यपाल पर था ।

मई 1898 में फिलीपीन (फिलिपीन)की राजनैतिक समस्याओं में अमरीकी समुद्री सेना द्वारा अनुचित हस्तक्षेप करने में तीन व्यक्तियों का प्रमुख योगदान था—प्रथम कैप्टन महन, द्वितीय अमरीकी संसद सदस्य हेनरी लाज एवं तृतीय जलसेना के सहायक सचिव थियोडोर रज्वेल्ट । इन्होंने अमरीका एवं स्पेन के मध्य संघर्ष के सुअवसर का लाभ उठाते हुये दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु एक अड्डे की स्थापना की । इस अमरीकी नीति के निर्णय का एक कारण तत्कालीन विश्व के प्रमुख देशों का मध्य उपनिवेशवाद प्रतियोगिता भी थी । इसके अतिरिक्त अमरीका के इस निर्णय के प्रति ब्रिटेन ने अत्यधिक सहानुभूति प्रदर्शित की क्योंकि ब्रिटेन जर्मन शक्ति के विरुद्ध अमरीका को प्रयोगात्मक मानता था । इस समय अमरीका में राष्ट्र भक्तों एवं प्रोटेस्टेन्ट ईसाइयों के मध्य भी उपनिवेश बनाने के प्रति अपना उत्साह था ।

मनीला की खाड़ी में अमरीकी एडमिरल ड्यूई (डूई) ने 'कातीपुनान' के नेता आजीनाल्डो, को जिसको स्पेन की सरकार ने फिलीपीन से निष्काषित कर दिया था, सिगापुर से हांगकांग बुलाया । उसके द्वारा फिलीपीन में स्पेन के अधिकार को समाप्त करने हेतु फिलीपीन की जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया । आजीनाल्डो 19 मई को मनीला की खाड़ी पहुँचा तथा एक मास के भीतर ही उन्हें फिलीपीन क्रान्तिकारी सरकार का प्रमुख बना दिया गया । 13 अगस्त को वाशिंगटन एवं स्पेन के मध्य शांति संधि हुई जिसके अनुसार स्पेन ने फिलीपीन द्वीप समूह को अमरीका को सौंप दिया तथा स्पेन ने 20 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति देने का भी वायदा किया ।

इस युद्ध के मध्य फिलीपीन वासियों ने अमरीकियों को सहयोग प्रदान किया था । उन्हें यह आशा थी कि वे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु युद्ध कर रहे थे, जब उन्हें फिलीपीन पर अमरीकी आधिपत्य का निर्णय ज्ञात हुआ, उन्होंने अमरीकी सरकार के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कर दीं । साढ़े तीन वर्ष के सैनिक प्रयासों के पश्चात् अमरीकी फिलीपीन में विद्रोही गतिविधियों को रोकने में सफल हुये । 1900 में आजीनाल्डो पकड़ा गया तथा उन्होंने अमरीकी सरकार के प्रति वफादार रहने की शपथ खाई, परन्तु उनकी



विलियम हॉवर्ड टॉपट (1857—1930)

सेना के एक अधिकारी फिलिप साल्वाडोर ने लगभग एक दशक तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। 1907 तक फिलीपीन में विद्रोही गतिविधियों का लगभग अन्त हो गया था। एमील्यो आजीनाल्डो जनप्रिय नेता के रूप में कार्य करते रहा। 1920 में फिलीपीन विधान सभा ने उन्हें पेंशन प्रदान की तथा इसके पश्चात् भी उसने मैनुअल केजान के राजनैतिक नेतृत्व को कई बार असफल चुनौती दी; आजीनाल्डो की इच्छा अपने देशवासियों के भविष्य को उज्ज्वल करना था तथा वह शीघ्र ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का इच्छुक था।

अमरीकी सरकार ने फिलीपीन गुरिल्लों के मध्य युद्धकाल में ही कॉर्नेल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डा. शुमान के नेतृत्व में एक पाँच सदस्यीय तथ्योद्घाटक शिष्टमंडल फिलीपीन भेजा था। इसने राष्ट्रपति मेकनली को विवरण प्रस्तुत किया जिसमें इस तथ्य का समावेश था कि फिलीपीन वासी अंततः स्वतंत्रता के इच्छुक हैं। परन्तु इस समय तक 1896 की संधि का अमरीकी संसद ने अनुमोदन कर दिया था जिसमें फिलीपीन के समामेलन के प्राविधान भी सम्मिलित थे। कुछ महीनों के पश्चात् विलियम हावर्ड टॉफ्ट की अध्यक्षता में दूसरा शिष्टमंडल फिलीपीन भेजा गया और इस शिष्टमंडल के विवरण के आधार पर 1901 में फिलीपीन में सैनिक सरकार के स्थान पर असैनिक सरकार की स्थापना की गई।

अमरीकी शासन एवं भूमि सुधार :—

फिलीपीन में अमरीकी शासन का प्राारूप विलियम हावर्ड टॉफ्ट ने निर्धारित किया। यह प्राारूप उन्होंने 1901 से 1904 तक फिलीपीन के कमिश्नर के रूप में, इसके पश्चात् राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मंत्रीमंडल में युद्ध मंत्री के रूप में, तथा अंततः 1909 से 1913 तक अमरीका के राष्ट्रपति के रूप में, निमित्त किया। टॉफ्ट ने सैनिक शासन का अन्त करके फिलीपीन के नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने चर्च एवं राज्य के मध्य पृथक्करण की स्थापना कर, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं तथा स्थानीय विधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। 1902 में कूपर 'अधिनिग्रम' के अमरीकी संसद द्वारा पारित होने के पश्चात् विलियम टॉफ्ट ने 1903 में प्रथम स्वतंत्र चुनाव कराये जिससे अमरीकी सरकार को म्युनिसिपल एवं ग्रामीण सरकार से सम्बन्धित मामलों में फिलीपीनी जनता के सुझावों से अवगत होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इस दिशा में एक अन्य प्रयास 1907 में किया गया जबकि साक्षर मतदाताओं के आधार पर आम चुनाव कराये गये। 1907

में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हेतु एक आर्थिक कोष की स्थापना की गई। विलियम टॉफ्ट ने विजित मोरो जनजाति के पारम्परिक नियमों को ध्यान में रखते हुये एक समान विधि संहिता का निर्माण किया तथा फिलीपीन के न्यायाधीश को इसकी व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

1901 में सर्वप्रथम फिलीपीन वासियों को एक शिष्टमंडल की सदस्यता प्रदान की गई थी। 1908 में सर्वप्रथम उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिये गये। इसके पश्चात् न्याय, वित्त एवं श्रम विभाग में फिलीपीनों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। 1909 के पश्चात् एक अस्थायी राज्य सभा गवर्नर जनरल की 'परामर्शदाता' समिति के रूप में स्थापित की गई। इस राज्य सभा में विधायिका के दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा बहुमत प्राप्त दल के नेताओं को भी सम्मिलित किया गया था। मंत्रिमंडल में जन-प्रशिक्षण को छोड़कर अन्य सभी पद फिलीपीन वासियों को दिये गये, परन्तु यह मंत्रिमंडल विधान सभा के स्थान पर गवर्नर जनरल (महाराज्यपाल) के प्रति उत्तरदायी था।

1907 में निर्वाचित फिलीपीन की विधान सभा को प्रारम्भ से ही गृह विधान के निर्माण, वित्त एवं भूमि नीतियों के नियमन तथा न्यायिक प्रशासन में अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई थी। 1907 में विधान सभा के उद्घाटन के समय ही विलियम टॉफ्ट ने फिलीपीन को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने का वचन दिया तथा उन्होंने सार्वजनिक मामलों को व्यवस्थित करने, न्याय एवं शान्ति की स्थापना करने गरीबों एवं, अमीरों की समान रूप से रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया। 1913 में राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल (महाराज्यपाल) की अधीनता में नियोजित फिलीपीन प्रतिनिधि मंडल उच्च सदन की भाँति कार्य करता रहा। इस प्रकार फिलीपीन की विधायिका के दोनों सदनों में फिलीपीनों का बहुमत था। 1901 और 1913 के मध्य विलियम टॉफ्ट द्वारा प्रतिपादित नीतियों ने यद्यपि फिलीपीनों को सन्तुष्ट नहीं किया, परन्तु वे अमरीकी सरकार के साथ सहयोग करने एवं व्यवस्थित प्रगति में संलग्न रहे।

अमरीकी शासन की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में ही यह स्पष्ट हो गया था कि अमरीकी सरकार को कृषकों का विश्वास प्राप्त करने हेतु याजक वर्ग के राजनीतिक प्रभाव को कम करना तथा भिक्षुओं के भूमि स्वामित्व को समाप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त फिलीपीन निवासी स्थानीय सरकार की विभिन्न गतिविधियों में याजक वर्ग के हस्तक्षेप के भी विरुद्ध थे। उपयुक्त गतिविधियों में जेलों एवं स्वास्थ्य सिद्धांतों का नियमन तथा पुलिस पर नियंत्रण

प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त वे भिक्षुओं के, म्युनिसिपल के सरकार आय एवं व्यय, करनीति, जनशिक्षा एवं राजा की भूमि के विभाजन एवं उपयोग पर नियंत्रण लगाने के विरुद्ध थे। फिलीपीन वासी स्थानीय तंत्र के पुनर्निमाण, भिक्षुओं के भूमि स्वामित्व की समाप्ति एवं जन प्रशिक्षण का धर्म निरपेक्ष नियंत्रण के अन्तर्गत प्रजातांत्रीय दिशा में निर्देशन की मांग कर रहे थे।

धार्मिक संस्थानों की शक्तियों को सीमित करने के सरकारी प्रयास में मुख्य पादरी पी. एल. चैपल ने कठिनाईयाँ उत्पन्न कर दी। पी. एल. चैपल को पोप के विशेष दूत के रूप में 1900 में मनीला भेजा गया था। उसने यह घोषणा की, कि अमरीकी सैनिक अधिकारियों को भिक्षुओं की पारम्परिक भूमि पर नियंत्रण हेतु सहायता करनी चाहिये तथा उनके वैध अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिये। उन्होंने चर्च एवं राज्य के पृथक्करण की नीति को चुनौती दी। चैपल ने राजा की भूमि पर याजक वर्ग के अधिकार के साथ-साथ स्कूलों, अनाथालयों एवं चर्चों पर भी याजक वर्ग के अधिकार की घोषणा की तथा उसने टॉफ्ट के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जिसमें भिक्षुओं की भूमि को सरकार द्वारा खरीदकर स्थानीय जनता में विभाजित करने का सुझाव दिया गया था। भिक्षुओं की भूमि पर नियंत्रण स्थापना के प्रयत्न के फलस्वरूप फिलीपीन में कृषकों का आन्दोलन तीव्र रूप से प्रारम्भ हुआ। 1902 के कूपर अधिनियम ने अमरीकी शिष्टमंडल को उक्त सम्बन्ध में शक्तियाँ प्रदान की जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भिक्षुओं की भूमि फिलीपीन सरकार की जन सम्पत्ति होगी एवं इसे सरकार द्वारा विक्रय अथवा किराये पर दिया जा सकेगा। चैपल के पश्चात् उनके इटलीवासी उत्तराधिकारी के साथ इस सम्बन्ध में समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भिक्षुओं की भूमि के एक बड़े भाग को क्रय कर लिया गया।

सरकार को इस भूमि का विक्रय करने में अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। एक व्यक्ति को 40 एकड़ एवं एक निगम को 2470 एकड़ भूमि खरीदने के अधिकार का प्राविधान रखा गया। 1916 में बची हुई भूमि को फिलीपीन की विधान सभा के नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया।

सामाजिक उत्थान के प्रयास

प्रथम फिलीपीनी शिष्टमंडल की नियुक्ति के समय ही अमरीकी सरकार ने यह घोषणा की थी कि अमरीका फिलीपीन में जनता की समृद्धि, शांति एवं परम्पराओं की रक्षा हेतु शासन करेगा। इस दिशा में सर्वप्रथम स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की दिशा में कार्य किये गये। 1898 में फिलीपीन के कुछ स्थानों

पर बच्चों की मृत्यु दर 80 प्रतिशत तक थी तथा मनीला में मृत्यु दर प्रति वर्ष 40 से 50 प्रति हजार थी। संक्रामक रोगों से मरने वालों की संख्या अत्याधिक थी। प्रारम्भ में इस दिशा में ग्रामीणों ने कठिनाईयाँ उत्पन्न की क्योंकि वे चेचक, हैजा, प्लेग के टीके को सन्देहात्मक नजरों से देखते थे। जल-वितरण व्यवस्था एवं मल निर्यास व्यवस्था की प्रगति पर एक बड़ी धनराशि व्यय की गई। 40 अस्पताल एवं कुछ हजार चिकित्सालयों की स्थापना की गई तथा एक दर्जन कोढ़ गृह भी स्थापित हुये। इस प्रकार प्रति वर्ष मरनेवालों की संख्या में अत्यधिक कमी हुई।

इस दृढ़ निश्चय के साथ अमरीकी प्रशासन ने निःशुल्क एवं धर्म निरपेक्ष शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर विकास किया। यद्यपि केन्द्रीय आय का एक तिहाई भाग शिक्षा के विकास पर आवंटित किया गया तथापि स्कूलों की सुविधायें फिलीपीनी जनता की माँग को पूर्ण करने में असमर्थ रहीं। प्रारम्भ में अमरीकी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता एवं अंग्रेजी भाषा में शिक्षण प्रदान करने में कठिनाई उत्पन्न हुई। स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत का पालन किया गया परन्तु फिलीपीन में अन्य देशों की आयातित वस्तुओं पर एक नवीन कर लगाया गया। इस प्रकार अमरीकी व्यापारियों को फिलीपीन में सुरक्षा प्रदान की गई। फलस्वरूप फिलीपीन के व्यापार पर वास्तविक रूप में अमरीकी एकाधिकार की स्थापना हुई जिसके कारण अमरीकीव्यापारिक प्रतिष्ठानों ने चीनी, तम्बाकू, सब्जी, तेल, काठ एवं सन (जूट) के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास किया। निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 1913 में अन्डरवुड-सिगन्स शुल्क अधिनियम पारित किया गया जिसने निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया। अंततः 1916 में जोन्स अधिनियम के द्वारा फिलीपीन की विधायिका को किसी भी देश के साथ सीमा शुल्क सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई परन्तु ऐसे सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किये जाने चाहिये।

अमरीकी शासन स्थापना के द्वितीय दशक के अन्त तक फिलीपीन के व्यापार पर अमरीकी अधिकार अत्यधिक बढ़ गया था। 1930 तक खानों का विकास तीव्रतम गति से हुआ। इस समय फिलीपीन के निर्यात का लगभग दोतिहाई भाग अमरीका का होता था तथा आयात का 85 प्रतिशत अमरीका से किया जाता था। उत्पादन वृद्धि ने फिलीपीन सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि की। फलस्वरूप सरकार ने सड़कों, के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा के विकास की दिशा में कार्य किया। परन्तु इस काल में कृषि सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया फलतः कृषकों की दशा में कोई प्रगति नहीं हुई। 1906-1907 में कृषि बैंकों की स्थापना की गई जिससे कृषकों को उदार व्याज

दर पर ऋण मिल सके परन्तु यह कार्यक्रम भी कुछ कारणों से असफल हो गया। किसानों की दशा खराब होने एवं चीनी महाजनों के अत्यधिक व्याज पर ऋण देने के कारण चावल का उत्पादन आवश्यकता की पूर्तिकरने में असफल रहा।

फिलीपीन में व्यापार एवं निर्माण कार्य में चीनी जनता को प्रमुखता प्राप्त थी। 1904 में चीनी 'चेम्बर आव कांमर्स' की स्थापना हुई। 1932 तक फिलीपीन के थोक व्यापार पर चीनी व्यापारियों का सम्पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया तथा तीन चौथाई फुटकर व्यापार चीनियों के हाथ आ गया। फिलीपीन की तीन चौथाई चावल मिलों पर चीनियों का अधिकार था। उन्होंने फिलीपीनों में शादी करके वहाँ की जमीन पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनका फिलीपीन के सम्पूर्ण राजस्व में तीन चौथाई का योगदान था।

फिलिपीनीकरण

1908 में टॉफ्ट ने फिलीपीन वासियों को स्व-शासन हेतु योग्य बनाने के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत किये। टॉफ्ट ने कहा कि उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु अमरीकी नियंत्रण के प्रशासन में स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना करनी चाहिये, स्थानीय जनता को सरकार एवं राजनीति में अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये तथा शिक्षा के क्षेत्र में निर्माणकारी कार्य करने चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रदेशीय पृथक्करण को समाप्त करने हेतु रेलवे, सड़कें, स्टीमर सेवा एवं म्युनिसिपल में अमरीकी शिक्षकों को फिलीपीन भेजा गया। 1915 तक अमरीकी शिक्षक प्राइमरी शिक्षकों के कुल योग का दसवाँ भाग थे एवं उच्च शिक्षा में यह अनुपात और अधिक था। 1930 तक शिक्षा के क्षेत्रीय नियंत्रक के पद पर अमरीकी शिक्षक ही कार्यरत थे। कोप आवंटन एवं प्रशिक्षणात्मक नियंत्रण केन्द्रिय प्रशासन के अधीन था। फिलीपीन में 1898 में साक्षरता 20 प्रतिशत थी जो 1940 में बढ़कर 40 प्रतिशत हो चुकी थी। स्पेनिश विश्व विद्यालयों के अतिरिक्त प्रोटेस्टेन्ट सिलिमान विश्वविद्यालय की ओरियन्टल नीग्रो प्रदेश में स्थापना हुई। इन सबमें प्रमुख मनीला का सरकारी विश्वविद्यालय था जिसमें दस से अधिक कालेज थे।

1919 में इस विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग भी सम्मिलित हो गये थे।

आर्थिक विकास की समस्या

फिलीपीन में अमरीकी शासन की स्थापना के पश्चात् प्रथम दशक में आर्थिक क्षेत्र में सीमित विकास हुआ क्योंकि स्पेन के साथ समझौते के अनुसार आगामी दस वर्षों तक अमरीका फिलीपीन में अमरीकी जहाजों के आवागमन अथवा अमरीकी वस्तुओं के विक्रय के सहायतार्थ कोई भी शुल्क नियम नहीं बना सकता था। उपर्युक्त समझौते की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् एक अर्ध व्यापारिक नीति का निर्माण हुआ। इस नीति के अन्तर्गत अमरीका एवं फिलीपीन के मध्य वस्तुओं के पारस्परिक आदान-प्रदान में सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अमरीकी सरकार आंग्ल भाषा को जनभाषा बनाने का प्रयत्न करेगी।

1902 के प्रायोगिक अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विधानसभाओं के चुनाव कराये गये। उपर्युक्त चुनावों में राष्ट्रवादी दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। विधान सभा का प्रथम अधिवेशन अक्टूबर 1907 में प्रारम्भ हुआ। 1907 में ही एक उच्च सदन की भी स्थापना की गई जिसमें 8 अमरीकी सदस्यों का बहुमत था। किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने से पूर्व दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त 1913 तक उच्च सदन के अमरीकी सदस्यों को फिलीपीन की विधान सभा के प्रस्तावों पर विशेषाधिकार प्राप्त था।

1912 तक अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में लोकतन्त्रिक दल की विजय के फलस्वरूप फिलीपीनीकरण की दिशा में एक नवीन काल का उदय हुआ। राष्ट्रपति विल्सन ने 'फ्रांसिस बर्टन हैरीसन' को फिलीपीन का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। हैरीसन ने फिलीपीन को स्वतंत्रता हेतु योग्य बनाने वाले कार्य तीव्रता से आरम्भ किये। उन्होंने फिलीपीनियों को सरकारी तंत्र में अधिकाधिक स्थान प्रदान किये। 1916 में जोन्स अधिनियम अमरीकी संसद द्वारा पारित कर दिया गया जिसमें यह घोषणा की गई कि फिलीपीन में स्थायी सरकार की स्थापना के साथ ही अमरीकी कांग्रेस उसे स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। यह भी घोषणा की गई कि स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु फिलीपीन जनता को, अमरीकी प्रभुसत्ता के अन्तर्गत, आन्तरिक मामलों में नियंत्रण प्रदान किया जाय। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का समिति पर नियंत्रण एवं विशेषाधिकार पुनः स्थापित किया गया। अपने सात वर्षीय कार्यकाल में उन्होंने फिलीपीन विधान सभा को 1916 के प्रशासनिक संहिता के निर्माण में सहायता प्रदान की। हैरीसन अधिनियम के मामलों में फिलीपीनी की विचारधारा का

समर्थक था। उनके प्रयत्नों से फिलीपीन सरकारी सेवा में 1913 में रत अमरीकी कर्मचारियों की संख्या 23 प्रतिशत से घटकर 1920 में केवल चार प्रतिशत ही रह गयी। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, मत्स्य एवं तकनीकी क्षेत्रों में अमरीकियों की संख्या सीमित हो गई थी। 'जोन्स अधिनियम' का महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उच्च सदन में अमरीकी बहुमत समाप्त करके 54 सदस्यीय उच्च सदन का गठन किया गया, जिसमें से 11 प्रदेशों द्वारा चुने हुये वाईस सदस्य थे तथा दो सदस्य नामांकित थे इस पर भी फिलीपीन की विधान सभा पर अमरीकी राष्ट्रपति एवं संसद का नियंत्रण था क्योंकि विधान सभा द्वारा पारित कोई विधेयक अमरीकी राष्ट्रपति की सहमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता था। अमरीकी संसद को फिलीपीन के किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि हैरीसन के कार्यकाल (1913-20) में उपर्युक्त अधिकारों का प्रयोग नहीं किया गया परन्तु उसके उत्तराधिकारियों ने इन अधिकारों का समय-समय पर प्रयोग किया।

इस प्रकार फिलीपीन विधान सभा विविध निर्मात्री संस्था से अधिक राजनैतिक संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस विधान सभा में 1907 से 1921 तक राष्ट्रवादी दल का बहुमत रहा। 1907 से 1921 तक इस दल का प्रमुख नेता सेरजियो ओसमेना था। 1922 में उच्च सदन का अध्यक्ष मेनुअल केजान राष्ट्रवादी दल का नेता हुआ।

1920 में अमरीकी राष्ट्रपति के चुनाव में रिपब्लिकन दल की विजय हुई तथा हार्डिंग अमरीका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। हार्डिंग प्रशासन ने जनरल लियोनार्ड वुड तथा फिलीपीन के भूतपूर्व गवर्नर जनरल केमरल फॉरव्स के दो सदस्यीय जाँच आयोग को फिलीपीन भेजा। इस आयोग ने अपने विवरण में फिलीपीन में कुप्रशासन, सरकारी अस्थिरता एवं राजनैतिक असन्तोष के अस्तित्व की सूचना राष्ट्रपति को दी। उपर्युक्त स्थिति को समाप्त करने हेतु लियोनार्ड वुड को फिलीपीन का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वुड का मत था कि फिलीपीन को स्वतंत्रता प्रदान करने के परिणामस्वरूप अमरीका की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव में ह्रास होगा। अतः नवीन गवर्नर जनरल फिलीपीन के राष्ट्रवादियों का सहयोग एवं सदभावना प्राप्त करने में असफल रहा।

गवर्नर जनरल वुड एवं फिलीपीन राष्ट्रवादियों के मध्य तनाव का मुख्य कारण यह था कि राष्ट्रवादी उसके निषेधाधिकार की व्यापकता को सीमित करना चाहते थे तथा वुड उसके विरुद्ध अपने अधिकार को समाप्त करने के पक्ष में नहीं था। भूतपूर्व गवर्नर जनरल हैरीसन द्वारा पाँच बार के निषेधाधिकार

की तुलना में वुड ने इस अधिकार का प्रयोग 126 बार किया। गवर्नर जनरल वुड एवं राष्ट्रवादियों के मध्य खुले युद्ध का अवसर 1923 में आया।

राजनैतिक उत्तरदायित्व को गवर्नर जनरल के स्थान पर विधान सभा में निहित करने के प्रयास में भूतपूर्व गवर्नर जनरल हैरीसन द्वारा संस्थापित परामर्शदाता समिति ने त्याग पत्र दे दिया। गवर्नर जनरल वुड ने त्यागपत्र स्वीकार कर सलाहकार (परामर्शदाता) समिति के अधिकारों को विभागीय उप-सचिवों में निहित कर दिया तथा सैनिक अधिकारियों की एक सलाहकार समिति का गठन किया। उपर्युक्त कृत्य में अमरीकी प्रशासन ने वुड का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त आर्थिक मामलों पर भी वुड एवं विधान सभा के मध्य तनाव में और वृद्धि हुई। विधान सभा ने 'मिन्डानों' एवं 'सुलू' के क्षेत्रों को अमरीकी रबर उत्पादन के लिये उपलब्ध करने के सुझावों का विरोध किया। गवर्नर जनरल ने हैरीसन द्वारा 'संस्थापित निगमों' पर अपने नियंत्रण कर की तथा हैरीसन द्वारा स्थापित 'नियंत्रण आयोग' को, जिनमें दोनों सदनों के अध्यक्ष सदस्य थे, समाप्त कर दिया। राष्ट्रवादियों ने गवर्नर जनरल के कृत्यों के विरुद्ध अमरीकी संसद से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। अमरीकी संसद में 1924 तक अनेक सुधार कार्यक्रमों पर विचार किया। परन्तु इसी वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव में कूलिज के विजयी होने के पश्चात उपर्युक्त सुधार कार्यक्रमों की शृंखला का अन्त हो गया। 1927 में जनरल वुड की मृत्यु हो गयी और इसके साथ ही फिलीपीन के इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ।

हेनरी एल. स्टिमसन को वुड का उत्तराधिकारी बनाया गया। स्टिमसन ने विधानसभा और गवर्नर जनरल के मध्य सहयोग स्थापित किया तक इस समय फिलीपीन के राष्ट्रवादी फिलीपीन के आन्तरिक मामलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने को दृढ़प्रतिज्ञ हो चुके थे। गवर्नर जनरल वुड द्वारा उत्पन्न राजनैतिक आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक नेताओं ने जनप्रिय क्रान्ति का पुनः आरम्भ किया सन 1924 के पश्चात कई स्थानों पर कृषकों ने प्रदर्शन किये। दक्षिणी विस्वास में बुकास ग्रान्दे ने एक क्रान्ति को जन्म दिया जो कि प्रभावशाली ढंग से दवा दी गयी परन्तु उक्त क्षेत्र में गुप्त संस्थायें क्रान्ति की दिशा में कार्य करती रहीं। द्वितीय विद्रोह फ्लोरेन्सियों के नेतृत्व में हुआ जिसने 1924 से 1927 तक फिलीपीन के सम्राट के रूप में कार्य किया। फ्लोरेन्सियो ने अपना मुख्यालय स्थापित किया तथा सदस्यों से 3 पेसोज (फिलीपीन की मुद्रा) का सदस्यता शुल्क ग्रहण किया। 1927 में फ्लोरेन्सियों को पकड़ लिया गया तथा पागल घोषित कर दिया गया परन्तु उसके अनुयायी सुधारों की मांग करते रहे।

गवर्नर जनरल स्टिमसन ने फिलीपीन विधानसभा के साथ सहयोग की नीति का पालन किया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात उक्त दल के सदस्यों में से किया। उन्होंने राज्य सभा का पुनर्गठन किया तथा इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके दोनों सदनों के सदस्यों की इसकी सदस्यता में सम्मिलित किया। तत्पश्चात स्टिमसन को अमरीका का विदेश सचिव नियुक्त किया गया और वह अमरीका वापस चला गया।

स्व शासन की ओर

1928 एवं 1929 में अमरीका में मंदी के लक्षण उत्पन्न हुये। फलस्वरूप अमरीकी सरकार ने फिलीपीन पर अपनी प्रभुसत्ता समाप्त करने का निर्णय लिया। फिलीपीन राष्ट्रवादी फिलीपीन की स्वतन्त्रता हेतु एक लम्बे समय से प्रयत्नशील भी थे। इसके अतिरिक्त अमरीकी उदारवादियों ने अमरीकी सरकार को 'जॉन्स अधिनियम' के अन्तर्गत दिये गये वचनों को पूर्ण करने हेतु सुझाव दिये। मंदी काल में अमरीकी सरकार ने फिलीपीन से चीनी, सब्जी, तेल एवं अन्य पदार्थों के आयात को प्रोत्साहन प्रदान किया जिसने उपर्युक्त वस्तुओं के अमरीकी उत्पादकों को अत्यधिक कष्टमय स्थिति में डाल दिया। फलस्वरूप अमरीकी उत्पादकों ने इस नीति के अन्त की मांग की। इस प्रकार लोकतन्त्रिक दल के परम्परावादी साम्राज्यवाद विरोधी सदस्यों को रूढ़िवादी क्षेत्रों से भी समर्थन प्राप्त हो गया। इसी मध्य अमरीका में विश्व शान्ति तथा स्थिरता की स्थापना से सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों में पृथक्तावादी विचारधारा का प्रसार हुआ। वे अमरीका द्वारा अन्य देशों को दिये गये आश्वासनों को समाप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त अमरीकी श्रमिकों ने फिलीपीनवासियों के अमरीका आकर बसने का विरोध किया जिसने अमरीका के फिलीपीन को स्वतन्त्रता प्रदान किये जाने का निर्णय करने में योगदान दिया।

फलतः अमरीका ने राजनैतिक स्वतन्त्रता के स्थान पर फिलीपीन की आर्थिक स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। इस नयी स्थिति ने फिलीपीन की आर्थिक दशा हेतु एक समस्या उत्पन्न कर दी। अनेक अमरीकी अधिकारी इस तथ्य से सहमत थे कि फिलीपीन के प्रशासन में व्यय फिलीपीन से प्राप्त लाभांश से कहीं कम है। 1929 के पश्चात तीव्रता से घटनायें हुई तथा 1932 में अमरीकी संसद ने 'हेयर-होस-कर्टिंग अधिनियम' पारित कर दिया। इस अधिनियम के विरोध में राष्ट्रपति हूवर ने निषेधाधिकार का प्रयोग, किया जिसे 1933 में अम-

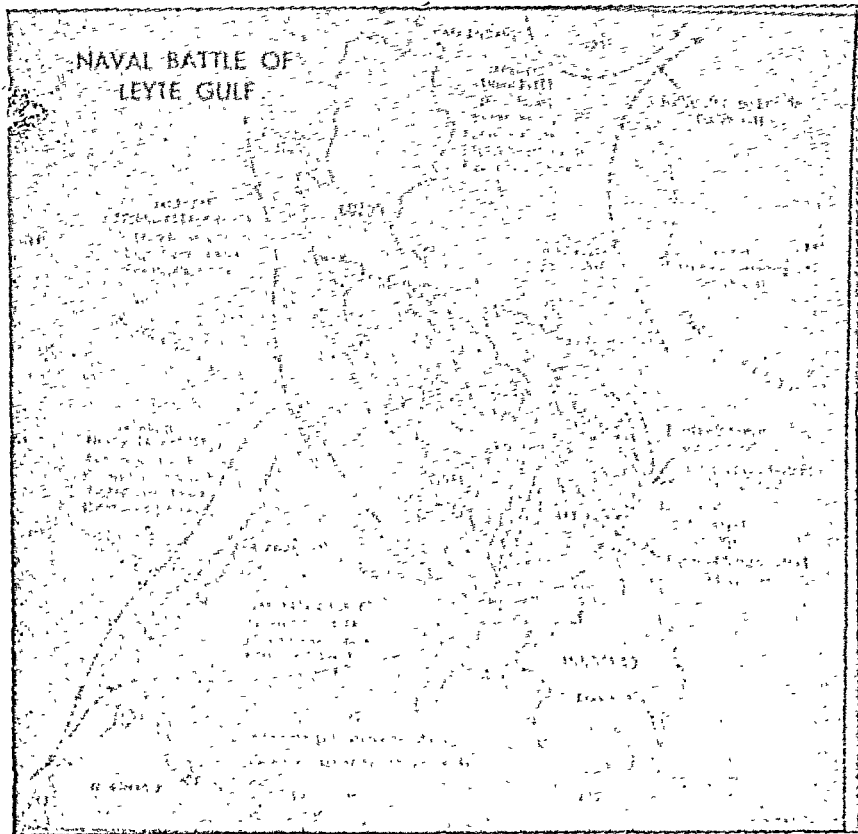
रीकी संसद ने उपेक्षित कर दिया। फिलीपीन को इस अधिनियम की सूचना दे दी गयी तथा इस अधिनियम का फिलीपीन विधानसभा द्वारा अनुमोदन करने का अनुरोध किया गया, परन्तु फिलीपीन में मैनुअल केजॉन एवं उसके अनुयायियों के प्रयास से इस अधिनियम को विधान सभा ने अक्टूबर, 1933 में अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि मैनुअल केजॉन अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों को फिलीपीन की स्वतन्त्रता का श्रेय नहीं देना चाहते थे। विरोधियों के मुख्य नेता ऑस्मेना रोहास एवं ओसिस थे। फिलीपीन विधान सभा ने इस अधिनियम को व्यापारिक प्राविधानों, अप्रवास पर प्रतिबन्ध एवं फिलीपीन में अमरीकी सैनिक एवं नौसैनिक अड्डों की स्थापना के विरोध में अस्वीकृत कर दिया।

उपर्युक्त प्राविधानों को समाप्त करने हेतु मैनुअल केजॉन एक शिष्टमंडल का अध्यक्ष बनकर अमरीका गये। नौ महीनों के प्रयास के पश्चात् अमरीकी सरकार सैनिक प्राविधानों को समाप्त करने पर सहमत हो गयी और 1934 में 'टाईडिंग्स मैकडफ अधिनियम' अमरीकी संसद ने पारित कर दिया जो पूर्व अधिनियम के लगभग समान ही था। फिलीपीन विधान सभा ने टाईडिंग्स मैकडफ अधिनियम का अनुमोदन मई, 1934 में कर दिया।

टाईडिंग्स मैकडफ अधिनियम ने आगामी दस वर्षों तक फिलीपीन की रक्षा व्यवस्था एवं विदेशी सम्बन्धों पर अमरीकी नियंत्रण स्थापित कर दिया। एक प्राविधान के अन्तर्गत अमरीकी राष्ट्रपति को मुद्रा, आयात एवं निर्यात से सम्बन्धित अधिनियमों अथवा संवैधानिक संशोधनों को स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया। अमरीकी सरकार को संवैधानिक सरकार की स्थापना हेतु फिलीपीन में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया गया। उपर्युक्त प्रतिबन्धों के उपरान्त भी फिलीपीन में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की स्थापना की गई। टाईडिंग्स मैकडफ अधिनियम के अनुमोदन के पश्चात् फिलीपीन में संविधान सभा हेतु चुनाव हुये। निर्वाचित सभा को संविधान निर्माण का उत्तरदायित्व दिया गया। संविधान के जनमत द्वारा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसे अनुमोदित कर दिया। इस प्रकार 15 नवम्बर, 1935 को फिलीपीन राष्ट्रकुल सरकार की स्थापना हुई। फिलीपीन के अन्तिम गर्वनर जनरल फ्रैंक मर्फी को प्रथम उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। केजॉन के शासन काल में कृषि, शिक्षा एवं सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई पर इस प्रगति की शृंखला को 1941 के जापानी आक्रमण ने ध्वस्त कर दिया।

जापानी आधिपत्य

जापानी अधिकार के विरुद्ध फिलीपीन वासियों की प्रतिक्रिया दक्षिण



23 से 25 अक्टूबर 1944 में लेटी खाड़ी (गल्फ) का अभियान द्वितीय विश्व-युद्ध के मध्य फिलीपीन क्षेत्र का महत्वपूर्ण नौसैनिक युद्ध था। इस युद्ध ने जापानी नौसेना को अत्याधिक क्षति ग्रस्त किया, और अमरीका का फिलीपीन के जल-क्षेत्र में पुनः नियन्त्रण स्थापित किया। दिसम्बर 15, 1944 को अमरीकी सेनाओं ने 'मिन्डोरो द्वीप' में अवतरण किया।

पूर्व एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा भिन्न थी। लगभग सम्पूर्ण स्थानीय जनता ने जापानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति अपनायी जो कि सम्पूर्ण आधिपत्य काल में प्रचलित थी परन्तु यह निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति थी। बटेविया के पतन के पश्चात् फिलीपीन राष्ट्रवादियों ने गुरिल्ला युद्ध प्रारम्भ किया। लूजॉन (लूसोन) में 'जापान विरोधी जन सेना' व 'हुक्स' का निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में था और जिन्हें स्थानीय जमींदारों एवं कृषकों का समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त मलय के चीनी साम्यवादी दल के सदस्यों ने भी 'हुक' विद्रोहियों को समर्थन दिया। हुक सेना का नेतृत्व 'लुइस तारुक' के हाथों में था जो एक यथार्थवादी, साम्यवादी था।

उपर्युक्त विद्रोहियों का दमन करने हेतु जापानी सैनिक अधिकारियों ने भीषण अत्याचार किये। इसमें किंचित मात्र सन्देह नहीं कि जापानी सैनिक प्रशासन ने सामाजिक ढांचे एवं राजनैतिक संगठन को अधिक हानि नहीं पहुँचायी, क्योंकि राजनैतिक समूह के एक बड़े भाग ने जापानी शासकों के साथ सहयोग की नीति अपनाई। इनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जोज लोरेल प्रमुख थे जिन्हें टोकियो विश्वविद्यालय की डिग्री से सम्मानित किया गया था। फिलीपीन के सरकारी अधिकारियों ने भी जापानी अधिकारियों के साथ सहयोग किया तथा 1943 में 'फिलीपीन गणतंत्र की जापानी नियंत्रण में स्थापना की गई जोज लोरेल को गणतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रपति की नियुक्ति की गयी। राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित अधिनियमों पर पूर्ण निषेधाधिकार प्रदान किया गया, तथा यह भी अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रीय सभा की स्वीकृति के बिना किसी भी विदेशी शक्ति के साथ समझौता कर सकता था। प्रत्येक क्षेत्र में ये पदाधिकारी जापानी अधिकारियों के निर्देशों को स्वीकार करने के लिये बाध्य थे।

1944 में राष्ट्रपति केजॉन की मृत्यु के पश्चात् अमरीका स्थित निष्कासित सरकार के राष्ट्रपति का पद ऑस्मेना ने ग्रहण किया। अक्टूबर, 1944 में अमरीका की फिलीपीन पर विजय के पश्चात् फिलीपीन में पुनः 'राष्ट्रकुल सरकार' (कॉमनवेल्थ) की स्थापना हुई जिसका राष्ट्रपति ऑस्मेना था।

स्वतन्त्रता

युद्ध के पश्चात् फिलीपीन की राष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। उच्च सदन का अध्यक्ष रोहॉस को इसका राजनैतिक नेता बनाया गया। 1946 के चुनाव में रोहॉस को राष्ट्रवादी दल के उदारवादी समूह ने राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया। दूसरी ओर राष्ट्रवादी दल

के राज्य भक्तों ने ऑसमेना को अपना उम्मीदवार बनाया। मार्च के चुनाव में रोहॉस राष्ट्रपति पद हेतु विजयी हुए, तथा संसद में उदारवादी राष्ट्रवादी दल को बहुमत प्राप्त हुआ। 4 जुलाई, 1948 में रोहॉस ने फिलीपीन गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सत्ता ग्रहण की।

रोहॉस प्रशासन का सर्वप्रथम प्रमुख ध्येय "वैल ट्रेड अधिनियम" का अनुमोदन था। इस अधिनियम के अन्तर्गत अमरीका को 8 वर्ष के लिये स्वतंत्र व्यापार की अनुमति एवं फिलीपीन में अमरीकी निवासियों को 1974 तक प्राकृतिक खनिजों के उपयोग हेतु समान अधिकार प्रदान किये जाने का प्राविधान था। उदारवादी दल में चीनी उत्पादको से सहानुभूति रखने वाला समूह उपर्युक्त अधिनियम के अनुमोदन का समर्थक था, क्योंकि अमरीका में स्वतंत्र चीनी व्यापार उनका ध्येय था। फिलीपीन की संसद ने इस अधिनियम को स्वीकृति दे दी, क्योंकि अमरीकी सरकार ने 'फिलीपीन पुनः स्थापन अधिनियम' के अन्तर्गत यह प्राविधान रखा था, कि जब फिलीपीन संसद द्वारा 'वैल ट्रेड विधेयक' को स्वीकृति प्रदान जायगी तब 500 डालर से अधिक की युद्ध क्षति पूर्ति का अमरीकी सरकार भुगतान करेगी। इस अधिनियम को पूर्णतया स्वीकृति प्राप्त होने में अन्तिम अवरोध फिलीपीन सरकार की 13वीं धारा थी जिसके अनुसार प्राकृतिक खनिज पदार्थों के उपयोग का अधिकार केवल फिलीपीन वासियों को ही था। इस संविधान संशोधन पर 1947 में जनमत संग्रह कराया गया जिसमें जनता ने बड़े बहुमत से संशोधन विधेयक के पक्ष में अपना मत दिया।

रोहॉस प्रशासन के समक्ष एक अन्य समस्या 'हुक' विद्रोहियों की थी। 1946 में इन विद्रोहियों के साथ एक समझौते का प्रयास किया गया परन्तु यह प्रयास असफल हो गया। फलतः फिलीपीन में 'हुक' विद्रोहियों एवं सरकारी सैनिकों के मध्य युद्ध प्रारम्भ हो गया तथा मार्च, 1948 में राष्ट्रपति रोहॉस ने 'हुक' संगठन को अवैध घोषित कर दिया। परन्तु अप्रैल में रोहॉस की हृदयगति बन्द हो जाने के कारण मृत्यु हो गयी। फलस्वरूप यह समस्या रोहॉस प्रशासन के रहते समाप्त न की जा सकी। 1950 में सरकार ने हुक विद्रोहियों के दमन के प्रयास में 18 अक्टूबर को 'हुक' मुख्यालय पर अधिकार कर लिया। 1953 में 'हुक' नेता लुइस तारुक ने आत्मसमर्पण कर दिया। हुक विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय रक्षा सचिव दामोन माँगसाइसाइ को था। तत्पश्चात् 'हुक' विद्रोहियों की गतिविधियाँ लगभग समाप्त हो गयी।

रोहॉस प्रशासन का एक अन्य मुख्य कार्य अमरीका के साथ एक सैनिक संधि पर हस्ताक्षर था। इस संधि पर 14 मार्च, 1947 को हस्ताक्षर किये गये

जिसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका को 99 वर्षों के लिये फिलीपीन में कुछ विशेष स्थानों पर सैनिक अड्डों की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई। इस संधि में यह प्राविधान भी था कि सैनिक आवश्यकता के समय अमरीका फिलीपीन के कुछ अन्य सैनिक अड्डों का भी प्रयोग कर सकता था।

‘वैल्ल व्यापार अधिनियम’ का 1954 में पुनः निरीक्षण किया गया जब तत्कालीन राष्ट्रपति ‘एल्पीडोक्यूरीनो’ ने अमरीकी राष्ट्रपति से उपर्युक्त अधिनियम का पुनः निरीक्षण करने का अनुरोध किया। इस अधिनियम पर 15 दिसम्बर, 1954 को पुनः हस्ताक्षर किये गये। इस अधिनियम के अन्तर्गत अमरीकी सरकार ने फिलीपीन मुद्रा पर अपने नियंत्रण को समाप्त करके उसपर स्थानीय सरकार के नियंत्रण की स्थापना की। इसके अतिरिक्त अमरीकी तथा फिलीपीन की जनता को अमरीका तथा फिलीपीन में व्यापार के समान अधिकार प्रदान किये गये, तथा फिलीपीन के निर्यात कर पर प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया। उपर्युक्त प्राविधानों द्वारा फिलीपीनियों को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई।

1951 में फिलीपीन के राष्ट्रपति एल्पीडोक्यूरीनो ने अमरीका के साथ पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। उक्त समझौते पर कुछ समय बाद आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने भी हस्ताक्षर किये। इस संधि में यह घोषणा की गई कि संधि के सदस्य देशों पर किसी अन्य शक्ति द्वारा आक्रमण का सभी राष्ट्र मिलकर मुकाबला करेंगे। यह समझौता कुछ समय पश्चात् ‘दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन’ में परिणत हो गया।

1956 में अमरीकी विदेश मंत्री जॉन फास्टर डलेस ने घोषणा की कि फिलीपीन को एशियन आणविक केन्द्र की स्थापना हेतु चुना जा रहा है। यह निर्णय कोलम्बो कार्यक्रम की सलाहकार समिति ने सिंगापुर में 1952 में किया था। इस केन्द्र का मुख्य ध्येय ‘एशिया वासियों के कल्याण हेतु आणविक शक्ति के शांति-पूर्ण प्रयोग पर शोध’ घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त अमरीका ने फिलीपीन में आणविक शक्ति के विकास हेतु एक समझौते का प्रस्ताव रखा।

30 दिसम्बर 1953 में रॉमोन मॉंगसाइसाइ को फिलीपीन का राष्ट्रपति चुना गया। उनके कार्य काल में जुलाई, 1956 को फिलीपीनके गणतंत्र की घोषणा के 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अमरीका एवं फिलीपीन के मध्य नवीन सम्बन्धों को लेकर राष्ट्रपति एवं सीनेट के सदस्य कालों एम. रेक्टो के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। फिलीपीन में अमरीकी सैनिक अड्डों के प्रश्न पर विवाद प्रारम्भ हुआ। अमरीका के एर्टानी जनरल हर्वर्ट ब्राडवेल ने घोषणा की, कि फिलीपीन पर अमरीकी प्रभुसत्ता की समाप्ति

के उपरान्त भी अमरीका का फिलीपीन के सैनिक अड्डों पर अधिकार बना हुआ था। इसके विरुद्ध सीनेट सदस्य रेक्टो ने उपर्युक्त अधिकार का खंडन करते हुये कहा कि सैनिक अड्डों की भूमि फिलीपीन सरकार की है जिसको 1947 के समझौते के अन्तर्गत अमरीका को प्रयोग के लिये दिया गया था। फिलीपीन के राष्ट्रवादी उपर्युक्त घोषणा से क्षुब्ध हो गये। इसी मध्य कुछ अन्य घटनाओं ने स्थिति को गम्भीर कर दिया। इसी मध्य राष्ट्रपति मॉगसाइसाइ एवं उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा सैनिक अड्डों पर फिलीपीन सरकार की प्रभुसत्ता को मान्यता प्रदान की। इसके पश्चात् अमरीकी तम्बाकू के फिलीपीन में आयात के प्रश्न पर मतभेद हो गये, जो अन्त में फिलीपीन सरकार द्वारा तम्बाकू के आयात को स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् समाप्त हो गये।

मार्च, 1957 में राष्ट्रपति मॉगसाइसाइ की मृत्यु पश्चात् कार्लोस पी. गार्सिया फिलीपीन के राष्ट्रपति चुने गये। गार्सिया के प्रशासन की मुख्य विशेषता आर्थिक एवं राजनैतिक राष्ट्रवाद की पुनः उत्पत्ति थी। इसका मुख्य ध्येय प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम में फिलीपीनों को उच्च स्थान प्रदान करना था। उक्त राष्ट्रवाद ने कार्लो एम. रेक्टो के लेखों से प्रेरणा प्राप्त की थी जिसमें रेक्टो ने क्यूरिनो प्रशासन के अमरीका के साथ सम्बन्धों की आलोचना की थी। मॉगसाइसाइ के प्रशासन काल में उपर्युक्त राष्ट्रवाद को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ क्योंकि प्रशासन पूर्णतया अमरीकी नीतियों के अनुसार ही था।

राष्ट्रपति गार्सिया की नीति को राष्ट्रवादियों ने पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। फिलीपीन के बुद्धिजीवी एवं व्यापारी वर्ग ने भी उपर्युक्त कार्यक्रम का समर्थन किया। अन्य प्रशासनों की भाँति ही गार्सिया प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं अन्य बुराईयों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और यही 1961 में गार्सिया की पराजय का एक मात्र कारण हुआ। 1961 के चुनाव में डिओसदादो मॉकापगाल राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। मॉकापगाल ने जन सामान्य के कल्याण एवं आर्थिक स्थायित्व की स्थापना हेतु एक पंचवर्षीय कार्यक्रम का निर्माण किया था। किसानों को शताब्दियों से प्रचलित दासता से मुक्त कर स्वतंत्र नागरिक बनाने हेतु एक भूमि सुधार संहिता को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके द्वारा कृषकों को जमीन पट्टे पर लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 'भूमि सुधार संहिता' ने कृषकों की दशा में अत्याधिक सुधार किया। मॉकापगाल ने फिलीपीन के स्वतंत्रता दिवस को 4 जुलाई के बदले 12 जून कर दिया जिस दिन आजीनाल्डो ने 1898 में फिलीपीन स्वतंत्रता की घोषणा की थी, परन्तु मॉकापगाल की लोकप्रियता उसके 4 वर्षीय कार्यकाल के अन्तिम दो वर्षों में अत्यधिक कम हो

गयी थी। इसके पाँच मुख्य कारण थे-प्रथम, वस्तुओं के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि रोकने में सरकार असफल रही, द्वितीय, लाभप्रद परिणामों हेतु माँका-पगाल की अधीरता की कार्य प्रणाली जिससे उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार उसके विरुद्ध निर्णय दिये, तृतीय देश में अशान्ति एवं अव्यवस्था में वृद्धि, चतुर्थ, भ्रष्टाचार एवं घूस में वृद्धि, एवं पंचम, उनकी सरकार तस्करी को रोकने में असमर्थ रही।

1965 में उच्च सदन के अध्यक्ष फर्डिनेन्ड मार्कोस को राष्ट्रवादी दल ने राष्ट्रपति के पद के लिये नामांकित किया और मार्कोस राष्ट्रपति चुन लिये गये। मार्कोस ने किसानों को प्रोत्साहन देकर एवं सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर फिलीपीन के चावल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की। फिलीपीन विश्वविद्यालय में अमरीकी निर्देशित अन्तर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना की गयी जिसने चावल की नयी किस्में खोजकर फिलीपीन को चावल निर्यात करनेवाले देशों की सूची में सम्मिलित कर दिया। इसके अतिरिक्त मार्कोस ने फिलीपीन की सड़कों, पुलों एवं स्कूलों आदि के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया। यद्यपि मार्कोस ने 'वियतनाम सहायता विधेयक' का 1965 में अत्यधिक विरोध किया तथापि राष्ट्रपति हो जाने के पश्चात् उसने 'सैनिक, इंजीनियर वटालियन' को दक्षिण वियतनाम भेजने का निर्णय किया। फलस्वरूप देश के प्रत्येक भाग में मार्कोस के उपर्युक्त निर्णय की तीव्र आलोचना की गई। अपने पुर्ननिर्वाचन के पश्चात् मार्कोस ने 'इंजीनियरिंग वटालियन' को जन प्रतिरोध से विवश होकर वापस बुला लिया। 1969 में मार्कोस राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचित किये गये। पुर्ननिर्वाचन के लगभग 1 मास पश्चात् ही फिलीपीन के छात्रों ने मार्कोस प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन मार्कोस प्रशासन के प्रत्येक मनुष्य को न्याय प्रदान करने में असफलता, न्याय, एवं व्यवस्था की स्थापना में असमर्थता, फिलीपीन से अमरीकी सैनिक अड्डों के उन्मूलन के प्रति लापरवाही तथा साम्राज्यवाद, (फॉशिज्म) फासीवाद, सामन्तवाद का सरकार द्वारा समर्थन करने के विरोध में था। इन प्रदर्शनों में कई छात्र मारे गये अथवा गम्भीर रूप से घायल हुये। फलस्वरूप बड़ी मात्रा में कृपकों, श्रमिकों एवं छात्रों ने प्रदर्शन किये तथा बुद्धिजीवियों ने मार्कोस की नीतियों की भर्त्सना की। जब मार्कोस ने कम्बोडिया को सैनिक सहायता देने की घोषणा की तो प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया। परिणामस्वरूप मार्कोस को अपना यह निर्णय वापस लेना पड़ा।

1969 के चुनाव में अत्यधिक व्यय के कारण फरवरी 1970 में मार्कोस को फिलीपीनी मुद्रा का अवमूल्यन करने हेतु बाध्य होना पड़ा। वेतन एवं

वस्तुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। 22 अगस्त, 1971 को विरोधी उदारवादी दल ने उच्च सदन के उम्मीदवार पर हथगोले का प्रयोग किया जब वे एक जनसभा में भाषण कर रहे थे। फलतः उनकी मृत्यु हो गयी। 22 अगस्त को राष्ट्रपति मार्कोस ने घोषणा की कि देश में साम्यवादी तत्व अराजकता फैलाना चाहते हैं। इसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर लोग बन्दी बनाये गये। इसके विरोध में प्रदर्शन हुये और राष्ट्रपति को जनता की इच्छा के सामने झुकना पड़ा और वन्दियों को रिहा करना पड़ा।

1971 में साम्यवादी गुरिल्लों ने, जो 'न्यू पीपुल्स आर्मी' के नाम से जाने जाते थे, सरकार के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप राजनैतिक स्थिति में बहुत अस्थिरता उत्पन्न हो गई। जून, 1971 में साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हुये और ईसाइयों के एक समूह ने मिन्दानो में कुछ मुसलमानों की हत्या कर दी। फलस्वरूप मुसलमानों एवं शान्ति स्थापना के प्रयासों में लगे हुये सरकारी सैनिकों के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया और 1972 तक यह आग देश के अन्य भागों में भी फैल गयी। इसी मध्य जुलाई, 1972 में बाढ़ के प्रकोप से हजारों आदमी मृत्युग्रस्त हुये एवं लाखों आवासहीन हो गये। खाद्य पदार्थों की कमी हो जाने के कारण साम्यवादी गुरिल्लों ने अपनी कार्यवाहियाँ तेज कर दी। फिलीपीन के रक्षा मंत्री की हत्या के प्रयास के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति मार्कोस ने 21 सितम्बर, 1972 को सैनिक शासन की घोषणा कर दी। इसके कारणों की व्याख्या करते हुये मार्कोस ने कहा कि सैनिक शासन का ध्येय सरकार उलटने का प्रयास करनेवाले तत्वों का दमन करना एवं देश में सुधारों का प्रारम्भ करना था।

इसके पश्चात सीनेटर रोहॉस एवं अन्य राजनीतिज्ञों को बन्दी बना लिया गया। जनसूचना सचिव फ्रान्सिसकों ने घोषणा की, कि सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार तथा कार्यों में सुधार किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मार्कोस ने घोषणा की, कि सैनिक एवं पुलिस ही आग्नेय अस्त्रों को धारण करने के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी समाचारपत्र, दूरदर्शन एवं प्रसारण केन्द्रों को बन्द कर दिया गया तथा मध्य रात्रि से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गयी मुख्य दूरभाष, विजली, जल, जहाजरानी एवं हवाई कम्पनियों पर सरकार का अधिकार स्थापित कर दिया गया। सितम्बर, 1972 में सभी शिक्षा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया। राष्ट्रपति ने विशेष सैनिक न्यायालयों की स्थापना की जिसमें सैनिक शासन की घोषणा के विरुद्ध कार्य करने वाले

अभियुक्तों की सुनवाई की गई। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को त्याग-पत्र देने हेतु बाध्य किया गया अथवा उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया।

अक्टूबर, 1972 में 6 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गयी जिसमें राष्ट्रीय आर्थिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, कस्टम एवं सीमा शुल्क की दरों का पुनः निर्धारण, कर व्यवस्था में सुधार, आवश्यक वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में कमी तथा भोग-विलास की सामग्रियों के आयात पर रोक इत्यादि सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार कार्यक्रम, प्रेस, सलाहकार समिति का गठन तथा फिलीपीनवासियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबन्धों की घोषणा भी की गई। इस प्रकार मार्कोस ने देश को शान्ति व्यवस्था एवं स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया।



अमरीका के राष्ट्रपति— एक परिचय

अध्याय 17

अमरीका के राष्ट्रपति—एक परिचय

1. जार्ज वाशिंगटन

जार्ज वाशिंगटन का जन्म 1732 में व्रिजेज क्रीक (वेस्ट मोर लैण्ड) में हुआ था। वह अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् (1743) वह अधिकतर माउन्ट वरनान में रहे और सर्वेक्षक का कार्य करते रहे। राज्यपाल रॉबर्ट डिनविडी ने उन्हें ओहायो घाटी के क्षेत्र पर फ्रांसीसी प्रयासों को चेतावनी देने के लिए भेजा, और 1755-59 के मध्य वाशिंगटन फ्रांसीसी और स्थानीय युद्धों में लैफ्टिनेन्ट कर्नल रहे। 1754 में उन्हें फोर्ट नैसेस्टी में आत्म-समर्पण करना पड़ा तथा 1755 में हुये ब्रैडॉक पराजय विनियोजन में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। फोर्ट ड्यूकेन पर अधिकार प्राप्त करने में उन्होंने भाग लिया। 1759 में उन्होंने मार्या डेन्डरज से विवाह किया और उसी वर्ष वर्जीनिया के सदन में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आन्दोलन को नेतृत्व प्रदान करते हुये वह प्रथम और द्वितीय महाद्वीपीय (कॉन्टीनेन्टल) कांग्रेसों में प्रतिनिधि रहे। 1776 में ट्रैन्टन और 1777 में प्रिंसटन में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की और देश प्रेम की भावना को विकसित किया। 1776 में ब्रेन्डीवाइन और जर्मन्टाउन की पराजय के पश्चात् उन्होंने फिलाडेल्फिया को अपने आधीन किया। उनकी सबसे महान उपलब्धि हडसन से चैसापीक खाड़ी तक का गुप्त और तीव्र अभियान था, जिसके परिणाम स्वरूप 1781 में यार्कटाउन में कार्नवालिस को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तत्पश्चात् 4 दिसम्बर, 1783 को वह अवकाश लेकर माउन्ट वरनान चले गये। उन्होंने 1786 में ऐनापोलिस सम्मेलन की अध्यक्षता के द्वारा पुनः लोक जीवन में प्रवेश किया। इस सम्मेलन में संविधान को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् वाशिंगटन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गये और दो सत्रों तक राष्ट्रपति रहे। इसी मध्य राष्ट्रपति ने हैमिल्टन की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया तथा 1795 में

“जे की सन्धि” को अनुमोदित किया।

वाशिंगटन ने अपने तीसरे निर्वाचन में पुनः राष्ट्रपति होना अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपने विदाई सन्देश में (19 सितम्बर, 1796) लोगों को असाधारण परिस्थितियों में भी नियमित कार्यों में विश्वास प्रतिपादित करने के लिये परामर्श दिया। 1798 में जब फ्रांस से युद्ध की आशंका होने लगी तो वाशिंगटन से उनके अवकाश प्राप्त जीवन से पुनः सेनापति पद पर आ जाने का अनुरोध किया गया परन्तु युद्ध स्थित के निवारण हो जाने के कारण वह अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते रहे। उनकी मृत्यु 1799 में माउन्ट वरनान में हुई।

2. जॉन एडम्स

जॉन एडम्स का जन्म 19 अक्टूबर, 1735 में ब्रेन्ट्री (अब क्वीन्सी) में हुआ। वह अमरीका के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1755 में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा उत्तीर्ण की और 1758 में मैसाचूसेट्स में वकालत प्रारम्भ की। 1763 में उन्होंने बॉस्टन (बोस्टन) गैजिट में “स्टैम्प अधिनियम” के विरुद्ध कई लेख प्रकाशित किये इसके अतिरिक्त 1770 में “बोस्टन हत्याकाण्ड” में उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की ओर से प्रतिवाद किया। 1770 से 1771 तक जनरल कोर्ट में, 1774 से 1775 तक ‘क्रान्तिकारी प्रान्तीय कांग्रेस’ में कार्य किया। 1774-78 में उन्होंने ब्रिटिश शासन को भेजी जाने वाली याचिका के पाण्डुलेखन में सहायता दी तथा वाशिंगटन को सेनानायक बनाने का समर्थन किया। 1784 में वह ‘युद्ध एवं आयुध विभाग’ के अध्यक्ष रहे और 1780 में ‘मैसाचूसेट्स संविधान’ के सम्मेलन के सदस्य थे। वह इस संविधान के मुख्य रचियता थे। 1783 में फ्रैंकलिन और जे. के साथ ग्रेट ब्रिटेन में हुई ‘पेरिस शान्ति सम्मेलन’ में भी उन्होंने भाग लिया। 1785 से 1788 तक एडम्स ब्रिटेन में अमरीका के दूत मंत्री रहे। 1789-1797 में वह अमरीका के प्रथम उप-राष्ट्रपति बने और 1797 से 1801 में वाशिंगटन के पश्चात् द्वितीय राष्ट्रपति बने। अपने राष्ट्रपति काल में हैमिल्टन की नीतियों के विरोध के कारण तथा “विदेशी राजद्रोही अधिनियम” ने, जिसमें परोक्ष रूप से उनका उत्तरदायित्व नहीं था, उनकी लोकप्रियता में प्रयाप्त ह्रास किया। फलस्वरूप संघीय दल का पतन हुआ। अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् वह पुनः क्वीन्सी में निवास करने लगे। वहाँ 4 जुलाई, 1826 में उनका देहान्त हो गया।

3. टॉमस जैफरसन

टॉमस जैफरसन का जन्म 13 अप्रैल, 1743 को शेडवेल में हुआ। वह



टॉमस जॅफरसन

अमरीका के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने विधि स्नातक होने के पश्चात् 1770 तक कालत की। 1774 में उन्होंने “ए समरी व्यू ऑफ दी राइट्स ऑफ अमेरिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 1775-76 में महाद्वीपीय कांग्रेस के सदस्य होकर स्वतंत्रता घोषणा की संरचना का पाण्डुलेखन किया। तत्पश्चात् वर्जीनिया विधान मंडल में उन्होंने प्रजातांत्रिक सरकार, धर्म निरपेक्षता तथा सार्वजनिक शिक्षा पद्धति की स्थापना की मांग की। उन्होंने दासों के व्यापार के उन्मूलन का भी समर्थन किया। 1779-1781 में वह वर्जीनिया के राज्यपाल रहे। 1783-84 में पुनः कांग्रेस में प्रवेश कर उन्होंने “दशमलव मुद्रा प्रणाली” तथा ‘भूमि अध्यादेश प्रणाली’ की योजना बनायी। 1785-1789 में वह फ्रांस में अमरीका के दूत मंत्री रहे और अपने इस काल में ‘नोट्स ऑन वर्जीनिया’ (पेरिस 1785) नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसी मध्य फ्रांसीसी क्रांति का प्रारम्भ हुआ और वे इस क्रांतिके प्रारम्भिक काल के स्रष्टा भी रहे 1793 तक वाशिंगटन के प्रथम राज्य सचिव रहे तथा इसी वर्ष हैमिल्टन की आर्थिक एवं केन्द्रीयकरण की नीतियों के विरुद्ध होने के कारण त्यागपत्र दे दिया। 1797-1801 तक वह जॉन एडम्स के उप-राष्ट्रपति रहे। 1798 में उन्होंने “विदेशी एवं देशद्रोही” अधिनियमों का विरोध किया और मेडिसन की सहायता से वर्जीनिया एवं कैंटेकी के प्रस्तावों की संरचना की। इस प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के विधि निर्माण को रद्द करने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हो गया।

1801-1809 में जैफरसन अमरीका के राष्ट्रपति रहे और उनका प्रशासन अपनी सरलता, निष्कपटता एवं आर्थिक नीति के कारण महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ ही साथ उन्होंने वारवेरी के समुद्री लुटेरों के विरुद्ध सफल युद्ध किया (1801-5), 1803 में ‘लुईसियाना (लुईजियाना) क्रय किया तथा ‘लुईस क्लार्क’ एवं ‘पाइक अभियानों’ को प्रेरित किया। 1807 में “पोत अधिरोध अधिनियम” पारित किया तथा 1809 में अमरीका के तटस्थता अधिकारों की सुरक्षा का असफल प्रयास किया। अवकाश प्राप्त के पश्चात् उन्होंने वर्जीनिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, और अमरीकी शास्त्रीय वास्तुकला के पुनरुत्थान में योगदान दिया। जैफरसन एक दार्शनिक राजनेता तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्व के स्वामी होने के कारण कृषकों के स्वायत्त समाज तथा शासकीय शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। इस महान् अमरीकी राष्ट्रपति का निधन मौन्टी-सिलों में 4 जुलाई, 1826 में हुआ।

4. जेम्स मैडिसन

जेम्स मैडिसन का जन्म 16 मार्च, 1751 में पोर्ट कौनवे (वर्जीनिया)

में हुआ। वह अमरीका के चौथे राष्ट्रपति थे। 1771 में न्यूजर्सी से वे स्नातक हुए। 1775 में वह औरंज कम्पनी, वर्जीनिया के नागरिक सुरक्षा के अध्यक्ष हुये और उन्होंने प्रान्तीय संविधान की रचना में योगदान दिया। 1780-83 तक उन्होंने महाद्वीपीय काँग्रेस में कार्य किया। 1784-86 तक वर्जीनिया में प्रतिनिधि सदन के सदस्य रहे। 1784 में उन्होंने "मेमोरियल एवं रेमान्सट्रेन्स" लिखा जिसमें उन्होंने धार्मिक अध्यापकों का पक्ष लेते हुये कर लगाने का विरोध किया तथा धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए "जैफरसन बिल" लागू किया। उन्होंने संविधान की रचना में प्रभावशाली भूमिका निभायी। मैडिसन 1789-97 में वर्जीनिया काँग्रेस सदस्यों के अभिपुष्टीकरण के लिये उत्तरदायी थे तथा उन्होंने संविधान में प्रथम दस संशोधनों का प्रस्ताव रखा जिसे अधिकारों का प्रस्ताव भी कहते हैं। हैमिल्टन के 'ऋण ग्रहण' और तत्पश्चात उनकी ब्रिटिश समर्थनता का विरोध करते हुए हैमिल्टन से उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया और वे जैफरसन गणतन्त्रवादियों के नेता बने। 1794 में उन्होंने 'डौली पेन टॉड' से विवाह किया। विदेशी एवं देशद्रोही अधिनियम की निन्दा करते हुए उन्होंने वर्जीनिया निर्णय की संरचना की। 1801-1809 में वह जैफरसन के राज्य सचिव रहे और फ्रान्स और ग्रेट ब्रिटेन के तटस्थ अधिकारों के वाद-विवाद में भाग लिया तथा 1809-17 तक वह अमरीका के राष्ट्रपति रहे। 1812 का युद्ध जिसमें (मिस्टर मैडिसन्स वॉर) अमरीका पूर्ण रूप से तैयार नहीं था और असंगठित भी था, इस महत्वपूर्ण युद्ध में अनुभव के अभाव तथा कुशल नेतृत्व की कमी से मैडिसन ने अपनी लोकप्रियता को प्रायः समाप्त कर लिया। उन्होंने अमरीका के द्वितीय वैक राष्ट्रीयकरण, द्वितीय प्रशासनिक प्रस्ताव को पारित कर एवं तटकरों में वृद्धि कर हैमिल्टन के राष्ट्रीयकरण की नीतियों का पुष्टिकरण प्रारम्भ कर दिया। 28 जून, 1836 में मॉन्टपीलियर में उनका देहान्त हो गया।

5. जेम्स मनरो

जेम्स मनरो का जन्म 28 अप्रैल, 1758 को वेस्टमोरलैंड वर्जीनिया में हुआ। वह अमरीका के पाँचवें राष्ट्रपति थे। वे 1774-76 के मध्य महाद्वीपीय सेना में सेवारत रहे। 1780-83 में उन्होंने जैफरसन के निर्देशन में कानून का अध्ययन किया, और 1782 में वर्जीनिया सदन के प्रतिनिधि बने तथा 1783-86 में "महाद्वीपीय काँग्रेस" में रहे। 1788 की वर्जीनिया सम्मेलन में उन्होंने संघीय संविधान का विरोध किया। 1790-94 में सीनेट सदस्य के रूप में



जॉन विन्सी एडम्स



जेम्स मनरो(1758-1831)

उन्होंने जैफरसन एवं गणतन्त्रियों के सम्बन्धों को सुदृढ़ किया। 1794-96 में आप फ्रांस में 'दूत मंत्री' रहे तत्पश्चात् आपको समझौते के कारण उत्पन्न विरोधी भावना के निराकरण के लिए बुलाया गया। 1799-1802 में वह वर्जीनिया के राज्यपाल रहे। 1802-03 में विशेषदूत के रूप में वह फ्रांस लौटे और वहाँ फ्रांस से न्यू ओरलीन्स (ऑरलियेन्स) और स्पेन से पश्चिम फ्लोरिडा क्रय करने हेतु उन्होंने आर० आर० लिविंगस्टन से सम्पर्क स्थापित किया। निर्देशों की सीमा से आगे बढ़कर उन्होंने सम्पूर्ण लुईसियाना का क्रय किया। इसके पश्चात् 1803-06 में वह ग्रेट ब्रिटेन के 'दूत मंत्री' रहे। 1811 में वह फिर वर्जीनिया के राज्यपाल नियुक्त हुये, तत्पश्चात् वह 1811-17 में मैडिसन के राज्य सचिव रहे और कुछ समय (1814-15) तक आप युद्ध सचिव भी रहे। 1816 के चुनाव में वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुये और 1820 में पुनः द्वितीय बार निर्वाचित हुये। संघवादियों तथा गणतंत्रवादियों के मध्य चौथाई शताब्दी तक प्रतिशोध की भावना के पश्चात् मनरो के प्रशासन को 'अच्छी भावना के युग' के प्रतीक की संज्ञा दी गई। कॅनेडा के साथ सीमा समझौता करके उन्होंने सीमान्त दुर्गों को विस्थापित किया तथा 1819 में फ्लोरिडा को अर्जित कर एडम्स के नवीनीकरण के सुझाव के साथ अपने 2 दिसम्बर, 1823 में मनरो के सिद्धांत निर्मित किया, जिसपर उन्होंने एक पक्षीय निर्णय लिया। 4 जुलाई, 1831 को न्यूयार्क शहर में उनका देहान्त हो गया।

6. जॉन क्विन्सी एडम्स

जॉन क्विन्सी एडम्स का जन्म 11 जुलाई, 1767 को ब्रेनट्री (अब क्विन्सी) मैसाचुसेट्स में हुआ। वह अमरीका के छठे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1778-79 में फ्रांस और 1780 में हॉलैण्ड में शिक्षा ग्रहण की, और 1781 में रूस में फ्रॉन्सिस डेना के सचिव तथा 1882-83 में ग्रेट ब्रिटेन में अपने पिता के सचिव के रूप में कार्य किया। अमरीका वापस आकर 1787 में उन्होंने हार्वर्ड से स्नातक किया। 1790 में विभिन्न वर्गों में प्रवेश कर उन्होंने बोस्टन में वकालत आरम्भ की। 1794-96 के मध्य नीदरलैण्ड में वॉशिंग्टन के दूत मंत्री रहे और 1797-1801 में अपने पिता के साथ प्रशासन में रहे। 1802 की कांग्रेस में पराजित हुये परन्तु आगामी वर्ष सीनेट में निर्वाचित कर लिये गये। 1807 के अधिरोध को प्रशासनिक समर्थन देने के परिणाम में उन्हें 1808 में त्यागपत्र देना पड़ा। कुछ समय तक वह हार्वर्ड में साहित्य शास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1809-14 तक आप रूस में दूत मंत्री रहे। 1814 में 'गेन्ट समझौते' की शांति

आयोग के अध्यक्ष रहे थे और 1815-17 में ग्रेट ब्रिटेन में दूत मंत्री रहे। 1817-25 में मनरो के राज्य सचिव बनाये गये और फ्लोरिडा का सम्बन्ध विच्छेद कराया, तथा 1829 में मनरो के साथ "मनरो सिद्धान्त" का सूत्रपात किया। 1824 में राष्ट्रपति के निर्वाचकीय मतों में जैक्सन के बाद द्वितीय स्थान प्राप्त किया, परन्तु प्रतिनिधिक सदन में हेनरी क्ले के समर्थन के द्वारा वह राष्ट्रपति चुन लिये गये। अपने प्रशासन में एडम्स ने आन्तरिक सुधारों के प्रति व्यापक राष्ट्रीय योजना कार्य किये। 1828 में जैक्सन से राष्ट्रपति के चुनाव में पराजित हुये। 1831-48 तक वह कांग्रेस के सदन के सदस्य रहे। आप ने इस काल में टेक्सास के संयोजन का विरोध किया, तथा दासता के विस्तार का अवरोध किया। अपने अन्तिम वर्षों में एडम्स दासता विरोधी प्रस्तावों का समर्थन करते रहे और 23 फरवरी, 1848 को वाशिंगटन में उनका देहान्त हो गया।

7. एण्ड्रू जैक्सन

एण्ड्रू जैक्सन का जन्म 15 मार्च, 1767 को वाक्सहो में हुआ। वह अमरीका के सातवें राष्ट्रपति थे। 1781 में अमरीकी क्रान्ति में (दक्षिण कैरोलिना) में किन्चित्त कार्य करने के पश्चात वह ब्रिटिश बन्दी बना लिये गये। सोल्सवरी में विधि शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात वह मार्टनविले में वकालत करने लगे। 1788 में उत्तरी कोलम्बिया के पश्चिमी नगर के लिये उनकी अभियोगी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हुई। 1796 में वह राज्य संवैधानिक सभा के सदस्य चुने गये। दिसम्बर, 1796 से मार्च 1797 तक वह टेनेसी से प्रथम कांग्रेस सदस्य रहे। संयुक्त राज्य के सीनेट (1797) के रूप में त्यागपत्र देकर आप 1798-1804 टेनेसी के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुये। वह एक निपुण दृन्द योद्धा थे और दृन्द युद्ध में उन्होंने चार्ल्स डिकिन्सन का वध किया। राष्ट्रपति जैफरसन तथा टेनेसी के राज्यपाल जॉन सेवियर से व्यक्तिगत मतभेद के कारण उनका सार्वजनिक जीवन अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। सेनापति के रूप में उन्होंने 1813-14 में क्रीक्स को पराजित किया। मेजर जनरल के रूप में उन्होंने न्यू ऑरलियेन्स में जनवरी 18, 1815 को अंग्रेजों को पराजित किया। 1818 में उन्होंने 'सेमीनोल युद्ध' के मध्य फ्लोरिडा पर आक्रमण किया और पेन्साकोला को अपने अधिकार में कर लिया। 1821 में वह फ्लोरिडा के सैनिक राज्यपाल नियुक्त किये गये और 1823-25 में अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे। 1824 के राष्ट्रपति चुनाव में



एण्ड्रु जॅक्सन (1767-1845)
अमरीका के सातवें राष्ट्रपति

उनको भारी बहुमत प्राप्त हुआ परन्तु प्रतिनिधिक विधान मंडल में वह जॉन क्विन्सी एडेम्स से पराजित हो गये। चार वर्ष पश्चात् 1829 में वह राष्ट्रपति घोषित किये गये। 1829 तथा 1837 तक उनके प्रशासन काल में अनौपचारिक परामर्शदाता (किचेन कैबिनेट) की पद्धति का प्रचलन रहा। जैक्सन ने “इनामी पद्धति” की नींव रखी। 1831 में उन्होंने मंत्रिमंडल को परिवर्तित किया। 1832 में अमरीकी बैंक का प्रतिरोध किया; उन्होंने आदिवासी समस्या के प्रति भूमि वितरण का कार्य किया। उनके प्रशासन में राष्ट्रपति के अधिकारों को महत्व प्रदान किया गया। वॉन व्यूरेन को अपनी इच्छा से राष्ट्रपति निर्वाचित करने के पश्चात् उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया। जून 1845 में अपने घर “हर्मिटेज” (नैशविल) में उनका देहान्त हो गया।

8. मार्टिन वॉन व्यूरेन

मार्टिन वॉन व्यूरेन का जन्म किन्डरहुक (न्यूयार्क) में 5 दिसम्बर, 1782 में हुआ था। वह अमरीका के आठवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1803 से किन्डरहुक में वकालत प्रारम्भ की वह 1812 से 1820 तक राज्य सीनेट के सदस्य रहे। 1815 से 1819 तक वह राज्य के प्रमुख अधिवक्ता रहे। वह ‘अल्बेनी रीजेन्सी’ नामक राजनैतिक संगठन के प्रमुख रहे। वह 1821 से 1828 तक संयुक्त राज्य के सीनेट सदस्य रहे। उन्होंने 1829 में क्राफोर्ड तथा 1828 में जैक्सन को समर्थन प्रदान किया। जनवरी, 1829 में उनकी नियुक्ति न्यूयार्क के राज्यपाल के रूप में हुई, परन्तु मार्च में उन्होंने जैक्सन मंत्रालय में राज्य सचिव पद पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया। ब्रिटिश वेस्ट इण्डोइज में प्रत्यक्ष व्यापार हेतु ब्रिटेन से समर्थन प्राप्त करने के पश्चात् वह ब्रिटेन के लिये दूतमंत्री बने पर कैल्हून द्वारा सीनेट में प्रतिरोध के पश्चात् वह लंदन से वापस लौट आये। 1833-37 में वह जैक्सन के आधीन उप राष्ट्रपति रहे। 1836 में उन्होंने हैरिसन को जैक्सन के समर्थित प्रत्याशी के रूप में पराजित कर दिया। उनके स्वतंत्र कोप नीति ने लोकतंत्रवादियों के मत को प्रतिबिम्बित किया, परन्तु 1837 के संकट के कारण उनकी लोकप्रियता को आघात पहुँचा। 1840 में वह हैरिसन के द्वारा पराजित हो गये। टैंसास के संयोजन के विरोध के कारण उनका नामांकन 1844 में राष्ट्रपति पद के लिये न हो सका। 1848 में वह पुनः राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी थे, परन्तु वाद में उन्होंने लोकतांत्रिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली और ‘सम्बन्ध विच्छेद नीति’ का विरोध किया। 24 जुलाई, 1862 में उनका देहान्त हो गया।

9. विलियम हेनरी हैरिसन

विलियम हेनरी हैरिसन का जन्म 9 फरवरी, 1773 में बर्कले नामक स्थान पर हुआ था। वह अमरीका के नवें राष्ट्रपति थे। 1787 से 1790 तक उन्होंने हैम्पडन-सिडनी कालेज में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक उन्होंने पेन्सिलवानिया विश्व विद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। तत्पश्चात् सेना में प्रविष्ट होकर 1798 में उन्होंने कप्तान के पद से त्यागपत्र दे दिया और उत्तर-पश्चिम राज्य क्षेत्र के सचिव नियुक्त किये गये। 1799 में कांग्रेस के प्रथम सदस्य निर्वाचित किये गये। 1800 में 'भूमि अधिनियम' के पाण्डुलेखन का कार्य किया। 1801 से 1812 तक राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने उन्हें इण्डियाना राज्य क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया। अपने इस काल में उन्होंने कई सीमा संधियाँ कीं एवं संधिवार्ता का कार्य किया। 1812 के युद्ध में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त हुये। इस युद्ध के मध्य उन्होंने ब्रिटिश तथा आदिवासियों को अक्टूबर 5, 1813 की 'टैम्स युद्ध' में पराजित किया। 1816 और 1819 में वह ओहायो से कांग्रेस के सदस्य रहे। 1819 से 1821 में वह प्रान्तीय सीनेट के सदस्य रहे तथा 1825 से 1828 के मध्य वह ओहायो से अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे। 1828 में वह कोलम्बिया में अमरीकी मन्त्री नियुक्त किये गये परन्तु राष्ट्रपति जैक्सन ने उनको आगामी वर्षों में वापिस बुला लिया। 1836 में वॉन व्यूरेन से पराजित हुये परन्तु 1840 में 'विग दल' के मनोनीत सदस्य होकर वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुये और एक माह के पश्चात ही 4 अप्रैल, 1841 को वॉशिंग्टन में उनका देहान्त हो गया।

10. जॉन टाइलर

जॉन टाइलर का जन्म 29 मार्च, 1790 को ग्रीनवे (वर्जीनिया) में हुआ। वह अमरीका के दसवें राष्ट्रपति थे। 1807 में उन्होंने विलियम एण्ड मैरी से स्नातक होकर 1809 में वकालत प्रारम्भ की। 1811 से 1816 तक वह प्रान्तीय विधायक रहे। 1816-21 में जैफरसन के लोकतांत्रिक दल के द्वारा कांग्रेस के सदस्य रहे। 1825-27 में वह वर्जीनिया के राज्यपाल का कार्य देखते रहे और 1827-36 के मध्य अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे। उन्होंने राष्ट्रपति जैक्सन की बैंक की नीति के कारण अमरीकी सीनेट से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात वह 1838-40 तक प्रान्तीय विधायक रहे। 1840 में वह 'विग दल' के द्वारा मनोनीत होकर उप-राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित हुये। अप्रैल 4, 1841 को हैरिसन के देहान्त के पश्चात वह राष्ट्रपति घोषित किये



जैकरी टेलर (1784-1850)

गये। सितम्बर 12, 1841 को हैनरी क्ले के बैंक विधेयक के प्रति निषेधाधिकार के अधिकार के प्रयोग करने के कारण डेनियल वैब्सटर के अतिरिक्त उनके पूर्ण 'विग मन्त्रिमण्डल' ने त्यागपत्र दे दिया। वैब्सटर ने भी मई 1843 में 'वैब्सटर-एणवर्टन' संधि के पश्चात् मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। मई, 1844 में राष्ट्रपति ने विग एवं लोकतांत्रिक दल के साथ पुनः अपने मन्त्रिमण्डल का गठन किया। उनके प्रशासन की मुख्य उपलब्धियों में पूर्व क्रम अधिकार, अधिनियम तथा टैक्सस का संयोजन था। अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् वह वर्जीनिया में अपने गृह 'शेरवुड फारेस्ट' में रहने लगे। 1861 में कुछ समय के लिये वह वाशिंगटन में शान्ति सम्मेलन के अध्यक्ष रहे तथा संघाधीन कांग्रेस में निर्वाचित किये गये परन्तु कार्यपूर्ण होने के पूर्व 18 जनवरी, 1862 को 'रिचमॉण्ड' में उनका देहावसान हो गया।

11. जेम्स नॉक्स पोक

जेम्स नॉक्स पोक का जन्म मैकजेनबर्ग (उत्तरी केरोलीना) में 2 नवम्बर 1795 में हुआ। पोक अमरीका के ग्यारहवें राष्ट्रपति थे। 1818 में उत्तरी केरोलीना विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होकर उन्होंने 1820 में कोलम्बिया में वकालत आरम्भ कर दी थी। 1823-25 में वे टेनेसी विधान मंडल के सदस्य रहे। 1835-39 में वे कांग्रेस के सदस्य रहे। 1835-39 में उन्होंने सदन अध्यक्ष के पद पर कार्य किया और 1839-41 में वह टेनेसी के राज्यपाल रहे। 1844 में लोकतांत्रिक दल से वे राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित हुये। अपने राष्ट्रपति काल में उन्होंने अपने मुख्य ध्येयों की पूर्ति की। उन्होंने 1846 में ओरगॉन समस्या का समाधान किया, सीमा शुल्क में कमी की और स्वतन्त्र राज्य-कोष पद्धति को पुनर्स्थापित किया। वह साम्राज्यवादी न होकर विस्तारवादी नीति के परिपालक थे। 1846-48 में टेक्सास की सीमा को लेकर मैक्सिको युद्ध उनके शासन काल में हुआ। पोक ने पुनः राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग नहीं लिया। वे 15 जून, 1849 में नेशविल में स्वर्गवासी हुये।

12. जैकरी टेलर

जैकरी टेलर का जन्म 24 नवम्बर, 1784 में 'मॉन्टवेलो' (वर्जीनिया) में हुआ था। यह अमरीका के बारहवें राष्ट्रपति थे। बाल्यकाल में टेलर का परिवार वर्जीनिया से केन्टकी में जाकर बस गया था। जैकरी टेलर ने अपनी शिक्षा स्वयं की थी और शिक्षा उपरान्त 1806 में 'केन्टकी सेना' में स्वयंसेवक

हो गये थे । 1808 में उनका संयुक्त राष्ट्र सेना में लेफ्टीनेन्ट पद पर चयन हो गया और इसके पश्चात् इन्होंने चालीस वर्षों तक सेना में सेवा की । सेना की इस अवधि में जैकरी टेलर ने अनेक युद्धों में सैनिक कुशलता का परिचय दिया और 1832-33 में 'ब्लैकहॉक' एवं 1837 में 'सेमीनोल युद्ध' में सक्रिय भाग लिया था । 1845-46 में वह मैक्सिको सीमा पर सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय सेना ने शत्रु विद्वेष का प्रदर्शन किया, जिसके कारण 1846 में मैक्सिको युद्ध आरम्भ हो गया । पालो आल्टो व डि ला पाल्मा के युद्ध में विजित होने पर इन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया । तत्पश्चात् पोक के सुरक्षा युद्ध के आदेशों के विपरीत इन्होंने मैक्सिको में आक्रमणकारी युद्ध शुरू कर दिया और मोन्टे को भी जीत लिया । 23 फरवरी, 1847 में इन्हें 'ब्यूनाविस्ता' युद्ध में सान्ताएना को पराजित किया और फिर राष्ट्रीय नायक के रूप में माने जाने लगे । विग दल ने इन्हें 1848 में राष्ट्रपति पद के लिये मनोनीत किया और लोकतांत्रिक दल के लुईस कास को पराजित कर राष्ट्रपति बने और दक्षिण के तुष्टीकरण का विरोध करते रहे एवं 1850 के समझौते पर प्रत्याविरोध किया । 9 जुलाई, 1850 को वाशिंगटन में इनका आकस्मिक स्वर्गवास हो गया ।

13. मिलर्ड फिलमोर

मिलर्ड फिलमोर का जन्म 7 जनवरी, 1800 को लॉक (न्यूयार्क) में हुआ । यह अमरीका के तेरहवें राष्ट्रपति थे । इन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त कर 1823 तक वकालत की और वफेलो में निवास करने लगे । थर्लोवीड से प्रभावित तथा आरक्षित होने के कारण प्रान्तीय विधान मंडल में 1829-31 तक सदस्य रहे । तत्पश्चात् 1834 में उन्होंने विग दल की सदस्यता ग्रहण कर सदन का नेतृत्व किया । 1842 में उन्होंने सीमा शुल्क अधिनियम के पाण्डुलेखन का कार्य किया । 1844 में विग दल में सदस्य होकर भी वह न्यूयार्क के राज्यपाल के चुनाव में पराजित हो गये । 1848 में वे उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 9 जुलाई, 1850 में राष्ट्रपति टेलर के देहान्त के पश्चात् वे राष्ट्रपति बने । 1850 में उन्होंने 'क्ले समझौता' किया और 'पलायक दासता अधिनियम' को उत्तरी लोकप्रियता के कारण प्रवर्तित करने में चेष्टाग्रस्त रहे । जापान के साथ 'पेरी संधि' को अनुमोदित किया । 1852 में वे राष्ट्रपति का चुनाव हार गये और 8 मार्च, 1874 को उनका वफेलो में देहावसान हो गया ।

14. फ्रैंकलिन पीर्स

फ्रैंकलिन पीर्स का जन्म 'हिल्सबरो' (न्यू हैम्पशायर) में नवम्बर, 1804

में हुआ था। वह अमरीका के चौदहवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1824 में विधि की शिक्षा प्राप्त की और 1827 में न्यू हैम्पशायर में वकालत प्रारम्भ की। 1829-32 में प्रान्तीय विधान मंडल के सदस्य रहे और अपने सदस्यता के अन्तिम वर्ष में विधान मंडल के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। वे लोकतांत्रिक दल से 1833-37 में कांग्रेस के सदस्य और 1837-42 तक अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे। तत्पश्चात् त्यागपत्र देकर कांग्रेड में वकालत करने लगे। 'मैक्सिको युद्ध' में उन्होंने 'विन फील्ड स्कॉट' के आधीन ब्रिगेडियर के पद पर कार्य किया। 1852 में लोकतांत्रिक प्रत्याशी के रूप में वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। उनका प्रशासन दासता के प्रति प्रभावित था। उन्होंने 'गेड्सडेन क्रय' के द्वारा अमरीकी दक्षिण सीमा का विस्तार किया और इसी वर्ष 1853 में पेरी को जापान भेजा। 1854 में उन्होंने 'कॉन्सास-नैब्राँस्का अधिनियम' पर हस्ताक्षर किये और 'निके-रागवा' में 'वाकर शासन' को मान्यता दी। 1856 में उनकी 'कॉन्सास रक्त स्रवण' की नीति के कारण उनको उत्तरी लोकतांत्रिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हो सका, और इस कारण वह पुनः प्रत्याशी नहीं हो सके। 8 अक्टूबर 1869 में कांग्रेड में उनका देहांत हुआ।

15. जेम्स व्यूकॉनन

जेम्स व्यूकॉनन का जन्म 23 अप्रैल, 1791 में मरसर्जवर्ग (पेन्सिलवे-निया) में हुआ। वह अमरीका के पन्द्रहवें राष्ट्रपति थे। 1809 में डिकिन्सन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर 1812 में लकान्स्टर में वकालत आरम्भ की। 1815-16 में वह संघीय प्रान्तीय विधान मण्डल के सदस्य रहे तथा 1820-31 में कांग्रेस के सदस्य रहे। वह 1831-33 में रूस में अमरीका के दूत मन्त्री रहे, जहाँ उन्होंने व्यापारिक संधि वार्ताओं को प्रोत्साहित किया। लोकतंत्रीय दल से 1835-45 में वह अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे। राष्ट्रपति पोक के मन्त्रिमण्डल में 1845-49 में वह राज्य सचिव रहे। इस काल में उन्होंने ओरगॉन विवाद का समाधान किया तथा स्पेन से क्यूबा को क्रय करने का प्रस्ताव रखा। 1853-56 में वह ब्रिटेन में दूत मन्त्री रहे और 'आस्ट्रेण्ड घोषणा पत्र 1854 का' आलेखन किया। व्यूकॉनन 1857-61 में लोकतांत्रिक दल से राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। अपने प्रशासन काल में उन्होंने दासता को अनैतिक घोषित किया परन्तु कॉन्सास में 1858 को 'लिकाम्पटन संविधान' को स्वीकृत प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। प्रान्तीय सम्बन्ध विच्छेद को अनैतिक मान कर भी वह इस समस्या का वैधानिक समाधान करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार इन्होंने संविधान में

संशोधन की इच्छा प्रकट कर दासता और पलायक दासों की प्रति प्राप्ति को मान्यता प्रदान की। गृह युद्ध में उन्होंने संघीय सरकार को समर्थन दिया। 1 जून, 1868 में वीटलैण्ड (पेनसिलवेनिया) में इनका देहान्त हो गया।

16. अब्राहम लिंकन

अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी, 1809 को हार्डिन (केटन्की) में हुआ वह अमरीका के सोलहवें राष्ट्रपति थे। वह 1816 में अपने माता-पिता के साथ इंडियाना में आ गये और 1830 में दक्षिणी इलेनॉय (इनिनॉयस) में एक दुकान में काम करने लगे। 1832 में ब्लैक 'हॉक युद्ध' में वह स्वयं सेवकों के कप्तान हो गये परन्तु इस में सक्रिय भाग नहीं लिया। 1833-36 के मध्य उन्होंने दुकान का कार्य किया, पोस्टमास्टर रहे और विधि की शिक्षा प्राप्त करते रहे। 1837 में स्प्रींगफील्ड में आकर उन्होंने वकालत आरम्भ की और शीघ्र ही इस व्यवसाय में अपनी ख्याति अर्जित की। 1834-42 में वह विग दल के विधान मण्डलीय सदस्य रहे और 1846 में कांग्रेस के सदस्य हो गये। 1854 में उन्होंने 'कॉन्सास नेब्रास्का अधिनियम' का खण्डन किया और 1856 में स्टीफन ए. डगलस के विरुद्ध सीनेट के चुनाव में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वाद-विवाद में भाग लिया और अपने भाषण में कहा 'कि विभक्त सदन स्वयं में स्थायी नहीं हो सकता'। लिंकन ने डगलस के साथ सात वाद-विवाद अभियानों के पश्चात उन्होंने डगलस को 'फ्री पोर्ट सिद्धांत' की घोषणा करने पर वाध्य किया। चुनाव में पराजित होने के उपरान्त भी लिंकन राष्ट्रीय नेता बन गये। उन्होंने 1861 में अपने राष्ट्रपति उद्घाटन भाषण में संवैधानिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्यों के सम्बन्ध वाध्यकारी तथा अपरिवर्तनीय थे। उन्होंने अपने मन्त्री मण्डल की सलाह के विपरीत फार्ट सुम्पटर का प्रबन्ध किया तथा युद्ध के प्रारम्भ पर उन्होंने राज्य सेना की सहायता ली, एवं 'बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम' को निरस्त कर दिया। दक्षिणी बन्दरगाहों के अवरोधों की घोषणा कर दी। दूसरे शब्दों में उन्होंने अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग खुलकर किया। उन्होंने अगस्त 30, 1861 में दासों के निरस्त्रीकरण हेतु फ्रीमॉन्ट घोषणा को पूर्णतया स्थागित कर स्वयं अपनी योजना दी और कहा कि मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य दासता के पक्ष तथा विपक्ष में नहीं परन्तु संघ (यूनियन) सुरक्षित रखने में है। जनवरी 1, 1863 को उन्होंने विमुक्तकी उद्धार घोषणा की। अपनी राजनयिकता के कारण उन्होंने अपने मन्त्रीमंडल एवं सेनाध्यक्षों का भली भाँति संचालन किया इसके फलस्वरूप

1864 में पुनः निर्वाचित हुये। उनके पुर्ननिर्माण योजना का आधार दक्षिण के राज्यसंघ का पुर्नस्थापन करना था। जुलाई 8, 1864 में वेड डेविस' विधेयक का लघुनिषेधाधिकार किया। लिंकन ने फरवरी 3, 1865 को व्यक्तिगत रूप से 'हैम्टन रोड सम्मेलन' में भाग लेकर परिसंघ के नेताओं से शांतिवार्ता की। राष्ट्रपति लिंकन के उल्लेखनीय भाषणों में नवम्बर 19, 1863 का गेटिसबर्ग तथा द्वितीय उद्घाटन भाषण प्रमुख थे। इन भाषणों में उन्होंने राष्ट्र को समय के आवश्यक कार्य पूर्ण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमको किसी के प्रति विद्वेष की भावना का संचन न कर' सबके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। सेनापति ली. के आत्मसमर्पण के कुछ समय पश्चात् अप्रैल 14, 1865 को राष्ट्रपति लिंकन को फोर्ड थियेटर (वाशिंगटन) में जॉन विल्क्स बूथ ने गोली मार दी और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई।

17. एण्ड्रू जॉनसन

एण्ड्रू जॉनसन का जन्म दिसम्बर 29, 1808 को रैले (उत्तरी केरोलिना) में हुआ। जॉनसन अमरीका के 17 वें राष्ट्रपति थे। वह स्वयं शिक्षित एवं स्वनिर्मित व्यक्ति थे और वह अपने प्रारम्भिक काल में 'ग्रीन-विल में दर्जी का कार्य करते थे। शीघ्र ही राजनीति में प्रवेश कर 1828 से 1830 तक पौरमुख्य (ऑल्डरमैन) हो गये। 1830-33 में मेयर और 1835-37 एवं 1839-41 में वह प्रान्तीय अवर सदन के लोकतांत्रिक दल से कांग्रेस में निर्वाचित हुये। उन्होंने टेनेसी के राज्यपाल के पद पर 1853-57 में कार्य किया तथा 1857-62 में अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे। अपने इस काल में वह दक्षिण के सीनेट सदस्यों में एकाकी थे, जिन्होंने गृह युद्ध में राज्यसंघ का समर्थन किया। 1862 में वह राष्ट्रपति लिंकन के टेनेसी में सैनिक राज्यपाल रहे। 1864 में संघीय-गणतन्त्रीय दल के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुये तथा राष्ट्रपति लिंकन के देहान्त के पश्चात् वह राष्ट्रपति नियुक्त हुये। अपने शासन काल में उन्होंने लिंकन के शान्तिकालीन पुर्ननिर्माण, नीति को पालन करने की चेष्टा की, और उग्रवादी गणतन्त्रीय दल से संघर्ष किया। इसके फलस्वरूप राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के ऊपर 1867 में 'पुर्ननिर्माण अधिनियम' पारित किया। जॉनसन ने अपने युद्ध सचिव एडविल स्टैन्टन को पदच्युत कर दिया और प्रतिनिधिक सदन एक मत से मई, 1868 में सीनेट के समक्ष राष्ट्रपति पर महाभियोग कार्यान्वित करने में असफल रहा। 1875 में वह सीनेट के सदस्य हुये, परन्तु उसी वर्ष जुलाई 31 को उनका देहान्त हो गया।

18. यूलिसस सिम्पसन ग्रान्ट

यूलिसस सिम्पसन ग्रान्ट का जन्म प्वाइंट प्लेजेन्ट (ओहायो) में अप्रैल 28, 1822 को हुआ। वह अमरीका के 18वें राष्ट्रपति थे। अमरीकी सैन्य अकादमी से 1843 में स्नातक हुये। मैक्सिको युद्ध में जैकरी टेलर तथा विन फील्ड स्काट के अधीन 1845-48 में कार्य किया। 1854 में सेना से सेवा निवृत्त होने के पूर्व आप कैलीफोर्निया तथा ऑरलियेन्स में सेवारत रहे। तत्पश्चात् आपने 1854 से 1860 तक अपने फार्म तथा चमड़े की दुकान गैलेना (इलिनाय) में कार्य किया। गृह युद्ध प्रारम्भ होने पर आप 21वीं (इक्कीसवीं) इलिनायेस स्वयं सेवक स्थल सेना में कर्नल हो गये। 1862 में आपको 'हेनरी किला' विजय करने के फलस्वरूप स्वयं सेवकों का मेजर जनरल बना दिया गया। अप्रैल, 1862 में उन्होंने 'गिलों' तथा जुलाई 4, 1863 को 'विक्सबर्ग' एवं नवम्बर 23-25 1862 को 'चेटनूगा' युद्ध जीता। मार्च, 1864 में आपको 'मिशनरी रिज परिसंधियों' को पराजित कर वापिस करने, तथा चेटनूगा का घेरा समाप्त कराने के कारण, संघीय सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष नियुक्त कर, लेफ्टीनेन्ट जनरल की पदवी प्रदान की गई। मई 5, जून 3, 1865 के मध्य आपने ली. के प्रतिरोध को पूर्णतया समाप्त कर दिया। पीटर्सबर्ग पर अधिकार कर अप्रैल 9, 1865 में ली. को आत्मसमर्पण करने के लिये बाध्य कर दिया। अप्रैल 1867 से जनवरी, 1868 को आप जनरल अधिकृत हुये एवं आन्तरिक युद्ध सचिव के रूप में आपकी नियुक्ति हुई। 1869 में आप गणतंत्रवादियों द्वारा नामांकित होकर राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। आपके प्रशासन की प्रमुख उपलब्धियाँ राष्ट्रीय ऋण का निधियन, सिक्कों का पुनरारम्भ, नागरिक सेवा में सुधार तथा ब्रिटेन के साथ 8 मई, 1871 की वाशिंगटन संधि थी। इसके विपरीत विकलन पक्ष में लोकवाद में उलझना जिससे 1869 को फिस्क गूल्ड द्वारा सोने का बाजार घेरना, 1873 को मोविलियर ऋण, 1874 में कोप सचिव रिचर्डसन द्वारा त्यागपत्र देना, अपने वैयक्तिक सचिव के ह्विस्की घेरे में उलझना तथा उनके युद्ध सचिव द्वारा महाभियोग से बचने के लिये त्यागपत्र देना पड़ा था। उनके प्रशासन को 1873 में अपनयन का भी सामना करना पड़ा। 1884 में ग्रान्ट एवं वार्ड के दिवालियेपन से राष्ट्रपति ग्रान्ट का भाग्य भाग्य चक्र विपरीत हो गया, परन्तु 1885 में पुनः उन्हें अपनी व्यक्तिगत जीवनी के द्वारा पाँच लाख डॉलर की प्राप्ति हुई। ग्रान्ट का देहान्त 23 जुलाई, 1885 को हुआ।

19. रदरफोर्ड वरकाॅर्ड हेज

रदरफोर्ड वरकाॅर्ड हेज का जन्म अक्टूबर 4, 1822 में डेलावेयर (ओहायो) में हुआ। वह अमरीका के 19वें राष्ट्रपति थे। 1845 में हावर्ड से विधि शिक्षा प्राप्त कर फ्रेमॉन्ट में वकालत आरम्भ की, तथा 1849 में वह सिनासिनाटी चले गये। प्रारम्भ में वह 'विग दल' के सदस्य थे परन्तु 1854 में वह गणतन्त्रीय दल के सदस्य हुये। 1858-61 तक सरकारी वकील के पद पर रहे, तथा 1868-72 में ओहायो के राज्यपाल रहे। 1877 में वह अमरीका के राष्ट्रपति हुये और अपने शासनकाल में उन्होंने दक्षिणी कैरोलीना से संधीय सैनिकों को वापस बुला लिया था, तथा नागरिक प्रशासन सेवा में सुधार लाने का असफल प्रयत्न किया। अपनी आन्तरिक नीति में रूढ़िवादी थे जिसके फलस्वरूप उन्होंने रेलवे हड़ताल के दमन हेतु सैन्य सहायता ली। 1878 में उन्होंने ब्लैण्ड-एलिसन 'चाँदी के सिक्के अधिनियम' पर निषेधाधिकार के अधिकार का प्रयोग किया परन्तु यह अधिनियम फिर भी पारित हो गया। जनवरी 17, 1893 में उनका फ्रेमॉन्ट में देहावसान हो गया।

20. जेम्स अब्राम गारफील्ड

इनका जन्म 'कीयेहोगा' (ओहायो) में 14 नवम्बर, 1831 को हुआ। आप अमरीका के 20वें राष्ट्रपति थे। 1856 में विलियम कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर वह 'वेस्ट्रन' रिजर्व इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट' (बाद में हायरम कॉलेज) में अध्यक्ष पद पर रहे। 1857-61 तक वकालत में रहकर 1859 में ओहायो सीनेट के गणतन्त्रीय सदस्य रहे। गृह युद्ध में गारफील्ड ने लब्ध प्रतिष्ठा प्राप्त की और 'फिट्स जॉन पोर्टर अभियोग' जांच आयोग के सदस्य रहे। इसी मध्य उन्होंने वाकपटुता तथा संसदीयता में प्रतिष्ठा अर्जित की। 1880 में अमरीकी सीनेट के सदस्य बने रहे और उसी वर्ष राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये अभी वह कार्यालय सम्बन्धी समस्याओं में ग्रस्त थे, कि 1881 में वॉशिंगटन रेलरोड स्टेगन पर उनकी हत्या कर दी गई।

21. चैस्टर एलन आर्थर

आर्थर का जन्म 5 अक्टूबर, 1830 को फेयरफील्ड में हुआ। वह अमरीका के इक्कीसवें राष्ट्रपति थे। 1848 में यूनियन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर 1853 में न्यूयार्क में वकालत आरम्भ की। वह दासता विरोधी नीति के परिपालक

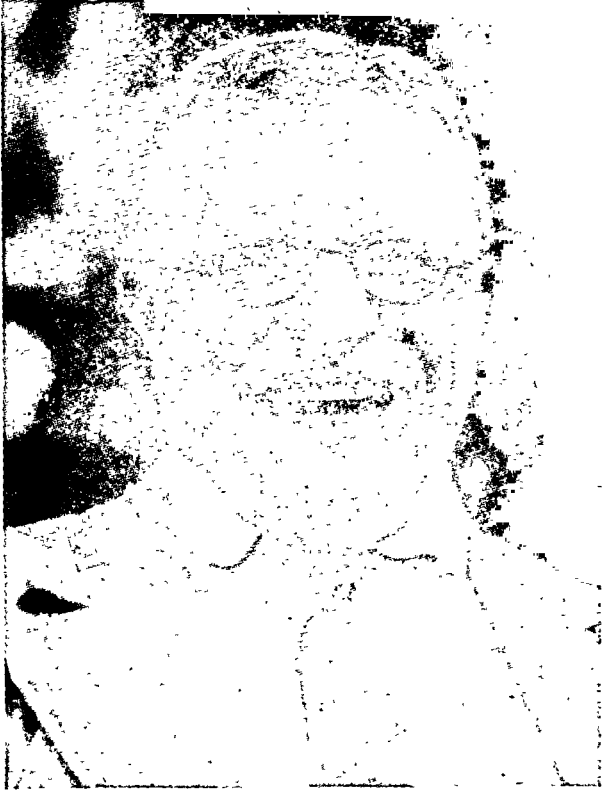
थे और इसलिये उन्होंने 'जानथन लेमान अभियोग' में प्रान्तीय वकील का कार्य किया जिसमें उनका कहना था कि दो पारस्परिक प्रांतों में दास पारगमन मुक्त रूप से होना चाहिए। गृह युद्ध में वह अधिकारी रहे और 1871 में राष्ट्रपति ग्रान्ट ने उन्हें न्यूयार्क में 'पोर्ट कलेक्टर' के पद पर नियुक्त किया। 1878 में राष्ट्रपति हेज ने उन्हें निष्कासित कर दिया। 1880 में वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुये। 19 सितम्बर 1881 में राष्ट्रपति गारफील्ड के हत्योपरांत वह अमरीका के राष्ट्रपति बने। अपने शासन काल में 'स्टाररूट' प्रतारणा अभियोग को सतत रखा। और 1883 में 'पेन्डलडन नागरिक सेना अधिनियम' पारित किया। इसके अतिरिक्त अमरीकी नौसेना के पुनर्निर्माण के कार्य का आरम्भ उनके प्रशासन में हुआ और चीन निवासियों के बहिष्करण विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया। 18 नवम्बर 1886 को न्यूयार्क में उनका देहावसान हो गया।

22. स्टीफेन ग्रोवर क्लीवलैण्ड

क्लीवलैण्ड का जन्म कॉलडवेल (न्यूजेरेसी) में 18 मार्च, 1837 को हुआ। वह अमरीका के 22 वें एवं 24वें राष्ट्रपति थे। बफेलो से विधि शिक्षा प्राप्त कर 1859 में उन्होंने वकालत न्यूयार्क में आरम्भ की। 1869 में लोकतन्त्रिक दल से शेरीफ और 1881-82 में बफेलो के मेयर और 1882-84 में न्यूयार्क के राज्यपाल निर्वाचित हुये। 1885-89 में वह अमरीका के लोकतान्त्रिक दलीय राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। उन्होंने ह्वाइट हाउस में 'फ्रैंकिस फॉल्सम' से शादी की, और दक्षिण के प्रति सहृदयता की नीति को अपनाया। उनकी निषेधाधिकारकरण की नीति तथा सीमा शुल्क की नीति ने उनके प्रति विरोध उत्पन्न कर दिया और 1888 में उपरोक्त कारणोंवश वे हैरिसन द्वारा पराजित हुये। 1892 में क्लीवलैण्ड पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुये और 1893-97 में 'कठोर मुद्रा प्रणाली' नीति को अपनाया और शर्मन चाँदी क्रय अधिनियम को 1893 में निरस्त किया। 1894 में इलेनॉय में सेना भेजकर पुलमैन हड़ताल को समाप्त किया और क्लीवलैण्ड ने 1895 में ब्रिटेन और वेनीज्वेला सीमा झगड़े में हस्तक्षेप किया। वह प्रति-साम्राज्यवादी नीति को मान्यता देते थे। इस संघर्षमय काल के पश्चात् 24 जून, 1908 को प्रिसटन में उनका देहान्त हो गया।

23. वेन्जमिन हैरिसन

हैरिसन का जन्म 20 अगस्त, 1833 में नार्थ वेण्ड (ओहायो) में हुआ।



थ्येडोर हजवेल्ट

आप अमरीका के 23 वें राष्ट्रपति थे और अमरीका के नौवें राष्ट्रपति विलियम हेनरी हैरिसन के पौत्र थे। 1852 में मियामी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर 1853 में सिनसिनाटी में वकालत आरम्भ की। 1876 तक इन्डियाना के उच्चतम न्यायालय में रिपोर्टर तथा गृह युद्ध में सैनिक अधिकारी रहे। 1876 में गणतंत्रिक प्रत्याशी के रूप में इन्डियाना के राज्यपाल का चुनाव हारे परन्तु 1881-87 में अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे। 1888 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुये और अपने प्रशासन काल में 'मेकिनले सीमा शुल्क' तथा 'शर्मन चाँदी अधिनियम' पारित किया। उन्होंने प्रशान्त क्षेत्र में साम्राज्यवादी नीति का परिपालन किया तथा 1892 में चुनाव में पराजित हुये। तत्पश्चात पुनः वकालत आरम्भ की और 13 मार्च, 1901 में उनका देहान्त हो गया।

25. विलियम मेकिनली

मेकिनली का जन्म नाईल्ज में 29 जनवरी, 1843 को हुआ। आप अमरीका के 25वें राष्ट्रपति थे। संघीय सेना में गृह युद्ध के मध्य भाग लिया। तत्पश्चात विधि की शिक्षा अलवेनी (न्यूयार्क) में प्राप्त कर केन्टन में वकालत आरम्भ की। वह 1882 को छोड़कर 1876-90 तक गणतंत्रिक दल के कांग्रेस के सदस्य बने। 1891 और 1893 में ओहायो के राज्यपाल निर्वाचित हुये। 1896 में राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित किये गये। उनके शासन काल में शुल्क संशोधन करके उसके मूल्य को अमरीका के इतिहास में अधिकतम कर दिया गया। '1900 में स्वर्णमानक अधिनियम' पारित किया गया और हवाई का संयोजन हुआ। 1899 में 'पोर्टोरीको, फिलीपीन्स', तथा 'ग्वाम' को स्पेन से युद्ध का अधिग्रहण करने से अमरीका विश्व शक्ति के रूप में समक्ष आया। 1900 में मेकिनली पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुये परन्तु वफेलो में एक अराजकतावादी ने उनकी हत्या कर दी।

25. थ्येडोर रुजवेल्ट

रुजवेल्ट का जन्म न्यूयार्क में 27 अक्टूबर, 1858 को हुआ। वह अमरीका के 26 वें राष्ट्रपति थे। 1880 में हारवर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर इतिहास लेखन में लग गये। उन्होंने 'दि नेवल वार आफ 1812' 1882 में तथा 'दि विनिंग आफ दी वेस्ट' 1889-96 में प्रकाशित की। 1884-86 में वह उत्तरी डेकोटा में अपने पशु फार्म पर ही रहे। 1886 में वह मेयर के चुनाव में असफल हुये परन्तु 1889-95 में नागरिक सेवा आयुक्त के रूप में उन्होंने

प्रशंशनीय कार्य किया। 1895-97 में वह न्यूयार्क में पुलिस आयुक्त परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1897-98 में नौसेना के अवर सचिव के रूप में कार्य किया और इस मध्य उन्होंने स्पेन के विरुद्ध युद्ध में अमरीकी नौसेना में नव-संचार की भावना प्रेरित की। 1898 में वह न्यूयार्क के राज्यपाल निर्वाचित हुये और राष्ट्रपति मैकिनली की मृत्यु के पश्चात वह अमरीका के राष्ट्रपति बने और 1904 में पुनः निर्वाचित किये गये। उन्होंने व्यापार संघ एवं न्यासिता को भंग करने का कार्य आरम्भ किया। अपने आन्तरिक प्रशासन में उन्होंने प्राकृतिक उत्पादन, खाद्य निरीक्षण तथा रेलवे विधेयक के प्रति प्रशंसनीय कार्य किये। 1903 में उन्होंने 'पनामा गणतंत्र' को स्वीकृत देकर 'पनामा नहर' के निर्माण हेतु अधिकार प्राप्त किये। रूजवेल्ट के 'रूस-जापान युद्ध में सफलता-पूर्ण मध्यस्थता के कारण उन्हें 'नोबुल शान्ति पुरस्कार' से पुरस्कृत किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने युद्ध सचिव विलियम हावर्ड टॉफ्ट को अपना उत्तराधिकारी बनाने का समर्थन दिया, परन्तु विदेश यात्रा (1909-10) से वापस आने पर उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश किया। परन्तु वुडरो विल्सन से चुनाव में पराजित हुये। 1914 में ब्राजील के अभियान के मध्य उन्होंने 'रिवर ऑफ डाउट' की खोज की, जिसका नाम तत्पश्चात रूजवेल्ट के सम्मान में 'रिया टयोडोरो' रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने में रूजवेल्ट ने मित राष्ट्रों का समर्थन किया तथा राष्ट्रपति विल्सन की तटस्थता की नीति की आलोचना की। 6 जनवरी, 1919 में ऑयस्टर बे (न्यूयार्क) में उनका देहान्त हो गया।

26. विलियम हावर्ड टॉफ्ट

टाफ्ट का जन्म 15 सितम्बर, 1857 में सिनसिनाटी (ओहायो) में हुआ। वह संयुक्त राज्य अमरीका के 27 वें राष्ट्रपति तथा नवें मुख्य न्यायाधीश थे। 1878 में येल से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1880 में सिनसिनाटी से विधि की परीक्षा उत्तीर्ण की, और वहीं पर वकालत आरम्भ की। 1881-82 तथा 1885-86 में वह अधिवक्ता के पद पर आसीन रहे। उन्होंने 1882-83 में ओहायो के प्रथम जनपद में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्य किये। 1887 से 90 में वरिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुये, तथा हैरिसन के राष्ट्रपित्वकाल में 1890 से 92 में वह अमरीकी मुख्य महाधिवक्ता तथा 1892 से 1900 तक संघीय न्यायाधीश बने। वह कुछ समय तक सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अधिष्ठाता भी रहे। राष्ट्रपति मैकिनली ने उन्हें 'फिलिपाइन आयोग' का सदस्य मनोनीत किया। 1901-04 तक वे फिलीपीन के प्रथम



वुडरो विल्सन

राज्यपाल नियुक्त हुये। इस अंतराल में उन्होंने फिलीपीन में महत्वपूर्ण सुधार किये। जिसमें शांति स्थापना, चर्च भूमि की समस्या का समाधान तथा समिति स्वायत्त शासन सम्मिलित थे। 1904-08 तक थ्येडोर रूजवेल्ट के युद्धमंत्री पद पर कार्य किया। 1908 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में वे गणतांत्रिक दल के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थित थे। अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी ब्राइन को पराजित कर वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुये। यद्यपि वे भूतपूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अनेक नीतियों-जैसे-न्याय विरोधी विधि का अत्यधिक शक्ति के साथ क्रियान्वयन ('स्टैंडर्ड आयल' व अमेरिकन टोर्बको ट्रस्ट की समाप्ति) के पक्ष में थे तथापि वे 'पेन-ओल्ड्रेच' सीमा शुल्क के संबंध में प्रगतिशील विचारों से अलग हो गये।

1912 में राष्ट्रपति पद हेतु पुनः नामांकित हुये परंतु विलसन, रूजवेल्ट और स्वयं के त्रिकोणी संघर्ष में पराजित हो गये। इसके पश्चात् 1913-21 में येल में विधि के मुख्य प्रोफेसर रहे तथा तथा 1921 एवं 1930 में राष्ट्रपति हार्डिंग ने इन्हें संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।

एक मेधावी पुरातनपंथी होने के कारण उन्होंने राष्ट्रपति को निष्कासित करने के अधिकारों को उचित बताया (मायर्स केस 1926) परंतु उनके श्रमिक संबंधी निर्णयों ने क्लेटन अधिनियम को संक्षिप्त कर दिया। टॉफ्ट का देहान्त 1930 में वाशिंगटन में हुआ।

27. टॉमस वुडरो विल्सन 1913-21

इनका जन्म 28 दिसम्बर, 1830 को स्टॉन्टन (वर्जीनिया) में हुआ। वे अमरीका के 28वें राष्ट्रपति थे, 1879 से प्रीन्सटन विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा तथा 1800 में वर्जीनिया विश्वविद्यालय से विधि स्नातक बने। 1881 में उन्होंने एटलांटा में वकालत आरम्भ की, तथा जान्स हार्फिंस के महा-विद्यालय से अपना शोध कार्य पूर्ण किया। 1885 से 1902 तक वे इतिहास, विधि, तथा राजनैतिक अर्थ शस्त्र के मुख्य प्रवक्ता का कार्य करते रहे। अपने इस कार्य में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्ति अर्जित की। 1902-10 तक प्रीन्सटन के अवैतनिक अध्यक्ष रहे। तथा वह हारवर्ड के चार्ल्स इलियट के पश्चात् अमरीका के द्वितीय शिक्षा राजनायक बने।

न्यूजर्सी के राज्यपाल के पद के चुनाव में लोकतांत्रिक दल के प्रत्याशी बन जाने के पश्चात् उन्होंने अपने पूर्व पद से त्यागपत्र दे दिया। 1912 में

लोकतांत्रिक दल से न्यूजर्सी के राज्यपाल रहे। अपने इस काल में उन्होंने सुधारों को कार्यान्वित किया, तथा लोकतांत्रिक राजनीति के आन्तरिक कलह के कारण अमरीका के 28वें राष्ट्रपति चुन लिये गये। अपने राष्ट्रपति काल के प्रथम प्रशासन में उन्होंने 'अण्डरवुड सीमा शुल्क अधिनियम', 'संघीय आरक्षण अधिनियम', 'संघीय व्यापारिक आयोग' तथा 'क्लेटन अधिनियम' जैसे कार्य किये। प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ में उन्होंने तटस्थता की नीति को अपनाया। 1916 में इस नीति के कारण पुनः निर्वाचित हुये। परन्तु 1917 में युद्ध में प्रवेश करने हेतु उन्होंने विश्व में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का नारा दिया। युद्धोपरान्त 'पेरिस शांति सम्मेलन' में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। राष्ट्रपति विल्सन ने पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता के मध्य अपने चौदह सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की, जिनका आधार विश्व शांति था।

विल्सन ने राष्ट्रसंघ को शांति समझौते के प्रति नितांत आवश्यक बताया। अपने इस दृष्टिकोण के कारण उनको अपने प्रतिपादित 14 सूत्रों से स्वयं समझौता करना पडा। जब सीनेट ने 'वारसाई' की संधि को स्वीकृति देने से इंकार किया, तो राष्ट्रपति ने 3 सितम्बर, 1919 को वाशिंगटन छोड़कर जनता के समक्ष इन दुराग्रही सीमित समूह के विरुद्ध अभियान आरम्भ किया, परन्तु 26 सितम्बर 1919 को प्यूब्लो में आकस्मिक अस्वस्थ हो जाने के पश्चात् वे पुनः स्वस्थ न हो सके। 3 फरवरी, 1924 को वाशिंगटन में उनका देहान्त हो गया।

28. वॉरेन जी. हार्डिंग 1921-1923

इनका जन्म 2 नवम्बर, 1865 को कोरसिका (ओहायो) में हुआ आप अमरीका के 29वें राष्ट्रपति थे। 1879-82 तक ओहायो केन्द्रीय विद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात् 1881 में विधि की कतिपय शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात् "मेरियम स्टार" नामक साप्ताहिक पत्र का सम्पादन किया जो बाद में दैनिक पत्र में परिवर्तित हो गया। राजनीति में उनका प्रवेश गणतंत्रिक दल की ओर से हुआ।

1900 से 1904 तक वह सीनेट के सदस्य रहे और 1904-06 में उप राज्यपाल बनाये गये। 1910 में वे राज्यपाल के प्रत्याशी के रूप में पराजित हुये। 1915-21 के मध्य वे ओहायो से अमरीकी सीनेट के सदस्य रहे, और उन्होंने 18वें संविधान संशोधन तथा 'वॉलस्टेड अधिनियम' का समर्थन किया। 1920 के गणतंत्रिक राष्ट्रीय सम्मेलन में वह राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रहे और भारी मतों से राष्ट्रपति के चुनाव में सफल हुये। हार्डिंग के प्रशासन काल की मुख्य उपलब्धि 1921-22 की नौसेना परिसीमन 'वाशिंगटन सम्मेलन' थी।

उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी कार्य प्रणाली तथा अनेक विभागों की भ्रष्टता तथा अयोग्यता का अनावरण हुआ। हार्डिंग की मृत्यु 2 अगस्त, 1923 को सॉन फ्रांसिस्को में हुई।

29. कॉल्विन कूलिज 1923-1929

आपका जन्म 4 जुलाई, 1872 को हुआ। आप अमरीका के 30वें राष्ट्रपति थे 1895 में एमहर्स्ट विद्यालय से स्नातक बने तथा 1897 में आपने नार्थम्पटन में अधिवक्ता का कार्य प्रारम्भ किया। 1907-08 में वे सामान्य न्यायालय के सदस्य चुने गये। 1910-11 में नार्थम्पटन के नगर प्रमुख, तथा 1912-15 तक राज्य के सीनेट सदस्य रहे। 1916-18 तक नार्थम्पटन राज्य के उप राज्यपाल तथा 1919-20 में राज्यपाल नियुक्त हुये। 1919 का बोस्टन पुलिस हड़ताल का दमन करने के वाद आपने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की।

1921 में आप अमरीका के उप राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति हार्डिंग के मृत्योपरान्त 1924 में अमरीका के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने दो बार 'फार्म रिलीफ बिल' पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया तथा 1927 की 'कोयला हड़ताल' में हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया। 1928 के राष्ट्रपति के चुनाव में आपने प्रत्याशी बनना अस्वीकार कर दिया।

1923 के संकट से पहले इन्होंने राष्ट्रपति पद त्याग दिया। 5 जनवरी, 1933 को नार्थम्पटन में उनका देहान्त हो गया।

30. हरवर्ट क्लार्क हूवर 1929-1933

हूवर का जन्म 10 अगस्त, 1874 को वेस्ट ब्रान्च में हुआ। वह अमरीका के 31वें राष्ट्रपति थे। 1895 में स्टेनफर्ड विश्वविद्यालय से खनिक अभियंता के स्नातक के रूप में उत्तीर्ण हुये। कई वर्ष अमरीका में कार्य करने के पश्चात् आपने आस्ट्रेलिया, चीन, अफ्रीका, मध्य एवं दक्षिण अमरीका तथा रूस की खानों में कार्य किया। प्रथम विश्व युद्ध के मध्य इन्होंने लन्दन में स्थित अमरीकी 'सहाय्य परिषद' के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभायी। इसके अतिरिक्त वह वेल्जियम में भी 'सहाय्य परिषद' के अध्यक्ष रहे तथा आपने अमरीका के खाद्य प्रशासक के रूप में भी कार्य किया। 1921 से 1928 तक इन्होंने राष्ट्रपति हार्डिंग तथा कूलिज के मन्त्रिमण्डलों में वाणिज्य सचिव के रूप में कार्य किया। 1928 में गणतंत्रवादी दल के उम्मीदवार के रूप में अमरीका के 31वें राष्ट्रपति चुने गये।

अपनी सत्ता सम्भालने के प्रथम वर्ष ही विश्व व्यापक आर्थिक संकट में उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों का पुनः परीक्षण किया। अपने शासन के अंतिम दिनों में उन्होंने 'पुनर्निर्माण वित्त निगम अधिनियम' पर हस्ताक्षर किये, जिसके द्वारा बैंकों और उच्च व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ऋण देने की व्यवस्था की गई।

20 जून, 1931 को उन्होंने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर, एक वर्ष तक, सभी राजकीय ऋणों की देय रोक दी। 1932 के राष्ट्रपतीय चुनाव में गणतंत्रवादी दल द्वारा नामांकित होने के पश्चात् आप फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से चुनाव में पराजित हो गये। 1947-49 तक तथा 1953-55 में उन्होंने 'हूवर कमीशन' के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1952 में उन्होंने पश्चिमी यूरोप से अमरीकी सेनाओं की वापसी की माँग की। उनकी तीन खण्डों में लिखित 'मेमो आयरस' और 'दि आरडील आफ बुडरो विल्सन' उत्कृष्ट रचनाओं में है।

31. फ्रैंकलिन डलेनो रूजवेल्ट 1925-45

आपका जन्म 30 जनवरी, 1882 को न्यूयार्क के हाइड पार्क में हुआ था। आप अमरीका के 32वें राष्ट्रपति थे। 1904 में हारवर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर कोलम्बिया के विधि विद्यालय से विधि स्नातक बने। 1907 में अधिवक्ता संघ में सम्मिलित हुये और न्यूयार्क में अधिवक्ता का कार्य प्रारम्भ किया।

1911 से 1913 तक न्यूयार्क राज्य सीनेट में लोकतांत्रिक सीनेट सदस्य रहे। 1913 से 1920 तक नौसेना के अवर सचिव पद पर आसीन रहे। 1920 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकतांत्रिक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में जेम्स काक्स से पराजित हुये। 1928-30 में न्यूयार्क के राज्यपाल रहे। 1932 में राष्ट्रपति के चुनाव में लोकतांत्रिक दल के प्रत्याशी के रूप में तत्कालीन राष्ट्रपति हूवर को पराजित कर राष्ट्रपति निर्वाचित हुये।

अपने प्रथम उद्घाटन भाषण में उन्होंने 'कठोर किंतु सीधा कदम' उठाने की घोषणा करते हुये 'आर्थिक संकट से उबरने', 'सामाजिक व्यवस्था', 'श्रमिक न्याय', 'विग्नर ऐक्ट', और 'फार्म विधि निर्माण' आदि हेतु प्रयास प्रारम्भ किया।

1940 में फ्रांस के पतन के पश्चात् इंग्लैण्ड को अमरीकी आर्थिक सहायता देने हेतु रूजवेल्ट ही उत्तरदायी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य मित्त राष्ट्रों ने आपसी सामन्जस्य बनाये रखने में भी रूजवेल्ट का प्रयास सराहनीय रहा। उन्होंने अपने निजी विदेशीय सम्बंध बनाये रखे। 24 जनवरी, 1944 को बिना शर्त आत्म समर्पण की घोषणा तथा काँसाव्लाँका, काँयरो ब्यूवेक,

तेहरान और याल्टा में मित्र राष्ट्रों के साथ की गयी वार्ताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् का आधार तैयार किया। 1940 में 'वेण्डल विल्की' को पराजित कर तीसरी बार तथा 1944 में टामस ड्यूवी को पराजित कर चौथी बार अमरीका के जनप्रिय राष्ट्रपति निर्वाचित हुये।

चौथी बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के तीन माह बाद ही मानसिक रक्त स्राव के कारण जार्जिया के 'वार्म स्प्रिंग्स' में 12 अप्रैल, 1945, को उनका स्वर्गवास को गया।

32. हैरी एस. ट्रूमैन

ट्रूमैन का जन्म 3 मई, 1884 को 'लेयार' में हुआ था। आप अमरीका के 33वें राष्ट्रपति थे। पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और अपने पारिवारिक फार्म पर 1906-17 तक कृषि संस्था की देख भाल करते रहे। प्रथम विश्व युद्ध में आपने सेना के विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने कॅन्सास के नागरिक विधि शिक्षा संस्थान से 1925 में विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1934 में मिसूरी से सीनेट सदस्य निर्वाचित हुये, तथा 1940 में पुनः निर्वाचित हुये। सीनेट की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अध्यक्ष के रूप में आप ने अत्यधिक ख्याति अर्जित की। 1944 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने आपको उप राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया।

12 अप्रैल, 1945 को रूजवेल्ट के देहान्त के पश्चात् आप अमरीका के 33 वे राष्ट्रपति बने। अल्पकाल में अत्यधिक सैन्य महत्व के निर्णयों को सफलता में परिणित करने में सफल रहे, जिसके अन्तर्गत जापान में परमाणु बम गिराने का आदेश भी सम्मिलित था। आपने विभिन्निका के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय शंति बनाये रखने में प्रभावशाली कार्य किया। 1946 में कांग्रेस में बहुमत समाप्त होने पर भी 'ट्रॉफ्ट-हार्टले अधिनियम' को पुनः निरस्त करने, और अपने धुआँधार चुनाव अभियान के द्वारा 1948 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली।

ट्रूमैन का द्वितीय कार्य काल रूस के प्रति 'शीत युद्ध' के लिये कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। मार्शल तथा ट्रूमैन योजनायें, कोरिया समस्या, चीन सम्बन्ध, नाटो, तथा जापान संधि (1951), उनके कार्यकाल की विधेय उपलब्धियाँ थीं।

33. डवाइट डेविड आइजनहावर

आइजनहावर का जन्म अक्टूबर 14, 1890 को टेक्सास प्रांत के 'डेनिसन' नामक स्थान पर हुआ। वह अमरीका के चौतीसवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने

संयुक्त राज्य सैन्य अकादमी से 1915 में स्नातकपरीक्षा उत्तीर्ण की। 1915-17 तक 19 वीं वाहिनी सेना में फोर्ट सैंम ह्यूस्टन (टेक्सास) में कार्य करने के पश्चात् प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब वे कैम्प कोल्ट में टैंकों पर काम करने वाली सेना के सिपहियों को प्रशिक्षित कर रहे थे, उन्हें कैप्टन की पदवी दी गयी। उन्होंने उच्च सैनिक शिक्षा 1926 में 'कमाण्ड एण्ड जनरल स्टाफ विद्यालय', 1929 में आर्मीवार कॉलेज में तथा 1932 में आर्मी इंडस्ट्रियल कॉलेज से प्राप्त की। उन्होंने पूर्ण रूपेण सुचारु रूप से सैन्य योग्यता ग्रहण कर तत्कालीन सेना अध्यक्ष 'डगलस मेकार्थर' के विशेष सहायक के रूप में 1933 में कार्य आरम्भ किया। 1935-39 तक मेकार्थर के आधीन फिलीपीन राष्ट्र मंडल के सहायक सैनिक परामर्शदाता नियुक्त किये गये। उनकी पदोन्नति 1936 में ले. कर्नल के पद पर कर दी गई। जनवरी, 1942 में वे सेनाध्यक्ष के कार्यालय में युद्ध नियोजन विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये। इसी वर्ष जून में उन्हें यूरोप में अमरीकी सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया। उन्होंने 8 नवम्बर, 1942 में उत्तरी अफ्रीका में प्रारम्भिक युद्ध अभियान में 'मित्र राष्ट्र सेना' का नेतृत्व किया। जनवरी, 1944 में वे पश्चिमी यूरोप में युद्ध करने वाली मित्र-राष्ट्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष नियुक्त किये गये। 6 मई, 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के पश्चात् वे संयुक्त राज्य द्वारा विजयी जर्मनी में अमरीकी सेनाओं के कमाण्डर थे।

नवम्बर, 1945 में वह सेनाध्यक्ष 'जार्ज मार्शल' के पश्चात् अमरीका की सेना के अध्यक्ष नियुक्त हुये। 7 जून, 1948 को वह कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर आसीन हुये। 1951 में मित्र राष्ट्र की सेनाओं के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात् कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अनुपस्थित अवकाश प्राप्त किया। 1952 में गणतान्त्रिक दल के प्रत्याशी घोषित होने के पश्चात् उन्होंने उक्त पद से त्यागपत्र दे दिया। 1952 में वे संयुक्त राज्य अमरीका के 34 वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। पुनः 1956 के चुनावों में भी वे राष्ट्रपति घोषित हुये। सोवियत संघ के मध्य एशिया में बढ़ते हुये प्रभाव को कम करने के लिये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया तथा सुदृढ़ नीति के लिये एक संतुलित बजट की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने 1948 में 'क्यूसेड इन यूरोप' नाम की पुस्तक भी लिखी।

34. जॉन फिट्सजिराल्ड कॅनेडी

संयुक्त राज्य अमरीका के 35 वें राष्ट्रपति कॅनेडी का जन्म मैसाचुसेट्स के 'ब्रुकलिन' नामक स्थान पर मई 29, 1917 को हुआ। इनके पिता जोसेफ

पी. कॅनेडी अमरीका के प्रख्यात पूंजीपति थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से बी. एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आपने प्रारम्भिक जीवन के कुछ वर्षों तक ब्रिटेन स्थित अमरीकी दूतावास में कार्य किया। आपके पिता उस समय ब्रिटेन में अमरीका के राजदूत थे। 1941-45 तक नौसेना में कार्य करते समय आपको नौसेना और 'मैरीन कोर' पदक प्रदान किये गये। पोस्टडैम सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ समय तक पत्रकार के रूप में कार्य किया। तदोपरान्त 1947-1953 तक आप तीन सत्रों में मैसाचुसेट्स के लोक-तंत्रिक दल से अमरीकी कांग्रेस के सदस्य रहे। 1952 में आपके द्वारा सीनेट के चुनाव में हेनरी कैवट लाज की पराजय अमरीकी राजनीति के इतिहास की काफी महत्वपूर्ण घटना है। 1956 में उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव में पराजित होने के पश्चात् 1958 में सीनेट के लिये बहुमतों से विजयी हुये। 1960 में कॅनेडी अपने राष्ट्रपति के चुनाव के प्रारम्भिक चरण में सेनेटर 'हर्बड हम्फ्री' को पराजित कर लोकतंत्रिक दल की ओर से राष्ट्रपति के चुनाव के अन्तिम चरण में प्रविष्ट हुये। फिट्स जेरालड कॅनेडी का यह चुनाव इसलिये ऐति-हासिक था क्योंकि 1884 के पश्चात् निकटतम चुनाव संघर्ष के द्वारा कॅनेडी विजयी हुये। कॅनेडी अमरीका के प्रथम कैथोलिक राष्ट्रपति थे, तथा सबसे कम आयु में वह इस पद पर आसीन हुये। उनकी पुस्तक 'प्रोफाइल्स इन करेज' को 1957 में प्रसिद्ध 'पुलितजर पुरस्कार' प्रदत्त किया गया।

35. लिन्डन वेन्ज जॉनसन (1963-69)

लिन्डन वेन्ज जॉनसन का जन्म 1908 में हुआ। वे अमरीका के 36वें राष्ट्रपति थे। आप 1954 के कांग्रेस के चुनाव में टेक्सास से निर्वाचित हुये। आप वैधानिक मामलों में पारंगत थे। नीग्रो जाति के वास्तविक समानता की स्थापना के क्षेत्र में आपने आइजनहावर तथा रेंवन की सहायता से एक 'नागरिक अधिकार प्रस्ताव' कांग्रेस में प्रस्तुत किया, जिसमें नीग्रो मताधिकार की सुरक्षा तथा संघीय जूरी सदस्यों के चयन में समानता तथा एक छः सदस्यीय 'नागरिक अधिकार आयोग' की स्थापना का प्रस्ताव था। पिछले ब्यासी वर्षों में यह प्रथम नागरिक अधिकार प्रस्ताव था, जिससे भविष्य में पर्याप्त आशा की जा सकती थी। जॉनसन विज्ञान तथा शिक्षा में प्रगति के पक्ष में थे। सोवियत संघ द्वारा 'स्पूतनिक प्रथम' के सफल प्रवर्तन ने आपको शिक्षा में प्रगति हेतु उपयुक्त सुअवसर प्रदान किया। इस क्षेत्र में सफलता के लिये आपने राष्ट्रीय 'सुरक्षा शिक्षा अधिनियम' के द्वारा विद्यालयों तथा स्नातकों को आर्थिक सहायता का प्राविधान प्रदान किया। 1959 में तत्कालीन प्रशासनिक

एवं प्रजातंत्रिक सदनीय नेतृत्व में सहयोग की भावना समाप्त हो गई । 1958 के कांग्रेस के चुनाव में दोनों सदनों में प्रजातंत्रवादियों को बहुमत प्राप्त हुई तथा राष्ट्रपति पद का आकांक्षी जॉनसन गणतंत्रवादियों को और अधिक समर्थन देने के पक्ष में नहीं था । 1960 के चुनाव के उपरान्त वे राष्ट्रपति कॅनेडी के उप-राष्ट्रपति हुये और 1963 में कॅनेडी की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति पद पर आसीन हुये । 1964 के चुनाव में लोकतंत्रिक दल ने उन्हें मनोनीत किया और गोल्ड वाटर के विरुद्ध चुनाव में निर्वाचित हुये । आप 1968 में निक्सन द्वारा पराजित हुये ।

36. रिचर्ड निक्सन (1969-74)

अमरीका के 37वें राष्ट्रपति एन. रिचर्ड निक्सन का जन्म 9 जनवरी, 1913 को हुआ था । आप फ्रांसिस ए तथा मया मिल हाउस निक्सन के पुत्र थे । आपने व्हिट्जर कालेज तथा ड्यूक विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की । आप 1942 में वाशिंगटन में विधि परामर्शदाता रहे तथा 1942-46 में अमरीकी नौसेना में सेवारत रहते हुये लेफ्टिनेन्ट कमान्डर के पद तक पहुँचे । 1947-50 तक निक्सन उप-राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे । 1960 में गणतंत्रवादी दल की तरफ से आप कॅनेडी के विरुद्ध उम्मीदवार रहे । 1962 में आप गणतंत्रवादी दल द्वारा कैलिफोर्निया के राज्यपाल पद के उम्मीदवार रहे । 1969 में आप अमरीका के 37वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 'वाटरगेट लोकापवाद' के कारण आपको 1974 में त्यागपत्र देना पड़ा । राष्ट्रपति फोर्ड ने आपको क्षमा याचना प्रदान की । राष्ट्रपति निक्सन का नाम 'वियतनाम संधि समझौता' (जनवरी, 1973), तथा 1972 में चीन तथा सोवियत संघ की यात्राओं के कारण सुप्रसिद्ध है यह आपका ही प्रयास था कि चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्ता प्राप्त हो सकी जिसके फलस्वरूप चीन-अमरीकी सम्बन्धों में सुदृढ़ता आ सकी और चीन अमरीका का एक प्रभावशाली मित्र बन गया । उन्होंने 1962 में 'सिक्स काइसिस', 1948 में 'निक्सन मेमोयर्स' नामक पुस्तकें प्रकाशित कीं ।

37. जिराल्ड रूडोल्फ फोर्ड (1974-76)

जिराल्ड रूडोल्फ फोर्ड प्रवर के पुत्र तथा अमरीका के 38वें राष्ट्रपति का जन्म 14 जुलाई, 1913 को ओहायो, नैब्राँस्का में हुआ । आपने मिशिगन तथा येल् विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की । 1941-42 में आप

‘फोर्ड ब्रुशेन विधि व्यवसाय संघ’ के भागीदार रहे। 1942-46 में आपने अमरीकी नौसेना की सेवा की, 1947-49 में आप वटरफोल्ड के विधि-व्यवसाय संघ के सदस्य रहे, तथा 1965-73 में अल्पमतों को सदन में नेतृत्व प्रदान किया। 1973-74 तक आप अमरीका के उपराष्ट्रपति रहे। निक्सन के त्याग-पत्र के पश्चात् 1974 में आप राष्ट्रपति नामांकित हुये। 1977 में आप मिशिगन विश्वविद्यालय के शैक्षिक विकास संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त हुये। आपको अमरीका के राजनीति विज्ञान में विशिष्ट सदन सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। आपने ‘पोट्रेट आफ दि एसेसिन’ नामक पुस्तक भी प्रकाशित की।

38. जिमी कार्टर (1976-80)

अमरीका के 39वें राष्ट्रपति जेम्स अर्ल अवर जिमी कार्टर का जन्म 1 अक्टूबर, 1924 को प्लेन (जार्जिया) में हुआ। आप जेम्स अर्ल कार्टर प्रवर तथा लिलियन गोर्डे के पुत्र हैं। 1946 में रोजिलिन स्मिथ से विवाह सूत्र में बंधे। आपने प्लेन हाईस्कूल, जार्जिया, साउथ-वेस्टर्न कालेज जार्जिया, जार्जिया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, यू. एस. नौसैनिक संस्थान से शिक्षा प्राप्त की। 1946-53 में यू. एस. नौसेना में सेवारत रहे, तथा लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर के पद पर आसीन हुये। मूंगफली के किसान के रूप में प्रख्यात कार्टर 1962-66 तक राज्य सीनेट के सदस्य रहे। 1971-74 में जार्जिया के राज्यपाल रहे। जनवरी, 1977 में अमरीका के लोकतंत्रिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुये। मिस्र-इसराएल समझौते (कैम्प डेविड-समझौता) में आपने विशेष भूमिका प्रदत्त की। परन्तु ईरान में बंधकों की समस्या को सुलझाने में पूर्णतया असफल रहे। अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के मामले में भी आपकी प्रयाप्त कूट-नीतिक पराजय हुई। आपने 1980 के मास्को ओलम्पिक का असफल वहिष्कार किया। आप पुनः 1980 में लोकतंत्रिक दल द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुये। परन्तु गणतंत्रवादी दल के रीगन द्वारा आप पराजित हो गये।



अमरीका का संविधान

अध्याय 18

अमरीका का संविधान

आमुख

हम संयुक्त राष्ट्र के लोग परिपूर्ण संघ के संगठन, न्याय-स्थापन, देशिक प्रशान्ति, समान सुरक्षा प्रबन्धक, सार्वजनिक कल्याण को प्रोत्साहन एवं अपनी वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के प्रति स्वाधीनता के अभियंत्रण को सुरक्षित करने हेतु संयुक्त राज्य अमरीका के इस संविधान का विधान एवं स्थापन करते हैं।

अनुच्छेद-1

खण्ड-1

इस संविधान सभा द्वारा प्रदत्त समस्त वैधानिक अधिकार संयुक्त राज्य की संसद (कांग्रेस) में निहित होंगे जो दो सदनों राज्य सभा (सीनेट) तथा प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव) नामक दो सदनों से युक्त होगा।

खण्ड-2

1. प्रतिनिधि सभा को संगठित करने हेतु सदस्यों का चुनाव प्रति दो वर्ष पश्चात् विभिन्न राज्यों के निवासियों द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों के लिये वही योग्यतायें होंगी जो उस राज्य के विधान मंडल के सर्वाधिक सदस्य वाले सदन के निर्वाचकों के लिये होंगी।

2. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो 25 वर्ष से कम आयु का, 7 वर्षों से कम समय से संयुक्त राज्य का नागरिक, उस राज्य जहाँ से निर्वाचित हुआ है, का निवासी न हो, प्रतिनिधि नहीं बन सकेगा।

3. इस संघ में सम्मिलित प्रत्येक राज्य के मध्य प्रतिनिधियों एवं प्रत्यक्ष

करों का संविभाजन राज्यों की निजी जनसंख्या के आधार पर होगा। इन संख्याओं का निर्धारण स्वतन्त्र व्यक्तियों की पूर्ण संख्या में, जिनमें नियत समय के लिये सेवा में अनुबंधित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे और कर न देने वाले अमरीकी आदिवासी सम्मिलित नहीं होंगे, अन्य व्यक्तियों की संख्या का 3/5 भाग जोड़कर किया जायेगा। जनसंख्या की परिगणना संयुक्त राज्य की इस संसद की बैठक के तीन वर्षों के अन्दर तथा तदुपरान्त प्रत्येक दस वर्ष के अन्तराल पर कानून द्वारा निर्धारित विधि से की जायेगी। प्रत्येक 30,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। किन्तु प्रत्येक राज्य से कम से कम एक प्रतिनिधि का निर्वाचन अवश्य होगा। उपर्युक्त परिगणना होने तक निम्नलिखित राज्य अधोलिखित संख्या में प्रतिनिधि भेजने के अधिकारी होंगे :—
न्यू हैम्पशायर-3, मैसाचूसेट्स-8, रोडद्वीप और प्राविडन्स-प्लान्टेशन-1, कनेक्टिकट-5, न्यूयार्क-6, न्यूजर्सी-4, पेन्सिल-वेनिया-8, डेलावेयर-1, मैरीलैण्ड-5-6, वर्जीनिया-10, उत्तरी कैरोलीना-5, दक्षिणी कैरोलीना-5 और जार्जिया-3।

4. किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में रिक्तता उत्पन्न होने पर उस राज्य का प्रशासन उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन की राजाज्ञा जारी करेगा।

5. प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन स्वयं करेगी तथा महाभियोग के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभा को ही प्राप्त होगा।

खण्ड-3

1. संयुक्त राज्य अमरीका की राज्य सभा का गठन प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल द्वारा निर्वाचित दो-दो सदस्यों (सीनेट) द्वारा होगा। प्रत्येक सदस्य जो 6 वर्षों के लिये निर्वाचित होगा एक मत का अधिकारी होगा।

2. अपने प्रथम निर्वाचन के पश्चात् सीनेटर एक स्थान पर एकत्रित होंगे जहाँ उनको 3 श्रेणियों में विभक्त किया जायगा। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का, द्वितीय श्रेणी के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का तथा अन्तिम श्रेणी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा। इस प्रकार प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य का निर्वाचन होगा। यदि कोई स्थान, किसी सदस्य के त्यागपत्र दे देने या अन्य किसी प्रकार से उस समय रिक्त हो जायेगा जिस समय उस राज्य के विधान मंडल का अवकाश हो उस समय सम्बन्धित राज्य का शासन, विधान मंडल की आगामी बैठक तक उक्त स्थान की अल्पकालिक पूर्ति कर सकेगा। उक्त रिक्त स्थान की स्थाई रूप से पूर्ति

विधान मंडल के आगामी अधिवेशन में होगी ।

3. कोई भी व्यक्ति जो 30 वर्ष से कम आयु का या 9 वर्षों से कम समय से संयुक्त राष्ट्र का नागरिक या निर्वाचन के समय जिस राज्य से निर्वाचित हुआ है उस राज्य का निवासी न हो, राज्य सभा का सदस्य नहीं निर्वाचित हो सकता ।

4. संयुक्त राज्य का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का अध्यक्ष होगा । उसे केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

5. राज्य सभा अपने अन्य पदाधिकारियों का निर्वाचन स्वयं करेगी । उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या जिस समय वह राष्ट्रपति के पद का दायित्व वहन कर रहा हो, राज्य सभा स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन भी करेगा ।

6. महाभियोगों के श्रवण का पूर्णधिकार राज्यसभा को प्राप्त होगा । जब राज्यसभा का अधिवेशन महाभियोग चलाने के लिये बुलाया जायेगा उस समय सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलेगा उस समय मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा । उपस्थित दो तिहाई सदस्यों की सम्मति के बिना कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं सिद्ध किया जायेगा ।

7. महाभियोग के निर्णयों के फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति को संयुक्त राज्य में पद से विमुक्ति, भविष्य में कोई भी सम्मान, विश्वास तथा लाभ के पद के लिये अनुपयुक्त घोषित करने के अतिरिक्त भविष्य में कोई दंड नहीं दिया जायेगा तथापि दंडित पक्ष नियमानुसार दोषारोपण, परीक्षण, निर्णय तथा दण्ड का भागी होगा ।

खण्ड-4

1. प्रतिनिधिसभा तथा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु समय तथा स्थान का निर्धारण सम्बन्धित राज्य के विधान मंडल स्वयं करेंगे किन्तु संसद किसी भी समय, राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन स्थलों की व्यवस्था को छोड़कर, कानून बनाकर नियमों एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी ।

2. संसद की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी । यदि संसद ने कोई नया कानून नहीं बनाया तो यह बैठक प्रत्येक वर्ष दिसम्बर मास के प्रथम सोमवार को होगी ।

खण्ड-5

1. प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की योग्यताओं निर्वाचन तथा प्रत्यावर्तन सम्बन्धी नियमों का निर्धारण स्वयं करेगा। इन विषयों पर कार्यवाही हेतु प्रत्येक सदन के सदस्यों में से बहुमत की उपस्थिति गणपूर्ति के लिये आवश्यक होगी। गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की उपस्थिति के अभाव में सदन की बैठक अगले दिन के लिये स्थगित कर दी जायेगी। सदन अपने निर्वाचित सदस्यों को उपस्थित रहने के लिये विधि द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत बाध्य करने का अधिकारी होगा।

2. प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही हेतु अपने नियम स्वयं बनायेगा। सदन को अपने सदस्यों के अनियमित आचरण के लिये दण्डित करने या उन्हें 2/3 सदस्यों के सम्मति से निष्कासित करने का अधिकार होगा।

3. प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के प्रकाशन हेतु एक पत्रिका का प्रकाशन करेगा जिसमें गोपनीय बातों के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यवाहियों का प्रकाशन होगा। इस पत्रिका में उपस्थित सदस्यों के 1/5 सदस्यों की इच्छा पर किसी भी विषय के पक्ष या विपक्ष में मत व्यक्त करने वाले सदस्यों के नामों का प्रकाशन भी होगा।

4. संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन की अनुमति के बिना तीन दिन से अधिक स्थगित नहीं हो सकेगा, न ही दो सदनों की बैठक स्थल से अपना अधिवेशन स्थल परिवर्तित कर सकेगा।

खण्ड-6

1. संसद के सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिये प्रतिदान मिलेगा, जिसका निर्धारण विधि द्वारा किया जायेगा तथा संयुक्त राज्य के राजकीय कोष से दिया जायेगा। संसद के अधिवेशन काल में संसद सदस्यों को, राजद्रोह, फौजदारी या शान्तिभंग की आशंका के अपराधों के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। संसद में सदस्यों के दिये गये भाषण पर उस सभा के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

2. संसद का कोई भी सदस्य अपने कार्य काल में, संयुक्त राज्य के किसी भी राजकीय पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसका सृजन इस काल में किया गया हो या जिसके वेतनमान में वृद्धि की गयी हो और संयुक्त राज्य शासनाधिकार के अन्तर्गत नियुक्त कोई भी व्यक्ति अपने सेवा काल में संसद का सदस्य नहीं निर्वाचित हो सकेगा।

खण्ड-7

1. राजस्व में वृद्धि सम्बन्धित कोई भी विधेयक सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जायेगा, किन्तु राज्य सभा अन्य विधेयकों के सदृश्य इसमें भी संशोधन प्रस्तुत कर सकेगी या प्रस्तुत संशोधनों पर सहमति व्यक्त कर सकेगी ।

2. प्रतिनिधि सभा और राज्य सभा द्वारा परित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पूर्व संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किये जायेंगे, जो अपनी सहमति की अवस्था में उस पर हस्ताक्षर कर देगा या अपनी आपत्तियों के साथ उस सभा को जहाँ से यह विधेयक प्रारम्भ हुआ है पुनर्विचार के लिये वापस कर देगा । वह सभा उन आपत्तियों को अपनी याचिका में उल्लिखित करके, विधेयक पर पुनर्विचार करेगी । पुनर्विचार के पश्चात् 2/3 सदस्यों की सहमति से यह विधेयक राष्ट्रपति की आपत्तियों के साथ, सभा दूसरे सदन को प्रेषित करेगी । पुनर्विचार के पश्चात् यदि उस सभा के 2/3 सदस्य इस विधेयक से सहमत हों तो यह विधेयक कानून में परिवर्तन हो जायेगा । इन सभी परिस्थितियों में विधेयक के पक्ष एवं विपक्ष में पड़ने वाले मतों का निर्धारण हाँ या ना से होगा और प्रत्येक पक्ष के सदस्यों के नाम दोनों सदनों की पत्रिका में अंकित किये जायेंगे । यदि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास से दस दिनों के अन्दर (रविवार को छोड़कर) वापस नहीं होगा तो वह स्वतः उसी प्रकार कानून बन जायेगा जिस प्रकार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् बनता । परन्तु यदि विधेयक के वापस होने से पूर्व संसद की बैठक स्थगित हो जाय तो वह विधेयक कानून नहीं बन पायेगा ।

3. प्रत्येक आदेश, प्रस्ताव और मत जिन पर सदन का सहमत होना आवश्यक है (अधिवेशन स्थगित करने के प्रश्न को छोड़कर) कार्य रूप में आने से पूर्व संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे जो उन्हें या तो स्वीकृत देगा या पुनर्विचार हेतु वापस कर देगा । वापस कर दिये जाने की स्थिति में सदन के दो तिहाई मतों के द्वारा पुनः पारित किये जाने पर वे विधेयक क्रियान्वित किये जा सकेंगे ।

खण्ड-8

कांग्रेस को अधिकार होगा:

1. संयुक्त राज्य के ऋणों के भुगतान तथा सार्वजनिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक कल्याण की व्यवस्था के लिये करों, शुल्कों, चुंगीकरों तथा आवकारी

करों को लगाने एवं वसूल करने का, परन्तु समस्त शुल्क, चुंगीकर तथा आवकारी कर सम्पूर्ण संयुक्त राज्य में एक समान होंगे ;

2. संयुक्त राज्य की साख पर ऋण लेने का, विदेशी राष्ट्रों के साथ, तथा विभिन्न राज्यों के साथ, तथा अमरीकी जनजातियों के साथ व्यापार नियंत्रण करने का ;

3. विदेशी राष्ट्रों, विभिन्न राज्यों तथा कबीलों के साथ वाणिज्य सम्बन्ध स्थापित करने का ;

4. संयुक्त राज्य में देशीकरण के एक समान नियम, तथा दिवालियापन के सम्बन्ध में एक समान विधि निर्भर करने का ;

5. मुद्रा ढालने, मूल्य निर्धारित करने, विदेशी मुद्राओं के साथ विनिमय दर निर्धारित करने तथा तौल और माप की मान ईकाईयों को निर्धारित करने का ;

6. संयुक्त राज्य के ऋणपत्रों तथा प्रचलित मुद्रा की कूटकर्की के प्रति दण्डित करने के लिये विधि बनाने का ;

7. डाकखाने और डाक मार्ग निर्माण करने का ;

8. विज्ञान और उपयोगी कला के क्षेत्र में प्रगति को प्रोत्साहित करने हेतु वैज्ञानिकों एवं लेखकों एवं आविष्कारकों को निश्चित काल के लिये उनके अधिकार को सुरक्षित करने का ;

9. सर्वोच्च न्यायालय के अधीन विभिन्न न्यायाधिक दलों को संगठित करने का ;

10. महासागरों में जल दस्युओं एवं महापराधियों को दण्डित एवं दण्ड परिभाषित करने का, तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध करने का ;

11. युद्ध घोषित करने का, किसी देश के व्यापारिक जहाज को बन्दी बनाने के लिये आदेश जारी करने, शत्रुओं का स्थल एवं जलमार्गों पर बन्दी बनाने व उनके सामान पर अधिकार करने के लिये नियम निर्माण का ;

12. किसी भी स्थान पर सेना के प्रेषण तथा उसकी सहायता करने के लिये धन की व्यवस्था जो 2 वर्षों से अधिक काल तक न करने का ;

13. नौसेना को सम्भरण एवं सम्पोषित करने का ;

14. सरकार के लिये नियम, स्थल सेना तथा नौसेना के लिये विनिमयन करने का ;

15. संघ के कानूनों को कार्यान्वित करने तथा आन्तरिक विद्रोहों के दमन एवं विदेशी आक्रमण के समय नागरिक सेना को बुलाने का ;

16. नागरिक सेना को संगठित करने, शस्त्रों से सुसज्जित करने, अनुशासित

करने तथा संयुक्त राज्य की सेवा में प्रयुक्त होने वाली नागरिक सेना के किसी भी भाग को अपने अधिकार में लेने का, अधिकारियों की नियुक्ति करने का तथा संसद द्वारा पारित नागरिक सेना के प्रशिक्षण के अनुशासनिक अधिकारों का;

17. जो भी विषय हो उन पर एक मात्र विधि निर्माण निष्पादित करने का, (उन क्षेत्रों पर जिनका क्षेत्रफल दस वर्ग मील से अधिक न हो), राज्य विशेष के अधिग्रहण द्वारा, कांग्रेस की स्वीकृति से संयुक्त राज्य की राजधानी बनने, का, ऐसे स्थानों जिन्हें राज्यों की विधान मंडल की सहमति से उपयोगी दुर्ग, शस्त्रागार, पत्तन अन्तः स्थल तथा अन्य उपयोगी भवनों के निर्माण हेतु ली गयी हो उसके सम्बन्ध में कानून बनाने के अधिकार का;

18. ऐसा समस्त विधि निर्माण करना जो पूर्वोक्त अधिकारों के पालने हेतु आवश्यक एवं उचित हो तथा इस संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार अथवा उसके किसी अधिकारी को प्राप्त अधिकारों को कार्यान्वित करने के लिये कानून बनाने का ।

खण्ड-9

1. जिन व्यक्तियों के आवास-प्रवास को वर्तमान राज्य उचित समझेंगे उसे संसद 1808 से पूर्व निषिद्ध नहीं कर सकेगी परन्तु ऐसे व्यक्तियों पर अधिक से अधिक 10 डालर का कर लगाया जा सकेगा ।

2. बन्दी प्रत्यक्षीकरण के विशेषाधिकारों को निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक आक्रमण अथवा विद्रोह के द्वारा नागरिक सुरक्षा के लिये यह आवश्यक हो ।

3. संकलुक्षीकरण विधेयक अथवा निर्माण पूर्व प्रभावित कानून पारित नहीं किये जायेंगे ।

4. कोई प्रतिव्यक्ति, कर व अन्य प्रत्यक्ष कर पूर्व जनगणना व परिगणना के अनुपात के आधार के बिना नहीं लगाया जायेगा ।

5. किसी भी राज्य (संयुक्त राज्य के अन्तर्गत) द्वारा निर्यात की हुई वस्तुओं पर कर व शुल्क नहीं लगाया जायेगा ।

6. किसी भी राज्य की पत्तनो (बन्दरगाहों) को किसी अन्य राज्य के प्रति वाणिज्य व राजस्व में वरीयता प्रदत्त नहीं की जायेगी, न ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जलपोतों के आगमन व निर्गमन पर, प्रविष्ट हेतु, सामान उतारने हेतु तथा शुल्क देने हेतु, बाध्य किया जायेगा ।

7. विधि विनियोग के अतिरिक्त राज्य कोष से धन नहीं निकाला जा सकेगा, सार्वजनिक धन के आय-व्यय का नियमित लेखा समय-समय पर प्रकाशित

किया जायेगा ।

8. संयुक्त राज्य किसी उच्चता सूचक पदवी को प्रदान नहीं करेगा, और न ही उसके अधीन लाभ व विश्वास प्राप्त पदासीन व्यक्ति कांग्रेस की अनुमति के बिना किसी नृप, युवराज अथवा किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का उपहार, पारिश्रमिक, पद व उपाधि ग्रहण कर सकेगा ।

खण्ड-10

1. कोई भी राज्य किसी भी संधि गुट अथवा राज्य संघ में सम्मिलित नहीं हो सकेगा, पोतों को शस्त्रों से सुसज्जित करने, शत्रु के जहाजों को अपने अधिकार में कर लेने पर उनके उपयोग करने का अधिकारी नहीं होगा, कोई भी राज्य दृष्टिजा जारी नहीं कर सकेगा, ऋणकी अदायगी के लिये सोने चाँदी के सिक्कों के अतिरिक्त वस्तुओं के भुगतान हेतु कानून सम्मत बना सकेगा । कोई संकलुपी विधेयक नहीं बना सकेगा, पिछली तिथियों से मान्य विधान विनिमय जो संविदा सम्बन्धी अनुबंध या उच्चता सम्बन्धी कोई पदवी से सम्बन्धित हो, नहीं बना सकेगा ।

2. संसद की अनुमति के बिना कोई भी राज्य अपने कानूनों को कार्यान्वित करने के लिये अति आवश्यक शुल्क या करों के अतिरिक्त आयात तथा निर्यात पर कोई अन्य शुल्क नहीं लगा सकेगा । इस प्रकार के शुल्कों और करों से प्राप्त आय पर संयुक्त राज्य के राजकोष का पूर्ण नियंत्रण होगा तथा ये सभी कानून संयुक्त राज्य की संसद द्वारा पुनर्विचार और नियंत्रण के विषय होंगे ।

3. संसद की अनुमति के बिना कोई भी राज्य पोतों की वहन क्षमता पर शुल्क नहीं लगा सकेगा, शांतिकाल में सेना व युद्ध पोत नहीं रख सकेगा, दूसरे राज्य से युद्ध या समझौता नहीं कर सकेगा जब तक कि उस पर आक्रमण न हुआ हो या विलम्ब होने से उसकी सुरक्षा के लिये भय की स्थिति उत्पन्न न हो गयी हो ।

अनुच्छेद 2

खण्ड 1

1. शासन के समस्त अधिकार संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति में निहित

होंगे । राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा निम्न प्रकार से निर्वाचित किये जायेंगे :

2. प्रत्येक राज्य अपने विधान मंडल के आदेशानुसार इस राज्य के लिये संसद में अधिकृत, राज्य सभा और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या के बराबर संख्या में एक निर्वाचक मंडल नियुक्त करेगा परन्तु कोई भी राज्य सभा का सदस्य, प्रतिनिधि सभा का सदस्य अथवा संयुक्त राज्य में विश्वास व लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति निर्वाचन मंडल का सदस्य नहीं हो सकेगा ।

निर्वाचन मंडल के ये सदस्य अपने-अपने राज्यों में एकत्रित होंगे और गुप्त मत प्रणाली द्वारा दो ऐसे व्यक्तियों के लिये मतदान करेंगे जिनमें से कम से कम एक उक्त राज्य का निवासी न हो । तदुपरान्त मत प्राप्त सदस्यों की नाम सूची और प्रति व्यक्ति प्राप्त मत संख्या की सूची जिसे वे अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेंगे तथा राज्य सभा के अध्यक्ष के नाम संयुक्त राज्य की राजधानी मुहरबन्द करके भेजेंगे । राज्य सभा का अध्यक्ष राज्य सभा और प्रतिनिधि सभा की उपस्थिति में समस्त प्रमाणिक सूची पत्रों का निरीक्षण करेगा तथा प्राप्त मतों की गणना की जायेगी । सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति जिसे कुल निर्वाचक मंडल के आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त होगा । राष्ट्रपति नियुक्त किया जायेगा । यदि ऐसा बहुमत मत प्राप्त करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हों और उनको भी समान मत मिले हों तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य उनमें से एक व्यक्ति को गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित करेगी, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक मंडल के आधे से अधिक सदस्यों का मत प्राप्त करने में असफल हो तो उस दशा में प्रतिनिधि सभा सर्वाधिक मत प्राप्त प्रथम पाँच व्यक्तियों में से राष्ट्रपति पद के लिये गुप्त मतदान द्वारा चुनाव करेगी किन्तु इस प्रकार मतदान में प्रत्येक राज्य के कुल प्रतिनिधि मंडल का एक मत गिना जायेगा । इसके लिये आवश्यक गणपूर्ति $2/3$ राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी तथा निर्वाचन के लिये आधे से अधिक राज्यों के मत प्राप्त करने होंगे । राष्ट्रपति के निर्वाचन के पश्चात् सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया जायेगा । यदि एक से अधिक व्यक्तियों को समान मत मिले हों तो राज्य सभा गुप्त मतदान द्वारा उनमें से किसी एक को उपराष्ट्रपति चुनेगी ।

3. संसद निर्वाचन मंडल के सदस्यों को चुनने तथा मत देने के लिये दिन निर्धारित करेगी जो सारे संयुक्त राज्य में एक ही होगा ।

4. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जन्म से संयुक्त राज्य अमरीका का नागरिक या इस संविधान के स्वीकृत होने के समय राज्य का नागरिक न हो या 35 वर्ष

से कम आयु का हो अथवा 14 वर्ष से संयुक्त राज्य का निवासी न हो राष्ट्र-पति निर्वाचित नहीं हो सकता है ।

5. राष्ट्रपति के पद से पदच्युत अथवा त्याग पत्र अथवा अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन की असमर्थता की दशा में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के कार्यों को सम्पादित करेगा । राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति दोनों के पद से पदच्युत, मृत्यु, त्याग पत्र अथवा असमर्थता की स्थिति में संसद यह निर्धारित करेगी कि कौन सा अधिकारी इस पद पर कार्य करेगा । यह अधिकारी उस समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा जिस समय तक निर्वाचित राष्ट्रपति की अयोग्यता समाप्त तक अथवा कोई नया राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाय ।

6. राष्ट्रपति को निश्चित समय पर अपने कार्यों के लिये प्रतिकर प्राप्त होगा जो उसके कार्यकाल में घटाया या बढ़ाया न जा सकेगा । अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति संयुक्त राज्य और इसके अन्तर्गत आने वाले किसी भी राज्य से अन्य कोई आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा ।

7. अपने कार्य पद पर आसीन होने से पूर्व राष्ट्रपति को निम्न शपथ व प्रतिज्ञापन करनी होगी :

“मैं विधिवत् शपथ (व प्रतिज्ञापन) करना हूँ कि मैं संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पद का कार्य निष्ठापूर्वक करूँगा, एवं पूर्ण क्षमता के साथ संयुक्त राज्य के संविधान का पालन, पोषण एवं संरक्षण करूँगा ।

खण्ड-2

1. संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य की स्थल एवं नौसेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, तथा वह संयुक्त राज्य की सेवा में बुलाई गई विभिन्न राज्यों की नागरिक सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होगा । वह किसी भी विभागाध्यक्ष से उस विभाग से सम्बन्धित किसी भी विषय पर लिखित सम्मति माँग सकेगा । महाभियोग को छोड़कर संयुक्त राज्य के विरुद्ध किसी भी अन्य अपराधों में तथा मृत्यु दण्ड को भी क्षमा प्रदान कर सकेगा ।

2. राज्य सभा में उपस्थिति 2/3 सदस्यों की अनुमति से राष्ट्रपति संधियाँ कर सकेगा । वह राजदूतों, मन्त्रियों, सरकारी अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संयुक्त राज्यके उन समस्त अधिकारियों जिनकी नियुक्ति का इस संविधान में उल्लेख नहीं है, मनोनीत करने तथा राज्य सभा की अनुमति या परामर्श से नियुक्त कर सकेगा । संसद यदि चाहे तो उक्त अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कानून द्वारा राष्ट्रपति में, न्यायालय में विभा-

गाध्यक्षों में निहित कर सकती है ।

3. राज्य सभा के अवकाश काल में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति राष्ट्रपति एक आयोग द्वारा कर सकेगा, परन्तु इनका काल राज्य सभा के आगामी अधिवेशन की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायगा ।

खण्ड-3

राष्ट्रपति समय-समय पर संसद को संघ के राज्यों की गतिविधियों की सूचनायें देता रहेगा तथा संसद के समक्ष विचारार्थ ऐसे कार्य को जो वह आवश्यक तथा कालोचित समझता हो प्रस्तुत करेगा । वह असाधारण समय में संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन की बैठक बुला सकता है । दोनों के आपसी असहमति पर वह सदनों को उस समय तक स्थगित कर सकता है जब तक कि वह उचित समझे । वह राजदूतों तथा अन्य राष्ट्र के मन्त्रियों का परिचयपत्र स्वीकार करेगा । वह ध्यान रखेगा कि विधि का नियमानुसार पालन किया जा रहा है, तथा वह संयुक्त राज्य के सभी अधिकारियों को किसी विशेष कार्य हेतु आदेश दे सकेगा ।

खण्ड-4

संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य सभी सरकारी कर्मचारी राजद्रोह, रिश्वत व अन्य फौजदारी तथा आचरण सम्बन्धी अपराधों के लिये महाभियोग चलाने और उनके सिद्ध होने पर पदच्युत कर दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद-3

खण्ड-1

संयुक्त राज्य की न्याय व्यवस्था एक सर्वोच्च न्यायालय और उन निम्न न्यायालयों में जिनकी स्थापना संसद समय-समय पर करेगी सन्निहित होगी । सर्वोच्च एवं अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश जब तक अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे जिसके लिये उन्हें नियत समय पर वेतन मिलेगा जो उनके कार्य-काल में कम नहीं किया जा सकेगा ।

खण्ड-2

1. इस न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में, संविधान में वर्जित कानून और समानता के अधिकार, जो राज्य द्वारा की गयी बयवा की जाने वाली संघियों

के द्वारा उत्पन्न होंगे, राजदूतों, सरकारी अधिवक्ताओं, मन्त्रियों व अन्य से सम्बन्धित मामले, वे समस्त विवाद जिनमें संयुक्त राज्य एक पक्ष होगा; संयुक्त राज्य के दो या दो से अधिक राज्यों के मध्यविवाद; किसी राज्य और किसी अन्य राज्य के नागरिकों के मध्य हुये, विवाद; विभिन्न राज्यों के नागरिकों के मध्य विवाद; एक ही राज्य के नागरिकों के मध्य विवाद; प्रत्येक पक्ष किसी अन्य राज्य द्वारा प्रदत्त अनुदानों के अन्तर्गत दी गयी भूमि पर अपने अस्तित्व की माँग करते हों, किसी एक राज्य या उसके नागरिकों एवं किसी विदेशी राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद, सम्मिलित होंगे।

2. उन सभी विवादों जो राजदूतों, मन्त्रियों या सरकारी अधिवक्ताओं से सम्बन्धित हों और जिनमें संयुक्त राज्य का कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा। पूर्व लिखित अन्य सभी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को विधि एवं वास्तविकता दोनों को ध्यान में रखते हुये संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत और उसके द्वारा निर्दिष्ट अपवादों के साथ याचिका सुनने का अधिकार होगा।

3. महाभियोग को छोड़कर अन्य सभी अपराधों की सुनवाई जूरी द्वारा उस राज्य में होगी जहाँ पर कथित अपराध किया गया हो किन्तु जहाँ अपराध किसी राज्य की सीमा के भीतर न किया गया हो उस परिस्थिति में मुकदमे की सुनवाई संसद द्वारा निर्धारित स्थानों पर होगी।

खण्ड-3

1. संयुक्त राज्य के विरुद्ध युद्ध करना, या शत्रु के साथ मिलकर कार्य करना, या शत्रु को सहायता या आश्रय देना, संयुक्त राज्य के विरुद्ध राजद्रोह का अपराध होगा। कोई व्यक्ति तब तक राजद्रोही नहीं घोषित किया जायेगा जब तक उसके किसी कार्य के विरुद्ध दो व्यक्तियों ने गवाही न दी हो या उसने खुले न्यायालय में अपना अपराध स्वीकृत न कर लिया हो।

2. संसद को राजद्रोह के अपराध का दंड घोषित करने का अधिकार होगा, किन्तु इस दण्ड के व्यक्तिगत व सम्पत्ति को सरकारी अधिग्रहण में लेने सम्बन्धी सरकारी आदेश, केवल सम्बन्धित व्यक्ति के जीवन काल तक ही लागू होंगे।

अनुच्छेद-4

खण्ड-1

एक राज्य में दूसरे राज्य द्वारा किये गये सार्वजनिक कार्यों, आलेखों

तथा न्यायिक कार्यवाहियों को. पूर्णतया प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माना जायेगा। संसद सामान्य कानूनों द्वारा उपर्युक्त कार्यों, आलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को प्रमाणित करने की विधि का निश्चय करेगी।

खण्ड-2

1. एक राज्य के नागरिकों को अन्य राज्यों में भी नागरिकों की समस्त सुविधायें और निरापदता प्राप्त होगी।

2. यदि कोई व्यक्ति जिस पर एक राज्य में राजद्रोह, महापराध, अथवा किसी अन्य अपराध के लिये अभियोग चल रहा हो, पलायन कर दूसरे राज्य में चला जाये तो उसे उस राज्य के जहाँ के न्यायालय में उस पर कानूनी कार्यवाही हो रही है, शासन की माँग पर उसे पुनः उस राज्य के शासन को सुपुर्द कर दिया जायेगा, जिसको उस पर अपराध के लिये न्याय करने का अधिकार होगा।

3. यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में उस राज्य के विधान के अन्तर्गत सेवा अथवा श्रम के लिये वचनबद्ध हो, पलायन कर दूसरे राज्य में चला जाय तो उसे उस राज्य में प्रचलित किसी भी विधान के अन्तर्गत सेवा अथवा श्रम से मुक्त नहीं किया जायेगा; अपितु उसे उस पक्ष के अध्ययन पर उस राज्य को वापस कर दिया जायेगा, जिसके विधान के अन्तर्गत वह कार्य करने के लिये बाध्य है।

खण्ड-3

1. संसद को इस संघ में नवीन राज्यों को सम्मिलित करने का अधिकार होगा; किन्तु एक राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दूसरे राज्य का निर्माण नहीं किया जायेगा; और दो अथवा दो से अधिक राज्यों के संयोजन से अथवा उनके भागों द्वारा विधान मण्डलों और संसद की अनुमति के बिना नये राज्य का निर्माण किया जायेगा।

2. संसद को, संयुक्त राज्य की सम्पत्ति और राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में आवश्यक नियम को बनाने और रद्द करने का अधिकार होगा। इस संविधान के अन्तर्गत कहीं गयी किसी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी, जिससे संयुक्त राज्य या किसी विशेष राज्य के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

खण्ड-4

संयुक्त राज्य इस संघ के प्रत्येक राज्य को गणतंत्रिक शासन प्रणाली

व्यवस्था लागू करने की प्रत्याभूत लेगा, तथा उनमें से प्रत्येक राज्य की आक्रमण से रक्षा करेगा; और उस राज्य के विधान मंडल की प्रार्थना पर अथवा उसके विधान मंडल की बैठक न हो सकने की स्थिति में उसकी कार्यपालिका की प्रार्थना पर आन्तरिक हिंसा में रक्षा करेगा।

अनुच्छेद-5

संसद के दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्य यदि आवश्यक समझें, इस संविधान में संशोधन कर सकते हैं या कुल राज्यों की 2/3 विधान मंडलों के अनुरोध पर संविधान में संशोधन करने के लिये अधिवेशन बुला सकते हैं। दोनों अवस्थाओं में प्रस्तावित संशोधन जब विभिन्न राज्यों की 3/4 विधान मण्डल में या 3/4 राज्यों के अधिवेशनों द्वारा अनुसमर्थित कर दिये जायेंगे, इनमें से कौन सी व्यवस्था प्रयुक्त हो इसका निर्णय संसद करेगी; तत्पश्चात् संशोधन संविधान के वैध अंग बन जायेंगे। परन्तु इस संविधान के अनुच्छेद 1 के खण्ड 9 के प्रथम एवं चतुर्थ वाक्यों में 1808 से पूर्व संशोधन नहीं किया जायेगा और न ही किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना राज्य सभा से समान मताधिकार से वंचित किया जायेगा।

अनुच्छेद-6

1. इस संविधान के प्रभाव में आने से पहले संयुक्त राज्य द्वारा लिये गये सभी ऋण या वचनदायित्व इस संविधान के पारित होने के पश्चात् भी उसी तरह वैध होंगे, जिस तरह वे इस संविधान से पूर्व राज्य संघ काल में वैध थे।

2. यह संविधान और इसके अनुसार बनाये गये संयुक्त राज्य के सभी विधान, और संयुक्त राज्य की ओर से की गयी या की जाने वाली सभी संधियाँ, इस देश के सर्वोच्च देशविधियाँ होंगी; प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उस राज्य के संविधान और कानून में किसी प्रतिकूल बात के होने के पश्चात् भी इन कानूनों द्वारा बाध्य होंगे।

2. पूर्व उद्धृत राज्य सभा के सदस्य और प्रतिनिधि सभा के सदस्य, विभिन्न राज्यों के विधान मण्डलों के सदस्य तथा संयुक्त राज्य एवं विभिन्न राज्यों के शासन और न्याय विभाग के समस्त कर्मचारी जपय लेकर या प्रतिज्ञापन करके, इस संविधान का समर्थन करने के लिये बाध्य होंगे, परन्तु राज्य के

अन्तर्गत किसी सरकारी पद या जनन्यास के पद पर कार्य करने हेतु किसी प्रकार के धार्मिक मापदंड आवश्यक नहीं होंगे ।

अनुच्छेद-7

नी राज्यों को अधिवेशनों का अनुसमर्थन उन राज्यों में इस संविधान के संस्थापन के लिये पर्याप्त होगा जिन्होंने इसकी अभिपुष्टि की । यह संविधान हमारे महाप्रभु ईसा मसीह के 1787वें वर्ष में और संयुक्त राज्य अमरीका की स्वाधीनता प्राप्ति के 12वें वर्ष में 17 सितम्बर के दिवस अधिवेशन में उपस्थित समस्त राज्यों की सर्वसम्मति से सम्पन्न हुआ जिसके साक्षी के रूप में इस प्रलेख को हस्ताक्षरित करते हैं ।

जार्ज वॉशिंगटन

(अध्यक्ष और वर्जीनिया के प्रतिनिधि)

न्यू हैम्पशर

मैसाचूसेट्स

कनेटिकट

न्यूयार्क

न्यूजर्सी

पेन्सिल्वेनिया

विलियम जैक्सन, सचिव

साक्षी

जॉन लेगडन

निकोलस गिलमैन

नेथनील गौरहैम

रूफस किंग

विलियम सैम्युअल जॉनसन

रोजर शेरमैन

एलैग्जैण्डर हैमिल्टन

विलियम लिविंग्स्टन

डेविड व्रीयरले

विलियम पेटरसन

जोना डेटन

वी. फ्रैंकलिन

टामस मिफलिन

राबर्ट मारिस

जार्ज क्लाइमर

टामस फ्रिटसाइमन्ज

जेरेड इन्गरसोल

जेम्स विलसन

गूवनर मोरिस

डिलावेयर

जोर्ज रीड

गर्निंग वैंल्फोर्ड जूनियर

जॉन डिकिन्सन

रिचर्ड वेसैट

जैकव ब्रूम

मेरीलैण्ड

जेम्स मैक्हैनरी

डेनियल आब सैट टामस जैनिफर

डेनियल कैरल

वर्जीनिया

जॉन व्लेयर

जेम्स मैडिसन जूनियर

नार्थ कैरोलाइना

विलियम ब्लीट

रिचर्ड ड्राक्स स्पेट

ह्यू विलियमसन

साउथ कैरोलाइना

जे. हटलेज

चार्ल्स कोटवर्थ पिफने

चार्ल्स पिफने

पीयर्स बटलर

ज्योजिया

विलियम फ्यू

एन्नाहम वाल्डविन

प्रशोधन

अनुच्छेद-1

संसद को धर्म या धार्मिक स्वतन्त्रता निषेधक कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, और न ही संसद भाषण तथा प्रकाशन की स्वतन्त्रता या शांतिपूर्ण सम्मेलन करने या शिकायतों को सुनने के लिये सरकार के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के नागरिकों के अधिकार को कम करने हेतु विधान बना सकती है।

अनुच्छेद-2

किसी भी स्वतन्त्र राज्य की सुरक्षा हेतु एक सुनियोजित नागरिक सेना आवश्यक होती है; अतः नागरिकों को अस्त्र-शस्त्र रखने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।

अनुच्छेद-3

कोई भी सैनिक शांति काल में और न ही युद्ध काल में किसी भी घर में उसके स्वामी की अनुमति के बिना नहीं रह सकता, जब तक विधि द्वारा निर्धारित न किया जाय।

अनुच्छेद-4

नागरिकों को अपने मकान, सामान या व्यक्तिगत पत्रों की अकारण तलाशी या आधिपत्य से रक्षा करने का पूर्ण अधिकार होगा और शपथ या घोषणा के बिना किसी सम्भावित कारण के तलाशी का अधिपत्र (वारन्ट) नहीं निकाला जा सकेगा। जिस स्थान की तलाशी लेनी हो, या जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना हो अथवा जिस सामान पर आधिपत्य करना हो, उसका अधिपत्र में विवरण आवश्यक है।

अनुच्छेद-5

कोई भी व्यक्ति अपने गृहित (गर्हणीय) अपराध का उत्तर देने के लिये वाध्य नहीं होगा, जबतक कि विशेष न्यायालय के समक्ष वह दोषारोपित नहीं हो जाता, या जब तक कि युद्ध या सार्वजनिक

सुरक्षा के समय कार्य करते हुये भू, नौसेना, नागरिक सेना सम्बंधी कोई आरोप न हो। न तो कोई भी व्यक्ति उसी अपराध के लिये मात्र संशय के कारण जीवन या अंग भंग से दण्डित किया जायेगा और न ही वह अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये बाध्य किया जायेगा एवं न ही विधि सम्मत नियमों के विरुद्ध अपने जान माल और स्वतंत्रता से वंचित किया जायेगा और न ही न्यायोचित क्षति-पूर्ति के सिवाय कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहित की जायेगी।

अनुच्छेद-6

सभी अभियुक्तों को सभी दण्ड प्रक्रियाओं में ऐसे निष्पक्ष न्यायालय में जिस जनपद या राज्य में अपराध किया गया हो, शीघ्र सार्वजनिक न्याय प्राप्त का अधिकार होगा, जो जनपद विधि द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया हो, अभियुक्त को अपराध के कारण और प्रकृति के विषय में जानकारी दी जायेगी ताकि वह अपने विरुद्ध साक्षी से आमने-सामने वार्ता कर सके। उसे अपने पक्ष में अधिवक्ता की सेवा लेने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-7

ऐसे दावे जिनका मूल्य 20 डालर से अधिक हो, में जूरी को सुनवाई के अधिकार को सुरक्षित रखा जायेगा, और एक जूरी द्वारा सुनाये गये निर्णय को संयुक्त राज्य के साधारण कानून के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं की जायेगी।

अनुच्छेद-8

अधिक प्रत्याभूत धन नहीं मांगा जायेगा, न तो अधिक दण्ड ही दिया जायेगा, और न क्रूर और असाधारण दण्ड ही दिये जायेगे।

अनुच्छेद-9

संविधान में वर्णित कुछ अधिकारों के परिगणन का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि जनता को दिये गये अधिकारों को घटा दिया गया है या उससे वंचित कर दिया गया है।

अनुच्छेद-10

जो अधिकार संयुक्त राज्य को संविधान द्वारा नहीं दिये गये हैं या जिन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, वे अलग-अलग राज्यों या जनता को प्राप्त समझे जायेंगे ।
(प्रथम दस संशोधन 1791 में पारित हो लागू किये गये)

अनुच्छेद-11

(8 जनवरी, 1798 को अनुसमर्थित)

संयुक्त राज्य के न्यायाधिकार, विधान न्यायालय सिद्धान्त संयुक्त राज्य के एक राज्य के नागरिकों द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध या किसी विदेश राज्य के नागरिकों या प्रजा द्वारा संयुक्त राज्य के किसी राज्य के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों में लागू नहीं होंगे ।

अनुच्छेद-12

(25 सितम्बर, 1804 को अनुसमर्थित)

निर्वाचक मण्डल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अपने अपने राज्यों में गुप्त मत प्रणाली द्वारा करेगा जिसमें से कम से कम एक उस राज्य का निवासी न होगा जिस राज्य का निर्वाचक मण्डल है । निर्वाचक मण्डल के सदस्य अपने मत पत्रों पर उस व्यक्ति के नाम अंकित करेंगे, जिसे राष्ट्रपति पद हेतु मतदान दिया गया है, तथा भिन्न मतपत्रों में उपराष्ट्रपति के पद हेतु मत होंगे तथा भिन्न सूचियाँ उन समस्त मतदाताओं की बनाई जायेगीं जिन्होंने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को मतदान दिया हो तथा प्रत्येक की मतदान संख्या भी सूची पत्रों में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित कर राज्य सभा (सीनेट) को, संयुक्त राज्य की राजधानी को प्रेषित करेंगे ।

राज्य सभा अध्यक्ष, संसद सदस्यों (राज्यसभा एवं प्रतिनिधि सभा के सदस्य) की उपस्थिति में प्रमाणपत्रों को खोलेगा और मतगणना की जायेगी ।

राष्ट्रपति पद के प्रति सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित किया जायेगा । यदि यह संस्था समस्त नियुक्त निर्वाचन मण्डल की संख्या में बहुमत प्राप्त करेंगे तथा यदि किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त न हो तब सर्वा-

अधिक मत प्राप्त व्यक्तियों में से जो सूची पत्र में अध्यक्ष पद हेतु मत प्राप्त तीन व्यक्तियों से अधिक न हो, प्रतिनिधि सभा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति के चयन में राज्यों से मतदान लिया जायेगा। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का एक मत होगा। इस कार्य हेतु दो तिहाई राज्यों के सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा पूर्ति होगी तथा इस चयन में राज्यों का बहुमत आवश्यक होगा और यदि प्रतिनिधि सभा आगामी 4 मार्च से पूर्व अपने चयन दायित्व के द्वारा राष्ट्रपति का चयन नहीं कर सकेगी, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य सम्भालेंगे जैसा कि राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा अन्य संवैधानिक नियोग्यता की स्थिति में होगा।

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे, वह उपराष्ट्रपति घोषित किया जायेगा यदि यह संख्या समस्त निर्वाचक मंडल की संख्या का बहुमत हो और यदि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त न हो तब सूची में सर्वाधिक मत प्राप्त दो व्यक्तियों में राज्यसभा उपराष्ट्रपति को चयन करेगी इस कार्य हेतु समस्त राज्य सभा के दो तिहाई सदस्यों की गणपूर्ति मान्य होगी और चयन के लिये समस्त संख्या का बहुमत अनिवार्य होगा परन्तु कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिये संवैधानिक रूप से अयोग्य होगा वह संयुक्त राज्य के उपराष्ट्रपति पद के योग्य नहीं होगा।

अनुच्छेद-13

खण्ड-1

(दिसम्बर 18, 1865 को अनुसमर्थित)

संयुक्त राज्य या उसके न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर किसी भी अपराध के लिये नियमित अपराधी घोषित होने पर दण्ड के अतिरिक्त न तो दासता और न ही अनैच्छिक दासता का ही कोई अस्तित्व होगा।

खण्ड-2

संसद को समुचित विधान बनाकर इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-14

खण्ड-1

(23 जुलाई, 1868 को संशोधित एवं स्वीकृत)

वे सभी मनुष्य जो संयुक्त राज्य में पैदा हुये या उन्हें संयुक्त राज्य की नागरिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र के न्याय क्षेत्र के

अन्तर्गत हो और उस राज्य के जहाँ वे रहते हैं, नागरिक हो, कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनायेगा या स्वीकृत करेगा जिससे संयुक्त राज्य के नागरिकों के विशेषाधिकार या स्वतंत्रताओं में अन्तर पड़े, न तो कोई राज्य बिना उचित कानूनी कार्यवाही किये बिना किसी भी व्यक्ति को जीवन, सम्पत्ति या स्वतंत्रता से वंचित कर सकेगा, और न हीं अपने शासनाधिकार के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को विधान की समान सुरक्षा से इन्कार कर सकेगा ।

खण्ड-2

विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के संख्या का विभाजन राज्यों की क्रमशः संख्या के आधार पर होगा, यह संख्या प्रत्येक राज्य की संख्या में से कर देने वाले अमरीकी आदिवासियों की संख्या को निकाल कर निर्धारित की जायेगी परन्तु जब कभी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों, किसी राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारियों या उस राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के चुनाव के अवसर पर राज्य के वे पुरुष जो 21 वर्ष से अधिक आयु और अमरीका के नागरिक हैं तथा उन्हें राजद्रोह या किसी अन्य गम्भीर आरोप में नागरिक अधिकारों से वंचित किया जायेगा या उनके अधिकारों में कमी की जायेगी तो प्रतिनिधित्व का आधार भी उसी अनुपात में कम हो जायेगा जो अनुपात मताधिकार से वंचित पुरुषों और राज्य के कुल 21 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुषों के मध्य होगा ।

खण्ड-3

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पहले संसद सदस्य या संयुक्त राज्य के अधिकारी या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदस्य या उसके न्यायपालिका या कार्यपालिका के सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य के संविधान के समर्थन की शपथ ली हो, और उसके बाद संयुक्त राज्य के विरुद्ध किसी राजद्रोह में भाग लिया हो, या उसके शत्रुओं की सहायता की हो संसद या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल का सदस्य नहीं बन सकता, और न हीं संयुक्त राज्य अथवा संयुक्त राज्य के किसी राज्य के नागरिक या सैनिक अधिकारी पद का कार्य कर सकता है । संसद को अपने प्रत्येक सदन के 2/3 मत से इस अयोग्यता को हटाने का अधिकार होगा ।

खण्ड-4

संयुक्त राज्य के किसी भी कानून द्वारा अधिकृत राजद्रोह के दमन में सेवाओं के आनुतोषिक जनसेवावृत्ति (पेंशन) या अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किये गये हो, आपत्ति नहीं की जा सकती लेकिन न तो संयुक्त राज्य या राज्य संयुक्त राज्य के विरुद्ध राजद्रोह के लिये किये गये ऋण की अदायगी करेगा, और न तो किसी दास की क्षति या मुक्ति के लिये किये गये ऋण की ही अदायगी करेगा। ऐसे सभी ऋण दावे या अनुबन्ध गैरकानूनी और अवैध होंगे।

खण्ड-5

इस अनुच्छेद की व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने के लिये संसद को समुचित कानून बनाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-15

खण्ड-1

(30 मार्च, 1870 को संशोधित एवं स्वीकृत)

संयुक्त राज्य के नागरिकों के मत देने के अधिकार को जाति या रंग या प्राचीन दासता के आधार पर संयुक्त राज्य या किसी राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत या संक्षिप्त नहीं किया जायेगा।

खण्ड-2

संसद को इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिये समुचित कानून बनाने का अधिकार रहेगा।

अनुच्छेद-16

(25 फरवरी, 1913 को संशोधित एवं स्वीकृत)

संसद की विना जनगणना या परिगणना और राज्यों में वॉटवारा किये विना किसी भी श्रोत से प्राप्त आय पर कर लगाने या इकट्ठा करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद-17

(31 मई, 1913 को संशोधित एवं स्वीकृत)

संयुक्त राज्य सभा की सूचना प्रत्येक राज्य से निर्वाचित दो सदस्यों (सिनेटरों) से होगी जिनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिये होगा, तथा प्रत्येक राज्य सभा सदस्य को एक मत का अधिकार होगा, इसके निर्वाचन मण्डल के लिये वही योग्यतायें होगी जो इस राज्य की विधान मण्डल के सर्वाधिक सदस्यों वाले सदन के निर्वाचकों की होगी।

राज्य सभा में किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व में कोई स्थान खाली होने पर उस राज्य का प्रमुख कार्य या क्रियाधिकारी उस स्थान की पूर्ति के लिये अधिघोषणा जारी करेगा, वशतें उस राज्य का विधान मंडल सर्वोच्च कार्याधिकारी को उस स्थान की अस्थाई पूर्ति हेतु नियुक्ति करने का अधिकार दे सकती है। बाद में उस राज्य की जनता विधान मण्डल द्वारा निर्देशित विधि से उस स्थान की पूर्ति करने की अधिकारी होगी।

इस संशोधन की ऐसी व्याख्या की जा सकेगी कि इसके पूर्व निर्वाचित किसी सिनेटर के कार्यकाल या चुनाव पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े।

इस संशोधन की ऐसी व्याख्या की जा सकेगी कि इसके पूर्व निर्वाचित किसी सिनेटर के कार्यकाल या चुनाव पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े।

अनुच्छेद-18

(29 जनवरी, 1919 को संशोधित एवं स्वीकृत)

इस अनुच्छेद के पारित होने के एक वर्ष के बाद किसी उन्मादक शराब के निर्माण, विक्रय, यातायात, आयात या निर्यात पर संयुक्त राज्य और अधीनस्थ राष्ट्रों में मादक द्रव्यों के उनके शासनाधिकार के अन्तर्गत ही प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा।

संसद तथा विभिन्न राज्यों को कानून बनाकर इस अनुच्छेद को एक ही समय में देश में लागू करने का अधिकार होगा।

यदि बहुत से राज्यों के विधान मण्डल इस संशोधन को संसद में प्रस्तुत करने के सात वर्ष के अन्तर्गत अनुसमर्थित नहीं करते तब तक यह अनुच्छेद कार्यान्वित नहीं होगा।

अनुच्छेद-19

(26 अगस्त, 1920 को स्वीकृत एवं संशोधित)

लिंगभेद के कारण संयुक्त राज्य के नागरिकों के मताधिकार को संयुक्त राज्य या उसके अन्तर्गत कोई भी राज्य कम या क्षीण नहीं कर सकेगा ।

संसद को इस अनुच्छेद को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कानून बनाने का अधिकार होगा ।

अनुच्छेद-20

खण्ड-1

(16 फरवरी, 1933 को संशोधित एवं स्वीकृत)

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 20 जनवरी को मध्याह्न समाप्त होगा और प्रतिनिधित्व सभा के सदस्यों एवं राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल जिस वर्ष उसकी अवधि समाप्ति हो रही हो, की 3 जनवरी के मध्याह्न समाप्त हुआ करेंगे, यदि अनुच्छेद स्वीकृत न हुआ हो, तथा इनके उत्तराधिकारियों की अवधि उस समाप्तिकाल से आरम्भ होगी ।

खण्ड-2

यदि संसद ने किसी कानून द्वारा अन्य दिन निर्धारित नहीं किया तो संसद बैठक वर्ष में कम से कम एक बार 3 जनवरी को मध्याह्न से आरम्भ होगी ।

खण्ड-3

यदि कार्यकाल प्रारम्भ होने से पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाय तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जायेगा । यदि निश्चित समय से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव न हो सका या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निर्धारित योग्यता प्राप्त करने में असफल हो, नवउपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति कार्य करने योग्य न हो जाय । यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और

उपराष्ट्रपति दोनों ही कार्य करने योग्य न हों तो संसद कानून बनाकर यह निश्चित करेगी कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। इस प्रकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति के योग्य न होने तक कार्य करेगा।

खण्ड-4

जब कभी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जिम्मेदारी प्रतिनिधि सभा पर आ पड़े और जिन व्यक्तियों में से राष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय या जब कभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का दायित्व राज्य सभा पर आ जाये तथा जिन व्यक्तियों में से उप राष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो किसी की मृत्यु हो जाय तो संसद कानून बना कर आवश्यक व्यवस्था कर सकती है।

खण्ड-5

इस अनुच्छेद के स्वीकृत होने वाले वर्ष के 15 अक्टूबर से इस अनुच्छेद के खण्ड 1 और 2 प्रभावी होंगे।

खण्ड-6

यदि यह संविधान संशोधन संसद में प्रस्तुत किये जाने के 7 वर्षों के अन्दर विभिन्न राज्यों के विधान मण्डल 3/4 मतों से स्वीकृत नहीं करते तो यह अनुच्छेद प्रभावी नहीं होगा।

अनुच्छेद-21

खण्ड-1

(5 दिसम्बर, 1933 को संशोधित एवं स्वीकृत)

इस अनुच्छेद द्वारा 18 वाँ संविधान संशोधन अनुच्छेद रद्द किया जाता है।

510/अमरीका का इतिहास

खण्ड-2

इस अनुच्छेद द्वारा संयुक्त राज्य के किसी राज्य में या प्रदेश या संयुक्त राज्य के किसी स्वमित्व वाले प्रदेश में सम्बन्धित कानूनों के विरुद्ध मादक द्रवों के हस्तान्तरित करने या प्रयोग के लिये आयात या निर्यात को निषिद्ध किया जाता है ।

खण्ड-3

यदि इस संशोधन के संसद में प्रस्तुत करने के 7 वर्षों के अन्दर विभिन्न राज्यों के विधान मण्डल संविधान में विधि द्वारा इसे स्वीकृत नहीं करते तो यह अनुच्छेद निष्प्रभावी होगा ।

अनुच्छेद=22

खण्ड-1

(26 फरवरी, 1951 को संशोधित एवं स्वीकृत)

कोई भी नागरिक राष्ट्रपति पद पर दो बार से अधिक नहीं चुना जा सकेगा और कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुना गया हो या उसने उन दो वर्षों से अधिक समय के लिये कार्य किया हो जिसके लिये किसी दूसरे राष्ट्रपति का चयन हुआ हो, एक बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर चुना जा सकेगा परन्तु यह अनुच्छेद उस व्यक्ति के लिये मान्य नहीं होगा जो इस अनुच्छेद के प्रस्तावित होने के समय राष्ट्रपति पद पर कार्यरत था ।



परिशिष्ट

रिचर्ड निक्सन का प्रशासन (1969-74)

1968 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियानों में गणतंत्रवादियों में नवीन आशा प्रज्वलित थी। राष्ट्रपति जॉनसन की अनेक नीतियों व व्यवस्थापनों की सफलता के फलस्वरूप भी उनके प्रशासन के अंतिम चरण में चारों ओर जटिल समस्याओं से युक्त वातावरण व्याप्त था। वियतनाम युद्ध की व्यापकता, और अमरीकी सम्बद्धता के पश्चात जॉनसन की विदेश नीति पूर्णतया असफल प्रमाणित हो गयी थी। कराधान में वृद्धि एवं मूल्यों की तीव्रता के कारण जनसमुदाय लोकतंत्रिक नीतियों की निन्दा कर रहा था। इसके अतिरिक्त अपराधों की गति भी तीव्र हो गयी थी। लोकतंत्रिक दल में नेतृत्व के विषय को लेकर पूर्व चुनावों की भाँति इस बार भी अनेक विवाद बने हुये थे। राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा चुनाव अभियान की दौड़ से पृथक हो जाने की घोषणा के पश्चात रावर्ट कैंनेडी और उपराष्ट्रपति हम्फ्री ही पद हेतु मुख्य आकांक्षी रह गये थे परन्तु वाद में रावर्ट कैंनेडी की हत्या कर दी गई इस प्रकार हवर्ट हम्फ्री ही अन्त में निर्वाचन हेतु मनोनीत हुआ। उसने घोषणा की कि वह जॉनसन की नीतियों को ही अपनायेगे। इस कारण गणतंत्रवादियों की विजय लगभग निश्चित हो गयी थी। नवम्बर के चुनाव में गणतंत्रवादी नेता रिचर्ड निक्सन को जनमत से भारी विजय प्राप्त हुई परन्तु दोनों सदनो में लोकतंत्रिक दल को अभी भी बहुमत प्राप्त था।

निक्सन प्रशासन की आर्थिक नीतियाँ

गणतंत्रवादी दल के प्रशासन में आते ही अमरीकी समाज नये आर्थिक संकटों से घिर गया। प्रारम्भिक दिनों में अत्यधिक उत्पादन के कारण मुद्रा विनिमय मूल्यों में न्यूनता आ गयी। इसके साथ ही साथ वर्ष 1970 के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या पचास लाख तक पहुँच गयी। इसके पश्चात स्थिर मूल्यों पर निर्णित 'ठोस राष्ट्रीय उत्पादन' की संख्या में भी कमी आ गई इस कारण फुटकर बाजार में उपभोक्ता मूल्यों में एकदम से वृद्धि हो गयी। 1971 में आर्थिक स्थिति में कोई सुधार न हो सका। प्रशासन की कई-नई योजनाओं के कारण वर्ष 1972 में ग्रास राष्ट्रीय उत्पादन में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु तब तक अमरीका को ऊर्जा संकट की नई समस्या ने घेर लिया था।

514/अमरीका का इतिहास

1973 में मध्य एशिया में स्थिति के खराब हो जाने के कारण उर्जा संकट अमरीकी प्रशासन का विषय बन गया। 1 फरवरी 1974 को कांग्रेस में आर्थिक सूचना की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति निक्सन ने 1973 को आर्थिक संकट का वर्ष बताया। तथा बेरोजगारी और मुद्रा प्रस्फुटन की समस्याओं के समाधान हेतु नवीन योजनायें दीं इसी प्रकार श्रमिक कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जातीय पक्षपातों के निवारण हेतु राजकीय सरकारों को निर्देश दिये। प्रशासन ने एक मूल्य निर्धारण आयोग एवं वेतन परिषद की स्थापना की। जनवरी 1972 से एक 'बेरोजगारी सुरक्षा अधिनियम' कार्यान्वित हुआ इसके अतिरिक्त पेंशन में वृद्धि कर दी गई। जुलाई 1971 में कांग्रेस ने एक विशेष सेवा आयोजन अधिनियम पारित किया इसके फलस्वरूप आगामी दो वर्षों में 2 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार मिला।

इन नवीन आर्थिक नीतियों के कार्यों के मध्य ही गणतंत्रवादी दल में एक नया संघर्ष आरम्भ हुआ। साथ ही साथ लोकतांत्रिक दल ने वाटरगेट की समस्या को लेकर अनेक विरोधी संगठन स्थापित कर लिये। गणतंत्रवादी प्रशासन को षडयंत्रकारी की संज्ञा दी गई। राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध अनेक राजनैतिक अभियान आरम्भ हो गये यह अमरीकी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर राजनैतिक संकट था। 'समाचारपत्र न्यूयार्क टाइम्स' ने भी प्रतिदिन इस विषय पर एक लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया इन्हीं समस्याओं के मध्य दल के राजनैतिक संकट के कारण उपराष्ट्रपति स्पाईरो एगन्यू ने 10 अक्टूबर 1973 को त्यागपत्र दे दिया। सदन के अल्प संख्यक नेता जेराल्ड फोर्ड को इस पद हेतु मनोनीति किया गया। 6 सितम्बर 1973 को कांग्रेस ने उन्हें इस पद हेतु निर्वाचित घोषित कर दिया। इन्हीं समस्याओं के साथ-साथ अमरीका में श्रमिक वर्ग के अनेक आंदोलन भी चल रहे थे।

श्रमिक आन्दोलन

संयुक्त राष्ट्र की 1970 की जनगणना में श्रमिक वर्ग की जनसंख्या लगभग तिरासी मिलियन दर्शायी गयी है। इस प्रकार 1940 की संख्या तिरपन मिलियन। इस प्रकार तीस वर्षों में श्रमिक वर्ग की छप्पन प्रतिशत वृद्धि हुई। श्रमिक वर्ग की इस तीव्र उन्नति का मुख्य कारण छोटे और सातवें दशक के औद्योगिक विकास की योजनाओं एवं सम्पन्नता में निहित था। इसी वृद्धि के साथ-साथ श्रमिक वर्ग के वेतनों में भी दोगुने से अधिक का अन्तर आयु का था। अनेक संघों के सृजन के पश्चात श्रमिक वर्ग अब एक संगठित पृथक

समाज के रूप में उभर चुका था। आठवें दशक के आरम्भ में ही इस श्रमिक समुदाय ने अमरीकी राजनैतिक पट पर एक नये आन्दोलन का सूत्रपात किया। व्यवसायिक और तकनीकी कार्यकर्ताओं की संख्या भी अत्यन्त अधिक हो गई थी। यह सभी वर्ग संगठित रूप से अधिक वेतन, समानता एवं अनेक अधिकारों की माँग कर रहे थे, जिनका सामना और समाधान निक्सन प्रशासन को करना था। श्रमिक वर्ग में असन्तोष का एक अन्य कारण स्वयं नियंत्रित तकनीकीयंत्रों व उद्योगों का विकास भी था, क्योंकि इसके फलस्वरूप श्रम कार्यशीलता में अनेक नये परिवर्तन आ गये थे। 1969-70 में आर्थिक संकट के कारण अमरीका में मुद्रास्फीति की गति त्वरित हो गई। गणतंत्रवादी प्रशासन ने इस आर्थिक समस्या का सामना करने के लिये अपनी श्रम नीति को जटिल रूप से दक्षिणपंथी विचारधारा के अनुकूल कर लिया। इस कारणों से अमरीकी श्रमिक वर्ग के सामने अनेकों नयी समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। इसके परिणामस्वरूप आन्दोलन, प्रदर्शन व हड़तालों का एक नया वातावरण उत्पन्न हो गया। 1970 में अमरीका में 5, 716 हड़तालें व आन्दोलन हुये जिनमें तीस लाख पाँच हजार श्रमिकों ने भाग लिया। श्रमिक वर्ग की इतनी बड़ी संख्या केवल 1945 तथा 1946 के आन्दोलनों में ही कार्यशील रही थी, जबकि उस समय द्वितीय विश्वोत्तर कालीन अनेक समस्याएँ व्याप्त थी। प्रतिशत संख्या के आधार पर 1970 की हड़तालों की संख्या अमरीकी इतिहास में सर्वाधिक थी। इन सभी समस्याओं के मध्य 1971 के अगस्त माह में राष्ट्रपति निक्सन ने 'नयी आर्थिक नीति' का प्रतिपादन किया। इस नीति के एक वर्ष पश्चात् ही प्रशासन अपनी सूचनाओं व सांख्यिकियों में यह प्रदर्शित करने लगा कि श्रमिकों का वास्तविक जीवन स्तर ऊँचा उठ रहा था। परन्तु मूल्यों व स्फीति की अवस्थाओं की तुलना में श्रमिक वर्ग अभी भी अनेक आर्थिक उन्मत् की दशाओं में रह रहा था। वास्तविक रूप से 1972 का वर्ष आर्थिक प्रस्फुटन का वर्ष था। यह निश्चित था कि अगस्त 1970 से अगस्त 1971 तक के मध्य दैनिक वेतन में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु आर्थिक स्थिरता के पश्चात् एक 6.3 प्रतिशत का तीव्र झुकाव आया। इसके कारण वर्ष 1972 तथा 1973 में श्रमिकों की स्थिति और दयनीय रही। श्रमिक संघों एवं अन्य व्यापार संघों ने निक्सन के गणतंत्रवादी प्रशासन की आर्थिक नीति की घोर निन्दा की एवं अनेक प्रदर्शनों का आयोजन किया। यूनाइटेड आटो वर्क्स के नये नेता ल्यूनार्ड वुडकाँक के कथनानुसार 'उद्योगी कार्यकर्ता एवं संघों का महत्व समाज में वास्तविकतापूर्ण है, वे इस आर्थिक उन्मत् का हमेशा शिकार बनते हैं, तथा राष्ट्रपति का यह कथन, कि उद्योगी संघ ही आर्थिक स्फीति उत्पन्न करते हैं, सर्वथा गलत है।'

इससे पूर्व के नेता वाल्टर रयूथर जिनका एक वायुयान दुर्घटना में निधन हो गया था, श्रमिक संघ के एक महान कार्यकर्ता थे। इसके भिन्न उद्योगी संगठनों के कांग्रेस संघ (सी. आई. ओ.) के नेताओं ने प्रशासन से सम्बद्ध हो कर चलना उचित समझा। इस नीति को अपनाते हुये उन्होंने ह्वाइट हाउस से उचित सम्बन्ध रखते हुये गणतंत्रवादियों की दक्षिणी पूर्वी एशिया की नीतियों का भी समर्थन किया। इस प्रकार की अनुचित नीतियों के कारण 1970 के कांग्रेस के चुनावों में अधिकांश श्रमिकों ने लोकतंत्रिक दल को अपने मत दिये। 1971 के पश्चात सी. आई. ओ. तक निक्सन प्रशासन के सम्बन्ध खराब होने लगे। 1971 की वार्षिक अधिशासी सभा में संघ के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रपति निक्सन की आर्थिक नीतियों की निन्दा की। अगस्त 1971 में, जब प्रशासन ने वेतन स्थिरता की नयी नीति लागू की, कांग्रेस ऑफ इन्डस्ट्रीयल आरगेनाईजेशन (सी. आई. ओ.) की कार्यकारणी ने गणतंत्रवादियों से सभी सम्बन्ध समाप्त कर दिये। इतना होने के पश्चात भी सी. आई. ओ. ने संगठित प्रदर्शन व आन्दोलनों का आयोजन नहीं किया। इस प्रकार की स्थिति 1947 का टॉफ्ट-हार्टले अधिनियम के पारित होने के पश्चात भी थी। मार्च 1972 में सी. आई. ओ. के प्रतिनिधियों ने वेतन परिषद की कार्यवाहियों का विरोध करते हुये त्यागपत्र दे दिया। 1972 के राष्ट्रपति चुनाव में निक्सन प्रशासन ने स्वयं यह विचारधारा स्थापित करने की कोशिश की कि सी. आई. ओ. के प्रमुख नेता वर्ग अभी भी गणतंत्रवादियों के समक्ष व समर्थन में हैं। इनको इस कार्य में काफी सफलता भी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त सी. आई. ओ. के नेता मेकगवर्न की नीतियों व योजनाओं से सन्तुष्ट नहीं थे, इस विचारधारा का भी राष्ट्रपति निक्सन को दूसरे सत्र के लिये विजयी होने में अत्यन्त लाभ हुआ। निक्सन ने लोकतंत्रिक नीतियों को प्रक्रियावादी बताया। चुनाव में विशेषज्ञों के अनुसार पचास प्रतिशत श्रमिकों ने गणतंत्रवादी प्रत्याशी निक्सन का समर्थन किया। परन्तु 1973 में कई समाचारपत्रों व नेताओं ने यह घोषणा की कि गणतंत्रवादी नेता श्रमिकों को गलत दिशाओं की ओर सम्बोधित करती थीं। समाचारपत्र 'दि नेशन' ने इस सम्बन्ध में कई लेख व सम्पादकीय छापे। धीरे-धीरे श्रमिक संगठनों के सम्बन्ध प्रशासक से खराब होते गये। सी. आई. ओ. के नेताओं ने श्रम सचिव की कार्य शिथिलता की निन्दा करनी आरम्भ कर दी। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने प्रशासन के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय की भी आलोचना की, और कहा कि मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय श्रमिकों के विरोधी निर्णय देता है, तथा पक्षपाती है। राष्ट्रपति निक्सन के निष्कासन व त्यागपत्र में सी. आई. ओ.

संगठन की भी अपनी एक विशेष भूमिका थी। पुराने संगठन 'एलाइन्स फॉर लेबर एक्शन' का महत्व अब लगभग पूर्णतया समाप्त हो चुका था। अमरीका के अर्न्तगत श्रमिकों के आन्दोलन की असफलता के कई कारण थे। सत्तारूढ़ दल हमेशा ही समझौते की स्थिति में बना रहता था। यूनियन के प्रमुखों की असफलता व बढ़ती आर्थिक संकट के कारण श्रमिक वर्ग हमेशा ही असंतोषित रहा। जातीय भिन्नता व काले वर्ग की समस्या भी निक्सन प्रशासन के साथ सम्बद्ध थी। 1972 में काले लोग अमरीका की कुल श्रमिक वर्ग का 11.5 प्रतिशत मात्र थी। इनकी वास्तविक जनसंख्या छियानवें लाख थी। विशेषज्ञों के अनुसार 1980 तक यह संख्या एक सी बीस लाख तक पहुँचने की आशा थी। अमरीकी संघीय व श्रमिक आन्दोलन में काले वर्ग के लोगों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1970 के पश्चात से नीग्रो आन्दोलन की प्रकृति व प्रवृत्ति में भी अत्यन्त परिवर्तन आया। पूर्व की भाँति अब आन्दोलन में हड़ताल व नृशंस घटनायें नहीं घटित होती थी। इस परिवर्तन में गणतंत्रवादी प्रशासन का कठोर सुरक्षा कार्य व कानून व्यवस्था की नीतियाँ ही कारण नहीं थी, वरन् अब नीग्रो समुदाए की नीतियाँ व लक्ष्यों में परिवर्तन हो गया था। 1960-69 में हुये सामूहिक आन्दोलनों का अमरीकी-जातीय सम्बन्ध के इतिहास में एक विशेष भूमिका थी। इस दशक में काले वर्ग के आन्दोलन का कार्य 'पुश' एक संस्था के द्वारा हो रहा था। इस 'प्यूपिल यूनाईटेड फॉर सालवेशन ऑफ ड्युनिटी' का केन्द्र शिकागो में था, तथा इसका ध्येय अब शान्तिमय तरीकों से आन्दोलन को बढ़ाना था।

वैदेशिक नीति तथा रूसी अमरीकी सम्बन्ध

दशक 1970 के आरम्भ में ही अमरीकी वैदेशिक नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आये। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण विश्व में शक्तियों के गठ-बध्धन में सभी ओर परिवर्तन हो रहे थे। समाजवादियों की स्थिति भी कई भागों में सुदृढ़ हो रही थी। इसके अतिरिक्त तृतीय विश्व के राष्ट्रों की एकाग्रता भी परिवर्तनमय थी। अमरीकी प्रशासन ने इस वर्ष पच्चीस वर्षों से चली आ रही द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की वैदेशिक नीति में महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक परिवर्तन किये। शीत युद्ध के स्थान पर शीत सम्बद्धता ह्वाइट हाउस का नया संदेश था। दक्षिणी पूर्व एशिया में अमरीकी पराजय से इन नीति बनाने वालों को विशेष शिक्षा मिली थी। 1969 की पतझड़ ऋतु में ही शस्त्रों के कम करने हेतु सोवियत संघ व अमरीका में बात चीत आरम्भ हो गई थी। प्रमुख सीनेट सदस्य एडवर्ड कौनेडी, विलियम फुल ब्राइट, माइक

मेनस्फील्ड, हू स्कॉट, तथा चार्ल्स परसे, वियतनाम में अमरीकी सम्बद्धता का निरन्तरविरोध कर रहे थे। अक्टूबर 1973 में सीनेट की वैदेशिक सम्बन्ध समिति के सभापति, फुल ब्राइट ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उनके अनुसार मित्रता पूर्ण सह स्थिरता (दितानते) आधुनिकतम युग की एक सबसे गम्भीर व नितान्त आवश्यकता थी। उसने संयुक्त राष्ट्र के प्रविधानों को अमल करने की पुकार दी तथा- 'पेक्स अमेरीकाना' की नीति को ठुकराया। इसी प्रकार के विचार अन्य अमरीकी नेताओं ने भी दिये। इसके विपरीत हंम यार गैन्थू जैसे रूढ़िवादी नीति सर्जकों ने पूर्व स्थिति के पक्ष में अपने विचार दिये। सीनेट सदस्य मेनस्फील्ड ने अमरीकी सेनाओं की बाह्य स्थिरता की कड़ी आलोचना की, परन्तु कांग्रेस में उसको समर्थन न मिल सका। वियतनाम युद्ध का निश्चय प्राप्त करना राष्ट्रपति निक्सन प्रशासन का सबसे जटिल कार्य व समस्या थी। प्रारम्भ में यह कार्य आत्यधिक सम्बद्धता से आरम्भ हुआ परन्तु यह मार्ग टुपकर था। अब यह सम्बद्धता तीन भूमियों में विलीन थी, 1970 में अमरीकी सेना कम्बोडिया तथा दिसम्बर 1971 में लाओस में भी युद्धमय हो गई थी। दिसम्बर 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने पूर्ण भीषणता युक्त बम बरसाने के आदेश पारित किये। परन्तु धीरे-धीरे अमरीकी प्रमुख अब यह समझने लगे थे कि भू राजनीति की दृष्टि से यह सम्बद्धता व युद्ध अत्यन्त हानिकारक है। जनवरी 27, 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्त हेतु एक समझौता हुआ। यह महान व द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात का सबसे बड़ा युद्ध समाप्त हुआ। यह अमरीका की एक बड़ी पराजय थी। 1976 में दोनों वियतनाम को युक्त करके नया समाजवादी वियतनाम बनाया गया। इन्हीं नीतियों के परिवर्तन के साथ-साथ सदियों से चली आ रही 'गुड नेहवर' की नीति भी परिवर्तन के लिये रखी गई। लेटिन अमरीका में अब अमरीकी प्रबुद्धता समाप्त हो अन्तर्राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1974 के प्रारम्भ में एक अमरीकी राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें अमरीकी राष्ट्रों को अपनी अलग-विदेश नीति बनाने की स्वतंत्रता दी गई।

मध्य एशिया में अमरीकी विदेश नीति अभी भी निश्चित दृढ़ता प्राप्त न कर पाई थी। उधर यूरोप में 'कॉमन मार्केट' का विस्तार हो रहा था। इसी 'मध्य वॉटर गेट समस्या' के कारण राष्ट्रपति निक्सन ने 8 अगस्त 1974 को त्यागपत्र दे दिया।

राष्ट्रपति जिराल्ड फोर्ड का प्रशासन

'वॉटरगेट पडयन्त्र' में राष्ट्रपति निक्सन की वास्तविक सम्बद्धता प्रमाणित

होने के पश्चात् 8 अगस्त 1974 को रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। अमरीका के इतिहास में प्रथम बार किसी राष्ट्रपति ने अपने सत्त के मध्य में त्यागपत्र दिया था। इस घटना चक्र के साथ ही एक अन्य अनोखी घटना 9 अगस्त, 1974 को उपराष्ट्रपति जिराल्ड फोर्ड का कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन था। जिराल्ड फोर्ड अमरीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन जनमत द्वारा उपराष्ट्रपति पद पर भी नहीं हुआ था। स्थाई एगन्यू के त्यागपत्र देने के पश्चात् वे उप राष्ट्रपति मनोनीत हुये थे। फलस्वरूप 20 अगस्त, 1974 को नेलसन रॉकफैलर-अमरीका के 41वें उपराष्ट्रपति बने।

गत पन्चवीस वर्षों से राष्ट्रपति फोर्ड मिशिगन राज्य से निर्वाचित अवर सदन (प्रतिनिधि सदन) के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त 1965 से वे इसी सदन में अल्प संख्यक राजतंत्रवादी दल के नेता भी थे। नीतियों के विषय में राष्ट्रपति फोर्ड एक सिद्धान्त व गूढ़वादी गणतांत्रिक नेता कहे जाते थे। वित्तीय मामलों में उनकी विचारधारार्थे परम दक्षिणपंथी थीं। इसी कारण से गणतंत्रवादी नेता विलियम वकले सदन में हमेशा उनका विरोध करते थे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को निक्सन प्रशासन से चली आ रही सभी समस्यायें उत्तराधिकारी सम्पत्तिके रूप में मिली थी मुद्रा स्फीतिकी अवस्था निरन्तर बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त उत्पादन में विशेष कमी के कारण-आर्थिक स्थिति और गहन हो गई थी। प्रशासकीय सत्ता की वागडोर संभालते ही राष्ट्रपति फोर्ड ने स्फीतिको समाप्त करने की अनेक योजनायें प्रारम्भ कीं। इसके अतिरिक्त आय-व्ययक को संतुलित करने हेतु उन्होंने सरकारी व्ययों में भारी कटौती की योजनायें दीं। परन्तु वैदेशिक नीति की दशाओं को देखते हुये सुरक्षा बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वेतनों के मूल्यों की निरन्तर वृद्धि व परिवर्तन को देखते हुये राष्ट्रपति ने एक नई संस्था "वेतन एवं मूल्य स्थिरता परिपद" की स्थापना की, परन्तु इस परिपद को केवल परामर्श व सूचना ही देने के अधिकार थे-किसी प्रकार के नियंत्रण प्रतिबन्ध लगाने का कोई अधिकार परिपद को नहीं प्राप्त था। राष्ट्र की आर्थिक व राजनैतिक स्थिति के अध्ययन व परामर्श हेतु राष्ट्रपति ने सितम्बर, 27 व 28, 1974 को एक व्यापक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में प्रशासन की नीतियों की कड़ी आलोचनायें की गईं और लोकतांत्रिक लोगों ने अनेक नये कार्यक्रम दिये। कोपागार सचिव विलियम साईमन ने भी प्रशासनिक व्यय की आर्थिक नियंत्रण की एक नवीन योजना प्रदान की। इस सम्मेलन के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने एक नयी आर्थिक परिपद का संगठन किया। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर जॉन डनलप की अध्यक्षता में एक

श्रम-प्रबन्ध समिति की स्थापना की गई। इस समिति का मुख्य कार्य आन्दोलन व स्फीतिकारी श्रमिक माँगों के विरुद्ध कार्यवाही करना था। इसके पश्चात् 8 अक्टूबर 1974 को राष्ट्रपति ने कांग्रेस में नई आर्थिक योजनायें प्रस्तुत की। 1974-75 की आर्थिक उन्मत्त के कई कारण थे। एक ओर तो अब उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। दूसरी ओर ऊर्जा श्रोतों में कमी से अत्यधिक संकट आ गया था यह अमरीकी इतिहास का छठवाँ आर्थिक संकट था। जनवरी 31, 1975 की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मूल्यों में वर्ष ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों की संख्या पैसठ लाख तक पहुँच गई थी। वर्ष 1975 की प्रथम अर्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अमरीका की आर्थिक स्थिति और भी गम्भीर होती गई। 1973 में जब ग्रॉस नेशनल उत्पादन 5.9 प्रतिशत बढ़ गया था तो श्रमिक वर्ग की स्थिति और भी खराब हो गई थी। बेरोजगारी बढ़ने के कारण श्रमिकों की दशा विगड़ती ही गई। निजी उद्योग खण्ड में श्रमिकों का साप्ताहिक वेतन 1.4 प्रतिशत घट गया। यह अन्तर पहले से अब अधिक था। निःसन्देह आर्थिक उन्मत्त और संकट के कारण वर्ष 1974 में श्रमिकों की दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आर्थिक परामर्श दात्री समिति की रिपोर्ट के अनुसार निजी खण्ड में वेतन-दर आठ प्रतिशत बढ़ गयी। परन्तु यह दर मूल्य-वृद्धि दर की तुलना में कम थी। अप्रैल, 1974 से अप्रैल 1975 के मध्य श्रमिक वर्ग की आय 4.1 प्रतिशत गिर गयी। जातीय अल्प संख्यक वर्ग तथा युवा वर्ग अभी भी पीड़ित थे। 1975 के प्रारम्भ तक अश्वेत जनसंख्या का 13.4 प्रतिशत भाग बेरोजगार था। इसके अतिरिक्त 20.8 प्रतिशत नवयुवक किसी भी कार्य से संलग्न नहीं थे। बहुत से नगरों में 60 से 70 प्रतिशत नवयुवक जातीय भिन्नता के कारण रोजगार पाने में असमर्थ थे। इस प्रकार इस संकट ने अति उत्पादन, कहीं पर अल्प उत्पादन तथा आर्थिक उन्मत्त जैसी स्थितियाँ एक साथ प्रस्तुत कर दी। परन्तु फिर भी पूंजी-पतियों की लाभ प्रतिशत निरन्तर वृद्धि करती गई, जो कि 1973 में 123 बिलियन डॉलर से 1974 में 141 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई। वर्ष के अन्त में राष्ट्रपति और उनके परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों ने आर्थिक संकट और बेरोजगारी के कारण अपनी आर्थिक स्थिति के अवलोकन हेतु नयी योजनायें बनाईं। इसमें आर्थिक उन्मत्त पर नियंत्रण रखने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया। यह कार्य केवल आर्थिक समाजिक स्थिति से ही नहीं वरन् दलीय राजनीति को ध्यान में रखते हुये भी आयोजित किया गया था। नवम्बर 1974 के चुनावों में, जब की पूर्ण अवर सदन में, एक तिहाई सीनेट तथा 35 राज्यों के राज्यपालों के चुनाव हुये-लोकतांत्रिक दल को महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई।

उन्होंने अवर सदन (प्रतिनिधि) में 291 स्थान प्राप्त किये जब कि गणतंत्रवादियों को 144 ही स्थान मिले। इस दल की स्थिति सीनेट में भी अच्छी नहीं थी। फलस्वरूप अब छत्तीस राज्यों में प्रशासन लोकतांत्रिक दल के ही हाथों था। गणतंत्रवादी दल की पराजय को इस दृष्टि से और भी महत्व दिया गया कि वे कैलीफोर्निया और न्यूयार्क जैसे बड़े राज्यों को खो बैठे। गणतंत्रवादियों की इस पराजय में वाटरगेट षडयन्त्र का कोई प्रभाव नहीं था।

इस विजय के पश्चात् लोकतांत्रिक दल ने दिसम्बर 6 से 8, 1974 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया। अमरीका के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने ऐसे समय में यह सम्मेलन बुलाया, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्ष नहीं था। इसका मुख्य कारण गणतंत्रवादी आर्थिक नीतियों का विरोध प्रकट करना था। लोकतांत्रिक दल एक बहुमत दल था, इसलिये उसकी आलोचनाओं की प्रशंसा सब ओर हो रही थी। सम्मेलन में कराधान के सुधार की कई योजनाये दी गयी तथा करों में न्यूनता लाने का प्रस्ताव रखा गया। बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु कांग्रेस में एक बेरोजगारी भत्ता देने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसके पारित होने के पश्चात् राष्ट्रपति ने एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किये। इसके अतिरिक्त एक दूसरा अधिनियम भी बनाया गया, जो आपात कालीन स्थितियों में विशेष सेवा आयोजन भर्ती हेतु था। इस प्रकार प्रशासन और कांग्रेस ने बेरोजगारी समस्या के समाधान हेतु कई सरकारी सेवाओं का सृजन किया। जनवरी 1975 में ह्वाइट हाऊस के पत्रकार सचिव रोनाल्ड नैसन ने राष्ट्रपति के नये आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की जो कि अब तक चली आ रही सिद्धांतवादी नीतियों से पृथक थी। ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं उर्जा तकनीकी नियंत्रण हेतु परमाणु उद्योग विभाग का पुनः गठन किया गया। पुराने परमाणु उर्जा आयोग को समाप्त करके दो नवीन संस्थाओं की स्थापना की गई। यह दोनों संस्थायें 'उर्जा शोध एवं विकास प्रशासन' तथा 'नाभकीय नियंत्रण आयोग' आज भी कार्यशील हैं। उर्जा स्रोतों के आर्थिककरण के लिये प्रशासन ने 'ईंधन उपभोक्ता' पर नये करों का प्रस्ताव भी रखा जुलाई 1975 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में अत्यधिक व्यय का प्रस्ताव रखा गया। इस आय व्ययक में अमरीकी इतिहास की सबसे अधिक व्ययक न्यूनता (अपूर्णता) दर्शित की गई थी। संघीय व्यय की मात्रा 367 बिलियन डालर निर्धारित की गई थी जब कि वर्षपूर्व की 68.8 बिलियन डालर अपूर्णता थी। कांग्रेस में लोकतांत्रिक दल का सामाजिक कार्यों में अधिक व्यय का प्रस्ताव मान लिया गया। राष्ट्रपति ने सुरक्षा योजनाओं के लिये

वजट का एक बड़ा हिस्सा व्यय हेतु घोषित किया इस प्रकार सरकारी व्यय के विभिन्न प्रस्तावों पर फोर्ड प्रशासन और कांग्रेस में बहुमत लोकतांत्रिक दल में कई विवाद उत्पन्न हो गये। मई 1975 में राष्ट्रपति ने 5.3 बिलियन डॉलर का एक आपात कालीन विधेयक सेवायोजन हेतु पारित किया।

फोर्ड प्रशासन काल की अन्य प्रमुख राजनैतिक घटना प्रशासन और विधायिका का निरन्तर सर्षष थी। कांग्रेस ने विरोधीदल का बहुमत होने के कारण विधायिका अब अधिशासी आदेशों को पारित करने में विम्वलव उत्पन्न करती थी 'वॉटर गेट षड्यंत्र' के पश्चात अमरीकी समुदाय और बुद्धिजीवी वर्ग की प्रवृत्ति आलोचनात्मक हो गई थी। अमरीका के 'पत्रकार वर्ग' भी अब विश्व व्यापी अमरीका के हस्तक्षेप की निन्दा कर रहा था। 22 दिसम्बर, 1974 को अमरीकी समाचार पत्र 'न्यूयार्क टाइम्स' ने सी. आई. ए. के आन्तरिक तथा विश्वव्यापी कुचक्रों की खोज करके उनकी घोर आलोचना की। सी. आई. ए. के निदेशक रिचर्ड हेल्म ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उनकी संस्था देश के आन्तरिक मामलों में भी गुप्तचर कार्य कर रही थी। उन्होंने अपनी संस्था का पक्ष लेते हुये यह स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्र के भीतर व विदेश में अमरीका के प्रति इतना अधिक प्रतिक्रियावाद प्रसारित हो रहा था कि सी. आई. ए. की यह समस्त कार्यविधियाँ नितान्त आवश्यक थी। यह आलोचनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं फलस्वरूप राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति रॉक फ़ैलर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया, जिसको सी.आई. ए. की गतिविधियों का पता लगाना था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने भी एक अन्य समिति की स्थापना की। इन सभी कार्यों के पीछे लक्ष्य जन समुदाय की ज्वाला को शान्त कर सी. आई. ए. की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था।

1975 के पश्चात 94 वीं कांग्रेस ने अमरीका के राजनैतिक जीवन में एक नवीन विचार धारा एवं जागरूकता का प्रदर्शन किया। कांग्रेसी समिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये तथा अवर सदन की वैकिंग, सुरक्षासेवा, कृषि व आवास, आदि समितियों के सभापति के पदों पर नवीन नियुक्तियाँ की गईं। नवीन कांग्रेस के अधिवेशन के आरम्भिक दिनों में ही अब तक प्रचलित अवर सदन की आंतरिक सुरक्षा समिति जो सी. आई. ए. के कार्यों में सलंगन थी, को समाप्त कर दिया गया। सभी 143 गणतंत्रवादी सदस्यों ने इस निरस्तीकरण का विरोध किया परन्तु 247 लोकतांत्रिक सदस्यों ने इस कार्य को नितान्त आवश्यक समझा। यह उल्लेखनीय है कि 1961 में साम्यवादी प्रसार के भय के कारण इस प्रकार का प्रस्ताव पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया गया था।

अनेकों नये राजनैतिक विकास लोकतांत्रिक दल में चैतन्यता आने के कारण हुये । 1974 के सम्मेलन में दल ने प्रथम बार एक प्रपत्र (चार्टर) को स्वीकार किया था, तथा दल में अल्प सरकारों की आवाज को उचित स्थान देने की योजनायें बनाई थी । अमरीकी इतिहास का वर्ष 1974 आन्दोलनों व प्रदर्शनों का वर्ष था । इस वर्ष आर्थिक उन्मत्त व स्फीति के कारण 5,900 बार हड़तालें अंकित की गई । इन हड़तालों में सत्ताईस लाख श्रमिकों ने भाग लिया । अनेको बार माँगों में प्रमुख रूप से अधिक वेतन की माँग थी । प्रशासन के सभी प्रयत्नों के पश्चात भी जातीय भिन्नता की भावना सेवा योजन विषयों पर व्यापक रूप से प्रचलित थी । जनवरी 15, 1975 को 'मार्टिन लूथर किंग' की जन्म तिथि पर पन्द्रह हजार लोगों ने एक विशाल प्रदर्शन कर जातीय भिन्नता के प्रति अपना विरोध प्रकट किया ।

इन समस्त परिवर्तनों के फलस्वरूप भी फोर्ड प्रशासन की वैदेशिक नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया । पश्चिमी यूरोप एवं जापान से अमरीकी सम्बन्ध वित्तीय मामलों में प्रतिस्पर्धा रूपी हो गये थे । संसारिक अर्थ व्यवस्था व कच्चा माल की खरीद के लिये इन देशों में सहयोग व प्रतिस्पर्धा के मिश्रण का वातावरण बना हुआ था । मई 1975 में 'नाटो राष्ट्रों' की समिति ने एक सम्मेलन आयोजित किया । अमरीकी प्रशासन दक्षिणी यूरोप में साम्यवादी भावना के प्रसार के कारण अत्यधिक चिन्तित था । पुर्तगाल, इटली व यूनान में साम्यवादियों की सफलता के फलस्वरूप ब्रसेल्स की सभा में राष्ट्रपति फोर्ड ने सैनिक शक्ति को पुनः गठन कर और सुदृढ करने का प्रस्ताव दिया । इसके अतिरिक्त स्पेन राष्ट्र को भी नाटो संधि में सम्मिलित करने की योजना थी ।

लेटिन अमरीकी राष्ट्रों से अमरीकी सम्बन्ध कैंनेडी काल से एक से बने हुये थे । दिसम्बर 1974 में कांग्रेस ने इन राष्ट्रों में अमरीका के व्यापार संबंधों का एक विधेयक पारित किया । इसमें 'ओपेक (तेल निर्यात करने वाले देश) राष्ट्रों से इन देशों की आर्थिक सम्बन्धों की नीति निर्धारित की गई थी । वेनजुएला व इक्वेडोर इससे विशेषतया प्रभावित हुये, फलस्वरूप विरोध प्रदर्शन में अमरीकी राज्यों की मार्च 1975 की सभा भी स्थगित कर दी गई । वॉशिंगटन में हुये मई 1973 के अमरीकी राज्यों के सम्मेलन में विदेश सचिव डा. किंसिजर ने सामूहिक सुरक्षा व एकाग्रता में अमरीकी योगदान की वचनबद्धता को पुनः दुहराया । इसके अतिरिक्त क्यूबा के आर्थिक बन्धन व पनामा नहर के विषय पर भी विवेचन किया गया । 1975 की वसन्त ऋतु में दीर्घ कालीन अमरीकी सम्बद्ध वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ । इस युद्ध के काल में अमरीका के चार राष्ट्रपति निर्वाचित हुये तथा सात बार कांग्रेस के चुनाव हुये । दक्षिणी

वियतनाम में अमरीकी सहयोगी सेनाओं की हार निश्चय ही दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात की एक बड़ी पराजय थी। इस युद्ध में अमरीका का 150 बिलियन डालर का व्यय तथा पचास हजार सैनिक शक्ति की हानि हुई। इस पराजय के पश्चात सुदूर पूर्व के लिये नव वैदेशिक नीति की तैयारी प्रारम्भ होने लगी मध्य पूर्व एशिया में अमरीकी नीतियाँ अब तेल तक ही सीमित न थी, और हिन्दसागर में 'प्रबुद्धता नीति' के लिये मध्य एशियाई देशों से सम्बन्ध अच्छे रखना स्वभाविकता उचित था। अमरीकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये सीयोनी आन्दोलन का समर्थन किया गया। सितम्बर 1974 के भाषण में राष्ट्रपति फोर्ड ने तेल निर्यात करने वाले देशों को उनकी नीति को विस्तारित करने के लिये कहा अन्यतः विश्व व्यापी आर्थिक संकट का भय था। 24 नवम्बर 1974 के संयुक्त सोवियत अमरीकी विज्ञप्ति में मध्य एशिया नीति के लिये "जेनेवा सम्मेलन" के प्रविधानों को दुहराया गया था। 23-24 नवम्बर 1974 को ब्लाडिवाँस्टक में ब्रैजनेव व फोर्ड का मिलन व एक समझौते पर हस्ताक्षर होना, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण कदम था। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने शस्त्रों को कम करने के प्रविधानों के लिये पृथक-पृथक समझौते किये। 17 जनवरी 1975 को सीनेट समिति के सदस्यों (जिसमें एडवर्ड कॅनेडी, वाल्टर मोनडेल, चार्ल्स मैथियास प्रमुख थे) ब्लाडिवाँस्टक के समझौते को स्वीकार कर लिया, तथा प्रशासन को अन्य विषयों पर तथा निःशस्त्रीकरण करने हेतु अन्य समझौतों के लिये प्रेरित किया। इसी के साथ सोवियत-अमरीकी व्यापार समझौता भी हुआ। इससे पूर्व 1972 के समझौते के पश्चात इन राष्ट्रों में तीन बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। फोर्ड प्रशासन ने साम्यवादी व समाजवादी राष्ट्रों से अमरीकी सम्बन्धों को सुदृढ़ करने हेतु अनेक सराहनीय कार्य किये। सितम्बर 1974 में अमरीका तथा जर्मन लोकतान्त्रिक गणराज्य (जी. डी. आर.) के कूटनीतिक व राजदूतिक सम्बन्ध स्थापित हुये। इससे स्पष्ट था कि अमरीका यह रुढ़िवादी-शीत युद्ध विचारधाराओं को त्याग कर नयी नीतियाँ स्थापित करना चाहता था। राष्ट्रपति ने कहा "साम्यवादी राष्ट्रों से अमरीका के घनिष्ठ सम्बन्धों का होना, विश्व वातावरण का महत्वपूर्ण तत्व है।

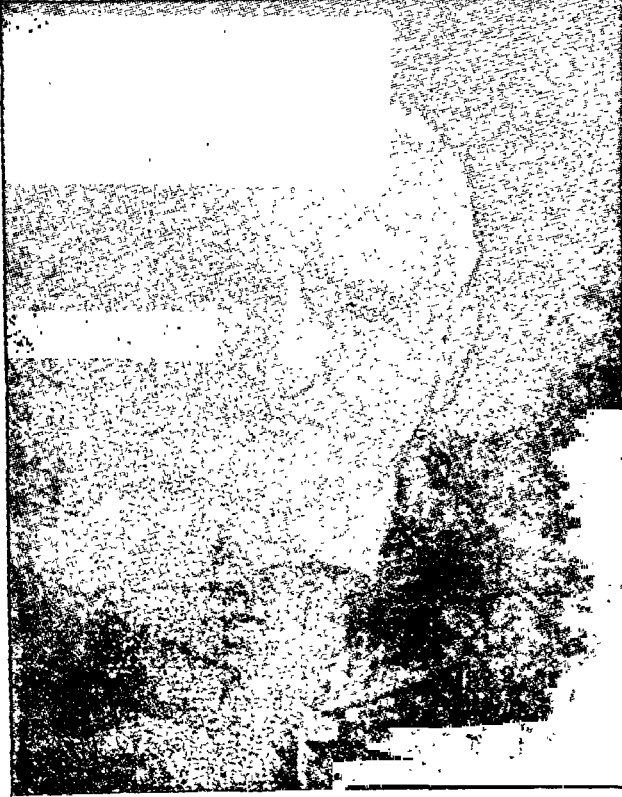
वर्ष 1976 अमरीकी राष्ट्र में पुनः राष्ट्रपति चुनाव के संघर्ष का हृदय स्थल बना हुआ था। फोर्ड प्रशासन के अनेक प्रयासों के फलस्वरूप भी आर्थिक क्लेषों के कारण जनता का झुकाव लोकतन्त्रिक दल की ओर बना हुआ था। नवम्बर के चुनावों में लोकतन्त्रिक जेम्स अर्ल कार्टर (जिम्मी) अमरीका के उन्तालीसवें राष्ट्रपति निर्वाचित हुये।



रॉल्फ वाल्डो एमर्सन (1803—1882)
प्रख्यात दार्शनिक, कवि एवं निवन्धकार



नैथेनियल हॉर्थान (1804-1864)
सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथा लेखक



फ्रांसिस पार्कमैन (1823-1893)
प्रख्यात इतिहासकार

संविधानवाद

1. Bancroft, George. : History of the United States of America (Boston, 1852) IV, pp. 12-13.
2. Craven, Wesley F. : The Revolutionary Era in John Higham, ed : the Reconstruction History (New York 1962) pp. 46-47.
3. Andrews, Charles M. : The American Revolution' an Interpretation''American Historical Review, XXXI (January 1926) 231.
4. Becker, Carl L. : The History of Political Parties in the Province of New York, 1760 - 1776 (Madison, 1909) p. 22.
5. Schlesinger, Arthur M. : The Colonial Merchants and the American Revolution' 1763-1776 (New York, 1918) p. 606
6. Morgan, Edmund S. and : The Stamp Act Crisis : Prol-
Morgan, Helen M. : ogue to Revolution, Revised

ed. New York 1963, pp.
369-70,

7. Bailyn, Bernard, ed : 'Pamphlets of the American Revolution' (1750 - 1776) (Cambridge, Mass., 1965-), I
8. Wood, Gordon; : 'Rhetoric and Reality in the American Revolution' William and Mary Quarterly, XXIII (January 1966), 13
9. Morison, Samuel E. ed. : "William Manning's the Key of Liberty" (William & Mary Quarterly, 3d SER., XIII (1956) (208).
10. Morgan, Edmund S. : 'The American Revolution : Revisions in Need of Revising' William and Mary Quarterly 3d. SER. XIV (1957) 14
11. Murray, William Vans. : "Political Sketches, Inscribed to his Excellency John Adams" (London, 1787), 21, 48
12. Tyler, Moses Coit; : 'The Literary History of the American Revolution', 1763-1783 (New York 1897) I. pp. 8-9
13. Becker, Carl L; : 'The Declaration of Independence: a Study in the History of Political Ideas' (New York 1922) pp. 133, 203, 207.
14. Ford, W. C; : Journals of the Continental Congress, ed. Washington 1904-37, II pp. 140-157

15. Davidson, Philip. : 'Propaganda & the American Revolution' (1763 - 1783) (Chapel Hill 1941)) pp. 141; 373,150.
16. Schlesinger, Arthur H.; : 'Prelude to Independence : The Newspaper War On Britain', 1764-1776 (New York, 1958 p. 34)
17. Schlesinger; Arthur M.; : 'New View points in American History' (New York, 1923) p. 179
18. Bailyn, Bernard; : 'Pamphlets of the American Revolution'. 1750 - 1776
and
Garret, Jane N.; : (Cambridge, Mass 1965-) I, viii, 60, X, 20.
19. Morgan, Edmond S. : 'The Birth of the Republic' 1763-89 (Chicago, 1956) p. 51.
20. Pocock, J.G.A.; : 'Machiavelli, Harrington and English Political Ideologies in the Eighteenth Century'
21. Namier, Sir Lewis; : 'England in the Age of American Revolution, 2D,ed., (London, 1961) p 131.
22. Arendt, Hannah : 'On Revolution' (New York 1963) p. 173.
23. Namier, Sir Lewis; : 'The Srutcture of Politics at the Accession of George III' 2D, ed.(London, 1961) p. 16.
24. Namier, Sir Lewis; : 'Human Nature in Politics'

- in Personalities and Power : Selected Essays (New York, 1965) pp 5-6.
25. Parker, Harold T : "The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries' : A Study in the Development of the Revolutionary Spirit (Chicago, 1937) pp. 22-23.
26. Miller, John C : Origins of the American Revolution, Little, Brown and Co. and the Atlantic monthly press, 1943, pp. 382-388
27. Duche ; Jacob ; : The American Vine : A Sermon, preached.....before the Honourable Continental Congress, July 20th, 1775. (Philadelphia, 1775) p. 29.
28. Wilson, Bryan A. "Millennialism in Comparative Perspective", Comparative Studies in Society and History, VI (1963-64) p. 108.
29. Smelser, Neil J. ; : "Theory of Collective Behaviour" (London, 1962); p. 83, 120, 383.
30. Kristol, Irving ; : The American Revolution as a Successful Revolution.
- and
31. Diamond, Martin, : "The Revolution of Sober Expectations" in America's Continuing Revolution. New Delhi, 1975. pp. 3-21. pp. 25-41.
32. Bailyn Bernard ; : "Political Experience and

Enlightenment Ideas In eighteenth Century America," American Historical Review, LXV II. (1961-62), 341. n.

33. Smith, Page : 'David Rmsay and the Causes of the American Revolution' William and Mary Quarterly 3d SER, XVII, 1960, 70-71.
34. Robert E. and Brown B, Katherine; Virginia, 1705-1786 : Democracy or Aristocracy? (East Lansing, Mich 1964) p. 236.
35. Evans, Emorys; : The Rise and Decline of the Virginia Aristocracy in the Eighteenth Century : The Nelson's in Darret B. Rutman ed; The old Dominion : Essays for Thomas Perkins Abernethy (Charlottesville, 1964) pp. 73-74.
36. Farrand, Max : The Framing of the Constitution of the United States, New Haven, 1913, pp. 4-10.
37. Bentley, Arthur F. : The process of Government : A Study of Social pressures (Chicago, 1908) p.152.
38. Bancroft, George; : 'History of the Formation of the Constitution of the United States of America, (2 Vol's : New York, 1882)
39. Fiske, John; : 'The Critical period of American History' 1783-1789, (Boston, 1893) p. 55.

40. Holst, Hermann Von; : "Constitutional History of the United States". (8 Vols, Chicago, 1876-1892)
40. Beard, Charles A.; : "An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, (Rev. ed. New York, 1935) p. 324.
42. Wright, Benjamin F.; : Consensus and Continuity 1776-1787 (Boston, 1958) p. 36.



लोकवाद

1. Caughey, John W. and May, Ernest R. : "A History of the United States", Chicago 1964, PP 151 ff.
2. Morison, Samuel Eliot and Commager, Henry Steele : "The Growth of the American Republic", Vol. I New York 1962 PP 372 ff.
3. Gettell, Raymond G. : "History of American Political Thought" New York 1928, PP 195-201.
4. Ford, Paul L. ed. : Jefferson Thomas, "Notes on the State of Virginia", New York 1894, PP. 202-203.
5. Adams, Henry : "History of the United States of America" New York 1890, I, PP. 185-217.
6. Richardson, James D. ed : "Messages and Papers of the Presidents", Washington 1896, I, PP. 326-332, 361-362.

7. Bowers, Claude G. : "Jefferson in Power, Boston 1963 pp. 33-49.
8. Ford, Paul, L.ed. : "The Writings of Thomas Jefferson" New York 1897, VIII, pp. 144-147.
9. Faulkner, Harold Underwood : "American Political and Social History", New York 1957, pp. 181 ff.
10. Hildreth, Richard : "The History of the United States of America" 6 Vols, New York 1875, IV, pp. 269 ff.
11. Schlesinger, Arthur M. : "The Problem of Richard Hildreth", New England Quarterly, XIII, June 1940. pp. 233-245.
12. Peterson, Merrill D. : "The Jefferson Image in the American Mind. "New York 1962, pp.279 ff.
13. Beard, Charles A. : "Economic Origins of Jeffersonian Democracy", New York 1915, pp. 467 ff.
14. Hertz, Louis : "The Liberal Tradition in America", New York, 1955, pp. 30 ff.
15. Miller, John C. : "The Federalist era, 1789-1801" New York. 1960.
16. Parrington, Vernon L. : "Main Currents in American Thoughts", Vol. I, 1927.

17. Tugwell, Rexford G. and Dorfman, Joseph : "Alexander Hamilton Nation Maker", Columbia University Quarterly 1937, pp. 209-226.
18. Borden, Morton, ed. : American's ten Greatest Presidents' 1961.
19. Hildreth, Richard : The History of the United States of America' 1788-1821 (6 Vols. Rev. ed, New York, 1875) IV P. 296.
20. Hafstadter, Richard, : The American Political Tradition and the Men Who made it' (New York. 1948) P. viii.
- 21 Cunliffe, Marcus F. : The Nation Takes Shape 1789-1837 Chicago , 1959 p. 71
22. Miller, John C. : The Federalist Era 1789-1801 (New York, 1960 , p. 61
23. Passos John Dos, : The Men Who Made The Nation(New York, 1957)p,57
24. Malone, Dumas, : Jefferson and his time, 3 Vols. to date (Boston 1948) II, p. 69
25. Schachner, Nathan, : Thomas Jefferson : A Biogapoy, 2 Vols. (new york 1951), II, p. 38 ff.
26. Miller, John C. : "Alexander Hamillton : Protrait In Paradox' (New York. 1959), p. 10
27. Faulkner, Haroid Underwood : "American Political and

- Socials History" New York
1957, PP. 232 ff.
28. Merriam. Charles Edward : "A History of American Political Theories", New York 1924, PP. 176-199.
29. Parton, James : "Life of Andrew Jackson", Boston 1888 PP. 169-171.
30. Mac Donald William : "Jacksonian Democracy" New York, 1906, PP.-66.
31. Richardson, James.D.ed' : "Messages and Papers of the Presidents".Washington1896 Vol. II. pp. 456-459,579-591.
32. Bowers, Claude. G. : "Party Battles of the Jackson Period" Boston 1922 pp227ff.
- 33: Sehlesinger Arthur M. "The Age of Jackson" Boston, 1945, pp 76-87.
(JR)
34. Morison Samuel Eliot, and Commager.Harry Steel : "The Growth of the American Republic", New York 1962, Vol, I, pp. 468 ff.
35. Caughey, John W, and May, Ernest R. : 'A History of the United States'" Chicage 1964, pp. 183 ff.
36. Parton, James : "Life of Andrew Jackson", 3 Vols., New York 1861, Vol III pp 694-700.
37. Von Holst, Hermann E. : "Constitutional and Political History of the United States" 8 Vols : Chicago, 1876 1892, Vol, II, pp 77.
- 38' Turner,Frederick Jackson : "Re United States 1830-

1850 The Nation & its Sections" New York 1935, pp 28

39. Schlesinger, Arthur M. (Jr.) : "The Age of Jackson", Boston 1945, pp. 76-90, 263 ff.
40. Hofstadter, Richard : The American Political Tradition and the Men who made it, New York, 1948, pp. 55 63.
41. McCormick, Richard P. : "The Second American Party System : Party Formation in the Jackson an Era" Chapel Hill, 1966, p. 13.
"New Perspectives on Jacksonian Politics", American Historical Review LXV, January 1960, pp 288-301.
42. Hammond, Bray : "Jackson, Bibble, and the Bank of the United States". Journal of Economic History, 1857, VII, pp. 1-10.
43. Meyers Marvin : "The Jacksonian Persuasion" American Quarterly, V. 1953 pp, 3-15.
44. Benson, Lee : "The Concept of Jacksonian Democracy : New York as a Test Case". 1961, pp. 329-338.
45. Grob, Gerald N. and Billias, George A. : "Inter pretations of American History : Patterns and Perspectives" Vol.I. New York 1967, pp 367 ff.
46. Remini, Robert V. : The Revolutionary Age of

- Andrew Jackson, Harper & Row: 1976-pp 15-19 30-35, 123 ff 105 ff. 164-174
47. Fish, C. R. : The Age of Common Man, 1937, p. 39 ff.
48. Parton, James : "Life of Andrew Jackson" (3 Vols: New York, 1881), III pp 694, 699.
49. Vonhost, Hermanne : The Constitutional & Political History of The United States (8 Vols:Chicago 1876-1892) II p. 77.
50. Turner, Frederick Jackson: 'The United State 1830-1850 The Nation and its Section, (New York, 1935) p. 28
51. Hofstadter, Richard : The American Political Tradition and The Men Who Made It (New York 1948)pp 55-63.
52. Mc Cromick, Richard P. : "News Perspective on Jacksonian Politics", American Historical Review LXV (January, 1960) 288-301.
53. Mc Cromick, Richard P. : "Suffrage Classes and party Alignments; A Study in Voter Behaviour" Mississippi Valley Historical review XLVI (December 1959) pp 397-410.
54. Mt Tchell, Broadvs : Alexander Hamilton, A concise Biography, oxford 1976. pp 230 ff.
55. Jefferson, Thomas : The Portable Thomas Jefferson edited, viking, 1975 pp. 10 ff, 270 ff, 430 ff. 510 ff.

संयुक्त राज्यवाद

1. Beale, Howard K.; : "What Historians have said about the causes of the Civil War" *In Theory and Practice in Historical study : A Report in the Committee on Historiography, Social Science Research Council, Bulletin 54. (1946) p. 55*
2. Wilson, Henry; : *History of the Rise and Fall of the slave power in America (3 Vols : Boston 1872-1877) I vi-vii*
3. Buchanan, James; : *The Administration on the Eve of the Rebellion : A History of four years before the war (London, 1865) p iv.*
4. Channing Edward; : *A History of the United States (6 vols : New York 1905-1925) VI, 3-4.*
5. Beard, Charles A, & Beard Mary R; : *The Rise of American Civilization (2 Vols : New York, 1927) II, pp. 53-54.*
6. Josephson, Matthew; : *The Robber Barons : The Great American Capitalsits*

- 1861-1901 (New York, 1934) p. viii
7. Allen, James S.; : Reconstruction : The Battle for Democracy 1865-1876 (New York, 1937) pp. 18, 26-28.
 8. Owsley, Frank L.; : The Irrepressible Conflict in Twelve Southern States; Take my stand (New York, 1930) pp. 77-78.
 9. Auchampaugh, Philip C.; : James Buchanan and his Cabinet on the eve of succession (Lancaster' 1926)
 10. Milton' George Fort; : The Eve of conflict : Stephen A Douglas and the needless war (New York, 1934)
 11. Bernes, Gilbert H.; : The Anti Slavery Impulse 1830-1844 (New York. 1033), p. 34
 12. Craven Avery; : The Repressible conflict 1830-1861 (Baton Rouge, 1939) p. 64
 13. Craven Avery; : The coming of the Civil war (New York, 1942) P. 2.
 14. Nicholas, Roy; : The disruption of American Democracy (New York 1948) p. 12-24
 15. Stamp-Kenneth M.; : And the war came : The North and the secession Crisis; 1860-1861 (Baton Rouge, 1950) pp. 2-6

16. Morison, Samuel Eliot; : Faith of a Historian : American
Historical Review LVI
January 1951) p. 267.
17. Pressly, Thomas J; : 'Americans Interpret their
Civil War' (Princeton, 1954)
pp. 321-323:
18. Goss, W. L. : Recollections of a Private,
New York, 1890, pp 1-4
19. Olcott, H. S. : The war's carnival of fraud,
Annals of the war, pp 706-
708.
20. Coulter, E. M. : The confederate states of
America 1861-65, case History
of south, VII, Baton Rouge,
1950, pp. 57-58, 68-71, 75
21. Williams, T. Harry : Lincoln and his Generals,
Alfred A Knopf, 1952, pp.
310-314
22. Freeman, Douglas : R. E. Lee, Vol. iv, Charles
Southall Scribner's sons, 1935., p 49
23. Smelser, Marshall & : American History at a glance
Gundersen, Joan R. Barnes and Noble, 1975., pp
61 ff.
24. Franklin, John Hope : A Southern odyssey, travelers
in the antebellum North,
Louisiana state University
1976., p 42.
25. Weils, Robert W; : Day light in the swamp,
Double Day, 1978., p. 12
26. Richard, Wheeler : Voices of the Civil War, crow-
Well, 1976., pp 34 ff.

27. Wood, W. Birkbeck & Edmonds, Jmese : The Civil War in the United States, London, 1937. pp xv, xix, 26-23, 276-288
28. Schle singer, Arthur M. JR : The Causes of the Civil War : A note on Historical Sentimentalism, Partisan Review, XVI, 1949, pp 969-981.
29. Charn wood, Lord : Abraham Lincoln, Bombay, 1964, pp. 184 ff, 248 ff, 297 ff.
30. Readings in American History, : Edited, Vol. I. Boston, 1956, pp. 294-311, 336-355.



पूँजीवाद

1. Bowers, Cloude G. : The Tragic era : The Revolution after Lincoln (Cambridge, 1929) pp V-VI
2. Coulter, Emerton : The South during Reconstruction (1865-1877) Baton Rouge 1947) p. 148
3. Wharton, Vernon L. : The Negro in Mississippi 1865-1890 (Chapelhill, 1947) pp. 172, 179-180.
4. Woodward C. Vann : Reunion & Reaction : The Compromise of 1877 & the end of reconstruction. (Boston 1951) p. 246
5. Beale, Howard, K : The Critical, Year : A study of Andrew Johnson & Reconstruction (New York 1950), p86
6. Stamp, Kenneth M. : The era of reconstruction 1865-77 (New York, 1965) p. 215.
7. Moore, Albert B : "One Hundred Years of reconstruction of the South," Journal of Southern History, IX, may, 1943, pp. 153-165.

8. Faulkner, Harold Underwood : American Political and Social History, New York, 1957, pp. 683 ff.
9. Caughey, John w. & Ernest R : A History of the United States, Chicago, 1965, pp. 300 ff.
10. Carnegie, Andrew : Triumphant Democracy, New York, 1886, p. 1.
11. Beard, Charles and Mary : The rise of American Civilization, 2 vols, New York, 1927, II' p. 177.
12. Parrington, Vernon L : Main currents in American thought, 3 vols, New York 1927-1930, III, pp. 12, 26.
13. Josephson, Matthew : The Robber Barons : The great American capitalists, 1861-1901, New York, 1934, pp. VII-VIII, 453.
14. Chandler, Alfred D (Jr) : The Beginnings of Big Business, in American industry, Business History Review' XXXIII, spring, 1959, pp, 1-10, 14-20, 22-31.
15. Destler, Chester M : Entrepreneurial leadership among the 'Robber Barons' : A trial balance, the tasks of Economic History (supplement) Journal of Economic History, vi, 1946, pp. 28-49.
16. Kirkland, Edward C : Divide and ruin, Mississippi valley Historical Review, XL III, June, 1956, pp3-17.

17. Wish, Harvey; : Contemporary America, New York 1955, pp. 612 ff, 655 ff,
18. Department of State Bulletin, : :xv pp. 771 ff.
19. Department of State Bulletin : xvi, pp. 1159 ff.
20. Selected speeches and Statements of President Truman, Department of state publication 3653, Washington, pp. 25-34.
21. Department of State, Press Release, June 27, 1950.
22. The New York Times, April 20, 1951.



साम्राज्यवाद

1. "Senate Documents", 63rd Congress, 2nd session, XXIX' Document no. 566.
2. "Papers Relating to the Foreign Relation of the United States, 1915". Washington 1928, Supplement' pp. 393-6.
3. "Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1916". Washington, 1929, Supplement, pp. 259-60.
4. "papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1915," Supplement, pp. 578-9,
5. "Congressional Record",; : 65th Congress, 1st Session, LV. i. 102.
6. "Congressional Record," : 65th Congress. 1st session, LV, 1, 213-14,
7. 'House Documents', : 65th Congress, 2nd session, CXIII, Document No. 765, pp, 3-7.
8. 'Senate Executive Documents' : 67th Congress, 4th session, Document no. 348, pp. 3336—45.

9. 'Senate Documents', : 66th Congress, 1st Session, XXXI, Document No. 76.
- 10 'Congressional Record', : 66th Congress, 1st session, LVI, 8781 ff.
11. 'Borchard Edwin, and Lage, William P. : 'Neutrality for the United States' Nes' Haven 1937, pp. 33-34.
12. Kennan George. : 'American Diplomacy 1900-1950', Chicago 1951, pp. 66.
13. May, Ernest R. : 'The world war and American Isolation 1914-1917', Cambridge 1959, pp. 437.
14. Barnes, Harry Elmer : 'The world war of 1914-1918' in Willard Waller, ed., 'War in the Twentieth Century, New York 1940, pp 71-82, 96-98.
15. Millis Walter : 'How we Entered the last one', The New Republic' LXXXIII, July 31, 1935, pp. 323-27.
16. Link, Arthur S. : 'Wilson the Diplomatist' Baltimore 1957, pp. 31-50, 73-90.
17. Osgood, Robert E. : Ideals & self-interest in America's Foreign Relations : The great transformation of the twentieth Century, Chicago, 1953. pp. 262-263.
18. Barton, Bruce. : The man no body knows : A discovery of the real Jesus, Indianapolis, 1925, preface.
19. Beard. Charles A & : The rise of American Civili-

- Mary R. : zation, 2 vols, New York, 1927, II, p. 800.
20. Stearns, Harold E : Civilization in the United States : An inquiry by thirty Americans, New York, 1922, pp. vi-vii.
21. Hicks, John D. : Normalcy & reaction 1921-1933 : An age of Disillusionment' Washington, 1960, p. 21.
22. Hoffman, Frederick J. : The Twenties : American writing in the post war decade, New York 1962, pp. 434-436.
23. May Henry F. : Shifting perspectives in 1920's, Mississippi valley Historical review, XLIII, December 1956, pp. 424-427.
24. Galbraith, John, K. : The great crash, Houghton Mifflin co & Hamish Hamilton Ltd.' 1955-pp. 30 ff.
25. Link, Arthur S. : What happened to the progressive movement in the 1920's, American Historical review, LXIV July, 1959, pp. 833-851.
26. Degler' Carl N. : The ordeal of Herbert Hoover, the yale review, L II, June. 1963, 563-583.
27. The New York Times, : oct. 30, 1929.
28. The New York Times, : may 5, 1930. oct. 5, 1932.
29. U. S. Statutes at Large, : XLI, i, 305-22.
30. Congressional record, : 72nd cong, I sess, LXXV, v 5086-6

प्रत्याक्रमणवाद

1. Grob, Gerald N. and; Billias, Geoge Athan : 'Interpretation of American History.' Vol. II, New York' 1967, pp. 383 ff.
2. Department of State; 'Bulletin' : I, 201.
3. 'Peace and War'; : Document No. 145, pp. 494—506.
4. 'Report of the Delegate of the United States to the meeting of the Foreign Ministers of the American Republics Held at Panama.' : September 23-October 3, 1939, Department of State Bulletin, Conference Series 44, pp. 62—4.
5. Department of State; 'Bulletin' : III, 138—9.
6. 'House Report,.' : 76th Congress, 3rd Session, No. 1476.
7. 'House Miscellaneous Documents' : 76th Congress, 3rd Session, Document No. 943.
8. 'U. S. Statutes at Large' : LIV, i. 885 ff.
9. 'Peace and War' : Document No. 184, PP. 573—4.

10. 'U. S, Statutes at Large, : LV, i, 53—5.
11. 'Peace and War,' : Document No. 229. pp. 717-9.
12. Department of State, 'Bulletin' : V, 380.
13. 'Foreign Relations of; the United States : Japan, 1931-1941, II, 755-6.
14. 'peace and War; : Document No. 267, pp. 839-40.
15. The London Times,; : December 12, 1941.
16. 'Senate Documents : 79th Congress, 2nd session, part V, 'Document No. 244 pp. 251 ff.
17. Calvocoressi Peter, and wint, Guy; : 'Total War', Great Britain 19-74, pp.186-195, 695-6, 714-19, 836—48.
18. Joll, James : 'Europe since 1870.' Great Britain 1976, pp. 391, 427—33. 452 ff.
19. Beard, Charles. A : 'President Roosevelt and the coming of the War. 1941 : A Study in Appearances and Realities. New Haven. 1948. p. 598.
20. Chamberlain, William, Henry : 'The Bankruptcy of a Policy' in 'Perpetual War for perpetual peace. ed. Harry Elmer Barnes, Caldwell. 1953. p. 491.

21. Ferrell, Robert H, : 'Pearl Harbor and the revisionists.' *The Historian*, XVII. 1955. pp. 233 ff.
22. Kennan, George F. : 'American Diplomacy 1900—1950.' Chicago 1951, pp. 48 ff.
23. Feis, Herbert : 'The Road to Pearl Harbor : the coming of war between the United States and Japan. Princeton 1950; pp. 68 ff. 'War Came at Pearl Harbor : Suspicions considered.' *The Yale Review*. XLV 1956 pp 378—390.
24. Schroeder, Paul W.; : 'The Axis Alliance & Japanese - American relations', 1941, Cornell University press, 1958 pp. 200-216.
25. Perkins, Dexter; : 'Was Roosevelt wrong?' *Virginia Quarterly Review*, XXX, 1954, pp. 355-372.
26. Rauch, Basil : 'Roosevelt : from Munich to Pearl Harbor,' New York, 1950, pp, 40 ff.
27. Commager, Henry Steele; : 'Twelve years of Roosevelt,' *American mercury*, LX April, 1945, pp. 391-401.
28. Freidel, Frank; : 'The New Deal in Historical perspective,' Washington. 1965, p. 6.
29. Hofstadter, Richard; : 'The age of reform : From

- Bryan to F. D. R., New York, 1955, pp. 314, 323.
30. Flynn, John T.; : The Roosevelt Myth, New York, 1956, pp. 414, 445.
31. Robinson, Edgar Eugene; : The Roosevelt leadership 1933-1945, Philadelphia, 1955, pp. 393, 397, 408.
32. Leuchten berg, William E; : Franklind, Roosevelt and the New Deal, New York, 1963, pp. 344-345
33. Schlesinger, Arthur M (JR); : Sources of the New Deal : reflections on the temper of a time, Columbia University forum, II, 1959, pp. 4-12.
34. Tugwell, Rexford G; : The New Deal in Retrospect, Western Political Quarterly, I, December, 1948. pp. 373-385,
35. Eulau Heinz; : Neither ideology nor utopia : The New Deal in retrospect, the antioch review, xix, Winter 1959-1960, pp. 523-37.
36. The New York Times, : March 5, 1933. January 5, 1939.
37. Senate reports, : 75th Congress, I session, report no. 711, pp. 41-4.
38. U. S. Statutes at large, : xlv iii, i. 58 ff.i.195 ff; xlix, i. 620 ff.

सिद्धान्तवाद

1. Spanier, J. W. : American foreign policy Since world war II, 1960, pp. 82 ff.
2. Hammond, P.Y. : Organizing for defence, 1961, pp. 102. ff.
3. Lukacs, John : A History of the cold war, 1961, pp. 70 ff.
4. Rostow, W. W. : The United States in the World Arena. 1960, pp. 205 ff.
5. Fleming' D. F. : The cold war & Its origins 1960, pp. 39 ff.
6. Leckie, Robert : Conflict : The History of the korean war, 1962. pp. 14 ff, 114 ff.
7. Rovere, Richard : Senator Joe Mccarthy, 1959, pp 76 ff.
8. Wish, Harvey : Contemporary America, 1955 pp 609 ff.
9. Nettle, J, P, : The Soviet Achievement, ENT 1967, p. 186

10. Horowitz, David : From Yalta to Vietnam, 1967, p 389.
11. Fulbright, J. William : The Arrogance of power, 1970, pp 107-8.
12. Nkrumah, K. : Neo-colonialism : The last stage of Imerialism, 1965, p, ix.
13. Aron, R. : Peace and war, 1966, p. 506.
14. Harkness, David, : The post, war world, 1974, pp 51 ff.



अस्तित्ववाद

1. 'Atomic Power for Peace, : official records of the General Assembly, 8th sess., An address by president Eisenhower, sept. 15. Dec. 9, 1953, pp, 450-52.
2. Dept. of state, Bulletin, xxxv, 751-5.
3. House Documents, 85th Cong, 1st Sess., Doc. No.46.
4. Dept. of state, Bulletin, xxxix' 181-2,
5. Dept, of state, Bulletin, xxxv, 700,
7. Senate Executive Report No, 2, 84th Cong., 1st. Sess.
8. The New York Times, Oct, 5, 1958.
9. The New York Times, Sept. 23, 1960.
9. The New York Times : Aug. 10, 1960.
10. The New York Times. Oct. 15, 1960.
11. The New York Times, Jan 4, 1961.
12. U. S. Statutes at large, LXVII, i, 29-33.
13. U. S. Statutes at Large, LXVIII, i, 775-80.

14. Senate Resolution 301, 83rd Cong., 2nd Sess.
15. 163 United States Reports 267.
16. 347 United States Reports 483.
17. U. S. Statutes at Large, LXXI, 634-8.
18. Legislative History of the Labor Management Reporting & Disclosure Act of 1959, 2 vols. (published by the National Labor Relations Board) (Washington : Government Printing Office, 1959) I, 1-29.
19. The New York Times, Dec. 16, 1960.
20. The New York Times, Jan. 20, 1961.
21. The New York Times, Feb, 10, 1961.
22. The New York Times, Mar. 2, 1961.
23. Wish, Harvey; : "Contemporary America-The National Scene since 1900", New York, 1955, pp. 665-678.
24. Caughey, John W and May, Ernest R; : "A History of the United States, Chicago, 1965, pp. 682-702,
25. G, Raebner, Norman, : "The New Isolationism", 1956, pp 101,
26. Hughes, E, J, : The Ordeal of Power, 1963, pp. 113 ff

27. Donovan, R. J.' : "Eisehower, the in side story" 1956, pp. 56 ff.
28. Eisenhower, D, : "Mandate for Change" 1963, pp 30 ff
29. Burns, J, M, : "John F Kennedy" 1960. pp. 81 ff
30. Fuller, Helen, : "Year of Trial : Kennedy's crucial decisions", 1962, pp 60 ff
31. Sidey, Hugh, : "John F Kennedy, President" 1963, pp 12 ff
32. Burns, J, M, : "Deadlock of democracy" 1963, pp, 41 ff
33. Schlesinger, Arthur M (JR) : "A thousand days" 1967 pp. 390 ff, 727 ff.
34. Drimmer, Melvin : "Black History : A Reappraisal" 1968, pp. 435-37, 439, 441, 468. 476.
35. Lipmann, Walter : "The Great Society-a plan" U. S. I. S, London 1965, pp. 25 ff.
36. President Johnson, : "In augural address" 20 January, 1965,
37. President Johnson, : "Address to Congress," 15 March, 1965.
- 38' Parkes, Henry Bamford : "The United States of America," 1968, pp. 755 ff.



नव्य उपनिवेशवाद

1. Bain, Chester A' : Vietnam : The Roots of Conflict. : Prentice-Hall, 1967, pp. 37 ff.
2. Chaffee, Frederic H, : et al. Area Handbook for the Philippines, Washington, D. C. : U. S. Government Printing office, 1969. A guide-book, including statistics and maps, to all aspects of the Philippines.
3. Committee of Concerned Asian Scholars : The Indochina story. New York : Bantam books. 1970 (Paperback). A documented study of the causes of war.
4. Fall, Bernhard. : The two Viet-nams A Political and Military analysis. New York: Praeger, 1964. An early work by the noted scholar.
5. Fisher, C. A. : South-East Asia; A social, Economic, & Political Geography, London: Methuen, 1964
6. Fitzgerald, Frances. : Fire in the Lake; The Vietnamese and the Americans in

Vietnam. Boston : Little Brown, 1972. A prize-winning account of the origins of the Vietnam War.

7. Ginsburg, Norton (ed.); : "The pattern of Asia" Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1958. A good geography. with maps, plates, and bibliographies.
8. Golay, Frank H. (ed), : "The United States and the Philippines". Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. Various perspectives on a unique relationship.
9. Hall, D. E. G., : A History of South-East Asia. New York : Macmillan, 1964. A scholarly account from the earliest times to post-world war II.
10. Ho chi Minh. : On Revolution : Selected writings, 1920-60. New York : International Publishers, 1970.
11. Larkin, John A & Benda, Harry, Jr; : "The world of south east Asia" : Selected Historical readings, New York ; Harper & Row, 1967.
12. Raskin, Marcus G., and Fall, Bernard B. : "The Viet-nam reader". New York : Random House, 1965.
13. Ravenholt., Albert : "The Philippines : A young Republic on the move,

- Princeton : Van Nostrand, 1962.
14. Reichauer E. & Fairbank, : "History of East Asian civiliza-
A. J. K. tions." 2 vols. Boston :
Houghton Mifflin Company,
1961-64.
 15. Sihanouk, Norodom. ; : "My war with the CIA". New
York : Random House. 1972.
Prince Sihanouk's description
of the U. S. role in Cambodia.
 16. Smith, Harvey H., : "et al. Area handbook for
North Vietnam". Washington,
D. C. : U. S. Government
Printing Office, 1967.
 17. Tarling, Nicholas. : "A concise History of south-
east Asia". New York : Prae-
ger, 1966. Analyzes the
origins of nationalis,
 18. Taylor, George R.; : "The Philippines and the
United States : problems of
Partnership". New York :
Praeger, 1964.
 19. U. S, Department of : "The pentagon papers". New
Defense.; York : Bantam Books, 1971.
: Essential for an understand-
ing of the U. S, role in
Southeast Asia.
 20. Chomsky, Noam. : "At War With Asia", Great
Britain, 1971, pp 27 ff.
 21. New York Times,; : December 14, 1945, p. 6.

22. Los Angeles Times'; : February 6, 1969.
23. Dayan, Moshe, : "Story of my life", London, 1976. pp. 291-301, 318-342, 387 ff, 463 ff, 551-574.
24. Meir, Golda., : "My Life "Futura Book.1975, pp. 16-51, 103-5, 244-5, 249-50, 320-30, 359-63, 369-76.
25. Armajani, Yahya., : "Middle East : past & Present". New Jersey, 1970, pp, 359-60, 390-91.

